

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DATE	SIGNATURE

मार्क्स स वतमान तक

७

धर्म नारायण मिश्र

एम. ए., पी-एच. डी.

राजनीति विज्ञान विभाग

गवर्नमेन्ट कॉलेज, अजमेर



स्वतन्त्र प्रकाशन, अजमेर

प्रकाशक

स मिश्रा

स्वतंत्र प्रकाशन

कोठारी भवन धीनगर रोड

अजमेर

● धर्मनारायण मिश्र

- लेखक की अन्य पुस्तकें
- समाजवाद स सर्वोदय तक
- समाजवाद

प्रथम संस्करण

1974-75

मूल्य 21 00

मुद्रक

अचना प्रकाशन

मेहरा हाउस बाग बाग अजमेर

मावसंवाद का अर्थ; मावसंवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद; मावसं- वाद सिद्धान्त, इन्द्रात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिक-वादो व्याख्या प्रतिरिक्त मूल सिद्धान्त, वर्ग-संघर्ष-संबंधों द्वारा प्रधिनायकत्व, साम्यवादी व्यवस्था; मूल्यांकन ।

भराजकतावाद

W. G. O. Book Bank

37-

अर्थ; विकास एवं परम्परा; प्रमुख भराजकतावादी; भराजकतावाद के सिद्धांत; भराजकतावाद एवं मावसंवाद-साम्यवाद; भराजकतावाद का मूल्यांकन सिन्डीकलवाद

66-

विकास; अर्थ, विचारसूत्र; प्रभाव एवं योगदान ।

फेबियनवाद

87-

अर्थ, फेबियन मोमार्टो की स्थापना एवं उद्देश्य, फेबियनवाद के प्रमुख प्रवर्तक फेबियन समाजवाद के सिद्धान्त, फेबियनवाद का मूल्यांकन एवं योगदान गिल्ड समाजवाद

100-

अर्थ, विकास, प्रभाव; प्रमुख गिल्ड समाजवादी; गिल्ड समाजवाद के विचारसूत्र; गिल्ड समाजवाद एवं राज्य; साधन; मूल्यांकन एवं योगदान साम्यवाद

125-

लेनिन, ट्राट्स्की, स्टालिन, माघो-स्वेंतुंग आदि प्रथम, साम्यवाद एवं मावसंवाद; लेनिनवाद-मावसंवाद और लेनिन 'साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अन्तिम अवस्था', एक देश में समाजवाद, का के लिए उपयुक्त अवस्था, साम्यवादी दल, राज्य का लोप;

ट्राट्स्की-ट्राट्स्की तथा लेनिन, ट्राट्स्की और स्टालिन, ट्राट्स्की के विचार एवं मूल्यांकन

स्टालिनवाद-स्टालिन-ट्राट्स्की मतभेद; कृषि का सामुदायीकरण, 'एक देश में समाजवाद', राष्ट्रीय स्वायत्तता का सिद्धान्त, राज्य का लोप, व्यक्ति तानाशाही

साम्यवादी विचारधारा में निहित स्त्रुचेव का योगदान; शोषण विरोधी सिद्धान्त माघोवाद-मृच्छभूमि एवं प्रादुर्भाव; माघोवाद एवं मावसंवाद; सैतिहर में साम्यवादी अन्ति का सिद्धान्त; अन्ति नीति एवं सामरिक चालें; एवं शक्ति, मोरतांत्रिक तानाशाही; 'सैबर्हों फूर्तों का सिद्धान्त, राष्ट्र संस्कृति, सांस्कृतिक अन्ति

तथा नवीन अन्तिदान; अन्तर्-राष्ट्रीय साम्यवाद, माघोवाद मूल्यांकन

साम्यवाद के अन्त प्रमुख पक्ष; दस-चौन विचार मतभेद; साम्य का मूल्यांकन

पुनर्विचार एव सशोधनवाद

पुनर्विचार एव सशोधनवाद से तात्पर्य, पुनर्विचार की पृष्ठभूमि-कडिनिन्ड लासेल, गोपा कन्वेंशन, द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय, एरफर्ट कार्यक्रम, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी,

एडुअड बन्सटोन-जीवनी, बन्सटोन पत्र 1898, बन्सटोन द्वारा मार्क्सवादी सिद्धान्तों का खण्डन, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग सघर्ष, साधन, सामाजिक युग परिवर्तन, मूल्य का धर्म सिद्धान्त, धर्म सगठन, सर्वहारा समाजवाद, राज्य का स्वभाव, राष्ट्रीय बनाम अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद, मार्क्सवादी यूटोपियायी, उदारवाद का समर्थन बन्सटोन के विचारों

का मूल्यांकन

काट्स्की—जीवनी, काट्स्की के विचार, काट्स्का तथा बन्सटोन, काट्स्की तथा लनिन द्वारा काट्स्की की आलोचना

पुनर्विचारवाद एव सशोधनवाद का वर्तमान स्वरूप

फासीवाद एव नात्सीवाद 10 32 200-232

फासीवाद एव नात्सीवाद का प्रादुर्भाव, प्रेरणा एव पृष्ठभूमि, फासीवाद की मार्क्सवादी व्याख्या, फासीवाद के सिद्धान्त, फासीवादी राज्य, कॉर्पोरेट राज्य, फासिस्ट दल एव नेतृत्व, फासीवाद एव अन्तर्राष्ट्रीयवाद, साधन, फासीवाद एव साम्यवाद, मूल्यांकन।

लोकतान्त्रिक समाजवाद 24 233-257

प्रारम्भिक व्याख्या, अर्थ, विकास—विभिन्न देशों में लोकतान्त्रिक समाजवाद, भारत और लोकतान्त्रिक समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद के विचार सूत्र, अर्थ व्यवस्था, साधन, लोकतान्त्रिक समाजवाद के विषय में सतर्कता,

मूल्यांकन एव योगदान।

गांधीवाद 258-304

अर्थ, प्रभाव एव पुर्ववर्ती दर्शन, सत्याग्रह सिद्धान्त, अहिंसा का दर्शन, साध्य एव साधन, अहिंसात्मक राज्य, अधिकार एव कर्तव्य, अक्षय्य एव दण्ड, अन्तर्राष्ट्रीयवाद, ट्रस्टीशिप सिद्धान्त, स्वदेशी सिद्धान्त, सामाजिक विचार, गांधीवाद तथा मार्क्सवाद, मूल्यांकन एव योगदान।

सर्वोदय 305-325

अर्थ, विकास, सर्वोदय एव गांधीवाद, सर्वोदय दर्शन, भूदान आन्दोलन, सम्पत्तिदान, ग्रामदान एव ग्राम राज, जीवनदान, सर्वोदय समीक्षा; गिहार एव सर्वोदय आन्दोलन।

सम्प्रभुता एव बहुलवाद 326-352

सम्प्रभुता—व्याख्या, सम्प्रभुता का एकत्ववादी सिद्धान्त, सम्प्रभुता सिद्धान्त का विकास, बोर्दा के विचार, हाब्स के विचार, फ्रांसिस् द्वारा सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त की व्याख्या

बहुलवाद—धर्म; प्रादुर्भाव, प्रमुख बहुलवादी, सम्प्रभु सिद्धान्त के विरुद्ध बहुलवादी तर्क; राज्य एवं समुदाय, समूह व्यक्तित्व सिद्धान्त, बहुलवाद तथा राज्य, बहुलवाद एवं प्रतिनिधि सरकार; बहुलवाद तथा गिल्ड समाजवाद; मूल्यांकन ।

हेराल्ड सास्की के राजनीतिक विचार 3 353-37.
सास्की की जीवनी; सास्की तथा राज्य सम्प्रभुता, बहुलवादी विचार; सास्की के समाजवादी विचार-बहुलवाद का समाज-वादी विवेचन, राजनीति प्राथमिक कारकों का प्रभाव; अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता; सम्पत्ति, विधि सिद्धान्त, जन सहमति द्वारा शक्ति; मार्क्सवाद की धार, सास्की के विचारों का मूल्यांकन ।

ग्राहम वालास के विचार

विवेक के विरुद्ध विद्रोह 378-40
'विवेक के विरुद्ध विद्रोह' की व्याख्या, कारण; विवेक विरोध का विकास अनुभववाद धीरे विवेक, प्रयोगवाद धीरे विवेक, समाजशास्त्र एवं अविवेकवाद; एमिल डकहोम; विलफ्रेडो पैरेटो—अवशिष्ट प्रवृत्तियों का सिद्धान्त; सामाजिक सन्तुलन सिद्धान्त, मूल्यांकन; ग्रहम वालास—राजनीति में मानव स्वभाव, शासन व्यवस्था धीरे मानव स्वभाव, महान समाज, मूल्यांकन; जेलियम मैकडुगल—वृत्ति सिद्धान्त, सामाजिक मनोविज्ञान, राष्ट्र व्यवहारवाद, मूल्यांकन; हेराल्ड सासवेल—राजनीति में मनोविज्ञान; मनोविकास एवं राजनीति, शक्ति एवं समाज, राजनीतिक व्यवहार; विवेक के प्रति विद्रोह का सामान्य मूल्यांकन ।

राजनीति विज्ञान के नवीन धारणा 407-44
राजनीति शास्त्र का परम्परागत स्वरूप; राजनीति विज्ञान का नवीन स्वरूप—मानव अध्ययन, सन्तर्भाव अध्ययन, शक्ति एवं राजनीति, नैतिक राजनीतिक सत्त्व, नवीन अध्ययन पद्धतियाँ

व्यवहारवादी अध्ययन-मार्ग
धर्म, विकास, धार्मिक वेन्टसे; वालस मेरिहम; व्यवहारवादी अध्ययन । प्रमुख विशेषताएँ, हेन्रि ईस्टन की बौद्धिक धारणा-शिक्षण; क्षेत्र पद्धतियाँ; सीमाएँ, धारणा—परम्परावादी धारणा; उत्तर व्यवहारवादी अध्ययन; निष्कर्ष

निर्णय निर्माण सिद्धान्त—सिद्धान्त की व्याख्या; हरबर्ट साइमन, रिचर्ड स्नोडर; निर्णय निर्माण सिद्धान्त की संरचना; निर्णय-प्रक्रिया; विभिन्न सिद्धान्त; मूल्यांकन ।

संचार सिद्धान्त—सिद्धान्त के प्रवर्तक, नारबर्ट वीनर, कार्ल डायश; सिद्धान्त की व्याख्या; साध्यव्यवस्था; फीडबैक सिस्टम; संचार सिद्धान्त तथा राजनीति; मूल्यांकन ।

आमुख

राजनीति विज्ञान के प्रगति क्रम में आधुनिक युग विचारधाराओं का युग । उन्नीसवीं शताब्दी से अब तक कई महत्त्वपूर्ण विचारधाराओं का प्रवर्तन हुआ जो अपने अपने ढंग से मानव कल्याण तथा सामाजिक व्यवस्था के लगभग समस्त ओं को नये सिरे से मजंन करने के प्रयाम एव सूझाव हैं । इन विचारधाराओं के ाप कई महान चिन्तकों के नाम जुड़े हुए हैं । मार्क्सवाद के प्रादुर्भाव से राजनीतिक न्त्न में एक नया मोड़ आया । यद्यपि मार्क्स एव एंजिल्स के पूर्वं अन्य समाजवादी न्तक जैसे सेन्ट साइमन, चार्ल्स फोरिये, राबर्ट ओवन आदि हुए हैं किन्तु समाज-ादी विन्तन को एक आन्दोलन, प्राति, दर्शन तथा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का ये मार्क्सवाद को है । कुछ अपने-प्रापे की द्योद कर समस्त आधुनिक विचारधाराएा तो समाजवाद के विभिन्न सम्प्रदाय हैं या किसी न किसी रूप में वे समाजवाद सम्बद्ध हैं ।

गांधीवाद के उपरान्त नवीन विचारधाराओं के विकास एव प्रादुर्भाव का म्म एक सा गया है, दूसरी ओर राजनीतिशास्त्र के स्वभाव, क्षेत्र तथा अध्ययन ङ्तिमें मे आमूल परिवर्तनों का प्रारम्भ हुआ है । यद्यपि 'विवेक के विरुद्ध विद्रोह' इस परिवर्तन की प्रवृत्ति निहित है किन्तु व्यवहारवादी अध्ययन के समावेश से राजनीति शास्त्र एक नया स्वरूप ग्रहण करता जा रहा है, वह शास्त्र से विज्ञान के ओर झुकता ही रहा है । अब व्यवहारवादी तथा इससे सम्बद्ध अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन अपूर्ण तथा असामयिक लगने लगा है ।

प्रस्तुत पुस्तक में मार्क्स से लेकर अब तक की विभिन्न समाजवादी विचार-ाराओं, प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं (जैसे सम्प्रभुता और बहुलवाद) कुछ प्रमुख न्तकों (जैसे हेरॉल्ड लास्की आदि) तथा राजनीति विज्ञान में नवीन प्रवृत्तियों का ष्लेषण प्रस्तुत किया गया है । यह अध्ययन सामान्यतः मूल क्षेत्रों पर आधारित है । यपि यह पुस्तक स्नातकोत्तर बुद्धिजीवियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए लिखी ई है, पर सामान्य पाठक भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे ।

इस पुस्तक की रचना में मुझे अपने गुरु प्रोफेसर ए० जी० भाबुर से सर्वा-प्रीत्याह्न मिला है । इस पुस्तक के विभिन्न पक्षों की जटिलताओं को समझने मुझे उनसे समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा, इसके लिये मैं उनके प्रति और आभार व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ ।

मार्क्सवाद

Karl Marx (1818-1883), Frederick Engels (1820-1895)

कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई, 1818 को ट्रीब्स (Treves) में, जर्मनी के एक प्रौद्योगिक धनी परिवार में हुआ। मार्क्स के माता-पिता यहूदी थे किन्तु जिस समय मार्क्स की आयु 6 वर्ष की थी, इनके माता-पिता ने प्रोटेस्टेंट (ईसाई धर्म की शाखा) धर्म प्रयोग कर लिया। 17 वर्ष की आयु में मार्क्स ने बोन (Bonn) विश्व-विद्यालय में कानून तथा वाद में दर्शन शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया। बर्लिन (Berlin) तथा जेना (Jena) विश्वविद्यालयों में भी मार्क्स ने अध्ययन किया। विद्यार्थी जीवन से ही वे हीगेल के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। 1841 में मार्क्स ने जेना विश्व विद्यालय में डॉक्टरेट (Doctorate) प्राप्त की। मार्क्स के शोध-ग्रन्थ का विषय था—The Difference Between the Natural philosophy of Democritus and of Epicurus. दो वर्ष के उपरान्त 1843 में, मार्क्स का विवाह प्रुसा (Prussia) के एक उच्च घराने की लड़की जेनी (Jenny Von Westphalen) के साथ हुआ। मार्क्स के साहित्यिक तथा क्रान्तिकारी जीवन का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव उनकी पत्नी जेनी पर पड़ा जिसने जीवन भर एक महान व्यक्तिकी तरह समस्त व्यथाओं को सहन किया। रागभंग इसी समय मार्क्स उपरवादी विचारक तथा क्रान्तिकारी बनना जा रहा था। उसके इस प्रकार के विचारों से उसे विश्व-विद्यालय में कार्य नहीं मिल सका। यदि मार्क्स को उस समय विश्व-विद्यालय में शिक्षक का कार्य मिल जाता तो सम्भवतः इस समय इतिहास कुछ और ही होता। तदुपरान्त मार्क्स उपरवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में उतर पड़ा। परिणामस्वरूप उसे प्रुसा (Prussia) में निर्वासित किया गया। इसके बाद मार्क्स ने 1848 तक क्रान्तिकारी जीवन व्यतीत किया तथा उसे यूरोप में निरन्तर दूधर में उधर भागना पड़ा। 1848 से अपनी मृत्यु तक मार्क्स इंग्लैंड में लगभग निर्वासित होकर रहा।

कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद का एक प्रमुख साधक भाग है। मार्क्सवादी धर्म का दूसरा भाग फ्रेडरिक ऐन्जिल्स है। ऐन्जिल्स का जन्म बार्मेन (Barmen), जर्मनी में, 1820 में एक धनी परिवार में हुआ। ऐन्जिल्स इंग्लैंड में अपनी पिता के व्यवसाय की-देख-रे

करता था। माक्स और ऐन्जिल्स का मिलन एक पत्र के माध्यम से हुआ। पेरिस में प्रकाशित एक पत्र—*Deutsch Französische Fahrbacher*—के प्रक में माक्स और ऐन्जिल्स दोनों के ही लेख प्रकाशित हुए। दोनों ही एक दूसरे के लेखों से बड़े प्रभावित हुए तथा 1842 से ये ऐसे घनिष्ठ मित्र हुए कि साहित्यिक जगत में इस प्रकार की युगलबन्धों का उदाहरण मिलना सम्भव नहीं है।

माक्सवाद को इन दोनों व्यक्तियों के योगदान का अलग अलग मूल्यांकन सम्भव नहीं। ये दो व्यक्ति किन्तु एक साहित्यिक आत्मा थे। 1847 में माक्स तथा ऐन्जिल्स ने सन्दन में कम्युनिस्ट लीग (Communist League) की स्थापना की। इस लीग के उद्देश्य एवं कार्यक्रम के रूप में माक्स तथा ऐन्जिल्स द्वारा 1848 में कम्युनिस्ट मैनीफेस्टो (The Manifesto of the Communist party) की रचना हुई। यही से वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) का युग प्रारम्भ होता है।¹ ऐन्जिल्स ने कई ग्रन्थ माक्स के साथ लिखे तथा कुछ का सम्पादन किया। माक्स की 'केपिटल' (Capital) के द्वितीय तथा तृतीय खण्डों का सम्पादन ऐन्जिल्स ने ही किया था। ऐन्जिल्स ने माक्स की साहित्यिक छेत्र में ही सहायता नहीं की किन्तु उसके परिवार के भरण-पोषण में भी धन राशि की मदद देता रहा। 1860 के पश्चात् तो वह माक्स के परिवार को 350 पौण्ड वार्षिक नियमित रूप से देने लगा। इतना सब होते हुए भी ऐन्जिल्स को माक्स का चिड़चिड़ा स्वभाव सहन करना पड़ता था। ऐन्जिल्स माक्स को सदैव ही आगे रख स्वयं पृष्ठभूमि में रहा। ऐन्जिल्स के विषय में ऐलेग्जेंडर ग्रे ने लिखा है—

“इतिहास में इस प्रकार के कई दृष्टान्त हैं जहाँ मनुष्य ने औरत के लिये तथा औरत ने मनुष्य के लिये सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। लेकिन ऐन्जिल्स जैसा उदाहरण इतिहास में मिलना मुश्किल है, बिना किसी रक्त-सम्बन्ध के एक सामान्य उद्देश्य के लिये उसने माक्स के लिये अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पण कर दिया। ऐन्जिल्स ने स्वतन्त्र रूप से महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं किन्तु उसने माक्स के अनुचर के रूप में ही रहना उचित समझा।”²

माक्स तथा ऐन्जिल्स ने यूरोप में क्रान्तिकारी आन्दोलनों को सगटित करने का काफी प्रयत्न किया तथा 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' की स्थापना की। 1883 में माक्स की मृत्यु के पश्चात् ऐन्जिल्स अपनी मृत्यु तक माक्सवाद का प्रमुख अग्रणी प्रवक्ता रहा। इतिहास में माक्स को ही अधिक सम्मान दिया है किन्तु माक्स को ऐन्जिल्स के बिना नहीं समझा जा सकता।

1 Kitzler and Ross, Western Social Thought, p 263

2 Gray, Alexander, The Socialist Tradition, p 298

माक्स तथा ऐन्जिल्स के निम्नलिखित प्रमुख ग्रन्थों में माक्सवाद की पूर्ण व्याख्या मिलती है:—

Engels, F., Condition of the Working Classes in England, 1844.

Marx and Engels, The Holy Family, 1844.

Karl Marx The Poverty of Philosophy, 1847.

Marx and Engels, The Manifesto of the Communist Party, 1848.

साम्यवादी घोषणा पत्र छोटी किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है। वास्तव में इनकी बाद की रचनाएँ इसी घोषणा पत्र की व्यापक टीकाएँ हैं।³

Karl Marx, The Critique of Political Economy, 1859.

Karl Marx, Value, Price, Profit, 1865.

Engels, F., Anti Duhring.

Karl Marx, Das Kapital (Capital) Vol. I., 1867.

Engels, F., Socialism, Utopian and Scientific, 1880.

Karl Marx, Das Kapital, Vol II edited by Engels, 1885.

Karl Marx, Das Kapital, Vol. III, edited by Engels, 1895.

वैज्ञानिक समाजवाद

माक्स अपने सहयोगी ऐन्जिल्स के साथ धर्मिक-वर्ग आन्दोलन के लिए वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है। माक्सवाद को प्रायः सर्वहारा समाजवाद (Proletarian Socialism), क्रान्तिकारी समाजवाद (Revolutionary Socialism) तथा वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) भी कहा जाता है। कार्ल माक्स का दावा था कि जिस समाजवाद का वह प्रतिपादन कर रहे थे वह वैज्ञानिक था। इसके लिए उसने उस समय के यूटोपियायी विचारों की आलोचना ही नहीं की, उसने न तो उनके कोई काल्पनिक आदर्श ही छपनाये तथा न उनसे अपना कोई विचार सम्बन्ध रखा। माक्स के अनुसार यूटोपियायी समाजवादी सर्वहारा वर्ग के विषय में धनभिन्न थे; समाजवाद लाने के लिए उन्होंने समस्त समाज, विशेषतः उच्च वर्ग से घनील की; उन्होंने भविष्य के बड़े आदर्शवादी-कल्पनावादी स्वप्न देगे; वे नैतिकता तथा मनुष्य की भ्रष्टाई को स्वीकार कर समाजवाद लाना चाहते थे। माक्स के अनुसार कल्पनाओं और सद्भावनाओं के आधार पर आदर्श समाज के स्वप्न को पृथ्वी पर मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिए यूटोपियायी वैज्ञानिक समाजवादी नहीं हो सके थे। माक्स तथा प्रयोग के विचार संपर्क के परिणामस्वरूप माक्स के विचारों में बड़ी प्रगति हुई। प्रयोग की पुस्तक—Philosophy of Poverty—के प्रत्युत्तर में माक्स ने

3. Kitzler and Ross, Western Social Thought, p. 263.

1947 म - Poverty of Philosophy - निखी । यह ग्रन्थ ही मार्क्स ऐजिन्ड द्वारा लिखित साम्यवादी घोषणा पत्र की भूमिका तैयार करता है ।⁴ इसी घोषणा पत्र म सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद का विवेचन किया गया है । साम्यवादी घोषणा पत्र म मार्क्स-ऐन्जिल्स न लिखा है —

“साम्यवाद घन शाब्दिक ग्रंथ म अवश्य ही एक विधि का सिद्धान्त है । यह उन नियमों को स्थापित करता है जिनके द्वारा पूँजीवाद को समाजवाद म बदना जा सकता है ।”⁵

ऐल्ग्वन्डर ग्रै न वैज्ञानिक समाजवाद को स्पष्ट करत हुए लिखा है —

“जैसा कि मार्क्स न प्रस्तुत किया है शास्त्रीय ग्रंथ म वैज्ञानिक समाजवाद कम स कम इतिहास का दर्शन है. बग-सघर्ष का मूर्तरूप, आर्थिक तर्कों पर आधारित घोषणा का सिद्धान्त तथा सवहार बग व अधिनायकत्व का स्वप्न है ।”⁶

ऐसी अवस्था म मार्क्स ही पहला समाजवादी लेखक है जिसके कार्यों का वैज्ञानिक माना जा सकता है । “उसने न केवल उस समाज का चित्र अंकित किया जिसे वह वाछनीय समझता था, अपितु उसन विस्तारपूर्वक उन दशाघ्रा का वर्णन किया जिनमें होकर उस आदर्श समाज को विकसित होता चाहिए ।”⁷ मार्क्स ने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक बतलाते हुए कहा है कि यह इतिहास क विज्ञान का परिणाम है न कि भस्तिष्क की कल्पना, यह उस विधि विधान पर आधारित है जिनके द्वारा मानव इतिहास प्रगति करता है । लेन लकास्टर (Lane Lancaster) के अनुसार मार्क्स-वाद के वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो प्रमुख आधार थे । प्रथम, यह वास्तविकता (realism) पर आधारित है न कि कल्पना पर । द्वितीय, यह पूर्ण तथा प्राधीन व्यवस्था को ही वैज्ञानिक तरीके से नहीं समझता किन्तु नई व्यवस्था प्राप्त करने के लिए भी वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है ।⁸ वास्तव म मार्क्स के समाजवाद का वैज्ञानिक होना तत्कालीन युग की भी देन तथा उनका स्वयं का दृष्टिकोण था । इन सम्बन्ध म मिलोवन जिलास (Milovan Djilas) लिखत हैं—

4 Kizer and Ross, Western Social Thought, p 253

5 Preface to the Communist Manifesto

6 “ in its classic form as presented by Marx (1818-1883) scientific socialism comprises a theory of philosophy, of history, of the class struggle, a theory of exploitation, based on presumed economic reasoning and a vision of the dictatorship of the proletariat ”
Gray, Alexander, The Socialist Tradition, p 5

7 जोड आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त प्रवेशिका, पृ 36.

8 Lancaster, L. W, Masters of Political Thought, vol III, p 163

“मार्क्स के विचार उस समय के वैज्ञानिक वातावरण से प्रभावित हुए, विज्ञान के प्रति उनका स्वयं का अध्ययन तथा अपनी शान्तिकारी भाकांक्षाओं से वे श्रमिक-वर्ग आन्दोलन को वैज्ञानिक आधार देना चाहते थे।”⁹

हेरोल्ड लास्की (Herold Laski) का मत है कि मार्क्स ने समाजवाद को एक कार्यक्रम एवं एक दर्शन दिया जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित था। इसके पहले ऐसा कोई विकल्प नहीं था।¹⁰ प्रसिद्ध इतिहासकार टेलर (A J P Taylor) का मत है कि मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या है वह उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है। इसके अलावा इन परिवर्तन करने वाली शक्तियों का विवेचन मानव मनोविज्ञान (Human Psychology) पर आधारित है।¹¹

मार्क्स के ग्रन्थों में ऐतिहासिक अन्तर्दृष्टि का परिचय तो प्राप्त होता ही है, उसने जो कुछ भी लिखा है तथा जो वह सिद्ध करना चाहता था वह तथ्यों पर आधारित है। उसके विचारों में कल्पना की छत्राग नहीं है। उसके ग्रन्थ तथ्य सम्बन्धी ज्ञान के अपूर्व भण्डार हैं। उसने उस समय प्रचलित ऐतिहासिक लेखन प्रवृत्ति का ही अनुसरण किया है। मार्क्स जब अपने सिद्धान्तों की विवेचना करता है तो वह आदम युग से प्रारम्भ करता है तथा यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य दिन दिन युगों से निराल चुका है। मनुष्य जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है इसका कारण समाज की अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन होना है। यह ऐतिहासिक विवेचन भी वैज्ञानिक पद्धति या एक प्रमुख संग्रह है। मार्क्सवाद के कई सिद्धान्त इसी ऐतिहासिक विवेचन के परिणाम हैं। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, पूँजीवादी से सम्बन्धित अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त मार्क्स के प्रमुख अन्वेषण हैं। ऐन्गल्स के शब्दों में —

“इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या तथा अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त द्वारा पूँजीवादी उत्पादन का रहस्योद्घाटन करना, इन दो महान अन्वेषणों के लिए हम मार्क्स के ऋणी हैं। इन दो खोजों से समाजवाद विज्ञान बन गया। इनके बाद तो गिफें इनके सम्बन्ध और विस्तार का ही कार्य रह गया।”¹²

9. “Marx's ideas were influenced by the scientific atmosphere of his time, by his own leanings towards science and by his revolutionary aspiration to give to the working class movement a more or less scientific basis.”
Milovan Djilas, *The New Class*, p. 5.

10. Laski, H J, *Marxism after Fifty Years*, *Current History*, March, 1933.

11. Taylor, A J P, *Manifesto of the Communist Party*, Introduction by A. J. P. Taylor, Penguin Book Co, Middlesex, 1970, pp. 10-11.

12. “These two great discoveries, the materialistic conception of history and the revelation of the secret of capitalist production through surplus value, we owe to Marx. With these discoveries socialism became a science. The next thing was to work out all its details and relations.”
Engels, F., *Socialism: Utopian and Scientific*, p. 44

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है माक्सं के पूर्व समाजवादियों ने कोई ऐसा वैज्ञानिक सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जिसके आधार पर एक निश्चित तर्क-संगत मापूहिक कार्यक्रम पड़ा किया जा सकता। माक्सं ने अपने ग्रन्थों, पुस्तकों, लेखा आदि में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति के सम्बन्ध में जो भी विचार प्रकट किए हैं वे मुख्यतः परस्पर अनुपपत्तया विरोध रहित थे। दूसरे, माक्सं ने अर्थशास्त्र में सम्बन्धित आर्थिक नियतवाद (Economic Determinism), मूल्य के निर्धारण में धर्म का महत्व समाज का विकास आदि का अध्ययन, क्रमबद्धता या क्रमिक विकास (logical development) पर आधारित उसकी विवेचना में कारण और परिणाम (causes and effects) प्रत्येक जगह विद्यमान है।¹³ माक्सं अपने निष्कर्षों को निश्चित समझना था, उदाहरणार्थ—

- (i) सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारण होने हैं।
- (ii) पूँजीवादी व्यवस्था परिपक्वता को प्राप्त करती ही पतन की ओर अग्रसर होती है।
- (iii) पूँजीवादी व्यवस्था में पूँजीपतियों और श्रमिकों का संघर्ष अनिवार्य है।
- (iv) केवल श्रमिक वर्ग ही जातिकारी होता है क्योंकि उनके पास अपने धर्म को छोड़कर कुछ नहीं है और न ही उसे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में मोह है।
- (v) पूँजीवादी व्यवस्था के बाद समाजवाद का आना आवश्यक-भावी है, तथा
- (vi) धर्म मूल्य का निर्धारक तात्व है।

उसके प्रतिष्ठित बहु-द्वैतात्मक भौतिकवाद को 'अकाद्य विज्ञान' मानता था। उसके अनुसार इतिहास के जो नियम उसने ढूँढ निकाले थे वे वैज्ञानिक सिद्धान्त की तरह निश्चित और निर्भंग थे। माक्संवाद को वैज्ञानिकता प्रदान करने वाले सभी सत्त्वों के मार का हरमन जड (Heromon Judd) ने इस प्रकार उल्लेख किया है—

‘माक्सं का दावा था कि उसका समाजवाद यूटोपियायी या ईसाई समाजवाद नहीं किन्तु वैज्ञानिक था। उसे विश्वास था कि किसी भी कार्यक्रम को स्याई रूप से सफलता के लिये वैज्ञानिक सत्य सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिये। उसका अनुसार सहयोग सिद्धान्त तथा पूँजी वर्ग से उदार स्वभाव की अपील करना ध्येय था। क्योंकि किन्हीं कारणों से वे उस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लायेंगे जिससे उन्हें लाभ होता है। माक्सं का विश्वास था कि उस समय की दशा के कारणों को जानने के लिए दूरगामी सुधार करने पड़ेंगे तथा उन शक्तियों का खोजना पड़ेगा जो इतिहास को गतिशील बनाती हैं। इसे केवल वैज्ञानिक श्रवण द्वारा

ही समझता सम्भव हो सकता है कि क्या गुडर बुरा है तथा भविष्य में क्या होगा। कोई अन्य पद्धति उसे चाहे कैसे भी अच्छे विचारों द्वारा प्रपनाया जाय, व्यर्थ है।¹⁴

मार्क्स पर प्रभाव तथा उनका वैज्ञानिक विवेचन

कार्ल मार्क्स के विचारों में मौलिकता (originality) के अभाव की बात सभी विद्वान कहते हैं। यह सत्य प्रथम है। समाज विकास का सिद्धान्त, पूँजीवाद के विकास और सामाजिक परिणाम, अतिरिक्त-मूल्य का सिद्धान्त (theory of surplus value), धर्म सिद्धान्त, सर्वहारा-वर्ग (proletariat) के प्रति हित कामना, प्रतिको के लिए सगठित रूप से राजनीतिक कार्य एवं आन्दोलन करने के लिए आह्वान आदि की पूर्व-ध्वनि मार्क्स के पहले ही गूँज रही थी।

हीगलवाद (Hegalism) उस समय का विचार फंशन (जैसा कि राजकमल भारत में समाजवाद है) था। हीगल से कार्ल मार्क्स ने ग्रहण किया कि विकास सिद्धान्त विरोधी तत्वों के संघर्ष में निहित रहता है। फ्यूरबाख (Feurbach) से मार्क्स ने भौतिकवादी (materialism) विचार प्राप्त किये। सम्भवतः वर्ग संघर्ष (class war) की प्रेरणा उसे फ्रंस के समाजवादियों से मिली हो क्योंकि कुछ समय जब मार्क्स फ्रंस में था वहाँ के समाजवादियों के सम्पर्क में रहा।¹⁵ उसके अर्थशास्त्र सम्बन्धी विचार अष्टादशवीं शताब्दी के मरकेन्टाइलिस्ट अर्थशास्त्रियों, विशेषतः रिकार्डो (David Ricardo), फिजियोक्रैट विद्वानों (Physiocrats) तथा अन्य लेखकों के ग्रन्थों में मिलते हैं।¹⁶

यह निःसंदेह सत्य है कि मार्क्सवाद को विभिन्न तत्व कई स्रोतों से ढूँढे जा सकते हैं। उसने ईट-पत्थरों की भाँति सब स्थलों से विचारों को एकत्रित किया। निम्न जिस विचार-भवन का निर्माण किया वह स्वयं उसकी ही इच्छानुसार था।¹⁷

14. "Marx claimed that his was a scientific rather than a utopian or Christian socialism. He was convinced that any programme which was to be permanently successful would have to be based upon scientifically valid principles. It was, he thought, totally useless to preach the doctrine of co-operation and to appeal to the benevolent nature of a capitalist class which, for reasons..... was unable consciously to alter the system from which it benefited. Reformers, Marx believed, would need to delve more deeply into the causes of the existing situation to investigate the forces that move history itself. Only through such a scientific investigation is possible to understand what has happened, what is happening, and what will happen. Any other approach, no matter how altruistically motivated, is useless." Judd Herman M., Political Thought from Plato to the Present, McGraw Hill, New York, 1964, p. 392.

15. Gray, Alexander., The Socialist Tradition, p. 300

16. मोरर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ० 44-47.

17. उपरोक्त पृ० 299.

माक्स ने इन सभी विद्वानों के विचारों के तथ्यों की व्यवस्था, उनकी विवेचना आदि स्वयं ही की थी। मार्क्स ने अपने मत की पुष्टि के लिए इन चिन्तकों एवं विद्वानों के विचारों का मार ग्रहण किया तथा अपने विचारों को तांत्रिक दृष्टि से सिद्ध करने के लिए उनका प्रयोग किया। उदाहरणार्थ, हीगल के दर्शन में विचार (idea) और राष्ट्र (nation) की प्रमुखता थी। माक्स के अनुसार हीगल का दर्शन ठीक तिर के बराबर उल्टा खड़ा हुआ था। मार्क्स ने इस नया रूप देकर पैरा पर उल्टा किया।¹⁸ हीगल के विचार और राष्ट्र के तथ्यों को मार्क्स ने बर्ग-सम्प के रूप में प्रस्तुत किया,¹⁹ तथा इस नियम को एक राष्ट्र तक ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में लागू होने वाला बनवाया।²⁰

माक्स का यही विवेचन समाजवाद और शान्ति का प्रमुख आधार है जो उसके विचारों को वैज्ञानिकता प्रदान करता है। प्रो लास्की (Harold Laski) के अनुसार उस समय समाजवाद एक अस्त-व्यस्त स्थिति में था किन्तु मार्क्स ने उसे एक आन्दोलन बना दिया। यही नहीं उसे तक सगत बनाने के एक नया दर्शन और एक नई दिशा प्रदान की। कई विद्वान मात्रम के विचारों में महत्त्व नहीं है कि तु वे भी उसके अध्ययन विश्लेषण और मूढता को स्वीकार करते हैं।

मार्क्सवाद की वैज्ञानिक सदिशता

उपरोक्त अध्ययन से यह लगभग स्पष्ट है कि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। क्योंकि मार्क्सवाद विचार तथ्यों पर आधारित है, इसमें ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया गया है, यह विवेचनात्मक अध्ययन है तथा इसे तर्कसंगत बनाकर 'कारण और परिणाम' के सब-ध को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। मार्क्सवाद के अन्तर्गत नये सिद्धान्त तथा नये निष्कर्षों को स्थापित किया गया है। इतना सब कुछ होने भी मार्क्सवाद के पूर्णरूप से वैज्ञानिक होने में संदेह व्यक्त किया जाता है। टेलर (A J P Taylor) ने मार्क्सवाद को सही वैज्ञानिक अध्ययन नहीं माना है।²¹ मिलोवन जिलास (Milovan Djilas), जो यूगोस्लेविया (Yugoslavia) के एक विद्रोही साम्यवादी चिन्तक हैं, का मत है कि मार्क्सवाद का विज्ञान के रूप में कभी भी महत्त्व नहीं रहा है। मार्क्स ने हीगल के विज्ञान को ही आगे बढ़ाया। इसमें उसका भूल योगदान कुछ भी नहीं था।²² कोल (G D H Cole) का विचार है कि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद कम तथा सिद्धान्त शास्त्र या अध्यात्म-शास्त्र (Metaphysics) अधिक है। यह उसके

18 Engels, F., Socialism Utopian and Scientific, p 37

19 Sabine, H S, A History of Political Theory, p 628

20 Kutzer and Ross, Western Social Thought, p 261

21 Taylor, A J, P, The Manifesto of the Communist Party, pp 10-11

22 Djilas, Milovan, The New Class, p 6

प्रतिरिक्त-मूल्य सिद्धान्त (Theory of Surplus Value) से स्पष्ट हो जाता है।²³

मार्क्सवाद का वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में सबसे बड़ी वृद्धि यह थी कि मार्क्स का अध्ययन निष्पक्ष नहीं था। उसने जो भी तथ्य एकत्रित किये, उनका जो विवेचन किया, उसका मुख्य उद्देश्य क्रान्ति द्वारा सर्वहारा-वर्ग की सत्ता की स्थापना करना था। इसके समर्थन में उसे जो तथ्य मिले उनका उसने प्रयोग किया तथा जो तथ्य उसके निष्कर्ष के विपरीत जाते थे उनकी अवहेलना की। इस प्रकार एक पक्षीय अध्ययन को पूर्ण विज्ञान कहना उपयुक्त नहीं होगा। आगे के पृष्ठों में मार्क्सवादी सिद्धान्तों के अध्ययन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है।

कार्ल मार्क्स तथा ऐन्जिल्स वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख प्रवक्ता हैं, किन्तु कुछ ऐसे भी समाजवादों हैं जो मार्क्स-ऐन्जिल्स के विचारों के कुछ तत्वों को स्वीकार करते हैं तथा कुछ को अस्वीकार। किन्तु उन्हें भी वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक माना जाता है। इनमें कार्ल रॉडबर्टस (Karl Rodbertus, 1805-1875) तथा फर्डिनेण्ड लासाल (Ferdinand Lassale, 1825-1864) के नाम प्रमुख हैं। मार्क्स ऐन्जिल्स तथा इनमें मतभेद इस बात पर है कि समाजवाद लाने के लिये तुरन्त क्या कार्यक्रम हो तथा राज्य के विषय में वास्तव में क्या दृष्टिकोण होना चाहिये। वैज्ञानिक समाजवाद के विषय में इन्होंने मार्क्स-ऐन्जिल्स की मान्यताओं का लगभग समर्थन दिया है हालांकि उनके कारण एक परिणाम कुछ भिन्न ही है।²⁴

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद

Dialectical Materialism

कार्ल मार्क्स की विचारधारा का आधारभूत सिद्धान्त द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है। द्वन्द्व का अर्थ तर्कसम्मत विचार-विमर्श है। किसी भी तथ्य की वास्तविकता को ज्ञान की प्राप्ति तर्क-सम्मत विचार-विमर्श से ही सम्भव होती है। सामाजिक विद्या-त्रम का ज्ञान करने के लिये सर्वप्रथम द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त की हीगल ने प्रवृत्ति किया था। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि ऐतिहासिक घटना-त्रम कुछ निश्चित नियमों के अनुसार चलता है। इन्हीं नियमों के आधार पर सामाजिक परिवर्तनों को समझा जा सकता है।

हीगल ने समाज की गतिमय तथा परिवर्तनशील चतलाते हुए विश्व-आत्मा (World Spirit) को उसका नियामक कारण माना है। हीगल ने द्वन्द्वात्मकता

23. Cole, G D H, A History of Socialist Thought, Vol II, pp 288-89.

Jay, Douglas, Socialism in the New Society, pp 57-58.

इस सम्बन्ध में देखिये—

Mayo, Henry B, Introduction to Marxist Theory, pp. 211-18.

24. Gray, Alexander, The Socialist Tradition, pp. 332, 334, 343-44

के अन्तर्गत होन वाले वीद्विक क्रम का 'अस्तित्व में होना' (being), 'अस्तित्व में न होना' (non being) और 'अस्तित्व में आना' (becoming) के रूप में देखा। हीगल ने इन तीनों क्रमों को 'वाद' (thesis), 'प्रतिवाद' (anti-thesis) और 'सम्वाद' (synthesis) से सम्बोधित किया है। कोई भी 'अमूर्त' (abstract) 'विचार' (idea) में प्रारम्भ होता है। विचार में विरोध' (contradiction) उत्पन्न होता है जिसे प्रतिवाद कहा जाता है। वाद और प्रतिवाद में द्वन्द्व के परिणामस्वरूप एक नया विचार का प्रादुर्भाव होता है जिसे हीगल सम्वाद कहता है। यही सम्वाद आगे चलकर वाद फिर प्रतिवाद और सम्वाद के द्वारा पुनः नया विचार के रूप में उत्पन्न होता है। यह क्रम-चक्र निरन्तर चलता रहता है।

हीगल परिवार को वाद के रूप में, समाज को परिवार के प्रतिवाद के रूप में, तथा राज्य को सम्वाद के रूप में एक विचार मानता था। इस प्रकार हीगल का द्वन्द्ववाद आदर्शात्मक था। हीगल के द्वन्द्ववाद के सार को कोल (G D H. Cole) ने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है—

"हीगल ने विश्व को दैविक न्याय की एक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जो निरन्तर विरोध और सघर्ष की प्रक्रिया द्वारा अपने को प्रसारित करता है। सम्पूर्ण मानव इतिहास—और केवल उसी से हमारा यहाँ सम्बन्ध है—उसके समक्ष विचारात्मक सघर्ष की एक लम्बी प्रक्रिया के रूप में फैल गया जिसका निश्चित परिणाम विश्व-भावना की पूर्ण सहानुभूति में विरोध का अन्तिम रूप से विनाश होगा। भौतिक स्तर पर समाज का विकास उसके लिये इस विचारात्मक प्रक्रिया की एक निपेधात्मक अभिव्यक्ति मात्र थी। मानव इतिहास में जो घटित हो रहा है वह यह नहीं है जिसकी प्राप्ति होती है बल्कि हर निरपेक्ष विचार में निहित वास्तविकता का क्रमिक तथा प्रगतिशील यथार्थीकरण है। प्रत्येक वस्तु विकास की सम्पूर्ण लौकिक प्रक्रिया में वीज रूप में विश्राम थी परन्तु वीज यथार्थ का रूप विचार के लम्बे सघर्ष द्वारा ही धारण कर सक्ता था। यह सघर्ष, जैसा कि इतिहास में दिखाई पड़ता है अपूर्ण विचारों के सघर्ष में होकर स्वानुभूति की ओर अग्रसर होता है।"²⁵

हीगल के द्वन्दात्मक सिद्धान्त को मार्क्स ने सामाजिक विकास के सम्बन्ध में लागू किया। किन्तु मार्क्स भौतिकवादी था। भौतिकवादी सिद्धान्त का तात्पर्य है कि विश्व में परम तत्व पदार्थ (matter) है जिसके मूल में कोई ईश्वरीय अथवा सार्वभौम अचेतना नहीं होती। पदार्थ ही प्रथम व प्रधान है। मार्क्स के द्वन्द्ववाद का आधार पदार्थ है, हीगल की भाँति विचार (idea) नहीं, भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है। मार्क्स के भौतिक द्वन्दात्मक सिद्धान्त को

निम्नलिखित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है—

(i) साव्यविक एकता:—विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएँ तथा घटनाएँ एक दूसरे से पृथक् न होकर पूर्णतया सम्बद्ध रहती हैं। अर्थात् प्रकृति के सभी पदार्थों में साव्यविक एकता रहती है।

(ii) गतिशीलता:—विश्व अथवा उसकी कोई भी वस्तु स्थिर अथवा अपरिवर्तनशील नहीं है। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ - रेत के छोटे दाने से लेकर सूर्य पिण्ड तक - गतिशील है।

(iii) परिवर्तनशीलता:—भौतिकवादी होने के कारण माक्स आर्थिक नियतिवाद (economic determinism) का समर्थक है। वह सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियों के रूप में आर्थिक परिस्थितियों को ही महत्त्व देता है। चूँकि भौतिक जगत में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है इसलिये सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन होता रहना है। द्वन्द्ववाद विवास और परिवर्तन की प्रक्रिया है।

(iv) भावात्मक-गुणात्मक परिवर्तन —परिवर्तन भावात्मक (quantitative) तथा गुणात्मक (qualitative) दोनों प्रकार के होते हैं। गेहूँ के एक अंकुर का कई दानों में परिणत हो जाना भावात्मक परिवर्तन है। पानी का हिम या भाप में परिवर्तन गुणात्मक कहलाता है।

परिवर्तन-क्रम में एक अवस्था ऐसी आती है जब परिमाणगत से गुणात्मक परिवर्तन एकाएक हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब पानी सामान्य गर्म होता है उसमें कोई परिवर्तन मासूम नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसका तापमान 100° सेन्टीग्रेड पर पहुँचता है वह उबलने लगता है तथा एकाएक उसके गुण में परिवर्तन हो भाप बनने लगता है। पानी का भाप में परिवर्तन ही गुणात्मक परिवर्तन है। इसी प्रकार सामाजिक विकास क्रम पहिले धीरे-धीरे चलता है लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें एक दम गुणगत परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन में आर्थिक तत्त्व प्रधान है न कि होगल की तरह विचार तत्त्व।

(v) अंतिकारी प्रक्रिया:—वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे-धीरे नहीं बल्कि सहसा धीरे भटके के द्वारा होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने की यह प्रक्रिया अन्तिकारी होती है।

(vi) सकारात्मक-नकारात्मक संघर्ष:—प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होने हैं—सकारात्मक (positive) और नकारात्मक (negative)। इनमें निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। संघर्ष के परिणामस्वरूप पुराना तत्त्व मिट जाता है तथा नवीन तत्त्व उत्पन्न होता है। यह निरन्तर संघर्ष विनाश-क्रम निर्धारण करता है।

माक्स के इन विचार को कोल (G. D. H. Cole) ने व्यक्त करते हुए निर्या है कि इतिहास के प्रत्येक युग में उत्पन्न शक्तियों से मनुष्यों में आर्थिक सम्बन्ध पैदा

होत हैं। मानव इतिहास न इन सम्बन्धा के फलस्वरूप मनुष्य आर्थिक वर्गों में विभाजित रहे हैं। प्राचीन ग्रीस में स्वतन्त्र नागरिक व दास, रोम में पेट्रीशियन व प्लेबियन, मध्य युग में भूमिपति और दास-विज्ञान, तथा वर्तमान युग में पूँजीपति व मजदूर-वर्ग के मध्य हुए संघर्ष से समाज आगे बढ़ता है।

द्वन्द्वमक भौतिकवाद सिद्धान्त से माक्स ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी समाज की स्थापना कैसे होगी। माक्स ने अपने द्वन्द्ववाद में जिस तीव्र शक्ति से परिवर्तन की ओर सचेत किया उससे उसने क्रान्ति के औचित्य को सिद्ध किया है। पूँजीवाद में शोषित वर्ग उन्नति नहीं किन्तु क्रान्ति द्वारा परिवर्तन करेगा। इस प्रकार माक्स द्वन्द्ववादी व्याख्या द्वारा वर्ग संघर्ष को अवश्यम्भावी बना देता है। माक्स के द्वन्द्ववादी भौतिकवाद का वाद, प्रति-वाद और सम्वाद आर्थिक वर्ग है। इनमें संघर्ष के परिणामस्वरूप एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें शोषण एक वर्ग-भेद सदैव के लिए समाप्त हो जायेगा। वर्गरहित समाज की स्थापना अन्तिम सम्वाद होगा जिसके बाद प्रतिवाद का जन्म नहीं होगा। यही पर दाग-संघर्ष की द्वन्द्वमक प्रक्रिया रुक जायेगी।

हीगल तथा माक्स के द्वन्द्वमक सिद्धान्त में अन्तर

हीगल तथा माक्स ने द्वन्द्ववाद सिद्धान्त की सामाजिक विकास के संदर्भ में व्याख्या की है किन्तु दोनों विचारकों के निष्कर्ष भिन्न-भिन्न हैं। प्रथम, हीगल के द्वन्द्ववाद का आधार विचार (idea) है। इसके विपरीत माक्स पदार्थ (matter) को प्रमुखता देता है। हीगल का द्वन्द्ववाद रहस्यात्मक-आदर्शात्मक है, माक्स भौतिकवादी है। द्वितीय, हीगल का विचार था कि यूरोपीय इतिहास की चरम परिणति जर्मन राष्ट्र के विकास में हुई है तथा जर्मनी यूरोप का आध्यात्मिक नेतृत्व ग्रहण करेगा। कार्ल माक्स ने सामाजिक इतिहास की चरम परिणति सर्वहारा वर्ग के उत्थान के रूप में स्वीकार की है। तृतीय, हीगल के समाज दर्शन में प्रेरक शक्ति एकस्व-विकासशील आध्यात्मिक सिद्धान्त है। माक्स के दर्शन में यह प्रेरक तत्त्व स्व-विकासशील उत्पादक शक्तियाँ हैं जो अपने लिए सामाजिक वर्गों में व्यक्त करती हैं। चतुर्थ हीगल के लिए प्रगति राष्ट्रों के संघर्ष में निहित है। किन्तु माक्स के लिए प्रगति सामाजिक वर्गों के विरोधाभास में निहित थी।²⁶

अनुसार हीगलवादियों ने हीगल के दर्शन का प्रतिन्यायावादी ढंग से प्रयोग किया। किन्तु इसी सिद्धान्त को माक्स ने क्रान्ति का उपकरण बना दिया। 'शोचियत मध्य के साम्यवादों दल के सक्षिप्त इतिहास' में इस सम्बन्ध में लिखा है कि द्वन्द्ववाद की सहायता से साम्यवादी दल प्रत्येक स्थिति के प्रति नहीं दृष्टिकोण बना सकता है सामाजिक घटनाओं के आन्तरिक सम्बन्धों को समझ सकता है

तथा उनकी दिशा को जान सकता है। वह न केवल यह जान सकता है कि वर्तमान में घटनाएँ किस दिशा में चल रही हैं, किन्तु यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में उनकी दिशा क्या होगी।²⁷

मूल्यांकन—द्वन्द्ववादी भौतनवाद मार्क्सवाद का मूल आधार है किन्तु इस विचार को मार्क्स ने पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया है। जगह जगह पर मार्क्स ने द्वन्द्ववादी भौतनवाद की विवेचना की है, वे अपनी रचनाओं में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण दर्शाने हैं, गभीर स्थानों पर इसे लागू करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन विस्तृत रूप में वे इसका कहीं भी विवेचन नहीं करते।

कार्ल मार्क्स सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को समझने के लिये एक मात्र भौतिक तत्त्व को प्रधानता देता है। वह पदार्थ को चेतना की अपेक्षा प्रमुखता देता है। यह समझ में आना असम्भव है कि किसी चेतन-सत्ता के बिना यह विश्व उत्पन्न और संचालित कैसे हो सकता है। यह मानना सही नहीं है कि सामाजिक जीवन में चेतना का योगदान नहीं है तथा भौतिक तत्त्वों द्वारा ही समस्त सामाजिक गति-विधियों का नियमन होता है। भौतिक तत्त्व को एकमात्र निर्णायक तत्त्व मानना भूल है।

यद्यपि द्वन्द्ववादी हमें मानव विकास के इतिहास में मूल्यवान् क्रान्तियों का दिग्दर्शन कराता है किन्तु मार्क्स का यह दावा स्विकार नहीं किया जा सकता कि सत्य का अनुसंधान करने के लिये यही एकमात्र वैज्ञानिक पद्धति है। सामाजिक घटनाओं को द्वन्द्व की सहायता के बिना भी भली भाँति समझा जा सकता है।

द्वन्द्ववाद के अध्ययन से यह बात समझ में आना बड़िन है कि पदार्थ जो स्वभाव में चेतनाहीन है, एक स्वयं विकसित होने वाला सिद्धान्त बन सकता है। इसमें धातुरिक शक्तियों को यथायथ करने की शक्ति नहीं होती और न उसमें विराम की सामर्थ्य होती है। जो भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने है वे बाह्य शक्ति द्वारा लिये जाते हैं। सामाजिक जीवन इतना जटिल होता है कि उसमें होने वाले परिवर्तनों में से वाद, प्रतिवाद तथा सशय किसे कहा जाय यह बताना अत्यन्त ही दुष्कर कार्य है। कैर्यू हन्ट (Carew Hunt) ने द्वन्द्ववादी भौतनवाद की भावोचना निम्नलिखित शब्दों में की है—

“मार्क्सवादो द्वन्द्ववाद के विरुद्ध एक गम्भीर आपत्ति उठाया जा सकता है। द्वन्द्ववाद को विरोधी तत्त्वों के बीच संघर्ष के द्वारा विचारों के विनाश पर लागू करना उचित है, और हीगल उस विषय की एक बुद्धि सग्य व्याख्या देता है। यद्यपि द्वन्द्ववादी भौतनवाद के भौतिक जगत में कुछ विरोधों के दृष्टान्त केवल एउदम मनमाने हैं परन्तु यदि वे ऐसे न भी होते तो फिर भी यह तो एक गृह्य ही बना रहता है कि भौतिक जगत में

²⁷ Hunt, Carew, (quoted) Theory and Practice of Communism, p. 28.

वे डिग्राई क्या पड़ने चाहिये। इन्द्रवादी भौतिकवाद वास्तव में यह कहना है कि पदार्थ पदार्थ है किन्तु इमना विकास विचारों की भांति होता है जब कि हम यह तो देख सकते हैं कि विचार उस प्रकार विकसित क्यों होते हैं जिस प्रकार कि वे होते हैं, जैसा कि, उदाहरण के लिये, धातु-विवाद में, हम किसी ऐसे कारण की कल्पना नहीं कर सकते कि भौतिक धनुष्या को भी उसी ढंग से विकसित क्या जाना चाहिये।²⁸

इतिहास को भौतिकवादी व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद Materialistic Interpretation of History

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को सम्भन्न से पहिले कुछ सम्बन्धित बातों का उल्लेख आवश्यक है। प्रथम, मार्क्स तथा एन्गिल्स के इस सिद्धान्त का नाम ही भ्रममूलक है। जिसे वे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं वास्तव में वह भौतिकवाद न होकर आर्थिक व्याख्या है। इस सिद्धान्त को भौतिकवाद नहीं कहा जा सकता क्योंकि 'भौतिक' शब्द का अर्थ 'चेतनाहीन पदार्थ' में होता है। उन्होंने सार्वजनिक परिवर्तना की बात करते हुए कहा है कि यह परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है। अतः इस सिद्धान्त का नाम 'इतिहास की आर्थिक व्याख्या' होना चाहिए था।²⁹ कात्र (G D H Cole) ने भी इस सम्बन्ध में लिखते हुए कहा है कि इस सिद्धान्त में मार्क्स ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया था इसलिए इसका नाम 'इतिहास का व्यवहारवादी सिद्धान्त' (Realist Conception of History) होना चाहिए था।³⁰ द्वितीय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या मार्क्सवाद का एक प्रमुख तथा मूल सिद्धान्त है लेकिन उनके किसी भी ग्रन्थ में कहीं भी इस सिद्धान्त का पूर्ण तथा व्यवस्थित वर्णन नहीं मिलता। यह उनके ग्रन्थों, लेखों में इधर उधर दिखाया हुआ है। तृतीय, इस सिद्धान्त के विषय में मार्क्स की अपेक्षा एन्गिल्स का योगदान अधिक एवं महत्वपूर्ण है। मार्क्स की पुस्तक—*Critique of Political Economy*—की प्रस्तावना में इस सिद्धान्त की जो व्याख्या की गई है, इसके बाद एन्गिल्स ने ही इसकी समय समय पर विवेचना की है।

सिद्धान्त की व्याख्या

इन्द्रवादी भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स ने मानव इतिहास की विवेचना की है। तदनुसार इन्द्रात्मक भौतिकवाद के सिद्धान्त केवल प्राकृतिज जगत में ही लागू नहीं होत, मानव समाज का विकास भी इन्हीं नियमों के अनुसार होता है। ऐतिहासिक

28 Hunt, Carew, Theory and Practice of Communism, p 33

29 Lancaster, Lane W., Masters of Political Thought, Vol III, Hegel to Dewey, 1959, p 167

30 Gray, A., The Socialist Tradition, p 301

भौतिकवाद का अर्थ द्रष्टव्यवादी भौतिकवाद के सिद्धान्तों को समाज के विकास के लिए लागू करना है।

मानव समाज निरंतर बदलता रहता है। जो समाज आज से एक हजार या एक सौ वर्ष पहले था वैसे आज नहीं है। उससे कई ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिन्होंने समाज को बाधा पकट दी है। लेकिन प्रमुख प्रश्न यह है कि इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं।

सामाजिक परिवर्तन के विषय में मार्क्स और ऐन्जिल्स की दो प्रमुख धारणाएँ हैं। प्रथम प्रकृति के नियम की तरह सामाजिक विकास के नियम भी निश्चित हैं। सामाजिक परिवर्तन न तो आकस्मिक होते हैं और न ही कुछ मनुष्यों की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ये विकास नियम वस्तुगत हैं तथा उनका स्वतन्त्र अस्तित्व है। द्वितीय, सामाजिक विकास में भौतिक परिस्थितियाँ ही प्रधान हैं; मन, विचार, भावनाएँ आदि गौण हैं। समाज को जिस प्रकार की भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं के अनुरूप सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन, धर्म, नैतिकता मूल्य और मान्यताएँ होती हैं। अन्य शब्दों में, भौतिक परिस्थितियाँ ही सामाजिक जीवन का आधार हैं। उनमें परिवर्तन होने का तात्पर्य सम्पूर्ण सामाजिक जीवन में परिवर्तन होता है। बोपाके ने इस सिद्धान्त को इस प्रकार व्यक्त किया है—

“मूल्य में इस दृष्टिकोण का यह तात्पर्य है कि सम्भवा का मूल ढाँचा, उदाहरण के लिए परिवार का स्वरूप, समाज में वर्ग विकास और उनके सम्बन्धों का निर्धारण मानव अस्तित्व की आवश्यकताओं, जलवायु और भोजन दशादि जिनके अन्तर्गत इन आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है, से होता है। केवल आर्थिक तथ्य ही वास्तविक या आकस्मिक हैं, अन्य वस्तुएँ तो इनका बाहरी रूप या प्रभावमात्र हैं।” 31

भौतिक परिस्थितियों से क्या अभिप्राय है? मार्क्स और ऐन्जिल्स के अनुसार 'उत्पादन के उपादान' ही भौतिक परिस्थितियाँ हैं। वे यह मानकर चलते हैं कि शक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन, वस्त्र, ईंधन, मरान आदि प्राप्त करने पड़ते हैं इनके बिना जीवन सम्भव नहीं हो सकता। इन सब की उपलब्धि उत्पादन के द्वारा होती है। अतः समस्त मानवीय क्रिया-कलापों की आधारशिला

31. In sum, the point of view amounts to this—that the fundamental structure of civilisation, the type of the family, for example, and the order of relations and development of classes in society, have been and must be determined by the primary necessities of human existence and the conditions of climate and nutrition under which these necessities are met. Economic facts alone, it is suggested, are real and causal; every thing else is an appearance and an effect."Bosanguet, B; The Philosophical Theory of State, Macmillan & Co Ltd London, 1953, p. 25

उत्पादन प्रणाली है। वस्तुओं का उत्पादन प्राकृतिक साधन, मशीन, यंत्र, उत्पादन बना, मनुष्य के मानसिक और नैतिक गुणों पर आधारित होता है। इस प्रकार उत्पादन के साधन और उत्पादन के तरीके 'उत्पादन के उत्पादन' के अन्तर्गत आते हैं। इन समस्त परिवर्तनशील उत्पादन शक्तियों का सामाजिक सम्बन्धों पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक युग की सम्बन्धिता संस्कृति, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था दशक कानून और मनुष्य का समाज के विभिन्न वर्गों में स्थान का निर्धारण उत्पादन और वितरण की प्रणाली के द्वारा होता है। आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन के सम्बन्धों में परिवर्तन आते ही उन्हीं के अनुरूप सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन आते हैं।

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित शब्दों में की है—
 "सामाजिक सम्बन्ध उत्पादन शक्तियों से अनिच्छित सम्बंधित हैं नवीन उत्पादन शक्तियों को प्राप्त करने के लिये मनुष्य अपने उत्पादन तरीकों में परिवर्तन करते हैं, और अपने उत्पादन तरीकों में तथा जीवन उपायों के ढंग में परिवर्तन करने से वह अपने समस्त सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन करते हैं। हस्तचालित मशीन से सामंतवाद तथा चालित मशीनों से औद्योगिक पूँजीवादी समाज की स्थापना हुई।"
 (The Poverty of Philosophy, p 12)

फ्रेडरिक ऐन्जल्स ने प्रथम रूप से इस सिद्धांत की व्याख्या की है। ऐन्जल्स के शब्दों में—

"इतिहास का भौतिकवादी विचार इस सिद्धांत से प्रारम्भ होता है कि उत्पादन तथा उत्पादन के साथ वस्तुओं के विनिमय, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का आधार है प्रत्येक समाज जिसका इतिहास में अभ्युदय हुआ है वस्तुओं के वितरण तथा इसके साथ समाज का वर्ग-विभाजन का निर्धारण इस बात से होता है कि क्या और किस प्रकार उत्पादन तथा वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। इस विचार के अनुसार सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक शक्तियों के अस्तित्व कारणों से, मनुष्यों के मस्तिष्क सत्य और न्याय आदि में नहीं बल्कि उत्पादन और विनिमय के तरीकों में देखा जा सकता है, वे दर्शन (Philosophy) में नहीं बल्कि उस युग से सम्बंधित प्रवृत्तियों में दृष्टिगोचर होना है।"³²

ऐन्जल्स ने सामान्यतः इस प्रकार के ही विचार अन्वय व्यक्त किए हैं। इस विषय में लेनिन के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। लेनिन ने लिखा है—

‘यह व्यक्त करने के लिये कि बिना किसी अंधाधुंध समस्त विचार और सभी प्रवृत्तियों की जड़ उत्पादन की भौतिक शक्ति सम्बन्धी दृष्टांत हैं, सामंतवाद

³² Anti Dühring, p 294, quoted by Gray, A., The Socialist Tradition, p 104

ने सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के उत्पादन, वितरण और वित्तन प्रक्रिया के सर्व-समावेश तथा व्यापक अध्ययन के मार्ग को दर्शाया है।³³

किसी भी समाज को भौतिक परिस्थितियाँ एक सी नहीं रहती, उनमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। मनुष्य द्वारा उत्पादन के नये-नये तरीके अपनाये जाते हैं तथा नये नये औजारों का आविष्कार होता है। उत्पादन के भौतिक तत्व बदल जाते हैं और उनका स्थान नये तत्व से लेते हैं किन्तु उत्पादन के सम्बन्ध पुराने ही स्थिर रहते हैं। पुराने उत्पादन के सम्बन्धों के मध्य उत्पादन के नये भौतिक तत्वों का विकास एवं समुचित समन्वय नहीं हो पाता। अन्य शब्दों में, पुराने उत्पादन तत्व नये तत्वों के विकास में बाधा डालने लगते हैं। अतः दोनों के बीच संघर्ष प्रारम्भ होता है। इस बात की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है कि पुराने उत्पादन साधनों का अन्त करके नये सम्बन्ध स्थापित किये जायें जो उत्पादन के नये तत्वों के अनुरूप हों और उनके विकास को सुगम बना सकें। मार्क्स-एन्गल्स के अनुसार यही सामाजिक क्रान्तियों का आधार है तथा इन्हीं कारणों से समाज एक युग से दूसरे युग में पदार्पण करता है।

सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएँ

उत्पादन प्रणाली के परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संगठन, वर्ग विभाजन तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन होता है। परिणामस्वरूप एक अवस्था से दूसरी अवस्था आती है। मार्क्स ने उत्पादन सम्बन्धी परिवर्तनों के आधार पर इतिहास में युग परिवर्तनों का उल्लेख किया है, प्रत्येक युग के उद्भव एवं पतन को इन्द्रजित्वा भौतिकवाद के आधार पर समझाया है।

आदिम साम्यवादी युग (Age of Primitive Communism)—यह मानव जाति का प्रारम्भिक युग था। इस युग में मनुष्य शिकार और फल-फूल प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित थीं। न परिवार संस्था थी और न ही व्यक्तिगत सम्पत्ति संचय करने का प्रश्न था। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु पर समान अधिकार था। यह युग सब प्रकार के शोषण से मुक्त था। मार्क्स इसे आदिम साम्यवादी व्यवस्था कहता है।

दासता का युग (Age of Slavery)—कृषि का आविष्कार होने पर प्रथम अवस्था में परिवर्तन आने लगा। इस युग में शेरों और वन्यपालन का शिकार प्रारम्भ हुआ। कृषि तथा वन्यपालन प्रथा से उत्पादन प्रणाली में नया परिवर्तन आया। अधिक उत्पादन और माल का संचय किया जाने लगा। अधिक कृषि उत्पादन के निम्न गृहस्थों को भी आवश्यकता महसूस हुई। युद्ध में पराजित लोगों को इस कार्य में निर्ये लगाया गया। इस प्रकार दास प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। व्यक्तिगत

³³ Lenin, The Teaching of Karl Marx, p. 11.

सम्पत्ति विकसित हुई। भूमि के स्वामित्व तथा स्थायी निवास की आवश्यकता प्रतीत हुई। दास का काम उत्पादन करना और स्वामी का काम उसके श्रम से उत्पादन हो गई वस्तुओं से आनन्द उठाना था। मालिक वर्ग दासों के श्रम के उपभोक्ता बन गये। यही से स्वामी और दासों के दो वर्गों की सृष्टि हुई।

सामन्तवादी युग (Age of Feudalism) -कालान्तर में उत्पादन के उपादानों में अधिक प्रगति एवं परिवर्तन हुए। लोहे के हल तथा करघे का प्रचलन हुआ। वृत्ति के क्षेत्र में वृद्धि हुई। भूमि उत्पादन का मुख्य साधन बन गई। समाज का मुखिया भूमि का मालिक बन गया। वह भूमि का विभाजन सामन्तों के मध्य करता था। ये सामन्त धीरे-धीरे भूमि के मालिक बनने लग और राजा को कर के रूप में सैनिक सेवा या अन्य सेवाएँ प्रदान करने लगे। ये सामन्त कृषि खण्ड वृषकों तथा वृषक अर्ध-दासों को भूमि दिया करते थे। यही सामन्तवादी संगठन था। वृत्ति उत्पादन का अधिकांश भाग सामन्तों को प्राप्त होता था। अर्ध-दास वर्ग, जो वास्तव में भूमि पर कार्य करता था का शोषण किया जाने लगा। यही सामन्तों की व्यवस्था थी। इस युग में किसान दास की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र था और निजी सम्पत्ति रख सकता था। किन्तु इस युग में सामन्तों ने अपने आधिकारों का भयंकर शोषण किया। इस व्यवस्था में सामन्त और शोषितों के बीच संघर्ष चलता रहा।

पूँजीवादी युग (Age of Capitalist Society) -ग्रैटारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औद्योगिक क्रांति हुई जिसने उत्पादन के उपादानों में आमूल परिवर्तन किया। मशीनों का आविष्कार हुआ तथा बड़ी बड़ी मिलों और कारखानों की स्थापना हुई। खेती के तरीकों में भी परिवर्तन हुआ। इस युग में कारखानों के स्वामी तथा श्रमिकों के मध्य नये सम्बन्ध स्थापित हुए। पूँजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी होता था किन्तु श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होना थे, उन्हें पूँजीपतियों को अपनी श्रम शक्ति बेचना पड़ती थी। फलस्वरूप श्रमिकों और पूँजीपतियों के मध्य वर्ग संघर्ष भी तीव्र हुआ। पूँजीवादी युग के अन्तर्गत राजनीतिक संस्थाएँ कानून, नैतिकता, कला, साहित्य, दर्शन आदि सब पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों के ही अनुरूप व्यवस्थित हुए। पूँजीपतियों का शासन व्यवस्था पर भी धीरे-धीरे नियन्त्रण बढ़ने लगा। माक्स-एन्गल्स के अनुसार यहीं से आधुनिक ढंग से पूँजीपति तथा श्रमिकों में संघर्ष प्रारम्भ होता है। यही संघर्ष पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त कर समाजवाद तथा आगे चलकर साम्यवाद के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

सूत्रावली

माक्सवाद की ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या एकपक्षीय, छद्मपूर्ण तथा प्रतिशयोक्तियों से परिपूर्ण है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या के साथ साथ और भी अन्य व्याख्याएँ हैं। नीतिशास्त्र सम्बन्धी, राजनीतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक आदि सभी ऐतिहासिक व्याख्याएँ हैं। भौतिकवादी व्याख्या महत्त्वपूर्ण होने हुए भी सब

बुद्ध नहीं है। न इन्ने समाज की सम्पूर्ण व्याख्या कहा जा सकता है। विभिन्न युगों में आर्थिक उत्पादन और वितरण प्रणाली से सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धित रहे हैं। केन्नु समस्त इतिहास को आर्थिक तत्त्वों की पृष्ठभूमि के आधार पर नहीं समझा जा सकता। कार्ल मार्क्स के इन कथन में प्रतिशयोक्ति है कि परिवर्तन केवल आर्थिक तत्त्वों के कारण ही होते हैं।

इतिहास में इस प्रकार के कई उदाहरण हैं कि राजप्रासादों में होने वाले पड़वन्त्र, अतिशयत दूषण, धार्मिक विरोध आदि ने भी इतिहास के क्रम में बड़े बड़े परिवर्तन लिये हैं। मध्ययुगीन यूरोप का इतिहास वास्तव में धर्म संघर्ष का इतिहास रहा है। भारत में मुस्लिम काल में कई बादशाहों ने जजिया कर लगाया। इसका कारण आर्थिक कम किन्तु धार्मिक बट्टरता तथा धार्मिक विरोध अधिक था। भारत विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण आर्थिक कारणों से नहीं, धार्मिक आधार पर हुआ था।

विश्व समाज में कुछ ऐसे महान व्यक्ति भी हुए हैं जैसे बुद्ध, ईसा, मुहम्मद आदि जिन्होंने सामाजिक जीवन, सामाजिक मूल्यों एवं धारणाओं में मूलभूत परिवर्तन किए। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। वह केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही प्रेरित नहीं होता। गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने, इनके विपरीत, भौतिक सुख को त्याग आध्यात्मिक मार्ग को अपना कर धार्मिक प्रान्तियों को जन्म दिया। इन सब परिवर्तनों को व्याख्या भौतिकवाद के आधार पर नहीं की जा सकती है।

मानसंवाद मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्यों की उपेक्षा करता है। मनुष्य केवल सम्पत्ति प्राप्ति की भावना से ही नहीं किन्तु अहंकार, प्रतिस्पर्धा, लोभ, अमानन्द, नारी आदि की भावना से भी ग्रस्त करते हैं। फ्राइड ने काम वासना को ही मनुष्य जीवन में सब से अधिक प्रेरक-तत्त्व माना है।

हेलोवेल (W. H. Hallowsell) के अनुसार महान वैज्ञानिक आविष्कारकों में भी शायद ही कोई आर्थिक कारणों से प्रेरित हुआ हो। "जितनी भी सौन्दर्य सृष्टि-वृत्तियाँ हैं, वह अर्थशास्त्र से उतनी ही दूर हैं जितना अर्थशास्त्र से विज्ञान दूर है।" 34

कार्ल मार्क्स ने आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर समाज को जिन अवस्थाओं में विभाजित किया है उसकी ऐतिहासिकता सदिग्ध है। प्रादिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था आदि के मान के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मानवशास्त्र (Anthropology) प्रादिम साम्यवाद के विवरण का समर्थन नहीं करता। मार्क्स यह भी कहता है कि समाज इन तमाम अवस्थाओं से निकल कर समाजवादी एवं साम्यवादी अवस्थाओं में प्रवेश करेगा। समाज विज्ञान का यह विश्लेषण यूरोपीय समाज के गन्दम में नहीं हो सकता है। अफ्रीका में अभी भी कई ऐसी जातीय सम्भत्ताएँ

34 उद्धृत, मार्शीवाडन्., राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ. 613.

है जा जन-तन्त्रीय युग के बाहर ही नहीं निकल पाई है। जो भी अफ्रीका राष्ट्र बन तक इस अवस्था में है व पूँजीवादी अवस्था को लाभ वर समाजवादी या प्रग अवस्था को और प्रथम हान का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार समाज विनाश प्रक्रिया एव प्रग भी अत्यन्त हाना जा रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवादी अन्तिम अवस्था है। इस अवस्था पर आकर विनाश प्रग रूख जायेगा। यह विचार व्यक्त कर मार्क्स स्वयं ही द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद पर आनन्द कर रहा है। द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के अनुसार विकास प्रग अवस्था नहीं होता विकास प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

इस सम्बन्ध में मार्क्सवाद में और भी अन्तर्विरोध दिखाई देता है। एक ओर तो मार्क्स एव एन्जिंग निपतिवादी हैं और उनका अनुसार जो कुछ भी होता है वह भौतिक परिस्थितियों के कारण होता है। वे मनुष्य का परिस्थितियों का दाम बनने देते हैं। दूसरी ओर वे मानव प्रयत्न को महत्त्व देते हैं। उनके शब्द "अपने तन दामनिक न विषय का विभिन्न प्रकार में निर्वचन किया है, वास्तविक कार्य उसको बदलना है"— कार्यशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार मार्क्सवाद दो विरोधी धारणाओं में उलझा प्रतीत होता है।

यह कहना भी सत्य नहीं है कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन में आन्तरिक परिस्थितियों का ही प्रभाव पड़ता है। बाह्य परिस्थितियाँ भी आन्तरिक परिवर्तनों को प्रभावित करती हैं। भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनमें कुछ बाहरी आक्रमणों का परिणाम है। मुसलमानों तथा अंग्रेजों के भारत में आने में देश में कई प्रकार के समन्वय दृष्टिगोचर होते हैं।

मार्क्स का कहना था कि जिनके पास आर्थिक शक्ति होती है वे ही राजनीतिक सत्ता का उपयोग करते हैं, उन्हीं का राज्य सत्ता पर नियन्त्रण रहता है। यह विचार सही नहीं है। वर्तमान युग में सैनिक आन्तियों द्वारा परिवर्तन भी हुए हैं तथा सैनिक शक्ति के आधार पर राज्य सत्ता पर नियन्त्रण किया गया है। इस प्रकार मार्क्सवाद का यह सिद्धान्त आन्तियों में पूर्ण किन्तु आंशिक सत्य है।

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त

Theory of Surplus Value

कार्टे मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का विवरण अपनी पुस्तक 'दाम केपिटल' (Das Capital) में किया है। मार्क्स ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि, प्रथम, मूल्य निर्धारण का आधार क्या है। द्वितीय, इसके द्वारा वह यह भी बताना चाहता था कि पूँजीवादी व्यवस्था में श्रमिक का शोषण किस प्रकार किया जाता है। उपरोक्त तथा कुछ अन्य आर्थिक कारणों से कार्टे मार्क्स के आर्थिक विचारों में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त का महत्वपूर्ण स्थान है।

मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त मूल्य सिद्धान्त (Theory of Value) पर आधारित है। इसविषये 'अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त' समझने के लिए मूल्य में सम्बन्धित कुछ महत्-सिद्धान्तों को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम, मार्क्स उपयोग-मूल्य (Value in Use) तथा विनिमय-मूल्य (Value in Exchange) के अन्तर को स्पष्ट करता है। उपयोग-मूल्य किसी वस्तु की उपयोगिता है जो मानव आवश्यकता को संतुष्टि करती है। विनिमय-मूल्य वस्तुओं का अन्य वस्तुओं में विनिमय का अनुपात है। यह विनिमय का अनुपात वस्तुओं की भिन्न-भिन्न उपयोगिता पर निर्भर करता है। किन्तु विनिमय-मूल्य, उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता। उपयोगिता द्वारा मूल्य का निर्धारण नहीं होता। शक्ति द्वारा दी गई पैठ की लकड़ी की उपयोगिता तथा उपयोग-मूल्य तो है, विनिमय-मूल्य नहीं। किन्तु पैठ पर थम का प्रयोग होने से उसका विनिमय-मूल्य प्रारंभ हो जाता है। किन्ती भी वस्तु के विनिमय मूल्य के लिए थम का प्रयोग आवश्यक है। वस्तुओं का विनिमय इसविषये होता है क्योंकि सभी वस्तुओं में थम लगा है।

किसी वस्तु के उत्पादन में कितना थम कितने समय तक लगाया गया, इस माध्यम पर ही मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त का विकास करता है। थम-समय में मार्क्स का अभिप्राय उम प्रवृत्ति में है जो समाज की परिस्थितियों में प्रौद्योगिक वस्तु उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु उत्पादन में थम-समय की गणना या प्रतिक्रिया में ही वस्तु का कम या अधिक मूल्य होता है।

अतिरिक्त मूल्य-सिद्धान्त की व्याख्या निम्नलिखित कई ढंग में की जा सकती है:—

(i) थमिक के पास स्वयं के उत्पादन साधन नहीं होते। वह अपने थम और मंदाओं को बेचना है। इस प्रकार थम अन्य वस्तुओं की ही तरह खरीदार और बेचा जाता है। थम का क्या मूल्य है? कार्ल मार्क्स थम का उपयोग-मूल्य (Use-Value) और विनिमय-मूल्य (Exchange-Value) में अन्तर बतलाना है। उपयोग-मूल्य का तात्पर्य थम द्वारा निर्मित वस्तु का मूल्य है। थम का विनिमय-मूल्य थमिक का उनका भोजन, कपड़ा, रहने की जगह है जो कि उनके जीवन अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पर्याप्त हो। मार्क्स ने इसे मजदूरी का कठोर नियम (Iron Law of Wages) कहा है। मार्क्स के अनुसार पूँजीपति थमिक को किसे उनका विनिमय-मूल्य ही देना है और स्वयं उपयोग-मूल्य लेता है। थम का विनिमय-मूल्य और उपयोग-मूल्य का अन्तर ही अतिरिक्त-मूल्य (Surplus Value) है।³⁵

(ii) अन्य शब्दों में, थमिक को अपने मामूली जीवन निर्वाह के लिए पौड़ी वस्तु जो कुछ भी मजदूरी दी जाती है जब वह उसमें अधिक उत्पादन करता है, वही अतिरिक्त मूल्य है। उदाहरणार्थ, एक मजदूर एक दिन 10 घंटे कार्य करता है लेकिन जिनसे मजदूरी उसे दी जाती है उनका कार्य

35 Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political Thought, pp 418-21.

वह 4 घण्टो म ही कर लेता है। घेप छ दण्टे के काय का मूल्य उसे नही मिलता। यह पूँजीपति ले लेता है। यही अतिरिक्त मूल्य है।

(iii) या, एक मजदूर दिन भर म अपनी श्रम शक्ति के विनिमय-मूल्य से कही अधिक मूल्य उत्पादन करता है। इन दोनों का ही अन्तर अतिरिक्त मूल्य है।

(iv) इसी सिद्धान्त को एक अन्य प्रकार से और प्रस्तुत किया जा सकता है। श्रमिक का अपने श्रम और कला का समुचित मूल्य नहीं मिलता। उसे सिर्फ जीवित रहने के लिए थोड़ी सी मजदूरी ही मिलती है। इस श्रम का बहुत बड़ा भाग ब्याज, किराया और लाभ के रूप में पूँजीपति का मिलता है। वास्तव में ये तीनों तत्व— ब्याज किराया और लाभ ही अतिरिक्त मूल्य है।³⁶

डा० आशीर्वादम् द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार जिनका मूल्य श्रमिकों के निर्वाह के लिए आवश्यक है उससे अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वह अतिरिक्त मूल्य है। पूँजीपति श्रमिकों को कबल निर्वाह के लिए मजदूरी देकर उनसे इतना श्रम कराता है कि उनके द्वारा उपन्न वस्तुओं का बाजार मूल्य उनकी मजदूरी से अधिक होता है। इस अतिरिक्त मूल्य को पूँजीपति हड़प लेते हैं। संक्षेप में पूँजीपति नाम किराया ब्याज के रूप में अतिरिक्त मूल्य का स्वयं लेते हैं और उसका उपयोग उत्पादन बढ़ाने, अधिक श्रमिकों को काम पर लगाकर निरन्तर अधिक से अधिक अतिरिक्त मूल्य की प्राप्ति करने में करते हैं।³⁷

मानस के अनुसार पूँजी के द्वारा कोई भी वस्तु निर्मित नहीं की जा सकती। पूँजी स्वयं ही श्रम के द्वारा निर्मित होती है। इसलिए पूँजीपति का अतिरिक्त मूल्य पर कोई अधिकार नहीं होता। पूँजीपतियों द्वारा अतिरिक्त मूल्य को हड़प जाना एक प्रकार की चोरी और श्रमिकों का शोषण है।

अतिरिक्त मूल्य पूँजी या मशीन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह निर्र श्रम को लगाकर ही सम्भव होता है। अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए पूँजीपति कई उपाय काम में लेते हैं जैसे—प्रथम, श्रमिकों के कार्य अवधि में वृद्धि कर, भोजन समय में कमी करना। उम प्रकार एक दिन की मजदूरी देकर उससे अधिक कार्य लेता। द्वितीय, मशीन का प्रयोग करना। मशीन से प्रयोग से श्रमिक अधिक कार्य कर सकता है। इसका तात्पर्य अधिक उत्पादन और अधिक अतिरिक्त मूल्य। तृतीय, श्रमिक परिवार की ओरतो और बच्चों को भी काम पर लगाने तथा उन परिवार के लिए जीवनयापन योग्य मजदूरी देकर अतिरिक्त मूल्य के अनुभव में वृद्धि की जाती है। वास्तव में पूँजीपति अतिरिक्त मूल्य श्रमिक के

36 Burns, P M, *Ideas in Conflict*, Methuen & Co, London, 1963, p 151

37 आशीर्वादम् राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 610

शोषण द्वारा ही प्राप्त करता है।³⁸ जब पूँजीपति अधिक में अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करते हैं उगमे उनकी पूँजी में वृद्धि होती है। यात्रिक साधनों के प्रयोग से श्रम में बचन तथा श्रमिकों की बेकारी में बढ़ती होती है। परिणामस्वरूप श्रमिकों और पूँजीपतियों में संघर्ष प्रारम्भ होता है।

मूल्यारकन

अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त में पूर्ण सत्यता नहीं है। मार्क्स ने केवल श्रम को ही मूल निर्धारक तत्त्व माना है। पूँजीपतियों के लाभ का स्रोत केवल मजदूरों का श्रम ही नहीं है। वह पूँजी लगाना है, जोखिम उठाता है तथा अपनी व्यावसायिक बुद्धि एवं कौशल का प्रयोग करता है। मूल्य निर्धारण में तथा इससे मिलने वाले लाभ में इन सभी का हिस्सा होना है।

मूल्य का निर्धारण एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त के द्वारा होता है जिसे 'माँग एवं पूर्ति का सिद्धान्त, (Theory of Demand and Supply) कहते हैं। यह सिद्धान्त इतना गवंध्यायी है कि मजदूर इससे प्रभावित रहे बिना नहीं रह सकते।

इसमें सन्देह नहीं कि मानव ने अतिरिक्त मूल्य सिद्धान्त की एक बड़ी ही तार्किक एवं संज्ञानिक दृष्टि में व्याख्या की है। वास्तव में यह अतिरिक्त श्रम का सिद्धान्त, न्यूनतम वेतन का सिद्धान्त, शोषण का सिद्धान्त आदि सब कुछ है। किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री अतिरिक्त मूल्य-सिद्धान्त को आंशिक रूप में ही सत्य मानते हैं।

वर्ग-संघर्ष सिद्धान्त Theory of Class War

मार्क्सवादी विचारधारा का एक और प्रमुख आधार वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त है। वर्ग-संघर्ष सिद्धान्त द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या तथा अन्य आर्थिक सिद्धान्तों का विस्तार एवं परिणाम है। बम्बुनिस्ट मेनीपेस्टो के प्रथम अध्याय में वर्ग-संघर्ष के कारण, विकसन आदि की व्याख्या की गयी है। इस सिद्धान्त के द्वारा मार्क्स-एंगेल्स ने यह दर्शाया है कि सम्पूर्ण मानव जाति का इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। इतिहास में युग-परिवर्तन रूप से विशाल-क्रम में श्रमिक तंत्रों की प्रधानता के साथ साथ मार्क्स ने प्रत्येक युग में ही परस्पर विरोधी सामाजिक वर्गों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। विश्व इतिहास राष्ट्रों के युद्ध, व्यक्तियों, गैनापतियों या राजाओं के कारनामों का तथा जोश नहीं है। मार्क्स वर्ग-संघर्ष से मानव इतिहास को समझने की कुंजी मानता है। इतिहास के प्रमुख मोड़ तथा परिवर्तन आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति के विरोधी वर्गों में संघर्ष की शृंगारता है। बम्बुनिस्ट मेनीपेस्टो में इस सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख किया गया है:—

³⁸ Gray, A. The Socialist Tradition, p. 331.

प्रायः तक के सम्पूर्ण समाज का इतिहास वर्ग सघर्ष का इतिहास है ।

स्वतंत्र व्यक्ति और दास, कुलीन और जनसाधारण, सामन्त और जूति शान, सघर्षपति और श्रमिक, मूकम म, जोपक और जोपित मदा एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर कभी प्रत्यक्ष ब कभी परोक्ष रूप से लगातार युद्ध करने रहे हैं । 39

उत्पुक्त जन्मा म मार्क्स ए एन्जल्स वर्ग-सघर्ष के विचारों की व्याख्या प्रारम्भ करते हैं । उनके अनुसार प्रत्येक काल और देश में समाज दो प्रमुख विरोधी वर्गों में विभक्त हो जाता है । एक तो विशेषाधिकार प्राप्त और उत्पादन के साधनों के स्वामि का छोटा सा वर्ग और दूसरी और एक बड़ा सर्वहास वर्ग । दास युग में स्वतंत्र व्यक्ति एक दास गानत शान म कुलीन तथा जन-साधारण, मध्य युग में सामन्त तथा ग्रह-दास औद्योगिक युग में सघर्षपति और श्रमिक तथा पूँजीवादी युग में पूँजीपति और श्रमिक वर्ग आदि का अस्तित्व एक सघर्ष रहा है । यह सघर्ष प्रायः प्रत्यक्ष रूप में चलता ही रहा है । परिणामस्वरूप या तो समाज का क्रान्तिकारी पुन निर्माण हुआ है अथवा सघर्षरत वर्गों का विनाश ।

वर्ग-सघर्ष के सन्दर्भ में मार्क्स-एन्जल्स का मुख्य उद्देश्य पूँजीवादी व्यवस्था तथा इसके अन्तर्गत पूँजीवर्ग और श्रमिक वर्ग के सघर्ष का व्यापक विश्लेषण करना है । पूँजीवर्ग के विषय में उनका कहना है कि इनके पास पूँजी, कारखाने, उद्योग आदि नष्ट होने हैं । पूँजीवर्ग के पास समाज की सम्पूर्ण पूँजी एकत्रित रहती है । इनका ही उत्पादन के साधनों आदि पर नियन्त्रण रहता है । यह अपने को पूँजी, धन, लाभ आदि का स्वामी समझता है और अपने उच्छ्रानुसार इनका प्रयोग एक समर्थक करता है ।

दूसरी और श्रमिक वर्ग होता है जो उत्पादन के साधनों में वंचित है और एकमात्र अपने श्रम का स्वामी है । वह वस्तुओं का उत्पादन अपने लिये नहीं बल्कि अपने मातृका के लिये करता है, जिन्हें बेचकर वह लाभ समझता है । श्रमिक अपने श्रम का बेच कर आजीविका कमाता है, वह भूमिपति की भूमि पर काम करता है या पूँजीपति के कारखाने में वस्तु-निर्माण में सहायता देता है । जीवनयापन के लिये उनके पास अपना श्रम-यूनतम मूल्य पर पूँजीपति के हाथ बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता ।

पूँजीवादी व्यवस्था में दोनों वर्ग एक दूसरे के पूरक एक आवश्यक हैं । यदि श्रमिक न हों तो काम कौन करे और यदि पूँजीपति न हों तो काम एक मजदूरी कौन दे । किन्तु दोनों वर्गों को एक दूसरे की चाहे कितनी ही आवश्यकता क्यों न हो उनके हित परस्पर विरोधी हैं । क्योंकि एक वर्ग का लाभ दूसरे वर्ग को हानि पहुँचा कर ही हो

सकना है। पूंजीपति मजदूर को कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम लेकर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके विपरीत श्रमिक अपने श्रम का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना चाहता है। इस संघर्ष में श्रमिक ही तुकगान में रहता है क्योंकि श्रम नाशवान होता है, श्रम को संग्रह करके नहीं रखा जा सकता, इसलिये या तो उसके श्रम का खरोददार मिलना चाहिये अन्यथा उदर-पोषण की समस्या प्रतिदिन सामने बनी रहनी है। लेकिन पूंजीपति के सामने इस प्रकार की कठिनाई नहीं होती। वह पूंजी लगाने के लिये प्रतीक्षा कर सकता है। चूंकि पूंजी नाशवान नहीं होती इसलिये वह श्रमिकों को अपने सामने झुकने के लिये विवश कर सकता है। पूंजीपतियों के हाथों से श्रमिकों का दमन एवं शोषण होता है। इस प्रकार एक वर्ग शोषक और दूसरा शोषित हो जाता है।

कालं मार्क्स को यह धारणा थी कि पूंजीवर्ग और सर्वहारावर्ग में वर्ग-संघर्ष अनिवार्य है तथा अन्त में पूंजीवर्ग का विनाश और सर्वहारावर्ग की विजय निश्चित है। मार्क्स पूंजीवर्ग का विनाश और वर्ग-संघर्ष के दो पक्षों पर प्रकाश डालता है। प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था इस प्रकार का है कि दमन स्वयं ही इसके पतन एवं विघटन के तत्त्व निहित है। इसकी आन्तरिक दुर्बलता तथा कार्यप्रणाली स्वयं के विनाश की ओर अप्रसर करेगी। द्वितीय, पूंजीवादी प्रणाली जिन प्रकार वर्ग-संघर्ष की ओर अप्रसर करती है तथा सर्वहारावर्ग जिन प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेरता है।

पूंजीवादी अर्थतन्त्र के स्वयं-विघटन की व्याख्या करते हुए मार्क्स इसके विनाश कारणों पर प्रकाश डालता है जैसे—

- (i) पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से होता है।
- (ii) पूंजीवादी व्यवस्था स्वर्द्धा पर आधारित है परिणामस्वरूप छोटे-छोटे पूंजीपतियों का उन्मूलन हो जाता है। ये छोटे-छोटे पूंजीपति बड़े-बड़े पूंजीपतियों के विरोधी और सर्वहारा वर्ग के समर्थक हो जाते हैं।
- (iii) यह बड़े-बड़े पूंजीपतियों के एकाधिकार को स्थापित करता है।
- (iv) पूंजीपति अपनी पूंजी का देश विदेश में प्रसार कर अधिकाधिक लाभ और पूंजी-संचय का निरन्तर प्रयत्न करते हैं।
- (v) पूंजीवादी अर्थतन्त्र में समय-समय पर आर्थिक सङ्कट उत्पन्न होते हैं। मशीनों के प्रयोग तथा अति-उत्पादन संकट से श्रमिकों में बेकारी तथा असन्तोष फैलता है।
- (vi) पूंजीपति अधिक अतिरिक्त मूल्य का गृहण कर श्रमिकों का शोषण करता है। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है।

जब भी श्रमिकों को अपने शोषण या ज्ञान हो जाता है वे इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इस शोषण प्रणिया के परिणामस्वरूप श्रमिकों में वर्ग-चेतना

का प्रादुर्भाव होता है। वे अपने अधिकारों और भागों के प्रति जागरूक होने हैं। जैसे हा उनमें यह चेतना प्रायेणी बैसे ही मजदूर संगठन रूप से अपनी भागों पूरी करने को प्रवृत्त होंगे।

चूँकि पूँजीगत अधिक लाभ कमाने के लिए देश-विदेशों में अपने उद्योग, कारखाने खोलते हैं, पूँजीवादी व्यवस्था एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बन जाती है। इससे व्यापक रूप से श्रमिका का शोषण होता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग-चेतना और संगठन को प्रोत्साहन मिलता है। श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है और शोषण के परिणामस्वरूप वे अधिक संगठित होते हैं। बौकर के शब्दों में—

“पूँजीवादी प्रणाली मजदूरों की संस्था बढ़ाती है, उन्हें यह सुसंगठित समुदायों में एकत्र कर देती है, उनमें वर्ग-चेतना का प्रादुर्भाव करती है, उनमें परस्पर सम्पर्क तथा सहयोग स्थापित करने से लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी श्रम-शक्ति को कम करती है, और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती है।”⁴⁰

श्रमिकवर्ग की चेतना और संगठन को पूँजीवात दवाने का प्रयत्न करेंगे, इससे वर्ग-चेतना अन्दोलन का रूप लेगी। श्रमिकों को संगठित होने व क्रांति का साह्वान करते हुए कम्युनिस्ट भेनोफेस्टो के अन्तिम वाक्यों में माक्स एव एन्जिल्स ने लिखा है—

‘साम्यवादी अपने विचारों व लक्ष्यों को छुपाने से घृणा करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि उनके उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब कि वर्तमान सामाजिक दशाओं को शक्तिपूर्वक समाप्त किया जाये। शासक वर्गों को साम्यवादी श्रान्ति के समक्ष बापने दो। सर्वहारा वर्ग को अपनी जमीनों के अलावा और कुछ नहीं खोना है। उन्हें विश्व पर विजय पाना है। समस्त देशों के मजदूरों एक हो।’⁴¹

सूच्यकन

माक्स-एन्जिल्स प्रत्येक समाज को दो वर्गों पूँजीवर्ग तथा सर्वहारावर्ग-में विभाजित करते हैं। उनके ये विचार सही नहीं हैं। प्रथम, वर्ग-भेद उतना स्पष्ट नहीं होना जितना कि माक्स आदि ने माना है। प्रत्येक समाज में कई वर्ग होते हैं जिनका वर्गीकरण करना भी दुष्कर रहता है। वर्गों के निर्माण और पुन निर्माण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। दूसरे, यह भी सही नहीं है कि सिर्फ आर्थिक आधार पर पूँजीवर्ग और सर्वहारावर्ग ही हो। आजकल धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक बुद्धिजीवी, कृषि आदि कई वर्ग होते हैं।

⁴⁰ नाकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 55

⁴¹ Marx and Engels, Manifesto of the Communist Party, p 69

धर्म-संपर्क केवल आर्थिक वर्गों तक ही सीमित नहीं रहता है। धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर कई संपर्क हुए हैं। नास्ती और यदूदियों का मूलतः नस्ल सम्बन्धी संपर्क था। अमेरिका में नोबो व्यक्तिओं के साथ भेदभाव का कारण मुख्यतः आर्थिक नहीं है। भारत की यह धारणा कि मनुष्य के सारे संपर्कों का स्रोत धर्म-संपर्क है, अतन्त्र है।

धर्म-संपर्क के अक्सर अर्थ काम होते जा रहे हैं। आजकल अनेक समाजवादी देश वैज्ञानिक कदम उठा कर श्रमिक वर्ग की अवस्था को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा सफल भी हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों को आघात व्यवस्था, पेन्शन व्यवस्था, जिज्ञा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ जुटाने से श्रमिकों का शोषण तो दूर रहा उनके मन में धर्म संपर्क की भावना ही घर नहीं कर पाती।

आधुनिक युग में एक सर्वोच्च शक्तिशाली धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। यह है मध्यम धर्म। इसी धर्म में प्रबन्धक, कुशल वारीगर, सफ़ाकार, बकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि सम्मिलित हैं। मध्यम वर्ग किसी भी राज्य में बहुमत में रहता है। इसकी मनोवृत्ति भी सामान्यतः मध्यमार्गीय रहती है जो पूँजीवादी और सर्वहारावादी प्रतिवादिना का समन्वय करने का प्रयत्न करती है। इस वर्ग ने दो धर्म सिद्धान्त को ही मान्य कर दिया है तथा पूँजीय और श्रमिक वर्ग में संपर्क के अन्तर्गत भी लगभग समाप्त कर दिये हैं।

धर्म-संपर्क के लिये बाल मानस विश्व के श्रमिकों को एक होने का आह्वान करता है ताकि समूचे विश्व से पूँजीवाद को उखाड़ पेंवा जाय। इस सम्बन्ध में भारत राष्ट्रीय भावना के महत्त्व को घटा ही काम आता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों गहित कई युद्ध पूँजीवर्ग ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़े हैं लेकिन फिर भी विश्व के श्रमिक वर्ग ने एक एवं समन्वित होकर काम नहीं किया। यही नहीं मजदूरों ने अपनी-अपनी सरकारों को पूर्ण सहयोग दिया। प्रत्येक देश का व्यक्ति सामान्यतः मातृभूमि और राष्ट्रीय भावना से अधिक प्रभावित होता है न कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिकवाद से। आजकल साम्यवादी राज्यों में भी जितनी राष्ट्रीयता की प्रबल भावना है उतना अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद सहयोग नहीं। चीन, यूगोस्लाविया, उत्तरी वियतनाम के साम्यवादी अपने राष्ट्रवाद को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के लिये न्योछावर नहीं कर सकते। यही नहीं, इस समय साम्यवादी राज्यों में ही संपर्क चल रहा है। चीन तथा रूस का संपर्क इस बात का प्रमाण है। ये विचारधारा को नहीं, राष्ट्रीय हितों को ही प्राथमिकता देने हैं।

दोनों विरोध तरकातीन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में पूँजीवादी राज्य, जैसे अमेरिका तथा उच्च साम्यवादी राज्य, जैसे चीन एक दूसरे के प्रति सहयोग के लिये हाथ बड़ा रहे हैं। इन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूँजी-

वादी और साम्यवादी राज्यों का वर्ग-सघर्ष न तो कुछ मजबूत ही रखता है और साथ ही साथ असम्भव भी होना जा रहा है।

वर्ग-सघर्ष एक खतरनाक और हानिकारक सिद्धान्त है। यह वर्ग घृणा की शिक्षा देता है। किसी भी देश के अन्दर यह राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा के लिये स्याई खतर के रूप में अस्तित्व ग्रहण कर लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सहयोग, भाई-चारे के मार्ग में वर्ग-सघर्ष एक बाधा है।

सर्वहारा अधिनायकत्व (Dictatorship of the proletariat)

माक्स तथा ऐन्जल्स के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था को नान्ति द्वारा नष्ट करने के तुरन्त बाद ही राज्य-विहीन, वर्ग-विहीन, शोषण-रहित साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होना असम्भव है। इसके उद्देश्य की उपलब्धि में कुछ समय लग जायेगा। इसलिए पूँजीवाद की समाप्ति के बाद एक नई व्यवस्था की स्थापना होगी जिसे 'सर्वहारा अधिनायकत्व' कहा गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत समाज तथा राज्य की समस्त शक्ति श्रमिकों के हाथों में आ जायेगी। सर्वहारा वर्ग राज्य के समस्त उपकरणों, अभिकरणों तथा उत्पादन के साधनों आदि को अपने नियंत्रण में करेगा।

सर्वहारा अधिनायकत्व स्याई नहीं किन्तु एक सक्रमणकालीन (transitional) व्यवस्था होगी। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व तब तक बना रहेगा जब तक पूँजीवादी व्यवस्था के समस्त अवशेषों को समाप्त नहीं कर दिया जाता तथा साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का कार्यन्तम पूरा नहीं हो जाता। यह व्यवस्था अन्तिम साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए अग्रगामी होगी।

सर्वहारा अधिनायकत्व में राज्य संस्था का अस्तित्व बना रहेगा। श्रमिक वर्ग द्वारा राज्य के माध्यम से पूँजीवर्ग के अवशेषों का पूर्ण उन्मूलन किया जायेगा ताकि पूँजीवादी व्यवस्था का भविष्य में किसी भी रूप में प्रादुर्भाव न हो सके।

सक्रमणकालीन सर्वहारा अधिनायकत्व के अन्तर्गत केवल समाजवाद की (साम्यवाद की नहीं) स्थापना होगी जिसके अन्तर्गत—

प्रथम, उत्पादन तथा वितरण आदि के साधन सम्पूर्ण समाज की सम्पत्ति होंगे। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के हित में नहीं किन्तु सम्पूर्ण समाज के लिए किया जायेगा।

द्वितीय, उत्पादन नियोजित (planned) ढंग से होगा जिसके अन्तर्गत उत्पादन के साधन तथा मानव श्रम का योजनाबद्ध प्रयोग किया जायेगा।

तृतीय, आर्थिक जीवन प्रतियोगिता की समाप्ति तथा इसमें उत्पन्न अव्यय का उन्मूलन किया जायेगा।

चतुर्थ, इस व्यवस्था में पूर्ण समानता या वस्तुओं का समान वितरण नहीं होगा। समाजवादी समाज 'प्रत्येक से उसनी योग्यतानुसार काम और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार वेतन', सिद्धान्त पर आधारित होगा। कम्युनिस्ट मनीफेस्टो में दस कार्यक्रम की कुछ विस्तृत रूपरेखा दी गई है।

साम्यवादी व्यवस्था (The Communist Order)

सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व और समाजवादी व्यवस्था सिर्फ संक्रान्ति काल के लिए ही रहेगी। यह पूंजीवादी ढांचे के विनाश और अन्तिम साम्यवादी व्यवस्था के बीच का युग रहेगा। सर्वहारा समाजवाद के अन्तर्गत उत्पादन शक्तियों का विकास, भौतिक परिस्थितियों तथा वातावरण में परिवर्तन के साथ-साथ समाज, राज्य, परिवार, सम्पत्ति, धर्म आदि के विषय में मनुष्य के दृष्टिकोण एवं चरित्र में परिवर्तन होगा। इसके बाद मनुष्य एक नई सामाजिक अवस्था में प्रवेश करेगा। मार्क्स के अनुसार यह साम्यवादी व्यवस्था होगी। साम्यवाद ही मनुष्यों का अन्तिम उद्देश्य और समाज के विकास की अन्तिम अवस्था होगी। मार्क्स और ऐंग्लिस के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी—

(i) राज्य का लोप (Withering away of the State)—साम्यवाद के अन्तर्गत राज्य लुप्त हो जायेगा। राज्य द्वारा पूंजीवर्ग तथा भू-स्वामी वर्ग अन्य वर्गों या शोषण करते हैं। राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर दबाव डालने तथा शोषण करने का साधन रहा है। यह उच्च वर्ग की सम्पत्ति और विशेषाधिकारों की रक्षा करता रहा है। राज्य वर्ग-समर्थन की उत्पत्ति एक अभिव्यक्ति है। किन्तु साम्यवाद में वर्ग-भेद तथा शोषण का अन्त हो जायेगा, इसलिए इस स्थिति में राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। राज्य का उन्मूलन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी यह स्वयं ही मर जायेगा।

(ii) यह वर्ग-विहीन व्यवस्था होगी। समाज में सभी वर्गों की समाप्ति हो जाएगी।

(iii) यह शोषण-रिहीन व्यवस्था होगी। जब समाज में शोषण करने वाले वर्गों का विनाश होगा तब एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का अन्त स्वतः ही हो जायेगा।

(iv) परिवार, सम्पत्ति तथा धर्म का लोप—व्यक्ति परिवार और सम्पत्ति का उदय साथ ही साथ हुआ था। साम्यवादी व्यवस्था में इनका लोप हो जायेगा। परिवार की समाप्ति के साथ धर्म का भी लोप हो जायेगा। पूंजीवादी एवं मध्य-वर्गीय नीतिन्याय के स्थान पर सर्वहारा वर्ग की नैतिकता होगी।

(v) राज्य का स्थान एक ऐसा सामाजिक उपकरण लेगा जो उत्पादन के साधनों का नियंत्रण और उसकी व्यवस्था कर सके। साम्यवाद में समाज एक

परिवार की भांति होगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन इतना होगा कि वस्तुओं का वितरण काम के अनुसार नहीं आवश्यकता के आधार पर होगा। मार्क्स ने साम्यवादी अवस्था का चित्रण करते हुए लिखा है—

साम्यवादी समाज की प्रतिम अवस्था में जब कि श्रमविभाजन की व्यवस्था से उत्पन्न व्यक्ति की क्षमतापूर्ण पराधीनता नष्ट हो जाएगी, शारीरिक परिश्रम तथा बौद्धिक परिश्रम का पारस्परिक विरोध समाप्त हो जायगा, परिश्रम जीवन का साधन ही नहीं बल्कि जीवन की उच्चतम आवश्यकता बन जायेगा। जब व्यक्ति की सभी शक्तियों के विकास के साथ-साथ उत्पादन की शक्तियों में भी तदनुसृत वृद्धि हो जायेगी और सामाजिक सम्पत्ति के स्रोत पहिले से अधिक प्रचुरता के साथ बहने लगेंगे, तब कही पूँजीवादी अधिकारों का सीमित दृष्टिकोण पूर्णतः नष्ट होगा और समाज अपने ध्वज पर इन शब्दों को अंकित कर लेगा—“प्रत्येक व्यक्ति में अपनी योग्यतानुसार काम, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार उपभोग की सामग्री।”⁴²

कल्पनाएँ—मार्क्स ने प्रारम्भ में यूटोपियायी समाजवादियों की कटु आलोचना की है। किन्तु मार्क्स की यह कौरी कल्पना है कि राज्य स्वयं ही समाप्त हो जायगा। वास्तविकता यह है कि मार्क्स जिसे सक्रमण-काल बतलाता है उसी का अन्त होना असम्भव है। आजकल साम्यवादी राज्यों में, विशेषतः आंग्लि के राष्ट्रीय सत्ता के बाद भी हम में सक्रमण-युग का प्रत नजर नहीं आता।

ममस्त साम्यवादी राज्यों में जिस प्रकार दिन-प्रतिदिन सत्ता का केन्द्रीकरण होता जा रहा है जिस तरह सत्ता का अधिनायकवादी उद्देश्य की वृद्धि के लिये उपयोग हो रहा है, तदा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मन्दर्भ में साम्यवादी राज्य निरन्तर अपनी शक्ति में अभिवृद्धि करते जा रहे हैं, इन परिस्थितियों में राज्य के सने शन स्रोत होने की बात सोची भी नहीं जा सकती। साम्यवादी राज्य इस मार्क्सवादी मिथान्त का अध्या अनुसरण कर रहे हैं तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वे सच्चे एवं थड़ायुक्त प्रतीत नहीं होते। सर्वहारा अधिनायकवाद के तत्वावधान में न तो राज्य की सत्ता और शक्ति में कमी आयेगी और न राज्य की ही समाप्ति होगी। इस प्रकार जिस साम्यवादी समाज की स्थापना की बात मार्क्सवाद में कही जानी है वह स्वयं ही कौरी कल्पना है।

इस सम्बन्ध में मार्क्स मानव स्वभाव की कमजोरियों की अग्रहेलना करता है शक्ति का प्राकृतिक स्वभाव है कि जो उसे प्राप्त कर लेता है वह उसे बढ़ाने और अधिक समय तक बनाए रखने का भरसक प्रयत्न करता है। सर्वहारा-वर्ग ज

रक्षा प्राप्त कर लेता है तो उसे फिर सत्ता से वंचित करना अगम्य एव प्रथावहारिक है।

माक्सवाद के अन्तर्गत परिवार उन्मूलन का अनुमोदन किया गया है। परिवार को समाप्ति की बात पूर्णतः अव्यावहारिक तथा मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति के विपरीत है। स्वयं भावमं भी एक पारिवारिक व्यक्ति थे तथा उनके जीवन में उनकी पत्नी के महत्त्व की अवहेलना नहीं की जा सकती। इनके अनिश्चित लेनिन जैसे भीषण्य माक्सवादी साम्यवादी व्यक्ति का अपनी पत्नी, परिवार तथा सम्बन्धियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम एवं श्रद्धा सर्वविदिन है।

वैसे आक्रान्त राज्य सत्ता में वृद्धि को खतरनाक भी नहीं माना जाता। राज्य मनुष्य का शत्रु नहीं वह उसका सबसे अच्छा मित्र है। साम्यवादी अगले दरवाजे से राज्य को बाहर निपालता है और पिछले दरवाजे से उसे किसी अन्य रूप में वापस ले आता है।

शक्ति-संघर्ष द्वारा विरोधी वर्गों का उन्मूलन कर जो भी व्यवस्था स्थापित की जाती है उसे शक्ति से ही कायम रखा जा सकता है। ऐसी अवस्था को प्रत्येक क्षेत्र से विरोध का आभास बना रहता है। विरोधियों का उन्मूलन करते करते राज्य का रूप धारण कर लेता है। इस कारण सत्रमण-युग की समाप्ति तथा उसके धर्म-विहीन, सहयोगपूर्ण साम्यवादी समाज की स्थापना एक आन्ति ही लगती है।

माक्सवाद का सामान्य मूल्यांकन

माक्सवाद का विश्व भर में बड़ा व्यापक प्रियेचन हुआ है। आधुनिक युग का कोई भी ऐसा विद्वान् एवं चिन्तक न होगा जिसने माक्सवाद के मर्मार्थन या विपक्ष में कुछ टीका टिप्पणियाँ न की हों। पिछले पृष्ठों में जब विभिन्न माक्सवादी विद्वान्तों का विवरण दिया है उन्हीं स्थलों पर उन विद्वान्तों से सम्बन्धित आलोचना का भी समावेश किया गया है। यहाँ माक्सवाद का सामान्य मूल्यांकन प्रस्तुत है।

पुनर्विचारवादियों या संशोधनवादियों (Revisionists) द्वारा माक्सवाद की आलोचना

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में माक्सवाद विचार एव विश्वास का प्रमुख केन्द्र बन गया। दिन-प्रतिदिन इसकी आलोचना करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। बहुत से समाजवादियों ने यह खोजा कि माक्सवाद की जो आलोचना हो रही है उनमें कुछ तथ्य भी हैं। इनके अलावा परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता जा रहा था। इन बदलती हुई परिस्थितियों के मद्दम में माक्सवाद कुछ पिछड़ी हुई सी विचारधारा प्रतीत होने लगी। इन परिस्थितियों के अनुकूल या परिस्थिति-संगत बनाना आवश्यक था। इसलिए कुछ समाजवादियों ने माक्सवाद पर पुनः विचार करने, उसकी त्रुटियों को दूर करने पर ध्यान दिया। वास्तव में इनमें एक छोटे मोटे आन्दोलन का रूप

धारण कर लिया। वे जो मार्क्सवाद में पुनर्विचार कर सशोधन करना चाहें वे उन्हें पुनर्विचारवादी या सशोधनवादी (Revisionist) कहते हैं तथा यह आन्दोलन (या इसे विचारधारा कहने की जाखिम ली जाय) पुनर्विचारवाद या सशोधनवाद (Revisionism) कहलाता है। यूरोप के विभिन्न देशों में इस प्रकार के सशोधनवादी थे जिनमें जर्मनी के एडुअर्ड बेर्नस्टीन (Eduard Bernstein 1850-1932) प्रमुख थे। मार्क्सवादी समर्थकों ने सशोधनवादियों को बड़ी धृष्टतापूर्वक दृष्टि से देखा। वे सशोधनवादियों की एक बड़ी सूची प्रस्तुत करते हैं। सशोधनवादियों ने मार्क्सवाद में निम्नलिखित दोषों की ओर ध्यान आकषिप्त करते हुए बतलाया कि—

- (i) पूँजीवाद का अन्त निकट नहीं है। इसलिए अनिश्चित काल तक क्रांति की प्रतीक्षा में बैठ रहना उचित नहीं,
- (ii) वर्ग संघर्ष में वृद्धि नहीं हुई किन्तु पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ वर्ग संघर्ष में कमी होनी जा रही है
- (iii) मार्क्स के इतिहास की एक युग से दूसरे युग पर आकस्मिक छद्मता की धारणा निश्चयनीय नहीं है,
- (iv) इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या सही नहीं है इतिहास निर्धारण के अर्थ तत्त्व भी होते हैं
- (v) मूल्य सिद्धान्त में सत्यता नहीं है बल्कि श्रम ही मूल्य निर्धारण का तत्त्व नहीं है तथा
- (vi) उच्चतम सर्वहारा वर्ग के अद्ययावकत्व का भी खण्डन किया।

सशोधनवादी तत्कालीन सुधारों में विश्वास करते थे। वे मार्क्स की क्रांति साधने के स्थान पर विकासवादी-जन्तवाधिक साधनों में विश्वास करते थे।

डुग्लस जे (Douglas Jay) द्वारा मार्क्सवाद की आलोचना

प्रसिद्ध समाजवाद-शास्त्री डुग्लस जे, जो लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं, ने अपनी पुस्तक—Socialism in the New Society (1970) में मार्क्सवाद की कई स्थलों पर कटु आलोचना की है तथा मार्क्सवादी सिद्धान्तों का खण्डन किया है। डुग्लस जे के अनुसार मार्क्सवादी सिद्धान्त में अज्ञान जहाँ बुद्धिपूर्ण दृष्टिगोचर होता है उससे कुछ मूल कारण थे जिनके ज्ञान में मार्क्स उलझा रहा। डुग्लस जे के अनुसार—

- (i) मार्क्स ने विज्ञान का अपने अध्ययन का जो आधार बनाया वह उस समय शैशव अवस्था में था तथा उसने कोई प्रगति नहीं कर पाई थी।
- (ii) मार्क्स दूरदृष्टा नहीं था वह अपने युग की आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति से ही प्रभावित हुआ। इन परिस्थितियों में बाद में जैत-जैत परिवर्तन हुए मार्क्स के सिद्धांत भी सत्य से दूर होते चले गये।

(iii) जिम युग में मार्क्स ने अपने विचार व्यक्त किये उस समय आर्थिक और राजनीतिक चिन्तन में बड़ा असमंजस था। उसके तथ्यों एवं नैतिक अनुमान में बड़ी अस्पष्टता रही है।⁴³ मार्क्स पर बड़ा ही तीव्र प्रहार करते हुए डुग्लस जे लिखते हैं:—

“मार्क्स ने कई बातों को कई तरह से श्रुतिपूर्वक ग्रहण किया जिन पर इतने लम्बे समय तक विश्वास किया गया। यह कोई विशेष आश्चर्य-जनक नहीं है। उनके विचार सत्य और असत्य का मिश्रण थे। यहाँ यह स्पष्ट करना है कि सभी बड़े धर्मों की तरह मार्क्सवाद के असाधारण अध्यापक मिदान्तों पर करोड़ों लोग इतने लम्बे समय तक विश्वास करते रहे।”⁴⁴

मार्क्सवाद के अन्तर्गत धर्म की कटु आलोचना की गई है। वे धर्मविरोधी हैं तथा धार्मिक मान्यताओं पर कटु प्रहार करते हैं। यद्यपि मार्क्सवाद धर्म पर निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है पर वह स्वयं मनुष्य का एक धर्म बन जाता है। हेनोवेल लिखते हैं:—

“मार्क्सवाद मिदान्तः धर्म को अस्वीकार करता है पर व्यवहारतः जो तीव्र भावना मार्क्सवाद के पीछे काम करती है, उसकी प्रकृति धार्मिक ही है।”⁴⁵

एक दूसरे स्थान पर हेनोवेल ने लिखा है कि—

“मार्क्सवाद न तो दर्शन, न आर्थिक सिद्धान्त, न आर्थिक कार्यक्रम है किन्तु धर्म के रूप में धर्मियों को आकर्षित करता है। मार्क्स ईश्वर के बटने ऐतिहासिक आवश्यकता को, धर्म प्रिय लोगों के स्थान पर सर्वहारा वर्ग को, धर्म राज्य के स्थान पर साम्यवादी राज्य को स्थानापन्न करता है।”⁴⁶

डा० प्रायोर्वादिम् इसे भागे बढ़ते हुए व्यंग्य लिखते हैं कि “मार्क्सवाद के अपने मिदान्त हैं, अपना पुरोहित वर्ग, अपने कर्मकाण्ड तथा अपने पापमोचक अनुष्ठान हैं।”⁴⁷ सर्वहारा-वर्ग तथा इसके अन्य समर्थक इसे द्विवेचनात्मक और तात्त्विक सत्यता

43. Jay, Douglas, Socialism in the New Society, p. 34

44. “Mark got so many things so wrong, and that so much error has been so long believed. This is not really strange, if we reflect first that there was much truth mixed up with the errors which have had to be exposed here; that in all great religions, doctrines of extraordinary crudity have been believed by millions for very long periods.”

Jay, Douglas, Socialism in the New Society, p. 57.

45. Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political Thought, p. 443.

46. Ibid., p. 445.

47. प्रायोर्वादिम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खंड, पृ. 614.

के आधार पर नहीं किन्तु एक धमन्ध और विश्वास के रूप में स्वीकार करते हैं। सर्वहारा-वर्ग माक्संवादी धर्म का बड़ा ही बड़ा अनुयायी समझा जाता है।

माक्संवाद की बहुत-सी धारणाएँ गन्त सिद्ध हो चुकी हैं। औद्योगिक प्रगति एक नम व्यवस्था को ध्यान में रखने हुए माक्सं ने कहा था कि साम्यवादी क्रांति पहिले अमेरिका तथा इंग्लैंड में होगी। लेकिन इसके विपरीत सर्वप्रथम साम्यवादी क्रांति रूस जैसे पिछड़े देश में हुई। मनमं का यह कहना कि साम्यवादी क्रांति केवल औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्या में ही सम्भव है सही नहीं रहा। रूस तथा चीन साम्यवादी क्रांतियों के समय औद्योगिक युग में नहीं आ पाये थे; वे उस समय व्यापक रूप से कृषि युग में ही थे, लेकिन फिर भी वहाँ क्रांतिया सम्भव हो सकीं। यही नहीं, साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना बिना क्रांतियों के भी हो चुकी है। पूर्वी यूरोप में रूस द्वारा धोपी गयी साम्यवादी व्यवस्था क्रांतियों का परिणाम नहीं है। भारत में बेरल में कई बार साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी है जा वर्ग-सघर्ष का नहीं मत-सघर्ष का परिणाम है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि साम्यवाद की स्थापना ससदीय प्रणाली के अन्तर्गत भी सम्भव है। एक और अन्य उदाहरण लेटिन अमरीकी राज्य चिली का दिया जा सकता है जहाँ 1970 में बिना क्रांति के साम्यवादी सत्ता ग्रहण कर चुके हैं।

माक्सं की यह भविष्यवाणी भी सही सिद्ध नहीं हुई कि निर्धन अधिक् निर्धन होत जायेंगे। अमेरिका तथा अन्य पूँजीवादी राज्यों में गरीबों की हालत में काफी सुधार हुआ है। उन्हें जीवनयापन के लिये ही नहीं बल्कि सुख सुविधा योग्य वेतन मिलता है।

माक्सं का पुन आगन्त (The second-coming of Marx)

माक्संवाद की जो इतनी आलोचना हुई है तथा माक्सं के वाद सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में जो व्यापक परिवर्तन हुए हैं, बहुत से लोगो की मान्यता है कि यदि माक्सं पुन वापस आये तो उसे अपने सिद्धान्तों तथा निष्कर्षों में बड़े परिवर्तन एवं सशोधन करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। इस प्रकार के विचारों को व्यक्त करने का उद्देश्य केवल माक्संवाद की आलोचना को अधिक गम्भीरता प्रदान करना तथा उसमें सशोधन की बात को और अधिक् तूल देना है। माक्संवाद का जो विवेचन हुआ है इस महान विचारधारा का जो भी औचित्य है वह पहले ही स्पष्ट है।

योगदान—

कार्ल माक्सं तथा ऐन्ग्ल्स ने अपनी माक्संवादी विचारधारा से सत्तार की नममोर दिया। माक्सं एक विचारक, दार्शनिक तथा इन सबसे अधिक् युग-प्रवर्तक थे। उनके विचारों ने राजनीतिक चिन्तन को नया मोड़ दिया। यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि

उनकी विचारधारा कहां तक सही है, किन्तु यह निर्विवाद है कि समाजवाद के सभी सम्प्रदाय माक्स से किसी न किसी रूप में प्रेरणा लेते हैं। आज विश्व की आधी से भी अधिक जनसंख्या माक्सवादी प्रभाव के अन्तर्गत है। हन्ट (R. N. Carew Hunt) के अनुसार ईसाई धर्म के अभ्युदय के पश्चात् माक्सवाद सबसे महान् आन्दोलन था।⁴⁸

माक्स ने अपने विचार कई स्रोतों से ग्रहण किए लेकिन इन सब को माक्स ने अपने आधरण पहनाया। माक्स का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान यह था कि दूसरों से उसने जो भी विचार ग्रहण किये उन्हें क्रान्तिकारी रूप प्रदान किया।

माक्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान करना माक्स-एन्जिल्स का महत्वपूर्ण योगदान है। माक्स के पूर्व समाजवाद का विवेचन करने वाले दार्शनिकों ने कपोल-कल्पित धारणाओं के आधार पर यूटोपियायी भावदर्श रखे किए। किन्तु माक्स का दृष्टिकोण यथार्थवादी था। उसने ऐतिहासिक तथा आर्थिक अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया। उसने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया उन्हें क्रमबद्ध ढंग से सम्बद्ध कर, कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित कर अपने विचारों को दर्शन का रूप प्रदान किया।

माक्सवाद की अन्य प्रमुख देन या जिनने व्यक्तियों को प्रभावित और प्रेरित किया निम्नलिखित हैं—

- (i) इन विचारधारा ने पूँजीवाद के दोषों को विश्व के समक्ष रखा।
- (ii) उन्होंने समाजवाद को श्रेष्ठ आन्दोलन का रूप दिया।
- (iii) माक्स-एन्जिल्स ने निम्न-वर्ग को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। माक्स के पहले कोई भी ऐसा विचारक नहीं हुआ जिसने समाज के पद-दलित एवं शोषित-वर्ग को इतना महत्व दिया हो। माक्स पहिला व्यक्ति था जिनने श्रेष्ठ-वर्ग को समाज का आधार स्वीकार किया।
- (iv) माक्सवाद ने यह सिद्ध कर दिया कि समाज सुधार उस ढंग की देन नहीं, ये क्रान्ति द्वारा सर्वहारा-वर्ग द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (v) उन्होंने मनुष्य के ईश्वरीय अङ्ग होने का खण्डन कर यह बतलाया कि मनुष्य पृथ्वी का है, इस लौकिक जीवन ही उसके लिए सब कुछ है।

माक्सवाद के अध्ययन को एन्ड्रू हेकर के शब्दों में समापन करना अधिक उपयुक्त लगता है। हेकर ने लिखा है :—

“माक्सवादी सिद्धान्त अब तक साम्यवादी विचारधारा को आधार प्रदान करता है मनुष्यों के दिल और दिमागों में भावनाएँ उभारता रहेगा। यदि आधा विश्व माक्स तथा एन्जिल्स के विचारों को मोते से लगाए हुए है तथा आधा विश्व इसके

अस्तित्व स ही घृणा करता है इससे दोना वा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि कम स कम ये सिद्धान्तकार जो कुछ कहना चाहते हैं उसे समझें।”⁴⁹

पाठ्य-ग्रन्थ

- 1 Cole G D H , A History of Socialist Thought, Vol II, Socialist Thought Marxism and Anarchism Chapter XI, Marx and Engels
2. Engels F , Socialism Utopian and Scientific
- 3 Gray, Alexander , The Socialist Tradition, Chapter XII, Scientific Socialism
- 4 Hacker Andrew , Political Theory , Chapter 13, Karl Marx and Friedrich Engels
- 5 Hallowell, J. H , Main Currents in Modern Political Thought Chapter 12, Karl Marx and Rise of ‘Scientific Socialism’
- 6 Hunt, R N Carew , The Theory and Practice of Communism- An Introduction, Part I, The Marxist Basis
- 7 Jay Douglas, Socialism in the New Society, Part I, Ch 4, Where Marx Went Wrong Ch 5, Marxist and the Second Coming
- 8 जोड , आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका अध्याय 5, साम्यवाद तथा अराजकतावाद
- 9 Kitz-r and Ross , Western Social Thought, Chapter 15, Marx and ‘Scientific Socialism
- 10 कोकर , आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, अध्याय 2, कार्ल मार्क्स
- 11 Laski, H J Karl Marx An Essay, London, 1922
- 12 Marx and Engels Manifesto of the Communist Party Moscow 1967
- 13 Mayo Henry B , Introduction to Marxist Theory
- 14 Sabine G H , A History of Political Theory , Chapter 33, Marx and Dialectical Materialism
- 15 Taylor, A J P., Introduction to the Manifesto of the Communist Party



49 Hacker, Andrew , Political Theory, p 570

अराजकतावाद

प्राधुनिक अराजकतावाद अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण तथा उन्नीसवीं शताब्दी की विचारधारा है। 'अराजकता' शब्द का उद्भव एक ग्रीक शब्द 'अनाकिया (Anarchia) से हुआ है जिसका अर्थ 'शासन का अभाव' है। इस प्रकार शाब्दिक आधार पर अराजकतावाद ऐसी विचारधारा की घोर संकेत करता है जो राज्य एवं सामन्यता उन्मूलन कर उसके स्थान पर राज्य-विहीन एवं वर्ग-विहीन समाज (Stateless and Classless Society) की व्यवस्था करता है, जिसमें सभी प्रकार के शोषण का अन्त और बल प्रयोग का लोप हो।

कोल (G.D.H Cole) ने अराजकतावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है:—

“एक दार्शनिक सिद्धान्त के रूप में अराजकतावाद समाज के संगठन के उन सब रूपों के पूर्ण विरोध से आरम्भ होता है जो बाध्यकारी सत्ता पर आधारित होते हैं। एक आदर्श के रूप में अराजकतावाद का अभिप्राय उस स्वतन्त्र समाज से है जिसमें से बाध्यकारी तत्वों का लोप हो चुका हो।”

फ्रान्सिस कोकर के शब्दों में:—

“अराजकतावाद का सिद्धान्त यह है कि राजनीतिक सत्ता, किराी भी रूप में, अनावश्यक एवं अवांछनीय है। प्राधुनिक अराजकतावाद में राज्य के सिद्धान्तिक विरोध के साथ धैर्यपूर्ण सम्पत्ति की संस्था का विरोध और संगठित धार्मिक संस्था के प्रति शत्रुता का भी समावेश है।”²

प्रसिद्ध अराजकतावादी ओपाट्किन (Peter Kropotkin) ने अराजकतावाद की व्याख्या करते हुए लिखा है:—

राज्यविहीन पक्षी पादरी के पुत्र और स्वयं पादरी से की प्रथम प्राधुनिक अराजकतावादी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक—An Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on General Welfare and Happiness—में अपने विचारों को व्यक्त करने हुए लिखा है कि यदि पूँजीवाद और मनुष्य के शोषण का अन्त कर दिया जाये तो मनुष्य आपस में प्रेम से रहेंगे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव

“धराजवतावाद जीवन तथा धारण का ऐसा सिद्धान्त धरवा नियम है जिसमें शासन-विहीन समाज की कल्पना की जाती है—ऐसे समाज में सामंजस्य न तो विधि के समझ धात्म-समबंध कर और न किसी अन्य शक्ति की धाजा पालन कर प्राप्त किया जाता है, अपितु वह उन विभिन्न प्रादेशिक और व्यावसायिक समूहों के मध्य किये गये स्वतन्त्र सविदाओं द्वारा प्राप्त किया जाना है जिनकी रचना स्वतन्त्र रूप से उत्पादन और उपभोग के लिए तथा सभ्य जीवन की अनन्त इच्छाओं और धावश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जानी है।”

विकास एवं परम्परा

यदि राज्य-विहीन, वर्ग-विहीन, शोषण-विहीन शक्ति-विहीन विचारों का ऐतिहासिक अध्ययन किया जाए तो अधुनिक धराजवतावाद अपने धारण में कोई नवीन विचारधारा नहीं है : चीन में लगभग 700 ईसा पूर्व एवं विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ जिसे टाओवाद (Taoism) कहते हैं। इस विचारधारा को निर्मात्रण या प्रतिबंध विरोधी तथा स्वतन्त्रता समर्थन की सबसे पुरानी विचारधारा माना जाता है। प्राचीन चीन में कई विचारधाराओं में इस प्रकार के विचार मिलते हैं। लगभग ईसा के 600 से 500 वर्ष पूर्व लाओत्सु (Lao-tse) और लगभग ईसा के 300 वर्ष पूर्व चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक च्वांग-त्सु (Chuang-tzu) ने कहा था कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर शासन करना मानव स्वभाव के प्रतिकूल है। प्राचीन चीन में स्टोइक विचारधारा (Stoicism) के अध्यायी जेनो (Zeno) ने भी एक राज्य-विहीन समाज का प्रतिपादन किया था।

पाश्चात्य विद्वानों ने अक्सर यह मत व्यक्त किया है कि पूर्व के देशों में राजनीतिक दर्शन का अभाव रहा है। इसका वास्तविक कारण यह था कि पूर्व की विचारधाराओं में राज्य का कम तथा स्वतन्त्रता का अधिक महत्त्व रहा है। प्राचीन भारत में इस प्रकार की विचारधारा का प्रचलन था। शान्ति पूर्व में उल्लेख है कि प्राचीन समाज गुण (virtue) और स्वतन्त्रता (freedom) का धारण था। इसी धारण में एक स्वयं पर उद्धृत है कि—

‘न तो राज्य था और न राजा ही, न विधि या न विद्वान निर्माता।
 व्यक्ति अपनी आन्तरिक चेतना के कर्तव्य से एक दूसरे की रक्षा करते थे।’

Marx and Dialectical Materialism

15 Taylor, A J P.,

Introduction to the Manifesto of the
 Communist Party

मध्य युग में ईसाई सभ्रशाही में भी धराजनावाद की अभिव्यक्ति मिलती है। उसे सुधार (Reformation) युग में पीटर सेलेस्की ने चर्च और राज्य के विषय में धराजनावादी सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए राज्य को एक शक्ति पर आधारित संस्था मान कर उसकी निन्दा की है। पुनर्जागरण (Renaissance) युग में मानवावादियों (Humanists) में रेबेले (Rebelais) ने भी उस आदर्श जीवन का वर्णन किया है जिसमें शक्ति एवं सत्ता का कोई नियन्त्रण या प्रतिबन्ध न हो। मट्टारह्वी गतास्की के साहित्य-विकास में, दीदरो (Diderot) साहित्यकार का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिन्होंने व्यक्ति की स्वतन्त्रता और प्राकृतिक अधिकारों को विशेष महत्त्व दिया है।

बुद्ध आधुनिक धराजनावादीयों ने अपने विचारों का प्रतिपादन काले भावसंघ में भी पहले किया है। लेकिन इन विचारधाराओं की आधुनिकता की ओर ले जाने में मार्क्सवादी विचारधारा से विशेष प्रोत्साहन मिला। धराजनावाद को भी समाजवाद की एक प्रसंग और विशिष्ट शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इस विचारधारा को आधुनिक ढंग से प्रतिपादन, व्यवस्थित एवं प्रमद्वद्ध करने का श्रेय बर्द फिल्लरों को है।

धराजनावाद के प्रतिपादकों का गाँठे रूप से दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है। प्रथम, व्यक्तिवादी धराजनावादी, जो राज्य का ही विरोध नहीं करते, यथा-सम्भव हर प्रकार के सामाजिक संगठन के बिना काम चलाना चाहते हैं। इसके पक्षधर जर्मनी के मैक्स स्टर्नर (Max Stirner, 1806-1856) तथा अमेरिका के बेंजामिन टकर (Benjamin Tucker, 1854-1908) के नाम उल्लेखनीय हैं।

दूसरी धरोड़ी में समष्टिवादी धराजनावादी अथवा धराजनावादी साम्यवादी आते हैं जो बाध्यकारी सत्ता का विरोध करते हैं किन्तु पारस्परिक सहयोग के आधार पर समाज व्यवस्था में विश्वास करते हैं। बाकुनिन (Bakunin, 1814-76) तथा पीटर क्रोपोटकिन (Peter Kropotkin, 1842-1921), के नाम इससे सम्बन्धित हैं। लेकिन बुद्ध धराजनावादी जैम गोडविन (William Godwin, 1756-1836), प्रॉण (Proudhon, 1809-1865) आदि व्यक्तिवादी और समष्टिवादी धराजनावादीयों के मध्य भी स्थिति स्पष्टता है।

विचित्र गोडविन (William Godwin, 1756-1836), जो कि एक व्यक्तिवादी पंथी पादरी के पुत्र और स्वयं पादरी से ही प्रथम आधुनिक धराजनावादी बहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक—An Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on General Welfare and Happiness—में अपने विचारों को व्यक्त करने हुए लिखा है कि यदि पूर्णजीवाद और मनुष्य के शोषण का अन्त कर दिया जाय तो मनुष्य आपस में प्रेम में रहेंगे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव

से विवेकशील है। इनके अनुसार राजनीतिक शक्ति पधवा सरकार एक भावस्वत बुराई है। यह शक्ति और हिंसा पर आधारित है। गॉडविन ने राज्य, सरकार, कानून न्यायालय, सम्पत्ति और परिवार के उन्मूलन का समर्थन किया है।

गॉडविन ने सम्पत्ति को बहुत सी सामाजिक और नैतिक बुराइयों का मूल मानता है, जो समाज में आर्थिक विषमता पैदा करती है। सम्पत्ति धनिकों में मिथ्याभिमान और गरीबों में हीनता की भावना को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार गॉडविन ने कई सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों की कटु निन्दा कर उनका उन्मूलन चाहा है। किन्तु इसका उद्देश्य एक ऐसी उच्च सामाजिक रचना या जिममें विभिन्न समुदाय स्वायत्त हो।⁵

टॉमस हॉजस्किन (Thomas Hodgskin, 1787-1869) को व्यक्तिवादी अराजकतावादी की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। वैसे इनका अराजकतावादी होना सदिग्ध है। ये राज्यसत्ता के तीव्र आलोचक थे। उनके अनुसार कानून निर्माण की समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। वे ऐसी व्यवस्था के समर्थक थे जिममें कोई राजनीतिक शक्ति विद्यमान न हो तथा व्यक्तियों को स्वाभाविक अधिकार प्राप्त हो।

हॉजस्किन का विश्वास था कि 'अखिल ब्रह्माण्ड का नियमन स्वाई एक अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा होता है। मन्त्रिम इस महान व्यवस्था का ही एक अंग मात्र है। अन्तः प्रति पल, प्रति क्षण उसका आचरण स्वाई तथा अपरिवर्तनीय नियमों द्वारा उसी प्रकार प्रभावित, नियन्त्रित तथा नियमित है जिस प्रकार वनस्पति का बढ़ना अथवा नक्षत्र-मण्डल की गति नियमित और नियन्त्रित है। फलतः किसी प्रकार के नियोजन अथवा व्यवस्थापन की कोई आवश्यकता नहीं। यदि व्यक्ति को अधिक धन मुक्त छोड़ दिया जाय तो अन्तः-हित का पूर्व प्रतिष्ठित सामजस्य प्राप्त हो जाता है।'⁶

मेक्स स्टर्नर (Max Stirner, 1806-1856) जर्मनी के रहने वाले थे। इनकी न तो ईश्वर में श्रद्धा थी, न राज्य में विश्वास। ये राज्य द्वारा निमित्त नियमों के विरोधी थे। ये एक दार्शनिक की तरह स्वयं की वास्तविकता में विश्वास करते थे।

पियरे जोसेफ प्रोद्यों (Pierre Joseph Proudhon, 1809-1865) सम्भवतः पहला दार्शनिक था जिसने स्वयं को अराजकतावादी कहा। प्रोद्यों स्वतंत्रता तथा मुक्ति का प्रबल समर्थक तथा शोषण का विरोधी था। उसका विचार में "मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर शासन प्रत्येक रूप में अत्याचार है। समाज की सर्वोच्च पूर्णता अराजकतावादी एकता एवं व्यवस्था में ही उपलब्ध होती है।"

5 Gray, A. The Socialist Tradition p 130

6 कोकर, आधुनिक राजनीति चिन्तन, पृ० 208

प्रधों ने जनता बैंक (Bank of the People) के सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत की, जिसका कार्य 'श्रम नोट' (Labour Notes) जारी करना था। इन नोटों में श्रम की इकाइयों का उल्लेख रहता था जिनकी माप उनकी अवधि अथवा कार्य काल से ज्ञात हो सकती थी।

प्रधों के धराजकतावादी विचारों में भी सम्पत्ति को कोई स्थान नहीं है; वह सम्पत्ति को चोरी कहता था तथा उसे शोषण से उत्पन्न मानता था। सम्पत्तिवान् व्यक्ति अन्यायपूर्वक सम्पत्ति का धर्जन करते हैं जिससे श्रमिकों का शोषण होता है। राज्य इन्हीं सम्पत्तिवान् व्यक्तियों के हित साधन का यंत्र है। प्रधों ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहता है जिसमें व्यक्ति सब प्रकार के राजनीतिक तथा आर्थिक बन्धनों से मुक्त होकर सहयोग तथा ऐच्छिक सघों के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का प्रबन्ध करें।

धराजकतावाद को प्रमवद्ध राजनीतिक दर्शन तथा विचारधारा का रूप प्रदान करने का श्रेय बाकुनिन तथा पीटर श्रोपॉट्किन को है।

5 माइकल बाकुनिन (Michael Bakunin, 1814-76) के जीवनकाल में मानसंवादी विचारधारा का काफी प्रचार हो चुका था और वह इस विचारधारा से किमी मीमा तक प्रभावित हुआ। बाकुनिन मानव विकास-क्रम का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करता है तथा यह बतलाता है कि प्रारम्भ काल से धर्म, सम्पत्ति और राज्य का अभ्युदय किस प्रकार हुआ। उसने धर्म, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा राज्य को मनुष्य के स्वतन्त्र विकास मार्ग में बाधक माना है। धर्म मनुष्य की स्वतन्त्र चेतना के मार्ग में बाधक है तथा स्वतन्त्रता को नियमित एवं सीमित रखता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति शोषण तथा असमानता पर आधारित है, राज्य शक्ति का प्रतीक और व्यक्तिगत सम्पत्ति का संरक्षक होने के नाते वर्ग संगठन का पोषक है। इन तीनों संस्थाओं का प्राप्ति द्वारा ही अन्त किया जा सकता है। इनकी समाप्ति के पश्चात् ही मनुष्य वास्तविक स्वतन्त्रता का अनुभव तथा स्वयं का विकास कर सकता है।

बाकुनिन ने राज्य की समाप्ति के पश्चात् भविष्य में सामाजिक व्यवस्था के विषय में भी विचार व्यक्त किये हैं। उसने अपनी नई समाज व्यवस्था को संघवाद का नाम दिया। संघवाद में मारा कार्य स्वैच्छा पर आधारित होगा तथा व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं रखा जायगा। कोकर ने बाकुनिन के संघवाद की व्याख्या करने हुए लिखा है कि—

"स्पान्तीय समाज मानूहिक जीवन की प्रारम्भिक इकाई होगा।

(इस प्रकार के समाज को धराजकतावादी भाषा में सम्पूत कहते हैं)

मानव सम्पन्न मित्ररूप प्रपत्ती आवश्यकतानुसार बड़े बड़े सघ बना लेंगे ।

य सघ भी पूणत ऐच्छिक आधार पर ही बनेंगे ।

पीटर क्रोपोट्किन (Peter Alexander Kropotkin, 1842-1921) के विचार बाबुनिन से बहुत मिलते जुलते हैं । वह जीवशास्त्र का विद्वान था । प्रजा मानव विकास क्रम की जीवशास्त्रीय विधि से विवेचना करता है । उसने प्रभुगार मनुष्य स्वभाव एवं समाज में वे सब तत्त्व विद्यमान हैं जिससे मनुष्य का विगत प्राकृतिक ढंग से हो सकता है । परन्तु राज्य, धर्म तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति इन विकास में बाधक हैं । य सस्थाएँ अन्याय, असमानता तथा शोषण की प्रवृत्ति को जन्म देती हैं । इनका नाश द्वारा उन्मूलन होना चाहिये ।

राज्य की समाप्ति के बाद क्रोपोट्किन का विश्वास था कि समाज में स्वतंत्र सस्थाएँ बनी रहेंगी जो ऐच्छिक समझौते पर आधारित होंगी । समाज में बुराईया, भगड़े आदि में ज़िलकुल ही कमी हो जायेगी क्योंकि इनको प्रोत्साहित करने वाली सस्थाएँ ही समाप्त हो जायेगी । मानव विकास में सहकार्य तत्त्व ही प्रमुख होगा न कि दमन, शक्ति और सत्ता ।

जोशुआ वारेन (Josiah Warren, 1798-1874) को पहला धर्मरीकी धराजकतावादी कहा जाता है । अमेरिका में सर्वप्रथम धराजकतावादी पत्र-Peaceful Revolutionist (शान्तिवादी प्रान्तिकारी)-के प्रकाशन का श्रेय वारेन को है । कुछ समय में शोषण के अनुयायियों की बस्ती न्यू हारमनी में भी रहे । बाद में इन्होंने प्रधो की तरह जनता बैंक की स्थापना की जहाँ ये धर्म-नोटों को जारी करते थे ये धर्म नोट वस्तुओं के विनिमय के नाम में धाते थे ।

ये राज्य की आवश्यकता में-विश्वास नहीं करते थे । ये राज्य को व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा दमनकारी प्रवृत्तियों का परिणाम मानते थे । राज्य-विहीन समाज की व्यवस्था के लिए इनका सुझाव था कि एक छोटी विशेषज्ञों की समिति थोड़े समयाने बुझाने के कार्यों के लिए पर्याप्त होगी ।

हेनरी डेविड थोरो—(Henry David Thoreau, 1817-1862) एक और धर्मरीकी-धराजकतावादी थे । वे मानते थे कि मनुष्य में अन्धेई की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । यह प्रवृत्ति स्वतंत्र तथा विवेक-सम्पन्न इच्छा के निर्देशन में ही पूर्णता प्राप्त कर सकती है । ये अन्तरात्मा को कानून से थोड़ा एक सर्वोच्च मानते थे ।

डेविड थोरो ने दासता के विरुद्ध किये जाने वाले सघर्ष में धर्मरीकी सरकार के विरुद्ध सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग करने का आग्रह किया । इन्होंने भविष्य के लिए एक ऐसे समाज के आदर्श को प्रस्तुत किया जिसमें शासन को कोई स्थान नहीं होगा ।

(1) बेन्जामिन टकर (Benjamin R. Tucker, 1854-1939) अमेरिका के मिसिसिपि अराजकतावादी थे। वे प्रयोग, योन तथा वारेन आदि में प्रभावित हुए। 1881 में टकर ने एक अर्ध-मासाहिक पत्र - Liberty-का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 1907 तक इस पत्र का प्रकाशन चलता रहा तथा दार्शनिक अराजकतावाद के सिद्धान्त के सम्बन्ध में अत्यन्त श्रद्धा प्राप्त की।

टकर के विचारों का आधार मनुष्य का विवेकपूर्ण आत्महित है। यह मान्य है मनुष्य को ऐसे समाज की ओर अग्रसर करता है जिसमें सब मनुष्य समान रूप में स्वतंत्र हों। स्वतंत्रता ही व्यवस्था का प्रभावकारी साधन है और उसी में सुख का मूल तत्व भी है। टकर समाज में राजनीतिक सत्ता के निष्कासन के पक्ष में है, क्योंकि राज्य ने हमेशा ही स्वतंत्रता के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है। राज्य को स्वीकार करने का तात्पर्य स्वतंत्रता के हनन की स्वीकार करना है। टकर राज्य के स्थान पर धर्मियों के स्वतंत्र समझौतों द्वारा निर्मित सम्झौतों के पक्ष में थे। इन सम्झौतों की मदद से तथा स्वयं मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिए।

यादृशित तथा शोषांतु के सिद्धान्तों का प्रचार योरोप के मजदूरों में अनेक पत्र पत्रिकाओं द्वारा किया गया तथा अनेकों बलवों की स्थापना हुई। जॉन मोस्ट (Johann Most) ने जर्मनी और मधुक्त राज्य में अराजकतावाद के लिए व्यापारिक प्रवृत्तियों का सफटन किया लेकिन इसकी विशेष सफलता नहीं मिल सकी। विद्यमानक रूप में अराजकतावाद के व्यावहारिक कार्यक्रम को मजदूर अधिक प्रोत्साहन कुछ अन्तर्गुण्यवादियों (Nihilists) ने मिला। शून्यवाद अराजकतावाद में अधिक व्यापक शब्द है, हमने अधिक उग्रवादी निर्येधों का बोध हीना है। यह समस्त प्रचलित एवं प्रतिष्ठित विचारों, सम्झौतों एवं मानदण्डों को अस्वीकार करता है। शून्यवाद के राजनीतिक पहलू सरगी नेचिचेव (Sergei Netschaiev, 1844-1882) के विचारों में स्पष्ट मिलते हैं। शून्यवाद धर्म, हिंसा, भय आदि उत्पन्न करने वाले सभी धर्म-धर्मों का समर्थन करता है।

मैन में भी एक नये अराजकतावादी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ जिसे अराजकता-मिन्टीरवाद के नाम से जाना जाता था। यह अराजकतावादी सिद्धान्तों तथा मिन्टीरवाद की भाषनों का सम्मिश्रण है।

यंग अराजकतावादियों को सूची बड़ी लम्बी है। लेकिन हम सम्बन्ध में विद्यो टॉलस्टॉय (Count Leo Tolstoi, 1828-1910) तथा महात्मा गांधी (1869-1948) के नाम का उल्लेख और किया जा सकता है। ये मता के विरोधी थे। टॉलस्टॉय को सामान्यतः अराजकतावादी माना जाता है, किन्तु महात्मा गांधी को पूर्णतः उग्रवाद के पक्ष में सोमित नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी तथा सर्वोदयी व्याख्याता, समाज विरोधी, शासन को सोमित करने, दिक्कतीकरण तथा स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं।

अराजकतावाद के सिद्धान्त-सूत्र

अराजकतावादी चिन्तकों का अध्ययन करने से इस विचारधारा के बहुत कुछ लक्षण स्वयं ही स्पष्ट हो जाते हैं। फिर भी उन्हें विस्तारपूर्वक एवं क्रमबद्ध व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

मानव स्वभाव (१)

अराजकतावादी मनुष्य को स्वभावतः, अच्छा, सहयोग प्रिय मानते हैं। वह एक दूसरे के साथ नि स्वार्थ सहचर जीवन व्यतीत करने की प्रवृत्ति रखता है। हेनरी डेविड थोरो ने ट्रांससेण्डेंटलिस्ट (Transcendentalist) वर्ग के लोगों के इन विचारों का अनुकरण किया है कि मनुष्य में अच्छाई की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति है और वह अपनी स्वतन्त्र एवं विवेक-सम्पन्न इच्छा के निर्देशन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है।⁸

अराजकतावादियों के अनुसार सामाजिकता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। क्रोपोटकिन की पुस्तक—Mutual Aid, a Factor of Evolution—मनुष्य की पारस्परिक सहयोग की प्रवृत्तियों का ही सबलन है। इससे उसमें डाब्लिन तथा हरवर्ट स्पेन्सर के विकासवाद का खण्डन किया है। विकास, सघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि पारस्परिक सहयोग पर आधारित है। वाकुनिन ने मानव स्वभाव के विषय में सामाजिक समझौतों के सिद्धान्त की भी प्रालोचना की है जिसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों में कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं था।

वास्तव में अराजकतावादियों की पूर्ण विचारधारा का आधार मानव स्वभाव पर निर्भर करता है। एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना तभी हो सकती है, जब मनुष्य में अच्छाई तथा पारस्परिक सहयोग की भावना हो।

उद्देश्य तन्वीन सामाजिक व्यवस्था - नकारात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण (२)

अराजकतावादी नकारात्मक एवं सकारात्मक आधार पर एक नय समाज की स्थापना करना चाहते हैं। नकारात्मक ढंग से यह व्यवस्था राज्य विहीन तथा वर्ग-विहीन होगी या समाज से उन सभी तत्वों और संस्थाओं (जैसे धर्म, परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति आदि) का उन्मूलन कर दिया जाये जो नियन्त्रण, शक्ति और शोषण के आधार हैं तथा इनको प्रोत्साहित करते हैं।

किन्तु अराजकतावाद केवल शक्ति का अभाव है, व्यवस्था का नहीं। उनके विचार सकारात्मक भी हैं। अराजकतावादी मनुष्य स्वभाव के अनुकूल समाज रचना करना चाहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना धामन होना तथा स्वाभाविक मानवीय

⁸ कोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 207.

धराजकतावाद (2)

प्रवृत्तियों के आधार पर स्वयं को नियंत्रित करेगा। मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार स्वयं प्रस्थाई (ad hoc) एवं ऐच्छिक समुदायों का निर्माण करेगा। इन समुदायों पर किसी भी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं होगा तथा सहकारिता के आधार पर अपने कार्यक्रम और नीति निर्धारण करेगा। डिकिन्सन ने लिखा है कि समुदायों का एक जटिल जाल जिसमें सर्वत्र व्यवस्था रहती है, और कहीं भी बल प्रयोग नहीं होता, धराजकतावादी समाज के निर्माण की सामग्री है क्योंकि धराजकता व्यवस्था का अभाव नहीं अपितु नियंत्रण का अभाव है।⁹

सूक्ष्म में, धराजकतावादी समाज निम्नलिखित सिद्धान्तों एवं आधारों पर गठित होगा—

- (i) राज्य-विहीनता
- (ii) वर्ग-विहीनता
- (iii) शक्ति-विहीन या बल प्रयोग रहित
- (iv) स्वतन्त्रता
- (v) समानता
- (vi) महयोग और सहकारिता के आधार पर ऐच्छिक और प्रस्थाई समुदायों का निर्माण।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (3)

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के समर्थन में धराजकतावादी व्यक्तिवादियों से भी आगे है। इन दृष्टि में धराजकतावाद व्यक्तिवाद का उग्र रूप है। ये स्वतन्त्रता को सर्वोच्च मर्यादा (supreme good) मानते हैं। व्यक्ति का पूर्ण विकास स्वतन्त्रता में निहित है तथा किसी भी प्रकार का नियंत्रण अवाञ्छनीय है। अपनी पुस्तक—What is Property—में प्रथो ने लिखा है:—

“राजनीति स्वतन्त्रता का विज्ञान है। मनुष्य पर मनुष्य द्वारा शासन (किसी भी नाम प्रयुक्त वेश में) अत्याचार है। व्यवस्था एवं धराजकता के सम्बन्ध में समाज अपनी पूर्णता प्राप्त करता है।”¹⁰


व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार की सहाय एवं नियंत्रण से मुक्त करना धराजकतावादीयों का प्रमुख उद्देश्य है। विमोचन: वे व्यक्ति को—

- (i) नागरिक के रूप में राज्य-बन्धन से मुक्त कराना;
- (ii) एक उत्पादक की हैमियन से पूँजीपति के बन्धन में मुक्त कराना;

9. Dickenson, *Lowes, Justice and Liberty*, pp. 122-23.

10 “Politics is the science of liberty. The government of man by man (under whatever name it be disguised) is oppression. Society finds its highest perfection in the union of order with anarchy.” p. 272

(iii) एक सामान्य मनुष्य के रूप में धर्म-विद्वानों (या ब्राह्मण-वर्णियों) से मुक्त कराना चाहते हैं।¹¹ *सोपेरा कितनी थी (1914)*

व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध  *सोपेरा कितनी थी (1914)*

व्यक्तिगत सम्पत्ति के विषय में अराजकतावाद एक साम्यवाद में कोई विशेष अन्तर्गत नहीं है। २ व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध करते हैं क्योंकि—

(i) साम्यवादियों की तरह अराजकतावादी सम्पत्ति को शोषण तथा अन्याय का प्रमुख कारण मानते हैं। तभी तो प्रथम ने कहा है कि 'सम्पत्ति चोरी है।' वे व्यक्ति जिनके पास कुछ सम्पत्ति है वे विलासपूर्ण, अकर्मण्य जीवन व्यतीत करन व साथ-साथ उनमें श्रेष्ठता की भावना तथा दूसरे पर अधिकार करने की इच्छा प्रबल होती है। सम्पत्ति शोषण का साधन एक उद्देश्य श्रोता ही है। सम्पत्ति का सबसे शोषण के माध्यम में ही होता है, व और अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा का शोषण करते हैं।

(ii) व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वतन्त्र प्रतियोगिता सिद्धान्त पर आधारित रहती है और सहयोग एवं सद्भाव की उपस्था करती है।

(iii) अराजकतावादियों के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था का मूल आधार व्यक्तिगत सम्पत्ति है। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति का विरोध करन व साथ-साथ पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था के भी कट्टर विरोधी थे। उनके विचार में उत्पादन किमी एक व्यक्ति के श्रम का परिणाम नहीं होता, बल्कि सम्पूर्ण समाज के श्रम का फल है। अतः सम्पत्ति पर किमी एक व्यक्ति का स्वामित्व अन्याय है, परिश्रम का फल सम्पूर्ण समाज को प्राप्त होना चाहिए। अराजकतावादी उस सिद्धान्त का समर्थन करते हैं कि प्रत्येक अपनी क्षमता के अनुसार काम कर और प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार मिले।

(iv) सम्पत्ति विषमता इतिहास में बहुत से युद्धों का कारण रही है। गॉडविन ने अपनी पुस्तक—An Enquiry Concerning Political Justice—में यूरोप में हुए युद्धों का विवेचन किया है। उनका निष्कर्ष है कि इन युद्धों का मूल कारण सम्पत्ति में विषमता था। (पृ 813)

(v) व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार पर समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्रथम, सुख-सौभाग्य वर्ग जिनका उत्पादन के साधन पर स्वामित्व होता है, अन्याय तथा श्रमिकों का शोषण करके निरन्तर अपनी पूँजी में वृद्धि करते हैं। इनका जीवन सामान्यतः स्वार्थी अर्थवैज्ञानिक तथा विनाशकारी होता है। दूसरे वर्ग में श्रमिक आते हैं, जिनका उत्पादन में प्रमुख योगदान रहता है, लेकिन फिर भी भ्रष्टा, वस्त्रहीन तथा

¹¹ जाड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त—प्रवर्धिका, पृ 105

मादामहीन रहता है। इस प्रकार अराजकतावादी सम्पत्ति को अधिक विपमता और सामाजिक अन्याय का द्योतक मानते हैं। व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन करना इनका मुख्य उद्देश्य है।

अराजकतावादी धर्म विरोधी है। इनके अनुसार धर्म मनुष्य को अकर्मण्य अन्धविश्वासों एवं भाग्यवादी बना देता है। धर्म के आधार पर मनुष्य में कायरता आ जाती है और वह सामाजिक अन्याय को सहन करने लगता है। समय-समय पर शासक वर्ग ने भी धर्म के नाम पर जनता का शोषण किया है। धर्म अन्यायपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को पुष्टि करने में शासक वर्ग का सहायक होता है। गॉडविन के अनुसार व्यवस्था और स्वतन्त्रता के दो ही शत्रु हैं, प्रथम राज्य, तथा द्वितीय ईश्वर।¹²

प्रद्यो ने चर्च को ग्याय का शत्रु कहा है। उसे ईश्वर में नहीं मानवता में विश्वास था। प्रद्यो ने अपनी पुस्तक—System of Economic Contradiction—में ईश्वर, धर्म और नैतिकता पर एक व्यापक अध्याय लिखा है। इसमें प्रद्यो ने लिखा है कि—

ईश्वर में विश्वास करना बेवकूफी और कायरता है, ईश्वर डोग एवं झूठ है, ईश्वर अत्याचार और विपत्ति है; ईश्वर अशुभ है।¹³

अराजकतावादियों के राज्य सम्बन्धी विचार (8)

राज्य समाज में अन्याय के समस्त कारणों जैसे सम्पत्ति, धर्म, पूंजीवादी व्यवस्था, नियन्त्रण, शक्ति आदि को आश्रय देने वाली प्रमुख संस्था है। अराजकतावादी राज्य विरोधी है और राज्य को अवांछित एवं अनावश्यक मानते हैं। राज्य विरोध के अराजकतावादियों ने निम्नलिखित तर्क दिये हैं:—

(i) राज्य समाज की विपमताओं तथा अन्याय की निरन्तर वृद्धि के लिये उत्तरदायी है।

(ii) वर्तमान राज्य का कुछ व्यक्तियों द्वारा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य उन एकाधिकारों का उन्मूलन नहीं कर सकता जिनकी वह रक्षा करता है। इस प्रकार जब तक राज्य का स्थान कोई अन्य व्यवस्था नहीं लेती, इन निहित-शक्तियों का अन्त नहीं हो सकता। बाबुनिन के अनुसार राज्य का प्रथम आवश्यक और अत्यन्तवादी कार्य सम्पत्ति कानूनों का निर्माण करना था, जिमसे शोषण करने वालों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर कानूनी रूप देना था।¹⁴

12. Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political Thought, p 433.

13. "God is stupidity and cowardice; God is hypocrisy and falsehood; God is tyranny and misery; God is evil"

Quoted by Bosc, A., A History of Anarchism, p 140.

14. Bosc, A., A History of Anarchism, p 180

- (iii) राज्य शक्ति का प्रतीक है ।
- (iv) ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो राज्य करता है तथा जिसे राज्य के अस्तित्व के बिना न किया जा सके । विदेशी आक्रमणों का सामना करने के लिये सेना की आवश्यकता नहीं है । राज्य की स्थाई सेनाएँ भी आक्रमणकारियों द्वारा परास्त हो जाती हैं । लेकिन जन-सेनाओं न जिनका संगठन राज्य द्वारा नहीं किया गया है आक्रमणों का मफरतापूर्वक सामना किया है । इस प्रकार रक्षा कार्य एक नागरिक सेना सुरक्षा द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है ।
- (v) आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था के लिये भी राज्य की आवश्यकता नहीं है । वातून, पुलिस, न्याय, दंड आदि की राज्य जो व्यवस्था करता है उससे अपराधों में वृद्धि है ।
- (vi) कला, शिक्षान, शैक्षणिक कार्यों के लिये भी राज्य की आवश्यकता नहीं है । समाज में बहुत सा शैक्षणिक कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है । शिक्षा के लिए राज्य की नहीं किन्तु ऐसी संस्थाएँ एवं विद्वत् परिपदों की आवश्यकता है जो शिक्षा कार्य में सफल हो । रॉयल सोसायटी, ब्रिटिश ऐसोसियेशन जैसी संस्थाएँ जो राज्य की भ्रंति शक्ति पर नहीं बल्कि स्वतंत्र महयोग पर निर्भर हैं, राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं से भी अच्छा कार्य किया है ।

शासन का विरोध 7

राज्य का समस्त कार्य सरकार द्वारा संचालित होता है । सरकार का संगठन उन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में रहता है जो हमेशा राज्य सत्ता को अपने हाथों में रखना चाहते हैं । अराजकतावादियों के अनुसार किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली सामाजिक कुरोतिया को दूर करने में असफल रही है । शासन सत्ता का प्रतीक होता है । सच्चा व्यक्ति को स्वार्थी, घमण्डी अत्याचारी और घ्राट कर देती है । "राजनीतिज्ञ अपने स्वभाव के कारण नहीं अपितु अपने पद के कारण दुष्ट हैं, इस कारण नहीं कि वह मनुष्य हैं परन्तु क्योंकि वह राजनीतिज्ञ हैं ।" इसी बात को ओपॉटकिन ने दूसरे शब्दों में कहा कि 'वह या वह मंत्री श्रेष्ठ मनुष्य होता यदि उसे सत्ता न दो गई होती ।'¹⁵ इस प्रकार अराजकतावादी सत्ता को मनुष्य के धनुर्मुखी पतन का कारण मानते हैं । 'डिविन्मन के अनुसार "सरकार का अर्थ धांधला, बजनशीलता, असतोष तथा पशुकृता है ।" किसी भी रूप, म, पक्ष, व्यक्ति, धर्म, लक्ष्य, व्यक्ति, पर, पणस्त, करने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

राज्य और शासन का अराजकतावादिया द्वारा इतना तीव्र विरोध है कि वे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं । अधिक

क्षेत्र में किसी प्रकार की शासन प्रणाली प्रत्येक व्यक्ति के अनुपातिक भाग का न्यायोचित निर्धारण करने में सफल नहीं हुई है। इनके अनुसार अभी तक समस्त शासनों का मुख्य कार्य यही रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग न्यायोचित न हो। इस अन्यायपूर्ण तथ्य को चुनौती देते हुए शोपांटकिन ने कहा है—

“सब कुछ प्रत्येक का है। यदि प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष तथा स्त्री, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में भाग लेता है तो उसका यह अधिकार है कि समस्त उत्पादित वस्तुओं में से, जिनका उत्पादन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया है, अपना भाग ले।”¹⁶

प्रतिनिधि शासन का विरोध

B-159
293

भराजकतावादियों ने प्रतिनिधि शासन की सबसे कटु आलोचना की है। वैसे सामान्यतः प्रतिनिधि सरकार ही सबसे उपयुक्त व्यवस्था है लेकिन व्यवहार में यह सत्य नहीं है क्योंकि—

- (i) शासन व्यवस्था में सारा का सारा कार्य बहुमत-सिद्धान्त के आधार पर चलाया जाता है। प्रतिनिधि सभाओं में बहुमत या एकमत प्राप्त करना सदैव फर्जी और बनावटी होता है। एक बार किनी बात पर निर्णय से लिया जाता है तो अल्पमत को उसे कार्यन्वित करने के लिये समर्पण करना पड़ता है। यह बहुमत के अन्याय और अल्पमत की युद्धिहीनता प्रदर्शित करती है।¹⁷
- (ii) विचार विभिन्नता के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।
- (iii) सरकार चलाने के लिये प्रतिनिधियों में जितना ज्ञान होना चाहिये उनमें नहीं होता। इसलिये प्रतिनिधि शासन उन व्यक्तियों द्वारा शासन है जो शासन के विषय में केवल इतना ही ज्ञान रखते हैं जिससे उनकी प्रयोग्यता ही प्रदर्शित होती है।
- (iv) यह शासन व्यवस्था उस वर्ग को जन्म देती है जिन्हें हम 'पेशेवर राजनीतिज्ञ' (professional politicians) कहते हैं। ये अपनी पज्ञानता और दुर्बलताओं को बाबालता अथवा भाडम्बर से छुपाये रहते हैं।
- (v) भराजकतावादो विन्ही भी परिस्थितियों में जनप्रतिनिधि की आवश्यकता ही स्वीकार नहीं करते। राज्य द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक प्रश्न पर जनता की इच्छाएँ, मान्यताएँ अलग-अलग होती हैं। महत्वपूर्ण

¹⁶ जोड., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 105.

¹⁷ G. J. A. In, An Enquiry Concerning Political Justice etc., pp. 570-71.

विषयो पर जनमत जानने के लिये अपने निर्वाचको की सभा बुलाई होगी जिसमें वाद-विवाद के पश्चात् अपने सकल्प या निर्णय करेंगे। लेकिन जब इस प्रकार की सभाओं की आवश्यकता होगी तो फिर जन-प्रतिनिधि की आवश्यकता का सवाल ही नहीं उठता।

सूक्ष्म में, अराजकतावादी प्रतिनिधि शासन को अयोग्य, अज्ञानियों की व्यवस्था मानने के साथ साथ इसे अनायश्यक भी मानते हैं।¹⁸

विकेन्द्री व्यवस्था 9

अराजकतावादी विचारधारा विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त पर आधारित है। प्रोफेसर जोड का कथन है कि 'आधुनिक सभ्यतावादी में अराजकतावाद का प्रथम तथा प्रधान उद्देश्य क्षेत्रीय तथा व्यावसायिक विकेन्द्रीकरण है।'¹⁹ अराजकतावादी समाज का प्रारम्भ स्थानीय छोटे-छोटे समूहों से होगा। स्थानीय समूह बड़े समूहों में संगठित एवं केन्द्रित किये जा सकते हैं, जिनका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण देश पर हो। यह समूहीकरण ऊपर से नहीं किन्तु नीचे से ऊपर की ओर होगा। अराजकतावादियों की विश्वास है कि स्वेच्छापूर्ण आधार पर संगठित समाज में झगड़ें नहीं होंगी। जो भी मतभेद होंगे वे मित्रता तथा सहकारिता की भावना से सुलभ जायेंगे।

अराजकतावादी उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन 10-

अराजकतावादी स्वेच्छापूर्ण सामाजिक संगठन के लिये वर्ग, राज्य, सम्पत्ति धर्म आदि का उन्मूलन आवश्यक मानते हैं। लेकिन इन उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन क्या हों? इस सम्बन्ध में अराजकतावादियों में मतभेद है। व्यापक रूप से साधन के आधार पर उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वे अराजकतावादी जो विनासवादी, शान्तिपूर्ण साधनों तथा हृदय-परिवर्तन द्वारा अपने उद्देश्यों की उपलब्धि करना चाहते हैं। द्वितीय श्रेणी में क्रान्तिवादी भातकवादी आदि अराजकतावादी आते हैं।

गॉडविन तथा व्यक्तिवादी अराजकतावादी शान्तिपूर्ण साधनों में विश्वास करते हैं। वारेन, स्टर्नर आदि विकासवादी थे। डेविड थोरो ने शान्तिपूर्ण किन्तु सक्रिय प्रवृत्ता आन्दोलन जैसे साधनों का सुभाव दिया जिसके द्वारा अमरीकी सरकार को वास्तव में उन्मूलन के लिये बाध्य किया जा सके। गॉडविन का क्रान्ति में कोई विश्वास नहीं था। फ्रांस की क्रान्ति के सन्दर्भ में अराजकतावादी साधनों की व्याख्या करते हुए गॉडविन ने कहा था —

18. अराजकतावादियों द्वारा प्रतिनिधि सरकार की आलोचना के लिये देखिये— जोड, आधुनिक राजनीति का सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ० 107-108.

19. उपर्युक्त, पृ० 112

"झीने भीड़ भागल, रिमा तथा यह आवेग जिनमे मनुष्य अनेकों में एकत्रित हो जाते हैं, की वल भर के लिये भी निन्दा करना बन्द नहीं रिया। मैं इस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन चाहता हूँ जो ममभरारी तथा हृदय की उदार भावनाओं में विरगित हों।" 20

इस प्रकार गाँडविन तथा टॉलस्टॉय जैसे धरातलतावादी बल-बद्धति के शब्द हैं। उनके मतानुसार अच्छे साधनों की प्राप्ति अच्छे साधनों के माध्यम से होनी चाहिये।

साधुतिन तथा त्रांसाटिफिन ज्ञानिकारी साधनों के समर्थक हैं। वास्तुनिन कार्य विमय का प्रतिबिम्ब देगने हैं। विश्व निम्नर परिश्रमशील होना रहना है। जलिये कार्य द्वारा परिवर्तन प्राकृतिक है। इसी प्रकार त्रांसाटिफिन का विचार वा के धरातलतावादी-माम्यवाद की स्थापना सिर्फ ज्ञानि द्वारा ही सम्भव है। ये मानते हैं कि राज्य, पूँजीवादी व्यवस्था, व्यक्तिगत सम्पत्ति, धर्म आदि संस्थाओं के समाप्त में इतनी गहरी एव सजकून जड़े हैं कि बिना ज्ञाति के इन्हें समाप्त करना सम्भव नहीं है। त्रांसाटिफिन ने तो इस की ज्ञानि (1917) का भी समर्थन किया है। ज्ञानिक उर्दे बाद में इगता पहुँचावा करना पड़ा। ज्ञानि तथा माम्यवाद के समर्थक होने के कारण उन्हें धरातलतावादी-माम्यवादी कहा जाता है।

इसी प्रकार इस के भूम्यवादी, श्वेत के धरातलता-विन्डीकनवादी तथा अन्य धरातलतावादी सोड-बोड, हृदताई, विरोधियों का बध करना तथा आतंक केवाना आदि साधनों में भी विश्वास करते थे।

धरातलतावाद और मार्सवाद-माम्यवाद

धरातलतावाद और मार्सवाद-माम्यवाद का जब हम अध्ययन करते हैं तो ज्ञान दोनों में सामान्यतः बहुत कुछ बातें समान प्रतीत होती हैं। ये दोनों विचार-संसार एव दूसरे में प्रतिबिम्बित होते हुए प्रतीत होती हैं। वास्तव में कुछ धरातलतावादी विचारकों ने बाले मार्ग के विचारों को प्रभावित किया और बाद के धरातलतावादी मार्सवादी-माम्यवादी विचारधारा में प्रभावित हुए। टॉलस्टॉय एवं रीन ने धरातलतावाद की मार्सवादी विचारधारा का ही विस्तार किया है। इसी ज्ञाति के भी विचार समर्थक ऐसे हैं।

20. "I never for a moment ceased to disapprove of mob government and violence, and the impulses which men collected together in multitudes produce on each other. I desired such political changes only as should flow purely from the clear light of the understanding and the erect and generous feeling of the heart."

Brown, Ford K., *Life of William Godwin*, London, 1926, p. 35.

21. "A further development of Marxist ideology is anarchism."
Killer and Ross, *Western Social Thought*, p. 216.

अराजकतावाद तथा माक्सवाद एव साम्यवाद के सम्बन्धों और सघर्षों का इतिहास भी बड़ा रोचक है जो इनकी समानता एव भिन्नता को व्यक्त करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता कि अराजकतावादियों का विचार सघर्ष माक्स से प्रारम्भ होकर लगभग स्टालिन तक चलता रहा।

प्रधों तथा माक्स

माक्स और प्रधों का मिलन 1844 में पेरिस में हुआ। ये दोनों एक दूसरे के सम्पर्क में आये तथा दोनों एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए। माक्स ने अपनी पुस्तक—Holy Family—जो 1845 में प्रकाशित हुई, में प्रधों के सम्पत्ति सम्बन्धी विचारों की सराहना की तथा उन्हें वैज्ञानिक विवेचन और राजनीतिक अर्थ व्यवस्था को सर्वप्रथम क्रान्तिकारी ढंग से प्रस्तुत करने वाला बतलाया। माक्स ने प्रधों से अपने अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन को सामूहिक रूप से संचालन करने के लिये भी आग्रह किया। किन्तु प्रधों माक्स के क्रान्तिवादी विचारों से सहमत नहीं था। इसलिये इन दोनों में मतभेद प्रारम्भ हुए।²²

1848 में प्रधों की पुस्तक—Philosophy of Poverty—प्रकाशित हुई तथा इसके प्रत्युत्तर में माक्स ने—Poverty of philosophy—लिखी। इसने एक विचार सघर्ष का रूप धारण कर लिया। माक्स ने प्रधों की तीव्र आलोचना की तथा उसे एक छोटा मोटा पूँजीपति बतलाया जो श्रमिकों को भुलावे में रखना चाहता था। साम्यवादी घोषणा पत्र (The Manifesto of the Communist Party) में भी माक्स-एन्जिल्स ने प्रधों पर प्रहार किया तथा उसे आदि से घबराने वाला मध्यवर्गीय, अनुदार समाजवादी (Conservative or Bourgeois Socialist) कहा।²³

प्रधों ने अपनी आलोचना का सिर्फ यही उत्तर दिया कि “माक्स को यही दुःख है कि प्रत्येक जगह मेरे और माक्स के विचार मेल खाते हैं किन्तु मैंने उन्हें माक्स से पहिले व्यक्त कर दिया है। सत्य यह है कि माक्स ईर्ष्यालु है।”²⁴

माक्स तथा प्रधों के इस विचार-सघर्ष के विषय में वास्तविकता यह है कि दोनों ही हीगल के द्वन्द्ववाद से प्रभावित हुए हैं। दोनों ही पूँजीवाद को शक्तिहीन स्वीकार करते हैं। माक्स ने प्रधों के उन विचारों को ग्रहण किया है जिनकी उसने आलोचना की है। किन्तु प्रधों क्रान्ति साधन में विश्वास नहीं करता था। यही माक्स तथा अराजकतावादी विचारों में एकता होने हुए भी विचार भिन्नता है।

22 Bose, A., History of Anarchism, p 141-42

23 The Communist Manifesto, pp 87-88

24 ‘The real sense of Marx is that he regrets everywhere that my thought agrees with his and that I have expressed it before him. The truth is that Marx is jealous’

Quoted by Bose, A., History of Anarchism, p 144

मार्क्स तथा बाकुनिन

1843 से बाकुनिन ने अपने निर्वासित जीवन के लगभग चार वर्ष फ्रांस में बिताये। यहाँ बड़े प्रघों तथा मार्क्स के सम्पर्क में आया और दोनों के विचारों से प्रभावित हुआ। मार्क्स तथा प्रघों के विचार मतभेदों का उन तक ही अन्त नहीं हो गया। प्रघों का स्थान बाकुनिन ने लिया। मार्क्स तथा बाकुनिन का विचार संघर्ष लगभग पन्चीस वर्ष तक चला।²⁵

प्रारम्भ में बाकुनिन मार्क्स का प्रशंसक था तथा मार्क्स को मजिद सभाजवादी एवं अग्रणीय धर्मशास्त्री बतलाया। यही नहीं बाकुनिन ने साम्यवादी घोषणा पत्र का हसी अनुवाद भी किया। इन दोनों के विचार प्रारम्भ में मिलते जुलते थे। जैसे दोनों ही:

- (i) शान्तिवारिषों की तरह पूर्ण आजावादी थे;
- (ii) हीगल के द्वन्द्ववाद में श्रद्धा रखते थे;
- (iii) तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के आलोचक थे; तथा
- (iv) प्रतिनिधि शासन में विश्वास नहीं रखते थे।

किन्तु धीरे-धीरे बाकुनिन का मार्क्स के प्रति दृष्टिकोण घृणात्मक होता चला गया। उनके मतभेद व्यक्तिगत तथा सैद्धान्तिक दोनों रूप में स्पष्ट रूप से उभर आये। बाकुनिन मार्क्स (साथ में ऐन्गिल्स को भी) को एक जर्मन, एक यहूदी तथा एक साम्यवादी के रूप में धृणा करने लगा, जबकि मार्क्स ने बाकुनिन को रूस का गुप्तचर कहकर प्रभुत्तर दिया।

मार्क्स तथा बाकुनिन के सैद्धान्तिक मतभेद बड़े व्यापक थे। ये मतभेद मूलतः निम्नलिखित थे:—

- (i) साम्यवादी व्यवस्था स्वतन्त्रता की विरोधी हैं। बाकुनिन मानव की बिना स्वतन्त्रता के कल्पना ही नहीं कर सकता।
- (ii) साम्यवादी जो कुछ भी करते हैं अन्ततः इससे राज्य की शक्ति में ही वृद्धि होती है। बाकुनिन न केवल राज्य किन्तु सत्ता के सभी अवशेषों को समाप्त करना चाहते थे।
- (iii) साम्यवादी समाज को ऊपर की ओर से व्यवस्थित करना चाहते हैं जबकि बाकुनिन ऐसे समाज की स्थापना चाहते थे जिसका संगठन स्वतन्त्रतापूर्वक नीचे से ऊपर की ओर हो। इस प्रक्रिया में सत्ता तथा शक्ति का कोई योगदान न हो।
- (iv) मार्क्स का संबंधूरा वर्ग में अमीम विश्वास था। बाकुनिन ने मार्क्स की आलोचना की कि उसने कृषक वर्ग की पूर्ण अज्ञानता की है।

(v) मार्क्सवाद में सर्वहारा अधिनायकत्व को सम्पूर्ण काल के लिए स्वीकार किया जाता है। बाकुनिन इस अधिनायकवाद के विरोधी हैं।²⁶

बाकुनिन ने मार्क्सवाद-साम्यवाद में अपने मतभेदों को शान्ति एवं स्वतन्त्रता लीग के अधिवेशन (1868) में व्यक्त किया।

प्रोपोटकिन (Peter Kropotkin) ने मार्क्स तथा बाकुनिन के मतभेदों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि वह वास्तव से सधात्मक तथा केन्द्रीकरण सिद्धान्तों, स्वतन्त्र कम्प्यून तथा राज्य का शासन के मध्य था।²⁷ काल मार्क्स तथा बाकुनिन के मतभेदों का मूल्यांकन किया जाय तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि इन दोनों में उत्तरे सैद्धान्तिक मतभेद नहीं थे जितने कि इन सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने में। बाकुनिन की अपेक्षा मार्क्सवाद व्यवहार में अधिक सत्ताधारी, अधिनायकवादी, स्वतन्त्रता विरोधी तथा राज्य का प्रबल समर्थक सिद्ध होगा।

प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय (First International)

मार्क्सवाद तथा धराजकतावाद के संघर्ष की चरम सीमा

अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए मार्क्स के प्रयत्नों से 1864 में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर परिषद् की स्थापना हुई। यह धर्मिक मान्यताओं एवं विचार विनिमय का प्रमुख फोरम था। बाद में इस परिषद् का नाम 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर सभ (First International)' रख दिया गया।

1868 में बाकुनिन ने अपने एक सगठन 'शान्ति एवं स्वतन्त्रता लीग' (League of Peace and Freedom) को भंग कर दिया तथा इसके स्थान पर 'सामाजिक लोकतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय सभ' (International Alliance of Social Democracy) की स्थापना की।

अगले वर्ष बाकुनिन मार्क्स के नेतृत्व में गठित 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' में सम्मिलित हुआ। बाकुनिन का उद्देश्य 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' को अपने नेतृत्व के अन्तर्गत लेना था। परिणामस्वरूप मार्क्सवादियों तथा धराजकतावादियों के मध्य इस सगठन के नेतृत्व की लेकर संघर्ष प्रारम्भ हुआ। बाकुनिन तथा मार्क्स में सैद्धान्तिक मतभेद तो थे ही। 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' में बाकुनिन ने मार्क्स तथा उसके समर्थकों की बड़ी निन्दा की। बाकुनिन के अनुसार मार्क्स 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' को एक दानव राज्य में परिवर्तित करना चाहते थे, जिसमें एक ही विचारधारा, एक ही सत्ता हो। मार्क्स इस सगठन के माध्यम से एक जर्मन राज्य (Pan-German State) की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे।²⁸

26 Carr, E. H., Michael Bakunin, London, 1937, p. 341

27 Bose A., A History of Anarchism, p. 209

28 Kenafick, Marxism, Freedom and the state, p. 45

‘प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय’ मे मार्क्स के समर्थक अधिक संख्या मे थे, वे बाकुनिन एव अराजकतावादियों के विचारों से बिलकुल सहमत नहीं थे। इसलिए 1872 मे ‘प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय’ के हेग अधिवेशन (Hague Congress) मे बाकुनिन तथा उसके अनुयायियों को निकाल दिया गया। यहाँ मार्क्सवादी तथा अराजकतावादियों का पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद हो गया।

पीटर क्रोपॉटकिन (Peter Alexander Kropotkin) ने अराजकतावाद को वर्ग-संगत तथा वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में अराजकतावाद और साम्यवाद मे अन्तर कम होता चला गया। कहीं-कहीं तो यह कहना असम्भव हो गया कि क्रोपॉटकिन अराजकतावादी है या साम्यवादी। इसलिए वह अराजकतावादी साम्यवादी कहलाता है। ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका (Encyclopaedia Britannica) मे अराजकतावाद के विषय मे दिए गए एक लेख मे क्रोपॉटकिन ने लिखा है:—

“शाश्वत रूप मे साम्यवाद की स्थापना अधिक सम्भव है विशेषतः जिस प्रकार कम्प्यून प्रगति कर रहे हैं, स्वतन्त्र या अराजकतावादी साम्यवाद ही वह साम्यवादी व्यवस्था है जिसे सभ्य समाज द्वारा स्वीकार किये जाने की अधिक सम्भावना है; इसलिए साम्यवाद एव अराजकतावाद विकास के दो पहलू हैं जो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं तथा एक दूसरे को सम्भव और स्वीकार योग्य बनाते हैं।” 29

यहाँ क्रोपॉटकिन के विचारों को व्यक्त करने का यही उद्देश्य है कि अराजकतावाद तथा मार्क्सवाद एवं साम्यवाद वहाँ तक एक दूसरे से सम्बन्धित हो गये। किन्तु इतना सब होते हुए भी इन दोनों विचारधाराओं का पूर्ण संगम नहीं हो पाया। जोड (C.E M. Joad) के विचार

जोड के अनुसार अराजकतावाद और साम्यवाद में राज्य के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होते हुए भी दोनों विचारधाराएँ एक ही वस्तु के दो पक्षों को प्रस्तुत करती हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुस्तक—Introduction to Modern Political Theory—के पाचवे अध्याय में साम्यवाद और अराजकतावाद का साथ-साथ विवेचन किया है। इन दोनों मे बहुत कुछ बातें समान हैं तथा इनके प्रमुख सिद्धान्त एक दूसरे के पूरक हैं। साम्यवाद एक ही विचारधारा की ‘पद्धति का दर्शन’ तथा अराजकतावाद उसके बाद ‘भ्रातृता समाज का उद्देश्य’ है। एक साधन तथा दूसरा साध्य के रूप में महत्वपूर्ण है। जोड के ही शब्दों में—

“प्रारम्भिक मतभेदों के होने पर भी आधुनिक घटना-क्रम के विवास ने इन दो विचारधाराओं को घनिष्ट रूप से सम्बन्धित कर दिया है। इसी

29. Quoted by Bosc, A., A History of Anarchism, p. 262.

बोल्शेविकी (Bolsheviks) के प्रभाव के कारण साम्यवाद विशिष्ट पद्धति का दर्शन बन गया अर्थात्, यह उस कार्यक्रम का सिद्धान्त है जिसके अनुसार पूँजीवाद से समाजवाद की ओर परिवर्तन होगा। अराजकतावाद उन सिद्धान्तों की घोषणा करता है, जो इस परिवर्तन के उपरान्त समाज में लागू होंगे।³⁰

जोड ने आगे लिखा है—

“अराजकतावादियों का सम्बन्ध केवल एक आदर्श समाज जिसकी वे स्थापना करना चाहते हैं और एक जीवन मार्ग से है। परन्तु साम्यवादियों को मुख्य समस्या यह है कि इस आदर्श समाज की स्थापना किस प्रकार की जाय तथा जीवन का यह आदर्श दृग किस प्रकार हरेक के लिये सम्भव बना दिया जाय। अर्थात् साम्यवादी साधनों पर विचार करते हैं तथा अराजकतावादी साधनों पर। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अब अधिकांश साम्यवादी समाज के अराजकतावादी आदर्श को स्वीकार करते हैं और अनेक अराजकतावादी यह मानने की तत्पर होगे कि इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था केवल साम्यवादी कार्यक्रम द्वारा ही सम्भव है।”³¹

उपर्युक्त अध्ययन में यह स्पष्ट है कि ये दोनों विचारधाराएँ सिद्धान्तिक दृष्टि से बहुत कुछ समानान्तर चलती हैं फिर भी दोनों में ताल-मेल स्थापित नहीं हो सका है। य अभी तक अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। वैसे अराजकतावाद तो मूल मूल ही है। अराजकतावाद तथा माक्सवाद (तथा साम्यवाद भी) में जो समानताएँ तथा भिन्नताएँ हैं उनका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

अराजकतावाद तथा माक्सवाद में समानताएँ—

- (i) दोनों ही उस समय प्रचलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दोषों की निन्दा करते हैं।
- (ii) दोनों ही पूँजीवादी व्यवस्था पर आधारित शोषण का विरोध करते हैं।
- (iii) दोनों विचारधाराएँ व्यक्तिगत मुक्ति की बड़ आलोचक हैं।
- (iv) अराजकतावाद तथा साम्यवाद माक्सवाद दोनों का एक ही उद्देश्य है—
वर्षहीन तथा राज्यविहीन समाज की स्थापना करना।

अराजकतावाद तथा माक्सवाद-साम्यवाद में अन्तर

इन विचारधाराओं में यह भ्रमणता वास्तव में सिर्फ बाह्य ही है। इनके मध्य निम्नलिखित तात्त्विक, अन्तरिक तथा सिद्धान्तों को व्यवहार में परिवर्तित करने के परिणामों में इतने मतभेद हैं कि इनके मध्य की खाई को भरना सम्भव नहीं है—

³⁰ जोड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका पृ 60-61.

³¹ साम्यवाद, पृ 101.

मानव स्वभाव—मानव स्वभाव, न्याय तथा नैतिकता के विषय में दोनों विचारधाराओं का विवेचन भिन्न है। साम्यवादियों के अनुसार न्याय और नैतिकता के कोई नियम या सिद्धान्त नहीं होते, वे देश एवं काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। मानव स्वभाव में स्थायित्व जैसी कोई बात नहीं होती उसमें वातावरण के अनुसार गुणात्मक परिवर्तन होता रहता है।

इसके विपरीत भराजकतावादी मानव स्वभाव के कुछ स्थाई तत्वों जैसे सहयोग, सहानुभूति तथा न्याय की भावना आदि में पूर्ण आस्था रखते हैं। उनके अनुसार ये तत्व मनुष्य के स्वभाव में निहित हैं तथा समाज के विकास की कुंजी हैं। भराजकतावादियों की विचारधारा मूलतः मनुष्य के उत्तम स्वभाव पर निर्भर है।

② समाज एवं व्यक्ति—साम्यवाद का आधार समाज है। वे व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्राथमिकता देते हैं भराजकतावाद का आधार व्यक्ति है। उनकी व्यवस्था में व्यक्ति को नहीं जाता। वे जो भी सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं उसका उद्देश्य व्यवस्था के साथ व्यक्ति का उत्थान है।

③ अधिनायकतावाद बनाम स्वतन्त्रता—मार्क्सवाद-साम्यवाद अधिनायकवाद में विश्वास करता है। किन्तु अधिनायकवाद, शक्ति तथा सत्ता का विरोध भराजकतावादियों का मूल मन्त्र है। वे व्यक्ति-स्वतन्त्रता को ऊँचा स्थान देते हैं और इस बात पर निर्भर रहते हैं कि वह सदा और सर्वत्र प्रभावकारी हो सकेगी। उनका विश्वास है कि एक समाजवादी समाज का उस समय तक प्रगति की ओर कदम नहीं सनभा जा सकता जब तक कि उसके आधार के रूप में बल-प्रयोग के स्थान पर स्वतन्त्रता प्रतिष्ठित न हो जाय।³²

④ मानववाद—भराजकतावादियों का दृष्टिकोण मानवतावादी है। वे जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसकी मपील मानव मात्र के लिये है। वे सभी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आह्वान करते हैं। साम्यवाद सर्वहारा का दर्शन है। साम्यवाद का मानवतावादी दृष्टिकोण सिर्फ सर्वहारा वर्ग तक ही सीमित है।

⑤ उद्योग—साम्यवादी आर्थिक प्रगति के लिये विशाल उद्योगों में विश्वास करते हैं। लेनिन के अनुसार साम्यवाद का अर्थ 'लोहा तथा बिजली' था। इस समय साम्यवादी राज्यों की प्राप्ति भारी उद्योगों पर ही आधारित है। किन्तु भराजकतावादी बड़े उद्योगों के विरोधी हैं। वे सप्ट उद्योगों का समर्थन करते हैं।

⑥ सत्ता—साम्यवादी गमस्त सत्ता के केन्द्रीकरण में विश्वास रखते हैं। प्रत्येक कार्य राज्य द्वारा होना चाहिये। इसके विपरीत भराजकतावादी सत्ता के पूर्ण विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद—मार्क्सवाद की सैद्धान्तिक विवेचना का मूल स्तम्भ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है जो उनके भौतिकवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। परन्तु अराजकतावादी इस प्रकार के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद में विश्वास नहीं करते, वे इसे तार्किक शीर्षमिन की सजा देते हैं।

साधन—मार्क्सवादी—साम्यवादी श्रान्ति में विश्वास करते हैं, वे हिंसा, दमन आदि के प्रयोग के बिना पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन न हो सकने की बात बहते हैं। शक्ति प्रयोग सत्ता हथियाने के लिए आवश्यक है। हालांकि अराजकतावादियों में अपने साध्या की प्राप्ति से विषय में मतभेद हैं, लेकिन प्रत्येक अराजकतावादी—व्यक्तिवादी अथवा साम्यवादी दोनों ही—या तो शक्तिपूर्ण साधनों में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करते या शक्ति प्रयोग को स्थाई साधन नहीं मानते। अराजकतावादियों के द्विचार में "हिंसा केवल रक्षा के लिए, सत्ता के संगठित विरोध के लिए एक उचित हथियार है, वह सहयोग का साधन नहीं है और, न वह एक सच्ची समाजवादी व्यवस्था में कार्य करने का साधन ही है। जब हिंसा को एक समस्या का रूप दिया जाता है, तो वह किसी के लिए भी स्वतन्त्रता प्राप्ति का साधन नहीं रह जाता।"³³

प्रारम्भ में क्रोपोटकिन तथा अन्य अराजकतावादी 1917 में रूसी श्रान्ति को समर्थन देते हुए प्रतीत होते हैं। उसकी धारणा थी कि इसके बाद राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना सम्भव हो सकेगी। लेकिन श्रान्ति के बाद रूस की दशा देखकर अराजकतावादियों का भ्रम दूर हो गया। लेनिन को लिखे गये एक पत्र में³⁴ क्रोपोटकिन ने रूस में हिंसा, दमन-चक्र की कटु निन्दा की। उन्हें रूस में केन्द्रीकरण, दोषान्वेषण और सर्वत्र आतंक ही नजर आया। इस प्रकार श्रान्तिकारी अराजकतावादी भी हिंसात्मक साधनों से विमुख हो गये। उनका विश्वास था कि स्वतन्त्र समाज की स्थापना इस प्रकार नहीं हो सकती। प्रसिद्ध अराजकतावादी एमा गोल्डमैन (Emma Goldman) के अनुसार कोई भी श्रान्ति मुक्ति-साधन के रूप में उस समय तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसकी प्राप्ति के साधन, भावना तथा प्रवृत्ति उन उद्देश्यों के समान न हो जिन्हें प्राप्त करना है।³⁵

१) वर्ग-उन्मूलन—अराजकतावादी तथा मार्क्सवादी जिस प्रकार वर्गों का उन्मूलन करना चाहते हैं इसमें वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं या, जिस प्रकार के वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं उस सम्बन्ध में इन दोनों के विचारों में प्राक्काश पाताल का अन्तर है। कोकर के अनुसार—

समाजवादी लोग, विशेष रूप से रूसी साम्यवादी केवल वर्गीय अधिनायकत्व में परिवर्तन चाहते हैं, वे विरोधी वर्गों की स्थिति को इस

33 कोकर., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 23-35

34 Quoted by Bose, A., A History of Anarchism, p 285-96

35 Goldman, Emma, My Further Disillusionment in Russia, 1924, p 175

प्रकार उलट देना चाहते हैं कि कल का सेवक यमं धाज का शासक बन जाय, और उन्हें विश्वास है कि इस प्रकार भविष्य में एक यमं विहीन समाज की स्थापना हो जायगी। दूसरी ओर, धराजयतावादी लोग सामाजिक व्यवस्था के सिद्धान्तों को एकदम उलट देना चाहते हैं, जिससे समाज में दमन के स्थान पर पारस्परिक सहयोग की स्थापना हो सके।³⁶

इस प्रकार साम्यवादी यमं-समर्पण के द्वारा तथा धराजयतावादी सहयोग, सहनशीलता के साधन पर अन्तिम लक्ष्यो की उपलब्धि करना चाहते हैं।

सर्वहारा अधिनायकत्व

धराजयतावादियों तथा रूस के समाजवादियों का लक्ष्य एक ही है सर्वोत्तम यमं विहीन तथा राज्य-विहीन समाज की स्थापना। निम्न उनके मार्ग बिलकुल अलग-अलग हैं। हमी समाजवादी यह मानते हैं कि क्रान्ति के बाद स्थापित सर्वहारा अधिनायकत्व में सम्पूर्ण मार्ग को नहीं स्थापना जा सकता। दूसरी ओर धराजयतावादी यह मानते हैं कि दमन तथा नियन्त्रण द्वारा स्वतन्त्र और ऐच्छिक सहयोग के सिद्धान्त पर साधारण समाज की स्थापना नहीं हो सकती। लेनिन के ही शब्दों में—

“हमारा धराजयतावादियों से अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य के विनाश के प्रश्न पर मतभेद नहीं निम्न मार्गवाद धराजयतावाद से इस बात में भिन्न है कि यह सामान्यतया क्रान्ति काल में तथा विशेषतः पूँजीवाद से समाजवाद की ओर अग्रसर होने के संक्रमणकाल में राज्य तथा राज्य की शक्ति की आवश्यकता मानता है।³⁷”

धराजयतावादी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि दीर्घकालीन दमनकारी पूँजीवादी शासन का अन्त सर्वहारा अधिनायकत्व के दीर्घकालीन दमनकारी शासन से हो सकेगा। उनके अनुसार संक्रमण-कालीन समाज व्यवस्था और उसके स्थान पर स्थापित की जाने वाली स्थाई समाज व्यवस्था में साम्य होना चाहिए।

अन्त में, राज्य की समाप्ति के बाद समाज की सारी व्यवस्था क्या होगा इस सम्बन्ध में धराजयतावादी हमारे सामने एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। निम्न साम्यवादियों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया।

धराजयतावाद का मूल्यांकन

पूर्ण अन्वयन का अभाव (1)

धराजयतावाद की यह प्रारम्भिक धारणा की जाती है कि यह विचार-धारा पूर्ण अन्वयन नहीं है। इस विचारधारा का कोई इतिहासकार भी नहीं

36. बोहर, साम्यवाद राजनीतिक विज्ञान, पृ. 224.

37. Lenin, State and Revolution, 1917, p 63.

है। पोल एल्टज़बेकर (Paul Eltzbacher) ने अपनी पुस्तक 'डेर एनेरकिमम' (Der Anarchismus)³⁸ में प्रमुख अराजकतावादियों का निष्पक्ष विमोचन किया है किन्तु यह भी अराजकतावाद का एकरूप न होकर विषमग दृष्टि सा अध्ययन प्रतीत होता है। अराजकतावाद का यह दुर्भाग्य है कि इसका कोई सम्पूर्ण अध्ययन नहीं हो पाया है। लेकिन हमने विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या और बहु-आलोचना ग्रन्थ-ग्रन्थ दृष्टिकोणों में इतनी अधिक हुई है कि इस विचारधारा में केवल बुगइयाँ ही बुराइयाँ नजर आती हैं।

स्पष्टता एवं विस्तृत विवेचन का अभाव ②

जो जोड़ के अनुसूचित अराजकतावादी विचारधारा अध्ययन रूप से अस्पष्ट है, क्योंकि इसकी रूपरेखा सरल होनी चाहिए थी यह केवल एक रूपरेखा के रूप में ही अपना अस्तित्व रखता है। इस विचारधारा में राज्य, पूँजीवाद, व्यक्तिगत सम्पत्ति, धर्म आदि का विभिन्न समर्थकों ने व्यापक विवरण दिया है। लेकिन यह केवल नकारात्मक एवं उन्मूलन व्यवस्था तक ही सीमित है। अराजकतावादियों ने सामाजिक संगठन का रूप, स्वरूप तथा इसकी प्राप्ति के आन्ति साधनों के विषय में या तो कुछ नहीं कहा या कोई विस्तारपूर्वक व्याख्या नहीं की है। इस प्रकार यह विचारधारा स्पष्ट ढंग से ध्वस्त नहीं हो पायी है। अराजकतावादी अपनी आकर्षक रूपरेखा को विस्तृत नहीं करते हैं अथवा ऐसा करके अक्षय्य हैं।³⁹ स्वतंत्र एवं मौलिक विचारधारा की सदिग्धता ③

अराजकतावाद का अध्ययन करने के बाद यह विश्वास नहीं हुआ कि यह एक स्वतंत्र और मौलिक विचारधारा भी है या नहीं। सामान्यतः अराजकतावादी विचारधारा साम्यवाद, सिन्डीकेलिवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद का सम्मिश्रण सा प्रतीत होता है। अतः हमें एक अलग और स्वतंत्र विचारधारा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और यदि इसे विचारधारा के रूप में स्वीकार भी किया जाता है तो साम्यवादी विचारधारा के वैज्ञानिक विवेचन और व्यापक प्रभाव ने इसे महत्वहीन कर दिया है। अराजकतावाद, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, साम्यवाद की पुनरावृत्ति सा प्रतीत होता है।

मनुष्य स्वभाव का एकपक्षीय विश्लेषण ④

अराजकतावादियों ने मनुष्य स्वभाव की जा मनोवैज्ञानिक विवेचना की है वह अशुद्ध और एकपक्षीय है। वे मानव स्वभाव की नैतिकता, सद्भाव, महत्कारिता के प्रति अत्यन्त ही आशावादी हैं। उनके अनुसार मनुष्य स्वभावक अशुद्ध होता है।

38 Paul Eltzbacher, Der Anarchismus, English translation by S T Byington, New York, 1930, Carter, April, The Political Theory of Anarchism, p 1

39 जाह, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त प्रसिद्धि, पृ 113

मनुष्य में करने ऊपर स्वयं ही सीमाएं एवं मर्यादायें निर्धारित करने की क्षमता होती है। मनुष्य स्वभाव के विषय में यही आशावादिता उनके राज्य विहीन, सत्ता विहीन समाज का आधार है। लेकिन यदि मनुष्य में निःस्वार्थ सहयोग की प्रवृत्ति है तो दूसरी ओर वह स्वार्थ भावना से भी प्रेरित होता है। अन्तर सिर्फ यही है कि स्वार्थ प्रवृत्ति किसी व्यक्ति में कम है या किसी में अधिक, लेकिन यह मनोवृत्ति का एक प्रमुख तत्व है। इस प्रकार भराजकतावादियों की सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार न तो मनोवैज्ञानिक गिद्दान्तों और न व्यावहारिक दृष्टि से सही कहा जा सकता है।

काल्पनिक सामाजिक व्यवस्था (5)

भराजकतावादी समाज की स्थापना असम्भव एवं अव्यावहारिक दोनों ही हैं। भराजकतावादी व्यवस्था की स्थापना कैसे होगी यह केवल काल्पनिक है क्योंकि इस दिशा में अभी तक न तो कोई सक्रिय कदम उठाया गया है और न ही इतिहास में इसका कोई उदाहरण मिलता है। भराजकतावादी विचारको ने जिस समाज रचना के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए हैं वे राज्य के स्थान पर संधारण विकल्प भी सिद्ध नहीं हो सकते। विभिन्न सामाजिक सगठनों की सफलता के विषय में आलोचक आशावादी नहीं हैं।

राज्य और सरकार का विरोध (6)

भराजकतावादी राज्य को एक बुराई मान कर उन्मूलन करना चाहते हैं। उनके ये विचार ऐतिहासिक न होकर काल्पनिक अधिक हैं। प्रत्येक युग में राज्य या शासन व्यवस्था किसी न किसी रूप में अवश्य ही विद्यमान रही है। राज्य या सब प्रकार की शासन व्यवस्थाएँ न तो शोषण वा साधन हैं और न बल-प्रयोग करने वाली संस्थाएँ हैं। आज के सभी कल्याणकारी राज्य जन-हित की भावना से प्रेरित होने हैं।

सम्पत्ति सम्बन्धी श्रुतिपूर्ण विचार (7)

भराजकतावादियों द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति को पूर्ण रूप से उन्मूलन किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति मनुष्य को मूल स्वायत्त प्रवृत्ति का परिणाम एवं फल है। यह व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक है। जब मानव है तो परिवार है, जब परिवार है तो सम्पत्ति को उससे अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भराजकतावादियों के सम्पत्ति सम्बन्धी विचार व्यावहारिक दृष्टिकोण में पूर्णतः सही नहीं हैं।

हिमात्मक साधन : सत्ता वा सत्ता द्वारा उन्मूलन (8)

कुछ भराजकतावादी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रान्ति एवं हिंसात्मक साधनों का समर्थन करते हैं। उनके यह विचार न तो उचित हैं और न तार्किक ही, क्योंकि—

प्रथम, अराजकतावादी अर्द्धे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये क्रान्ति का समयन करते हैं। द्वितीय, ये सत्ता को उन्मूलन शक्ति-सत्ता के द्वारा करना चाहते हैं और यदि सत्ता द्वारा सत्ता का विरोध-जब चलता गया तो वह स्थिति कभी नहीं धायेगी जब स्वेच्छापूर्वक सामाजिक समूहों की स्थापना होगी। यह तो निर्विवाद सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये कि क्रान्ति या हिंसा के द्वारा परिवर्तन या तो क्षणिक होने हैं या हिंसा के द्वारा प्राप्त की गई व्यवस्था शक्ति द्वारा ही स्थिर रखी जा सकती है। इस परिस्थिति में मनुष्य की सद्भावना एवं सहयोग प्रभावहीन हो जाता है या उस पृष्ठभूमि की ओर धकेल दिया जाता है।

सत्ता विरोध का औचित्य 9

स्वतन्त्रता और सत्ता विरोध अराजकतावादियों के मूल मंत्र है। इन्होंने स्वतन्त्रता और सत्ता को परस्पर विरोधी माना है। आजकल सभी व्यावहारिक प्रजा-तांत्रिक विचारधाराएँ स्वतन्त्रता और सत्ता को सीमित करके समुचित समन्वय के पक्ष में हैं। असीमित स्वतन्त्रता जब स्वच्छन्दता में परिवर्तित होती है तो यह असीमित सत्ता से भी अधिक खतरनाक है। स्वतन्त्रता कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित न रहे आज इसका मंत्र समाज उपयोग करे या स्वतन्त्रता का प्रयोग पूर्ण समाज हित में किया जाय, इसमें लिये सत्ता का आशिक एवं न्यायोचित प्रयोग अत्यन्त ही आवश्यक है। इस प्रकार अराजकतावादियों का पूर्ण सत्ता-विरोध उचित नहीं लगता।

अराजकतावादी विचारधारा में विरोधाभास 10

अराजकतावादी विचारधारा के बहुत से तर्क परस्पर-विरोधी या तर्कयुक्त नहीं हैं। जेन्कर (E N Zenker) के शब्दों में —

‘अराजकतावाद अभी तक की गयी मनुष्य-व्यवस्था की महानतम भूलों में से एक है क्योंकि जिन विचारों से यह प्रारम्भ होता है तथा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह मनुष्य-स्वभाव और जीवन मयार्थता का पूर्ण विरोधाभास है।’⁴⁰

यह विरोधाभास अराजकतावाद के कई पक्षों में व्यक्त होता है। अराजकता-वादियों ने राज्य उन्मूलन के बाद ऐसे समाज की कल्पना की है जो कई स्थानीय समूहों में विभाजित होगा। ये स्थानीय समूह स्वेच्छा पर आधारित होंगे तथा इनका कार्य किसी न किसी प्रकार के जनतांत्रिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा ही किया

40 "Anarchism is certainly one of the greatest errors ever imagined by man, for it proceeds from assumptions and leads to conclusions which entirely contradict human nature and the facts of life"

Zenker, E N, Der Anarchismus, quoted by Bose, A., A History of Anarchism, p 395

वादी। इस प्रकार धराजकतावादियों ने जो आलोचना प्रतिनिधि शासन व्यवस्था के विषय में की है वह इन समूहों के विपरीत में भी लागू हो सकते हैं। धराजकतावादों एक ओर तो यह कहते हैं कि उनकी सामाजिक व्यवस्था मनुष्य के सहयोग एवं सहभावना पर आधारित है लेकिन साम्यवादो-धराजकतावादी उसी व्यक्ति को राज्य एवं अन्य सत्ताओं के उन्मूलन के लिये क्रान्ति एवं हिंसा के लिये कहते हैं, यह स्पष्टतः विरोधाभास व्यक्त करता है।

मानवकों की यह शक्ति होना स्वाभाविक ही है कि जिन समाज में शासन द्वारा किसी भी प्रकार का न्यूनतम नियंत्रण नहीं होगा तथा सामाजिक व्यवस्था को मनुष्य के स्वतन्त्र विचार और सहभावना पर छोड़ दिया तो मनुष्यों में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष होना स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति से कुछ स्वार्थी तत्व विद्यमान रहने हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि समाज में सबल जीवित रह सकता है। क्रोस्टकिन ने अपनी पुस्तक "Mutual Aid: A factor of Evolution" में हार्विन के निदान्त 'survival of the fittest' की कटु आलोचना की है और यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि यह निदान्त धराजकतावादी मनाज में लागू नहीं होगा। किन्तु यदि धराजकतावादी निदान्त को व्यावहारिक रूप दिया जाय तो उनके मनाज में भी सबल की स्वतन्त्रता ही कायम रह सकती है।

धराजकतावादियों ने धर्म की कटु आलोचना की है। वास्तव में-धर्म और मनुष्य की नैतिकता में बड़ा सम्बन्ध है। धर्म उन्मूलन का तात्पर्य नैतिकता के श्रेय का ही विनाश करना है। प्रजातन्त्र व्यवस्था तो नैतिकता पर ही निर्भर करती है। इन समय जो आवश्यकता है वह धर्म-उन्मूलन की नहीं, किन्तु धार्मिक ग्रन्थ-विश्वास को समाप्त तथा धर्म के वैज्ञानिक अध्ययन की है।

कुछ धराजकतावादी चिन्तकों के जीवन एवं विचारों में निम्नता दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ, विनियम गॉडविन ने विवाह को भी एक वधुमाना है लेकिन उन्ने स्वयं ही तीन विवाह किये। प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद उसे विवाह एवं पारिवारिक महत्व का पता चला। गॉडविन द्वारा इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध कवि शैली के ऊपर भी अपनी पुत्री मैरी (Mary) के साथ विवाह करने के लिये जोर डाला गया कि विवाह व्यवस्था का गॉडविन ने अपने विचारों में विरोध किया है। यह विवाह तभी सम्भव हो गया जब शैली की पत्नी हैरिउट (Harriet) ने धाम्यता काली।

गॉडविन ने राज्य की हमेशा ही आलोचना की है, लेकिन अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में जब वह निर्धन अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय सरकार ने कुछ धार्मिक सहायता का प्रस्ताव रखा जिसे गॉडविन ने महर्षि स्वीकार

कर लिया। इस प्रकार राज्य अथवा सरकार की कृपा पर ही उमे निर्भर रहना पडा। इसी प्रकार वाकुनिन ने यूरोप में सर्वत्र क्रान्ति का समर्थन ही नहीं किया, किन्तु व्यक्तिगत सहयोग भी दिया। उसने अपने क्रान्ति स्वतन्त्रता आदि सम्बन्धी विचारों से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के क्रान्तिकारियों को प्रभावित किया। लेकिन 1851 में जब रूस में उसे बन्दी बनाया गया तो रूस के मन्नाट्ट चार निकोलेस प्रथम में उसने बड़े दयनीय स्वरो में क्षमा याचना की।⁴²

अराजकतावादी विचारधारा की आलोचना का निष्कर्ष व्यक्त करते हुये एलेग्जेंडर येन लिखा है —

अराजकतावादी के साथ प्रमुख कठिनाई यह है, कि वह बुद्धिमान है उसमें विवेक नहीं है। इस प्रकार अराजकतावाद की रचनात्मक व्याख्या सम्भवतः असम्भव है। यदि वे यह स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने अपना घोसला आकाश में बनाया है तो कोई भी शब्द उन्हें इस बात के लिए तैयार नहीं कर सकता कि वे अवास्तविक तथा अव्यावहारिक विश्व में रह रहे हैं। अराजकतावादी बहुत ही बुद्धिमान तथा काल्पनिक शिशुओं की नस्ल है जो अपनी बचबाना लेखनी व बाहर कुछ देख सकें, विश्वास नहीं किया जा सकता।”

अराजकतावादियों के विषय में एलेग्जेंडर येन के विचार अत्यधिक तीव्र बटाक्ष हैं। वास्तव में अराजकतावादियों के प्रत्येक पक्ष पर प्रत्येक ओर से प्रहार किया गया है। यहाँ तक कि इसे एक राजनीतिक विचारधारा मानना सदिग्ध है। किंतु अराजकतावाद की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि इन विचारधारा के समर्थकों को अराजकतावादी समाज की स्थापना में कभी भी विजय प्राप्त नहीं हुई। यह इस विचारधारा की अचरलता का प्रमुख कारण है।⁴⁴

योगदान

अराजकतावाद का एक विचारधारा के रूप में आज तक कोई विशेष महत्त्व नहीं रहा है। ये अपने विचारों में अश्वि उन्नत है। इनकी व्यक्तिवादिता, समाज-

42 Letter of Confession to the Tzar, quoted by Bose, A., A History of Anarchism, pp 109, 181

43 "The fundamental trouble with the anarchist is that, though he may be highly intelligent, he has no sense. It follows that a fruitful discussion of anarchism is almost an impossibility. If they do not realise that they have set their nest among the stars, no word of man will persuade them that their thoughts are moving in a world unreal and unrealisable. Anarchists are a race of highly intelligent and imaginative children, who nevertheless can scarcely be trusted to look after themselves outside the nursery pen."

Gray, A., The Socialist Tradition p 380

44 Carter, April, The Political Theory of Anarchism, p 1,

वादिता, कल्पनावादिता आदि सभी उपग्रन्थी हैं। लेकिन यदि इनके सिद्धान्तों में से उन्नता निकाल दें तो उनमें बहुत कुछ बातें महत्वपूर्ण एवं आधुनिक मिलती हैं। उनके विचारों में कम से कम निम्नलिखित बातों को किसी सीमा तक स्वीकार कर सकते हैं—

प्रथम, ये अधिनायकत्व के विरोधी और मानव स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक हैं।

द्वितीय, सभी समाजवादियों की तरह ये व्यक्तिगत सम्पत्ति का सामाजिक हित में प्रयोग करने के लिए इंगित करते हैं। वैयक्तिक सम्पत्तिके विषय में उनकी आलोचना में बहुत सत्यता है।

तृतीय, भराजकतावादियों का यह कथन भी सत्य है कि अधिक सम्पत्ति सचय या एकाधिकार आधिक विषमता तथा शोषण को जन्म देता है। अन्त में, भराजकतावादी धार्मिक अन्ध-विश्वास की कटु निन्दा करते हैं। उनके धर्म सम्बन्धी विचारों को पूर्णतः स्वीकार करने में आपत्ति हो सकती है, किन्तु धर्म को विवेकपूर्ण आधार पर स्वीकार करने की बात तो स्वीकार की जाने योग्य है।

भराजकतावाद, लेन लंकास्टर के मतानुसार, अव्यावहारिक है लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि उनके द्वारा आधुनिक समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों की आलोचना का कोई महत्व ही नहीं है। यद्यपि वे कोई व्यावहारिक सामाजिक योजना प्रस्तुत नहीं करते किन्तु शक्ति, एकरूपता और कुशलता पर आधारित आधुनिक समाज के विरुद्ध वे जो कुछ कहते हैं वह महत्वहीन नहीं है।⁴⁵

पाठ्य-ग्रन्थ

1. Bose, Atindranath., A History of Anarchism,
2. Carter, April., The Political Theory of Anarchism.
3. बोकर, फ्रान्सिस; आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, अध्याय 7, भराजकतावादी
4. Cole, G. D. H., A History of Socialist Thought Vol. II, Socialist Thought: Marxism and Anarchism.
5. Gray, A., The Socialist Tradition., Chapter XIII, The Anarchist Tradition,
6. Hunt, R. N. Carew, The Theory and Practice of Communism-An Introduction, Chapter XII, Anarchism,
7. जोर., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, अध्याय 5, साम्यवाद तथा भराजकतावाद

⁴⁵ Lancaster, L. W., Masters of Political Thought, vol. III, p 263

सिन्डीकलवाद

फ्रांस समाजवादी विचारधाराओं का घर रह चुका है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ एक और समाजवादी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ जिसे सिन्डीकलवाद या श्रम सघवाद (Syndicalism) कहते हैं। इसे इसे एक विचारधारा की अपेक्षा श्रमिक आन्दोलन कहना अधिक उपयुक्त होगा।

सिन्डीकेलिज्म शब्द फ्रेंच शब्द सिन्डीकेट (Syndicat) से निकला है जिसका अर्थ श्रमिक सघ (Labour Union) है। इस शब्द को स्पष्ट करते हुए लॉरविन (L. Lorwin) ने लिखा है कि “सिन्डीकेट एक व्यवसाय या एक जैसे हो व्यवसायों के श्रमिकों का समुदाय है, जो समान हित से संगठित रहते हैं।¹ जब उन्नीसवीं शताब्दी की अन्तिम दशाब्दी में फ्रांस के धर्म-संघों के प्रमुख राष्ट्रीय संगठन उग्र पन्थियों तथा नरम-पन्थियों में विभक्त हो गये तब इन दोनों की विरोधी नीतियों के लिए ‘आतिवादी सिन्डीकेलिज्म’ (Revolutionary Syndicalism) तथा ‘सुधारवादी सिन्डीकेलिज्म’ (Reformist Syndicalism) शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। कालान्तर में श्रमिक संगठनों पर आतिवादी सिन्डीकेलिस्टों का अधिकार हो गया। तभी से फ्रांस में श्रमिक-सघ की नीति केवल ‘सिन्डीकेलिज्म’ (Syndicalism) के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरे देशों में भी छोटे-छोटे धर्म संगठनों के ऐसे ही सिद्धांतों के लिए इसी शब्द का प्रयोग होने लगा।²

सिन्डीकलवाद ऐसी समाजवादी विचारधारा है जिसमें सामाजिक आन्ति वर्ग-संघर्ष के परिणामस्वरूप होती है। अन्य आन्तिवारी समाजवादी विचारधाराओं की तरह सिन्डीकलवाद भी आन्ति के उपरान्त राज्य तथा सरकार की समाप्ति करके उनका सम्पूर्ण दायित्व श्रमिक सघों (Syndicats) को देना अपना लक्ष्य मानता है। उग्र अराजकतावाद तथा साम्यवाद की भाँति सिन्डीकलवाद भी हिंसात्मक आन्ति के साधनों को अपनाता है।³

1 Lorwin L., Syndicalism in France, New York, 1914 p 125

2 कोकर आधुनिक राजनीतिक चिंतन, पृ 289.

3 Gray, A., The Socialist Tradition, pp 408 409

विकास इतिहास

मिन्डीकलवाद का प्रादुर्भाव मुख्यतः फ्रांस में हुआ। इसका कारण यह था कि फ्रांस में तत्पूवमाने के उद्योग अधिक थे तथा इन उद्योगों के संघ भी छोटे-छोटे रहते थे। सामान्यतः छोटे-छोटे श्रमिक संघ अपने लिये व्यापक संगठनों में संगठित नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसे बड़े श्रमिक संघों की ओर फ्रांस की सरकार हमेशा शंका की दृष्टि से देखती थी। यही कारण है कि मिन्डीकलवाद ने श्रम की छोटी-छोटी इकाइयों को अधिक महत्व एवं प्राथमिकता दी गयी है।⁴

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम काल की अवधि तक फ्रांस में श्रमिकों के ऊपर प्रत्यधिक प्रतिबन्ध लगे हुए थे। उन्हें अपने संघ निर्माण करने की आज्ञा नहीं थी; हड़ताल वर्जित थी तथा सामूहिक रूप से कोई सौदेबाजी भी नहीं कर सकते थे। उन्हें सरकार की ओर से दमनकारी नीति तथा पूंजीपतियों की ओर से शोषण का सदैव सामना करना पड़ता था। अपने अधिकारों के लिए जब कभी श्रमिकों ने कोई आन्दोलन किया उसे राज्य द्वारा पूरी तरह दबाया गया। यही कारण है कि उस समय श्रमिक-वर्ग का राज्य के ऊपर से विश्वास हट गया। वे उसे पूंजीपतियों के हित-साधन तथा श्रमिक वर्ग का दमन करने वाली सस्था समझने लगे। श्रमिक-वर्ग को अपने प्रतिनिधियों पर भी विश्वास नहीं रहा। उनके जो प्रतिनिधि संसद में चुनकर जाते थे वे श्रमिकों के हितों को दृष्टावर राज्य की दमन नीति के सहयोगी बन जाते थे। मिलरेण्ड (Millerand), विवेनी (Viviani), ब्रिया (Briand) ऐसे ही श्रमिक प्रतिनिधि थे जो श्रमिक उग्रवादिता छोड़कर शासन के समर्थक बन गये। श्रमिकों का अपने प्रतिनिधियों तथा प्रतिनिधि सभाओं से भी विश्वास हटता गया। इन परिस्थितियों में समाजवाद का प्रविष्ट, सोरेल (George Sorel) के अनुसार, स्वशासित श्रमिक संघों पर ही निर्भर था।

इसी बीच मार्क्सवादी तथा अराजकतावादी विचार भी यूरोप के विभिन्न भागों में फैलने जा रहे थे। फ्रांस के मिन्डीकलवादियों पर इन दोनों विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। फ्रांस की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन दोनों विचारधाराओं में त्रुटि भी उपयुक्त प्रतीत हुआ ग्रहण किया। मानस से उन्होंने वर्ग-संघर्ष (class war) तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष ग्रहण किया। अराजकतावादियों, विशेषतः प्रद्यो, से उन्होंने सघोष स्वायत्तता (federal autonomy) के विचार लिए। उन्होंने अराजकतावादियों की कार्य प्रणाली भी अपनाई। इसलिये मिन्डीकलवाद को मार्क्सवाद और अराजकतावाद का समन्वय कहा जाता है। हेरबर्ट रीड (Herbert Read) के अनुसार मिन्डीकलवादी सिद्धान्त में चाहे जो भी व्यवहार में अराजकतावादी है।⁵

4. Lancaster, L.W., Masters of Political Thought, vol. III, p. 277.

5. Read, Herbert, Anarchy and Order, Faber and Faber, London, 1954, p. 101.

इस समय फ्रांस का मजदूर वर्ग दुविधा में था। एक ओर तो उन्होंने यह अनुभव किया कि मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी वे मार्क्स के बताये गये कार्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। दूसरी ओर फ्रान्स में सर्वोद्योगिक सुधारों की गति में कई बार रुकावट आई। इसलिये उन्हें अपने भाग्य सुधारने में न तो वैधानिक माध्यम कारगर प्रतीत हुए और न उनके प्रतिनिधि ही विश्वास के पात्र थे। इस परिस्थिति में फ्रांस का श्रमिक वर्ग ऐसे साधनों की खोज में था जिनसे उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। सिन्डीकलवाद इसी का परिणाम था।

फ्रांस में जब समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता जा रहा था उसी समय श्रमिक वर्ग के कुछ दार्शनिक नेताओं ने भी अपने विचारों से श्रमिकों की चेतना का विस्तार करने में योगदान दिया। इनमें फर्नेण्ड पेलोतिये (Fernand Pelloutier, 1867-1901) तथा जार्ज सोरेल (George Sorel, 1847-1922) प्रमुख थे। विशेषतः सोरेल सिन्डीकलवाद का मुख्य व्याख्याता माना जाता है।

पेलोतिये सम्भवतः सबसे प्रथम व्यक्ति था जिसने यह विचार व्यक्त किया कि फ्रांस के श्रमिकों को समस्त फ्रेंच राष्ट्र से भ्रगत हो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। इसे राजनीतिक समाजवादियों में तनिक भी विश्वास नहीं था। लेबर एक्सचेंज (Bourses du Travail)⁶ को इन राजनीतिक समाजवादियों के नियन्त्रण से पृथक रखने के लिये पेलोतिये 1894 में राष्ट्रीय फेडरेशन का मन्त्री बना जिम पद पर वह लगभग सात साल तक रहा। पेलोतिये की सगठन शक्ति से लेबर एक्सचेंज ने कुछ प्रगति की। उसने फ्रांस के मजदूर आन्दोलन पर इस विचार का प्रभाव डाला कि मजदूरों को स्थानीय लेबर एक्सचेंजों द्वारा कार्य करके अपने ही सहकारी उद्योगों द्वारा अपनी मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

सोरेल सबसे पहिली बार एक श्रमिक विचारक के रूप में प्रस्तुत हुआ। वह स्वयं शिक्षित व्यक्ति था। अविवेकवाद (Irrationalism) को राजनीतिक पक्ष के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय सोरेल को है। उसने मनुष्यों को तर्क-युक्त विचारों से नहीं किन्तु उनकी भावनाओं को भड़काने तथा अविवेकपूर्ण बातों को स्वीकार करने के लिये प्रभावित किया जिससे श्रमिक दिना सोचे समझे उसके विचार एवं कार्यक्रम स्वीकार कर लें।⁷

श्रमिकों में अपने विचारों का प्रसार करने के लिये सोरेल ने एक भासिक पत्र श्रम-संघ (Trade Unions) का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इस पत्र के माध्यम से उसने इस विचार का प्रतिपादन किया कि समाजवाद का सम्पूर्ण भविष्य मजदूरों के सिन्डीकेटों के स्वतन्त्र विकास में है।

⁶ लेबर एक्सचेंज फ्रांस में छोटे छोटे श्रमिक सगठन थे जहाँ श्रमिक बैठकर अपने निजी हितों की चर्चा तथा कार्यक्रम पर विचार करते थे।

⁷ Lancaster, L W, Masters of Political Thought, Vol III p 276

वेलोतिये तथा सोरेल को सिन्डीकलवाद के मूल विचार व आधार प्रदान करने का श्रेय है। उनका विचार था कि "सर्वहारा वर्ग जिस सामाजिक परिवर्तन को चाहता है, वह आत्म-परिवर्तन होना चाहिये और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का स्थान जो नई व्यवस्था लेगी वह उन संस्थाओं के रूप में होगी जो मजदूरों द्वारा स्वयं अपने ही प्रयत्न से और सरकार के विरोध की उपेक्षा करके बनाई जायेगी।" 8

यूरोप में समाजवाद की प्रगति का प्रभाव, फ्रांस में उग्र श्रमिकों का अभ्युदय तथा कुछ चिन्तकों के विचारों से प्रभावित हो फ्रान्स की सरकार को आखिर झुकना पड़ा। सन् 1864 में एक कानून के द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को स्वीकार किया गया। इसके चार वर्ष बाद ही फ्रान्स की सरकार ने घोषणा की कि उन सभाओं के कार्य में जिनके उद्देश्य शान्तिपूर्ण हैं राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन प्रतिबन्धों के हट जाने तथा शासन की नरमाई से श्रम-संघवाद ने फ्रांस में प्रगति करना प्रारम्भ किया।

वैसे फ्रांस में श्रमिक संगठनों पर कड़े प्रतिबन्ध होते हुए भी यात्री सहायक सभाएँ (Travelers' Aid Societies) तथा पारस्परिक सहायता सभाएँ (Mutual Aid Societies) स्थापित की गयी थी। जब सरकार के कुछ उदारवादी दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप 1884 में एक कानून द्वारा मजदूरों को अपने संघ स्थापित करने का अधिकार दिया तो श्रमिकों ने इस कानून का पूरा लाभ उठाया। स्थानीय श्रमिक संघों के कार्यों को संगठित करने के प्रयोजन से 1886 में मजदूर सभाओं का एक राष्ट्रीय संघ (National Federation) स्थापित किया गया। 1887 में सबसे पहला लेबर एक्सचेंज पेरिस में स्थापित हुआ तथा कुछ ही समय में अन्य नगरों में लेबर एक्सचेंजों की स्थापना की गई। इन लेबर एक्सचेंजों का उद्देश्य मजदूरों के लिए रोजगार की खोज, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना, समाचार पत्रों का प्रकाशन करना, बेकार श्रमिकों को आर्थिक सहायता देना था। शीघ्र ही लेबर एक्सचेंज श्रमिक गतिविधियों के मुख्य केन्द्र बन गये।

1893 में इस लेबर एक्सचेंजों का राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया तथा 1895 में मजदूरों की एक नवीन तथा सर्वाङ्ग-पूर्ण संस्था को जन्म दिया गया जिसका नाम जनरल कन्फेडरेशन ऑफ लेबर (Confederation Generale du Travail or C.G.T.) था। क्रान्तिवादी सिन्डीकलवाद की विचारधारा तथा कार्यश्रम का मूजन इसी संस्था के तत्वावधान में हुआ। इसके ही माध्यम से सिन्डीकलवाद को व्यावहारिक रूप दिया गया।

फ्रान्स का लेबर कन्फेडरेशन शक्तिशाली था, जिसके तत्वावधान में काफी हड़तालों तथा तोड़फोड़ की गतिविधियाँ आयोजित की गईं। किन्तु यह एक संगठित

8 बोकर., प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ० 246-47.

सघ नहीं बन सका। इसमें पहले से ही नरम एवं उग्रवादियों में मतभेद चल रहे थे। 1906 में यह श्रमिकों की कार्य-अवधि के प्रश्न पर मतभेद हो जाने के कारण और भी विभाजित हो गया।

सिन्डीकलवाद का फ्रान्स में धीरे-धीरे पतन होने लगा। 1906 में सिन्डीकलवादियों ने एक व्यापक देशव्यापी ग्राम हड़ताल के लिए घोषणा किया। यह हड़ताल हुई और यही इसने पतन का प्रारम्भ था। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोगों का ध्यान युद्ध संचालन की तरफ अधिक था और सिन्डीकल आन्दोलन पृष्ठभूमि में होता चला गया।

सिन्डीकलवाद का प्रभाव फ्रान्स तक ही सीमित नहीं रहा, स्पेन तथा अमेरिका में भी इसके प्रभाव का प्रसार हुआ। स्पेन में प्रद्यो के अनुयायी मारगाल (P. Margall) ने श्रमिक आन्दोलन को प्रोत्साहित किया। 1910 में एक श्रमिक-सघ (Federation of Labour) की स्थापना हुई। इसने स्पेन में बहुत कुछ उद्योगों को संचालित किया तथा रचनात्मक कार्यों को अपने हाथों में लिया।

अमेरिका में भी सिन्डीकलवाद ने श्रमिकों को प्रभावित किया तथा एक श्रमिक-सघ (Industrial Workers of the World or I. W. W.) की स्थापना हुई जिसमें 1905 में एक समाजवादी कार्य-भ्रम स्वीकार किया। अमरीकी सिन्डीकलवादियों ने, जिनका प्रमुख कार्य स्थान शिकागो था, हड़तालों को आयोजित किया तथा प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिक सेवा के लिये सरकार का विरोध किया। इस कारण उन्हें अमरीकी सरकार तथा रूस के समर्थक समाजवादियों की आलोचना का शिकार होना पड़ा। इनकी गतिविधियों के कारण अगस्त 1919 में इन पर मुकदमा चलाया गया तथा बहुत से प्रमुख कार्यकर्ताओं को लम्बे सजाएँ दी गयीं। बहुत से सदस्यों ने अमेरिका के साम्यवादी दल की सदस्यता स्वीकार कर ली। तदुपरांत अमेरिका से सिन्डीकलवाद का पतन होता चला गया।

प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त रूस के साम्यवादी दल ने विश्व के सभी मजदूर सघों को एक अन्तर्गण्ट्रीय सघ स्थापित करने के लिये आमन्त्रित किया। बहुत से सिन्डीकलवादियों ने इसका स्वागत किया जिसका सिन्डीकल आन्दोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। युद्ध के उपरान्त ही फासीवाद विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। फासीवाद ने बहुत कुछ सिन्डीकलवादियों से ग्रहण किया। यूरोप में जैसे जैसे फासीवाद लोकप्रिय होता गया वैसे वैसे ही सिन्डीकलवादी इसके समर्थक बनने लगे।

इसी समय गिल्ड समाजवाद का प्रादुर्भाव हुआ। इस समाजवादी सम्प्रदाय में सिन्डीकलवाद के कुछ तत्वों को ग्रहण किया। इसने सिन्डीकलवाद की नृटियों को भी दूर करने का प्रयत्न किया। सिन्डीकलवाद केवल उत्पादकों का ही समर्थन करता था, गिल्ड समाजवाद ने उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के ही हितों

को नंरक्षण दिया । साथ ही साथ गिल्ड समाजवाद शान्तिपूर्ण साधनों की ओर जा हुआ था । इस प्रकार वे श्रमिक जो हिंसा, तोड़फोड़ तथा अन्य प्रत्यक्ष कार्यवाहियों से परेशान हो चुके थे, गिल्ड समाजवाद के समर्थक बन गये ।

उपरोक्त कारणों से सिन्डीकलवाद के प्रभाव में कमी आयी और पतन की ओर अग्रसर हुआ । किन्तु इसके अवशेष विश्व के कई राज्यों में शेष है ।

सिन्डीकलवाद का अर्थ

सिन्डीकलवाद की परिभाषा करते हुए कोकर ने लिखा है—

“मोटे तौर से सिन्डीकेलिज्म यह मानता है कि श्रमिकों को ही उन स्थितियों का नियन्त्रण करना चाहिये जिनके अधीन वे कार्य करें और जीवन निर्वाह करें, जिन सामाजिक परिवर्तनों को वे चाहते हैं उन्हें वे केवल अपने ही प्रयत्नों से और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल साधनों से ही प्राप्त कर सकते हैं।”⁹

जोड के अनुसार—

“शिल्पी-संघवाद (सिन्डीकलवाद) की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि यह वह सामाजिक सिद्धान्त है जो श्रमिक-संघों को नवीन समाज की आधार शिला और साथ ही साथ वह साधन भी मानता है जिसके द्वारा अभिनव समाज की स्थापना की जायेगी । शिल्पी-संघवाद स्पष्टतः समाजवादी है, क्योंकि यह अन्य समाजवादी मतों की भाँति पूँजी को चोरी मानता है तथा वर्ग-युद्ध की धारणा की पुष्टि करता है । यह उत्पत्ति के साधनों के निजी स्वामित्व का अन्त कर उसके स्थान पर सामुदायिक स्वामित्व को प्रतिष्ठापित करना चाहता है।”¹⁰

लेइलर (H. W. Laidler) ने अपनी पुस्तक—Social Economic Movements, में सिन्डीकलवाद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यह विचारधारा व्यापार और उद्योग दोनों के श्रमिक संघों के मजदूर संगठन के लिये अत्यधिक जोर देती है ताकि नये औद्योगिक ढाँचे का व्यवहार हो । वह उपभोक्ता की अपेक्षा उत्पादक को अधिक महत्त्व देता है; तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिये आम हड़ताल और प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसे साधनों को महत्त्व देता है । इसके अलावा यह राजनीतिक राज्य की उन्मूलन की आवश्यकता तथा श्रमिकों की मुक्ति के लिये राजनीतिक कार्यवाही की प्रभावशून्यता की बात बहते हैं ।

9. कोकर., प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ० 241.

10. जोड, प्राधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ० 62.

हूवर (G. E Hoover) ने स्वयं की पुस्तक—*Twentieth Century Political Thought*—में सिन्डीकलवाद का अर्थ उन आन्तिवारियों के सिद्धान्त और कार्य-क्रम से है जो औद्योगिक संघों की आर्थिक शक्ति का प्रयोग पूंजीवाद को नष्ट करने और समाजवादी समाज का संगठन करने के लिये करते हैं ।¹¹

सिन्डीकलवाद के विचार-सूत्र

सिन्डीकलवाद निपेक्षात्मक दर्शन है । इसमें लगभग सभी प्रचलित तत्कालीन व्यवस्थाओं और प्रणालियों का विरोध किया गया है । सिन्डीकलवादी विचार सूत्रों का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है ।

1) सिन्डीकलवाद और अविवेकवाद (Syndicalism and Irrationalism)

सिन्डीकलवाद अविवेकवाद पर आधारित है । यह तर्क-संगतता या विवेक में विश्वास नहीं करता है । सोरेल को महाद् अविवेकवादी कहा जाता है । सोरेल का विश्वास था कि व्यक्तियों को उन बातों से प्रभावित करना चाहिये जो उनकी भावनाओं को छू लें । इसी कारण सोरेल आन्तिव्या (myth) का भी प्रबल समर्थक था ।¹²

अविवेकवाद का दूसरा पक्ष सोरेल का अज्ञानवाद (anti-intellectualism) था । सोरेल ने सुकरात से लेकर अपने तत्कालीन दार्शनिकों तक लगभग सभी की घृणित नडी निन्दा की है । उन्हें सोरेल ने घाखन्डी (humbug), उच्च दर्जाय कीटाणुओं के सेवक, मायावी (charlatans) आदि कह कर पुकारा¹³ जिन्होंने विश्व को गुमराह कर प्रगति-पथ पर कभी आगे नहीं बढ़ने दिया । इस प्रकार सोरेल का उद्देश्य सिर्फ अपने विचार की अभिव्यक्ति कर व्यक्तियों को प्रभावित करना था । उसने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया कि कोई तर्क-संगत या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता भी है या नहीं ।

2) पूंजीवाद का विरोध

सिन्डीकलवादी पूंजीवाद के प्रबल विरोधी हैं । उन्होंने अन्य समाजवादियों की भांति पूंजीवाद तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति के विरुद्ध अपने लगभग वही तर्क दिये हैं । पूंजीवादी व्यवस्था को वे शोषण व्यवस्था मानते हैं । ये कारखाने, कल-प्रोड्यारों के स्वामी होने के नाते सब लाभ हूडप लेते हैं । इन्होंने सम्पूर्ण समाज को कारखाने के नमूने पर संगठित कर रखा है । पूंजीवाद का उन्मूलन करना सिन्डीकलवादियों का प्रमुख उद्देश्य है ।

3) वर्ग-सघर्ष

सिन्डीकल आन्दोलन ने मार्क्सवाद से वर्ग-सघर्ष का सिद्धान्त ग्रहण किया है । ये वर्ग-सघर्ष को प्रमुख स्थान देते हैं । किन्तु यही सब कुछ नहीं है । इनके अनुसार

11 उद्धृत, आशीर्वादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय भाग, पृ 618

12 Lancaster, L. W, Masters of Political Thought, Vol III, p 289

13 Ibid, p. 301

वर्ग-संघर्ष महत्वपूर्ण है किन्तु अपनी विचारधारा में इसे साध्य या उद्देश्य के रूप में स्वीकार नहीं करते।¹⁴ वे समाज में पूँजीपति तथा श्रमिक वर्गों के प्रतिस्व को स्वीकार करते हैं। पूँजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के कारण श्रमिकों का शोषण करता है। फलस्वरूप दोनों वर्गों में निरन्तर संघर्ष बना रहता है। दोनों वर्गों के परस्पर-विरोधी हित हैं। इस प्रकार की स्थिति के कारण श्रमिकों में वर्ग चेतना विकसित होती है और वे संगठित होकर पूँजी वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करने को तैयार होते हैं।

श्रमिकों की स्वतन्त्रता एव मुक्ति (f)

सिन्डीकलवादी श्रमिकों को उद्योगपति तथा पूँजीपतियों के चंगुल से मुक्त कर उन्हें उत्पादक की श्रेणी में लाना चाहते हैं। उनका कथन है कि "मानव व्यक्तित्व की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, उसकी रचनात्मक शक्ति का प्रमाण उत्पादक कार्य में ही है। कम से कम, कार्य इस कोटि पर उस समय होता है जबकि वह उसका निजी कार्य हो जिसे उसने स्वैच्छा से ऐसे उद्देश्यों तथा ऐसी अवस्थायों में किया हो जिनका उसने स्वयं या अपने माथे मजदूरों के सहयोग से निर्धारण किया हो। तत्कालीन समाज में श्रमिक नीचे से ऊपर तक पराधीनता के बन्धनों में जकड़ा हुआ है। जहाँ उद्योगपति गान्धी, यन्त्रों तथा मशीनों के स्वामी होते हैं वहाँ मजदूर कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं कर सता। सिन्डीकलवादी कारखाने आदि को स्वतन्त्र कराना चाहते हैं। जब कारखाना स्वतन्त्र होगा तो समाज भी स्वतन्त्र रहेगा और मजदूरों में गौरव तथा पराधीनता की भावना पुनः जागृत होगी।"¹⁵

मध्यमवर्ग तथा मध्यमवर्गीय समाजवाद का विरोध (5)

सिन्डीकलवादी मध्यमवर्ग के विरोधो होने के साथ साथ मध्यमवर्गीय समाजवाद के प्रति भी श्रद्धा नहीं रखते। उनका कहना है कि श्रमिक समाजवादियों को छोड़ कर अन्य सभी समाजवादी मध्यमवर्गीय थे। सिन्डीकलवाद को छोड़कर सभी समाजवादी सिद्धान्त धनुर मध्यमवर्गीय सिद्धान्तशास्त्रियों के मस्तिष्क की उपज हैं। बुद्धिजीवियों ही समाज की जो व्यवस्था आदर्श प्रतीत होती है उसी के अनुसार वे श्रमिकों को संगठित करना चाहते हैं। उन्हें श्रमिकों की आवश्यकताओं का कोई ज्ञान नहीं होता। इन आवश्यकताओं को श्रमिकों द्वारा निर्मित व्यवस्था ही व्यक्त कर सकती है। इसलिये सिन्डीकलवादियों का यह दावा था कि उनका समाजवाद स्वयं श्रमिकों का है, जो श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरित आसानी से कर सकता है। इन सम्बन्ध में सिन्डीकलवादी एक और तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार श्रमिकों और मध्यमवर्गीय शक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार का समन्वय नहीं होना चाहिये।

14 Hallowell, J H, Main Currents in Modern Political Thought, p 459.

15 बोहर., प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 248.

समाज में वर्ग चेतना को जीवित रखना अत्यन्त आवश्यक है। मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवियों के साथ रहने या उस वर्ग में मिलने से श्रमिकों में श्रान्ति या अन्य कार्यवाही करने के उल्हाह में मन्दी पड़ जाती है।¹⁶

राज्य का विरोध ६

सिन्डीकलवादी राज्य के प्रवृत्त विरोधी हैं। इनका इस सत्त्वा में बिलकुल विश्वास नहीं है। राज्य के प्रति विरोधःघोर अविश्वास के ये निम्नलिखित कारण देते हैं —

प्रथम, राज्य को सिन्डीकलवादी एक मध्यमवर्गीय सत्त्वा मानते हैं। इन प्रकार इनका मध्यमवर्ग के प्रति विरोध राज्य के प्रति भी लागू होता है।

द्वितीय, राज्य समाज में पूँजीपतियों के शोषण का साधन है। राज्य इस शोषण का श्रमिकों के पक्ष में कभी विरोध नहीं कर सकता।

तृतीय, राज्य में केन्द्रीय व्यवस्था होती है। "हर केन्द्रीय संगठन एकरूपता और प्रमद्वृत्ता को घोर प्रवृत्त होता है। उसमें कल्पनाशोभना एवं उपक्रम का अभाव होता है, तथा वह स्थानीय विकास और उद्यम को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। इसलिये, यदि किसी उदार राज्य को भी उद्योग का नियंत्रण सौंप दिया जाय, तो वह बालान्तर में प्रगति का घनु हो जायेगा।"¹⁷

चतुर्थ, राज्य सेवा में निमुक्त व्यक्ति अधिकाराभिमानी और सहानुभूतिहीन होते हैं। वे उन लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं देने, जो वास्तविक-उत्पादन कार्य में सलग्न होते हैं। लोक सेवा का मध्यमवर्गीय पदाधिकारी श्रमिकों की आवश्यकताओं को नहीं जान सकता। यही कारण है कि औद्योगिक संगठन का कार्य शारीरिक धन करने वाले श्रमिकों के हाथ में ही होना चाहिये।

राष्ट्र तथा राष्ट्रीय भावना का विरोध (7)

राज्य के साथ साथ सिन्डीकलवादी राष्ट्र तथा राष्ट्रीय भावना का भी विरोध करते हैं। इनका कहना है कि 'हमारा देश' 'हमारा राष्ट्र' आदि नारे एवं डोंग हैं। ये धारणाएँ पूँजीवादियों द्वारा प्रसारित की गई हैं। श्रमिकों की कोई मातृभूमि नहीं होती। वस्तुतः समस्त ससार के श्रमिकों की समस्याएँ एक हैं तथा उनमें कोई विरोध नहीं है।

जनतान्त्रिक व्यवस्था का विरोध (8)

शासन व्यवस्था के विषय में सिन्डीकलवादियों पर फ्रांस की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का प्रभाव पड़ा है। फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता, लोकतान्त्रिक सत्त्वाओं

16. जोड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ० 65.

17. जोड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ० 64.

का घोषा विपत्त; श्रमिक प्रतिनिधियों का श्रमिकों के प्रति विश्वासघात; शासन का श्रमिक मुद्धारों के प्रति उदासीन दृष्टिकोण आदि के कारण सिन्डीकलवादी सभी प्रकार की शासन व्यवस्था, विशेषतः लोकतान्त्रिक प्रणाली, के विरोधी हो गये तथा उसकी उन्होंने कटु आलोचना की। लोवतन्त्र की निन्दात्मक व्याख्या करते हुए सिन्डीकलवाद के प्रमुख प्रवक्ता सोरेल ने कहा था :—

“लोवतन्त्र मनुष्यों के मस्तिष्कों को उलझन में डालने में सफल होता है, बुद्धिमान व्यक्तियों को वास्तविकता पहचानने में रूकावट डालता है, क्योंकि इस व्यवस्था में वे भाग लेते हैं जो समस्याओं को उलझाने में निपुण हैं। लोवतान्त्रिक युग के विषय में यह कहा जा सकता है कि मानव शब्द-आडम्बर से शासित होता है न कि विचारों से; फारमूलेबाजी से न कि विवेक से....”¹⁸

सोरेल के अनुसार जन-शासन सिर्फ कल्पना है। संसदीय घातावरण हमेशा जहरीला रहता है। यह मनुष्य को छोटे-मोटे पूंजीपति के रूप में पतित कर देता है। जिस प्रकार बहुमत प्राप्त किया जाता है उससे किसी भी प्रकार की छुट्टाई की आशा करना व्यर्थ है।¹⁹ बहु-संघकों का शासन-गिद्धान्त मध्यवर्गीय भ्रष्टविश्वास के फलवा कुछ नहीं। संक्षिप्त में सिन्डीकलवाद—

- (i) लोकतान्त्रिक व्यवस्था का विरोध करता है, इसके साथ साथ,
- (ii) संसदीय प्रणाली में अविश्वास; तथा
- (iii) राजनीतिक दलों में किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं रखता।

अधिनायकत्व एवं राज्य समाजवाद का विरोध (9)

जब सिन्डीकलवाद में राज्य का विरोध किया गया है तो वे उन सभी सिद्धान्तों का विरोध करते हैं जिनके द्वारा राज्य की उपयोगिता एवं महत्ता को स्वीकार करने के साथ साथ राज्य को अधिनायकवादी अधिकार प्रदान करते हैं। इस सन्दर्भ में वे न तो सर्वहारा अधिनायकत्व (Dictatorship of the Proletariat) में घोर न राज्य समाजवाद (State Socialism) में विश्वास रखते हैं। सर्वहारा अधिनायकत्व प्रारम्भ में तो श्रमिकों को सत्ता उपलब्ध करता है किन्तु अन्तिम रूप में यह एक दल तथा एक नेता के अधिनायकत्व की स्थापना करता है। इसी प्रकार राज्य समाजवाद में सरकारी अधिकारियों का उत्पादन पर नियन्त्रण बढ़ जाता है। यह मनोवृत्ति उत्पादकों के लिये हानिकारक होती है।

भाषी समाज को हरेला (10)

सिन्डीकलवादियों ने जितना साधनों का महत्त्व दिया है उतना साध्य को नहीं।
जिन उद्देश्यों या भाषों समाज का ये सज्जन करना चाहते हैं उसका उन्होंने कोई

18. Quoted by Lancaster, L. W., Masters of Political Thought. Vol III, p 280

19 Ibid., pp. 280-81.

विशद चित्र प्रस्तुत नहीं किया है।²⁰ वास्तव में वे भावी समाज का व्यापक चित्र प्रस्तुत करना भी नहीं चाहते थे। उनका विश्वास था कि इस प्रकार की योजना प्रस्तुत करना असम्भव एवं अनावश्यक दोनों ही था। उनका कहना था कि ऐसा करने से निश्चय ही हानि होगी। समाज की कार्पनिक रूपरेखा यदि प्रस्तुत की जाय तो व्यक्तिगत में सुधारवादी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होंगी तथा पौडा बहुत हीर फेर करके वे इसी समाज व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे। इसलिये इस समय वे सिर्फ वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने तक ही अपने को सीमित रखते हैं।

इतना सब होते हुए भी सिन्डीकलवाद के व्याख्याताओं की रचनाओं में भावी समाज की कुछ मोटी सी रूप-रेखा मिल ही जाती है। विशेषतः दो भूतपूर्व पराज-कतावादी पातान्द (Patand) तथा पूगे (Pouget) की पुस्तक—How We Shall Bring About Revolution, 1913—में भावा सिन्डीकलवादी समाज का चित्रण किया गया है।

सिन्डीकलवादियों के विचारों से भावी समाज से सम्बन्धित कुछ सैद्धान्तिक बातें स्पष्ट हो जाती हैं जैसे—

प्रथम, वे माक्सवादियों की तरह रत्कालीन व्यवस्था का शान्ति द्वारा उन्मूलन कर किसी भी प्रकार के अधिनायवत्व के पक्ष में नहीं हैं।

द्वितीय, वे विकासवादी समाजवादियों की भाँति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था का भी निर्माण नहीं करेंगे।

तृतीय, सिन्डीकलवादी धराजवतावादियों की तरह राज्य को तत्काल समाप्त करने की कहते हैं किन्तु राज्य की समाप्ति के बाद के व्यक्तियों की अपनी इच्छानुसार समाज सर्जन करने के लिये स्वतन्त्र भी नहीं छोड़ना चाहते।

सिन्डीकलवादी समाज का मूल-आधार श्रमिक-संघ हैं। वे फास में स्थापित थमिक वनपेरेडेसन (C.G.T) के नमूने पर नवीन सामाजिक सगठन की बात सोचते थे। इस वनपेरेडेसन में दो-प्रकार की संस्थाएँ थी—सिन्डीकेट और बोर्ज (लेबर एक्सचेंज)। सिन्डीकेट में एक ही उद्योग से सम्बन्धित श्रमिक सम्मिलित हुआ करते थे, किन्तु बोर्ज स्थानीय-संस्था होती थी। एक बोर्ज में एक ही स्थान पर विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले थमिक शामिल होते थे। सिन्डीकलवादियों का विचार था कि बोर्ज जैसा थमिक-संघ स्थानीय सामाजिक सगठन की-इकाई होगा। इस प्रकार के स्थानीय सगठन के निम्नलिखित कार्य होंगे—

(1) उद्योगों से सम्बन्धित इमारतों, मशीन तथा अन्य उत्पादक सामग्री की सुरक्षा करना,

²⁰ जोड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ 65,

कोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 257.

- (ii) उत्पादन के सारे काम की देखभाल करना;
- (iii) माल के आयात-निर्मात की देखभाल करना,
- (iv) स्थानीय आर्थिक आवश्यकताओं से परिचित होना, तथा
- (v) इसी प्रकार के अन्य दूसरे श्रमिक संघों से सम्पर्क बनाये रखना, आदि।

सिन्डीकलवादियों राज्य का उन्मूलन तो करते हैं लेकिन वे भाषो समाज की व्यवस्था हेतु किसी न किसी प्रकार के केन्द्रीय संगठन का समर्थन करते हैं। वे राज्य से सम्बन्धित सस्थाओं जैसे कारागार, पुलिस, न्यायालय की समाप्ति की बात कहते हैं क्योंकि उनकी कल्पना है कि नयी सामाजिक व्यवस्था में इस तरह का वातावरण होगा जो हर व्यक्ति की उन्नति और विकास के अनुकूल हो। इनलिये अपराधों की स्वतः ही समाप्ति हो जायेगी। किन्तु कुछ ऐसे भी कार्य हैं जैसे डाक-व्यवस्था, रेल, माध्यात्मिक सेवाएँ, उद्योगों के मध्य ताल-मेल बँटाना आदि जिनके लिये वे राष्ट्रीय श्रमिक संघों को आवश्यक मानते हैं।

अन्त में तो जी. टी. की भाँति एक व्यापक राष्ट्रीय श्रमिक-संघ होगा जो उन सब मामलों के विषय में निर्णय लेगा जैसे उद्योगों में एक-सी नीति अपनाना, बच्चे, बूढ़े और बीमारों की देखभाल, काम के लिए न्यूनतम और अधिकतम ध्रायु का निर्णय, वेतन का माप दंड तथा काम के घण्टे आदि का निर्धारण करना।

रक्षा व्यवस्था के विषय में सिन्डीकलवादियों की धारणा है कि उनका समाज जारी युद्ध नहीं करेगा दूसरे श्रमिकों और जनता में इतना घनिष्ठ सम्पर्क होगा कि उनके मन में समाज विरोधी कार्य करने का विचार उत्पन्न ही नहीं होगा। इनलिये स्थायी पेशेवर सेना, पुलिस तथा सैनिक स्कूलों की आवश्यकता नहीं रहेगी। किन्तु कभी-कभी विशेष स्थिति या मामला करने के लिए हर संघ में सशस्त्र श्रमिकों की एक टुकड़ी होगी जिसका मुख्य कार्य प्रतिप्रियावादियों को रोकना होगा। कई संघों की ऐसी टुकड़ियाँ मिलाकर बड़ी टुकड़ियाँ बना ली जायेंगी जिन्हें केन्द्रीय संघ से अधिनार आदि दिये जायेंगे। प्रतिरक्षा की दृष्टि से सिन्डीकलवादी इतनी ही व्यवस्था को पर्याप्त समझते हैं।²¹

साधन-पद्धति (Means and Methods) (11)

यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि राजनीतिक साधनों से परिवर्तन करने में सिन्डीकलवादी विपनाग नहीं करते। वे श्रमिकों के कल्याण के लिए अपने प्रतिनिधियों को भी श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते। अनुभव से उन्होंने यह सीखा है कि श्रमिकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वयं पर ही निर्भर रहना चाहिये। "श्रमिकों

²¹ सिन्डीकल समाज की रूप रेखा के लिए देखिये—

जोड, आधुनिक राजनीतिक विद्वान्त-प्रवेशिका, पृ. 66-68.

बोरर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 255-58.

को राज्य की सत्ता ससद्-सदस्य या प्रतिनिधियों द्वारा परोक्ष रूप से प्राप्त करने की अपेक्षा न कर प्रत्यक्ष रूप से अपने मध्य की शक्ति द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।²² धार्मिक साधन ५०)

सिन्डीकलवाद साधनों के विषय में इस धारणा से प्रारम्भ होता है "कि धार्मिक शक्ति ही सत्ता ग्रहण करने की कुंजी है।" धर्मियों के राजनीतिक मत भिन्न-भिन्न होते हैं किन्तु उनके धार्मिक हित समान हैं अतः औद्योगिक क्षेत्र में उनमें एक प्रकार की ऐसी सुदृढ़ एकता होती है जिसका सामान्यतः राजनीतिक क्षेत्र में अभाव होता है। वे हड़ताल एक साथ करेंगे परन्तु एक मत से एक ही व्यक्ति को निर्वाचित नहीं करेंगे। प्रत्येक दृष्टि से राजनीतिक दल ज्ञान्ति वा एक अत्यन्त ही निर्बल साधन है, वह विभिन्न रहता है, उसके अधिवेशन कभी-कभी होते हैं, और उसका आकार इतना बड़ा होता है कि वह लोक-सर्वत्व को प्रत्यक्ष रीति से अभिव्यक्त नहीं कर सकता।²³

इस प्रकार सिन्डीकलवादी अपनी सारी शक्ति को धार्मिक क्षेत्र में केन्द्रित करते हैं, जो उन्हें एकता, सर्वता तथा अतिरिक्त शक्ति प्रदान करते हैं।

सिन्डीकलवादी अपने साधनों में माक्स के निवृत्त होते हुए भी उसकी शिक्षा का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते। वे ज्ञान्ति में इसलिये विश्वास नहीं करते क्योंकि उसके लिये स्थिति उपयुक्त नहीं है। पूँजीपति सौदा करके, समझौता करके, धर्मियों में मतभेद कर तथा स्वामी और श्रमिकों के मध्य अन्तर कम करने का प्रयत्न करते हैं। इन परिस्थितियों में ज्ञान्ति का सफल होना सदिग्ध है। किन्तु वे हिंसात्मक कार्यवाहियों से भी अचहेचना नहीं करते। "मह हिंसा ही है।" सोरेल के शब्दों में, 'जिससे समाजवाद उच्च नैतिक मान्यता ग्रहण करता है, जिनसे माध्यम से आधुनिक विश्व की मूर्ति होगी।'²⁴

२) प्रत्यक्ष कार्यवाही (direct action)—इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सिन्डीकलवादी कई साधनों का सुझाव देते हैं जिनके द्वारा पूँजीवादी व्यवस्था की समाप्ति कर श्रमिक संधी की व्यवस्था प्रारम्भ होगी। सभी साधन प्रत्यक्ष कार्यवाही (direct action) पर आधारित थे। सोरेल के शिष्य लेगारदे (Lagarde) के अनुसार, प्रत्यक्ष कार्यवाही का तात्पर्य था कि कार्यो को दूसरों पर न छोड़ा जाय जैसा कि प्रतिनिधि प्रणाली के अन्तर्गत होता है। श्रमिक वर्ग को स्वयं ही कार्यवाही करने के लिये हृदय निश्चित होना चाहिये।²⁵ इस प्रत्यक्ष-कार्यवाही के, सिन्डीकलवादीयों के अनुसार, निम्नलिखित स्वरूप है—

22 जोड, आधुनिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 68.

23 उपरोक्त, पृ. 69

24 Quoted, Bose, A., A History of Anarchism, p 312

25 Ibid, p 304

—ग्राम हड़ताल (General Strike)²⁶—सिन्धीकलवादी हड़ताल को सबसे प्रभावकारी साधन मानते हैं जिसके द्वारा वे पूँजीवादी व्यवस्था का अन्त कर सामाजिक शान्ति का उत्पादन के साधनों पर अधिकार कर लें। सोरेल की पुस्तक—Reflections on Violence—वास्तव में हड़ताल का ही दर्शन है। हड़ताल के घोषित्व को सही सिद्ध करने के लिए वे कई तर्क देते हैं, जैसे—

1. प्रथम, हड़ताल से श्रमिकों की दबी हुई शक्ति का प्रदर्शन होता है।

2. द्वितीय, यह श्रमिकों में सहयोग एवं एकता की भावना जागृत करती है।

3. तृतीय, यह वर्ग-भेद तथा दोनों वर्गों के मध्य तनाव पैदा करती है जिससे श्रमिकों में युद्ध करने जैसी शक्ति आती है और वे पूँजीवाद को उखाड़ने के लिये और दृढ़-सकल हो जाते हैं।

अतुर्थ, ग्राम हड़ताल के साधन को अपनाते से श्रमिक-वर्ग मध्य-वर्ग की धोखा-धड़ी में नहीं फस पाता।

पंचम, जब अनता अपने शासन से असन्तुष्ट होती है तो वह हड़तालों द्वारा अपना क्रोध व्यक्त करती है। इसका सरकार के विरुद्ध लोकमत निर्माण करने के लिये भी प्रयोग किया जाता है।

अन्त में, हड़ताल में श्रमिकों द्वारा हिंसा का प्रयोग नैतिक है। इससे उनकी मर्यादितता की अभिवृद्धि होती है।

हड़ताल के महत्व का यत्न करते हुए सोरेल ने कहा है:—

“हड़तालों द्वारा श्रमिक-वर्ग में श्रेष्ठतम, आन्तरिक तथा मर्मस्पर्शी भावनाओं का प्रकटन होता है; ग्राम हड़ताल उन सबका समुहिकरण कर एक संयोजित विभ्र-उपस्थित करती है और उन्हें एक-दूसरे के निकट लाकर प्रत्येक को अत्यधिक तीव्रता प्रदान करती है।”²⁷

इस सम्बन्ध में सिन्धीकलवादियों के विचारों को व्यक्त करते हुए लॉरबिन ने लिखा है कि—

“हिंसा-संपर्क में हड़ताल श्रमिकों और स्वामियों की धामने-सामने लाकर खड़ा कर देती है। विजय की चमक की भाँति हड़ताल श्रमिकों और मालिकों के बीच गहरे विरोध को एक दम स्पष्ट कर देती है। इससे

25 For detailed study of this method see Gray, A., The Socialist Tradition, pp 418-32.

27. “Strikes have engendered in the proletariat the noblest, deepest and most moving sentiments that they possess; the general strike groups them all in a co-ordinated picture, and by bringing them together gives to each one them its maximum intensity.”
Reflections on Violence, p. 137.

उनके बोध की खाई और भी गहरी हो जाती है जो मजदूरों की एकता तथा संगठन को दल प्रदान करती है। यह एक क्रान्तिकारी तत्व है जिम्मा महान महत्व है।" 28

सिन्डीकलिवादी जब हड़ताल की बात करते हैं, इससे उनका तात्पर्य आम हड़ताल (General strike) से है न कि उन छोटी मोटी हड़तालों से—जो बतन बौद्धि, बोनस, वाय अथवा घटान आदि व. लिये की जाती है। किन्तु सिन्डीकलिवादियों के अनुसार आम हड़ताल का तात्पर्य यह नहीं कि देश भर के मजदूर एक साथ कार्य करना बन्द कर दें। इसका अर्थ हड़ताल में बहु-संख्यक श्रमिकों का सम्मिलित होना भी नहीं है। एक सिन्डीकलिवादी के लिये वही आम हड़ताल है जि-देश के मुख्य उद्योगों में काम करन वाले मजदूर पर्याप्त सख्या में हड़ताल कर दें। उनका विश्वास था कि आधुनिक युग में इतनी पारस्परिक निर्भरता है कि अल्प सख्या में भी मजदूर प्रत्यक्ष कार्यवाही करके पूरी व्यवस्था को ठप्प कर देंगे। जैसे ही एक पर्याप्त सख्या में वर्ग-चेतना से ओत-प्रोत और अनुशासनवद्ध श्रमिक तैयार हो जाएँ वैसे ही आम हड़ताल की घोषणा कर उत्पादन साधनों पर अधिकार कर लेना चाहिये।

—सामान्यतः सिन्डीकलिवादी आम हड़ताल को ही प्राथमिकता देने हैं किन्तु वे दिन-प्रतिदिन छोटी-छोटी हड़तालों के महत्व की अवहेलना नहीं करते। उनके अनुसार प्रत्येक हड़ताल अपने में अच्छी चीज है। जब भी और जहाँ भी अवसर मिले हड़ताल को प्रोत्साहन देना चाहिये। हर हड़ताल आम हड़ताल की तैयारी में सहायक होती है। यदि कोई हड़ताल असफल भी हो जाये तो भी कोई हानि नहीं। कम से कम उससे श्रमिकों में वर्ग-चेतना, आत्मिकारी उत्साह और आन्दोलन के लिए उग्र भावना का विकास तो हुआ। ऐलेग्जेंडर ग्रे के शब्दों में "छोटी से छोटी हड़ताल यदि बार-बार की जाय तो श्रमिकों में समाजवादी भावना को प्रबल करने, उनमें वीरता, त्याग व एकता की भावना भरने तथा क्रान्ति की आशा को चिरस्थायी बनाये रखने में असफल नहीं हो सकती।" 29

ध्वसात्मक कार्य अथवा तोड़-फोड़ की नीति (Sabotage)—सिन्डीकलिवादियों का संप्रथ निरन्तर तथा कई प्रकार से चलता रहता चाहिये। हड़ताल के अलावा वे और भी अन्य साधनों का समयन करते हैं जैसे तोड़-फोड़, छाप (label) तथा बहिष्कार आदि। इन अन्य साधनों के अपनाने का मूल उद्देश्य यह है कि जब तक आम हड़ताल द्वारा पूरा जीवाद् तथा राज्य का विनाश न हो जाय तब तक श्रमिकों को निरन्तर उनका विशुद्ध कोई न कोई कार्य करते रहना चाहिये।

ध्वसात्मक कार्य का अर्थ, बोस्टर के अनुसार, यह है कि उद्योगपति की सम्पत्ति का विनाश श्रमिकों द्वारा आलस्यपूर्ण कार्यों, ढंग से—कार्य न. करने स्वामी की

28 Lorwin, L., Syndicalism in France, New York, 1914, pp 126-27

29 Gray, Alexander, The Socialist Tradition, pp 419-20

सम्पत्ति की फिजूलखर्ची तथा अन्य ध्वंसात्मक कार्यों से किया जाय। ध्वंसात्मक कार्यों को कारखानों में काम करते हुए या हड़ताल के समय कभी भी करते रहना चाहिये।³⁰ अन्य शब्दों में तोड़-फोड़ के मुख्य रूप है मन लगाकर कार्य न करना धीरे-धीरे काम करना, आदेशों का प्रक्षरशः पालन न करना, आहकों की वस्तुओं में दोष बतलाना जिससे वे वस्तुएं न खरीदें, मशीनों को जान बूझ कर खराब करना आदि। हालांकि सोरेल ने तोड़-फोड़ की नीति का विरोध किया, क्योंकि भविष्य इसमें श्रमिकों को हानि होगी तथा उनके चरित्र पर प्रभाव पड़ेगा, किन्तु सिन्डीकलवाद के प्रत्यक्ष साधनों में इसका भी महत्व रहा है।

१०४ छाप (Label)—इसका यह तात्पर्य है कि श्रमिकों के नियन्त्रित कारखानों में बनी हुई वस्तुओं पर श्रमिक एक छलक प्रकार की छाप लगाकर जनता से अपील करेंगे कि वे सिर्फ श्रमिकों द्वारा नियन्त्रित कारखानों में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें न कि पूंजीपतियों के कारखानों में निर्मित माल। सिन्डीकलवादी समझते थे कि पूंजीपतियों के माल की बिक्री पर गहरा एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

वहिष्कार—वहिष्कार साधन के अन्तर्गत श्रमिक पूंजीपतियों के माल का बहिष्कार करने का प्रचार करेंगे। जहां सम्भव होगा वहां वे स्वयं भी वहिष्कार में भाग लेंगे। इससे वे पूंजीपतियों के माल की बिक्री में विघ्न डालकर हानि पहुंचा पाते हैं।

इसके साथ-साथ श्रमिक कैंकनी-नीति ('Ca' canny) नीति भी अपनाएँ इसका अर्थ है कि वे अधिक सावधानी से काम करें ताकि पूरे समय में बहुत काम हो।³¹

उपरोक्त सिन्डीकलवादी साधन वास्तव में हिंसा और अहिंसा दोनों का मिश्रण है। हड़ताल हिंसात्मक या बिना हिंसा के भी हो सकती है। तोड़-फोड़ नीति के साथ हिंसा सम्बन्धित है। किन्तु 'छाप' तथा वहिष्कार अहिंसात्मक श्रेणी में आते हैं। फिर भी सिन्डीकलवादी इन सभी साधनों को हिंसा पर आधारित मानते हैं क्योंकि वे हिंसा को भी अपने कार्य-क्रम एवं दर्शन में उचित स्थान देते हैं।³² भी हो उनके साधन पूर्णतः हिंसात्मक नहीं हैं।

(1) सिन्डीकलवाद का मूल्यांकन

सिन्डीकलवाद का अविद्वेकीन (Irrationalist) आधार

सिन्डीकलवाद तथा इसके प्रमुख ध्यात्मता सोरेल के विचारों का आधार है। अविद्वेकीवाद का तात्पर्य किसी वान की तथ्यो तथा तर्क संगतता के आधार पर कार्य करना नहीं होता। इनके अन्तर्गत मनुष्य की भावनाओं और मूल प्रवृत्तियों का

30. बोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 252-53.

31. जोर, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 71.

होगा है।³² अधिवक्तावादी मानते हैं—उद्देश्य-की प्राप्ति-के-दिये भ्रान्तिपूर्ण (myth) का सहारा लेते हैं। जब सिन्डीकलवादी का यह आधार है तो विवेक, तर्क-बद्धता की अपेक्षा करता व्यर्थ है। जहाँ पर बुद्धिजीवियों की पूर्ण निन्दा की जाती हो तो ऐसी विचारधारा से ज्ञान अज्ञान के तत्व हूँदना भी असम्भव है। यही कारण है कि भराजवतावाद में सर्वत्र दोष ही दोष दृष्टिगोचर होने हैं।

राज्य का विरोध 2)

माक्सवादी एवं भराजवतावादियों की भाँति सिन्डीकलवादी राज्य के उन्मूलन का समर्थन करते हैं। सिन्डीकलवादियों का यह विचार बिल्कुल ही अभ्यावहारिक है। मनुष्य के जीवन में राज्य के महत्व की जो वृद्धि हो रही है तथा यह सस्था सक्रिय रूप से जिस प्रकार सभ्यतामय एवं जनवल्यास के कार्यों को अपने हाथों में ले रही है इससे तो यही निश्चिन्त होता है कि राज्य मनुष्य का मित्र है तथा अच्छे जीवन व्यतीत करने में सहायता देने के लिये सर्वोत्तम साधन है।

हालाँकि सिन्डीकलवादी राज्य की समाप्ति की बात कहते हैं लेकिन जिस समाज की वे कल्पना करते हैं तथा जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय धर्म सगठनों को जो अधिकार दिये जायेंगे वे वास्तव में वे ही कार्य हैं जिन्हें आजकल राज्य करता है। इस प्रकार एक ओर तो ये राज्य के उन्मूलन का समर्थन करते हैं लेकिन दूसरी ओर पिछले दरवाजे से वे राज्य को पुनः वापस ले आते हैं। इस सम्बन्ध में बार्कर (Ernest Barker) के विचार उल्लेखनीय हैं। बार्कर ने लिखा है कि—

“या तो राज्य की समाप्ति हो जानी चाहिये जैसा कि सिन्डीकलवादी व्यक्त करते हैं, इसका तात्पर्य भराजवता (अस्त-व्यस्त या उथल-पुथल) होगा, या फिर राज्य को रहना चाहिये—और यदि आप समाजवाद चाहते हैं तो वह राज्य द्वारा ही सम्भव हो सकेगा। अगर राज्य को रखना है तो राज्य में अपने नागरिकों के जीवन से सम्बन्धित अंतिम रूप से उत्तरदायित्व निहित होना चाहिये।”³³

राष्ट्रीयता 3)

सिन्डीकलवादी राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के विरोधी हैं। ये धर्मियों का न तो कोई राष्ट्र मानते हैं और न राष्ट्रीयता। यह सिर्फ एक भावि ही है। राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता की

32 Kitzler and Ross, Western Social Thoughts, p. 281

33 “Either the state must go, as Syndicalists seems to advocate, and that means chaos, or the state must remain and then, if you are to have Socialism it must be a state Socialism. If there is to be a state, it must have the final responsibility for the life of its citizens”

Barker, E., Political Thought in England, p. 203

परिधि को लाँफकर सिन्डीकल समाज की स्थापना ठीक प्रतीत नहीं होती।³⁴ युद्ध के समय यह बात कई बार स्पष्ट हो चुकी है कि विभिन्न देशों के श्रमिक अपने-अपने देशों की सरकार को किस प्रकार व्यापक समर्थन देने हैं। श्रमिकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एकता की बात किसी सीमा तक स्वीकार की जा सकती है किन्तु राष्ट्र को समाप्त कर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक समाज की स्थापना करना एक यूटोपियायी विचार ही प्रतीत होता है।

मध्यम वर्ग

मिन्डीकलवादियों ने मध्यम वर्ग की जो निन्दा की है वह उनकी मूर्खता का प्रमाण है। प्रत्येक समाज में मध्यवर्ग संख्या में सबसे अधिक, अतिवादितों का विरोध करने वाला तथा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान करने वाला होता है। यह बात आधुनिक राज्य में ही सही नहीं किन्तु प्राचीन काल में अस्तु ने भी राजनीति में मध्यमवर्ग के योगदान को व्यापक रूप से स्वीकार किया। मध्यम वर्ग का उन्मूलन कौन भी स्थायी समाज की स्थापना नहीं हो सकती।

निश्चित भावी समाज की व्यापक रूप रेखा का अभाव

सिन्डीकलवादियों के समक्ष कोई निश्चित आदर्श-समाज की व्यापक रूप रेखा नहीं है। वे जो भी रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं वह न तो स्पष्ट है और न निश्चित इसलिए यह विचारधारा उद्देश्य-हीन प्रतीत होती है। जिस विचारधारा में निश्चित उद्देश्य नहीं होने तो उसके प्रभाव का संकुचित होना भी स्वाभाविक था। कोई व्यक्ति हड़ताल या हिंसात्मक कार्योंवाहियों में क्यों सम्मिलित होगा जब उसके यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा करने के लिये वह किसलिसे प्रेरित हो रहा है। उद्देश्यहीन विचारधारा कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकती।

संकीर्ण शोभीयवाद (6)

लेकिन सिन्डीकलवादियों ने अपना जो सामाजिक रूप रेखा प्रस्तुत की है उसी स्थानीय श्रमिक संघों को अत्यधिक महत्व दिया है। आलोचकों का कहना है कि प्रसार को व्यवस्था संकुचित शोभीयवाद को जन्म देगी जो सामाजिक एकता की प्रगति के मार्ग में बाधक होगी।³⁵

उपभोक्ताओं की अवहेलना (7)

मिन्डीकलवाद एकपक्षीय विचारधारा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह उत्पादकों का ही समाजवाद है। वे उपभोक्ताओं की पूर्णतः अवहेलना करते हैं लेडलर (Laidler) के शब्दों में "उत्पादकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों पर बहुत अधिक और उपभोक्ताओं के अधिकारों और उत्तरदायित्वों पर बहुत कम

34. आनीवार्दम्., राजनीतिशास्त्र, द्वितीय भाग, पृ. 621.

35. जोर., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेगिता, पृ. 67.

देकर यह उपभोक्तियों को अपने विरुद्ध कर देता है।³⁶ कोई भी विचारधारा तब तक पूर्ण या व्यावहारिक नहीं हो सकती जब तक वह समाज के इन दोनों श्रेणियों के हित को ध्यान में न रखे।

(8)

सिन्डीकलिवादी साधनों की आलोचना

सिन्डीकलिवादी साधन-पद्धति के विरुद्ध प्रारम्भिक चोप यह है कि ये हिसा को मान्यता देते हैं। सिन्डीकलिवादी हिंसा को शान्ति के अन्तर्गत भी नहीं लिया जा सकता। वे हिंसात्मक साधना का जिस सीमा तक प्रयोग करें, स्पष्ट नहीं है। नैतिक दृष्टि से हिंसात्मक साधनों के औचित्य को कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता।

सिन्डीकलिवादियों का मुख्य शस्त्र हड़ताल है। इस साधन की आलोचकों ने बटु नन्द्या की है। हड़ताल को द्वारा सामाजिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये आम हड़ताल द्वारा शान्ति एक भ्रम है। यदि एक बार हड़ताल प्रारम्भ हो जाती है और लम्बी चल जाय तो इसका श्रमिकों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। वे भूखो मरने लगते हैं। इस प्रकार हड़ताल की सफलता बहुत कुछ श्रमिकों की प्राथमिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब श्रमिकों द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है उसके बाद कोई नहीं जानता कि इसका अन्त कहाँ होगा। यह श्रमिकों के समक्ष अनिश्चितता का वातावरण प्रस्तुत करता है जो सफलता के मार्ग से बाधक सिद्ध होता है। "आम हड़ताल एक कल्पना मात्र है। यह सगठित श्रमिकता से अधिक शीघ्र कुच्छ नहीं है।"³⁷

सिन्डीकलिवादियों द्वारा आयोजित की गयी हड़तालों पर यदि दृष्टिपात किया जाये तो उनकी व्यवहार में अनुपयुक्तता एवं असफलता स्वाभाविक प्रतीत होती है। 1894 से 1907 तक मात्र म हजारों हड़तालों हुईं लेकिन उनमें 23 प्रतिशत उफल, 36 प्रतिशत में समझौता हुआ तथा 41 प्रतिशत असफल हुईं। यहाँ तक कि 1906 में आयोजित देश व्यापी विशाल हड़ताल पूर्णतः असफल रही।³⁸ इससे नहीं निष्कर्ष निकलता है कि हड़तालों द्वारा सिन्डीकलिवादी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब देश में बार-बार हड़तालों की जायेंगी उससे जन जीवन पर जो असर पड़ेगा उसके परिणामस्वरूप सिन्डीकलिवादी सामान्य जनता को भी अपने पक्ष में नहीं कर सकने।

अन्य साधन जैसे तोड़-फोड़, बहिष्कार आदि अधिक प्रभावशाली प्रतीत नहीं होते। तोड़-फोड़ की नीति द्वारा शान्ति का नारा एक मजाक सा प्रतीत होता है। तोड़-फोड़ की नीति से श्रमिकों को भी हानि उठानी पड़ेगी, मशीनें नष्ट हो जायेंगी,

³⁶ Laidler, H. W., History of Socialist Thought, P 310

³⁷ आशीर्वादम्., राजनीति शास्त्र, द्वितीय भाग, पृ 621.

³⁸ Bose, A., A History of Anarchism, p 322

कारगाने बन्द हो जायेगे और उन्हें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। निरंतर तोड़-फोड़ करते रहने से श्रमिकों का चरित्र गिर जायेगा, उनमें जिम्मेदारी की भावना नष्ट हो जायेगी। यह आशा करना व्यर्थ होगा कि क्रान्ति के बाद तोड़-फोड़ करने वाले श्रमिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करेंगे। वास्तव में गिन्डीकलवादियों के साधनों में खोखलापन अधिक है तथा वे सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये अनुपयुक्त सिद्ध होंगे।

प्रभाव एवं योगदान

गिन्डीकलवाद का काफी अध्ययन हुआ है। कई विद्वानों ने इस पर व्यापक टीकाएँ की हैं। इतना सब होते हुए भी, ऐलेग्जेन्डर ग्रो का मत है, निष्कर्ष में लिखने के लिये लगभग कुछ भी नहीं है।³⁹ इस कथन में सत्यता तो है किन्तु गिन्डीकलवादी विचारधारा ने कुछ प्रभाव अवश्य ही छोड़े हैं। लोकतन्त्र की...

गिन्डीकलवाद का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव लोकतन्त्र के विकास पर पड़ा। इस विचारधारा के प्रादुर्भाव से यूरोप में जितनी अधिक सध्या में व्यक्ति इससे प्रभावित हुए यह एक आश्चर्य की बात थी। इससे पनपते हुए लोकतन्त्र का मार्ग अवश्य ही भ्रष्ट हुआ। किन्तु इसने लोकतन्त्र के समर्थकों को एक आत्म-विवेचन (self analysis) का अवसर प्रदान किया। वे इस बात पर विचार करने लगे कि आगिर लोकतन्त्र व्यवस्था में क्या कमी है जिसके कारण इतनी संख्या में व्यक्ति लोकतन्त्र से विमुख हो रहे हैं।⁴⁰ इस आत्म-विवेचन से लाभ ही हुआ। कई देशों में लोकतन्त्र की वृद्धियों को दूर करने के प्रयत्न किये गये सुधारों की शृंखला में वृद्धि हुई।

गिन्डीकलवाद के प्रभाव ने आगे चलकर फासीवाद (Fascism) को प्रोत्साहित किया। शुरू की बातों में गिन्डीकलवाद तथा फासीवाद में व्यापक अन्तर है किन्तु इनके बीच एक बड़ी मजबूत बड़ी है। मुसोलिनी सोरेल की रचनाओं को पढ़े पाठ में पढ़ता था। वास्तव में मुसोलिनी ने 1922 में गिन्डीकलवादी साधनों से ही सत्ता प्राप्त की।⁴¹

अनिग्रनाथ बोम ने गिन्डीकलवाद के योगदान की चर्चा करते हुए लिखा है कि इस विचारधारा की शक्ति इसमें निहित है कि इसने श्रमिकों में तोड़ता, आत्म-विश्वास और साहस की भावना का विकास किया। द्वितीय, इन्होंने आर्थिक समस्याओं को सर्वाधिक महत्व दिया। ये आर्थिक सुधारों के लिये निरन्तर दबाव बनाये रहे। परिणामस्वरूप श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये यूरोप में कानूनों के

39. Gray, A, The Socialist Tradition, pp. 430-31.

40. Hallowell, J. H, Main Currents in Modern Political Thought, p. 463.

41. Sabine, G H, A History of Political Theory, p 714

निर्माण की गति में तेजी आई। तृतीय, सिन्डीकलवाद का आधुनिक राजनीतिक चिन्तन को सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज के बहुलवादी सिद्धान्त (Pluralism) का व्यापक प्रतियोगदान करना था, जिससे व्यावसायिक आर्थिक संस्थाओं (functional economic organisations) की महत्ता स्वीकार की गई।⁴²

पाठ्य-ग्रन्थ

1. Bose A , A History of Anarchism , Chapter IV, Syndicalism
2. कौकर, फ्रान्सिस , आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, अध्याय 8 सिन्डीकलिज्म
3. Gray, A , The Socialist Tradition, Chapter 15 Syndicalism
4. जोड., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, अध्याय 4 शिल्पी सघवाद (सिन्डीकलवाद) और श्रेणी-सघवाद
5. Laidler, H W , History of Socialist Thought, Chapter XXII.
6. Lancaster, L W , Masters of Political Thought, vol III, Chapter 8, Irrationalism, George Sorel

⁴² Bose, A , A History of Anarchism, p 322.

फेबियनवाद

फेबियनवाद समाजवाद की एक अंग्रेजी विचारधारा है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्क्सवाद चर्चा तथा विवाद का मुख्य विषय था। मार्क्स ने अपने विचारों का प्रतिपादन इंग्लैण्ड में ही किया। किन्तु मार्क्सवाद वहाँ के लोगों को प्रभावित नहीं कर सका। इंग्लैण्ड की उदारवादी, व्यावहारिक तथा समझौता प्रिय जनता पर मार्क्सवाद के वर्ग-सर्प, श्रान्ति तथा अन्य विचारसूत्रों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इससे भी मना नहीं किया जा सकता कि मार्क्स ने उस समय के विचार चिन्तन को नया मोड़ नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति जिरमं थोडी बहुत चिन्तन-क्षमता थी इस प्रवाह से अलग नहीं रह सका। इसके साथ-साथ उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति भी ऐसी थी जिसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता थी। इन सभी कारणों ने इंग्लैण्ड के बुद्धिजीवी-वर्ग को चिन्तन के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप फेबियनवाद का अस्तित्व हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार बीयर (M. Beer) का विचार है कि उस समय सामाजिक-आर्थिक-नैतिक कारणों से कई प्रकार की राष्ट्रीय समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी थीं। उन्हें सुलभाने के लिए राष्ट्रीय प्रयत्नों की आवश्यकता थी ताकि देश दक्षता और प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। इस कार्य को विचार-चिन्तन के माध्यम पर पूरा करने का दायित्व फेबियनवादियों ने लिया।¹ इस प्रकार एक नई समाजवादी शाखा का जन्म हुआ।

फेबियन-समाजवाद का मुख्य विचार-स्यत फेबियन सोसायटी (Fabian Society) था। फेबियन सोसायटी का प्रादुर्भाव एक समाजवादी संस्था के रूप में नहीं हुआ था। 1883 में थॉमस डेविडसन (Thomas Davidson, 1840-1900) जो स्कॉटलैण्ड में पैदा हुए तथा अमेरिका में एड. निशा शास्त्री का काम कर रहे थे, का लन्दन आगमन हुआ। ये नैतिकवादी एवं रहरवादी थे तथा एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो इस अण्डपूर्ण विषय से दूर हो। इस तत्त्व में इनके प्रवचनों का लंदन में आयोजन किया गया। लंदन का बुद्धिजीवी समूह इनसे बहुत प्रभावित हुआ तथा डेविडसन के आदर्शों की उपलब्धि के लिए एक संस्था की स्थापना की गयी। लेकिन

1. Beer, M., A History of British Socialism, Vol II, p 277.

ये उद्देश्य तो घृष्टभूमि में रह गये और समाजवादी उद्देश्यों को लेकर एक नए सगठन को स्थापना हुई। इस प्रकार जनवरी 4, 1884, को फेबियन सोसायटी को स्थापना हुई। इस सोसायटी के सदस्य एक रोमन जनरल फेबियस क्वटेटर (Fabius-Cunctator) की कार्य पद्धति से बड़े प्रभावित थे। इसलिए इस सस्था का नाम फेबियस के नाम पर फेबियन सोसायटी रखा गया। ग्रे के अनुसार सस्था का नामकरण कोई सुखप्रद नहीं था।² इस सोसायटी के ज्ञान की व्याख्या फ्रैंक पॉडमोर (Frank Podmore) द्वारा लिखित इसके आदर्श-सूत्र (motto) से होती है। इन सम्बन्ध में लिखा गया है कि—

‘आपको उपयुक्त अवसर के लिए उसी प्रकार प्रतीक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार होर्नबॉन स युद्ध करते समय फेबियस ने की थी, यद्यपि कई लोगों ने देर करने के लिए उसकी निन्दा की थी, किन्तु जब अवसर आ जाता है तो आपको फेबियस के समान कठिन चोट करनी चाहिए अन्यथा आपका प्रतीक्षा करना व्यर्थ एवं निष्फल होगा।’³

कुछ ही समय में फेबियन सोसायटी ने इंग्लैंड के कई प्राख्यात बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया जिनमें प्रमुख थे—सिडनी वेब (Sydney Webb), श्रीमती बीट्रिस वेब (Mrs Beatrice Webb or Mrs Sidney Webb), जाज बर्नार्ड शॉ (George Bernard Shaw), सिडनी ऑलीवियर (Sydney Olivier), ग्राहम वालास (Graham Wallas), श्रीमती ऐनी बेसेन्ट (Mrs. Annie Besant) ह्यूबर्ट ब्लॉ (Hubert Bland), विलियम क्लार्क (William Clarke), कैम्पबेल (J Campbell), हेरॉल्ड लास्की (Harold Laski), कोल (G D H Cole) आदि। किन्तु इनमें सबसे प्रमुख एवं प्रारम्भिक योगदान सिडनी वेब तथा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का था। ये ही फेबियनवाद के प्रवर्तक थे।⁴

फेबियनवाद के विकास की प्रमुख विशेषता यह है कि इस समाजवादी विचार-धारा के प्रतिपादकों का धर्मिकी से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, यह सिर्फ़ अर्थशास्त्री विद्वानों के मस्तिष्क की उपज थी। दूसरे, यह वह समाजवादी सम्प्रदाय था जिस पर पूर्व समाजवादियों जैसे श्रोडन या मार्क्स आदि का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये इसकी

2 Gray, A, The Socialist Tradition, p 386

3 “For the right moment you must wait, as Fabius did most patiently when warring against Hannibal, though many censured his delays, but when the time comes you must strike hard, as Fabius did, or your waiting will be in vain, and fruitless”

Pease, Edward R, History of the Fabian Society, p 32


4 Beer, M, A History of British Socialism, Vol II, p 217

प्रेरणा के स्रोत नहीं हैं।⁵ इसकी प्रेरणा के स्रोत तो कुछ गर-समाजवादी व्यक्ति जैसे रिकार्डो (David Ricardo), मिल (J. S. Mill), हेनरी जार्ज (Henry George) आदि हैं। बार्कर (Ernest Barker) का विचार है कि पेबियनवादियों पर मुख्य प्रभाव मिल का था। उन्होंने मिल के आर्थिक विचारों का अनुकरण किया। मिल ही ने यद्भाव्यम् (laissez faire) नीति और सामाजिक समन्वय (social adjustment) तथा राजनीतिक प्रगतिवाद (Political Radicalism) और आर्थिक सामाजिकरण (economic socialisation) के मध्य सेतु स्थापित किया। लगभग यही कार्य पेबियनवादियों का था।⁶

पेबियन सोसायटी के सभी सदस्य प्रथम श्रेणी के बुद्धिजीवी समालोचक थे। मोगापरी की स्थापना के बाद इनका प्रथम कार्य उस समय की आर्थिक-सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर कुछ निष्कर्षों का निर्धारण करना था। इन्होंने मार्क्स, लासेल (Lassalle), प्रथों, घोवन, प्रमुख अर्थ-शास्त्री - स्मिथ, रिकार्डो तथा मिल आदि के विचारों का अध्ययन किया। यह अध्ययन 1884 से 1897 तक चलता रहा। इन वर्षों में मार्क्स घोवन तथा चार्टिस्ट आन्दोलनकारी इनको आलोचना के प्रमुख केन्द्र थे। मार्क्स तथा घोवन से ये प्रभावित तो हुए किन्तु उनके विचार पेबियनवादियों के लिए चाह्य नहीं थे। बीयर (M. Beer) के शब्दों में:—

“घोवन-समाजवाद संक्षिप्त एवं साधारण था; मार्क्सवादी समाजवाद आन्तिकारी एवं सैद्धान्तिक था; पेबियन समाजवाद सामाजिक पुनरुत्थान के लिए दिन-प्रतिदिन की राजनीति था।”⁷

फिर भी ये स्वयं को घोवन तथा मार्क्स से पृथक् नहीं कर सके। घोवन हमें इ-निवादी थे। उनके समाजवादी विचार और सहकारिता के क्षेत्र में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता था। मार्क्सवाद पूर्ण यूरोप पर छाया हुआ था। कोई भी समाजवाद मार्क्सवाद के विवेचन के बिना अपूर्ण था।

 फेबियन समाजवाद के सिद्धान्त
फेबियनवादियों द्वारा इतिहास की व्याख्या

अपने सैद्धान्तिक लेखों में पेबियन समाजवादियों ने ऐतिहासिक एवं आर्थिक आधार स्पष्ट करने में मार्क्सवादी परम्परा का अनुसरण किया। किन्तु इतिहास तथा अर्थ-शास्त्र में उन्होंने जो मामूली की एवं जो निष्कर्ष निकाले हैं वह मार्क्स से भिन्न हैं।

5 “The early Fabians owed little to previous Socialist thinkers, and in particular nothing to either Owen or Marx. Their intellectual derivation was wholly non-socialists—from Ricardo, Mill, Jevons, and Henry George” Crossland, J. C. A. R., The Future of Socialism, p. 84.

6 Barker, E. Political Thought in England, p 90.

7 Beer, M., History of British Socialism, Vol. II, p. 281.

पेवियनवादियों के अनुसार इतिहास यह बतलाता है कि समाज स्थिर नहीं है। इतिहास में समाजवाद की जो व्याख्या है उससे मार्क्स की तरह यह सिद्ध नहीं होता कि प्रत्येक वस्तु पर आर्थिक अवस्थाओं का आधिपत्य रहता है। पेवियन यह मानते हैं कि इतिहास लोकतन्त्र तथा समाजवाद की ओर एक निरन्तर प्रगति प्रकट करता है। इस सम्बन्ध में सिडनी वेब लिखते हैं कि इतिहास 'लोकतन्त्र की अदम्य प्रगति' और 'समाजवाद की प्रायः निरन्तर प्रगति' को लगातार व्यक्त करता है। यह इस बात से स्पष्ट हो जाना है कि इंग्लैण्ड में कुलीनतन्त्र से बिना प्रकार मध्यवर्गीय लोकतन्त्र में परिवर्तन हुआ तथा आर्थिक क्षेत्र में विपुल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का धीरे-धीरे निष्कासन हो रहा है।⁸

पेवियनवाद का आर्थिक पक्ष⁽¹⁾

पेवियनवाद आर्थिक विकास के सिद्धान्त पर आधारित है। यह आधार समाज द्वारा उत्पन्न मूल्यों के सिद्धान्त में निहित है। रिकार्डो (David Ricardo, 1772-1823) ने लगान-सिद्धान्त (Theory of Rent) के आधार पर 'परिश्रम-हीन आय' (uncearned increment) के सिद्धान्त को जन्म दिया। पेवियनवादियों ने यह स्वीकार करते हुए यतलाया है कि 'परिश्रम-हीन आय' का सिद्धान्त सिर्फ भूमि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उद्योगों के ऊपर भी चरितार्थ होता है। किसी उद्योग में पूंजी लगाने मात्र से किसी भी व्यक्ति को उनकी आमदनी का उचित अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। उद्योगों में 'परिश्रम हीन आय' को मुट्ठी भर पूंजीपति भूमि और पूंजी पर स्वामित्व के कारण हड़प जाते हैं।⁹ वास्तव में यही समाज में अनेक बुराइयों का मूल कारण है। इससे आर्थिक विषमता फैलती है। धनिक वर्ग के हाथों में पूंजी के वेन्दोकरण होने से वह अपना दुरुपयोग विलासिता के साधनों पर करता है, जब कि दूसरी ओर जनसाधारण निर्धन होने जाते हैं। इन बुराइयों का धन केवल भूमि और पूंजी का राष्ट्रीयकरण या सामाजिककरण (socialisation) करके ही किया जा सकता है। पेवियनवादी राज्य के आर्थिक साधनों पर किसी भी एक वर्ग का नियंत्रण स्वीकार नहीं करते। वे उत्पादन साधनों को समस्त समाज की सम्पत्ति मानते हैं।

पेवियनवाद के समर्थक मार्क्सवादी मूल्य का थम-सिद्धान्त (Labour Theory of Value) को स्वीकार नहीं करते। इसके अनुसार थम ही एक मात्र मूल्य का निर्धारक तत्व नहीं है। इसके विपरीत में जेवन्स (Jevons) द्वारा प्रतिपादित सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त (Marginal Utility Theory) को मान्यता देने हैं, जिसका अनुसार मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के सिद्धान्त (Theory of Demand

⁸ फोर्जर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 110-111.

⁹ Sabin, G. H., A History of Political Theory, p 619

and Supply) तथा मिल (J.S. Mill) द्वारा विकसित उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) के द्वारा होता है।

फेबियनवादियों के अनुसार प्रतिरिक्त मूल्य का स्रोत श्रमिक या पूँजीपति की परिश्रम-हीन आय नहीं है। यह आय उत्पादन साधनों के स्वामित्व के परिणाम-स्वरूप भाड़े (rent) से प्राप्त होती है। किन्तु फेबियनवादी यह मानने को भी तैयार नहीं हैं कि यह आय भूमि तथा पूँजी के व्यक्तिगत स्वामियों को मिलनी चाहिये। यह अन्वय है। इस आय पर समस्त समाज का अधिकार होता है। 'वह शासन जो सामाजिक सुधारों के प्रति गम्भीर है उसे अपना ध्यान उस ओर देना चाहिये जिससे औद्योगिक तथा कृषि आय का उपयोग आंशिक रूप से करो द्वारा, आंशिक रूप से म्यूनिसिपलकरण और राष्ट्रीयकरण द्वारा सम्पूर्ण समाज के हित में किया जाय।'¹⁰

(ii)

वर्ग-संघर्ष सिद्धान्त का विरोध

फेबियनवादियों ने स्वयं को न तो कभी श्रमिकों का प्रतिनिधि कहा और न उन्होंने कोई पृथक वर्ग बनाने का प्रयत्न ही किया। अपने समाजवादी उद्देश्यों को प्राप्त के लिये उन्होंने वर्ग-संघर्ष को मान्यता नहीं दी। किन्तु उनके विचारों में वर्ग-संघर्ष का प्राभास अवश्य मिलता है। "जहाँ तक वर्तमान उत्पादन एवं वितरण प्रणाली समाज में हित-संघर्ष को उत्पन्न करती है वह संघर्ष फेबियनों के अनुसार वेतन पर काम करने वालों तथा उनको काम में लगाने वालों के बीच नहीं बरन् एक ओर समाज और दूसरी ओर पूँजी लगाकर धनी बन जाने वालों के बीच है।"¹¹ कुछ भी हो, फेबियनवादियों का उद्देश्य वर्ग-संघर्ष-द्वारा एक वर्ग का विनाश कर दूसरे वर्ग की शासन व्यवस्था स्थापित करना नहीं था। फेबियन समाजवाद उन समस्त योजनाओं को हटनापूर्वक अस्वीकार करता है, जो समाज के समस्त उत्पादन को किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को सौंपती है। उसका उद्देश्य स्वाम्य श्रमियों को नहीं समाज को सौंपना है। इस हस्तान्तरण में उन्होंने क्रमिक विकास के अवश्यभावोपन (inevitability of gradualness) पर जोर दिया है।

फेबियन समाजवाद के उद्देश्य (iii)

यह प्रायः यह कहा जाता है कि फेबियन सोसायटी न तो समाजवादी दल था और न मूलतः कोई समाजवादी विचारधारा, किन्तु कुछ व्यक्तियों के एक सन्नूह द्वारा उस समय की प्रावश्यक सामाजिक समस्याओं को सुलभाने के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रसार करना तथा उनकी प्राप्ति के लिये व्यवस्थापित तथा प्रशासनिक

10 Beer, M., A History of British Socialism, Vol. II, p. 283

Also see Kilzer and Ross, Western Social Thought, p. 284

11. बीयर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 112-113.

समाधान की ओर इंगित करना था 12 प्रारम्भिक फेबियन समाजवादी निःनालिखित सामान्य समझोते से प्रतिज्ञाबद्ध थे —

“इस सोझाघटी के सदस्य यह मानते हैं कि प्रतियोगी प्रणाली से सुख-सुविधाएँ कम व्यक्तियों को मिलनी हैं और बहुसंख्यक जनता को कष्ट मिलता है इसलिए समाज का पुन सगठन इस प्रकार होना चाहिए जिससे समाज के समस्त व्यक्तियों का सुख एवं कल्याण सुनिश्चित हो सके।”¹³

1894 में बर्नार्ड शा द्वारा तैयार किये गये घोषणापत्र में सोझाघटी ने अग्रिम स्पष्ट शब्दों में समाजवाद को स्वीकार किया तथा कहा कि भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और राज्य को प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिए।

फेबियनवाद में समय समय पर तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्यों में समोधन एवं परिवर्धन हुए हैं। 1919 में फेबियनवादियों ने फिर यह घोषणा की कि—

“भूमि और औद्योगिक पूँजी को व्यक्तिगत स्वामित्व से मुक्त करके और उन्हें सार्वजनिक हित के लिए समाज के हाथों में सौंप कर समाज का पुनर्गठन करना इसका लक्ष्य है। सभी देश की प्राकृतिक और अर्जित सम्पत्ति को पूरी जनता में न्यायपूर्वक बाँटना सम्भव है।”

“इसलिए भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का उन्मूलन करने के लिए समाज कदम उठाता है। ऐसा करने में वह प्रतिष्ठित भाषाओं का और धर तथा यथोचित के स्वामित्व का न्यायसम्मत विचार रखता है। यह उन सब उद्योगों को समाज के आधिपत्य में लाने के कदम उठाता है, जिनका संचालन सामाजिक रीति से किया जा सकता है तथा उत्पादन, वितरण और सेवा के नियमन में व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सार्वजनिक हित को प्रधान लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है।”¹⁴

इन उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए लेडलर (H W Laidler) ने लिखा है कि इसका यह अर्थ हुआ कि फेबियनवाद —

प्रथम, पूँजीवाद से समाजवाद के संक्रमण को एक क्रमिक प्रक्रिया मानता है।

द्वितीय, शान्तिपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक उपकरणों के माध्यम से ही उद्योगों के सामाजिककरण की आवश्यकता समझता है।

12 Beer, M, A History of British Socialism, Vol, II pp 276-77

13 Pease, Edward R, History of the Fabian society, p 269

14 Pease, Edward R, History of the Fabian Society, p 259

तृतीय, मध्यवर्ग को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसका उपयोग नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए शासन कला का विकास करने में किया जा सकता है।

— चतुर्थ, समाजवाद को प्राप्ति के लिए समाजवादी आदर्शों के विषय में सामाजिक चेतना की जागृत और सश्रिय करना महत्वपूर्ण कदम है।¹⁵

इंग्लैंड में जैसे जैसे समाजवादो विचारधारा का प्रभाव बढ़ता गया तथा जैसे ही लेबर पार्टी की मश्रियता में वृद्धि हुई फेबियनवाद का महत्व कम होता गया। इनके सदस्यों में भी मतभेद होने लगे। परिणामस्वरूप फेबियनवाद के उद्देश्यों का पुनः मूल्यांकन किया गया। कोल (G. D. H. Cole) जो 1939 से 1946 तक फेबियन सोसायटी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने 1942 में फेबियनवाद की निम्नलिखित शब्दों में फिर से व्याख्या की—

“हमारा विश्वास है कि समाजवादी आन्दोलन में कहीं एक ऐसी समस्या की आवश्यकता है जो नवीन विचारों को सोचने और उनका प्रचार करने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र हो। शले ही ऐसे विचार समाजवादी परम्परा के अनुसार शास्त्र-सम्मत न हों। समाजवाद कुछ निश्चित नियमों का सङ्ग्रह नहीं है, जिसे समय या स्थान का विचार किये बिना ही प्रयोग में लाया जाय।”

आगे कोल लिखते हैं:—

फेबियन समाज का संगठन विचार-विनिमय के लिए है न कि चुनाव लड़ने के लिए। यह काम उसने अन्य संस्थाओं के लिए छोड़ दिया है। फेबियनों को अपने चुने हुए काम-लेखन और अनुसंधान में लगा रहना चाहिये, पर चूँकि अब यह विस्तृत कार्य (समाजवादी दल में समाजवादी प्रचार) करने वाला कोई नहीं है, इसलिये फेबियन पुस्तक-लेखन और शोध कार्य द्वारा पूरे दल पर अपना बाधित प्रभाव डालने में असमर्थ है। यदि अन्य कोई इस कार्य को नहीं करता है तो फेबियनों को ही सामने आना होगा और समाजवाद का प्रचार करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा।¹⁶

बोत्र भी यह व्याख्या निश्चय ही फेबियनवाद के पतन को व्यक्त करती है। अब लेखन और शोध-कार्य में फेबियनवादियों का विशेष महत्व नहीं रहा, कोई विशेष समाजवादी कार्य-यत्न प्रस्तुत करना तो भूलग रहा। लेबर पार्टी अब तक पूर्ण विरामित राजनीतिक दल ही नहीं बन चुकी थी किन्तु सराा को अपने हाथों में भी ले चुकी थी। धीरे-धीरे फेबियन सोसायटी लेबर पार्टी की छाया मात्र ही बनकर रह गई।

15 Laidler, H W, Social Economic Movements, p 184

16 Cole, G D H, Fabian Socialism, p 164

फेबियनवाद तथा राज्य

फेबियनवादियों का राज्य में विश्वास है। वे राज्य की प्रतिनिधि, संरक्षक, व्यवसायी, प्रबन्धकर्ता आदि सभी समझते हैं। किन्तु राज्य के विषय में उनके विचार मार्क्स से भिन्न थे। न तो वे राज्य के शोष में विश्वास करते थे और न सर्वहारा-अधिनायकत्व की भाँति राज्य के इतने व्यापक अधिकार के पक्ष में थे।¹⁷ उनका कहना था कि राज्य बिना किसी क्रान्तिकारी परिवर्तन के निर्दोष तथा विश्वासपात्र बनाया जा सकता है। इसलिये उन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिये कि विना क्रान्ति के ही राज्य के आन्तरिक स्वभाव में परिवर्तन हो जाय। ये सुझाव थे मन्त्राधिकार का विस्तार प्रशिक्षित लोक सेवा (Civil Services), सबके लिये समान अवसर आदि।

फेबियनवादी राज्य के कार्य विस्तार को समाजवाद के लिये आवश्यक मानते थे। राज्य के कार्य में वृद्धि करने का तात्पर्य था कि राज्य के तत्वावधान में स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को अधिक कार्य करने के अवसर देने चाहिये।¹⁸ राज्य द्वारा कई प्रकार के कार्य करने नागरिक सेवाओं तथा औद्योगिक स्पर्धा में भाग लेने आदि से फेबियनवादियों का मुख्य आशय यह था कि ये कार्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निय जायेंगे वे वृद्धि के कार्यों के म्यूनिसिपलकरण (Municipalisation) के पक्ष में थे।

राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में कहीं तक वृद्धि करनी चाहिये इस विषय में फेबियनवादी स्पष्ट नहीं हैं। उनका लिये समाजवादी मार्ग की ओर बढ़ना एक ऐसी यात्रा व ममान था जिसकी कोई निश्चित मजिल न हो।¹⁹ किन्तु राज्य के माध्यम से प्रयत्न ही निरन्तर बटने रहना चाहिये। इंग्लैंड में जब जब लेबर पार्टी की सरकार बनी उसने फेबियनवादी सिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया। उनके कार्यकाल में कई उद्योगों के राष्ट्रीयकरण किये गये तथा नगरपालिकाओं में कई नागरिक सेवाओं को अपने नियन्त्रण में लिया।

कार्य-पद्धति (Methods and Means) (५)

फेबियनवादी समाजवादियों में सर्वाधिक सक्रिय किन्तु किञ्चित् मान भी प्रतिधारी नहीं थे।²⁰ उन्होंने हमेशा ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रातिपूर्ण एवं सर्वैधानित साधना का समर्थन किया। वे श्रमिक-प्रगतिवादी (Gradualist) थे। कार्य पद्धति के विषय में उनके लिये यह प्रयास गति अधिक उपयुक्त थी—

17 Crosland, C A R, The Future of Socialism, p 84

18 Gray, A, The Socialist Tradition, p 387,
Cole G D H, Fabian Socialism, pp 164, 172

19 Gray, A, The Socialist Tradition, p 399

20 Ibid, p 399

हम बढ़ेंगे,
निरन्तर थोड़ा-थोड़ा आगे ।²¹

जैसा कि अग्र्यत्र उल्लेख किया गया है फेबियनो का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था । वे समाजवादी विचारधारा को जन साधारण तक पहुँचाना चाहते थे । इसलिये उन्होंने मूलतः प्रसार साधनों को ही अपनाया था ।²² उन्होंने पुस्तक-प्रकाशन, लेखों, व्याख्यानो तथा अध्ययन संस्थानों का सहारा लेकर अपने विचारों से जनमानस को प्रभावित करने का प्रयत्न किया ।

फेबियनवादी उच्च कोटि के बुद्धिवादी थे । फेबियन समाज के तत्वावधान में कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सजन हुआ । पीज (Edward Pease)²³ द्वारा लिखित—*History of the Fabian Society*; फेबियनवादियों के लेख तथा व्याख्यानो का संग्रह—*Fabian Essays in Socialism* (1889) तथा *Fabian Society Tracts*, 1884-1924, Nos. 1-212 आदि अधिक प्रसिद्ध हैं ।²⁴

1888-89 में फेबियन सोसायटी के सदस्यों ने सात सौ से अधिक व्याख्यान दिये । 1912 में सोसायटी ने एक फेबियन ग्रन्थपत्र-विभाग खोला । समय समय पर फेबियन शीप्म स्कूलों (Fabian Summer Schools), विश्व-विद्यालयों तथा कई शहरों में फेबियन कोष्ठों (Fabian Cells) की स्थापना की गई । इन सभी ने फेबियन समाजवादी विचारधारा का प्रसार तथा इसे लोकप्रिय बनाने का व्यापक एवं सफल प्रयत्न किया और यही फेबियनो का उद्देश्य था ।

महिला उत्थान (५ :)

महिला उत्थान के क्षेत्र में फेबियन सोसायटी की महिला सदस्यों ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया । इनका विश्वास था कि समाज में महिला-मुक्ति तथा उनकी प्रगति समाजवाद का एक अन्तर्निहित भाग है । महिलाओं की उन्नति तथा समाजवाद का विकास बहुत बुद्ध समानान्तर चलता है । राष्ट्रीय जीवन के पूर्ण सामाजिककरण के लिये महिलाओं की राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता अत्यन्त आवश्यक है । इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 1908 में फेबियन सोसायटी के तत्वावधान में एक फेबियन महिला ग्रुप (Fabian Women's Group) की स्थापना की गई । इस संस्था का मुख्य कार्य महिलाओं से सम्बन्धित राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं का ध्यान देने का प्रयत्न करना तथा उन्हें मनों के स्तर तक लाना था । इन्होंने बिना

21. We shall go,
Always a little further
Ibid., p. 399

22. Ibid., p. 357.

23. एडवर्ड पीज 1884 से 1912 तक फेबियन सोसायटी के सचिव थे ।

24. For literary and scientific work of Fabian Society See Beer, M.,
A History of British Socialism, Vol. II, pp. 288-92.

किसी भेदभाव के स्त्री तथा पुरुषों की समानता की मांग की। ये वास्तव में यह भ्रान्ति दूर करना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष अलग अलग कार्यों के लिये ही उपयुक्त हैं।

महिला उद्योग से सम्बन्धित इस ग्रुप ने व्याख्यानों का आयोजन किया तथा रचनाएँ प्रकाशित की। इन रचनाओं में प्रमुख थी—

- 1 Hutchins B L. (Miss), The working life of women
- 2 Pember Reeves (Mrs), Family life on one pound a week
- 3 Charlotte Wilson (Mrs) and Helen Blagg (Miss), Women and Prisons
- 4 Mobern Atkinson (Miss), The Economic Foundation of the Women Movement.

मूल्यांकन

रमसे मैकडोनेल्ड (J Ramsay MacDonald), 1924 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री, के मतानुसार पेरियन सोसायटी का समाजवादी संगठन के विकास में बिलकुल मामूली योगदान रहा है। वास्तव में पेरियन सोसायटी ने उन बहुत से विचार और नीतियों का विरोध किया जिसने इंग्लैंड में एक विशेष ढंग के समाजवादी भ्रान्श्लेन का निर्धारण किया। ये एक स्वतन्त्र श्रमिक दल के अलग अस्तित्व के विरुद्ध थे।²⁵

पेरियन सोसायटी सिर्फ एक अन्वेषण-केन्द्र तथा मुद्दों भर बुद्धिजीवियों का विचार-विनिमय का फोरम था। यही कारण था कि पेरियनों ने अपनी सख्या में वृद्धि नहीं की। 1914 में इसकी सदस्य संख्या लगभग 3000 थी।²⁶ इस सदस्य संख्या से सिर्फ सीमित विचार-क्रान्ति या विचार-परिवर्तन ही सम्भव था। इसका तात्पर्य था कि पेरियनवादी जन साधारण के साथ न तो धुले मिले और न उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ रह कर समझ सके। इनमें तथा जन-साधारण के मध्य भारी खाई थी।

पेरियनवादी प्रहार करने के इच्छुक तो हैं, लेकिन उसके लिये उनमें क्षमता नहीं थी। वे अपने विचारों से मार्क्स ओवन तथा अन्य की आलोचना करते हैं, वे परिश्रम-हीन आय, जिसका सम्बन्ध पूँजीवाद से ही हो सकता है, की भी निन्दा करते हैं, ये समाजवादी प्रगति के लिये कार्यन्वय भी सुभाते हैं, लेकिन जहाँ तक कार्यशील होने का प्रश्न था इन्होंने सामान्यतः अपने अध्ययन-रक्षा की सीमा को पार करने की हिम्मत नहीं की। यही उनका कार्य-स्थल था। फिर भी ये कम से कम निम्न वर्ग के लिए, जिसका कि प्रत्येक देश में बहुमत होता है, कुछ कार्यशील होने की

25 Ramsay MacDonald J., *Socialism Critical and Constructive*, p 82

26 Beer, M., *A History of British Socialism*, vol II, p 296

प्रेरणा दे सकते थे। वे यह भी नहीं कर सके। वे जो कुछ भी चाहते थे राज्य के माध्यम से करवाना पसन्द करते थे। इसका सीधा यही तात्पर्य था कि राज्य जित पर पूँजीपतियों का अधिकार था वही जन कल्याण की ओर कदम उठाये। यह व्यापक रूप में सम्भव था। ये राज्य को तथा उच्च वर्ग को उदारवादी बनाना चाहते थे, समाजवादी नहीं। सम्भवतः उच्च-वर्ग से फेबियनों के सम्बन्ध अच्छे थे।

फेबियनवादी इस विषय पर मौन हैं कि जिस व्यवस्था का वे समर्थन करते हैं, क्या वह राजनीतिक लोकतन्त्र को बनाये रखने में सफल होगी! लेन लेन्कास्टर का विचार है कि सम्भवतः यह आसान नहीं होगा। क्योंकि फेबियनवादी राज्य को एक सेवा करने वाली सार्वजनिक कर्मचारियों की संस्था मानते हैं। ये सार्वजनिक कर्मचारी अपना स्वयं ही एक वर्ग बना लेते हैं। कर्मचारी दक्षता पर अधिक बल देते हैं और यह व्यक्तियों तथा राज्य के मध्य एक चौड़ी सार्ई की स्थापना करता है।²⁷

योगदान

एलेग्जेण्डर ग्रे के विचारानुसार फेबियनों का महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने समाजवाद को एक सम्मानित विचारधारा बनाया। इसके पहले समाजवाद को विध्वंसकारी, विप्लवकारी, तोड़-फोड़वादी, मजदूर वर्ग की विचारधारा माना जाता था। फेबियनों ने ऐसे समाजवाद का मर्जन किया जिसे मध्य-वर्ग, तथा थोड़ा बहुत पड़ा किया व्यक्ति भी आसानी से ग्रहण कर सके। जिस तरह उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया समाजवाद एक सम्मानित विचारधारा ही नहीं बल्कि एक फ़ैशन बन गया।²⁸

साहित्यिक महत्त्व (1)

फेबियनवादी अपनी गतिविधियों से इंग्लैंड के समाज पर छा गये। उनके ग्रन्थों, पुस्तिकाओं आदि का राजनीतिक ही नहीं किन्तु साहित्यिक महत्त्व भी था। बर्नाड शॉ तथा ग्रन्थ का फ्रेंचो साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है।

फेबियन साहित्य मजा हुआ, सधा हुआ साहित्य था। उन्होंने जो कुछ लिखा यह शोध एवं साहित्यिक भाषा में ही लिखा। काल भावर्ष की तरह भावपूर्ण आन्तरिक गन्दों का प्रयोग नहीं किया।²⁹ यही कारण था कि इंग्लैंड की विकासवादी जनता उनके विचारों से प्रभावित हुई।

इंग्लैंड की गृह नीति पर प्रभाव

फेबियनों का मुख्यतः प्रभाव इंग्लैंड की गृह नीति के क्षेत्र में पड़ा। उन्होंने ग्रन्थों की स्थिति को उठाने, उद्योग वर्ग के स्वामियों की सम्पत्ति कम करने,

27. Lancaster, L. W., Masters of Political Thought, vol. II, p. 330.

28. Gray, Alexander., The Socialist Tradition, p. 400.

29. Kilzer and Ross, Western Social Thought, p. 285.

लाभो का न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए कई व्यावहारिक योजनाएँ बनाईं और तर्क एवं तथ्यों द्वारा उनको शक्ति प्रदान की।³⁰ बोकर ने भूत ध्वस्त किया है कि उन्होंने तात्कालिक प्रयोग के लिए व्यावहारिक योजनाएँ बनाईं जो कई प्रकार से काम में लाई जा सकती थी जैसे—

- 1 सामाजिक विधि-निर्माण द्वारा काम के घंटों में कमी, देवारी के समय सरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा, वेतन के लिए न्यूनतम स्तर तथा शिक्षा की उपलब्धि
2. राष्ट्रीय तथा म्यूनिसिपल सरकारों द्वारा सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं (public utility Services) और स्वाभाविक एकाधिकारों पर सार्वजनिक स्वामित्व,
- 3 उत्तराधिकार पर कर, भूमि-कर तथा तगी हुई पूँजी की आय पर कर आदि ।

इन सभी क्षेत्रों में फेबियन समाजवादियों ने अधिक स्पष्ट प्रभाव डाला है। इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड में म्यूनिसिपल सामाजिककरण के विस्तार को शीघ्रता से बढ़ाने में इनके प्रचार साहित्य तथा व्याख्यानो से बड़ी सहायता मिली। "उनसे उस लोचनन को तैयार करने में बड़ी सहायता मिली जिसने सम्पत्ति पर कर लगाने के गये ढङ्गों को कार्य में लाने समय राष्ट्रीय सरकार का समर्थन किया, जैसे, तगी हुई पूँजी से होने वाली आय पर सापेक्ष दृष्टि से ऊँचा कर लगाना, उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति पर भारी शुल्क लेना और (1910 के स्वास्थ्य कानून द्वारा) काम में नहीं लगे हुई भूमि तथा काम में लाई हुई भूमि के मूल्यों में अनजित वृद्धि पर विशेष कर लगाना।"³¹ इसमें कोई शक नहीं कि फेबियनवादियों ने कर लगाने के जो नये-नये सुभाव दिये वे महत्वपूर्ण थे। कोई भी समाजवादी दल या राज्य इन कर सुभावों की अवहेलना नहीं कर सकता।

इंग्लैंड के मजदूर दल पर प्रभाव । ३)

फेबियन समाजवादी इंग्लैंड में मजदूर दल (Labour Party) के सैद्धान्तिक पक्ष को व्यक्त करते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समय समय पर फेबियनों ने मजदूर दल का सैद्धान्तिक मार्ग निर्देशन किया। सन् 1918 में सिडनी वेब ने मजदूर दल के लिए एक नया विधान तथा कार्य-क्रम बनाया जिसके कारण उसकी सदस्यता में विस्तार हुआ। फेबियन सोसायटी तथा मजदूर दल का सम्बन्ध काफी घनिष्ठ था तथा फेबियनों में बहुत से मजदूर दल के सक्रिय सदस्य थे। इंग्लैंड में

³⁰ बोकर., प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 113-14.

³¹ उपरोक्त, पृ 114

जब जब लेबर पार्टी को परक्युलर उन्में पेवियन समाज के सदस्यों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। मन् 1924 के प्रथम मजदूर मन्निमण्डल में लगभग 9 पेवियन समाज-कारी थे जिनमें प्रमुख सिडनी वेब, लार्ड भालीवर, नोएल ब्यूटन (Noel Buton) आर्थर हेन्डरगन, लार्ड टामसन आदि थे। यही नहीं प्रधानमन्त्री रेगजे मैकडनिल्ड तथा उनके विनमन्त्री स्नोडन (Lord Snowden) भी पेवियन सोसायटी के द्रुतपूर्व सदस्य थे। मजदूर दल की सरकारों के माध्यम से पेवियनों ने अपने समाजवादी कार्य-क्रम को कार्यान्वित करने का प्रयत्न ही नहीं किया, किन्तु इंग्लैण्ड की सम्पूर्ण राजनीति को समयानुसार चलाये रखने के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पेवियनवाद तथा सोवियान्त्रिक समाजवाद

पेवियनवादियों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह था कि इन्होंने सोवियान्त्रिक समाजवाद को स्थापित ही प्रदान नहीं किया, उसकी गति में वृद्धि करने में भी योगदान दिया। सोवियनवाद के द्रुतोन्निवादी विचारों से ऊपर उठकर तथा मार्क्स के श्रान्तिकारी विचारों का टटकर गैदान्त्रिक सामना कर इन्होंने सोवियान्त्रिक या विश्वशासकी समाजवाद के मार्ग को प्रशस्त तथा स्पष्ट दोनों ही किया। इंग्लैण्ड का मजदूर दल जो विश्वशासकी समाजवाद का द्योतक था पेवियनवादियों से उत्पन्नित हुआ था।

पाठ्य-ग्रन्थ

1. Beer, M., A History of British Socialism, vol II, Chapter XIV, The Fabian Society.
2. बीर, प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन., अध्याय 5, प्रजातान्त्रिक एवं विकासवादी समाजवाद
3. Cole, G.D.H., Fabian Socialism, London, 1943,
4. Cole, Margaret., The Story of Fabian Socialism. London, 1963.
5. Gray, Alexander, The Socialist Tradition., Chapter XIV (a), Fabianism
6. Laidler, Harry W., History of Socialist Thought., Chapters XVII and XVIII.
7. Pease Edward R., History of the Fabian Society, London, 1916, Revised edition 1925.
8. Pelling, Henry (Ed.), The Challenge of Socialism, Chapter II, Fabian Society.

गिल्ड समाजवाद

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इंग्लैंड में एक और समाजवादी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ जिसे गिल्ड समाजवाद (Guild Socialism) कहते हैं। गिल्ड समाजवाद का प्रवर्तन कुछ रेवियनवादियों ने मिलाकर किया।¹ गिल्ड या श्रेणी (Guild) का अर्थ है स्वेच्छा पर आधारित पारस्परिक-निर्भर व्यक्तियों की यह स्व-शासित संस्था जिम्मा सगठन समाज के किसी विशेष वर्तुल्य को उत्तरदायित्व के साथ पूरा करने के लिए संगठित किया गया हो।² गिल्ड या श्रेणी पर आधारित समाजवाद ही गिल्ड समाजवाद है।

गिल्ड समाजवाद की किलजर एब रॉस के अनुसार, यह परिवर्तना थी कि समस्त उत्पादकों को सामान्यतः छोटी छोटी आत्म-निर्भर औद्योगिक इकाइयों में संगठित किया जाय, जहाँ दस्तकारी के कार्य की प्रधानता तथा श्रमिका में अधिक उत्तरदायित्व की भावना होगी, जो पूँजीवादी व्यवस्था में सम्भव नहीं है। इनकी प्राप्ति श्रमिका के कार्य के गुण तथा सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को लोकतान्त्रिक ढंग से व्यवस्थित करने से होगी।³

कोकर ने मत व्यक्त किया है कि गिल्ड समाजवाद पूँजी के मालिकों से उन अवसरों का निर्णय करने की सत्ता जिनके अधीन मजदूर काम करते हैं और मजदूर जो कुछ उत्पादन करते हैं उससे लाभ उठाने का अधिकार छीन लेना चाहता है। परन्तु वह उत्पादकों या मजदूरों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक हितों को भी स्वीकार करता है।⁴

लेकिन गिल्ड समाजवाद के जो भी उद्देश्य या कार्यक्रम हैं उनका माध्यम गिल्ड व्यवस्था ही होनी चाहिए। इस तथ्य को हमारे शब्दों में प्रस्तुत करते हुए जीड ने लिखा है —

‘श्रेणी समाजवादियों के विषय में यह कहना सत्य है कि वह सिद्धान्तवादियों की एक छोटी सी मण्डली है, जो श्रमिक आन्दोलन के

1 Kilzer and Ross, Western Social Thought, p 285

2 Orage, A R, An Alphabet of Economics, London, 1917, p 53

3 Kilzer and Ross, Western Social Thought p 285

4 कोकर, आधुनिक राजनीतिक विन्तन, पृ 275

अन्तर्गत उनके प्रभावशाली सदस्यों को अपना मतवर्ती बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं तथा सामान्यतः अपने विचारों के समर्थन के लिए वे जनता से सीधी अपील नहीं करते।⁵

उपरोक्त परिभाषाएँ तथा विचार गिल्ड समाजवाद को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करते। वास्तव में गिल्ड समाजवाद वह विचारधारा है जिसके समर्थक एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसका आधार गिल्ड प्रणाली हो। यह मूलतः श्रमिकों का आन्दोलन है किन्तु सभी प्रकार के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को सरक्षण प्रदान करता है। गिल्ड समाजवादी राज्य विरोधी होने हुए भी किमी न किसी रूप में राज्य हितैषी है।

विकास: प्रभाव एवं कारण

गिल्ड समाजवाद की प्रेरणा-स्रोत मध्यकालीन यूरोप की व्यवस्था थी। मध्य-कालीन यूरोप में औद्योगिक और व्यावसायिक संघ जो गिल्ड (Guild) कहलाते थे, का आर्थिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। एक गिल्ड (सब या श्रेणी) में एक उद्योग से सम्बन्धित सभी कारीगर और श्रमिक सम्मिलित होते थे। वे गिल्ड मजदूरी, कार्य-परिस्थितियों आदि का स्वयं निर्धारण करते थे। गिल्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण, उनकी पारिवारिक सहायता आदि का प्रबन्ध भी इनके द्वारा किया जाता था। इसके अलावा सामाजिक सेवा इनका मुख्य उद्देश्य था। वास्तव में उस समय की अर्थ व्यवस्था इन्हीं संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित होती थी।

गिल्ड समाजवादियों पर इस व्यवस्था का मूल प्रभाव था। अपनी पुस्तक—*Guild Socialism* में कोल ने इस प्रभाव को स्पष्टतः स्वीकार किया है। किन्तु उनका उद्देश्य मध्यकालीन व्यवस्था को पूर्णतः लागू करना नहीं था। उसे आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ग्रहण करना था। विशेषतः गिल्ड समाजवादी मध्यकालीन गिल्ड व्यवस्था की व्यावसायिक नैतिकता तथा समाजसेवी भावना से अत्यधिक प्रभावित हुए।⁶

गिल्ड समाजवाद पर बहुलवाद (Pluralism) की छाया स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। प्रमुख बहुलवादी नेविल फिगिस (J. Neville Figgis) जो इंग्लैंड में पादरी थे, ने अपने विचारों से बहुत से व्यक्तियों को प्रभावित किया। हेरॉल्ड लास्की (Harold J. Laski), लिन्डसे (A. D. Lindsay) के अलावा कोल (G. D. H. Cole) स्वयं भी प्रमुख बहुलवादी थे।—वास्तव में कोल को किसी विशेष विचार-धारा तक सीमित नहीं किया जा सकता।

J. L. Laski, 1910

⁵ जोड., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 76-77.

⁶ Cole, G. D. H., *Guild Socialism*, Allen & Unwin, London, 1923
pp. 35-37.

गिल्ड समाजवाद को बहुलवाद की देन राज्य सत्ता को सीमित करने तथा राज्य के अन्तर्गत समुदायों को व्यापक अधिकार करने के क्षेत्र में है। बहुलवादी राज्य के व्यापक अधिकारों का विरोध तथा विनेन्द्रोत्तन राज्य (Decentralised State) का समर्थन करते हैं। गिल्ड व्यवस्था के अन्तर्गत भी लगभग ऐसे ही विचारों का निरूपण किया गया है।

यहां यह प्रश्न उठता है कि इंग्लैंड में इस समाजवादी सम्प्रदाय की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई? मार्क्सवाद की प्रेरणा से यूरोप में कई समाजवादी सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। फ्रांस में मिन्डीकलवाद तथा इंग्लैंड में फेब्रियनवाद ने कुछ समय तक समाजवादी आन्दोलन को प्रभावित किया। लेकिन समष्टिवाद और मिन्डीकलवाद दोनों ही अग्रजों की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं थे। इंग्लैंड में राज्य समाजवादी आन्दोलन की जड़ें कभी भी गहरी नहीं हो पाई हैं।⁷ उन्हें मिन्डीकलवाद अत्यधिक उग्र, नातिनारी तथा अराजकतापूर्ण प्रतीत हुआ। दूसरी ओर, फेब्रियनवाद अधिक उदारवादी होने के कारण अग्रजों को आकर्षित करने में असफल रहा। अग्रज परम्परागत मध्यमार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने फेब्रियनवाद और मिन्डीकलवाद की अतिवादिता को त्याग कर दोनों की अच्छी बातों का सम्मिश्रण कर एक नये समाजवादी सम्प्रदाय गिल्ड समाजवाद का जन्म दिया। अन्य शब्दों में गिल्ड समाजवाद को मिन्डीकलवाद और समष्टिवाद का 'बुद्धिवादी शिशु' (Intellectual Child) भी कहते हैं।

गिल्ड समाजवाद की सिद्धान्तिक आधार प्रदान करने का श्रेय उत्तमवी शनान्सी के कुछ विद्वानों को है। कारलायल (Thomas Carlyle, 1795-1881), स्टांटलेड के लेखक एवं दार्शनिक तथा जॉन रस्किन (John Ruskin 1819-1900), अग्रजों के लेखक, आलोचक और समाज सुधारक आदि ने अति उत्पादन, शक्तिशाली शोषण का विरोध तथा छोटे छोटे समूहों का समर्थन किया था। विलियम मोरिस (William Morris, 1834-1896) ने अपनी सूटोपियायी पुस्तक—*News from Nowhere*—में ऐसी कल्पना की है जहाँ बड़े-बड़े नगर नहीं थे, व्यक्ति विनेन्द्रोत्तम ग्रामों में सुखपूर्वक तथा सहयोगपूर्ण भावना को लेकर रहते थे। इसके साथ ही साथ उन्हें अपनी कला और हुनर पर गर्व था।⁸ मोरिस, कारलायल तथा रस्किन के लेखों में गिल्ड समाजवाद का केवल आभास ही मिलता है, उन्हें गिल्ड समाजवादी नहीं कह सकते।

7 Ramsay MacDonald J., *Socialism Critical and Constructive*, pp 89-90

8 Kitzler and Ross, *Western Social Thought*, p 285

9 *Ibid.*, p 153

पेन्टी (A. J. Penty, 1875-1937), जो एक शिल्पकार थे, को गिल्ड-समाजवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है।¹⁰ 1906 में प्रकाशित पेन्टी की पुस्तक—The Restoration of Guild System (अर्थात्, गिल्ड व्यवस्था को पुनर्स्थापना)—में गिल्ड समाजवाद के प्रारम्भिक विचार मिलते हैं। इस पुस्तक की धोर लोगो का ध्यान दायरित हुआ। पेन्टी के अनुसार उद्योग में स्व-शासन के मध्यकालीन सिद्धान्त को पुनः स्थापित करना चाहिए। इस व्यवस्था में दस्तकार, जो कि एक स्व-शासित श्रेणी का सदस्य होता था, उत्पादन के साधनों का भी स्वामी होता था और वही यह निश्चय करता था कि किस प्रकार का तथा कितना माल तैयार किया जाय।¹¹

1909 तक इस सिद्धान्त ने अधिक व्यावहारिक रूप धारण नहीं किया था। 1909 से 1912 तक इंग्लैंड में बड़ी श्रमिक अशांति रही जिसमें श्रमिक संघों ने प्रमुख भाग लिया। इस श्रमिक अशांति तथा आन्दोलन का मार्ग निर्देशन करने में अरिज (A.R. Orage, 1875-1934), जो पत्रकार, दार्शनिक एवं निवन्धकार थे, तथा पत्रकार एवं वक्ता हॉब्सन (S. G. Hobson, 1864-1907) ने महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। इन्होंने 1907 में एक पत्रिका—New Age—के माध्यम से इस प्रकार के विचार प्रसारित किये कि प्राचीन गिल्ड प्रणाली के विचार को वर्तमान श्रमिक संगठनों के आधार पर आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाना चाहिए। इनका सुभाव था कि उद्योग में उससे सम्बन्धित श्रमिकों का स्व-शासन हो। इसके लिए उनका संगठन एक औद्योगिक गिल्ड व्यवस्था में किया जाय जिसका प्रारम्भ वर्तमान श्रमिक संघों के आधार पर किया जा सकता है।¹²

न्यू एज (New Age) में प्रकाशित लेखमाला के आधार पर एक अन्य पुस्तक—National Guilds, An Inquiry into the Wage System and the Way Out—प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के द्वारा गिल्ड समाजवाद को पेन्टी के मध्य-कालीन विचारों से मुक्त करा कर तथा एक नवीन दिशा प्रदान कर आधुनिक राजनीतिक और भाषित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया गया।

¹⁰ हेलोवेल ने गिल्ड समाजवाद का विवरण देने में पेन्टी का नाम ही उल्लेख नहीं किया है। संभवतः वे पेन्टी के योगदान को स्वीकार नहीं करते।
Hallowel, H. J., Main Currents in Modern Political Thought, pp. 456-458.

¹¹ जोट., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 75.

¹² उपरोक्त., पृ. 79;

A Summary of articles published in the New Age is given in A History of British Socialism by M. Beer, p. 365-66

गिल्ड समाजवाद के सबसे प्रबल समर्थक कोल (G. D. H. Cole, 1889-1959) थे जिन्होंने अपनी दर्जनों पुस्तक-पुस्तिकाओं में इस विचारधारा को विवेचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया।

इन सम्बन्ध में कोल की निम्नलिखित पुस्तकें अत्यन्त ही महत्वपूर्ण थीं —

1. Self Government in Industry, 1917.
2. Social Theory, 1918
3. Guild Socialism Restated, 1920
4. Guild Socialism, 1920 (a Fabian tract)

इन पुस्तिका के माध्यम से गिल्ड समाजवाद को पूर्णतः विवक्षित, व्यवस्थित तथा आन्दोलन का रूप देने का श्रेय कोल को ही है।

गिल्ड समाजवादी, विशेषतः अरिज, किसी प्रकार की गिल्ड संस्था की स्थापना के विरोध में थे। इसलिए गिल्ड समाजवाद के संगठित आन्दोलन का रूप ग्रहण करने में कुछ कठिनाई हुई। किन्तु 1915 में गिल्ड समाजवाद के दो नये समर्थक घावस-फोर्ड के विद्वान विलियम मेलोर (William Mellor) तथा मोरिस रेस्कट (M. B. Reckitt) आदि ने एक राष्ट्रीय गिल्ड संघ (National Guilds League) की स्थापना की। अरिज, हॉक्सन तथा बोल इनकी कार्यकारिणी के सदस्य थे। राष्ट्रीय गिल्ड संघ इस समाजवादी विचारधारा का प्रमुख केन्द्र बन गया। इसने कई बुद्धि-जीवियों को आकर्षित किया। इसने एक मासिक पत्र—Guilds Man—निकाला जो बाद में 'Guild Socialist' हो गया।

गिल्ड समाजवादियों ने इंग्लैण्ड में कुछ रचनात्मक कार्य भी किये। 1920 में मैनचेस्टर के अनेक भवन निर्माण मजदूर संघों ने 'भवन निर्माणकारी संघ' (A Builder's Guild) स्थापित किया। हाक्सन इस संघ के मंत्री थे। इस संघ ने ठेके लवर लगभग दस हजार सस्ते मकानों का निर्माण किया। लेकिन सरकार का इसमें प्रति कुछ विरोधपूर्ण दृष्टिकोण रहा। इसे आर्थिक सहायता बन्द कर दी गई तथा छ माह के अन्तर्गत Builder's Guild का अन्त हो गया। 1925 में राष्ट्रीय गिल्ड्स-लीग को भी नग कर दिया गया। इसके बाद गिल्ड समाजवादी आन्दोलन का ह्रास होता चला गया।

गिल्ड समाजवाद के विचार-सूत्र

गिल्ड समाजवाद के सामान्यतः दो पक्ष हैं। प्रथम, गिल्ड समाजवादी, पूँजीवादी और प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था की वैसी ही परम्परागत आलोचना करते हैं जिस प्रकार समाजवाद के अन्य सम्प्रदाय। इस सम्बन्ध में गिल्ड समाजवाद, समाजवाद की अन्य शाखाओं में भिन्न नहीं है। द्वितीय, गिल्ड समाजवादी समाज के आर्थिक और राजनीतिक मण्डल में आमूल परिवर्तन आवश्यक मानते हैं। इसने लिये वे कुछ

रचनात्मक सुझाव देते हैं जिनके कारण गिल्ड समाजवाद अन्य समाजवादी शाखाओं से हट कर एक अलग विचारधारा के रूप में स्वीकार किया जाता है। गिल्ड समाजवाद की प्रमुख विशेषताएँ, इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती हैं।

उत्पादन का ह्रासः—पूँजीवाद के अन्तर्गत आर्थिक संगठन की गिल्ड समाजवादी बटु धारणा करता है। इसके अनुसार श्रमिकों ने शिक्षा तथा जीवन-अनुभवों से यह सीखा है कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था उत्पादन वृद्धि के उपयुक्त नहीं है। श्रमिक बटोर परिश्रम द्वारा उत्पादन में वृद्धि तो कर सकता है किन्तु इसका वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसके विपरीत उत्पादन यदि सीमित है तो माग के अनुपात में वृद्धि कम होगी और इस प्रकार कम उत्पादन में ही अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन अधिक या कम क्यों न हो श्रमिकों को लाभ नहीं होता। किन्तु प्रमुख बात यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहित नहीं करती।

मूल्य-निर्धारण

गिल्ड समाजवादियों का कहना है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य श्रम से निर्धारित होता है। लेकिन भू-स्वामी, उद्योगपति और पूँजीपति मूल्य अधिक लेते हैं और श्रमिकों को जो कुछ मिलता है वह बहुत ही अनुपयुक्त होता है। इस सम्बन्ध में इनका सुझाव है कि या तो वर्तमान प्रथा का अन्त कर दिया जाय या मजदूरी, किराया, लाभ, व्याज आदि की दर को निश्चित करने का कोई समन मिद्दान्त प्रस्तावित जाय।

मजदूरी-प्रथा का उन्मूलन

पूँजीवादी दोषों को ध्यान में रखते हुए गिल्ड समाजवादी मजदूरी प्रथा को योग्यपूर्ण मानते हैं। प्रथम, मजदूरी प्रथा श्रमिकों को उसके श्रम से अलग कर देती है ताकि एक दूसरे के बिना दोनों को बेचा और खरीदा जा सकता है। द्वितीय, मातृक मजदूरी तभी देना है जब उसे लाभ हो। तृतीय, सिर्फ मजदूरी के बदले श्रमिक उत्पादन के संगठन पर अपना नियन्त्रण छो देना है। चतुर्थ, मजदूरी प्रथा के अन्तर्गत श्रमिक अपने द्वारा निर्मित वस्तु से भी अपना दावा और अधिकार छोड़ बैठता है। इस प्रकार मजदूरी प्रथा नैतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा बलात्कृत दृष्टि से उचित नहीं है। प्रचलित मजदूरी प्रथा श्रमिकों में निर्भरता एवं दासता की भावना उत्पन्न करती है और अपनी मृदुलात्मक प्रवृत्ति को सीमित तथा कुण्ठित करती है।

मजदूरी प्रथा में उपरोक्त दोषों के परिणामस्वरूप गिल्ड समाजवादी इस प्रथा को अन्त करने के ही पक्ष में है। इसके अलावा वे चाहते हैं कि श्रमिकों को जो कुछ मजदूरी प्राप्त हो वह उसे अनुपयुक्त गमक के दी जाये। द्वितीय, वैरोजगारी तथा बीमारी के समय श्रमिकों को भत्ता दिया जाय। तृतीय, उत्पादन साधनों पर श्रमिकों का

नियन्त्रण तथा स्वयं के द्वारा निर्मित वस्तु पर अधिकार हो। साधारण भाषा में इसका तात्पर्य यह हुआ कि मजदूरी के स्थान पर श्रमिकों को उनके कार्य के लिए किसी अन्य ढंग, तरीके या व्यवस्था के अन्तर्गत देतन दिया जाये, श्रमिक की सुरक्षा की गारंटी हो श्रमिक का उत्पादन प्रक्रिया पर ही नहीं किन्तु विक्रय प्रक्रिया पर भी नियन्त्रण हो।¹³

मशीनयुगीय दुष्परिणामी का अन्त

रस्किन, कारलायल तथा विलियम मोरेस मशीन युगीय व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करते हैं जिनका गिल्ड समाजवादियों पर स्पष्ट प्रभाव है। गिल्ड समाजवादियों के अनुसार मशीन युग में पूँजीवादी व्यवस्था मशीन व्यवस्था पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिक आघात पर इस व्यवस्था में श्रमिक के व्यक्तित्व, भावनाओं और कलात्मकता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उत्पादन प्रक्रियाओं का इतना व्यापक एवं सूक्ष्म विभाजन हो गया है कि श्रमिक एक मशीन को भाँति एवं निश्चित क्रिया को निरन्तर दुहराता रहता है। इससे उसके कार्य में आनन्द, पहल करने की शक्ति एवं क्षमता तथा सृजनात्मक और कलात्मक रचि का ह्रास होता है। इसलिए गिल्ड समाजवादी ऐसी अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें श्रमिक आनन्दपूर्वक उत्पादन में सहयोगी हो। वे उत्पादन प्रक्रिया और परिस्थितियों में परिवर्तन चाहते हैं। बोकर ने इस भावना को व्यक्त करते हुए लिखा है कि—

‘ गिल्ड समाजवाद के लिये प्रमुख आर्थिक समस्या बला या कारीगरी की भावना के पुनः स्थापन का मार्ग खोज निकालने की है तथा एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की है जिससे मजदूरी में केवल दक्षता का ही विकास न हो धरम् उन्ह अपने काम के गौरव का भी अनुभव हो, केवल अपने उपाजित धन की रकम में ही दिलचस्पी न हो वरन् अपने उत्पादन के रूप और गुण में भी दिलचस्पी हो।’¹⁴

सम्पत्ति का सामाजिक उपयोग

अन्य समाजवादियों की तरह गिल्ड समाजवादी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति के आलोचक हैं। किन्तु वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के पूर्णरूपेण उन्मूलन के पक्ष में नहीं हैं। सम्पत्ति के समन्वय में गिल्ड समाजवादी नैतिक तर्क देते हुए कहते हैं कि सम्पत्ति और सामाजिक हित का पूर्ण समन्वय होना चाहिये। वे व्यक्ति जो समाज सेवा नहीं कर सकते, उन्हें सम्पत्ति आरण और उपभोग करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मनुष्य को स्वार्थ की दृष्टि से नहीं, समाज सेवा की भावना से कार्य करना चाहिये।

13 Gray, A., The Socialist Tradition, pp 438-39

14 बोकर, माधुनिद राजनीतिक चिन्तन, पृ 280

व्यावसायिक प्रजातन्त्र: (Democracy in Industry)

व्यावसायिक प्रजातन्त्र का सिद्धान्त गिल्ड समाजवाद के प्रमुख विचार-सूत्रों में से एक है। "व्यावसायिक प्रजातन्त्र का सिद्धान्त केन्द्रीय, सर्वशक्तिशाली राज्य की कल्पना के विरुद्ध, इन बातों का समर्थन करता है कि शक्तियों तथा कार्यों को विवेकीकरण द्वारा विभिन्न निकायों को दे दिया जाय। इससे यह आशा की जाती है कि आधुनिक जटिल समाज में मनुष्य के विविध हितों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो सकेगा।"¹⁵

व्यावसायिक प्रजातन्त्र के दो आधार या दो पक्ष हैं। प्रथम, गिल्ड समाजवादी, विशेषतः कोल, मानस के इस कथन से सहमत हैं कि "आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति की पूर्ववर्ती होती है अर्थात् वे यह मानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातन्त्र तभी सम्भव है जब आर्थिक क्षेत्र में पहले प्रजातन्त्र की स्थापना की जाय। यदि उद्योगों का समूह प्रजातन्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर हो तो समाज का समूह अनिवार्यतः प्रजातन्त्रिक हो जायेगा।"¹⁶

द्वितीय, व्यावसायिक प्रजातन्त्र के अनुसार गिल्ड समाजवादी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धान्त (Territorial Representation) का समर्थन नहीं करते। "किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करना असम्भव है। इसलिए अभी तो जो भी प्रतिनिधि संस्थाएँ रही हैं वे वास्तव में प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं। यद्यपि यह सच है कि कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह उनके उद्देश्यों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर सकता है।"¹⁷ इसका तात्पर्य है कि गिल्ड समाजवादी अलग अलग हितों के लिए अलग अलग गिल्डों की स्थापना करने का समर्थन करते हैं। ये गिल्ड ही व्यक्तियों के अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में ही गिल्ड समाजवादी क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रणाली को निरस्त कर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (Functional Representation) सिद्धान्त को मान्यता देने हैं।

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (Functional Representation)

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गिल्ड समाजवादियों का मूल मंत्र है। उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रणाली को आलोचना की है क्योंकि—

(i) प्रचलित प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। राज्य को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

¹⁵ जोस., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 79.

¹⁶ उक्त पृ. 79-80.

Also see, The Socialist Tradition by Gray, A., pp. 441-42.

¹⁷ जोस., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 77.

- (ii) एक क्षेत्र से एक या अनक प्रतिनिधि चुने जाने हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में कई व्यक्तियों के लोग रहने हैं जैसे किसान, मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखन प्रकाशन, मकान मालिक, किसानों के आदि। कोई भी प्रतिनिधि इन विभिन्न हिता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। वे तो सिर्फ अपने क्षेत्र के सामान्य हिता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
- (iii) एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न व्यावसायिक व्यक्तियों के हित भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये विभिन्न हित एक निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहते। बहुत से व्यावसायिक हित स्थानीय क्षेत्र से प्रारम्भ होकर राष्ट्रीय स्तर तक जाने हैं।
- (iv) वर्तमान शासन मूलतः राजनीतिक व्यवस्था है। किन्तु बहुत से कार्य और प्रश्न ऐसे हैं जो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं हों। प्रचलित शासन प्रणाली आर्थिक मामलों में निष्पक्ष और लगन से काम चराने में अनमर्थ है। उदाहरण के लिये वर्तमान शासन व्यवस्था में श्रमिका को उन परिस्थितियों के निर्माण और नियन्त्रण आदि निर्धारण करने में भाग नहीं लेना दिया जाता जिनमें उन्हें कार्य करना पड़ता है। इसके विपरीत राज्य परम्परागत सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा कर घोषण व्यवस्था बनाये रखने में सहायता देता है।

इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर चुनाव हुआ कोई भी प्रतिनिधि चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, उसका अनुभव एक ज्ञान कितना ही व्यापक क्यों न हो, इन विभिन्न व्यावसायिक हितों से सम्बन्धित समस्याओं को न तो वह पूर्ण रूप से समझ सकता है और न इन सभी के प्रति उसकी समान सहानुभूति ही रह सकती है।¹⁸

उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिए गिण्ड समाजशास्त्री सामाजिक सगठन के लिये निम्नलिखित सुझाव देते हैं—

- (i) समाज का पूर्ण सोवर्ताधिक सगठन तभी हो सकता है जब उसका सगठन कार्यों और व्यवसायिक आधार (functional basis) पर किया जाय।
- (ii) गिल्ड संस्था में उठने होने चाहिए जिनमें समाज में होने वाले कार्य। समस्त प्रमुख व्यवसायों में काम करने वाले व्यक्तियों को पृथक-पृथक गिल्ड (श्रेणियों) में संगठित किया जाये। एक गिल्ड में केवल एक ही व्यवसाय के व्यक्ति सम्मिलित किय जाएँ।
- (iii) प्रत्येक गिल्ड में सख्त सभी कुशल एवं अनुकूल धर्मिक, देवताश्रयण, प्रसासक एवं प्रबन्धक आदि सभी सम्मिलित होने चाहिए।

¹⁸ कोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 281

- (iv) गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत न केवल औद्योगिक गिल्ड होंगे बल्कि उपभोक्ता गिल्ड, नागरिक गिल्ड तथा अन्य कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जीविकाओं के क्षेत्र में भी गिल्ड होंगे जिनका संगठन स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय माध्यम पर होगा। उपभोक्ता गिल्ड उत्पादक गिल्ड आदि से मिलकर उत्पादन ध्यय, उत्पादन सीमा तथा मूल्य आदि के विषय में विचार एवं निर्माण करेंगे।
- (v) गिल्ड स्थानीय प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किये जाने चाहिये या नहीं इस बात पर गिल्ड समाजवादियों में मतभेद था। पेन्टी ने स्थानीय गिल्ड संगठन को ही अधिक महत्त्व दिया। वह नहीं चाहता था कि प्रादेशिक या राष्ट्रीय गिल्ड स्थानीय गिल्डों पर नियन्त्रण रखें जिससे श्रमिकों की स्वतन्त्रता एवं शिल्पकारिता का हनन होने की सम्भावना थी। लेकिन अधिकतर गिल्ड समाजवादों प्राधुनिक परिस्थितियों में तथा बड़े पैमाने पर प्रचलित उत्पादन पद्धति के माध्यम पर स्वीकार करते थे कि गिल्ड का उच्च स्तरों पर भी संगठन होना चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय को आवश्यकानुसार विभिन्न स्तरों पर गिल्ड निर्माण करने चाहिए, जैसे कर-भारोपण (taxation), प्रतिरक्षा (defence) आदि राष्ट्रीय मामलों के राष्ट्रीय गिल्ड होंगे तथा बिजली, पेयजल, पुलिस आदि की व्यवस्था स्थानीय गिल्ड करेंगे। लेकिन स्थानीय गिल्ड को अधिक से अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए।

सामान्यतः समस्त महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक उत्पादन तथा उपभोक्ता क्षेत्रों में राष्ट्रीय गिल्ड (National Guild) होंगे। राष्ट्रीय गिल्ड किसी भी एक उद्योग से सम्बन्धित सभी प्रकार के श्रम या कार्य जैसे प्रशासनिक, कार्यपालिका तथा उत्पादन आदि का संगम होना। इसमें वे सभी सम्मिलित होंगे जो हाथ या मस्तिष्क से कार्य करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम कर सकता है इनका सदस्य बन सकता है।¹⁹ यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय गिल्ड कोई एक ही नहीं होगा। प्रत्येक उद्योग या गतिविधियों से सम्बन्धित राष्ट्रीय गिल्ड हो सकते हैं। इस प्रकार गिल्ड प्रणाली के अन्दर कई राष्ट्रीय गिल्ड हो सकते हैं। इनका कार्य अपने ही उद्योग में नीचे के गिल्ड को परामर्श देना, उनके कार्यों में सात-मेल बैठाना, पूरे उद्योग से सम्बन्धित नीति निर्धारण करना आदि होगा।

गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत सबसे अन्तिम संगठन कम्यून (Commune) कहलायगा। यह राज्य का स्थान ग्रहण करेगा। कम्यून में सभी राष्ट्रीय गिल्ड के प्रतिनिधि होंगे। रोज के अनुसार कम्यून निम्नलिखित कार्य करेगा:—²⁰

19 Hobson, S. G., Guild Principles in War and Peace, 1938, pp. 26-27.

20 Col. G. D. H., Guild Socialism, Allen & Unwin, London, 1920, p. 125.

- (i) वित्तीय मामले जैसे राष्ट्रीय स्रोतों का वितरण, आयदानी, मूल्य आदि से सम्बन्धित समस्याएँ,
- (ii) नीति के मामलों में विभिन्न गिल्ड (श्रेणियों) के मतभेदों को सुलभाना,
- (iii) विभिन्न गिल्ड के अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित सवैधानिक समस्याओं का समाधान करना,
- (iv) विदेशी मामले,
- (v) आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का प्रयोग, तथा
- (vi) वे कार्य जो किसी अन्य गिल्ड के अधिकार क्षेत्र में न आते हैं ।

चूँकि कम्पून राज्य के स्थान पर कार्य करेगा इसलिए स्थानीय, क्षेत्रीय स्तर पर भी इसकी शाखाएँ होंगी जो अपने अपने स्तरों पर यही कार्य करेंगी जो राज्य करता है तथा जिसे कम्पून स्वीकार करे ।

प्रत्येक स्तर पर श्रेणियों का संगठन स्वायत्तता और लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के आधार पर होगा । प्रथम, प्रत्येक गिल्ड अपने प्रबन्ध के लिए स्वायत्त होगा । लेकिन वे दूसरी श्रेणियों के साथ पारस्परिक निर्भर होंगे । उन्हें अपनी इस स्वतन्त्रता या स्वायत्तता का अन्य गिल्ड के साथ समन्वय करना होगा ताकि उनमें संघर्ष या स्पर्धा न हो । दूसरे प्रत्येक गिल्ड का सम्पूर्ण प्रबन्ध लोकतान्त्रिक पद्धति से होगा । सदस्यों की इच्छानुसार उनके प्रतिनिधियों का चयन किया जाय । गिल्ड के सदस्य अपने अधिकारियों, समितियों तथा ऊपर के स्तर की श्रेणियों के लिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे ।

गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत राज्य की स्थिति

गिल्ड व्यवस्था पर आधारित समाज में राज्य की क्या स्थिति हो इस सम्बन्ध में गिल्ड समाजवाद के समर्थक एकमत नहीं हैं, लेकिन राज्य के विषय में इनके दो पक्ष पूरण स्पष्ट हैं । प्रथम, गिल्ड समाजवाद मुख्यतः धार्मिक और प्रौद्योगिक व्यवस्था से सम्बन्धित है । यह उद्योग पर राज्य के प्रबन्ध, नियंत्रण या हस्तक्षेप का समर्थक नहीं है । गिल्ड समाजवादी उद्योगों को राज्य के आधिपत्य से मुक्ति चाहते हैं तथा गिल्ड प्रणाली को अधिक महत्त्व देते हैं ।

द्वितीय, अराजकतावादी और सिन्डीकलवादियों की भाँति गिल्ड समाजवादी राज्य को पूर्णरूप से समाप्त करने के पक्ष में भी नहीं हैं । स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर गिल्ड प्रणाली की स्थापना से ही पूरे सामाजिक कार्य नहीं चल सकते । समाज की कुछ ऐसी भी आवश्यकताएँ हैं जिन्हें चकाने के लिये गिल्ड समाजवादी राज्य की किसी न किसी रूप में आवश्यकता स्वीकार करनी है । देश की रक्षा, अराजकता की रोकथाम आदि ऐसी बातें हैं जिन्हें गिल्ड नहीं कर सकते । इनके लिए वेदल राज्य ही उपयुक्त है । गिल्डों द्वारा न किया जाने वाले समस्त

राजनैतिक कार्य राज्य ही करेगा। इस प्रकार गिल्ड समाजवाद राज्य के अस्तित्व एवं आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी उसके सीमित अधिकारों का समर्थक है।

बार्कर (E. Barker) के अनुसार गिल्ड समाजवाद के समर्थक राज्य तथा श्रेणियों (Guilds) दोनों के लिये गुजाइश छोड़ते हैं। शक्ति-विभाजन के आधार पर ये राज्य तथा गिल्ड के अस्तित्व को मान्यता देते हैं। किन्तु राज्य का स्तर फिर भी सबसे महत्वपूर्ण होगा। बार्कर के शब्दों में—

“गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत आधुनिक राज्य व्यावसायिक श्रेणियों का एक समुदाय होगा। किन्तु राज्य इस प्रकार की श्रेणियों के समूह से कुछ अधिक ही होगा। राज्य सिर्फ एक कोष्ठक या हायफन (hyphen) ही नहीं किन्तु स्वयं का एक वास्तविक अस्तित्व होगा।”²¹

गिल्ड समाजवादियों में राज्य की उपयोगिता एवं कार्य-क्षेत्र के विषय में मुख्यतः मतभेद हाब्सन तथा कोल में है। ये दोनों ही दो दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राज्य के विषय में हाब्सन (S. G. Hobson) के विचार

हाब्सन हालांकि गिल्ड समाजवादो है, लेकिन उनके राज्य-सम्बन्धी विचार गिल्ड समाजवाद की अपेक्षा राज्य-समाजवाद के अधिक निकट हैं; या उनके विचार राज्य-समाजवाद और बहूलवाद के सम्मिश्रण हैं। हाब्सन गिल्ड व्यवस्था का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन प्रत्येक गिल्ड समाज के किसी विशिष्ट अंग का ही प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिये राज्य जैसी संस्था का होना परमावश्यक है जो सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और शक्ति का अन्तिम स्रोत माना जाये। हाब्सन के राज्य सम्बन्धी विचारों की विवेचना से निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं:—

प्रथम, राज्य सम्पूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है।

द्वितीय, राज्य की आर्थिक सत्ता को गिल्डों में वितरित कर राज्य की शक्ति को कम कर दिया जाये।

तृतीय, उत्पादन की सारी मशीनों, कारखानों का स्वामित्व राज्य का होगा। यह उन्हें तमाम गिल्डों को पट्टे पर देगा। इनका प्रयोग गिल्ड समाज-हित में ट्रस्टी के रूप में करेंगे।

चतुर्थ, राज्य समस्त गिल्डों से कर आदि बमूल करेगा तथा ऐसी श्रेणियों को महायता देगा जो स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि की निःशुल्क सामाजिक सेवा करती है।

21. “Under Guild Socialism the modern state will be a community of professional Guilds. But the state will be more than a sum of such Guilds. It will not be a mere bracket or hyphen, but a real entity in itself.”
Barker, E., Political Thought in England, 1843 to 1914, p 201.

पक्ष, राज्य के अन्य कार्य प्राथमिक एवं वास्तु सुरक्षा का उत्तरदायित्व, प्रमुख कानूनो का निर्माण तथा गिल्डो के आपसी विवादो को सुलभाना होगा।

राज्य एवं कम्पून व्यवस्था के विषय में कोल (G H Cole) के विचार—

हॉब्सन की तुलना में कोल राज्य को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। हॉब्सन के विचार जो राज्य को महत्त्व देते हैं, कोल ने उसका घण्टन किया है। कोल अपने विचारों में मूलतः बहुलवादी (Pluralist) हैं। कोल के अनुसार—

- (i) राज्य उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली आवश्यक संस्था है।
- (ii) उत्पादन संस्थाओं पर राज्य का नियन्त्रण नहीं होना चाहिए।
- (iii) समाज में राज्य का स्थान अन्य संस्थाओं जैसा ही होना चाहिये। राज्य अनेक समुदायों में एक समुदाय है। राज्य स्वयं भी एक प्रादेशिक गिल्ड जैसा होगा। जिसका कार्य समाज सुरक्षण, शिक्षा व्यवस्था, विवाह-तलाक नियन्त्रण, अपराधों की रोकथाम तथा बच्चों की देखभाल आदि होगा।

राज्य और अन्य गिल्डों के विवाद समाप्त करने तथा गतिविधियों में तालमेल बैठाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाये जिसका नाम Democratic Supreme Court of Functional Equity—(कार्यत्मक न्याय का सोवैतान्त्रिक उच्चतम न्यायालय) होगा। यह न्यायालय राज्य तथा अन्य गिल्डों के ऊपर होगा। यह शान्ति व्यवस्था, पुष्टि, कानून आदि का नियन्त्रण करेगा। समाज में यही सर्वोच्च संस्था होगी।

कोल राज्य के कार्य-क्षेत्र को प्रिलुल सङ्चित ही नहीं करते किन्तु वह राज्य की सम्प्रभुता सम्पन्न धारणा को भी स्वीकार नहीं करते। राज्य के विषय में कोल के विचारों में प्रागे चल कर और भी परिवर्तन हुआ है। कोल के अनुसार राज्य धीरे-धीरे मुरभा जायेगा तथा उसका स्थान एक कम्पून व्यवस्था लेगी।

कम्पून प्रणाली (Commune System)

समस्त समुदायों में सामन्जस्य कार्य के लिये कोल कम्पून प्रणाली का प्रतिपादन करता है, यह समस्त समाज की संस्थाओं का एकीकरण करने वाली संस्था होगी। कम्पून का संगठन स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तरों पर होगा। प्रत्येक स्तर पर कम्पून उत्पादकों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक गिल्ड के प्रतिनिधियों को मिलाकर स्थानीय कम्पून की रचना होगी। प्रादेशिक स्तरों तथा अन्य क्षेत्रों के गिल्डों के प्रतिनिधियों का प्रादेशिक कम्पून होगा। राष्ट्रीय स्तर के तमाम गिल्डों का राष्ट्रीय कम्पून बनाया जायेगा। प्रत्येक स्तर पर कम्पून के निम्नलिखित कार्य होंगे—

- (i) राजस्व प्रवन्ध, मूल्य निर्धारण तथा श्रृण व्यवस्था ।
 (ii) विभिन्न गिण्ड के कार्य-क्षेत्र एवं शक्तियों का निर्धारण करना ।
 (iii) गिण्डों के बीच नीति सम्बन्धी मनभेदों का निराकरण करना ।
 (iv) राजनीतिक कार्य, जैसे:— 420
 (अ) युद्ध, शान्ति की घोषणा तथा सैन्य बल पर नियन्त्रण;
 (ब) वैदेशिक सम्बन्धों का नियन्त्रण,
 (स) नगरों, कस्बों तथा प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण;
 (द) व्यक्तिगत सम्बन्धों तथा वैयक्तिक सम्पत्ति पर नियन्त्रण आदि ।
 (v) बलप्रयोग करना । समाज की समस्त सस्थाओं को कानून के अनुसार अपने-
 तायं पालन करने के लिये बाध्य करना । पुलिस कार्य तथा दण्ड व्यवस्था भी
 राज्य के कार्य होंगे ।

गिण्ड समाजवादी साधन

राजनीतिक साधन

गिण्ड समाजवादी अपनी कल्पनानुसार जो सामाजिक रचना करना चाहते हैं उमरी प्राप्ति के साधन के विषय में ये एक तो पूर्णतः स्पष्ट नहीं है तथा दूसरे इस विषय पर इसके समर्थक एतन् भी नहीं हैं । सामान्यतः ये राजनीतिक तथा सर्व-
 धानिक साधनों में श्रद्धा नहीं रखते क्योंकि:—

प्रथम, पूंजीवादी व्यवस्था में यह असम्भव है कि श्रमिक वर्ग में पूर्ण वर्ग चेतना प्राये और वह संगठित हो कर एक मास मतदान करें ।

द्वितीय, परिवर्तन लाने में प्रति विलम्ब होगा । लम्बे समय तक इन साधनों में गिण्ड प्रणाली की स्थापना नहीं हो सकती ।

तृतीय, पूंजीवादी वर्ग और शासन वर्ग इस प्रकार के परिवर्तन के मार्ग में बाधाएँ प्रस्तुत करेंगे ।

अतः में, गिण्ड समाजवादियों की यह धारणा है कि राज्य सस्था स्वयं ही इस प्रकार की समाज रचना के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त नहीं है ।

अतः गिण्ड समाजवादियों का प्रादुर्भाव इंग्लैण्ड में हुआ इसलिये इसके समर्थक वहाँ के राजनीतिक आतावरण के प्रभाव में अपने को अलग नहीं कर सके । इसलिये राजनीतिक साधनों के विरुद्ध होने हुए भी सर्वधानिक एवं शान्तिपूर्ण साधनों तथा श्रमिक विभाग के सिद्धान्त का पूर्णतः बहिष्कार नहीं करते तथा ऐसे ही साधनों में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं ।

धार्मिक साधन

गिण्ड समाजवादी प्रत्यक्ष कार्यवाही (direct action) जैसे हड़ताल, तोड़-
 फोड़ आदि में विश्वास तो नहीं रखते, लेकिन युद्ध ऐसे धार्मिक साधन हैं जिनमें उनका पूर्ण विश्वास है । गिण्ड समाजवादी निम्नलिखित धार्मिक साधनों को प्रमुच्यता देने हैं:—

धीरे-धीरे नियन्त्रण प्राप्त करने की नीति (The policy of encroaching control)—इसका तात्पर्य है कि शनैः शनैः श्रमिक स्वामियों से अधिकारों को छीन लें। इस नीति के अन्तर्गत श्रमिकों को इस बात का आग्रह करना चाहिए कि कारखानों के मालिकों जैंगे फोरमेन, मीस्टरसिपर, टेक्नीशियनों आदि की नियुक्तियों के लिए श्रमिक स्वयं चुनाव करेंगे। इसके अलावा श्रमिक जिन अधिकारियों को पसन्द न करें उन्हें नौकरी से हटा दिया जाय। इस प्रकार नियुक्ति तथा पद से हटाने का अधिकार जब श्रमिकों के हाथों में आ जायेगा तो धीरे-धीरे सम्पूर्ण कारखाने पर उनका आधिपत्य हो जायगा। इस साधन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि श्रमिक तथा समाज के अन्य वर्गों हिंसा तथा मारकाट से बच जायेंगे।

औद्योगिक प्रतिस्पर्धा (Industrial Competition) श्रमिक सघ सामूहिक रूप से पूँजीपतियों से स्पर्धा करेंगे तथा स्वयं उद्योगों की स्थापना करेंगे। गिल्ड उद्योगों का गवर्नलन योग्यता के साथ कर पूँजीपतियों को झुका देंगे।

सामूहिक ठेका या संविदा (Collective Contract)—इसका तात्पर्य यह है कि श्रमिक सगठन कारखाने के मालिकों के साथ समझौता करें तथा उत्पादन का स्वयं ठेका ले लें। इससे अनुसार यह निश्चय करना होगा कि किस प्रकार के माल का कितना उत्पादन होगा तथा उसकी इकट्ठी मजदूरी कितनी होगी। सघ सगठन उत्पादन का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लें, अपने काम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करें तथा काम करने के बाद पूरी मजदूरी माँगने में विनरित कर लें।

मुद्रास्वयं का विरोध—यदि उपरोक्त साधनों से पूँजीपतियों से उनकी सम्पत्ति ले ली जाती है तो गिल्ड समाजवादी उसका मुद्रास्वयं देने के पक्ष में नहीं हैं। इसके बदले अधिक से अधिक उद्योग स्वामियों की सहायता के रूप में कुछ भत्ता दिया जा सकता है।

सगठन शक्ति

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गिल्ड समाजवादी यह चाहते हैं कि श्रमिक सगठनों की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाये। इसके लिये वे कुछ सुझाव देते हैं : प्रथम, गिल्ड व्यवस्था को व्यापक बनाया जाय ताकि चपरासी से स्केपर मैनजर तक सभी गिल्ड के सदस्य बन। इस प्रकार का गिल्ड पूँजीपति को अधिक सफलतापूर्वक चुनौती दे सकता है। द्वितीय, श्रमिक सगठनों का आन्तरिक ढाँचा पूर्णतः लोक-तान्त्रिक हो। समस्त सघों में एकता और सहयोग हो ताकि उनका श्रमिक शक्ति पर पूर्ण आधिपत्य हो, तृतीय, इस प्रकार के पूँजीवादी व्यवस्था का अच्छी तरह मुकाबला कर सकेंगे। तृतीय, श्रमिक मन्त्रियों के सगठन को सुदृढ़ बनाया जाय जिससे सगठन समर्थन में आवश्यकता पडने पर वे सम्पूर्ण काम सुचारु रूप से चला सकें।

गिल्ड समाजवादी साधनों से यह बात स्पष्ट होती है कि वे अर्थ व्यवस्था पर क्रमिक नियन्त्रण प्राप्त करना चाहते हैं। वे वर्तमान श्रमिक-संघ संगठन के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सम्भवतः उनकी चंष्टा यह है कि पूँजीवादी तथा समाजवादी समाज के मध्य जो खाई है उस पर पुल बांध दिया जाये। तभी वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति पर सक्ते हैं।²²

गिल्ड और ट्रेड यूनियन (Guilds and Trade Unions)

गिल्ड समाजवाद का अध्ययन करते समय कहीं-कहीं यह भास होता है कि गिल्ड और ट्रेड यूनियन एक जैसी ही संस्थाएँ हैं जैसे दोनों ही श्रमिक वर्ग का बल्याण चाहते हैं, दोनों ही उत्पादन में श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान का पक्ष लेते हैं, तथा उद्योगों में श्रमिकों की कार्य परिस्थितियों में सुधार एवं श्रमिक नियन्त्रण का समर्थन करते हैं। फिर भी गिल्ड प्रणाली और श्रमिक संघ एक नहीं हैं। इनमें निम्नलिखित अन्तर स्पष्ट ही अपने आप स्पष्ट होता है —

- (i) ट्रेड यूनियन सीमित संस्थाएँ हैं। इनके केवल श्रमिक ही सदस्य हो सकते हैं। गिल्ड व्यवस्था में उस उद्योग के श्रमिक, प्रबन्धक, बुद्धिजीवी आदि सभी सदस्य हो सकते हैं। गिल्ड की सार्वभौमता व्यापक है।
- (ii) ट्रेड यूनियन मजदूरी में वृद्धि तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार चाहते हैं। गिल्ड प्रणाली पूरे उद्योग का नियन्त्रण चाहती है।
- (iii) ट्रेड यूनियन मुख्यतः प्रबन्धकों से संपर्क तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही में विश्वास करते हैं। गिल्ड प्रणाली में यह बात स्वीकार नहीं की जाती।
- (iv) ट्रेड यूनियन स्वार्थ पर निर्भर हैं। यह अपने सदस्यों के हित को ही सर्वोपरि मानता है। गिल्ड व्यवस्था का उद्देश्य सम्पूर्ण समाज की भलाई है।

मध्यमार्गीय समाजवाद

गिल्ड समाजवाद मध्यमार्गीय विचारधारा है। उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित समाजवादी विचारधाराएँ गिल्ड समाजवादियों को या तो अधिक उग्र या अत्यधिक उदार लगीं। यूटोपियायी विचारकों के साधन एवं आदर्श सामाजिक व्यवस्था उन्हें प्रभावित नहीं कर सकीं। मार्क्सवाद उन्हें श्रौंमकपक्षीय एवं क्रान्तिकारी प्रतीत हुआ। धराजन्ततावाद उद्देश्यहीन सा लगा। सिन्टीकलवाद में उन्हें मार्क्सवादी उग्रता तथा धराजन्ततावाद की धराजन्तता दृष्टिगोचर हुईं। पेथियनवाद सिर्फ बुद्धिवादी और श्रमिक कार्य-क्रम रहित जान पड़ा। समष्टिवाद भी अधिनायकत्व तथा राज्य सत्ता में वृद्धि का समर्थक जैसा लगा।

22. जोड., धातुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 86.

किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि उन्होंने पूणत इन सभी विचारधाराओं का जड़ मूल से ही खण्डन किया हो। गिल्ड समाजवादियों का उद्देश्य समाजवादी विचारधाराओं की शक्तिकारी उन्नति तथा कुछ की प्रति उदारवादियों का त्याग कर अग्रज मनोवृत्ति व अनुभूत एक नये समाजवादी सम्प्रदाय का सर्जन करना था। इस आधार पर उन्हें अन्य विचारधाराओं में जा भी अच्छा लगा ग्रहण किया। इस प्रकार यह सामन्वयगत विचारधारा थी। इसे समष्टिवाद तथा सिन्डीकलवाद का बुद्धिजीवी शिशु (Intellectual Child) भी कहा जाता है। अन्य शब्दों में इसका उद्भव समष्टिवाद (और फियलिवाद भी) और सिन्डीकल क संयोग से हुआ।

गिल्ड समाजवादी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति व हालातों को हैं। वे पूँजीवाद तथा उससे सम्बन्धित दुर्गुणों की निन्दा करते हैं। लेकिन उनका विचारों में मानसवाद और सिन्डीकलवाद की वह उन्नति नहीं है जो प्रचलित व्यवस्था का पूणत उन्मूलन कर एक नई व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। गिल्ड समाजवादी प्रचलित दोषों को दूर करने श्रमिकों का शोषण समाप्त करने के लिए तत्कालीन व्यवस्था का नष्ट नहीं करना सुझाए कर नई व्यवस्था की रचना उनका उद्देश्य है।

सिन्डीकलवाद में राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है। दूमरी और समष्टिवाद पूँजीवाद के दापों को दूर नहीं कर सकता। वे पूँजीवादी राज्य के स्थान पर शीकरशाही केन्द्रीकरण राज्य की स्थापना करते हैं। श्रमिकों को अपनी व्यवस्था तथा दशाओं का निर्धारण करने के लिए यह कुछ नहीं करता। गिल्ड समाजवादी न तो सिन्डीकलवादियों की तरह राज्य के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं और न ही समष्टिवादियों की भाँति राज्य स्वामित्व की स्थापना व पक्ष में हैं। गिल्ड समाजवाद राज्य के सीमित अधिकार तथा साथ ही साथ गिल्ड व्यवस्था की स्थापना का अनुमोदन करता है।

गिल्ड समाजवादी सम्पूर्ण क्षेत्रों में गिल्ड व्यवस्था की रचना चाहते हैं। वे सिन्डीकलवादियों की भाँति गिल्डों को सामाजिक संगठन का आधार बनाना चाहते हैं। लेकिन समष्टिवादियों की तरह राज्य की भी उपयोगिता में विश्वास रखते हैं। गिल्ड समाजवाद राज्य के सीमित अधिकार साथ ही साथ गिल्ड व्यवस्था की स्थापना का अनुमोदन करते हैं। यहाँ वे सिन्डीकलवाद तथा समष्टिवाद से दूर हान हुए भी दापों के निन्दा हैं।

सिन्डीकल समाज आर्थिक जीवन में उत्साहों का प्रमुख स्थान देकर उत्पादन पर उन्हीं का नियंत्रण चाहता है। समष्टिवाद तथा राज्य समाजवाद मनुष्य को बस उपभोक्ता व हीरुन में देखना है। गिल्ड समाजवादी उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को ही महत्त्व देते हैं। इसने समष्टिवाद तथा सिन्डीकलवाद के एकपक्षीयपन का दूर कर सामन्वय स्थापित किया।

साधनों के विषय में भी गिल्ड समाजवादी व्यक्तिवादी नहीं हैं। वे मानसवाद की क्रान्तिकारी पद्धति तथा सिन्डीकलवाद की संधि या प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसे हड़ताल आदि में विश्वास नहीं करते। क्रान्ति के आधार पर समाजवाद की धाकड़िक स्थापना निश्चित संघेजों को प्रभावित नहीं कर पाई। दूसरी ओर यूटोरियायी साधन जैसे उच्च वर्ग से सुधार की धनी करना या व्यक्तिवादियों की भीति प्रत्यक्ष कक्ष से बँडे बँडे ही कामजी कार्यवाही जिसमें सक्रियता का कोई स्थान न हो आदि में गिल्ड समाजवादियों की निष्ठा नहीं थी। उनमें साधन कम उपरिन्तु प्रभावपूर्ण स्थापित कार्यवाही पर आधारित थे।

इस प्रकार गिल्ड समाजवाद अन्य समाजवादी विचारधाराओं का समन्वयपरक गिल्ड हुआ। समन्वय का प्रभाव मध्यमार्गीय ही हो सकता था और वास्तव में गिल्ड समाजवाद मध्यमार्गीय समाजवाद था भी।

मूलसंकन

गिल्ड समाजवादी आन्दोलन लगभग दो दशकों तक चला। 1906 में पेंटी के ग्रन्थ—Restoration of Guild System—ने प्रवाशन से प्रारम्भ हुआ और 1925 में—National Guild League—के विघटन के साथ ही इस आन्दोलन का अन्त हो गया। यह सम्प्रदाय समाजवादी आन्दोलन को न तो लोकप्रिय और न प्रभावशाली ही बना सका। गिल्ड समाजवाद कई दृष्टिकोणों से एक निर्वल विचार-धारा और अन्त्यावहारिक विकल्प साबित हुआ।

इंग्लैंड की परम्परा के विरुद्ध ①

संघेज चरित्र की यह विशेषता है कि वे केवल उन्नी विचार को ग्रहण करते हैं जो व्यावहारिक एवं विकास का परिणाम हो। यहाँ सोमिउराउअन्त, लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था तथा उदारवाद का धीरे-धीरे विकास हुआ और इनकी जड़ें वहीं बहुत ही हड़नापूर्वक जम चुकी हैं। गिल्ड समाजवाद ने जो कुछ विचार रखे थे प्रथम, उस शासन प्रणाली को चुनौती देने हैं, जिन्हा सदियों से विकसित हुआ है। द्वितीय, वे जो कुछ विकास के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह इतना निर्वल सिद्ध हुआ कि संघेजों ने न तो इन पर ध्यान रखा ही मन्वीरनापूर्वक मनन किया और न ही स्वीकार किया। इस प्रकार यह कुछ दरों के विचार आन्दोलन के बाद स्वयं ही समाप्त हो गया।

मौलिकता का प्रभाव ②

गिल्ड समाजवाद में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसे विषय में इसके समर्थक मौलिकता का दावा कर सकें। इसे राज्य समाजवाद और पेरियनवाद का बुद्धिजीवी शिशु कहा जाता है। क्रिजजर एवं रॉन ने इसे सिन्डीकलवाद तथा पेरियनवाद का यहोउर कहा है। यभी-कभी इसे फ्रॉग के सिन्डीकलवाद का संघेजो नमानान्तर

वहते है। हेनोवेल ने इसे मिन्डीनलवाद वा रक्तहीन रूपान्तर की सजा दी है।²³ गिल्ड समाजवाद के सबसे प्रमुख समर्थक कोल (G D H. Cole) का एक पैर १६ विघनवादी भवन म था जो दूसरा गिल्ड समाजवादी रोमे मे। ये इन दोनों विचारधाराओं के माय-भाय बहलवादी भी थे। गिल्ड समाजवाद मे प्रभाव डालने वाली विचार-मौलिनता का प्रभाव तो था ही यह उस समय प्रचलित विचारधाराओं का समुचित जन्मव्य भी नहीं बन पाया।

अनिश्चित विचारधारा

गिल्ड समाजवाद एक निश्चित विचारधारा भी नहीं बन पाया। इसके स्तिपादको म मतभेद है। हाथ्यन तथा कोन मे इन मून बातों पर ही मतभेद है कि गिल्ड प्रणाली पर आधारित समाज का क्या स्वरूप होगा। राज्य के अस्तित्व एवं क्षेत्राधिकार के विषय म भी उनके विचारों मे भारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।

ऐनेजेन्डर से वा विचार है कि बीसवीं सदी के प्रारम्भ मे "समाजवाद चौराहे पर एक छोए बच्चे के समान था जिसे यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ से आया है तथा कहाँ जाना चाहता है। समाजवाद ही यह दुर्देश बनाने म काफी सीमा तक गिल्ड समाजवाद उत्तरदायी है। इन्होंने राज्य समाजवाद वा राष्ट्रीयकरण के विचार को पूरी तरह नष्ट करने का भरमन्न प्रयत्न किया। इनके अनुसार राज्य समाजवाद एक बेमार सा विकरन वा। गिल्ड समाजवादिया ने पुराने समाजवादी विचार को समाप्त तो किया, किन्तु इसने स्थान पर व कोई ऐसा विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके जैसे स्वीकार किया जा सके।"²⁴

प्रज्य एत सरकार

गिल्ड समाजवादी जब राज्य के विषय मे विचार व्यक्त करते हैं उस समय वे एक मूल नुडि करने हैं, वे राज्य और सरकार मे अन्तर नहीं करते। यदि वे इस अन्तर को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देते, तो उनके विचार बहुत बुद्ध ठीक प्रतीत होते। वे जिस सस्था को राज्य कहते हैं वह वास्तव मे राज्य नहीं सरकार है। ज्य की समाप्ति अक्षम्य है। अधिकार सरकार के कर्म किये जा सक्ते हैं।

23 Kitzler and Ross, Western Social Thought, p 285,

Hallowell, J H, Main Currents in Modern Political Thought, p 469

24 "Socialism today is rather like a lost child at the cross roads, not quite sure where it has come from and not knowing where exactly it wants to go. For this the Guild socialists are to a considerable extent responsible. They killed, and killed rather effectively, the old idea of State socialism, meaning thereby straight forward nationalisation, and they showed that it was rather a poor and unimaginative ideal. But having destroyed the old faith of socialism, they have provided no new abiding faith to take its place"

Gray, A, The Socialist Tradition, p 458

हाइसन के राज्य सम्बन्धी विचार किसी सीमा तक उचित है। लेकिन कोल के विचार उचित प्रतीत नहीं होते। कोल जब राज्य को अन्य समुदायों जैसा कहता है तब राज्य राज्य नहीं रहेगा; तथा जब वह किसी न्यायालय या कम्प्यून की स्थापना की वृत्ता है तो यह कम्प्यून व्यवस्था ही वास्तव में राज्य की शासन व्यवस्था होगी।

द्वैध शासन प्रणाली (६)

एक ही राजनीतिक समाज में राज्य के कार्यों को गिल्ड समाजवादी दो भागों में विभाजित करते हैं—राजनीतिक और आर्थिक। आर्थिक कार्य गिल्ड करेंगे तथा राजनीतिक कार्य राज्य के पास ही रहेंगे। इस प्रकार एक ही शासन व्यवस्था को गिल्ड समाजवादी दो शाखाओं में विभाजित करते हैं तथा इन दोनों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व दो प्रकार की समस्याओं को देते हैं। यह सैद्धान्तिक रूप में ठीक नहीं है।

गिल्ड समाजवादी समाज के आर्थिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन करते हैं। आर्थिक कार्य गिल्ड करेंगे तथा राजनीतिक कार्य राज्य के पास छोड़ दिये जायेंगे बहुत ही व्यापक या मोटे रूप से कुछ कार्यों को आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन यह सामान्यतः संभव नहीं है। समाज में आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों का स्पष्ट एवं निश्चित विभाजन नहीं हो सकता व्यावहारिक दृष्टि से ये दोनों पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्धित हैं। जब यह विभाजन स्पष्टतः नहीं हो सकता तो कौन से कार्य राज्य को छोड़े जायें, कौन से कार्य गिल्डों को दिये जायें, तथा जो पूर्ण रूप से दोनों पक्षों में आते हैं उन्हें राज्य या गिल्डों में से किसको दिये जायें यह संभव नहीं है। इस प्रकार उनकी विचारधारा का प्रमुख आधार ही समाप्त हो जाता है।

गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत राज्य तथा श्रेणियों में अधिकार-विभाजन का वाकर (E. Barker) ने आलोचना की है। वाकर ने लिखा है—

“ वास्तव में, शक्ति-विभाजन का कोई भी सिद्धान्त, जैसा कि गिल्ड समाजवाद समर्थन करता है, घराशाही हुए बिना नहीं रह सकता क्योंकि यह सामान्य तथ्य है। आजकल के वृद्ध समाज में पारस्परिक निर्भरता अत्यन्त आवश्यक है। राज्य एक शरीर है; कोई भी व्याख्या इस तथ्य से अलग नहीं की जा सकती।”²⁵

25 “In truth, any doctrine of separation of powers, such as Guild Socialism advocates, is bound to collapse before the simple fact of the vital inter-dependence of all the activities of the great society of today. The state is one body, no clever essay in dichotomy can get away from that fact.”

Barker, E., Political Thought in England, 1843 to 1914, p. 203.

समर्थ की सम्भावना

गिल्ड समाजवादी प्रत्येक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में गिल्ड की स्थापना चाहते हैं। प्रत्येक स्तर पर सम्पूर्ण व्यवस्था भी होगी। साथ ही साथ प्रत्येक स्तर पर राजनीतिक दायों के लिये राज्य निम्न न किसी रूप में रहेगा ही। इसके अलावा बहुत कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे आर्थिक अधिक हैं या राजनीतिक। इन परिस्थितियों में समाज में सम्पूर्ण गिल्ड व्यवस्था में अराजकता तथा समर्थ होना अवश्यम्भावी है। समाज में इतनी संख्या में विभिन्न संस्थाओं का होना ही प्रतिद्वन्द्वता तथा गतिरोध के लिये पर्याप्त है।

अव्यावहारिक एवं त्रुटिपूर्ण प्रतिनिधि प्रणाली

गिल्ड समाजवादी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का खण्डन कर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। इनके क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की आलोचना में आशिक सत्यता तो है, लेकिन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व उसका विकल्प नहीं हो सकता। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व स समर्थ का राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो जायगा। समर्थ एक परस्पर-विरोधी विभिन्न व्यावसायिक हितों का संपूहमात्र ही रह जायगी। इसके अलावा विभिन्न व्यावसायिक हितों का समान प्रतिनिधित्व अनुचित एवं अव्यावहारिक दोनों ही हैं। समाज में कुछ व्यवसाय अधिक बहुतरासपूर्ण होते हैं तथा कुछ कम। इनके अनुपातिक महत्त्व को भी गिल्ड समाजवादी स्वीकार नहीं करते।

शिल्पकारिता का धर्ममूलक समर्थन

गिल्ड समाजवादी उत्पादन क्षेत्र में शिल्पकारिता के समर्थन हैं तथा उसे पुनर्जीवन करने के लिए उन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था और बड़े पैमाने पर उत्पादन का विरोध किया है। जिस समाज में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जहाँ समाज की माँगें निरंतर बढ़ रही हैं, इन समाजों में बड़े पैमाने के उत्पादन द्वारा ही समर्थ है। बड़े पैमाने पर उत्पादन मूकम धर्म-विभाजन (Division of Labour) और विशेषीकरण (Specialisation) पर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में केवल शिल्पकारिता के लिए ही आधुनिक अर्थ व्यवस्था का छोड़ना असंभव एवं अवांछनीय दोनों ही होगा।

पेन्टी (A J Penty) दम्तकारिता तथा शिल्पकारिता के प्रथम समर्थक थे। जोड (C E M. Joad) के अनुसार 'पेन्टी के तर्क' प्रथम, भावुकता तथा प्रश्न सौन्दर्यात्मक आधारों पर आधारित हैं तथा वे बड़े पैमाने पर उत्पादन तथा व्यापार के आधुनिक पद्धतियों के विरुद्ध हैं। इन कारण अन्ततः दम्तकारों के आधार पर अर्थोत्पादकों के संगठन का प्रस्ताव आधुनिक परिस्थितियों में अव्यावहारिक नहीं है।" 26

दूसरे, शिल्पकारिता की भावना को किन्हीं क्षेत्रों में तो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन यह मनुष्य को स्वयं-केन्द्रित और व्यक्तिवादी बनाता है। मनुष्य सामूहिक एवं सामाजिक प्रयत्नों की अपेक्षा करता है। यदि यह विचारधारा सामूहिक और सामाजिकता के विरुद्ध है तो इसे समाजवादी विचारधारा बहना ही उपयुक्त न होगा।

आधुनिक अर्थ-व्यवस्था के अनुपपुक्त 9

आधुनिक अर्थ व्यवस्था बड़े पैमाने (Large Scale) और विशिष्टीकरण (Specialisation) के ऊपर आधारित है। किसी एक बड़ी वस्तु के महत्वपूर्ण भागों के निर्माण के लिये अलग स्थानों पर उद्योगों की स्थापना की जाती है। अलग अलग स्थानों पर निर्मित भागों को फिर एक जगह एकत्रित किया जाता है। इसके लिये उद्योगों की पूर्ण परस्पर निर्भरता और समन्वय अत्यन्त ही आवश्यक है। इस प्रकार की उत्पादन व्यवस्था में गिल्ड समाजवाद या तो उपयुक्त नहीं है या इस तरह औद्योगिक विकास गिल्ड प्रणाली के अन्तर्गत सम्भव ही नहीं है।

आधुनिक युग में प्रत्येक राज्य सीमित या व्यापक रूप में उद्योगों या जन उपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) का राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीय उत्तरदायित्व लेते हैं इससे राज्य की उपयोगिता में वृद्धि हुई है। जब समाज इस प्रकार की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है तब गिल्ड प्रणाली की कल्पना ही मूर्खतापूर्ण होगी।

औद्योगिक अवनति 10

गिल्ड व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक अवनति की अधिक सम्भावना है। किसी सीमा तक मनुष्य स्वार्थी होता है। हो सकता है कि मनुष्य गिल्ड का अपने स्वार्थ के लिये प्रयोग करे। गिल्ड व्यवस्था में श्रमिक सघों का उत्पादन पर पूर्ण आधिपत्य होगा। उनके ऊपर एक कुशल प्रबन्धक का अभाव होगा। इस दशा में श्रमिक मेहनत और कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकेंगे। इससे औद्योगिक गतिहीनता आ जायेगी।

उत्पादक वर्ग की प्राथमिकता 11

गिल्ड समाजवाद जैसे समस्त सामाजिक वर्ग जैसे उत्पादक वर्ग, उपभोक्ता वर्ग आदि के हितों का संरक्षण करता है किन्तु वास्तव में यह विचारधारा उत्पादक के रूप में श्रमिकों की ओर अधिक मुकी हुई है। यह उत्पादक वर्ग को प्राथमिकता देती हुई प्रतीत होती है।²⁷ यह सम्भव हो सकता है कि उत्पादक वर्ग उपभोक्ताओं पर हावी हो जाय। इस प्रकार समाज के सभी वर्गों के संरक्षण की बात में खोखलापन अधिक है। इसके अलावा उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य विभेद करना

27. Crosland, C. A. R., The Future of Socialism, p. 86.

अव्यावहारिक है। उपभोक्ता किसी न किसी प्रकार का सजंन कार्य करता है और उत्पादक उपभोक्ता होता ही है। यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होता।

एकाधिकार को प्रोत्साहन (12)

गिल्ड समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योगों में गिल्ड का ही एकाधिकार होगा। स्पर्धा का अभाव में गिल्ड कुशलता के साथ कार्य कर सकेंगे या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। सम्भवतः नहीं।

एकाधिकार के कारण क्या गिल्ड समाज सेवा के उद्देश्य से काम करेंगे? 'ऐसा ही सत्य है कि समाज-सेवा का उद्देश्य, जिसकी यथार्थता को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत लाभ की तुलना में समय सिद्ध न हो सके। यह भी सम्भव है कि मनुष्य सर्वप्रथम अपना हानि-लाभ देखता है, इसके बाद वह मार्जनिज कल्याण की ओर ध्यान देता है। यदि ऐसा है तो गिल्ड समाजवाद मग हो जायेगा तथा समाज में अराजकता व्याप्त हो जायेगी क्योंकि यह एक ऐसी थैलियो (गिल्ड) के शोषण का केन्द्र-स्थल हो जायेगा जिनको अपने उद्योगों के क्षेत्र में एकाधिकार होने के कारण पूज्यपतियों से भी अधिक समुदाय का शोषण करने के मुक्त साधन उपलब्ध होंगे। 28

समाज के सामान्य हितों की क्षति (13)

विभिन्न उद्योगों के लिये पृथक-पृथक गिल्ड होने का तात्पर्य यह होगा कि समाज विभिन्न हितों में विभाजित हो जायेगा। प्रत्येक गिल्ड अपने-अपने विशेष हितों की रक्षा का प्रयत्न करेगा। इस परिस्थिति में समाज के सामान्य हितों की क्षति होगी। सामान्य हितों को समुचित महत्व नहीं मिलेगा। राज्य का राष्ट्रीय स्वरूप नष्ट हो जायेगा। राज्य ही सामान्य हितों का रक्षक होता है जिस समस्या को गिल्ड समाजवादी अथवा सत्वाओं के समान ही मानते हैं।

साधनों की अनुपयुक्तता (14)

गिल्ड समाजवादी गिल्ड व्यवस्था की स्थापना के लिये जिन साधनों की अपेक्षा है उसमें सफलता की आशा नहीं की जा सकती थी। वे हिमात्मक साधन और राजनीतिक साधन दोनों को ही नहीं अपनाते। जिन आर्थिक साधनों का वे समर्थन करते हैं उनसे कुछ आर्थिक उद्देश्य तो प्राप्त हो सकते हैं लेकिन पूज्यवाद का उन्मूलन राज्य के अधिकारों को पूर्णतः सीमित कर गिल्ड प्रणाली की स्थापना करना सम्भव नहीं। इसी कारण वे अपनी विचारधारा को धार्मिक करने में सफल रहे हैं।

योगदान

गिल्ड समाजवादी आन्दोलन का जीवन बड़ा छोटा रहा, किन्तु यह कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ गया। अब श्रमिक सभो, युद्धोत्तर सिन्डीकलवादी, समष्टिवादी आदि राष्ट्रीयकृत उद्योगों की व्यवस्था तथा व्यक्तिगत उद्योगों के नियंत्रण की योजनाओं ने गिल्ड समाजवादी सिद्धान्तों को व्यापक रूप में स्वीकार करते हैं। 1917 में व्हिटले रिपोर्ट (Whitley Report) के बहुत कुछ सुभाव तथा इनके अन्तर्गत जो श्रमिक समितियाँ नियुक्त की गयीं उन पर गिल्ड समाजवाद का स्पष्ट प्रभाव था। इन्होंने गिल्ड समाजवाद से ही प्रेरणा ग्रहण की।²⁹

अमेरिका में भी गिल्ड समाजवाद का प्रभाव पड़ा। जिन परिवर्तनों की माँगें गिल्ड समाजवादियों ने कीं उनमें से कुछ माँगें औद्योगिक नियन्त्रण के विस्तृत पुनर्गठन की योजना द्वारा 1933 से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार कर ली गयीं हैं। 1933 में राष्ट्रीय पुनरुद्धार कानून (National Recovery Act) के अनुसार सरकार ने काम के घंटों का मूल्य तथा उत्पादन की दर तथा प्रतियोगिताओं के सम्बन्ध में जो अधिकार प्राप्त किये उनको कार्यान्वित करने के लिये श्रमिकों के प्रतिनिधियों में परामर्श एवं समझौता किया जाने लगा। केन्द्रीय प्रशासक बोर्ड (Central Administrative Board) को परामर्श देने के लिये उद्योगपतियों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की समितियाँ होती हैं। इस प्रकार सभी सम्बन्धित हितों को संयुक्त भागीदार बनाना, गिल्ड समाजवाद की ही देन है।³⁰

एलेग्जेन्डर ग्रे ने लिखा है कि गिल्ड समाजवादी विचारधारा ने श्रमिक आन्दोलन को भी प्रभावित किया। अब श्रमिक संगठन अधिक औद्योगिकवादी तथा जागरूक हुए और वे कार्यप्रणाली के विषय में भी सोचने लगे। गिल्ड समाजवादियों ने लोकतान्त्रिक चुनाव प्रणाली की जो निन्दा की है उससे चुनाव प्रणाली के विषय में सुधारों के लिये इन्होंने नवीन शक्ति प्रदान की। प्रजातन्त्र के विषय में लोगों की जो शंकाएँ थीं उनको बल मिला। परिणामस्वरूप कई देशों में प्रतिनिधि प्रणाली में बहुत कुछ परिवर्तन हुए।³¹

कोकर के अनुसार गिल्ड समाजवादियों ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ सैद्धान्तिकों को प्रभावित किया है। बहुलवादियों के इस सिद्धान्त को सुझाकर या उनका समर्थन करके कि वर्तमान उद्योग की अवस्थाओं के अधीन स्वतंत्रता तथा समानता की प्राप्ति, कुलीनतन्त्र अथवा धनिकतन्त्र के स्थान पर समष्टिवादी प्रजातन्त्र व्यवस्था स्थापित करने से नहीं, किन्तु श्रमिकों की स्वायत्तशासी समुदायों में जो समाज सेवा के लिये

29. Kilzer and Ross, Western Social Thought, p. 297.

30. कोकर., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 299.

31. Gray, A., The Socialist Tradition, pp. 457-58.

त्रिगुण्ट आर्थिक या सांस्कृतिक कार्य के लिये संगठित हो, मरता का विभाजन करने से ही हाया।³²

गिल्ड समाजवाद के ये सिद्धान्त जिन्हें किसी न किसी रूप में आज भी मान्यता दी जाती है निम्नलिखित हैं —

- (i) मजदूरी पद्धति के दोषों की ओर ध्यान आकर्षित करना,
- (ii) श्रमिक सहयोगी संस्थाओं की महत्ता को समाज के सामने रखना,
- (iii) उद्योग प्रबन्धन न श्रमिकों के भाग की वाछनीयता पर जोर देना,
- (iv) राज्य के सर्वेध्यायी, सर्व-सत्ताधारी सिद्धान्त को अस्वीकार करना
- (v) ममान के छोटे छोटे हिस्सों को भी महत्ता प्रदान करना,
- (vi) क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा विकन्दोकरण के महत्त्व को स्वीकार करना,
- (vii) इन बातों पर जोर देना कि उत्पादन का उद्देश्य लाभ नहीं सामाजिक उपयोगिता है
- (viii) शान्ति एवं हिंसा के माध्यम से उद्देश्या की प्राप्ति की धारणा को अस्वीकार करना,
- (ix) प्रतिवादिता के स्थान पर मध्य-मार्गीय सिद्धान्त की महत्ता को स्वीकार करना, तथा
- (x) राजनीतिक स्वतन्त्रता का उपयोग करने के लिये आर्थिक क्षेत्र में लोक-तन्त्र की स्थापना की आवश्यकता का पूर्ण समर्थन करना, आदि । ❊

पाठ्य-ग्रन्थ

- 1 Beer, M , A History of British Socialism , Vol II Chapter XVIII, Rise of Guild Socialism
- 2 कोकर, फ्रान्सिस , आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, अध्याय 9, गिल्ड समाजवाद
- 3 Cole, G D H , Guild Socialism, 1920.
- 4 Gray, Alexander , The Socialist Tradition, Chapter XVI, Guild Socialism
- 5 जोड, मी ई एम , आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका अध्याय 4, शिल्पी सघवाद और श्रेणी सघवाद
- 6 MacDonald, R , Socialism Critical and Constructive, Chapter III, Socialism Its Organisation and Idea
7. Pelling, Henry, (Ed.) , The Challenge of Socialism, Chapter 14, Guild Socialism.

³² कोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 300

साम्यवाद

लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, माओ त्से-तुंग आदि

साम्यवाद का कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसका अर्थ समाज के ऐसे मिद्धान्त के रूप में लिया जाता है जिसमें सम्पत्ति पर सबका समान अधिकार हो। अन्य स्थलों पर साम्यवाद का प्रयोग समाजवाद के पर्याय के रूप में किया जाता है।¹ प्रायः लोग मार्क्सवाद और साम्यवाद को एक ही मिद्धान्त समझ लेते हैं, जो सही नहीं है। हालाँकि मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता माना जाता है, मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों ही साम्यवाद में भिन्न हैं।

साम्यवाद, मार्क्सवाद से प्रयुक्त होने हुए भी अभिन्न है। साम्यवाद मुख्यतः कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है। आगे चलकर मार्क्स के अनुयायियों ने मार्क्सवाद को जो सिद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूप प्रदान किया, इन्हीं ही हम साम्यवाद कहते हैं। अन्य स्थलों में, साम्यवाद का आधार मार्क्सवाद है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रत्येक साम्यवादी मार्क्सवादी तो होता ही है। किन्तु साम्यवाद विद्युत् मार्क्सवाद नहीं है। मार्क्स के सिद्धान्तों के आधार पर रूस में 1917 की क्रांति का संगठन किया गया। व्यावहारिक आवश्यकताओं के कारण रूसी क्रांति के नेता लेनिन (Lenin, 1870-1924) ने मार्क्स के सिद्धान्तों में कुछ परिवर्धन किये और नये तत्वों को जोड़ा। लेनिन द्वारा प्रतिपादित मार्क्सवाद ही साम्यवाद है। या, हम यह कह सकते हैं कि "साम्यवाद वह मार्क्सवाद है जिसका निर्द्वन्द्व और परिवर्धन लेनिन ने किया।" या, लेनिनवाद (Leninism) जो मार्क्सवाद का सशोधित एवं श्रियात्मक रूप है साम्यवाद कहलाता है।² लेनिनवाद साम्यवाद का प्रथम चरण है।

साम्यवाद लेनिन के विचारों तक ही सीमित नहीं रहा। लेनिन के पश्चात् यह माना जाता है कि स्टालिन (Joseph Stalin, 1879-1953) ने साम्यवाद का सर्जनात्मक विकास किया। लेनिन का भाति स्टालिन भी मृत्युपर्यन्त रूसी साम्यवादी व्यवस्था का प्रमुख नेता तथा दार्शनिक बना रहा। स्टालिनवाद साम्यवादी विचारधारा परिवर्धन में दूसरा चरण है।

1. जोड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ. 91-92.

2. रूस की क्रांति (1917) के समय लेनिनवाद बोल्शेविज्म (Bolshevism) के नाम से जाना जाता था।

सामान्यतः यही माना जाता है कि साम्यवाद का महत्वपूर्ण विक्रम स्टालिन तक ही हुआ है। या, मूकम म 'माम्मवाद-लेनिनवाद-स्टालिनवाद' ही साम्यवाद है। इनके विभिन्न विद्वाना न साम्यवाद को परिभाषा देने हुए साम्यवाद के स्टालिन तक के ही विकास की व्याप्त न रखा है। साम्यवाद को परिभाषित करने हुए गेटेल (R G Gettell) ने लिखा है कि—

'साम्यवाद मानव विकास के विषये भौतिकवादी सिद्धान्त पर आधारित एक इतिहास का दर्शन है जिसका प्रारम्भ बाले माकर्म और फ्रेड्रिक एन्जिल्स न हुआ। इनको लेनिन तथा स्टालिन मज्जित, एन नई विचारधारा के संभवता न रूप न सम्मानित किया जाता है जिनका आधुनिक प्रेम नहीं किन्तु वग-मर्षण और विद्रोह का सिद्धान्त है।'³

जाड (C E M Joad) ने साम्यवाद को एक आन्ति-पद्धति क रूप न समझने का प्रयत्न किया है। उन्हीं के शब्दों म—

'साम्यवाद मूलतः एक पद्धति का दर्शन है। यह उन सैद्धान्तिक तर्कों का निरूपण करता है जिनके आधार पर पूँजीवादी समाज का समा-जवादी समाज न परिवर्तित किया जायेगा। हमारे दो मूलतन्त्र हैं-वगजुद तथा आन्ति द्वारा अर्थात् वद प्रयोग द्वारा मर्षण वग को जति न सम्मानरण।'⁴

यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि जाड के समस्त साम्यवादी राज्य स्वयं को समाजवादी घोषित करते हैं। वास्तव म इन साम्यवादी राज्यों का समाजवाद ही साम्यवाद है। माकर्म न सर्वहारा-अधिकायतक के युग को समाजवादी युग कहा या। साम्यवादी राज्य इसी युग में चल रहे हैं। हमारे जय साम्यवादी अपने विषय समाजवादी कहते हैं ता हम घम में नहीं पड जाता चाहिए। रूस, चीन, पूर्वी यूरोप न राज्य, उत्तरी जियरमन, क्यूबा आदि की समाजवादी व्यवस्था ही साम्यवाद हैं। कुत्र लेउकन ने साम्यवाद को समाजवाद का उग्र, आन्तिकारी एव अतिताक-वादी स्वल्प माना है।

उपरोक्त परिभाषायो एक विद्वानों के विचारों के विवेकन में साम्यवाद को अधिक स्पष्ट करने हेतु निम्नलिखित तर्क पुन प्रस्तुत किये गये हैं—

प्रथम, साम्यवाद का आधार एक मात्र माकर्मवाद है, जिसमें फ्रेड्रिक एन्जिल्स के विचार भी सम्मिलित हैं। समा साम्यवादी माकर्मवाद न निम्नलिखित आधार-भूत सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं जैसे—

(1) इन्द्रात्मक भौतिकवाद एक इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।

3 Wantass, Lawrence C, Gettell's History of Political Thought, p 359

4 जाड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेगिता पृ 92

- (ii) पूँजीवादी-व्यवस्था के दोष तथा इसका अवश्यम्भावी पतन ।
- (iii) वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त ।
- (iv) श्रमिक क्रान्ति ।
- (v) सर्वहारा अधिनायकत्व ।
- (vi) वर्ग-रहित, राज्य-रहित, शोषण - विहीन साम्यवादी समाज की स्थापना ।⁵

द्वितीय, रूस में साम्यवादी क्रान्ति के समय तथा बाद में जब मार्क्सवाद का प्रयोग किया गया तब नवीन परिस्थितियों के सम्बन्ध में क्रान्ति के नेता लेनिन ने इसमें कुछ संशोधन किये जिसे लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है । यह साम्यवाद का सबसे प्रथम महत्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष है ।

तृतीय, साम्यवाद के विषय में स्टालिन के विचार तब ही माघारणत साम्यवाद की व्याख्याएँ सीमित रहती हैं । किन्तु स्टालिन के बाद साम्यवादी विचारधारा में कुछ और परिवर्धन हुआ है । रूस में ही निकिता ख्रुश्चेव (Nikita Khrushchev) ने साम्यवाद की आधुनिक समीक्षा की । चीन में साम्यवादी क्रान्ति के नेता माओ त्से-तुंग (Mao Tse-tung) ने साम्यवाद की वृहद् व्याख्या की है जिसे माओवाद (Maoism) कहते हैं । विश्व के और कई साम्यवादी नेताओं ने भी टीका-टिप्पणियाँ की हैं, जिनमें युगोस्लाविया के मार्शल टीटो (Marshal Tito), उत्तर कोरिया के किम इल सुंग (Kim Il Sung), उत्तर वित्रतनाम के जनरल जिपेप (General Giap) आदि प्रमुख हैं । इन सभी के विचारों में साम्यवाद के सिद्धान्तिक या व्यावहारिक पक्ष को प्रभावित किया है । इसके अलावा कई राज्यों में साम्यवादी प्रणाली की स्थापना हो चुकी है, जिनमें रूस और चीन प्रमुख हैं । इन राज्यों में साम्यवाद को जो व्यावहारिक रूप दिया गया, नई संस्थाओं की स्थापना की गयी, उनसे साम्यवाद के कुछ और तत्व स्पष्ट होते हैं जैसे साम्यवादी दल को महत्ता, व्यक्ति-पूजा, साम्यवाद की विस्तारवादी प्रकृति आदि । इन सभी को साम्यवाद के अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित करते हैं ।

लेनिनवाद (Leninism)

लेनिन (Vladimir Ilyitch Ulanov,⁶ 1870-1924) रूस में साम्यवादी क्रान्ति के प्रमुख नेता थे । वे एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए थे । लेनिन के पिता सरकारी स्कूलों के निरीक्षक थे तथा उन्हें अपनी सरकारी सेवाओं के लिए पुरस्कार-स्वरूप कुलीनता (nobility) का अलंकरण प्राप्त हुआ था । लेकिन इनका परिवार क्रान्तिकारी विचारों एवं गतिविधियों से मुक्त नहीं था । 1886 में लेनिन के ज्येष्ठ भ्राता को जार एलेग्जेंडर तृतीय की हत्या के पड्यन्त्र में मृत्यु दण्ड दिया गया था ।

5. मार्क्सवाद के पूर्ण विवरण के लिये अध्याय 'मार्क्सवाद' देखिये ।

विद्यार्थी जीवन से स्वयं लेनिन का मुकाबल श्रान्तिकारी गतिविधियों का शोर था। नेत्र पीटसवग विश्वविद्यालय से विधि स्नातक बनने के उपरांत भी उनकी रचि-रामिकों को संपादित करने की था। 1890 में वे श्रान्तिकारी आन्दोलन में सम्मिलित हो गये। 1897 में इन्हें मास्को में निष्कासित किया गया। साख्वेरिया में उन्हें लेना (Lena) नाम का स्थान पर रखा गया। उस स्थान के नाम पर इन्होंने अपना नाम लतित रखवा। 1900 में इन्होंने रूस छोड़ा। माक्स तथा एन्गल्स के विचारों का अध्ययन करने के लिये अनेक वर्ष विदेशों में गिरे। प्रथम विश्व युद्ध में इन्हें आस्ट्रिया में बनी बंदी बन जा गया। तब से रूस वापस आने के लिये 1917 में तबत सरकार के सहयोग से वे रूस वापस आये और साम्यवादी श्रान्ति का नेतृत्व किया। रूसी श्रान्ति से तबत मृत्यु पर्यन्त (1924 तक) के रूस में सावियत दल का सर्वप्रथम नेता ही नहीं अपितु माक्सवाद-साम्यवाद के प्रमुख एवं अग्रणीय प्रवक्ता भी रहे। उस प्रकार लेनिन सिद्धांतवादी और कमाल दाली हैं।

लेनिन ने अपने विचारों को कई ग्रन्थों में प्रस्तुत किया है किन्तु इनमें निम्नलिखित अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं—

- 1 What Is to Be Done 1902
- 2 Imperialism The Highest Stage of Capitalism 1916
- 3 State and Revolution 1917
- 4 The Immediate Task of the Soviet Government 1918
- 5 The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky 1918

अपने सक्षिप्त सद्भाविक लेखों एवं पुस्तकों में लेनिन ने बड़े तार्किक ढंग से साम्यवाद सिद्धान्तों का विवेचन किया है। लेनिन को श्रान्तिवादी कहा जाता है।

माक्सवाद और लेनिन

लेनिन माक्सवाद के परम अनुयायी थे। वे माक्सवाद में निश्चय भी श्रान्ति का सहायक नहीं चाहते थे। ऐसे सयोगवादी तबत एडुवार्ड बेर्नस्टान (Eduard Bernstein) तथा कथित माक्सवादी कार्ल काउत्स्की (Karl Kautsky) श्रान्ति से उर्ध्व घृणा थे। किन्तु तबत एम व्यक्तिगत माक्सवाद में श्रान्ति का निष्पत्ति किया था उर्ध्व नये विवेचन के साथ प्रस्तुत किया तबत लेनिन ने रूस का विरोध किया। तबत प्रत्युत्तर में लेनिन ने जो कुछ व्यक्त किया वे वे श्रान्तिवादी श्रान्तिवादी हैं।

लेनिनवादी माक्सवाद की पुनरावृत्ति पुनर्श्रान्ति श्रान्ति और परिवर्धन सब कुछ था। लेनिन प्रबल माक्सवादी थे। लेनिन द्वारा माक्सवाद का श्रान्ति श्रान्ति मध्यम दाली पर ले स्पष्ट होता है। प्रथम लेनिन में रूस तथा एन्गल्स के श्रान्तिवादी श्रान्ति की श्रान्ति स भग हुआ सम्भव थे। वे माक्स के गभीर विवेचना को बल वाचक मानते थे और

तदनुसार उनकी व्याख्या करते थे। द्वितीय, लेनिन ने मार्क्सवाद की रक्षा इस प्रकार की जैसे कट्टर धर्मवितान्धी अपने धर्म की करता है। अपने विरोधियों के ऊपर उनका सबसे बड़ा आक्षेप यह रहता था कि वे मार्क्सवाद के धर्म में अपमिश्रण करते हैं। मार्क्सवाद का पूर्ण अनुमोदन करते हुए लेनिन ने कहा था—

“मार्क्सवाद का दर्शन फौलाद के एक टोस पिन्ड की तरह है। आप इसमें से एक भी मूलभूत धारणा, एक भी सारभूत अंश नहीं निकाल सकते। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप वस्तु सत्य को त्याग देते हैं, आप पूंजीवादी-प्रतिनिधियोंवादी भूठ के हाथों में पड़ जाते हैं।”⁷

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद तथा वर्ग-सघर्ष को लेनिन मार्क्सवाद की अन्तरात्मा मानते थे। “लेनिन की धारणा के अनुसार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसी सार्वभौम पद्धति बन गया जो विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में लागू हो सकती थी और सही पथ-प्रदर्शन कर सकती थी। इस दृष्टिकोण ने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को एक उच्चतर ज्ञान, एक प्रकार का धर्मशास्त्र बना दिया जो समस्त विज्ञानों के गहनतम प्रश्नों का निर्णय कर सकता था।”⁸

वर्ग-सघर्ष के विषय में भी लेनिन का ऐसा ही दृष्टिकोण था। लेनिन के अनुसार जैसा कि सेबाइन ने लिखा है, “वर्ग सघर्ष एक परम सिद्धान्त है। यह अस्थायी रूप से धूमिल पड़ सकता है, लेकिन उसे कभी हटाया नहीं जा सकता। वर्ग-सघर्ष का शाश्वत तत्त्व द्वन्द्वात्मक पद्धति का अनिवार्य परिणाम है।”⁹

लेनिन मार्क्सवादी होने के साथ-साथ यथार्थवादी भी थे। वे मार्क्स के सिद्धान्तों को सर्वकालीन सत्य मानने के साथ साथ उसे विकासशील भी स्वीकार करते थे। मार्क्स ने अपने विचार उस युग में प्रस्तुत किये जब पूंजीवाद का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। सर्वहारा वर्ग भी क्रान्ति के लिए सजल तथा संगठित नहीं था। लेनिन ने अपने विचार उक्त समय प्रकट किये जब पूंजीवाद का पूर्ण विकास हो चुका था तथा रूस में सर्वहारा क्रान्ति हो चुकी थी। इसलिए दोनों के विचारों में मौलिक एकरा होने हुए भी उनमें भेद होना स्वाभाविक था। उपयोगितावाद के विषय में जो अन्तर केन्पम और जॉन स्टुअर्ट मिल में था, साम्यवाद के विषय में वही मार्क्स और लेनिन के विषय में कहा जा सकता है।

कार्ल मार्क्स ने सिर्फ मंडान्तिक आधार ही प्रस्तुत किये थे। उन्हें किसी क्रान्ति का नेतृत्व कर साम्यवादी शासन की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका था। यदि मार्क्स को यह अवसर प्राप्त होता तो नवीन परिस्थितियों के

7. सेबाइन, राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृ. 763.

8. उपयुक्त., पृ. 766.

9. उपयुक्त., पृ. 767.

सन्दर्भ में अपने विचारों में अग्रगण्य ही कुछ परिवर्तन करते। लेकिन वो यह अग्रगण्य प्राप्त हुआ। उन्होंने रूसी क्रान्ति का नेतृत्व किया और विश्व में सर्वप्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने मार्क्सवाद का प्रयोग रूसी परिस्थितियों में बहुत ही बुद्धिमत्ता से किया, यद्यपि कुछ विशेष बातों में मार्क्सवाद में समीप भी करना पड़ा।¹⁰ रूसी बोल्शेविक (Bolsheviks) के प्रभाव के कारण, जोड़ के शब्दों में, साम्यवाद विशिष्ट पद्धति का दर्शन (Philosophy of method) बन गया, अर्थात् यह उस नामधर का सिद्धान्त बन गया जिसके अनुसार पूँजीवाद से समाजवाद की ओर निम्न प्रकार परिवर्तन होगा।¹¹ इस सन्दर्भ में लेनिनवाद को नवीन मार्क्सवाद (New form of Marxism) तथा रूसी साम्यवाद को सोवियत मार्क्सवाद (Soviet Marxism) भी कहा जाता है।

रूस में क्रान्ति के बाद लेनिन के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण समस्या साम्यवादी शासन के अस्तित्व को बनाये रखने के अलावा उसे संगठित तथा सफल बनाने की थी। उस समय रूस की अन्तरिक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में लेनिन को कुछ दाव-पेच खेलने पड़े, तथा चाले चलनी पड़ी। इन्हीं बातों से लेनिन रूस में पूँजीवादियों के समर्थकों तथा यूरोपीय राज्यों के बाह्य हस्तक्षेप का मुकाबला कर सके। वे दाव-पेच और चाले (tactics) मार्क्सवादी विचारधारा का भाग है। इस सम्बन्ध में स्टालिन के विचार भी उल्लेखनीय हैं —

“लेनिनवाद साम्राज्यवाद तथा सर्वहारा शांति के युग का मार्क्सवाद है। अधिक सही अर्थ में लेनिनवाद सामान्य तौर पर सर्वहारा की क्रान्ति का सिद्धान्त और सामरिक चाल तथा विशिष्ट रूप से सर्वहारा अधिनायकत्व का सिद्धान्त और चाल (tactics) है।¹²”

लेनिन के नेतृत्व में अनेक विशेषताएँ थीं। उनमें बटोरता और नम्यता का अपूर्व समन्वय था। वे अक्सर से सुरन्त लाभ उठा सकते थे, वे मोर्चा बदल सकते थे। लेकिन उनका मोर्चा बदलना युक्तिसंगत अगला कदम भासूम पड़ता था। लेनिन ने क्रान्तिविद्या को एक सिद्धान्त का रूप दिया।¹³ इस विद्या के अन्तर्गत विद्रोह को एक बला कहा गया। उन्होंने पेशेवर क्रान्तिकारियों के संगठन तथा चाला के बड़े सुभाव दिए।

लेनिन की क्रान्ति विद्या या चालों का एक अन्य प्रमुख सिद्धान्त पक्ष 'समझौते का सिद्धान्त' (Theory of Compromise) है। लेनिन का कहना था कि परिस्थितियोंवाश क्रान्तिकारियों को समझौते के लिये या अन्य विकल्पों के लिये भी

10 ग्रामीवादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय भाग पृ 629

11 जाड, अधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ 90.

12 Stalin, J V, Foundation of Leninism, Little Stalin Library, Moscow, p. 10

13 सेवार्डन, राजनीति दर्शन का इतिहास पृ 745,
Gray, A, The Socialist Tradition, pp 480-81.

तैयार रहना चाहिये। लेनिन ने इस समझौते गिद्दान्त के कुछ पक्ष दिये हैं। प्रथम, साम्यवादियों को श्रम संगठनों में प्रवेश कर उनका अपने हित में प्रयोग करना चाहिये। द्वितीय, साम्यवादी गिद्दान्तों के अन्तर्गत संगदीय प्रणाली को चाहे कुछ भी आलोचना की गई हो साम्यवादियों को चुनावों में भाग लेकर संगद में प्रवेश करना चाहिये। ससद के अन्दर फिर उन्हें अपने हित को देखते हुए कार्य करना चाहिये। तृतीय, परिस्थितियोंद्वारा साम्यवादियों द्वारा दूरसे राजनीतिक दलों में भी मध्यस्थन करना चाहिये। किन्तु ऐसे दलों या तयारकथित मित्रों पर दौरे ही बड़ी गजर रखनी चाहिये जैसे कि एक जगह पर।¹⁴

इन चालों या साम्यवादी प्रत्येक देश में आज तक गुप्त प्रयोग करते हैं। जब कभी भी साम्यवादी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए साम्यवादी गिद्दान्तों पर आघात होती है तो वे इसे सामयिक व्यवस्था कहकर एक चाल बतलाते हैं। वास्तव में आज साम्यवाद चाल-सिद्धान्त (doctrine of tactics) ही अधिक है। हर्बर्ट मार्क्यूज (Herbert Marcuse) के शब्दों में—

‘सोवियत मार्क्सवाद (लेनिनवाद, स्टाकिनवाद तथा उमकेवाद) रूस की नीतियों की सही एवं विवेकपूर्ण बतलाने के लिए कमिनिन द्वारा घोषित विचारधारा ही नहीं है किन्तु यह रूस की साम्यवादी नीतियों को बड़े प्रकार से धुँस कर रहा है।’¹⁵

एलेग्जेंडर ग्रे (Alexandra Gray) ने लेनिन को राजनीतिक चालों तथा राजनीतिक रणनीति का गुप्त बतलाया है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेनिन रणनीति में नीतिगत नीति केवल के भी मुक्त थे। इस पक्ष में वे गतिविधियों के अधिन निरत थे।¹⁶ साम्यवाद के लिए लेनिन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक चालों के रूप में ही है।

साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अन्तिम अवस्था (Imperialism : the Last Stage of Capitalism)

मार्ग पूंजीवाद या विरोधी था। किन्तु लेनिन पूंजीवाद का मार्ग में भी अधिक महत्त्व धारण करता था। वास्तव में पूंजीवाद-साम्राज्यवाद विचार को पूंजीवाद से लेनिन ने ही विरहित किया। इसके साथ ही उगमे संशोधनवादियों की आलोचना का भी करारा उत्तर दिया।

लेनिन ने प्राचीन और मध्यकालीन साम्राज्यवाद तथा आधुनिक साम्राज्यवाद में अन्तर स्पष्ट किया है। प्राचीन तथा मध्यकालीन साम्राज्यवाद साम्राज्यों की विजय

14 Gray, A., *The Socialist Tradition*, pp 430-31
 15 Marcuse, Herbert., *Soviet Marxism—A Critical Analysis*, Routledge and Kegan Paul, London, 1958, p. 1.
 16 Gray, Alexander., *The Socialist Tradition*, p. 461.

आकांक्षारों का व्यावहारिक रूप था। साम्यवादी समाजवाद मुख्यतः आर्थिक है। समाजवादियों ने एडुअर्ड बर्नस्टोन ने मार्क्सवाद की आलोचना करते हुए कहा था कि मार्क्स को यह भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं हुई कि पूँजीवाद की वृद्धि से मजदूरों की दशा और अधिक शोचनीय होगी। न पूँजीवादियों की संख्या में कमी हुई है और न उनका पतन ही निकट है। समाजवादियों का उत्तर देने हुए लेनिन ने कहा कि पूँजीवाद अपनी चरम अवस्था साम्यवाद में पहुँच चुका है। लेनिन ने विनपन इसका विवेचन अपनी पुस्तक—*Imperialism The Highest Stage of Capitalism*—में की है। लेनिन ने ही शब्दा म—

साम्यवाद पूँजीवादी विकास का वह चरण है जिसमें एकाधिकार और वित्तीय पूँजी का प्रभुत्व अपना आकार स्थापित कर चुका है, जिसमें पूँजी-निर्माण महत्ता प्राप्त कर चुकी है, जिसमें विश्व का विभाजन अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्ट (International trusts) में प्रारम्भ हो चुका है, जिसमें विश्व की समस्त भूमि का विभाजन पूँजीवादी महासाम्राज्यों के मध्य पूर्ण हो चुका है।¹⁷

इस सिद्धान्त के द्वारा लेनिन ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि साम्यवाद पूँजीवादी विकास और प्रगति का स्वाभाविक परिणाम है। लेनिन पूँजीवाद साम्यवाद में परिणत एक विशेष और उच्च स्तर की प्राप्ति का वाद ही होता है। साम्यवाद किस प्रकार पूँजीवाद की उच्चतम व्यवस्था या शिखर है लेनिन ने इसे पूँजीवाद से साम्यवाद तक की प्रगति एवं प्रक्रिया के माध्यम से स्पष्ट किया है। लेनिन के इस सिद्धान्त को निम्नलिखित ढंग में प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. पूँजीवाद की मूल प्रवृत्ति—पूँजीवादी व्यवस्था स्वतन्त्र स्पर्धा पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्वतन्त्र स्पर्धा पूँजीवाद का कोई आधारभूत सिद्धान्त या साध्य है। पूँजीवादी विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस व्यवस्था में स्वतन्त्र स्पर्धा और पूँजीवाद का सामान्य स्वरूप दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि स्वतन्त्र स्पर्धा में एकाधिकार की प्रवृत्ति होती है। स्पर्धा में औद्योगिक इकाइयाँ अपना आकार बढ़ाती हैं, छोटे छोटे पूँजीपति समाप्त हो जाते हैं और केवल दानव प्रकृति वाले पूँजीपति ही अपना अस्तित्व बनाय रख सकते हैं। इस प्रकार पूँजीवाद एकाधिकारवादी व्यवस्था में प्रवेश करता है।

17 "Imperialism is capitalism in that stage of development in which the domination of monopolies and finance capital has taken shape, in which the export of capital has acquired pronounced importance, in which the division of the world by the international trusts has begun and in which the partition of all the territory of the earth by the greatest capitalist countries has been completed."

2. एकाधिकार—एकाधिकार पूँजीवादी व्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंगला चरण है। साम्य में पूँजीवाद के अन्तर्गत स्वतन्त्र स्पर्धा और एकाधिकार परस्पर-निरोधी होते हुए भी एकाधिकार अवश्यम्भावो है। राष्ट्र की छोटी-छोटी आर्थिक इकाया समाप्त हो जाती है। एकाधिकार सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था पर छा जाता है। एकाधिकारवादी चरण में पूँजी व उत्पादन एक अत्यन्त ही छोटे मनुष्य में केन्द्रित एवं संचित हो जाता है। इन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विकास उद्योगपति और वैरुपतियों के समुक्तोकरण से विकृत वित्तिय कुलीनत्व (Financial Oligarchy) जैसी व्यवस्था की स्थापना होती है। औद्योगिक संसार के निर्माण के साथ साथ उत्पादन के ऊपर उत्पादकों का नियन्त्रण उनके हाथों में निम्न कर थोड़े में दानव वित्त-धारियों के हाथों में चला जाता है।

पूँजीवाद से साम्राज्यवाद तक बढ़ने की प्रक्रिया में एकाधिकार वाली व्यवस्था को लेनिन बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। वे एकाधिकार को ही साम्राज्यवाद जैसा समझते हैं। इसी सन्दर्भ में लेनिन ने साम्राज्य की परिभाषा करते हुए लिखा है—

“यदि साम्राज्यवाद की कोई सूक्ष्म परिभाषा देने की आवश्यकता है तो हमें कतना चाहिए कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद की एकाधिकार वाली व्यवस्था है।”¹⁸

3. पूँजी निर्घात—लेनिन के अनुसार पूँजीवाद राष्ट्रीय सीमाओं के अन्तर्गत बन्ध कर नहीं रह सकता। इसमें विस्तारवादी प्रवृत्ति होती है। जब बाजार विस्तार-व्यापी हो जाता है एकाधिकारवादी संस्थाएँ अपने आर्थिक हितों में अभिवृद्धि के लिये पिछड़े हुए देशों को और दृष्टि डालती हैं। पिछड़े एवं अविश्रान्त राज्यों में पूँजीवादी राज्य कच्चा मान प्राप्त करते हैं तथा उनमें अपनी पूँजी लगाते हैं। यह व्यवस्था उपनिवेशवाद की ओर अग्रसर करती है।

4. एकाधिकारवादियों के मध्य स्पर्धा—संसार के उन्नततम राष्ट्रों के एकाधिकारों के मध्य अविश्रान्त तथा पिछड़े हुए देशों पर अधिकार करने की होड़ लग जाती है। अद्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह हो जाता है कि बांग्ला के बांग्ला प्रदेशों तथा जनसत्ता का किस प्रकार विभाजन किया जाय। लेनिन 1914 के विश्वयुद्ध का उदाहरण देकर कहते हैं कि यह युद्ध जर्मन पूँजीपतियों के मिन्डीकेटों तथा इंग्लैंड एवं फ्रांस के मिन्डीकेटों के बीच अफ्रीका के नियन्त्रण के लिए मध्य था। लेनिन ऐसे और भी कई उदाहरण देते हैं।

लेनिन का कहना है कि इस स्थिति में विश्व के पूँजी एकाधिकारवादी मिलकर विश्व के आर्थिक हितों को स्वयं में विभाजित कर लेते हैं। तदुपरान्त विश्व के पूँजीपति सम्पूर्ण विश्व का स्वयं में क्षेत्रीय विभाजन कर लेते हैं। इस प्रकार “एकाधिकार और वित्त पूँजीवाद स्वतन्त्र प्रतिपोगितापूर्ण पूँजीवाद का स्वाभाविक

18. Quoted, Anjerson, T., Masters of Russian Marxism, p. 73.

परिणाम है। राजनीति साम्राज्यवाद एकाधिराज पूँजीवाद का स्वाभाविक परिणाम है और युद्ध पूँजीवाद का स्वाभाविक परिणाम है। साम्राज्यवाद पूँजीवादी विकास की उच्चतम व्यवस्था है।" 19

साम्राज्यवादी युद्ध—लेनिन युद्ध को पूँजीवाद के विकास का एक आवश्यक चरण मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का विवेचन करते हुए लेनिन ने कहा था कि यह युद्ध जर्मन पूँजीपतिशाली व सिन्टीकेटा तथा इंग्लैंड और फ्रांस के मिन्डीकेटों के बीच अफ्रीका के नियंत्रण के लिए भयंकर था। कुस्तुनतुनिया के प्रति हमी पूँजीवादी (जान्ति के पूर्व) और चीन के प्रति जापान के दृष्टिकोण को इसी सन्दर्भ में समझा जा सकता है।

साम्राज्यवादी युद्ध में जिसका विजय दोष है, लेनिन के अनुसार यह सोचना व्यर्थ है। सभी पूँजीवादी राष्ट्र आर्थिक स्वार्थों से प्रेरित रहते हैं। वे सभी लुटते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का सर्वहाग ज्ञानि के दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण करते हुए लेनिन साम्राज्यवादी युद्ध को गृहयुद्ध और सर्वहारावर्ग की ज्ञानि के रूप में वर्णन की आशा रखते थे। उनका विश्वास था कि इस प्रकार की ज्ञानि सम्पूर्ण विश्व में होने वाली है।

एक देश में समाजवाद (Socialism in one state)

मार्क्सवाद अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है जो विश्व के श्रमिकों की एकता और ज्ञानि के लिए आह्वान करती है। लेनिन ने इन बातों को स्वीकार किया है, किन्तु मार्क्सवाद के प्रारम्भिक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की एक राष्ट्रीय व्याख्या करके उसका शोषण किया। लेनिन ने "एक देश में समाजवाद" के सिद्धान्त को जन्म दिया। "उनका कहना था कि जैसे पूँजीवाद अपने उदयान में समार के विभिन्न भागों में एक साथ नहीं रहा, ठीक उसी तरह समाजवाद का विस्तार भी सब जगह एक समान नहीं होगा। एक ही प्रयत्न में समार में साम्यवाद जैसी कोई चीज स्थापित नहीं हो सकती। उसका प्रसार असमान और असम्बद्ध रूप में ही होगा। लेनिन का विश्वास था कि पूँजीवाद के नागर के बीच इस रूपी एक समाजवादी द्वीप सारे समार के सर्वहाग वर्ग के ज्ञानिकारी आन्दोलन के लिए एक प्रकाश पुञ्ज का काम करेगा।" 20

'एक देश में समाजवाद' के समर्थक होने के साथ साथ लेनिन का उत्साह अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विषय में भी बना रहा। उनके प्रयत्नों से मार्च 1919 में 'तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय' (Third International) की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य समार के मजदूरों को एक सूत्र में बाधना और पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना था।

19 सेवान, राजनीति दर्शन का इतिहास, पृ० 771

क्रान्ति के लिए उपयुक्त सामाजिक अवस्था

मावर्स के अनुसार क्रान्ति सर्वप्रथम उन देशों में होगी जो औद्योगिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़े हों तथा जहाँ पूँजीवाद का पूर्ण विकास हो चुका हो। पूँजीवाद का सामंतिप्रतिक परस्पर-विरोध प्राप्ति की ओर अग्रसर करेगा। रूस की प्राप्ति के संदर्भ में लेनिन मावर्स की इस धारणा से सहमत नहीं थे। लेनिन के अनुसार मावर्स ने क्रान्ति के लिए प्रत्येक देश में पूँजीवाद की आवश्यकता को अलग अलग ध्यान। जब पूँजीवाद विश्वव्यापी बन गया है, इसलिए जहाँ भी पूँजीवाद निर्यात हो, शासक वर्ग की कमजोर स्थिति हो, अधिकतर जनता क्रान्तिकारियों का साथ देने को तैयार हो, वहीं पर सामाजिक क्रान्ति हो सकती है। लेनिन ने कहा कि किसी भी देश में पूँजीवाद के पूर्ण विकास की प्रतीक्षा अनावश्यक है। क्रान्ति किसी भी विद्युत् द्रव्य देश में हो सकती है।

कृषक वर्ग की साम्यवादी प्रवृत्ति

मावर्स साम्यवादी क्रान्ति के लिए औद्योगिक राजदूतों को अधिक उपयुक्त और उपयुक्त समझते थे। सर्वहारा वर्ग के पास अपना मुद्दा नहीं होता तथा प्रत्येक समय क्रान्ति व विद्रोह के लिए तैयार रह सकता है। लेनिन इस बात से सहमत तो था किन्तु उतने किसानों के योगदान को भी स्वीकार किया। रूसी क्रान्ति में लेनिन को कृषक वर्ग से बहुत सहायता मिली थी। परिणामस्वरूप लेनिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक अधिक ही नहीं किन्तु कृषक वर्ग भी साम्यवादी क्रान्ति में सहायक होता है।

सर्वहारा-अधिनायकत्व बनाम साम्यवादी दल अधिनायकत्व

मावर्स के अनुसार क्रान्ति के पश्चात् सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होगा जो साम्यवादी अवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। लेनिन ने इसका खण्डन नहीं किया किन्तु रूस में क्रान्ति के बाद जिग सर्वहारा वर्ग की सान्नाशाही की स्थापना हुई यह धारणा में साम्यवादी दल की सान्नाशाही थी। लेनिन के अनुसार साम्यवादी दल ही सर्वहारा वर्ग का मार्ग निर्देशन करेगा। रूसी के शब्दों में—

सर्वहारा-अधिनायकत्व परस्पर में आवश्यकताानुसार साम्यवादी दल का अधिनायकत्व हो गया क्योंकि प्रत्येक मातृत्वपूर्ण कार्य के लिये साम्यवादी दल समय-समय से अभिन्न है। साम्यवादी दल का अधिनायकत्व भी उस दल के समस्त सदस्यों का अधिनायकत्व नहीं है।¹

1. "The dictatorship of the proletariat, in fact became necessarily the dictatorship of the communist party, for every serious purpose, the party has been identical with the apparatus of the state. But the dictatorship of the party has not meant the dictatorship of the rank and file." Laski, H. J., Reflection on the Revolution of our Time, p. 57.

अन्य शब्दों में, माक्स के सर्वहारा अधिनायकत्व के स्थान पर लेनिन ने साम्यवादी दल के अधिनायकत्व की स्थापना की, जो व्यवहार में कुछ ही नेताओं की तानाशाही में परिवर्तित हो गया।

साम्यवादी दल

माक्स तथा लेनिन में सभ्ये महत्त्वपूर्ण विचार भेद सर्वहारावर्ग की भूमिका के विषय में था। माक्स तथा ऐन्ज़लस ने साम्यवादी भ्रान्ति के लिये दल के सगठन की ओर अधिनायकत्व नहीं दिया। उनका विचार था कि पूँजीवाद परिस्थितियों तथा शोषण ने परेशान होकर श्रमिक वर्ग में वर्ग चेतना पैदा होगी और सर्वहारा वर्ग स्वयं ही भ्रान्ति की ओर अग्रसर होगा। लेनिन ने पार्टी को अधिनायकत्व दिया। लेनिन यह मानने के लिये तैयार नहीं थे कि श्रमिकों में इतनी चेतना स्वयं उत्पन्न हो सकती है कि वे संगठित होकर सरकार तथा पूँजीपतियों से लोहा ले सकें। समाजवादी भ्रान्ति के लिये लेनिन ने सर्वहारा आन्दोलन का कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया। लेनिन ने सेन्ट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों का काफी अवलोकन एवं अध्ययन किया था। यहाँ श्रमिकों का गतिविधियाँ में भाग लेने के बाद लेनिन का निष्कर्ष था कि किसी फौजदारी में कार्य करने से श्रमिक अपने आप में समाजवादी नहीं बन जाते। सर्वहारा या श्रमिक आन्दोलन, लेनिन के अनुसार, टूट यूनिजन इष्टिओण बनना लेंगे हैं। उनका उद्देश्य अर्थवाद तक ही सीमित होकर रह जाता है। सर्वहारावर्ग समाजवादी चेतना तथा वर्ग संघर्ष के लिये तब तक सक्षम नहीं हो सकता जब तक समाजवाद और वर्ग-संघर्ष चेतना उनमें नहीं भरती जाय। समाजवादी भ्रान्ति के लिये सर्वहारा वर्ग को संगठित करने, उनमें भ्रान्ति भावना का विकास करने का कार्य केवल साम्यवादी दल ही कर सकता है। इस प्रकार साम्यवादी दल ही भूमिका का जिसकी ओर माक्स तथा ऐन्ज़लस ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेनिन के विचारों में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेनिन ने साम्यवादी दल को 'भ्रान्ति का अग्रणी' बनाया।

लेनिन ने जर्मनी की भ्रान्ति की बागडोर अपने हाथों में ली वह इस भ्रान्ति को दो आधारों पर रखना चाहता था। प्रथम, मानसवादी सिद्धान्तों के आधार पर आदर्श व्यवस्था द्वितीय, भ्रान्तिकारों समूह का कठोर अनुशासन और सगठन। 1902 में भ्रान्ति के लिये दल सगठन के विषय में लेनिन ने लिखा था—

"एक छोटा सुगठित गुट, जिसमें विश्वसनीय, अनुभवी और कठोर-हृदय मजदूर हों, मुख्य केन्द्रों में अपने उत्तरदायी एजेंटों को रखकर, कठोर योग्यता के नियमों के आधार पर भ्रान्तिकारियों के सगठनों के साथ सम्बन्ध होकर और जनता का व्यापक सम्पर्क मिलने पर, बिना किन्हीं विश्रुत नियमों के ही अधिनायक सभ्ये सगठन के समस्त कार्यों को कर सकता है।" 22

दो वर्ष बाद 1904 में लेनिन ने अपनी पुस्तिका—One Step Forward. Two Steps Back—में इन सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए लिखा—

“अपने शक्ति संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के पास संगठन के अतिरिक्त अन्य कोई हथियार नहीं।”²³

दल के संगठन की ओर लेनिन ने अपना सबसे अधिक ध्यान दिया। वे क्रान्तिकारी दल को प्रत्येक दृष्टि से सशक्त बनाना चाहते थे। लेनिन एक पेशेवर, अनुशासित क्रान्तिकारियों के समूह की गतिविधियों का समर्थन करते थे जो सर्वहारा वर्ग का क्रान्ति के समय तथा क्रान्ति के उपरान्त मार्गदर्शन कर सके। लेनिन के विचार में दल का महत्व केवल क्रान्ति तक ही सीमित नहीं रहता क्रान्ति के बाद निर्माण कार्य में भी वे दल के नेतृत्व को शक्तिमत्ता देते थे।

क्रान्ति के उपरान्त साम्यवादी दल के महत्व का उल्लेख करते हुए लेनिन ने, 1920 में कहा—

“साम्यवादी दल मजदूर वर्ग का एक भाग है। वह उत्तम सबसे उन्नत, वर्ग-चेतन और इसलिये सबसे अधिक क्रान्तिकारी भाग है। साम्यवादी दल सबसे अच्छे, सज्जे बुद्धिमान, आत्म-त्यागी और दूरदर्शी मजदूरों से मिलकर बनता है। साम्यवादी दल वह संगठित राजनीतिक व्यवस्था है जिसके द्वारा मजदूर वर्ग का अधिक उन्नत भाग समस्त मजदूरों और भ्रष्ट-मजदूरों को सही दिशा में ले जाता है।”²⁴

साम्यवादी दल के संगठन के लिये लेनिन के बहुत से समकालीन नेताओं ने लोकतान्त्रिक संगठन का समर्थन किया। वे साम्यवादी दल के लोकतान्त्रिक संगठन के पक्ष में थे। लेनिन ने इसका विरोध किया। वे साम्यवादी दल को पूर्ण सुसंगठित तथा समान दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के दल के रूप में देयना चाहते थे। वे साम्यवाद में महानुभूति रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी का सदस्य बनाने के पक्ष में नहीं थे, किन्तु सचे हुए विश्वासपात्र कार्यकर्ताओं को ही पार्टी के सदस्य बनने का समर्थन करते थे।

इसके अतिरिक्त लेनिन ने पार्टी में केन्द्रवाद (centralism) पर विशेष जोर दिया जिसके अनुसार पार्टी की निचली इकाइयों को ऊपर की इकाइयों की आज्ञा माननी पड़ेगी, किन्तु दल के आन्तरिक लोकतन्त्र को जीवित रखने के लिये लेनिन ने आलोचना के महत्व को स्वीकार किया।

राज्य का लोप (withering away of the state)

मान्यवादी सिद्धांतों के अन्तर्गत यह मान्यता है कि सर्वहारा क्रान्ति से जब पूंजीवाद का अन्त होगा, तत्पश्चात् राज्य का भी अन्त हो जायगा। लेनिन ने इस

23. सेबाइन., राजनीतिक दर्शन का इतिहास, पृ० 758-59.

24. उद्धृत, सेबाइन., राजनीति दर्शन का इतिहास, पृ. 759.

श्रीर ट्रॉट्स्की के सिद्धान्त सघर्ष में तीव्रता आ गई । 1927 तक रुस के साम्यवादी दल में ट्रॉट्स्की के सभी सिद्धान्तों को द्वारा दिया तथा उन्हें रुस से निष्काशित कर दिया गया । निष्कासन में भी ट्रॉट्स्की स्टालिन तथा स्टालिन के विचारों का प्रतिरोध करते रहे । 1940 में सम्भवतः एसी एचेंटा ने मेक्सिको में ट्रॉट्स्की की हत्या कर दी ।

ट्रॉट्स्की ने साम्यवादी सिद्धान्तों की व्याख्या के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखी जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं —

- 1 Our Revolution 1906
- 2 Terrorism and Communism A Reply to Karl Kautsky, 1920
- 3 Toward Socialism or Capitalism, 1925
- 4 In Defence of Marxism, 1939-40

स्थायी क्रांति का सिद्धान्त (Theory of the Permanent Revolution)

ट्रॉट्स्की ने साम्यवाद के विभिन्न पक्षों को लेकर टीकाएँ की हैं किन्तु उनका स्थायी क्रांति का सिद्धान्त अधिक महत्वपूर्ण है । वास्तव में ट्रॉट्स्की के ग्रन्थ विचार भी स्थायी क्रांति के सिद्धान्त से ही सम्बद्ध हैं ।²⁶

स्थायी क्रांति सिद्धान्त का अर्थ, ट्रॉट्स्की के अनुसार, उस क्रांति से है जिसमें अन्तर्गत वर्ग-शासन के विभी भी स्वरूप को स्वीकार नहीं किया जाता, क्रांति लोकतांत्रिक व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहती इसका उद्देश्य समाजवादी क्रांति की उपलब्धि है । साथ ही साथ देश के बाहर प्रतिनियामादिशा के विरुद्ध मोर्चा लिए रहना ही स्थायी क्रांति है । ग्रन्थ शब्दों में जब तक वर्ग-भेद का उन्मूलन नहीं हो जाना, जब तक देश में समाजवाद की पूर्ण स्थापना नहीं हो जाती और जब तक रुस की साम्यवादी क्रांति का विरोध करने वालों को समाप्त कर उन्हें समाजवादी व्यवस्था से अन्तर्गत नहीं ले लिया जाता तब तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरन्तर सघर्ष एवं प्रयास करने रहना ही स्थायी क्रांति है । ट्रॉट्स्की स्थायी क्रांति के सिद्धान्त के निम्नलिखित पक्षों को स्पष्ट करते हैं —

लोकतान्त्रिक क्रांति से समाजवादी क्रांति की शीघ्र सम्पन्न

स्थायी क्रांति के इस पक्ष के अन्तर्गत पिछड़े हुए राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के अन्तर्गत ही सम्भव है । इसका तात्पर्य है कि समाजवादी क्रांति के लिए सर्वहारा लोकतंत्र एक प्रारम्भिक अवस्था है । लोकतान्त्रिक क्रांति से समाजवादी क्रांति की शीघ्र अग्रसर होना क्रांति के स्थायित्व को स्वीकार करना है ।

²⁶ साम्यवाद के विभिन्न पक्षों पर ट्रॉट्स्की के रुस के विचारों के लिये देखिये - Anderson, Thornton, Masters of Russian Marxism, pp 135-160, Also see Communism and Revolution by Black and Thornton, pp 27-42

समाजवादी क्रांति

स्थाई क्रांति का दूसरा पक्ष समाजवादी क्रांति है। इसके अन्तर्गत निरन्तर सघर्ष के द्वारा सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन करना है। प्राथिक, तकनीकी, विज्ञान, परिवार, नैतिकता आदि के क्षेत्र में क्रांति स्थाई क्रांति का समाजवादी स्वरूप है।

समाजवादी क्रांति के विषय में ट्राट्स्की का सबसे महत्वपूर्ण सुभाव कृषि का सामूहिकीकरण (collective farming) था।

क्रान्ति का व्यापक आधार : कृषक वर्ग के समर्थन की अपेक्षा

रूस में साम्यवादी क्रांति को स्थाई बनाने तथा उसे व्यापक आधार प्रदान करने के लिये ट्राट्स्की का विश्वास था कि सर्वहारा वर्ग को कृषकों का समर्थन प्राप्त करना चाहिए। सत्ता में आते ही बोल्शेविक कृषक वर्ग के समक्ष एक मुक्तिदाता के रूप में आयेगे। सर्वहारा वर्ग कृषकों को अपनी ओर मिताने के लिए उस भूमि पर कृषकों के स्वामित्व को स्वीकार कर लेगा जो उन्होंने क्रांति के समय छोड़नी थी किन्तु कृषक वर्ग स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन करने के सर्वप्रथम अयोग्य है। ट्राट्स्की एक प्रकार से सर्वहारा-कृषक अधिनायकत्व (Dictatorship of the Proletariat and the Peasantry) का समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं।

श्रम सैन्यीकरण (Militarisation of labour)

रूस में साम्यवादी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध के अन्तिम चरण में हुई। इसलिए रूस में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान युद्ध स्तर पर किया जा रहा था। साम्यवाद की व्याख्या तथा कार्य प्रणाली पर युद्ध का प्रभाव पड़ा। इस संदर्भ में अस्थाई रूप से 'युद्ध साम्यवाद' (War Communism) नामक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। 1920-21 में रूस को युद्ध साम्यवाद से निकाल कर सामान्य साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत लाने की बात सोची गई। ट्राट्स्की का इस सम्बन्ध में सुभाव था कि 'युद्ध साम्यवाद' का विकल्प भी उग्र होना चाहिए। ट्राट्स्की के अनुसार उत्पादन, प्राथिक नियोजन, श्रमिक तथा श्रमिक सगठनों आदि को चाहे सेना के अधिकार में न भी रखा जाय किन्तु इन्हें सैनिक अनुशासन जैसी स्थिति के अन्तर्गत प्रवेश लाया जाय। ट्राट्स्की ने ट्रेड यूनियनों के सैन्यीकरण का सुभाव दिया। प्रत्येक श्रमिक, ट्राट्स्की के अनुसार, श्रम सैनिक है (Every worker is a soldier of labour). *Man must work in order not to die*

ट्राट्स्की प्रत्येक श्रमिक से अनिवार्य श्रम लेने के पक्ष में थे। 'मनुष्य को श्रम करना चाहिए ताकि वह जीवित रह सके' (Man must work in order not to die) ट्राट्स्की का नारा था।²⁷ ट्राट्स्की ट्रेड यूनियनों की स्वायत्तता के विरुद्ध थे तथा दल के अन्दर लोकतन्त्र स्थापी उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया।

27. Anderson, Thornton, Masters of Russian Marxism, p. 128.

श्रमिकों के सं-वीकरण का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना था। इसके लिए अर्थ व्यवस्था का नियोजन एवं संचालन केन्द्र से होना चाहिए। इस सम्बन्ध में ट्राॅट्स्की 'अति राज्यवादी' थे।

ट्राॅट्स्की के ये मुझाव रूस में एक विचार के कारण बन गये। श्रमिकों तथा उन राजनीतिज्ञों ने जो ट्राॅट्स्की को लेनिन का उशाराधिकारी बनना पसन्द नहीं करते थे, ट्राॅट्स्की के ये सिद्धान्त दल में स्वीकार नहीं किये गए। इनमें उनकी सोव-प्रियता को काफी धक्का लगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व क्रान्ति

अपने मार्क्सवादी विचारों में ट्राॅट्स्की पूर्णतः अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के समर्थक थे। उन्होंने दूसरे देशों में क्रान्ति का निर्वात करने के लिए आन्नामक दृष्टिकोण अपनाया। ट्राॅट्स्की का विश्वास था कि साम्यवादी क्रान्ति को रूप तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। क्रान्ति स्थायी होनी चाहिए जिससे विश्व के अन्य भागों में क्रान्ति के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था भी स्थापना की जा सके। इसके लिए ट्राॅट्स्की साम्यवाद का प्रचार एवं विस्तार करने वाली मास्को मियत 'तृतीय अंतर्राष्ट्रीय' (Third International) संस्था का प्रयोग करना चाहते थे। ट्राॅट्स्की का विचार था कि विश्वव्यापी निरन्तर एवं स्थायी क्रान्ति से रूस की क्रान्ति का भी स्थायित्व एवं सुरक्षा प्राप्त होगी। अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति से रूस की सर्वहारा क्रान्ति को ट्राॅट्स्की सुरक्षा इसलिये और प्रदान करना चाहते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि रूस का तबद्वारा बग अलग-थलग होकर क्रान्ति को स्थायी नहीं बना सकता। सूक्ष्म में ट्राॅट्स्की ने 'एक देश में समाजवाद' के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद को प्राथमिकता दी।

अन्तर्राष्ट्रीय बोलशेविक क्रान्ति के समर्थक ट्राॅट्स्की पश्चिम यूरोप में क्रान्ति को ज्वाला प्रज्वलित करना चाहते थे। इसके लिये चिन्तनशील महकाने का कार्य रूस को करना चाहिये। इस सम्बन्ध में ट्राॅट्स्की निम्नलिखित दो प्रमुख सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है —

प्रथम— किसी भी देश में क्रान्ति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह पू-जी-वादी विकास की सीमा प्राप्त कर चुका हो तथा औद्योगिक श्रमिक वर्ग शक्तिशाली बन चुका हो।

द्वितीय— ट्राॅट्स्की का विचार था कि समाजवादी क्रान्ति के लिए व्यापक जन समर्थन या श्रमिक वर्ग की सख्या में वृद्धि आदि आवश्यक नहीं है। क्रान्ति कुछ समाजवादी अल्प-संख्यकों द्वारा भी की जा सकती है। यहाँ इसका आशय यह भी हुआ कि जब तक पश्चिम यूरोप का श्रमिक वर्ग क्रान्ति के लिये धारो नहीं बढ़ता, तब तक क्रान्ति का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। ट्राॅट्स्की की यह धारणा रूस की

क्रान्ति के सन्दर्भ में ही बनी। जब नवम्बर 1917 में बोल्शेविक सत्ता में आए इसका कारण सम्पूर्ण जनता का सहयोग या समर्थन नहीं था। उस समय बोल्शेविकों की सदस्य संख्या केवल दो लाख के लगभग थी। रूस की क्रान्ति वास्तव में बोल्शेविक अल्प-संख्यकों द्वारा सरकार का तटन पलट कर शासन पर अधिकार करना था।²⁸

सुल्यॉकिन

लेनिन के बाद ट्रॉट्स्की को साम्यवादी सिद्धान्तों का अग्रणीय टीकाकार माना जाता था। वे सिद्धान्तकार और साम्यवादी क्रान्ति के कर्मठ कार्यकर्ता दोनों ही थे। साम्यवादी क्रान्ति को स्थायित्व देने के लिये उनका स्थायी क्रान्ति का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ रूस में साम्यवादी क्रान्ति का सक्रिय संचालन करने में ट्रॉट्स्की का महत्वपूर्ण योगदान था। वे साम्यवादियों में उग्रपथी थे।

यद्यपि ट्रॉट्स्की ने साम्यवादी सिद्धान्तों की विद्वत्तापूर्वक व्याख्या की है परन्तु विश्व के साम्यवादी उनके योगदान को स्वीकार नहीं करते। इसका प्रमुख कारण स्टालिन तथा ट्रॉट्स्की के मध्य सिद्धान्तिक मतभेद एवं सत्ता सम्बन्धी सघर्ष या जिसमें स्टालिन सफल रहा। रूस में स्टालिन युग में उनके विचारों के विरुद्ध एक व्यापक एवं व्यवस्थित ढंग से प्रचार किया गया इससे ट्रॉट्स्की के विचारों का प्रभाव समाप्त होता चला गया। आज साम्यवादी परिभाषा में ट्रॉट्स्कीवाद का अर्थ मार्क्सवाद से विचलन, मार्क्सवादी सिद्धान्तों से हटना या उनमें संशोधन करना माना जाता है। साम्यवादी इन सभी तत्वों की निन्दा करते हैं। यद्यपि रूस में ट्रॉट्स्की को खूब अपमानित किया गया, ट्रॉट्स्की का ऐसा कोई विचार नहीं था जिसे आगे चलकर स्टालिन ने स्वीकार न किया हो।²⁹ यहाँ तक कि 'अप्रैल थीसिस' (April Theses, April, 1917) के उपरान्त लेनिन भी ट्रॉट्स्की के क्रान्ति सम्बन्धी विचारों के अधिक निकट थे। रूस में साम्यवादी क्रान्ति के समय तथा बाद में लेनिन ने ट्रॉट्स्की के स्थायी क्रान्ति के विभिन्न सिद्धान्तों को कार्यान्वित किया।³⁰

वर्तमान में विश्व के किसी भी राज्य का साम्यवादी दल ट्रॉट्स्की को अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मानता। केवल श्री लंका ही एक ऐसा अपवाद है जहाँ ट्रॉट्स्की के सिद्धान्तों के आधार पर एक राजनीतिक दल सक्रिय है।

स्टालिनवाद (Stalinism)

स्टालिन (Joseph V. Dzhugashvili, 1879-1953) का जन्म कोंकेशत में हुआ। स्टालिन की माँ अनपढ़ किन्तु धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी किन्तु स्टालिन का पिता एक मोची था जिसे शराब पीने की लत थी। प्रारम्भ में स्टालिन ने वर्ष

28 Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political Thought, p. 488.

29 Deutscher, Isaac, The Prophet Armed, Trotsky, p. 515.

30 Labeledz, Leopold., Ideology; The Fourth Stage; in Political Thought Since World War II, edited by W. J. Stankiewicz, p. 176

साहित्य का अध्ययन किया तथा चौदह वर्ष की आयु में एक धार्मिक सभ्यता की ओर से छात्रवृत्ति भी मिली। लेकिन धीरे धीरे स्टालिन का ध्यान मार्क्सवाद की ओर आकर्षित होता चला गया। 1898 में ये एक मार्क्सवादी समूह के सक्रिय सदस्य बन गये। 1903 के लगभग स्टालिन लेनिन के प्रमुख अनुयायी एव साथी बन गये। इनकी समझन योग्यता तथा कट्टर मार्क्सवादी होने के कारण 1912 में स्टालिन बॉलशेविक केन्द्रीय समिति के सदस्य नियुक्त किये गये। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व 1913 में स्टालिन को यन्दी बनाकर साइबेरिया निष्कासित कर दिया गया। मार्च 1917 में स्टालिन जब निर्वासन से वापस आये तो रूस की क्रान्ति में कूद पड़े। रूस की क्रान्ति में स्टालिन ने लेनिन को अत्यधिक सहयोग दिया।

क्रान्ति के उपरांत स्टालिन को काफी उत्तरदायी कार्य सौंपे गये। वे साम्यवादी दल के मुख पत्र 'प्रोबदा' के सम्पादक रहे तथा राष्ट्रीयता, श्रमिकों, किसानों आदि से सम्बन्धित मन्त्रालयों का कार्यभार सम्भाला। अक्टूबर 1920 में स्टालिन को सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद—साम्यवादी दल के महासचिव—पर नियुक्त किया गया। यही से स्टालिन के हाथों में सत्ता सघन का प्रारम्भ होता है। 1924 में लेनिन की मृत्यु से लेकर 1953 में स्वयं की मृत्यु तक स्टालिन रूस के सर्वोच्च तानाशाह बन कर रहे।

मार्क्सवाद-साम्यवाद में स्टालिन के योगदान को स्वीकार किया जाना है। स्टालिन के कुछ प्रमुख ग्रन्थ, जिनमें उन्होंने मार्क्सवाद में परिवर्तन किया, निम्नलिखित हैं—

- 1 Foundations of Leninism, 1924 ,
- 2 On the Problems of Leninism 1926 ,
- 3 Dialectical and Historical Materialism, 1938 ,
- 4 Marxism and National Question, 1942 ,
5. Economic Problems of Socialism in the USSR 1952, e c

स्टालिन-ट्राट्स्की मतभेद

लेनिन की मृत्यु के पश्चात् रूस का नेतृत्व स्टालिन के हाथों में आया। किन्तु इसी समय स्टालिन और ट्राट्स्की (Trotsky, 1879-1940) के मतभेदों ने साम्यवादी दल को जड़ें हिला दीं। रूस की साम्यवादी पार्टी में गुट हो गये। एन गुट का नेता ट्राट्स्की था और दूसरे का स्टालिन। स्टालिन और ट्राट्स्की का सघर्ष व्यक्तिगत तथा सैद्धान्तिक दोनों ही था। अन्तिम रूप में यह सत्ता का सघर्ष था।³¹ स्टालिन तथा ट्राट्स्की के जो सैद्धान्तिक मतभेद हुए इन्होंने साम्यवादी सिद्धान्तों की व्याख्या को भी भ्रमसर प्रदान किया। निम्नलिखित पत्रियों में ट्राट्स्की स्टालिन मतभेद के साथ-साथ स्टालिनवाद भी स्पष्ट हो जाता है।

31 Hallowell, J H , Main Currents in Modern Political Thought, p 498

स्टालिन और भूमि समस्या - कृषि का सामुदायीकरण (1)

साम्यवादी सिद्धान्त को स्टालिन का सबसे प्रारम्भिक योगदान भूमि समस्या के समाधान के क्षेत्र में है। मार्क्सवाद को छोटे छोटे कृषक फार्म तथा किसानों की निष्क्रियता, उनके असहयोगपूर्ण एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का पहले से ही ज्ञान था। लेकिन वे साम्यवादी क्रांति में कृषकों की 'द्वितीय पंक्ति' के रूप में भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते थे। फिर भी उस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या भूमि का मार्क्सवादी समाधान करने की थी। इस समस्या के समाधान के लिये भूमि का सामाजीकरण, कम्पून व्यवस्था, भूमि विपत्तारण तथा राष्ट्रीयकरण के सुझाव दिये गये। 1906 में स्टॉकहोम पार्टी कांग्रेस में स्टालिन ने इन तीनों विचारों का विरोध किया। उस समय स्टालिन का विचार था कि किसानों को भूमिपतियों से भूमि छीन लेने के लिये कहा जाय और फिर उसका व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में वितरण कर दिया जाय। स्टालिन का विचार था कि इससे कृषक वर्ग साम्यवादी क्रांति का बम से कम कुछ समय के लिये समर्थन करेगा। 1917 में रूस में क्रांति के उपरान्त भूमि का सामाजीकरण और स्टालिन के विचार दोनों का प्रयोग बसता रहा। लेनिन की मृत्यु के बाद इसी समस्या को लेकर ट्राॅट्स्की और स्टालिन में मतभेद हो गये। ट्राॅट्स्की का विचार था कि किसानों का सामुदायीकरण (Collectivisation) किया जाय। उस समय की परिस्थितियों के सन्दर्भ में स्टालिन कृषि का पूर्ण सामुदायीकरण न कर किसानों को कुछ सुविधाएँ देना चाहते थे। किन्तु आगे चलकर स्टालिन ने स्वयं ही कृषि के सामुदायीकरण (Collective farming) को स्वीकार किया।

एक देश में समाजवाद 2

'एक देश में समाजवाद' का प्रारम्भिक विवेचन लेनिन के विचारों में मिलता है किन्तु स्टालिन ने इसका और विस्तार किया। स्टालिन और ट्राॅट्स्की में इस विषय पर कड़ा मतभेद था कि पहले रूस में साम्यवाद को हट किया जाय मथवा विश्व-व्यापी साम्यवादी क्रांति ही और ध्यान दिया जाए। ट्राॅट्स्की का विचार था कि जब तक रूस पूँजीवादी देशों से घिरा है (Capitalist encirclement) तब तक रूस में क्रांति स्थायी नहीं रह सकती। पूँजीवादी देशों से आक्रमण का भय सदैव बना रहेगा। ट्राॅट्स्की समझता था कि अन्य देशों में साम्यवादी क्रांति की विफल योजना बनाई जाय। जब कई राज्य विशेषतः पश्चिम यूरोप के राज्य, समाजवादी क्रांति के घन्तगत भा जायेंगे तो इससे रूस की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और पूँजीवादी घेराव (Capitalist encirclement) भी कोई हानि नहीं कर सकेगा। ट्राॅट्स्की ने स्थायी साम्यवादी क्रांति का समर्थन किया।

स्टालिन इस विचार से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि एक देश में भी साम्यवाद की स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा दूसरे देशों में क्रांति का

निर्वासित नहीं किया जा सकता। किंगो भी देश में गान्धि तभी हो सकती है जब वहाँ कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध हों। स्टालिन का दृष्टिकोण था कि पहले रूस में ही साम्यवाद को हट तथा मफल बनाया जाय।

सितम्बर 1925 में साम्यवादी दल के चौदहवें अधिवेशन में स्टालिन का मत स्वीकार कर लिया गया। दिसम्बर 1927 में ट्राँस्टकी को साम्यवादी दल से निष्कासित तथा देश से निर्वासित कर दिया गया। बाद में अमेरिका में उसकी हत्या कर दी गई।

स्टालिन और ट्राँट्स्की के सैद्धान्तिक मतभेदों में स्टालिन के विचारों की आलोचना हुई है। आलोचकों के अनुसार स्टालिन ने माक्सवादी सिद्धान्तों को पूर्णतः ठुकरा दिया। 'एक देश में समाजवाद' माक्सवादी विचारधारा के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त इस आधार पर स्टालिन ने कमसे कम उस समय तथा तत्कालीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी गान्धि का त्याग कर दिया। यहाँ स्टालिन का उद्देश्य रूस के हित को सुरक्षित रखना था न कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी हित को। इस विवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्टालिन का दृष्टिकोण बहुत कुछ राष्ट्रवादी हो गया था। इन बातों से, आशीर्वादम् के शब्दों में, ऐसा मालूम होगा कि लेनिनवाद स्टालिन के हाथों में अकर अष्ट हो गया।³² उन्हें कट्टर माक्सवादी या सशोधनवादी कहा जाय, इस पर साम्यवादी स्वयं भी एक मत नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रसार को भी स्टालिन ने कभी नहीं छोड़ा। इस सम्बन्ध में उसने नई चीजों को अपनाया तथा उनमें सदैव परिवर्तन करता रहा। 1928 में 'तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय' (Third International) के छठे विश्व-सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें उल्लेख था कि—

"अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद का अन्तिम उद्देश्य विश्व को पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था के स्थान पर विश्व-व्यापी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना है जिसके अन्तर्गत समस्त मनुष्य जाति को सोवियत समाजवादी गणतन्त्रा के विश्व-संघ में निर्माण करना है।... क्योंकि रूस सर्वहारा तानाशाही और समाजवादी निर्माण का देश है इसलिए यह स्वाभाविक रूप से विश्व आन्दोलन का आधार (या केन्द्र) है।"³³

उस समय विश्व में साम्यवादी गान्धि सम्भव नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्टालिन ने एक बंदम पीछे हटने की चाल चली। हिटलर के विरुद्ध इंग्लैंड, अमेरिका आदि से सहायता प्राप्त करने के लिये 1943 में रूस ने कोमिन्टर्न की समाप्ति कर दी। किन्तु युद्ध के बाद इसका फिर पुनर्दान कर दिया। युद्ध में रूस ने पूर्वी यूरोप के राज्यों पर अधिकार कर उनका सोवियतकरण करना प्रारम्भ

³² आशीर्वादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ. 632.

³³ Bazar, Emile, (Ed) A Hand book of Marxism, London, 1935, p 964

कर विश्व के अन्य देशों में साम्यवादी दलों को सहायता तथा समर्थन देना प्रारम्भ किया। इसलिए स्टालिन द्वारा ट्रॉट्स्की का विरोध करना सैद्धान्तिक नहीं व्यक्तिगत प्रतीत होता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्टालिन के विचार एवं व्यवहार परस्पर-विरोधी थे, क्योंकि स्टालिन ऐसा चाहता भी था।

स्टालिन ने ट्रॉट्स्की के साथ अपने सैद्धान्तिक मतभेदों को जान बूझ कर तूल दिया। सत्ता-संघर्ष में साम्यवादी दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए स्टालिन ने यह सर्वप्रथम सिद्धान्तों की आड़ लेकर लड़ा। वास्तव में स्टालिन और ट्रॉट्स्की के मतभेदों को मतभेद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इन दोनों में तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ राजनीतिक चाल में ही कुछ अन्तर प्रतीत होता है। इन मतभेदों के होने हुए भी स्टालिन ने ट्रॉट्स्की के पतन के बाद उन्हीं सिद्धान्तों को अपनाया जिनका ट्रॉट्स्की ने समर्थन किया।

स्टालिन और क्षेत्रीय स्वायत्तता का सिद्धान्त 3

स्टालिन का दूसरा सैद्धान्तिक योगदान 'राष्ट्रीय समस्या' के विषय में है। 1913 में स्टालिन की पुस्तक—The National Question and Social Democracy—में इस समस्या के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं। उस समय दो परस्पर-विरोधी विचारों—राष्ट्रीय स्वाधीनता और सर्वहारा वर्ग की अन्तर्राष्ट्रीय एकता-से विवाद उत्पन्न हो गया था। राष्ट्रवाद के समर्थक राष्ट्रीय स्वाधीनता तथा मार्क्सवादी अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकता में विश्वास करते थे। स्टालिन ने अपने विचारों में इन दोनों परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों का समन्वय किया है। स्टालिन ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों (national minorities) के आत्म-निर्णय (Self-determination) अधिकार को स्वीकार किया है यदि उनका शोषण और दमन किया जाता है। वैसे स्टालिन ने राष्ट्रीयता की पूँजीवादी विचार, व्यक्तियों को विभाजन करने, राष्ट्रीय बाधाएँ उत्पन्न करने वाला विचार कह कर आलोचना की है। दूसरी ओर पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा शासन की स्थापना अव्यावहारिक है। इन दोनों के विकल्प में स्टालिन ने क्षेत्रीय स्वायत्तता (regional autonomy) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया—जिसके अन्तर्गत एक समाजवादी राज्य में क्षेत्रीय स्वायत्तता के आधार पर कई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक रह सकते हैं। 1936 में निर्मित स्टालिन-संविधान में इस सिद्धान्त की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है।

राज्य का लोप (Withering away of the State) 4

स्टालिन ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद में एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया। मार्क्सवाद में राज्य के लोप होने की बात कही गई है। लेनिन ने राज्य के लोप होने को अल्पकालीन रूप से अव्यावहारिक माना है। किन्तु स्टालिन इस सम्बन्ध में लेनिन से बहुत आगे है। उस समय प्रायः यह प्रश्न जिया जाता था कि राज्य का लोप तथा

साम्यवादी समाज की स्थापना कम होगी ? मार्च 1938 में सोवियत साम्यवादी-दल-कांग्रेस के अधिवेशन में स्टालिन ने इस बात को लेकर काफी चर्चा की ।

स्टालिन ने बतलाया कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद को हमें एक रूढ़िवादी धारणा (dogma) के रूप में स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए । आज की प्रत्येक परिस्थिति के लिये मार्क्स-एन्जिल्स आदि न कोई उपचार नहीं बतलाये । इन सिद्धान्तों को हम तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही समझना चाहिये ।

स्टालिन के अनुसार यदि किसी देश का विकास केवल उसकी आन्तरिक परिस्थितियों पर निर्भर होता, या उस देश के अधिकतम भाग में समाजवाद की स्थापना हो गई होती तो राज्य के लोप होने की कल्पना की जा सकती थी । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता, रूस का पूँजीवादी राज्यों द्वारा घिरा होना (Capitalist encirclement) जो रूप की समाजवादी व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिये कटिबद्ध है, राज्य के लोप होने की बात नहीं कही जा सकती । इसके विपरीत स्टालिन ने राज्य को अधिन शक्तिशाली तथा सर्वहारा अधिनायकत्व को अधिन मुद्दह करने पर विशेष बल दिया ।³⁴

व्यक्तिगत तानाशाही 5

काले माक्स ने सर्वहारा वर्ग को महत्व दिया, लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के स्थान पर साम्यवादी दल को प्राथमिकता दी, किन्तु स्टालिन ने सर्वहारा वर्ग तथा साम्यवादी दल को स्वयं भ्रम समा लिया और इस प्रकार अपनी व्यक्तिगत तानाशाही की स्थापना की । स्टालिन जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने पूर्ण तानाशाह की तरह शक्तियों का प्रयोग किया । (आगे कई स्थलों पर स्टालिन के अधिनायकत्व के व्यक्ति पूजा को स्पष्ट किया गया है)

सूक्ष्मांकन 6

स्टालिनवाद मार्क्सवाद-साम्यवाद को शृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है किन्तु स्टालिन के योगदान के विषय में अत्र साम्यवादी विभाजित हैं । यद्यपि विश्व के बहुत से साम्यवादी दल (चीन सहित) स्टालिनवाद के महत्व को स्वीकार करते हैं किन्तु स्वयं रूस में ही निर्रिक्ता ज़ुश्चेव ने अपने शासन काल में स्टालिनवाद को दूरता दिया । ज़ुश्चेव के पतन के बाद स्टालिनवाद का ज़ाने-शने किन्तु सीमित रूप में फिर पुनरुत्थान किया जा रहा है ।

स्टालिन युग के पहले तथा बाद में स्टालिन के निचारों की लोकप्रियता कम होने के कई कारण हैं । स्टालिन ने स्वयं को सर्व सैनिकों का सहायक समझा । कमरिये लेनिनवाद के समर्थ स्टालिनवाद को सा सा समझा था । इसके अनिश्चित

34 Hallowell, J H., Main Currents in Modern Political Thought, pp 511-13

स्टालिन ने अपने शासन काल में कुछ ऐसे अधिनायकवादों, हिंसात्मक, अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जिनके कारण स्टालिन लोकप्रिय न हो सका।

स्टालिन ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को एक कदम और धीरे बढ़ाया। सैद्धान्तिक दृष्टि से स्टालिन लेनिन की अपेक्षा अधिक ग्यार्थवादी थे। 'एक ही देश में समाजवाद तथा 'राज्य के लोप' के विषय में स्टालिन अधिक स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत रूस में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्देशन, कृषि का सामूहिकरण रूस को 1936 में नवीन संविधान देने तथा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त रूस को एक महा शक्ति का स्तर प्रदान करने में एम निष्पक्ष पर्यवेक्षक स्टालिन के योगदान की अवहेलना नहीं कर सकता। ख्रुश्चेव के शासन काल से स्टालिन के विरुद्ध अभियान चलाने के बावजूद भी स्टालिन से साम्यवाद को जो सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक स्वल्प दिया आज के सभी साम्यवादी उनके इस योगदान को स्वीकार करते हैं।

साम्यवादी विचारधारा में निकिता ख्रुश्चेव (Nikita Khrushchev) का योगदान

स्टालिन की मृत्यु के कुछ ही समय बाद निकिता ख्रुश्चेव ने रूस में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। राजनीतिक विरोधियों को मार्ग से हटाकर सरकार और साम्यवादी दल दोनों का नेतृत्व ख्रुश्चेव ने अपने में केन्द्रित कर लिया। लगभग एक दशक तक रूस पर इनका एकदम प्रभुत्व रहा। रूस की आन्तरिक दशा, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा रूस-चीन के सैद्धान्तिक मतभेदों के सन्दर्भ में इन्होंने साम्यवाद के कुछ पक्षों का नया विवेचन प्रस्तुत किया, जिसे रूस का शासक और दलीय वर्ग आज भी मान्यता देता है। ख्रुश्चेव का साम्यवादी विवेचन निम्नलिखित सिद्धान्तों के विषय में है:—

(1) व्यक्ति-पूजा (Cult of personality) का विरोध तथा सामूहिक नेतृत्व (Collective leadership) का समर्थन

1956 में सोवियत साम्यवादी दल के बीच अधिवेशन से ख्रुश्चेव ने स्टालिन की निन्दा करना प्रारम्भ किया। उन्होंने स्टालिन पर व्यक्ति-पूजा, व्यक्तिगत तानाशाही स्थापित करने का आरोप लगाया। ख्रुश्चेव ने कहा कि यह मार्क्सवाद-लेनिनवाद की भावना के विरुद्ध है कि किसी व्यक्ति को देवता की तरह ऊँचा उठाकर दल और जनता की सफलता का सारा श्रेय एक ही व्यक्ति को दे दिया जाय। व्यक्ति-पूजा के स्थान पर ख्रुश्चेव ने सामूहिक नेतृत्व का समर्थन किया।

ख्रुश्चेव ने स्टालिन-पूजा का विरोध किया, लेकिन अपने कार्यकाल में वे स्वयं भी इस और बढ़ते हुए प्रतीत होते थे। उनके उत्तराधिकारी ब्रेज्नेव, कोसीगिन तथा पादगोर्नी आदि ने ख्रुश्चेव को पदच्युत करते समय भी यही आरोप लगाया कि वे अपनी व्यक्ति-पूजा को प्रोत्साहन दे रहे थे।

युद्ध का विरोध १

माक्सवाद-लेनिनवादी वर्ग सघर्ष तथा विश्व म पूंजीवादी और साम्यवादी राज्यों के मध्य युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। ख्रुश्चेव ने युद्ध की अनिवार्यता का समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार परमाणु युग म युद्ध असम्भव है। बड़ी शक्तियों में अब जो भी युद्ध होगा वह परमाणु घसन शम्बो से ही होगा। इस युद्ध में विश्व का सर्वनाश होगा तथा न कोई विजेता होगा न पराजित। इस स्थिति म युद्ध से साम्यवादी विस्तार नहीं हो सकता। विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय धम-युद्ध साम्यवाद प्रसार के साधन के रूप म अब व्यावहारिक नहीं रहा।

एक अन्य तर्क देने हुए ख्रुश्चेव ने कहा कि युद्ध से सामान्यतः थमिक वर्ग की ही हानि होती है चाहे वे पूंजीवादी या साम्यवादी राज्यों म रहते हों। युद्ध का पूंजीपतियों पर नहीं थमिकों के जीवन और जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। युद्ध का समर्थन करना थमिकों के हितों का विरोध करना है। -

इसके अलावा साम्यवाद ने अभी तन आ प्रगति की है, इसका जो विस्तार हुआ है विश्व युद्ध से यह भी समाप्त हो जायगा। अब, ख्रुश्चेव के अनुसार, साम्यवादी राज्यों का अपनी शक्ति संगठित करनी चाहिए ताकि यदि भविष्य म उ-ह युद्ध का सामना करना पड़े तो वे उसीना उटकर मुजाबला करे।

शान्तिपूर्ण एवं सशस्त्र साधनों का समर्थन

माक्स, लेनिन स्टांलिन सभी का विश्वास था कि किसी देश म सशस्त्र क्रान्ति क जिना समाजवादी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ख्रुश्चेव के अनुसार हम म अबतक त्राति उन ऐतिहासिक परिस्थितियों म एक मात्र मार्ग था अब विश्व स्थिति म आमूल परिवर्तन हो चुके हैं। विभिन्न देशों में साम्यवादिया की सव्या में वृद्धि हुई है जिन्नु के दतने सग्न नहीं हैं रि शक्ति द्वारा सत्ता ग्रहण कर लें। उनमें त्राति के प्रति जोश म भी उतार आया है। अब इस बात की सम्भावना अधिन बढ गई है कि मजदूर वर्ग शान्तिपूर्ण तथा सशस्त्र मार्ग से राज्य की शक्ति पर अपना अधिनार कर लें।³⁵ सन्वत् 1957 में वेरन में आम चुनावों के बाद साम्यवादी दल सत्ता में आया इसने ख्रुश्चेव की इस धारणा की प्रोसाहित किया हो। आज-कल साम्यवादी इस तत्व से और भी प्रभावित हुए हगे कि लेनिन अगरीबी राज्य चिली में राष्ट्रपति सेल्बोडोर ऐलन्डे (Salvador Allende) के नेतृत्व में 1971 में चुनावों के माध्यम से साम्यवादी सत्ता में आ गये थे। इससे ख्रुश्चेव सिद्धान्त की और भी गत मिला।

एस और यूनीस्लाविया सम्बन्ध

समाजवाद के कई मार्ग (Many ways of socialism) का सिद्धान्त—

पूर्वी यूरोप के राज्यों का साम्यवादीकरण के साथ-साथ उनका सोवियतकरण (Sovietization) भी किया गया। इन राज्यों की दलीय एव शासन व्यवस्था रूस की प्रणाली पर ही आधारित है। किन्तु मार्शल टोटो (Marshal Tito) के नेतृत्व में यूगोस्लाविया रूसी नियंत्रण से निकल गया। यूगोस्लाविया ने मार्शल टोटो के नेतृत्व में जो साम्यवादी व्यवस्था अपनाई है वह रूस से कुछ दृष्टि से भिन्न है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यूगोस्लाविया रूस का पिछड़नगुच्छा नहीं है। वह रूस के सैनिक संगठन का भी सदस्य नहीं है। यह एक प्रमुख तटस्थ राज्य है जो सभी के साथ, जिनमें पूँजीवादी राज्य भी सम्मिलित हैं, अपने सम्बन्ध अच्छे रखना चाहता है।

स्टालिन ने यूगोस्लाविया के साम्यवाद और मार्शल टोटो को सदैव ही पूर्ण की दृष्टि से देखा। दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध भी ठीक नहीं थे। निकिता ख्रुश्चेव यूगोस्लाविया के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने का प्रयत्न किया। इसी सन्दर्भ में ख्रुश्चेव ने यह स्वीकार किया कि साम्यवाद की प्राप्ति के लिये रूसी प्रणाली ही एकमात्र मार्ग नहीं है। अन्य समाजवादी प्रणालियों से भी साम्यवाद की उपलब्धि हो सकती है। इस प्रकार साम्यवाद के कई या विभिन्न मार्गों के सिद्धान्त की स्वीकार किया गया।

साम्राज्यवाद का बदलता स्वरूप :

सह-प्रस्तित्व (Co-existence) का समर्थन

ख्रुश्चेव के विचार से पूँजीवादी-साम्राज्यवादी राज्यों की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ है। अब अमरीका जैसी महाशक्ति साम्यवादी राज्यों की घनीभित शक्ति से परिचित है। वे भी युद्ध की व्यापकता और विभीषिका से डरने लगे हैं तथा शान्ति के इच्छुक हैं। साम्यवाद, मानववाद और शान्ति पर आधारित है। अतः युद्ध से बचने, तथा साम्यवादी राज्यों में आर्थिक प्रगति को और अधिक गति प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि साम्राज्यवादी राज्यों के प्रति नीति में कुछ परिवर्तन किया जाय। विकल्प रूप में ख्रुश्चेव ने सह-प्रस्तित्व के सिद्धान्त का समर्थन किया। साम्राज्यवादी-पूँजीवादी राज्यों के साथ साम्यवादी राज्यों का सह-प्रस्तित्व हो सकता है, किन्तु उन्हें आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करना चाहिए। जो भी व्यवस्था ठीक होगी विश्व के राज्य उसे स्वीकार कर लेंगे। यदि साम्यवादी राज्य स्वयं अचछा धादर प्रस्तुत करते हैं तो ख्रुश्चेव का विश्वास था कि इस प्रतियोगिता में साम्यवादी राज्य पूँजीवादी-साम्राज्यवादी राज्यों को परास्त कर देंगे।

असंलग्नता (Non-alignment) की नीति का समर्थन

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् धीरे-धीरे एशिया और अफ्रीका में नये-नये स्वतन्त्र राज्यों का प्रादुर्भाव होने लगा तथा उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। कुछ ही राज्यों को छोड़ कर लगभग सभी राज्यों ने असंलग्नता की नीति अपनाई। वे अमरीकी या सोवियत सैनिक गुट में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। वैसे साम्यवादी सिद्धान्ततः

पूर्वजीवादि और संघट्टारा राज्या क अन्तर्गत तटस्थ राज्यों की स्वीकार नहीं करत क्योंकि इससे पूर्वजीवादी और संघट्टारा राज्यों के मध्य संधप म डिलार्ड आयेगी। कि तु परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के सन्दर्भ म ख़ुश्चव का कहना या कि अब "हे यह नीति छोड़ देनी चाहिये कि जो साम्यवादिया क साथ गैरी है वह उनका जत्र है।" उनका यह प्रयत्न होना चाहिये कि तटस्थ राज्य कम से कम पूर्वजीवादी सेमे म सम्मिलित न हो जाय।

तटस्थ राज्यों की अधिक सट्या जिसका सयुक्त राष्ट्र म मददान के समय महत्व की ध्यान से रखते हुय अविश्वसित अफ्रीकी ऐशियायी राज्या म साम्यवाद क शक्तिपूर्ण प्रसार के अर्च्छ अवसर अर्पण आर्थिक हिता तथा इहे अर्पण प्रभाव क्षेत्र (Sphere of influence) म नेने क निय ख़ुश्चव न तटस्थ राज्या की नीतिया की मान्यता तथा सहायता देने का प्रयत्न समथन किया। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति लेनिन के समय म नहीं थी तथा स्टालिन के अंतिम वर्षों म थोड़ा बहुत अम्बुदय हो चुका था। कि तु न नवीन परिस्थितियों क सन्दर्भ म निम्नित ख़ुश्चव न अस्सल्य राज्या के महत्व को जिस तरह स्वीकार किया उससे आम्भवा "रुनियवा" क सैद्धांतिक पक्ष को ही बल नहीं मिला उसने इस क राष्ट्रीय हिता को भी मरक्षण प्रदान किया।

★ ब्रजनेव सिद्धांत (The Brezhnev Doctrine)

1964 म निम्नित ख़ुश्चव ने पत्तन क उपरांत इस का शासन सामूहिक नतृव ने सम्हाला। इससे लिओनार्ड ब्रेजनेव (L. S. Brezhnev) स दियत साम्यवादी दल के महामन्त्री होने के नान कुछ अत्रिक शक्तिशाली बनत जा रहे हैं। अन्तान समय समय पर विशेष परिस्थितिया के परिक्षेप म कुछ सद्धांतिक विचार प्रकट किय हैं जिहे साम्यवादी महत्व देते हैं।

ब्रजनेव का तथाकथित योगान्त सिर्फ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद क विषय म है। 1968 मे चेकोस्लावाकिया मे रुम त्रिराधा विद्राह हुआ। रोवियत सेना ने इस विद्रोह का पूण दमन किया। रुसी हस्तक्षेप की विश्व म काफी भ सता भी जा गई। ब्रजनेव ने रुसी हस्तक्षेप को सही बतनाते हुए निम्नलिखित दो वाक्ता को स्पष्ट किया—

अथम अन्तन भी समाजवादी (पूर्वी यूरोप के साम्यवादी राज्य और रुस के विशेष सन्दर्भ मे) राज्य हैं उनका सम्प्रभुता पारस्परिक व्यवहार मे सीमित है। अपेसी सम्बन्धो म इनमे से कोई भी राज्य पण सम्प्रभुता का दावा नहा कर सकना। सभी की सम्प्रभुता सीमित रहनी है।

द्वितीय इतमे से किना भी राज्य की साम्यवादी प्रणाला को यदि आन्तरिक या बाह्य खतरा उत्पन्न होता है तो समाजवादी व्यवस्था को रक्षा क लिय अथ समाजवादी राज्यों को हस्तक्षेप करन का अधिकार है।

यही श्रेयनेव सिद्धान्त है। यूरोप-आफ्रिका, अमेरिका, रूसिया ने इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है, फिर भी इससे रूसी नेताओं का अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के क्षेत्र में वर्तमान दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। व्यवहार में रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त सर्वत्र ही पूर्वी यूरोप के राज्यों को जननिवेशों की तरह समझा है किन्तु श्रेयनेव का योगदान इसमें है कि उन्होंने इस तथ्य को एक सैद्धान्तिक भावपूर्ण पहना कर हस्तक्षेप को ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया।

माओवाद (Maoism)

जीवनी

माओ त्से-तुंग का जन्म 26 दिसम्बर 1893 में ह्यूनान प्रान्त के एक गाँव में हुआ। 1911 में मंचू शान्ति के बाद माओ ने लगभग छः माह तक सैनिक सेवा की। इस अल्पकालीन सैनिक सेवा ने माओ के सैनिक दर्शन को उभारने का अन्तार दिया। 1918 में माओ ने एक शिक्षक महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। कुछ समय के लिये इन्होंने पीकिंग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में एक छोटे में पत्र पर कार्य किया। 1922-23 में माओ ह्यूनान प्रान्त में एक प्राथमिक शाला के प्रिन्सिपल रहे।

1920-21 में चैन तु-शिन (Chen Tu-hsin) के प्रयासों एवं पहल करने से जिस साम्यवादी समर्थनों का सम्मेलन आयोजित किया गया तथा चीन के साम्यवादी दल की स्थापना हुई, माओ त्से-तुंग उसके संस्थापकों में से एक थे। 1927 में ह्यूनान प्रान्त में माओ ने सक्रिय भाग लिया। इसी वर्ष माओ ने सुयसिद्ध चीनी सेनापति चू तेह (Chu Teh) के साथ किम्लानसी में लाल सेना (Red Army) और सोवियत सरकार की स्थापना की। यहाँ से माओ त्से-तुंग का ध्यान भूमि सुधार की ओर गया जो माओ चन कर इयक साम्यवाद का एक तरह बन गया।

धीरे-धीरे माओ त्से-तुंग साम्यवादी दल के अग्रणीय नेता बनते जा रहे थे तथा उनके शान्तिचारी मतिविधियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। इस समय चीन की स्थिति अति दयनीय थी। आन्तरिक विघटन के साथ-साथ आपात निरन्तर चीन पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा था। 1934 में माओ ने अपने साथियों द्वारा निधारसी से चोत्सी तक लगभग तीन हजार मील की शान्ति यात्रा की। इस यात्रा के दौरान माओ की प्रथम पत्नी की मृत्यु हुई। इस लम्बी शान्ति यात्रा के उपरान्त माओ त्से-तुंग चीन में साम्यवादी मानदोलन एक अग्र नेतृत्व इनके हाथों में आ गया। 1939 में माओ ने शंघाई की एक अभिनेत्री चिंग ग चो से अपना चौथा विवाह किया।

आन्तरिक दृष्टि से चीन इस समय दो क्षेत्रों में विभाजित था। प्रथम, साम्यवादी विद्रोही नेतृत्व चांग काई-शेक कर रहे थे, तथा जिनका शासन पर अधिकार था। द्वितीय, साम्यवादी शान्तिचारी जिनका नेतृत्व माओ कर रहे थे। चीन पर

जापान का आक्रमण तथा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में राष्ट्रवादियों एवं साम्यवादियों के सहयोग में कई उतार चढ़ाव आये किन्तु इनमें हृदय से सहयोग कभी स्थापित नहीं हो सका।

अक्टूबर 1949 में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी शासन की प्रस्थापना हुई। 1949 से 1959 तक माओ त्से-तुंग चीन के राजाध्यक्ष रहे। अंग्रेजों के सार्वजनिक जीवन अलग रहे वरन् केवल साम्यवादी दल के अध्यक्ष के रूप में शासन व्यवस्था का निर्णय निर्देश देते रहते हैं तथा राजनीति के दाव पच प्रदर्शित करते रहते हैं।

माओ त्से-तुंग के विचारों को माओवाद (Maoism) की संज्ञा दी गई है क्योंकि माओ सपथक यह मानते हैं कि उनका विचारों से मार्क्सवाद-लेनिनवाद में अभिवृद्धि का माध्यम तथा चीन की परिस्थितियों के परिपक्व नये साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है। माओवाद की सामग्री माओ द्वारा लिखे गये निबन्धों, दलों तथा समय-समय पर दिये गये भाषणों में मिलती है। माओ के कुछ प्रमुख ग्रन्थ निम्नलिखित हैं—

New Democracy, 1940, On Coalition Government, 1945;

The Present Position and the Task Ahead, 1947,

The People's Democratic Dictatorship, 1949

माओ त्से-तुंग के सम्पूर्ण विचारों का संग्रह Mao's Selected Works में मिलता है जिनका समय-समय पर प्रकाशन हुआ है। चीन में माओ के विचार (Thought of Mao Tse-tung) साम्यवादी दल के लिए विचार एवं कार्य के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। 'वास्तुनिक आति' के समय माओ के विचारों की 'लाल पुस्तक' (Red Book) तथा माओ के कथन दंडे लोकप्रिय हुए। माओवाद चीन की एक मात्र साम्यवादी विचारधारा है।

माओवाद की पृष्ठभूमि एवं प्रादुर्भाव

प्राचीन काल से चीन की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के विकास में निरंतरता और निरोधाभास का जन्म रहा है। चीन की परम्परा में आदर्शवादी, साम्राज्यवादी, पूँजीवादी, समाजवादी आदि विचारधाराओं का समय-समय पर प्रतिपादन हुआ है। वास्तव में चीन की परम्परा से किसी भी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो सकता था। इसलिए चीन में साम्यवाद तथा माओवाद के विभिन्न पक्षों का विकास होना कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। चीन में साम्यवादी व्यवहार के स्रोतों को आसानी से खोजा जा सकता है।

चीनी साम्यवाद की उद्गता, विस्तारवादिता, राष्ट्रीय दृष्टि चीन में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे। प्राचीनकाल में चीन के लोग अपने देश को 'मध्य साम्राज्य' (Middle Kingdom) कहते थे। उनका विश्वास था कि अन्य

आस पास के देशों को चीन के प्रभाव क्षेत्र में रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त चीन के लोगों में अपने विचार, व्यवहार, जीवन-पद्धति, संस्कृति आदि को अ्योसता में पूर्ण विकास रहा है। मार्सोवाद इन सभी विशेषताओं का समन्वय है।

चीन में ईसा के पूर्व चौथी शताब्दी में शांग यांग (Shang Yang) का दर्शन कन्फ्यूशियस के विरुद्ध था। इस दर्शन ने राज्य की निरकुशता, देश की व्यवस्था में एकपता, शिक्षा का केन्द्रीकरण, माहित्य पर नियन्त्रण आदि का समर्थन किया था। चीनी साम्यवाद इन सभी का पालन कर रहा है।

चीन के इतिहास के प्रारम्भ में, जब चीन का नाम चीन नहीं मध्य साम्राज्य (Middle Kingdom) था, कई छोटे-छोटे नगर राज्य निरकुश शासकों के अधीन थे। इस युग में 'दर्शन के सैकड़ों सम्प्रदाय' (Hundred Schools of Philosophy) नामक विचार प्रचलन में था जिसके द्वारा मनुष्य और समाज तथा मनुष्य और प्रकृति के सम्बन्धों पर प्रकाश डाला गया था। मार्सो त्से-तुंग का 'सैकड़ों फूलों तथा सैकड़ों विचार सम्प्रदायों' वाला सिद्धान्त उपर्युक्त मध्ययुगीय विचार पर आधारित था।

मार्सो त्से-तुंग का 'नवीन लोकतन्त्र' (New Democracy) का सिद्धान्त वांग मांग साम्राज्य (Wang Mang, 9-23 A. D.) के विचार 'नवीन राजवंश' (New Dynasty) से ग्रहण किया गया था। 'नवीन राजवंश' का विचार था कि सम्पूर्ण भूमि पर राज्य का अधिकार है, कृषकों से कम लगान लिया जाय, कृषकों को कम व्याज पर ऋण दिया जाय, तथा उत्पादन के कई पक्षों पर राज्य का एकाधिकार होना आदि।

मार्सो त्से-तुंग के सैनिक विचार और सामरिक चाले आदि चीन के लिए कोई नया विचार नहीं है। कन्फ्यूशियस के समकालीन सुन त्जु (Sun Tzu) ने कई सामरिक चालों का प्रतिपादन किया। उदाहरणार्थ सुन त्जु ने कहा था "युद्ध बरके विजय प्राप्त करना कोई महान् वात नहीं है, महानता इसमें है कि बिना युद्ध किए ही शत्रु के सामर्थ्य को नष्ट कर दिया जाय। स्वयं का और शत्रु का सही मूल्यांकन करो तो तुम्हें सैकड़ों युद्धों में भी पराजय का मुँह नहीं देखना पड़ेगा।" 36 इसी प्रकार मार्सो त्से-तुंग के समकालीन प्रसिद्ध सेनापति चू तेह (Chu Teh) की सामरिक नीति और सैनिक चालों को मार्सो ने ग्रहण किया है।

चीन में साम्यवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव इस में साम्यवादी क्रान्ति के बाद हुआ था। 1919 में चीन के साम्यवादी प्रवर्तक चैन तू-शिन ने रूस में स्थापित तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International or Comintern) से चीन का सम्पर्क स्थापित किया। 1920 में एक व्यक्ति श्री मालिंग तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के प्रतिनिधि रूप में शंघाई आये और समाजवादी दल की स्थापना का प्रवन्ध किया। तदुपरांत

चेन तू-शिन न साम्यवादी समझने का एक सम्मेलन आयोजित किया तथा मई 1920 में चीन में साम्यवादी दल का प्रादुर्भाव हुआ। चेन तू-शिन नये दल के अध्यक्ष चुने गये तथा माओ त्से-तुंग दल के एक प्रमुख सदस्य थे लेकिन धीरे-धीरे माओ त्से-तुंग इतर अग्रणीय नेता बन गये।

चीन में साम्यवादी आन्दोलन पर मार्क्सवाद तथा रूसी साम्यवाद का प्रभाव था। माओ त्से-तुंग ने स्वयं ही अपने साम्यवाद पर मार्क्स-लेनिन-स्टालिन के प्रभाव का स्वीकार किया है किन्तु माओवाद या चीनी साम्यवाद मुख्यतः चीन की उपज अग्रिम है। एक बार माओ त्से-तुंग ने कहा था—“रूस के इतिहास ने रूस की व्यक्तियों को जन्म दिया चीन का इतिहास चीनी व्यक्तियों का निर्माण करेगा।” चाओ साम्यवादी पहले चीनी है बाद में साम्यवादी। माओवाद इस प्रकार राष्ट्रवाद और साम्यवाद दोनों का समन्वय है।

द्वितीय विश्व के अन्त तक चीन में माओ त्से-तुंग और साम्यवाद का व्यापक प्रभाव होता जा रहा था किन्तु माओ त्से-तुंग एक विशिष्ट साम्यवादी चिन्तन के रूप में सामन नहीं आये। सम्भवतः माओ त्से-तुंग स्वयं को एक गृहक मार्क्सवादी-साम्यवादी टीकाकार के रूप में घोषित कर रूस से नाराज नहीं करना चाहते थे। 1945 में माओ त्से-तुंग को एक विशिष्ट मार्क्सवादी सिद्धान्तकार के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया। इस वर्ष ल्यू शाओ ची (बाद में चीन के राजाध्यक्ष, माओ के सम्मानित उत्तराधिकारी किन्तु सोवियत आन्ति में पदच्युत एक अपमानित) का दावा था कि माओ त्से-तुंग न चीन में नानि सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जो साम्यवादी सिद्धान्त श्रृंखला में एक नवीन प्रयास है। सभी से चीन का साम्यवादी दल माओ त्से-तुंग के विचारों को एक विशिष्ट साम्यवादी विचारधारा के रूप में प्रचार कर रहा है। चीनी साम्यवादी दल का दावा है कि माओ त्से-तुंग ने मार्क्सवाद-साम्यवाद का एक दर्जन से भी अधिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इस समय साम्यवादी सिद्धान्तों की व्याख्या का स्रोत केवल माओ ही नहीं है, उतन ही अद्विष्ट रूप में वेबिंग से भी साम्यवादी विचारों का विवेचन होता रहता है। वास्तव में रूस और चीन दोनों ही समानान्तर रूप से साम्यवादी विचारधारा का केन्द्र बन गये हैं।

माओ त्से-तुंग एक मार्क्सवादी दार्शनिक के रूप में (1)

चीन के साम्यवादियों का कहना है कि माओ त्से-तुंग ने मार्क्सवादी दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके अनुसार माओ ने मार्क्स के द्वन्द्वमय भौतिकवाद में परिचय देकर उस अधिक स्पष्ट किया है। उनका यह दावा माओ त्से-तुंग के दो निबन्धों—On Practice और On Contradiction—पर आधारित है जो माओ ने 1937 में लिखे तथा 1950 और 1952 में तमाम प्रकाशित हुए। चीनी साम्यवादी टीकाकारों का मत है कि On Practice (कार्य अथवा प्रयोग) में माओ

त्से-तुंग ने मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्त के व्यावहारिक पक्ष का और घाते विकास एवं विस्तार किया है। इस निबन्ध में माओ ने ऐन्जिल्स तथा लेनिन के दो प्रमुख सिद्धान्तों—Principles of Absolute and Relative Truth—को पूर्णतः स्पष्ट किया है।

माओ त्से-तुंग का दूसरा निबन्ध—On Contradiction (परस्पर-विरोध)—के विषय में यह बतलाना है कि यह लेनिन के द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त पर घाते का विकास है जिसमें 'विरोध में एकरता' (Unity of opposites), 'घातार्थक परस्पर-विरोध' (Internal Contradiction) तथा 'बाह्य घातार्थक तत्त्वों का विनाश पर प्रभाव को स्पष्ट किया है।

माओ त्से-तुंग के इन दोनों दार्शनिक निबन्धों पर मतभेद है। सर्वप्रथम आलोचकों का आरोप है कि ये निबन्ध माओ त्से-तुंग द्वारा नहीं लिखे गये हैं क्योंकि माओ के विचारों के प्रारम्भिक सफलन में इनको सम्मिलित नहीं किया गया। सिद्धान्तिक दृष्टि से भी इन निबन्धों की कटु आलोचना की गई है। इन निबन्धों में ऐसी कोई नई बात नहीं है जिसके लिये माओ को इनकी मौलिकता का श्रेय दिया जाय। माओ ने जो कुछ लिखा है वह ऐन्जिल्स तथा लेनिन के विचारों की पुनरावृत्ति ही है।³⁷ खेतिहर देश के लिये साम्यवादी क्रान्ति का सिद्धान्त (2)

माओवाद को लेनिनवाद का ही एक ऐसा स्वरूप माना जा सकता है जो खेतिहर देश की परिस्थिति के अनुकूल हो। भूमि की भूय चीन की प्रधान समस्या रही है और माओवाद उसी समस्या का उत्तर है।³⁸ माओ त्से-तुंग ने अपने विचारों में खेतिहर देशों में साम्यवादी क्रान्ति की सम्भावना पर काफी प्रकाश डाला है। 1927 में चीन के ह्यूनान (Hunan) प्रान्त में कृषकों ने विद्रोह किया था। माओ त्से-तुंग स्वयं इस घान्दीयन का अवलोकन करने ह्यूनान पहुँचे। कृषक विद्रोह के विषय में माओ ने एक प्रतिवेदन—Report of an Investigation into The Peasant Movement in Hunan—तैयार की। वास्तव में यह प्रतिवेदन ही माओ त्से-तुंग का 'खेतिहर देश में क्रान्ति' सिद्धान्त का आधार है। माओ त्से-तुंग ने खेतिहर देश में क्रान्ति के सिद्धान्त में निम्नलिखित विचारों का प्रतिपादन किया है:—

प्रथम, साम्यवादी क्रान्ति औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश, या खेतिहर देश में भी सम्भव है।

द्वितीय, खेतिहर देश में कृषक वर्ग के माध्यम से भी साम्यवादी क्रान्ति लाई जा सकती है।

37. Cohen, A. A., How Original is Maoism, in Political Thought Since World War II, edited by W. J. Stankiewicz, pp. 226-229

38. आशीर्वादन, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ. 634.

तृतीय, शिथिल दृष्टि वर्ग एवं श्रमवसनीय शक्ति है तथा श्रमिक वर्ग का मित्र रहना है।

माओ त्से-तुंग समझा है कि उनके इन विचारों के आधार पर एशिया तथा अफ्रीका के देशों में साम्यवादी क्रान्तियाँ सम्भव हैं क्योंकि इन महाद्वीपों के देश भूमिगत नेता ही हैं।

3) शान्ति नीति एवं सामरिक चालें (Communist tactics)

प्रत्येक व्यक्ति या किसी शक्ति का नगृत्व करता है शान्ति का सफल बदलने के लिये कुछनीतियों तथा चालों का निर्माण करता है। इसलिये सामरिक चालें भी शान्ति या एक महत्प्रयत्न में ही बन जाती हैं। माओ त्से-तुंग ने चीन की शान्ति के सम्दर्भ में रणनीति एवं चालों का निर्माण किया जो साम्यवाद का एक आवश्यक पक्ष बन गया है। इस सम्बन्ध में माओ त्से-तुंग ने दो पक्षों का मुख्य विचार किया है। प्रथम देहाती क्षेत्र की शान्ति का आत्म निर्भर आधार बनाना, द्वितीय गुरिल्ला युद्ध सम्बन्धी रणनीति एवं चालें।

देहाती क्षेत्र में शान्ति गवानन करने के लिए माओ त्से-तुंग का विचार है कि देहाती क्षेत्र में शान्ति की शिथिल सम्भव है। देहात को एक दीर्घकालीन शान्ति का आधार बनाया जा सकता है। जब शान्ति लम्बे समय तक चल सकती है तो विचार प्राप्त करने का प्रमुख साधन गुरिल्ला युद्ध ही हो सकता है।

1938 में माओ का निबन्ध 'युद्ध के विस्तार पर' (On Protracted War) का प्रकाशन चीन तथा जापान के एक दशक से भी अधिक समय तक चलने वाले युद्ध के परिपेक्ष में किया गया था। जापान के साथ युद्ध करने में माओ ने कहा था कि युद्ध को अधिक समय तक अधिक क्षेत्र पर विस्तार करने में लंबा अधिक दिन तक नहीं टिक सकेगा। इस सम्बन्ध में माओ ने निम्नलिखित सामरिक चालों का प्रतिपादन किया—प्रथम, शत्रु का आक्रमण तथा चीन द्वारा सामरिक रक्षा, द्वितीय, शत्रु द्वारा रक्षा और चीन द्वारा आक्रमण का तीसरा, तृतीय, चीन द्वारा आक्रमण और शत्रु द्वारा पीछे हटना आदि। साथ ही साथ माओ का कहना था कि युद्ध के समय उस एक क्षण के लिए भी राजनीति से पृथक् नहीं किया जा सकता।

4) युद्ध एवं शक्ति का सम्बन्ध

साम्यवादी शान्ति के लिए माओ त्से-तुंग युद्ध तथा शक्ति का सम्बन्ध करते हैं। उनसे अनुसार सत्ता शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है (Power comes from the barrel of gun) माओ ने पूँजीवादी दशा की समझ में लिए साम्यवादी राज्यों द्वारा युद्ध की बात कही है यद्यपि यह सम्भव है और सम्भव होना जा रही है। सामरिक राजनीति के अतिरिक्त माओ दूमरे देशों के साथ विवाद सुलझाने में युद्ध

एवं शक्ति का प्रयोग एवं प्रदर्शन करते हैं। भारत के साथ 1962 में मीमा विनाइ हूत करने में माओ ने युद्ध का समर्थन किया। इसी वर्ष प्यूबा साट के समय रूस द्वारा अमेरिका से युद्ध न करने तथा पीछे हट जाने की चीन ने निन्दा की। जनवरी 1974 में दक्षिण चीन सागर में चीन ने दक्षिण वियतनाम के विरुद्ध पारासेल द्वीपों पर शक्ति द्वारा अधिकार कर लिया।

माओ के विचारों का विशेष महत्त्व युद्ध और सामाजिक क्षेत्र में भी है। उन्होंने साम्यवादी गुरिन्ना युद्ध, रणनीति आदि के विषय में विस्तारपूर्वक विचार व्यक्त किये हैं। वे साम्यवादी दल जो अपनी सरकारों के तख्ते उलटने में या विदेशी प्रभाव से मुक्त होने के लिए सज्ज हो रहे हैं, उनके लिए माओ के विचारों में पृथक् सारे सुझाव मिल सकते हैं। युद्ध में आगे बढ़ने, पीछे हटने, शत्रु को धोखा देने, दूसरे राज्यों को अपने साथ मिलाने, विरोधी को विभाजित करने लिए माओवाद में विचारों का अभाव नहीं है।³⁹

नवीन लोकतन्त्र या लोकतान्त्रिक तानाशाही 5

साम्यवादी क्रान्ति के उपरान्त चीन में शासन चलाने के लिए माओ त्से-तुंग ने 'नवीन लोकतन्त्र' (New Democracy) के सिद्धान्त को स्वीकार किया। 1940 में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन माओ ने एक छोटी सी पुस्तिका—New Democracy—में किया था। चीन की शासन व्यवस्था चलाने के लिए नवीन लोकतन्त्र के दो सिद्धान्तिक पक्षों को स्वीकार किया गया। प्रथम, जनता के लिए लोकतन्त्र तथा द्वितीय, प्रतिक्रियावादियों के लिए तानाशाही। इन दोनों पक्षों के सम्मिलित रूप को 'लोकतान्त्रिक तानाशाही' (Democratic Dictatorship) का नाम दिया गया।

माओ त्से-तुंग ने लोकतान्त्रिक तानाशाही को सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। या, यह कहा जा सकता है कि लोकतान्त्रिक तानाशाही द्वारा माओ ने सर्वहारा अधिनायकत्व को चीन के सन्दर्भ में परिभाषित किया है। सूक्ष्म में लोकतान्त्रिक तानाशाही की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(i) चीन की व्यवस्था को लोकतन्त्र की ओर अग्रसर करना।

(ii) चीन में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना।

(iii) लोकतान्त्रिक केन्द्रीकरण (Democratic Centralism) की स्थापना

करना जिसका तात्पर्य व्यक्तियों को एक सीमा तक स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र का उपभोग करने देना किन्तु साथ ही साथ उन्हें समाजवादी अनुशासन स्वीकार करना चाहिए। शासन व्यवस्था में केन्द्रीय निर्देशों को प्राथमिकता देना आदि।

39 इसे सम्बन्ध में देखिये—

Selected Works of Mao Tse-tung, Lonnon, 1954 Vol. II, deals with Protracted war, Strategic Offensive and Defensive Guerrilla Warfare.

(iv) लोकतान्त्रिक तानाशाही के अन्तर्गत श्रमिक वर्ग (व्यवहार में साम्यवादी दल) के नेतृत्व को स्वीकार करना जो श्रमिक एवं वृषण वर्ग के सहयोग पर आधारित हो। माओ की लोकतान्त्रिक व्यवस्था के विषय में रिचर्ड वाकर ने लिखा है —

“माओ का लोकतान्त्रिक तानाशाही का सिद्धान्त लेनिन से ग्रहण किया हुआ है जिसने अन्तर्गत सेना, पुलिस और न्यायालयों की भूमिका के विषय में स्टालिन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। क्रम के अनुभव ने यह बतलाया कि राज्य शक्ति को पूर्णतः नियन्त्रित करने के लिये एकीकृत (या पूरा संगठित) दल आवश्यक है।”⁴⁰

लोकतान्त्रिक तानाशाही पूर्णतः लेनिन-स्टालिनवादी व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था समझौते के सिद्धान्त पर आधारित है। इसका सार्वभौम सर्वहारा वर्ग तथा साम्यवादी दल के तत्वावधान में प्रातिशील तत्वों का समन्वय करना था। तद्विना लोकतान्त्रिक तानाशाही के उद्देश्यों के विषय में माओ स्टे-तुंग ने कहा था —

“इस समय हमारा कार्य जन-शासन व्यवस्था को मजबूत करना है, अन्य शब्दों में, जन-सेना, जनता पुलिस व्यवस्था और जन-न्याय लक्ष्यों को सुदृढ़ कर राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हितों को संरक्षण देना है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत सर्वहारा वर्ग और साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीन का वृषि देश स औद्योगिक देश में नवीन लोकतन्त्र से समाजवादी व्यवस्था तथा प्रतिम रूप में वर्ग-उन्मूलन कर व्यापक सहयोग के आधार पर साम्यवादी समाज की ओर विकास करना है।”⁴¹

‘सैंडहो फूलो वाला सिद्धान्त’ (1955-57) 31 नवम्बर 1957

1949 में चीन के साम्यवादी दल ने एशिया में पराधीन राज्यों की मुक्ति के लिए आन्ति का आह्वान किया था। एशिया के राज्यों में इस विषय में ठीक प्रतिनिधियां नहीं हुईं। 1955 में बान्दुंग में अफ्री एशियायी राज्यों के सम्मेलन में चीन के इस विचार को शक्ति की दृष्टि से देखा गया। बान्दुंग सम्मेलन का मुख्य विचार ‘अन्यता में एकरता’ (Unity in diversity) था। समग्र दली समय हम और यूरोप-अमेरिका के सम्बन्धों के सम्बन्ध में ‘समाजवाद के विभिन्न स्वरूपों’ के सिद्धान्त को कार्यान्वित किया जा रहा था। स्वयं हरा में ही स्टालिनवादी दलव को काफी गंभीर दृष्टान्तों का प्रयत्न जारी था। इसके अतिरिक्त चीन अलग अलग रहने की नीति को स्थापित कर आन्तिक कारणों से एशियायी राज्यों से सम्बन्ध बढ़ाने का इच्छुक था। इन परिस्थितियों के सम्बन्ध में माओ स्टे-तुंग ने मई 1955 में ‘सैंडहो फूलो’ वाले विचार को चीनी जनता के समक्ष रखा। माओ के अनुसार—

⁴⁰ Walker, Richard, China Under Communism, p. 5

⁴¹ Mao Tse-tung, People's Democratic Dictatorship, quoted by R. C. Gupta, Great Political Thinkers, p. 87

संकड़ों फूलों को खिलने दो,
संकड़ों विचार सम्प्रदायों को सन्तुष्ट होने दो ।⁴²

प्रारम्भ में चीन की जनता ने उस नवीन विचार की ओर शंका की दृष्टि से देखा किन्तु धीरे धीरे गैर साम्यवादी विचार सतह पर आने लगे। आगे चलकर इसने साम्यवाद विरोधी रूप ले लिया। माओ त्से-तुंग नहीं चाहते थे कि आलोचना निश्चित सीमा को पार करे। इसलिए साम्यवादी दल ने साम्यवाद का विरोध करने वालों का उन्मूलन प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार इस नई स्वतन्त्रता का वातावरण छ. सप्ताह से अधिक न चल सका। पर्यवेक्षकों का विचार है कि माओ त्से-तुंग का यह नवीन नारा धोखा एवं भ्रमजाल था। माओ त्से-तुंग अपने विरोधियों तथा ईमानदारी से मतभेद रखने वालों से निपटने के लिए विशेष उपाय काम में लेते हैं। 'संकड़ों फूलों' वाले वातावरण ने माओ त्से-तुंग के विरोधियों को उभरने का अवसर दिया। जब साम्यवाद विरोधी या गैर-साम्यवादी तत्व प्रबल हुए तो उनका उन्मूलन कर दिया गया।

राष्ट्रीय संस्कृति : सांस्कृतिक क्रान्ति

माओ त्से-तुंग का विचार है कि चीन में नवीन साम्यवादी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक नवीन राष्ट्रीय संस्कृति की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संस्कृति का तात्पर्य यह नहीं कि इसके अन्तर्गत चीन के राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रतिबिम्बन किया जाय। इसका तात्पर्य, माओ के अनुसार, विश्व साम्यवादी संस्कृति, चीन की नई शासन व्यवस्था तथा चीन की कुछ विशेषताओं को एक नया रूप प्रदान करना है। अन्य शब्दों में, चीन की परम्परागत संस्कृति को साम्यवादी संस्कृति में परिणत करना है।⁴³ इसके लिये यह आवश्यक होगा कि चीन की परम्परा एवं जन-जीवन से सामन्तवादी, प्रतिस्वार्थवादी, साम्यवाद विरोधी विचारों एवं व्यवहार को समाप्त किया जाय। माओ त्से-तुंग का उद्देश्य चीन को एक नवीन साम्यवादी जीवन पद्धति (Communist way of life) प्रदान करना है। नवीन राष्ट्रीय संस्कृति के अन्तर्गत चीन का मानव-मस्तिष्क परिवार, धर्म, सम्पत्ति आदि से प्रभावित न होकर द्वन्द्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शन से निर्देशित हो।

इन विचारों की अभिव्यक्ति 1966-1968 में 'सांस्कृतिक-क्रान्ति'⁴⁴ (Cultural Revolution) के समय हुई। सांस्कृतिक क्रान्ति को स्पष्ट व्याख्या करना

42. Let a Hundred Flowers Blossom,
Let a Hundred Schools of Thought Contend.
Quoted, Issae Deutscher., Russia China and the West, p. 103.

43. Chou Hsiang-Kuang., Political Thought of China, p. 277.

44. सांस्कृतिक क्रान्ति के अध्ययन के लिये देखिये—
China's Cultural Revolution by Gargi Dutt

प्रसम्भ है। यह सांस्कृतिक क्रान्ति न होकर एक प्रकार से बहुउद्देशीय आन्दोलन था। सम्पूर्ण चीन में लाल रक्षकों (Red Guards) के माध्यम से माओ त्से-तुंग ने अपने कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया। चीनी जनता को माओवाद से पूर्णतः परिचित कराया गया, माओवाद में विचलन होने वालों को लड़ी पर लाया गया।

सांस्कृतिक क्रान्ति को वास्तव में पार्श्विक और अराजकतावादी बहाना बनाया था। इस तथाकथित सांस्कृतिक क्रान्ति के द्वारा माओ ने अपने विरोधियों को अन्तर्निहित करने, उन्हें उच्च पदों से हटाने का कार्य प्रारम्भ बनाया। परिणामस्वरूप माओ त्से-तुंग चीन के राज्याध्यक्ष ल्यू शाओ ची, विदेश मंत्री चेन यी तथा अन्य से घुटकारा पा सके। जैसे विरोध उन्मूलन साम्यवादी व्यवस्था में कोई नया तत्व नहीं है, माओ त्से तुंग ने विरोध उन्मूलन की प्राप्ति घोषित तथा केवल ऊपर से ही अच्छे लगने वाले साधनों द्वारा की।

नवीन अभियान—माओ त्से-तुंग स्वयं और निरन्तर क्रान्ति के समर्थक हैं। प्रभो तथाकथित सांस्कृतिक क्रान्ति को चार वर्ष भी नहीं हुए थे कि 1973 में एक नवीन अभियान तथा आन्दोलन की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। यह नवीन अभियान 1968-69 में निष्कृत माओ के उत्तराधिकारी लिन-पियाओ तथा चीन के सर्वकालीन प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस (Confucious, 551-478 B.C.) के विरुद्ध है। 1971 में लिन पियाओ द्वारा माओ से सत्ता छीनने के प्रयास में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु के बाद चीन के साम्यवादी दल ने लिन पियाओ के विचार एवं समर्थकों को दल एवं चीन की राजनीति से उन्मूलन करना प्रारम्भ किया। किन्तु लिन पियाओ के साथ कन्फ्यूशियस के विरुद्ध अभियान को ओड़ने की बात समझ में नहीं आती। यद्यपि कन्फ्यूशियस का दर्शन और साम्यवादी विचारधारा एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं किन्तु माओ त्से-तुंग का कन्फ्यूशियस के विरुद्ध प्रचार का कोई विशेष कारण प्रतीत नहीं होता। जबो कभी माओ ने भी कन्फ्यूशियस के प्रति निष्ठा व्यक्त की है।⁴⁵ 1973 के मध्य से लिन-कन्फ्यूशियस विरोधी अभियान अत्र व्यापकता ग्रहण करता जा रहा है। वास्तव में यह आन्दोलन तथाकथित सांस्कृतिक क्रान्ति का ही विस्तार है। सम्भवतः माओ त्से-तुंग चीन के विचार क्षितिज पर अक्सरे ही सूर्य की भांति

⁴⁵ उदाहरणार्थ माओ त्से-तुंग ने अपनी निम्नलिखित कविता में कन्फ्यूशियस की प्रशंसा की है :—

I care not that the wind blows and the waves beat,

It is better than idly strolling in a countryyard,

It was on a river that the Master said

This is the whole of nature flowing

उपरोक्त कविता की तीसरी पंक्ति में 'Master' शब्द का प्रयोग कन्फ्यूशियस के लिये किया गया है।

Quoted by Frank Moraes, The Sunday Standard, April 7, 1974, p. 4.

साम्यवाद

बमकते रहना चाहते हैं। वे उन सभी चिन्तक, दार्शनिकों के भी न के भी चीन में लोक-प्रियता और व्याप्ति अर्जित कर चुके हैं के विचार प्रभाव का उन्मूलन करना चाहते हैं।

कम्यून व्यवस्था (Commune System) ५

चीन के लोगों में अपने देश को एक बड़ी शक्ति बनाने की लालसा सदैव रही है। माओ त्से-तुंग में यह महत्वाकांक्षा सम्भवतः सबसे अधिक है। माओ के अनुसार देश को शक्तिशाली बनाने के लिये आर्थिक प्रगति अति आवश्यक होती है। चीन में साम्यवादियों के सत्ता में आने के पश्चात् ही आर्थिक योजनाएँ प्रारम्भ की गयीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1953-57) में देश की आर्थिक प्रगति तो हुई लेकिन उतनी नहीं जो चीन को एक आर्थिक आधार प्रदान कर सकती। माओ त्से-तुंग किसी ऐसी योजना को कार्यान्वित करना चाहते थे जिसके द्वारा चीन आर्थिक क्षेत्र में एक लम्बी छलांग लगाकर पाँच-सात वर्ष में ही एक पीढ़ी की आर्थिक प्रगति कर आत्म निर्भरता की ओर मार्ग प्रशस्त कर सके।⁴⁶

अपनी आर्थिक योजनाओं पर चीन उस समय रूस पर एक बड़ी सीमा तक आश्रित था। माओ त्से-तुंग नवम्बर 1957 में रूस को दूसरी बार यात्रा की। आर्थिक सहायता के रूप में चीन को अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1958-62) के लिये रूस से कोई विशेष सहायता का आश्वासन नहीं मिल सका। चीन को अब अपने ही साधनों पर निर्भर रहने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। फलस्वरूप फरवरी 1958 में राष्ट्रीय जन कांग्रेस (National People's Congress) ने देश के लिये 'लम्बी छलांग' (Big Leap Forward) का आह्वान किया। कुछ ही सप्ताहों में सम्पूर्ण देश में आर्थिक गतिविधियों की एक बाढ़ प्रारम्भ हो गयी। गाँवों औद्योगिक एवं कृषि कम्यून (Commune) स्थापित हुए। सर्वप्रथम कृषि कम्यून अप्रैल 1958 में हॉनान प्रदेश (Honan Province) में स्थापित किया गया। इसका नाम स्पुतनिक (Sputnik) रखा गया। मई 1958 में साम्यवादी दल को पूर्ण सैन्य एवं सतर्क बनाया गया तथा दल के सदस्यों को आदेश दिया गया कि वे 'लम्बी छलांग' कार्यक्रम को सफल बनाएं। दून के अन्त तक अकेले हीपाइ प्रान्त (Hopei Province) में ही लगभग पाँच लाख फैक्ट्री और वर्कशाप स्थापित किये गये जिनमें बरोहों चीनियों को काम पर लगाया गया। अगस्त 1958 से साम्यवादी दल के नेतृत्व में सम्पूर्ण चीन में कम्यून प्रणाली की स्थापना करने का आदेश दिया।

कम्यून व्यवस्था को लागू करने के पूर्व चीन में सामूहिक खेती (Collective Farming) प्रचलित थी। इस कार्य के लिये लगभग 7,40,000 कृषि उत्पादक सहकारी संघाएँ (Agricultural Producers' Cooperatives) सक्रिय थीं। किन्तु

46 चीन में कम्यून व्यवस्था की पृष्ठभूमि के लिये देखिए—

Dutt, Gargi, Rural Communes of China, pp 1-20.

कम्यून प्रणाली के अन्तर्गत 'जन-स्वामित्व' के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। सभी कृषि उत्पादक सहकारी संस्थाओं को लगभग 25000 कम्यूनो में परिवर्तित कर दिया गया। प्रत्येक कम्यून के अन्तर्गत औसतन 10,000 एकड़ भूमि तथा 5000 परिवार सम्मिलित किये गये। एक कम्यून पर सामान्यतः दस हजार व्यक्तियों को कार्य पर लगाने का सामान्य प्रावधान है। अन्य शब्दा में, 'एक एकड़, एक व्यक्ति' का सिद्धान्त लागू किया गया।⁴⁷

1958 में डा. एम. चन्द्रशेखर तथा उनके कुछ अन्य साथियों ने अपने चीन भ्रमण के समय चंगचौ (Chengchow) के निकट एक आदर्श कम्यून का अवलोकन किया। यहाँ साम्यवादी सिद्धान्त—'प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार मिले'—का प्रयोग किया जा रहा था। यहाँ कुछ अपवादों को छोड़ कर मुद्रा विनियम समाप्त कर दिया गया था। कार्य के उपलक्ष में यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित सोलह गारण्टियाँ (गुविधाएँ या अधिकार) दी गयी-

1. छुट्टा, 2. भोजन, 3. रहने का स्थान, 4. कार्यस्थल तक आने-जाने की सुविधा, 5. प्रसूति सुविधा, 6. बीमारों के समय अवकाश तथा मुफ्त दवा, 7. मुफ्त वृद्धावस्था हिफाजत, 8. मुफ्त अन्त्येष्टि व्यवस्था (जिसके अन्तर्गत मृत व्यक्तियों को सामान्यतः दस फीट की गहराई पर दफनाया जाता है ताकि भूमि के ऊपर खेती हो सके तथा वह स्थान शमशान बनकर बेकार न हो जाये) 9. मुफ्त शिक्षा, 10. बच्चों का मुफ्त सालान पालन, 11. मुफ्त मनोरंजन, 12. विवाह के लिये कुछ अनुदान तथा नवविवाहितों के स्वागत तथा विवाह भोजन की मुफ्त व्यवस्था, 13. एक वर्ष में बारह बार बाल बटाने की मुफ्त सुविधा, 14. एक वर्ष में गर्म जल से बीस बार नहाने की व्यवस्था, 15. कपड़े सिलाने की व्यवस्था तथा 16. मुफ्त बिजली।⁴⁸ ये सुविधाएँ उस समय कुछ आदर्श कम्यून व्यवस्थाओं के लिये ही उपलब्ध थीं।

कम्यून दिनचर्या का प्रारम्भ प्रातः कालियों में लाउडस्पीकर की आवाज से होता था। यह आवाज व्यक्तियों को जगाने के लिये की जाती थी। आधे घंटे सुली हवा में व्यायाम के उपरान्त सामूहिक नाचना, तदुपरान्त व्यक्तियों का विभिन्न कार्य समूहों में विभक्त होकर खेत या कारखाने के कार्य पर जाना था। यह आवश्यक नहीं था कि एक परिवार के सदस्य एक ही समूह में रहे। दोपहर सभी भोजन के लिये एकत्रित होते थे। यदि कार्य स्थान अधिक दूर है तो वही भोजन भेज दिया जाता था। भोजन में चावल, भोटे आलू तथा कभी-कभी छोटा भात प्रादि दिया जाता था। भोजन करने के बाद फिर कार्य पर प्रस्थान करना था। सायनाल कक्षाएँ लगनी थीं जहाँ सभी व्यक्तियों को रेडियो तथा शय्याओं की खबरें सुनाई जाती थीं। उसके उपरान्त सिनेमा या नाटक या सर्विस जैसे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे।

47. Clubb, Edmund, 20th Century China, p. 356, pp. 357-58.

48. Chandrashekar, S., and Others, A Decade of Mao's China, pp. 31-32.

ग्रन्थ में साम्यवादी दल की बैठक होती थी जिसमें सभी श्रमिक भाग लेते थे। यह दिनचर्या का ग्रन्थ था। इसके बाद सभी को आठ घण्टे की निद्रा, विश्राम आवश्यक था।⁴⁹

शासकीयता—कम्यून निर्माण कार्य बड़ी ही जल्दगामी से किया गया। जुलाई 1958 में कम्यून कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ तथा लगभग पांच सप्ताह में ही चीन के बारह-बारह करोड़ ग्रामीण परिवारों को कम्यून प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया। इस प्रकार प्रारम्भ में कम्यून प्रणाली ठीक प्रकार से व्यवस्थित नहीं हो पाई।

कम्यून प्रणाली के अन्तर्गत मनुष्य से पशु की तरह काम लिया जाता है। मनुष्य को कार्य रचि का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। उनसे सेती, कारखाने, पहाड़ों की तोटना, बोगले की खानों में कार्य आदि सभी करवाया जाता है। एक कम्यून में काम करने वाला व्यक्ति एक ही शाय किसान है, श्रमिक है, सैनिक है।⁵⁰ इसके अतिरिक्त कम्यून में काम करने वालों को पर्याप्त विश्राम भी नहीं मिलता। उन्हें प्रतिदिन 12-14 तथा कभी-कभी 20 घण्टे कार्य करना पड़ता है। इस परिस्थिति में जब व्यक्ति को शारीरिक विश्राम का पूर्ण समय नहीं मिल पाता तब इस प्रकार के व्यक्ति से किसी भी प्रकार का चिन्तन करने की कल्पनाव्यर्थ होगी। कम्यून प्रणाली में कार्य करने वाला व्यक्ति चीनी साम्यवादी नेतृत्व तथा नयी तुली विचारधारा के पीछे अन्धी भेड़ चाल चलने तथा अनुकरण करने वाला व्यक्ति ही बन सकता है और वास्तव में चीनी साम्यवादी ऐसे ही स्तर का व्यक्ति चाहते हैं। यही उनकी योजना और कल्पना में फिट हो सकती है।

कम्यून प्रणाली मानव प्रवृत्ति के प्रतिकूल है। परिवार तथा सम्पत्ति अर्जन मानव से स्वभावतः सम्बद्ध है। कम्यून-जीवन परिवार प्रथा तथा सम्पत्ति संस्था का उन्मूलन है। साम्यवाद, राष्ट्रवाद, आदि के प्रचार द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क को सफाई द्वारा विचार परिवर्तन कर उसे कम्यून जीवन के उपयुक्त बनाया जाता है। उसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता। मनुष्य की मनोवृत्ति फिर भी विद्रोह कर दे तो शक्ति का प्रदर्शन उसे कम्यून साधे में ढालने के लिये पर्याप्त है। यदि मनुष्य को थोड़ा भी स्वतन्त्र वातावरण प्रदान किया जाय तो वह इस प्रकार के कठोर, नियन्त्रित समूहवादी जीवन में कभी भी रहना पसन्द नहीं करेगा।

आर्थिक प्रगति एवं पहल (initiative) के लिये व्यक्ति को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन भी आवश्यक है। यह प्रोत्साहन उसे कुछ उचित लाभान् या अपने उत्पादन का कुछ भाग देकर भी दिया जा सकता है। कम्यून प्रणाली में प्रोत्साहन और लाभान् आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप साग-सब्जी उत्पादन तथा

49. Ibid, p. 31.

50. Clark, Gerald, Impatient China: Red China Today, p. 91.

मात की पूर्ति में काफी नमी आयी। वहीं-वहीं व्यक्तियों ने अपने उत्पादन को युग कर रचना प्रारम्भ कर दिया।

कम्यून प्रणाली का रूस तथा चीन के प्रारम्भिक मतभेदों में वृद्धि करने में भी योगदान रहा है। रूस के साम्यवादी युद्धजीवियों तथा दल के नेतृत्व ने चीनी कम्यून व्यवस्था को अल्पाधिकारिक एवं बेहूदा बनाया है। उनका विचार है कि रूस में जब यह प्रणाली अस्तित्व रही फिर चीन में सफल होना संदिग्ध है।

चीन के साम्यवादी नेतृत्व ने कम्यून प्रणाली की नुटिया का अध्ययन किया है तथा जहाँ तक सम्भव हो गया है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उसे अधिक व्यावहारिक बनाने का प्रयत्न किया। किन्तु अब यह निश्चित है कि कम्यून प्रणाली चीन की आर्थिक व्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। इस समय चीन में लगभग 80000 कम्यून आधीन क्षेत्र में हैं। इनके द्वारा बड़ा-बड़ा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

चीन के साम्यवादी दल की अपनी कम्यून व्यवस्था पर बड़ा गर्व है। उनका विश्वास है कि यह व्यवस्था जो रूस में सफल नहीं हो सकी चीन इस इस क्षेत्र में रूस से कहीं आगे बढ़ गया है। अतः से अधिक जनसंख्या को कम्यून प्रणाली के अन्तर्गत लाने में उनकी कल्पना है कि सम्पूर्ण देश को एक बृहद् कम्यून बनाया जाय।

कम्यून व्यवस्था के माध्यम में चीनी साम्यवादी कुछ दूरगामी राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। उनका विचार है कि यदि सभी खेतिहर लोग सामूहिक भाजन करेंगे, उनके बच्चों का कुम्भक बाल-मूहों में जो आवश्यकता पारन किया जायेगा उससे परम्परागत परिवार प्रणाली अथवा अति-जीवित नहीं रह सकेगी तथा व्यक्तियों की श्रद्धा तथा प्रेम को आकर्षण करने वाली समय में हलपूर्ण बटोर बड़ी एवं केन्द्र समाप्त हो जायेगा। ऐसे नागरिक साम्यवादी व्यवस्था के अतिरिक्त अनुकूल होंगे तथा शुद्ध मार्क्सवादी आदर्श साम्यवादी समाज की उपनिधि में स्थायक शाय।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद

■ माओ त्से-तुंग के साम्यवादी विचार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही हैं। उन्होंने प्राचीन चीन की गरिमा एवं प्रभुत्व तथा साम्यवादी उन्नति का सम्मन्धन किया है। वे किसी भी राज्य के अन्तर्गत चीन की स्थिति स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए वे एक साम्यवादी महाशक्ति रूस में सैद्धान्तिक एवं राजनीतिक सहायता ले रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में माओ विश्व साम्यवाद में भी विश्वास रखते हैं। वे चीन में साम्यवादी ज्ञानि को विश्व ज्ञानि का ही एक अंग मानते हैं। साम्यवादी चीन के प्रसार कई राज्यों में बड़ा की सरकारों के विरुद्ध विद्रोह का साहजान करते हैं। उनके विचारों के ही कारण विश्व के लगभग सभी राज्यों में चीन सम्बन्धित साम्यवादी दल हैं। माओ त्से-तुंग के साम्यवादी विचार का प्रमुख केन्द्र एशिया है। इन विचारों की

अभिव्यक्ति, सम्भवतः माओ रचित वह कविता, जिसका शीर्षक—East is Red—है, सं होता है, जिसे चीन द्वारा भेजा गया अन्तरिक्ष यान निरन्तर प्रसारित कर रहा था।

माओवाद का मूल्यांकन

चीन के अतिरिक्त विश्व के कई भागों में माओवाद के समर्थक हैं। वे माओवाद को मार्क्सवाद-लेनिनवाद-स्टालिनवाद के आगे की एक कड़ी मानते हैं। किन्तु माओ स्ले-तुंग को एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ चिन्तक की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। उनके विचारों में राजनीतिक दर्शन जैसी कोई बात नहीं है। उनका चिन्तन कुछ व्यावहारिक विचार, कुछ नयी साम्यवादी अश्रावली, कुछ वयोटुड जैसी शिक्षाओं का संकलन है।

माओवाद के समर्थकों का यह दावा भी सदिग्ध है कि माओ ने मार्क्सवादो विचारधारा को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वास्तव में माओवाद में मौलिकता का अभाव है। माओ स्ले-तुंग ने जो कुछ भी कहा है उसका अधिकांश भाग चीन में विचार या व्यवहार के क्षेत्र में पहले ही व्यक्त किया जा चुका है। माओ स्ले-तुंग ने उन्हें या तो मार्क्सवादी आवरण पहना दिया है या चीन की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप उनका विवेचन प्रस्तुत किया है।

एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ और नेतृत्व की दृष्टि से माओ स्ले-तुंग सफलतम व्यक्ति बड़े जा सकते हैं। चीन में साम्यवादी शान्ति का संगठन करना; विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश में साम्यवादी शान्ति को सफल बनाना, तदुपरान्त चीन को एक महाशक्ति के स्तर तक लाना, पूर्ण देश को अपने गैंगूठे के नीचे दबा कर रखना और इस प्रकार लगभग आधी शताब्दी तक चीन पर एक छत्र की भाँति छाये रहना किसी असाधारण व्यक्ति का ही कार्य हो सकता है। चीन में माओ स्ले-तुंग का वही स्थान रहेगा जो रूस में लेनिन का है।

साम्यवाद के अन्य प्रमुख पक्ष

लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद आदि के अध्ययन से साम्यवाद के कुछ विशिष्ट सिद्धान्त स्पष्ट हो जाते हैं। किन्तु साम्यवाद के कुछ अन्य सामान्य पक्ष भी हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। अगले पृष्ठों में साम्यवाद के कुछ और प्रमुख पक्षों का विवेचन प्रस्तुत है।

शक्ति ही राजनीति

साम्यवादी साधन: शान्ति एवं शक्ति राजनीति (1)

सम्पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था का केन्द्र शक्ति है। प्रारम्भ से लेकर जब तक वर्ग विहीन और राज्य विहीन साम्यवाद की स्थापना नहीं हो जाती, जो कभी कल्पना है, साम्यवादी विचारधारा शान्ति एवं शक्ति-साधनों पर आधारित है। पूँजीव्यों और सर्वहारा वर्ग में शक्ति संघर्ष आदि का आधार शक्ति ही है। पूँजीवादी ढाँचे का उन्मूलन करने के लिए सभी रक्तपात तथा शान्ति में विश्वास करते हैं।

साम्यवादी घोषणा पत्र की अन्तिम पंक्तियों में उल्लेख किया गया है कि साम्यवादी अपने उद्देश्या की प्राप्ति शक्ति द्वारा करना चाहते हैं। शक्ति द्वारा ही वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। लेनिन का शक्ति एवं शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनके मतानुसार ही सर्वप्रथम सफल साम्यवादी शक्ति रूस में हुई। पूँजीवाद की समाप्ति के लिये ही शक्ति की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सर्वहारा वर्ग को सत्ता में वनाय रखने, विरोधियों का दमन करने आदि सभी के लिए लेनिन ने शक्ति अर्जन और प्रयोग का समर्थन किया। लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग शक्ति में विश्वास करता है। सन्तुलन काल में सर्वहारा अधिनायकत्व द्वारा राज्य-यन्त्र का प्रयोग इमरिज किया जाता है क्योंकि यह सत्ता शक्ति का स्रोत है जिसकी आवश्यकता किन्हीं अर्थों में उद्देश्या की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।⁵¹ प्रसिद्ध मजदूर-कार कमानेव (Kamanev) ने लिखा है कि शक्ति को सत्ता हस्तगत करने के लिए तो उपयुक्त स्वीकार करना ही है, परन्तु जो समुदाय साम्यवादियों से पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं उनमें आत्मरक्षा के लिए उसे साधन न मानना मूर्खता होगी।⁵²

इसी प्रकार स्टालिन ने भी शक्ति एवं शक्ति के रिषय में विचार व्यक्त किये हैं। स्टालिन ने अपने शासन काल में बल-प्रयोग खुल कर किया। समस्त विरोधियों को निष्क्रिय या मौत के घाट उतार दिया गया। फरवरी 1956 में साम्यवादी दल के धीसरे अधिवेशन में स्टालिन की निंदा करते हुए ख्रुश्चेव ने कहा कि स्टालिन ने देश में भय-शासन (Reign of terror) स्थापित कर रक्खा था। माओ त्स तुंग का प्रसिद्ध कथन कि 'सत्ता शक्ति से प्राप्त की जाती है,' सर्व-विदित है।

साम्यवादी दल

साम्यवादी शासन एक-दलीय व्यवस्था होती है। इसके अन्तर्गत विरोधी दल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। इस शासन व्यवस्था में साम्यवादी दल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यह सत्ताधारी दल होता है। राजनीतिक गतिविधियों, विवाद, परिचर्चा आदि का मुख्य फोरम साम्यवादी दल ही रहता है। साम्यवादी शक्ति, विरोधी विचारधारा का उन्मूलन, राज्य सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण जनता को दलीय विचारधारा से अवगत कराने आदि का उत्तरदायित्व साम्यवादी दल पर ही होता है। इसलिये साम्यवादी राज्यों के सविधानों में इस दल की विशेष स्थिति का सदैव ही उल्लेख किया जाता है। मोरिषियस के सविधान में यह लिखा गया है कि शक्ति वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए देश समस्त राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक समुदाय एवं सध साम्यवादी दल द्वारा एकता के सूत्र में बन्धे हुए हैं।⁵³

51 Lenin, *Imperialism The State and Revolution*, Vanguard Press, New York, 1926, pp 27-28

52 Kamanev, *The Dictatorship of the Proletariat*, 1920, p 12

53 अनुच्छेद- 26.

साम्यवादी समाज के निर्माण संघर्ष में यह धर्मजीवियों का अग्रणीय (या पथ प्रदर्शक) है तथा धार्मिक संगठनों, राजकीय या सार्वजनिक, का प्रधान केन्द्र स्थान है।⁵³ किन्तु दल की भूमिका एव सक्रियता उस राज्य के नेतृत्व के ऊपर निर्भर करती है। स्टालिन के कार्य-काल में साम्यवादी दल सदैव ही ऊपर से नियन्त्रित रहता था तथा तानाशाह की इच्छाओं को कार्यान्वित करने का एजेण्ट-मात्र था।⁵⁴

साम्यवादी दल व्यवहार में राज्य के भीतर एक समानान्तर राज्य के रूप में कार्य करता है। हेरॉल्ड जिंक के मतानुसार सोवियत रूस में साम्यवादी दल और राज्य का विषय है यद्यपि दल और राज्य के कार्य अलग-अलग हैं, दोनों की अभिन्नता इतनी पूर्ण है कि यह कह सकना सम्भव नहीं है कि दल के कार्यों का अन्त और सरकार के कार्य-क्षेत्र का प्रारम्भ कहाँ से होता है।⁵⁵

यूगोस्लाविया के बिद्रोही साम्यवादी नेता एवं विचारक मिलोवेन जिलास (Milovan Djilas) ने साम्यवादी राज्य को 'पार्टी राज्य' (The Party State) की सजा दी है। उनके स्वयं के ही शब्दों में—

“साम्यवादी शक्ति-यंत्र बिल्कुल साधारण है जो शुद्ध निरंकुशता तथा अत्यन्त कठोर शोषण की ओर अग्रसर करता है। इस शक्ति-यंत्र का अन्वय इस तथ्य से होता है कि सिर्फ एक ही दल-साम्यवादी दल-सम्पूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सैद्धान्तिक गतिविधियों का मूल आधार है। सम्पूर्ण सार्वजनिकजीवन का एक स्थान पर बना रहना, आगे बढ़ना, पीछे जाना या मुड़ना यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि दल में क्या हो रहा है।”⁵⁶

साम्यवादी दल के सदस्यों का महत्व एवं शक्तियों की व्याख्या करते हुए मिलोवेन जिलास ने कहा है कि इससे एक 'नये वर्ग' (The New Class) का प्रादुर्भाव हुआ है।⁵⁷ मुनरो (William Munro) ने इसे 'राज्य का कुलीनवर्ग' (Aristocracy of the state) नाम से सम्बोधित किया है।⁵⁸

व्यक्ति-पूजा (Cult of Personality) (3)

सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व साम्यवादी दल करता है; दल के अधिकार कुछ अग्रणीय सदस्यों के सामूहिक नेतृत्व में निहित रहते हैं; सामूहिक नेतृत्व व्यवहार में एक व्यक्ति की तानाशाही के अभाव और कुछ नहीं। सैद्धान्तिक रूप में सर्वहारा वर्ग

54. Munro, W. B. and Aycarst., The Governments of Europe, p. 691.

55. Zink, Harold, Modern Governments, D. Van Nostrand Co., New York, 1958, p. 571

56. Milovan Djilas., The New Class, An Analysis of the Communist System, Thames and Hudson, London 1957, p. 79.

57. The New Class, जिलास की पुस्तक के तृतीय अध्याय का शीर्षक है।

58. Munro and Aycarst., The Governments of Europe, p. 683.

व साम्यवादी दल पूजनीय है। लेकिन सामूहिक नेतृत्व में जैसे ही किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति का अभ्युदय हुआ, वह सब सत्ता का स्रोत बन जाता है। जैसे ही यह व्यक्ति कुछ लम्बे समय तक सत्ता में टिक जाता है तो उसकी पूजा और प्रशंसा होने लगती है जिसे हम व्यक्ति-पूजा (Cult of personality) कहते हैं। स्टालिन और माओ त्से-तुंग की व्यक्ति-पूजा' घससिग्घ है। स्टालिन के लिए प्रशंसा गीतों और कविताओं का सृजन हुआ जिनमें उसे महान् एव ईश्वर तुल्य माना गया। हम के प्रसिद्ध कवि जेम्बॉल जेबाए (Djamboul Djabaev) की कविता स्टालिन की व्यक्ति-पूजा का ज्वलन्त उदाहरण है। इस कविता का अर्थ इस प्रकार है—

मैं उसकी समता पर्वत से करता—

किन्तु पर्वत के शिखर है,

मैं उसकी समता समुद्र से करता—

किन्तु समुद्र के सतह है,

मैं उसकी समता चमकीले चन्द्रमा से करता—

किन्तु चन्द्रमा अर्धरात्रि में ही चमकता है, दोपहरी में नहीं,

मैं उसकी समता प्रतिभावाप् सूर्य से करता—

किन्तु सूर्य दोपहरी में ही प्रकाश देता है, मध्यरात्रि में नहीं।

इसी तरह सोवियत साम्यवादी दल के मुखपत्र प्रावदा (Pravda) के अगस्त 28, 1936, के अंक में प्रकाशित कविता—

O great Stalin, O leader of the peoples

Thou who broughtest man to birth,

स्टालिन पूजा ही थी जिसका पाठशालाओं आदि में स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता था।⁵⁹ स्टालिन-पूजा की निन्दा करते हुए 1956 में सोवियत साम्यवादी दल कांग्रेस के बीचवें अधिवेशन में निन्ता ख्रुश्चेव ने कहा—

“इस समय हम उस प्रश्न से अधिक सम्बन्धित हैं, जो दल के वर्तमान और भविष्य के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है, कि स्टालिन-पूजा का किस प्रकार विकास हुआ और एक निश्चित समय पर वह इस सीमा तक बढ़ गई, जिसने दल के सिद्धान्तों, दल का लोकतन्त्र और शान्ति की वैधानिकता को गम्भीर रूप से छुट्ट कर दिया।”⁶⁰

⁵⁹ Quoted Hollowell, J. H., *Main Currents in Modern Political Thought*, p. 514

⁶⁰ निन्ता ख्रुश्चेव का यह भाषण Supplement, *Freedom First*, July 1956, में न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times) की स्वीकृति से अमरीकी विदेश विभाग ने प्रकाशित किया।

यही स्थिति चीन में मामो त्से-तुंग की है। 'स्टालिन की तरह मामो भी भव सार्वजनिक व्यक्ति नहीं रहे, वे भ्राति बन गये हैं। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वे कहा रहते हैं; उन्हें केवल पीकिंग के भ्रमण ही महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को छोड़कर, सम्भवतः ही वही देखा जा सकता है। इस पर भी सभी को यह धारणा कराया जाता है कि वे चीन में साम्यवादी शासन के मार्ग-दर्शक हैं। उनकी तस्वीरें प्रत्येक घर और सार्वजनिक भवनों को सुशोभित करती हैं।⁶¹ वे अब चीनी जनता के देव-तुल्य एवं पैगम्बर बन गये हैं। उनके लिये भी गीतों और प्रार्थनाओं का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित कविता मामो-स्तुति के रूप में बहू लोकप्रिय है—

The East Shines red,
the Sun arises,
Mao Tse-tung appears in China,
Toiling for the happiness of the people;
The savior of the people.⁶²

अर्थात्, 'पूर्व में साम्यवाद का विस्तार हो चुका है, सूर्य की भूमि मामो त्से-तुंग का प्रादुर्भाव थमिको की सुशहाली और जनता के संरक्षक के रूप में हुआ।' वास्तव में व्यक्ति पूजा साम्यवादी व्यवस्था का एक अंग बन गई है। व्यक्तिपूजा व्यक्तिगत तानाशाही की अभिव्यक्ति के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं।

साम्यवाद व राज्य (Communism and State)

साम्यवादी विचारधारा में राज्य बुराई माना जाता है किन्तु विशेष परिस्थिति में वे राज्य की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। राज्य के विषय में साम्यवाद के निम्नलिखित दृष्टिकोण हैं—

प्रथम, साम्यवादियों के अनुसार राज्य पूंजीवादी राज्य है, जिसके माध्यम से वे थमिकों का शोषण करते हैं। राज्य के कानून पूंजीपतियों की शोषण इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। वर्ग संघर्ष में राज्य पूंजीपतियों की सहायता करता है। जब तक राज्य का अस्तित्व है वर्ग-द्वेष समाप्त नहीं हो सकता।

द्वितीय, साम्यवादी राज्य को समाप्त करना चाहते हैं—किन्तु पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य संक्रमण काल में वे राज्य-सत्ता का अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयोग करना चाहते हैं। संक्रमण काल में सर्वहारा-अधिनायकत्व राज्य-शक्ति द्वारा विशेषियों या बलपूर्वक दमन करके साम्यवादी मार्ग की ओर प्रवृत्त करेगा।

61. Walker, Richard L., *China Under Communism*, George Allen & Unwin, London, 1956, pp. 180-81.

62. *Ibid.*, p. 181.

तृतीय, राज्य का महत्व केवल सत्रमण काल में ही है। वे राज्य की स्थाई संस्था नहीं मानते। उनकी धारणा है कि जैसे ही साम्यवादियों की कल्पना के समाज की रचना प्रारम्भ हो जायेगी राज्य धीरे-धीरे स्वयं ही समाप्त हो जायेगा।

उपर्युक्त तीन दृष्टिकोणों में प्रथम एवं द्वितीय ही साम्यवाद के सन्दर्भ में सही हैं। तृतीय दृष्टिकोण जिसमें साम्यवादी राज्य के लोप होने की बात कहते हैं व्यवहारिक नहीं हो सकता। सर्वहारा अधिनायकत्व की अस्थाई अवधि एक 'दीर्घ ऐतिहासिक युग' भी हो सकता है।⁶³ यदि साम्यवाद को हम मानसंबाध या वैज्ञानिक समाजवाद का व्यावहारिक पक्ष कहते हैं तो राज्य के लोप होने की बात साम्यवाद के अन्तर्गत नहीं आती।

साम्यवाद तथा जनतन्त्र

साम्यवाद में जनतन्त्र व्यवस्था का क्या स्थान है? इस बात पर साम्यवादों तथा अन्य जनतान्त्रिक विचारधाराओं में मूल मतभेद हैं। साम्यवादी पश्चिमी देशों में प्रचलित जनतन्त्र को वास्तविक जनतन्त्र नहीं मानते। यह पूँजीवादो जनतन्त्र है, यह निर्धनों का नहीं धनिकों का जनतन्त्र है। इसी प्रकार वे समदीय प्रणालियों को भी बर्बात तथा पूँजीवादी सदन कह कर उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन यदि साम्यवादी पश्चिमी जनतन्त्र की निन्दा करते हैं तो साम्यवादी व्यवस्था स्वयं किसी भी दृष्टि से जनतान्त्रिक नहीं है।⁶⁴ साम्यवादी राज्य आर्थिक जनतन्त्र प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करते हैं, किन्तु राजनीतिक जनतन्त्र से वे बड़ी दूर रहते हैं। साम्यवादी राज्यों में न तो विरोधी विचारधारा पनप सकती है और न विरोधी दल ही। यहाँ तक कि साम्यवादी दलों में भी आन्तरिक जनतन्त्र का पूर्ण अभाव रहता है।

सैद्धान्तिक रूप से भी साम्यवादी व्यवस्था शक्ति एवं सत्ताशाही से पूर्णतः बंधी हुई है। दण-संधर्ष तथा पूँजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन के लिये क्रान्तिकाल में जनतान्त्रिक व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता। सत्रमण काल में वे स्वयं ही सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात करते हैं। इसके बाद की व्यवस्था जिसे वे साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं, अभी तक सिर्फ आदेश और कल्पना ही है। अतः इस विचारधारा के अन्तर्गत व्यापक जनतन्त्र के लिये बहुत कम क्षेत्र शेष रहता है।

साम्यवाद एक विस्तारवादी विचारधारा के रूप में

साम्यवाद प्रकृति से ही एक विस्तारवादी विचारधारा है। इसकी कोई सीमा या कोई मर्यादा नहीं है। जॉर्ज केनन (George Kennan) ने, जो साम्यवादी जगन के अमरीकी विशेषज्ञ है, यह विचार प्रतिपादित किया कि "साम्यवाद विस्तारवाद में

⁶³ बोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 194.

⁶⁴ इसके लिये देखिये जोड, पृ 101-103

विश्वास करता है।" जॉर्ज केनन के ये विचार रूस के सम्बन्ध में थे, किन्तु यह अन्य साम्यवादी राज्यों, विशेषतः चीन पर पूर्णतः लागू होते हैं।⁶⁵

साम्यवादी विचारधारा विस्तार के दो प्रमुख पक्ष हैं। प्रथम, जिस राज्य में साम्यवाद शासन की स्थापना हो चुकी है उस राज्य के अन्दर किसी अन्य विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जाता। तब साम्यवाद का ही अनुमोदन, विमोचन ही सकता है। और इसमें भी नेतृत्व के विचार ही सही समझे जाते हैं। स्टालिन को उसके कार्यकाल में मार्क्सवाद और साम्यवाद का सही विमोचनकर्ता समझा जाता था। उसके शब्द ही समाजवाद थे।⁶⁶ चीन में माओ त्से-तुंग के विचारों (Thought of Mao Tse-tung) को थोड़ा विज्ञान और मूल दर्शन माना जाता है।⁶⁷ यही बात आजकल उत्तर कोरिया के साम्यवादी नेता किम इल सुंग (Kim IL Sung) के विषय में कही जानी है। ये भी मार्क्सवाद-लेनिनवाद में परिवर्धन कर रहे हैं।

द्वितीय पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय है। एक बार सत्ता में आने के बाद साम्यवादी शेष विश्व का पुनः निर्माण अपनी इच्छानुसार करने का प्रयत्न करते हैं।⁶⁸ इस्ताम की भाँति साम्यवाद आक्रामक विचारधारा (offensive ideology) है। साम्यवादी युद्ध और शक्ति द्वारा विचारधारा का प्रचार और प्रसार अपना कर्तव्य समझते हैं।⁶⁹ मार्क्स ने साम्यवाद का अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में ही प्रतिपादन किया था। विश्व वर्ग-संघर्ष मार्क्सवाद की प्रमुख विशेषता थी। इसलिये उसने विश्व के समस्त मजदूरों के लिए एकता का आह्वान किया था। उसके अनुसार श्रमिकों का न तो कोई देश है और न कोई राष्ट्रियता। साम्यवाद एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता।⁷⁰ समस्त विश्व साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत आना चाहिए।

साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस सिद्धान्त का समय समय पर पूर्ण समर्थन किया। 1919 में कमिन्तर्ने (Comintern or Third Communist International) की स्थापना का उद्देश्य रूस की भाँति अन्य राज्यों में शक्ति का नेतृत्व करना था। 1928 में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Comintern) के विश्वसम्मेलन में सम्पूर्ण विश्व में पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था।⁷¹ जब साम्यवादी राज्य अपनी सैनिक शक्ति

65 द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त रूस ने पूर्वी यूरोप के राज्यों का जब साम्यवाद-करण प्रारम्भ किया उस समय जॉर्ज केनन ने यह विचार प्रतिपादित किया था।

66 Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political Thought, p. 514.

67 Walker, Richard L., China Under Communism, p. 180.

68 Djilas, Milovan, The New Class, p. 1.

69 Straus-Hupe and Possény, International Relations, 1950, p. 423

70 The Communist Manifesto, p. 71.

71 Burns, Emile, (Ed.) A Hand-book of Marxism, London, 1935, p. 964

म वृद्धि कर विश्व-शक्तियों की श्रेणी में आ जाते हैं, इसमें विश्व में साम्यवादी प्राश्नमण तथा विस्तार का भय और भी बढ़ जाता है।⁷²

साम्यवादियों ने अपने इस दृष्टिकोण में समय समय पर परिवर्तन किया है। यह विवाद का विषय भी रहा है। स्टालिन व ट्रॉट्स्की का सघर्ष इसी परिवर्तन में देखा जा सकता है, जिसमें स्टालिन के 'एक देश में समाजवाद' की विजय हुई। किन्तु कॉमिनटर्न का अस्तित्व यथावत् बना रहा। तात्कालिक युद्ध स्थिति को देखते हुए कॉमिनटर्न को मई 22, 1943, को गगन कर दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि रूस या अन्य साम्यवादियों ने अपना अन्तर्राष्ट्रीय चोला सदैव के लिए उतार दिया हो। उसे सिर्फ कुछ समय के लिए शीत-युद्ध में सुरक्षित रखा दिया गया। अक्टूबर 5, 1947 को अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद को कॉमिनफॉर्म (Cominform or Communist Information Bureau) के नाम से पुनः संगठित किया गया किन्तु यूगोस्लाविया से सम्बन्ध सुधारने की उत्सुकता में इसे भी समाप्त कर दिया।

इसी समय निकिता ख्रुश्चेव ने पत्रशोल या शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व (Peaceful Co-existence) के सिद्धान्तों का समर्थन देना प्रारम्भ किया। इसका पुनः यही अर्थ लगाया जा सकता था कि साम्यवादी विश्व में यथा-स्थिति (Status quo) स्वीकार कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक प्रणालियों के अन्तर्गत रहते हुए भी विश्व के राज्य शान्तिपूर्ण सहयोग कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में साम्यवादी दुरगो जाती (double talks) और घोषा देने में अधिन उलझे प्रतीत होते हैं। उनके दृष्टिकोण में समय समय पर जो परिवर्तन हुए हैं, वे सिर्फ चाल या राजनीतिक दाव पेश के रूप में ही हुए हैं, अन्तर्गत साम्यवाद को स्थापने के लिए नहीं। सह-अस्तित्व की बात राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, दूसरे देशों से आर्थिक सहयोग, व्यापार या मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिये ही नहीं जाती है।⁷³ इतना अवश्य है कि साम्यवादी अथवा यह स्वीकार करने लगे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद अन्ति के द्वारा शासक सम्भव नहीं है। यह बस ख्रुश्चेव के विचार, जिसमें पूँजीवादी राज्यों के साथ शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात बड़ी गई है, के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। साम्यवादी स्थिति के अनुसार कभी भी शान्ति या शान्तिपूर्ण साम्यवादी प्रसार में विश्वास कर सकता है।

(7) राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध (Wars of National Liberation)

पराधीन राज्यों द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति तथा स्वाधीनता के लिये सघर्ष एवं युद्ध के लिये आह्वान करना तथा उन्हें समर्थन प्रदान करना साम्यवादी विचारधारा का एक प्रमुख तत्व बन गया है। यद्यपि माक्स ने इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष विचार प्रस्तुत नहीं किये तथा लेनिन ने राष्ट्रीय विद्रोह के समर्थन में विचार व्यक्त किये, किन्तु इस

72 Jay, Douglas, Socialism in the New Society, pp 77

73 Muntro and Aycarst, The Governments of Europe, p 695.

दिशा में निकिता ख्रुशचेव ने सर्वप्रथम स्पष्टतः अपने विचार व्यक्त किये। 1961 में ख्रुशचेव ने मुक्ति-युद्ध या स्वाधीनता संघर्ष की व्यापक व्याख्या की। मुक्ति-युद्ध या स्वाधीनता संघर्ष का तात्पर्य एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीकी राज्यों द्वारा उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादी राज्यों के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करते रहना है। साम्यवादी ऐसे संघर्ष एवं युद्ध को पूर्णतः उचित बतलाते हैं। यह पराधीन राज्यों की जनता का कर्तव्य है कि वे पूंजीवादी-उपनिवेशवादी-साम्राज्यवादी श्रेणियों से स्वयं को संघर्ष द्वारा मुक्त करें। चीन में एक समय माओ त्से-तुंग के उत्तराधिकारी लिन पियाओ (Lin Piao, 1910-1971) ने भी एक दूसरे सन्दर्भ में ऐसे ही विचारों का प्रतिपादन किया। विश्व विजय के उद्देश्य से लिन पियाओ ने एक मुक्ति मुभाई थी जिसका तात्पर्य एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीकी राज्यों की जनता पूंजीवादी श्रेणियों द्वारा समर्थित सरकारों के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष द्वारा देहाती शोषण पर अधिकार कर नगरो को घेर लेना चाहिये तथा बाढ़ में शहरों पर अधिकार कर सम्पूर्ण राज्य को प्रतिक्रियावादियों से मुक्त कर लेना चाहिये। जयप्रद सभी उग्रवादी साम्यवादी मुक्ति संघर्ष एवं स्वाधीनता के लिये युद्ध का समर्थन करते हैं।

राष्ट्रीय मुक्ति युद्ध द्वारा साम्यवादी विश्व को साम्यवादी प्रणाली के अन्तर्गत लाने के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं। परमाणु युग में इन विचार का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। परमाणु युग में साम्यवादी तथा पूंजीवादी राज्यों द्वारा युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। इस स्थिति में साम्यवादी राष्ट्रीय मुक्तियुद्ध द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति करने का विचार रखते हैं। ऐसे संघर्ष एवं युद्ध में साम्यवादी राज्य प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित तो नहीं होंगे किन्तु संघर्षरत जनता की सहायता एवं समर्थन करते रहेंगे। वियतनाम युद्ध, अफ्रीका में पुर्तगाली उपनिवेश अंगोला तथा मुजान्बिक में स्वाधीनता संग्राम तथा कई लेटिन अमरीकी राज्यों में गुरिल्ला संघर्ष को साम्यवादी राष्ट्रीय मुक्तियुद्ध मानते हैं।

साम्यवादी विचारधारा बनाम राष्ट्रीय हित [8]

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद की समस्याएँ तथा रूस-चीन के सैद्धान्तिक मतभेदों के सन्दर्भ में साम्यवादी विचारधारा एवं राष्ट्रीय हित में प्राथमिकता के प्रश्न को समझ लेना आवश्यक है। एक साम्यवादी राज्य के लिये विचारधारा का विस्तार महत्वपूर्ण है या उसका स्वयं का राष्ट्रीय हित? यदि विचारधारा को प्राथमिकता दी जाय तो प्रत्येक साम्यवादी राज्य का कर्तव्य है कि वह दूसरे देशों में साम्यवाद का विस्तार करे, विचारधारा के प्रसार में सभी साम्यवादी राज्य सहयोग करे। किन्तु व्यवहार में यह बात नहीं है।

प्रत्येक राज्य, साम्यवादी या गैर-साम्यवादी, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि महत्व देता है। साम्यवादी राज्यों में यदि हितों का टकराव है तो विचारधारा की एकता होते हुए भी उनमें सहयोग नहीं हो सकता और इसका साम्यवाद की

अन्तर्राष्ट्रीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रूस और चीन दोनों ही साम्यवादी देश हैं लेकिन दोनों के परस्पर-विरोधी हितों के कारण वे विचारधारा को उतना महत्व नहीं देते जितना कि राष्ट्रीय हित को।

इसके अलावा यदि दो विरोधी विचारधाराओं के पालन करने वाले राज्यों में राष्ट्रीय हितों का समाधान होता है तो वे विचारधारा को सहयोग के मार्ग में बाधा नहीं बनने देते। चीन और अमेरिका परस्पर-विरोधी विचारधाराओं के समर्थक हैं, लेकिन रूस व विरुद्ध दोनों के सहयोग में वृद्धि हो रही है। इसके पहले 1939 में रूस और नाजी जर्मनी ने अनामक संधि पर हस्ताक्षर किये, जिसने दूरदर्शी राजनीतिकों को भी आश्चर्य में डाल दिया। साम्यवाद और नाज़ीवाद दोनों ही एक दूसरे के बड़े शत्रु थे लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विचारधारा सम्बन्धी तथ्यों को तान पर रख यह समझौता किया। इसका यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि साम्यवाद का अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष उतना सबल नहीं है जितना कि समझा जाता है। साम्यवादी राज्यों में हमेशा सहयोग और भ्रातृत्व की भावना रहे, यह भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार राष्ट्रीय हित और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने साम्यवाद के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू को कमजोर एवं विभाजित कर दिया है।

रूस-चीन मतभेद तथा इसका साम्यवादी विचारधारा पर प्रभाव

रूस और चीन के मतभेदों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक नया तत्व प्रदान किया है। विश्व के प्रमुख राज्यों की विदेश नीति निर्धारण पर इसकी छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। दोनों पड़ोसी राज्य विश्व शक्तियाँ हैं, दोनों ही साम्यवादी व्यवस्थाएँ हैं। दोनों राज्यों में जो तनाव उत्पन्न हुआ उसे एक नवीन शीत-युद्ध (A new Cold War) कहा गया है।⁷⁴ इन मतभेदों का वास्तविक कारण दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों का टकराव है। किन्तु साम्यवादी होने के कारण रूस और चीन ने अपने मतभेदों को प्रारम्भिक वर्षों में सैद्धान्तिक मतभेदों के रूप में प्रस्तुत किया।⁷⁵ दोनों राज्यों ने सैद्धान्तिक पक्ष लेकर एक दूसरे की बड़े आलोचना की है। इसमें सैद्धान्तिक मतभेदों की वास्तविकता है या नहीं निश्चित रूप में कहना आसान नहीं। फिर भी इन मतभेदों के सन्दर्भ में साम्यवाद की जो व्याख्या हुई है वह महत्वपूर्ण है तथा इस विचारधारा की नवीन प्रवृत्ति एवं स्वभाव पर प्रकाश डालती है।

रूस और चीन के सैद्धान्तिक मतभेदों में रूस अधिक नमनीय, व्यावहारिक और प्रगतिशील प्रतीत होता है। चीन रुढ़िवादी या परम्परावादी मानसवाद-लेनिन्वाद-

74 एडवर्ड क्रैकशॉ (Edward Crakshaw), जो साम्यवादी राजनीति के एक प्रमुख टीकाकार हैं, की रूस-चीन विचार पर लिखी पुस्तक का शीर्षक ही—The New Cold War, Moscow V p kug— है।

75 Lowenthal, Richard, World Communism, p 132

स्टालिनवाद में ही उलझा है। माओ स्ते-तुंग तथा चीन के साम्यवादी दल ने खूबश्वेक के लक्षण सभी विचारों का छन्दन किया है। रूस द्वारा स्टालिन को जो निन्दा की गई है चीन ने उसे मान्यता नहीं दी है। यद्यपि स्टालिन ने कुछ भूलें भ्रवश्य की, चीन साम्यवादी जगत तथा रूस में स्टालिन के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। चीन के दृष्टिकोण से स्टालिन मार्क्सवाद-लेनिनवाद का बटूर समर्थक था। चीन साम्यवादी विस्तार के लिए शान्तिपूर्ण साधनों को मान्यता नहीं देता। माओ स्ते-तुंग खूबश्वेक के इस मत से गहमन नहीं है कि लोकतान्त्रिक तरीके से समाजवाद लाया जा सकता है। साम्यवादी प्रसार केवल शान्ति एवं युद्ध से ही सम्भव है।

दोनों साम्यवादी राज्यों का साम्राज्यवाद के प्रति भी अलग-अलग दृष्टिकोण है। चीन रूस के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि पूँजीवादी-साम्राज्यवादी शांति चाहते हैं। माओ के अनुसार साम्राज्यवादियों की प्रकृति में कोई आन्तरिक परिवर्तन नहीं हुआ है। समाजवादी देशों को उनके विरुद्ध संपर्क करने के लिए अधिक शक्ति-शाली बनना चाहिए। इसलिए चीन सर्वहारा राज्यों वा साम्राज्यवादी-पूँजीवादी राज्यों के साथ सह-अस्तित्व में विद्यमान नहीं करता।

चीन और रूस ने एक दूसरे की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना की है। चीन ने खूबश्वेक की वृत्ति नीति की आलोचना की जिसके अन्तर्गत रूस लाभ के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ता है। चीन के अनुसार लाभ सिद्धान्त पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था में ही सम्भव है। इसके विपरीत रूस ने चीन में प्रारम्भ हुई 'कम्यून प्रणाली' (Commune System) की बटु निन्दा की है।

इन सैद्धान्तिक मतभेदों के बाद इन दोनों राज्यों का वास्तविक संपर्क स्पष्ट हो गया है। उनके सीमा विवाद, उनकी एशिया और अफ्रीका में विस्तारवादी नीति तथा आर्थिक स्पर्धा से विश्व पुरातः अलग है।

रूस और चीन के सैद्धान्तिक विवाद का अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद पर व्यापक विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रथम, साम्यवाद की व्याख्या के विषय में साम्यवादी राज्य एक मत होकर निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। उनके विचारों में परस्पर-विरोध ही दृष्टिकोण होना है। इससे साम्यवाद का सैद्धान्तिक पक्ष निर्वृत हुआ है। द्वितीय, इस विवाद ने साम्यवादी राज्यों को दो भूटों में विभाजित कर दिया है। एक ओर चीन, अलबानिया आदि तथा दूसरी ओर रूस और अन्य पूर्वी यूरोप के राज्य हैं। कुछ राज्य, जैसे रूमानिया, लक्षण तटस्थ रहते हैं। साम्यवादी राज्यों की एकता समाप्त होने से इनकी शक्ति विभाजित हो चुकी है। इससे अन्तरसाम्यवादी राज्यों में साम्यवादी विस्तार के दृष्टि में भी भारी कमी आई है। तृतीय, रूस-चीन मतभेदों से विश्व में अन्य राज्यों के साम्यवादी दल भी विभाजित हुए हैं। दल का एक भाग रूस समर्थक तथा दूसरा चीन का प्रशंसक रहता है। भारत में इस आधार पर अलग अलग दल बन गये हैं, जैसे भारतीय साम्यवादी दल रूस समर्थक है तथा भारतीय

साम्यवादी दल (माकर्मवादी) चीन का गमयन है। जो भी हो इसमें दल की शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात हुआ है।⁷⁶ लेबेड्ज एवं अरुन (Labeledz and Urban) ने रूस-चीन मतभेदों का अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद पर प्रभाव का उल्लेख करके यह लिखा है कि इन विवाद ने—

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद आन्दोलन के अन्त का प्रारम्भ कर दिया है;
- (ii) समस्त विश्व की सर्वहारा राष्ट्रीयता की भावना का घण्टन कर दिया है, तथा
- (iii) साम्यवादी भावना के अन्वयम्भावों स्वल्प को मनास्त कर दिया है।⁷⁷ अन्वय में इन दोनों राज्यों के परस्पर-विरोधी हितों को ध्यान में रखते हुए इनमें सुनहला होना सम्भव था लगता है। किन्तु एक बात निश्चित है कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सन्दर्भ में चीन को भी रूस जैसा ही उदारवादी नमनीय नीति अपनाती पड़ेगी। चीन को भी सह-अस्तित्व, सहयोग, सहस्य राज्यों का समर्थन आदि की नीति ग्रहण करनी पड़ेगी। फरवरी 1972 में अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा ने यह और भी स्पष्ट कर दिया है कि चीन इस मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। चाहे यह दृष्टिकोण परिवर्तन बाह्य दिशाओं के लिए ही क्यों न हो, लेकिन हो रहा है।

मूल्यांकन

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है माकर्मवाद ही साम्यवाद का आधार एवं स्रोत है। साम्यवादी, माकर्मवाद के जो सिद्धान्त स्वीकार करते हैं, जैसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग-संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त, सर्वहारा अधिनायकत्व आदि, उनका आलोचनात्मक अध्ययन माकर्मवाद के सन्दर्भ में पहले ही किया जा चुका है। उन्हीं तत्वों को यथा प्रस्तुत करना पुनरावृत्ति ही होगी। फिर भी यह नहीं भूल जाना चाहिए कि माकर्मवादी सिद्धान्त साम्यवाद के प्रमुख आधार हैं। यहाँ सिर्फ साम्यवाद से सम्बन्धित विशेष समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन किया जा रहा है।

माकर्मवाद को अष्ट करने का आरोप

आलोचकों का यह कहना है कि साम्यवाद, माकर्मवाद का न तो तर्कसंगत विस्तार है और न सही परिग्रहण। साम्यवादियों ने माकर्मवाद का सजोड़न किया है। या, साम्यवादियों ने माकर्मवाद को अष्ट कर दिया है। यद्यपि माकर्म ने आग्नि

⁷⁶ भारतीय साम्यवादी दल के क्विंटन का विवरण माहन राम लिखित पुस्तक—*Indian Communism split with a split* (1969) में काफी अच्छा दिया हुआ है जिसका अध्ययन उपयुक्त होगा।


⁷⁷ Labeledz and Urban, *The Sino-Soviet Conflict*, p. 9

और सर्वहारा अधिनायकत्व का समर्थन किया था किन्तु उसका दृष्टिकोण लोक-तान्त्रिक था। उसका विश्वास था कि किसी देश में क्रांति तभी सम्भव होगी जबकि वहाँ मजदूरों का बहुमत ही जायेगा। इसके अलावा मार्क्स का विचार स्वतन्त्रता से बड़ा प्रेम था। अपने तात्कालिक युग में प्रशा (Prussia) तथा अन्य निरकुशवादी राज्यों की प्रेस विरोधी नीतियों की मार्क्स ने कटु आलोचना की थी।

साम्यवाद विरोधियों के अनुसार मार्क्स के अनुयायियों ने, जिन्हें साम्यवादी कहा जाता है, मार्क्सवाद की इस प्रकार व्याख्या की है जो उनकी स्वार्थ-सिद्धि की पूर्ति और उनकी त्रुटियों पर आवरण डालने में सहायक हो। मिलोवेन जिलास (Milovan Djilas) के शब्दों में—

“मूल मार्क्सवाद का अर्थ लगभग कुछ नहीं बचा है। पश्चिम में यह समाप्त हो चुका है या समाप्त होने जा रहा है। पूर्व में साम्यवादी शासन की स्थापना से मार्क्स के द्वन्द्ववाद और भौतिकवाद की सिर्फ औपचारिकता और ढोंगवादिता ही शेष रही है जिसका प्रयोग उन्होंने सत्ता को सुदृढ़ करने, निरकुशता को सही सिद्ध करने तथा मानव-आत्मा का उल्लंघन करने के लिए किया है।”⁷⁸

साम्यवादियों ने मार्क्सवाद की विचार-आत्मा को नहीं समझा है। साम्यवादी राज्यों में जनतन्त्र के स्थान पर अल्पसंख्यकों की तानाशाही, सर्वहारा के स्थान पर दल अधिनायकत्व और व्यक्तिपूजा की स्थापना होती है, जिसका मार्क्स ने शायद ही समर्थन किया हो।

काल्पनिक उद्देश्य (2) 

मार्क्सवादी सिद्धान्तों का अन्तिम उद्देश्य 'साम्यवादी समाज' की स्थापना करना है जिसमें न तो शोषण, न कोई वर्ग और न कोई राज्य ही होगा। मार्क्सवाद का यह उद्देश्य काल्पनिक है किन्तु साम्यवाद को मार्क्सवाद या वैज्ञानिक समाजवाद का व्यावहारिक रूप समझा जाता है। साम्यवाद के अन्तर्गत व्यावहारिक दृष्टि से राज्य का लोप होना असम्भव है। इसके विपरीत राज्य की शक्तियों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। साम्यवादी इतने व्यावहारिक होते हुए न जाने क्यों इस काल्पनिक उद्देश्य में अनावश्यक रूप से उलझे हुए हैं।

78 "Almost nothing remained of original Marxism. In the West it had died out or was in the process of dying out; in the East, as a result of the establishment of Communist rule, only a residue or formalism and dogmatism remained of Marx's dialectics and materialism, this was used for the purpose of cementing power, justifying tyranny and violating human conscience."

(2)

साम्यवाद का नवीन विवेचन एक धोखा है

लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव, माघो स्ने-तु ग ने माक्सवाद में जो व्यावहारिक परिवर्तन किये हैं उनसे मूल आधारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इन सभी को नया समर्थन, शान्ति, आदि में पूर्ण आस्था है। जब ख्रुश्चेव जैसे साम्यवादियों ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, लोकतांत्रिक साधनों का समर्थन किया, इससे उन्होंने विश्व को भ्रम में डालने का प्रयत्न किया है। यदि साम्यवादी लोकतांत्रिक और शान्तिपूर्ण साधनों को स्वीकार करते हैं तो फिर वे साम्यवादी पहलान का दावा नहीं कर सकते। इस प्रकार के सैद्धांतिक परिवर्तनों का प्राणम मूल उद्देश्यों में परिवर्तन करना नहीं किन्तु इन उद्देश्यों को उपलब्धि के लिए अपनी कूटनीति और चालाकी में परिवर्तन करना है। इसलिए यदि विश्व की जनता से यह कहा जाय कि साम्यवादी अब शान्तिपूर्ण लोकतांत्रिक साधनों में विश्वास रखते हैं तो यह उनके साथ धोखा करना है। साम्यवाद से अबगत व्यक्ति शायद ही साम्यवादियों के इस रण-परिवर्तन पर विश्वास करें।

अधिनायकवादी व्यवस्था (Totalitarian system)

साम्यवाद पूर्णतः आरोपित एवं ऊपर से नियन्त्रित व्यवस्था है। इसमें एक दल, एक विचार, एक रंग, एक ढंग में ही व्यक्ति बन्दी रहता है। कला, साहित्य दर्शन, विज्ञान सभी को एक ढाँचे में ढालने का प्रयत्न किया जाता है। साम्यवाद के अकुश में रहना ही स्वतन्त्रता है। व्यक्तिगत अधिकारों की बात करना व्यर्थ है। साम्यवादी दल के बीचों-बीच अधिवेशन में (1956) में तात्कालिक महामन्त्री निकिता ख्रुश्चेव का भाषण स्टालिन युग के रूप में प्रचलित अधिनायकवादी व्यवस्था का ही प्रतिवेदन था। राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत जीवन में भी रहता है, यहाँ तक कि लेनिन की पत्नी (Nadezhda Konstantinovna Krupskaya) ने भी स्टालिन द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इस विषय में लेनिन ने स्टालिन को एक पत्र लिखकर उससे क्षमा मागने के लिए कहा था।⁷⁹

79 Form Lenin to Stalin—
Dear Comrade Stalin

You permitted yourself a rude summon of my wife to the telephone and a rude reprimand of her. Despite the fact that she told you that she agreed to forget what was said, nevertheless Zenoviev and Kameney heard about it from her. I have no intention to forget so easily that is being done against me, and I need not stress here that I consider it as directed against me which is being done against my wife. I ask you therefore that you weigh carefully whether you are agreeable to retracting your words and apologizing or whether you prefer the severance of relations between us.

March 5, 1923

Sincerely,
Lenin

This letter was produced by Nikita Khrushchev before the Twentieth Congress of the CPSU, 1956 Supplement Freedom First July 1956 State Department U.S.A.

स्टालिन की पुत्री स्वेतलाना की भी यही शिकायत थी। उन्हें अपनी इच्छानुसार विवाह करने पर सोवियत सरकार ने कई प्रकार की बाधाएँ पैदा की। कुछ समय बाद स्वेतलाना को गुप्त रूप से रूस छोड़ना पड़ा। यह सब कुछ तब हुआ जब स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस में कुछ उदारवादी प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगी थी। इस समय भी यह सुनने में आता है कि रूस में विचारकों और प्रमुख लेखकों को यातनायें भोगनी पड़ती हैं क्योंकि वे सरकार द्वारा निर्देशित विचार-मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। 1974 के प्रारम्भ में रूस के प्रसिद्ध साहित्यकार एलेग्जेंडर सॉलजेनित्सिन को देश से निष्कासित किया गया है। इस प्रकार अब आलोचकों को निष्कासित करने का एक नया कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है। 1968 में चेकोस्लोवाकिया के उदारवादी आन्दोलन का दमन भी वर्तमान नेतृत्व के समय में ही हुआ है।

चीन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सभी पहलू माओ त्से-तुंग के विचारों के अन्तर्गत आने चाहिए। माओ के विचारों का विरोध करना अपराध करने जैसा है। चीन के राष्ट्रपति ल्यू शाओ ची (Liu Shao Chi), विदेश मंत्री चैन यी (Chen Yi), 1965 में मनोनीत माओ के उत्तराधिकारी लिन पियाओ (Lin Piao) तथा अन्य माओ-विचारों को ठीक तरह ग्रहण नहीं कर सके, परिणामस्वरूप सभी को अपमानित हो अपने पदों से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार के अतिनायकवादी तत्व सभी साम्यवादी राज्यों में विद्यमान रहते हैं। मनुष्य का अर्च्छा बुरा बहुत कुछ गुप्तचर विभाग पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था में मनुष्य आर्थिक चिन्ताओं से मुक्ति पा सकता है किन्तु आत्मिक शान्ति एवं स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती।

साम्यवादी सम्पूर्ण विश्व को समस्याओं का हल एक मात्र अपने ही मार्ग से मानते हैं। यह विश्वास भ्रान्तिपूर्ण है। विश्व विविधताओं का पुञ्ज है। अलग अलग राज्यों या क्षेत्रों में जीवन पद्धति, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार इस विश्व-विभिन्नता से सम्बन्धित समस्याओं की जटिलता भी इतनी ही व्यापक होगी। साम्यवाद अकेला ही इन सबका समाधान नहीं कर सकता। लास्की (H.J. Laski) के अनुसार—

“सामाज्य अर्थ में, निःसन्देह साम्यवाद की भूल यह है कि वह विश्व की जटिलता को स्वीकार नहीं करता। उसका बतलाया उपचार अवास्तविक है, क्योंकि विश्व बड़ा पेचीदा है और सम्पूर्ण विश्व के लिए कोई एक उपचार नहीं हो सकता।”⁸⁰

१०



80 Laski, H J, Communism, p 243,

Deane, Herbert A, The Political Ideas of Harold Laski, p 132,

पाठ्य-ग्रन्थ

- 1 Clark, Gerald Impatient China, Chapter 7,
The People's Communes
- 2 वोकर, फ्रांसिस , आधुनिक राजनीतिक चिन्तन,
ग्रन्थ 3, समाजवादी आन्दोलन तथा मार्क्स के
बहुतर अनुयायी, भ्रमण विश्वयुद्ध के पूर्व ।
- 3 Deutscher, Isaac, Russia, China and the West,
Chapter 5, The Twentieth Congress
of the Soviet Communist Party
- 4 Djilas, Milovan , The New Class An Analysis of the
Communist System, Chapter 3,
The New Class Chapter 4, The Party Sta..
- 5 Donnelly,
Desmond , Struggle for the World Chapter 2,
Socialism in One Country
- 6 Dutt, Gargi Rural Communes of China
- 7 Gargi Dutt and
V P Dutt , China's Cultural Revolution
- 8 Ebenstein W , Today's isms, Chapter 1,
Totalitarian Communism
- 9 Fainsod, Merle How Russia is Ruled, Chapter 5,
The Dictatorship of the Party in Theory
and Practice
Chapter 13, Terror as a System of Power
- 10 Gray, Alexander , The Socialist Tradition,
Chapter XVII, Lenin
- 11 Hallowell J H., Main Currents in Modern Political
Thought,
Chapter 14, Socialism in the Soviet Union
- 12 Hunt, R N Carew , The Theory and Practice of Communism
An Introduction, Chapter XV,
Lenin's Contribution to Marxist Theory

- Chapter XVI, Stalin's Contribution to Marxist-Leninist Theory.
13. जोड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, अध्याय 5, साम्यवाद तथा अराजकतावाद
14. Lowenthal, Richard., World Communism, Chapter, 5, The Distinctive Character of Chinese Communism.
15. Paloczi-Horvath G., Khrushchev : The Road to Power, Chapter 14, Who is to Lead the Communist World.
16. Schapiro Leonard , The Communist Party of the Soviet Union, Chapter 16, The Defeat of Trotsky Chapter 17, Party Composition : Relations with the Government.
17. Stankiewicz, W. J. (Ed), Political Thought Since World War II, Part III, Marxism and Communism
18. Wanlass, Lawrence, D , Gettell's History of Political Thought, Chapter XXVII, Communism
-

पुनर्विचारवाद एवं संशोधनवाद

बर्न्सेटीन, कॉट्स्की आदि

माक्स तथा ऐन्जिल्स के विचारों ने यूरोपीय समाजवादी चिन्तन तथा श्रमिक आन्दोलन को एक नवीन प्रेरणा एवं दृष्टान्त, एक नयी गति और एक नया मोड़ प्रदान किया। कोई भी चिन्तक एवं राजनीतिज्ञ माक्सवाद की व्यापकता से स्वयं को अज्ञात नहीं रख सका। सभी उसके समर्थक अथवा आलोचक के रूप में उससे सम्बद्ध थे।

पुनर्विचार एवं संशोधनवाद से तात्पर्य

पूरे अध्याय में उल्लेख किया गया है कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माक्सवाद की आलोचना करने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी। यूरोप में बहुत से समाजवादियों ने यह स्वीकार किया कि माक्सवाद की जो आलोचना हो रही है उसमें तथ्य है। माक्सवाद के आलोचकों का विचार था कि यूरोपीय समाज के परिवर्तित परिदृश्य में माक्सवाद पिछड़ा हुआ सा लगता है। माक्सवाद को परिस्थितियों तथा समय के अनुकूल बनाना आवश्यक सा हो गया। इसलिए यूरोप में कुछ समाजवादियों ने माक्सवाद पर पुनर्विचार करने पर जोर दिया। वास्तव में इसने एक छोटे मोटे आन्दोलन का स्वरूप ले लिया। वे जो माक्सवाद में पुनर्विचार कर संशोधन करना चाहते थे उन्हें कट्टर माक्सवादियों ने घृणात्मक दृष्टि से पुनर्विचारवादी या संशोधनवादी कहा तथा इस आन्दोलन एवं कार्यक्रम को पुनर्विचारवाद तथा संशोधनवाद (Revisionism) कहते हैं।¹

पुनर्विचारवाद एवं संशोधनवाद दो प्रमुख प्रवाहों एवं प्रवृत्तियों में विभाजित हो जाता है। प्रथम संशोधनवाद श्रेणी में एडुअर्ड बर्न्सेटीन जैसे समाजवादी आते हैं जो माक्सवाद के सम्पूर्ण सिद्धान्तों को अपनी आलोचनाओं से अछूना नहीं छोड़ते। वे माक्सवाद को अधिक तार्किक, वैज्ञानिक, सामयिक, व्यावहारिक बनाने के लिये पुनर्विचार और संशोधनवाद का सुझाव देते हैं। यूरोप, विशेषतः जर्मनी, में सोशल

¹ संशोधनवाद के व्यापक अध्ययन के लिए देखिए—

Labeledz, L., Ed., Revisionism, 1962

डेमोक्रेटिक पार्टी इस प्रकार के संशोधनवाद का प्रमुख केन्द्र थी। इस श्रेणी के समर्थकों ने मार्क्सवाद के श्रान्तिकारी तत्वों को छोड़ दिया तथा वे अपने दर्शन में विकासवादी और नीति में सुधारवादी हो गये।² संशोधनवाद का यह प्रवाह उदारवादी समाजवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा विकासवाद को धोर ले जाता है।

पुनर्विचारवाद एवं संशोधनवाद की दूसरी श्रेणी में साम्यवादी संशोधनवादी आते हैं। साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत, चाहे वह राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय हो, संशोधनवाद एक स्थाई तत्व बन गया है। लेकिन यह संशोधनवाद राष्ट्रीय राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी जगत में सत्ता एवं प्रभाव संघर्ष का एक माध्यम बन गया है। ट्रॉट्स्की तथा स्टालिन के मतभेद, रूस तथा चीन के सैद्धान्तिक मतभेद, यूगोस्लेविया के मार्शल टिटो का पृथक दृष्टिकोण आदि सभी इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। इस दृष्टि से प्रायः प्रत्येक साम्यवादी संशोधनवादी है। स्टेन्कीविच (W. J. Stankiewicz) ने साम्यवादी जगत में इस संशोधनवादी स्थिति को 'बहुकेन्द्रवाद' (Polycentrism) की सजा दी है।³

मार्क्सवादी-साम्यवादी साहित्य में पुनर्विचारवाद एवं संशोधनवाद एक निन्दात्मक शब्दावली बन गया है। इसकी अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। यदि अपने किसी साथी की भ्रष्टता करनी होती है तो उसे आजकल विचलनवादी (Deviationist); सामाजिक साम्राज्यवादी (Social imperialist), भगोडा (Renegade) आदि कहकर सम्बोधित किया जाता है। सूक्ष्म में किसी भी व्यक्ति को पुनर्विचारवादी एवं संशोधनवादी निम्नलिखित आधारों पर कहा जा सकता है:—

प्रथम, वह व्यक्ति मार्क्सवादी या साम्यवादी होने का दावा करता हो।
द्वितीय, वह मार्क्सवाद-लेनिनवाद का आलोचक हो किन्तु प्रत्येक आलोचक संशोधनवादी की श्रेणी में नहीं आता। इस शब्द का प्रयोग उस 'काली भेड़' (black sheep) के लिये किया है जो मार्क्सवादी आन्दोलन में रहते हुए भी पुनर्विचार का सुभाव देता हो।
तृतीय, जिसका मार्क्सवादी मार्ग से विचलन हो चुका हो।
चतुर्थ, जिसने तत्कालीन स्थिति के संदर्भ में मार्क्सवाद-लेनिनवाद (चीन में माओवाद भी) की ध्यात्वा की हो किन्तु साम्यवादी राज्यों में सत्ता संघर्ष में पराजित हो चुका हो।

पुनर्विचार की पृष्ठभूमि

मार्क्सवाद कभी भी एक निश्चित विचारधारा नहीं बन सका जिसे सभी मार्क्सवादी सर्व सम्मति से स्वीकार कर सकते थे। मार्क्स के जीवन के अन्तिम वर्षों में तथा मरगोपरान्त मार्क्सवादियों तथा अन्य समाजवादियों में मार्क्सवाद के विवेचन को लेकर मतभेद प्रारम्भ हो चुके थे। 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' (First International,

² सेवान, जार्ज एच., राजनीति-दर्शन का इतिहास (अनुदित) पृ० 748.

³ Stankiewicz, W. J., Political Thought Since World War II, pp 125-128.

अब दो गुटों में विभाजित हो गया। इन मतभेदों से गम्बन्धित एक गुट कट्टरपंथी मार्क्सवादी (Orthodox Marxists) तथा दूसरा गुट पुनर्विचारवादी या संशोधनवादी (Revisionists) कहलाया।

यूरोप में इस 'नरम तथा व्यावहारिक समाजवाद' के सिद्धान्त कई विद्वानों जैसे जर्मनी में एडुअर्ड बर्न्स्टीन, फ्रांस में जॉन जोरेस (Jean Jaures), बेल्जियम में अन्सेले (Edouard Anseele), रूस में बेरोनोव्स्की (Tugan Baronowsky) तथा स्वीडन में कार्ल ब्रान्टिंग (Karl Branting) के वक्तव्यों तथा ग्रन्थों में, बेल्जियम का मजदूर दल, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, फ्रान्स तथा इटली के समाजवादी दलों के सिद्धान्तों एवं कार्यक्रमों से व्यक्त होते हैं।⁴ किन्तु जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा एडुअर्ड बर्न्स्टीन को संशोधनवादी भ्रान्दोलन के प्रमुख प्रतिनिधि मानकर इसके अध्ययन को समझा जा सकता है।

एडुअर्ड बर्न्स्टीन

Eduard Bernstein, 1850-1932

एडुअर्ड बर्न्स्टीन जर्मनी के प्रमुख समाजवादों में थे। इनका जन्म बर्लिन में एक यहूदी इन्जीनियर परिवार में हुआ। प्रारम्भ में बर्न्स्टीन ने एक बैंक में नौकरी की किन्तु वे तत्कालीन राजनीति से भ्रम को पृथक् नहीं कर सके। 1878 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पर जब सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया बर्न्स्टीन को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा। स्विट्जरलैंड में बर्न्स्टीन ने 1880 से 1888 तक-Social Democrat-पत्र का सम्पादन किया। जर्मनी में इस पत्र पर प्रतिबन्ध होने हुए भी इसका मुक्त रूप से काफी वितरण होता रहा। विस्मार्क के दबाव के कारण बर्न्स्टीन को स्विट्जरलैंड छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा जहाँ अनेक मार्क्सवादियों से इन्होंने मित्रता स्थापित की। लगभग 22 वर्ष की अवस्था में वे जर्मनी में समाजवादी दल 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी' के सदस्य बने। बर्न्स्टीन ने इंग्लैंड तथा स्विट्जरलैंड का काफी भ्रमण किया। सम्भवतः वे वहाँ के उदारवादी वातावरण से प्रभावित हुए हों। 1932 में बर्न्स्टीन की मृत्यु के पहले जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनके विचारों को अपने कार्यक्रम का सिद्धान्तिक आधार स्वीकार किया।

अपने चिन्तन एवं राजनीतिक जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में एडुअर्ड बर्न्स्टीन 'मार्क्सवाद के समर्थक थे किन्तु ऐन्जिल्स की मृत्यु से बाद बर्न्स्टीन ने मार्क्सवाद के प्रति पुनर्विचार और संशोधनवाद का अभियान प्रारम्भ किया। बर्न्स्टीन ने अपने समाजवादी विचारों को एक जर्मन पत्र-Die Neue Zeit-में एक लेखमाला-'समाजवाद की समस्याएं' के अन्तर्गत 1896 से 1918 के मध्य प्रकाशित किया। इन लेखों के परिणामस्वरूप बर्न्स्टीन का मानसवाद के कट्टरपंथी कार्ल कॉट्स्की

4. कोरर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 115.

से एक वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ। वॉर्नर वॉन वॉर्नर को अब पूर्ण रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस हुई। 1899 में वॉर्नर द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ—*Evolutionary Socialism*⁵ (विकासवादी समाजवाद)—इसी विवाद का प्रत्युत्तर था। इस पुस्तक में वह बहुचर्चित पत्र भी है जिसे वॉर्नर ने अक्टूबर 1898 में जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिवेशन के लिए लिखा था।

वॉर्नर पत्र, 1898

वॉर्नर जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख सिद्धान्त व्याख्याता थे। अक्टूबर 1898 में स्टुटगार्ट (Stuttgart) में आयोजित जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के अधिवेशन के लिये लिखे गये एक महत्वपूर्ण पत्र में वॉर्नर ने नवदृष्टियों मानसैवादिया पर करारा प्रहार किया तथा मार्क्सवाद के सम्बन्ध में धारणियों को सामने रखा। इस सम्मेलन में वॉर्नर ने मार्क्स के कई विचारों का खण्डन कर सशोधित विचारों को प्रस्तुत किया। इस पत्र के माध्यम से वॉर्नर ने निम्नलिखित तत्त्वों की श्रेष्ठ समाजवादिया का ध्यान आकर्षित किया—

- (i) पूँजीवाद के पतन की धारणा पर विश्वास करना एक भूल होगी।
- (ii) सामाजिक सम्पत्ति में जो व्यापक वृद्धि हुई है, या हो रही है उसका कारण, जैसा कि मार्क्स ने कहा है, बड़े बड़े पूँजीपतियों की सत्ता में कमी होना नहीं है। सामाजिक सम्पत्ति में वृद्धि पूँजीपतियों की सत्ता में वृद्धि के कारण ही सम्भव हो सकती है।
- (iii) उद्योगों का केन्द्रीकरण उस गति से नहीं हो रहा जैसा कि मार्क्स ने कहा था और न यह प्रक्रिया एक समान तथा एकदृष्ट हो रही है।
- (iv) समाजवाद ऐतिहासिक आवश्यकता नहीं है। यदि समाजवाद आवश्यकता होता तो विश्व में समाजवादी दलों की गठित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी।
- (v) कोई भी व्यवस्था अन्तिम नहीं होती। इसलिये समाजवाद के अन्तिम उद्देश्य में विश्वास नहीं किया जा सकता।
- (vi) वॉर्नर ने समाजवादी आन्दोलन में भी अपना विश्वास व्यक्त किया। श्रमिक वर्ग की प्रगति, समाज की व्यापारिक वर्ग से मुक्त कराना, प्रत्येक क्षेत्र में तीव्रतन्त्र को प्रोत्साहन देना तथा वे जो श्रम करते हैं, जो उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनके हितों की संरक्षण देना आवश्यक है।⁶

⁵ इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद 1909 में प्रकाशित हुआ।

इस सम्बन्ध में देखिये—*Western Social Thought* by Kizer and Ross, p 275.

⁶ Hallowell, J H., *Main Currents in Modern Political Thought*, pp 445-50

सोवियत डेमोक्रेटिक पार्टी के इस अधिवेशन से एडुवर्ड बर्न्स्टीन तथा कट्टर मार्क्सपथी कॉट्स्की के मध्य खुले रूप से द्विचार संघर्ष प्रारम्भ हुआ। बर्न्स्टीन ने अपने पत्र में मार्क्सवाद के मूल सिद्धान्तों पर प्रहार किया था। मार्क्सवादी इसे सहन नहीं कर सके। परिणामस्वरूप बर्न्स्टीन के विचारों को यूरोप के श्रमिक और अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी मंच पर मान्यता नहीं मिल सकी।⁷ किन्तु बर्न्स्टीन द्वारा मार्क्सवाद के विरोध में कमी नहीं आई। उन्होंने और अधिक तीव्रता से मार्क्सवाद के सिद्धान्तों के खण्डन का अभियान आगे बढ़ाया।

बर्न्स्टीन द्वारा मार्क्सवादी सिद्धान्तों का खण्डन ✓

बर्न्स्टीन ने अपने ग्रन्थ—Evolutionary Socialism—में मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धान्तों का खण्डन कर उनमें संशोधन का सुझाव दिया है। विभिन्न मार्क्सवादी सिद्धान्तों के प्रति बर्न्स्टीन का निम्नलिखित पुनर्विचारवादी-संशोधनवादी दृष्टिकोण है—

इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या बर्न्स्टीन ने मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को केवल संशोधन रूप में ही स्वीकार किया। उनका कहना था कि सामाजिक विकास तथा परिवर्तनों में उन कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जो आर्थिक नहीं हैं। आर्थिक कारक विचार निर्माण में अवश्य सहायक होते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें बराबरी रूप दिया जाय यह बहुत से अन्य कारकों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

वर्ग-संघर्ष—मार्क्स वर्ग-संघर्ष को अवश्यम्भावी मानता है। वर्ग-संघर्ष में निरन्तर वृद्धि तथा अन्त में श्रमिक शासन के विचार को बर्न्स्टीन स्वीकार नहीं करते। इस सम्बन्ध में बर्न्स्टीन का तर्क है कि, प्रथम, पूँजीवाद के विकास के साथ साथ वर्ग-संघर्ष में शिथिलता आई है। द्वितीय, श्रमिकों के शोषण के स्तर पर उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। तृतीय, मध्य वर्ग और छोटे छोटे व्यापारियों की संख्या में वृद्धि से समाज के दो वर्गों में ध्रुवीकरण के अवसर कम होते जा रहे हैं। चतुर्थ, लोकतन्त्र के विकास ने श्रान्ति की सम्भावना को और भी कम कर दिया है। सूक्ष्म में, बर्न्स्टीन का कहना था कि श्रमिक आन्दोलन के कारण श्रमिकों के शोषण में कमी आई है। कारखानों के विषय में नए नए कानूनों के बनने, शासन में लोकतन्त्र के विकास में, श्रम संगठनों पर प्रतिबन्ध उठने, सहयोगी व्यापार में वृद्धि होने आदि से श्रान्ति के अवसर कम होने जा रहे हैं।⁸ बर्न्स्टीन ने श्रमिकों को आह्वान किया कि वे वर्ग-संघर्ष के परिणामस्वरूप श्रान्ति की प्रतीक्षा में अनिश्चित काल तक न बैठे रहें। उन्हें तत्कालीन आवश्यकता को ही अपने अनुसृत बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

साधन—सामाजिक परिवर्तनों के साधन के रूप में बर्न्स्टीन से श्रान्ति तथा हिंसा का समर्थन नहीं किया। वह कानूनी के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। हिंसा

7. Crossland, C A R, The Future of Socialism, p 98.

8. Lancaster, Lane, Masters of Political Thought, Vol III, p. 306.

के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में शीघ्रता हो सकती है किन्तु कानूनो के द्वारा मु्यार प्रधिप्त स्थायी होने हैं । कानूनो द्वारा परिवर्तनों से भावना के उपर बुद्धि तथा विवेक की विजय होनी है किन्तु कान्ति में भावना विवेक पर हावी रहनी है । बर्न्सटीन कानून को एक व्यवस्थित शक्ति मानत थे । समाजवादी शान्दोलन में सभी को साथ नकर रचनात्मक विचार की आवश्यकता है न कि विध्वंसक भावना की ।

सामाजिक दुः परिवर्तन—मानस की धारणा थी कि जब जब उत्पादन के साधनों या अन्य प्रार्थिक उपादानों में परिवर्तन होता है समाज एक प्ररस्या से दूसरी अवस्था में ह्दयाग लगाकर प्रवेश करता है । मानस का यह विचार द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या तथा वर्ग-सघर्ष के सिद्धान्त का निष्कर्ष था । बर्न्सटीन ने इस धारणा को भी स्वीकार नहीं किया है । बर्न्सटीन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का कारण जीवन की मूलभूत परिस्थितियों में परिवर्तन होता है । परिवर्तनों का कारण वर्ग-सघर्ष नहीं किन्तु मनुष्य का परिवर्तित परिस्थितियों के साथ स्वयं का सामन्जस्य करना तथा आवश्यकतानुसार अपनी सस्थाओं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का सामर्थ्य है ।

मूल्य का श्रम सिद्धान्त—इसी प्रकार बर्न्सटीन ने मूल्य-के श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) के विषय में शराएँ व्यक्त की हैं । मानस द्वारा प्रतिपादित मूल्य का श्रम सिद्धान्त, बर्न्सटीन के अनुसार, पूँजीवादी अर्थ व्यवस्था के दुर्गुणों का भण्डारोड करने में अवश्य ही उपयोगी सिद्ध हुआ है, किन्तु इस सिद्धान्त को मूल्य तथा श्रम से सम्बन्धित सभी तत्त्वों एवं तथ्यों को समझने के लिये एक कुँजी मानना भूत होगी । वह सभी जानते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था में अनिश्चित मूल्य का अस्तित्व तथा ध्वापक प्रचलन है, किन्तु इस आधार पर कि श्रमिक को उसके श्रम तथा उत्पादन का पूर्ण फल नहीं मिलता एक वैज्ञानिक समाजवाद का आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

श्रम सगठन—श्रम सगठना के विषय में बर्न्सटीन का कहना है कि सामाजिक एवं उत्पादन कार्यों में उनके महत्त्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु बर्न्सटीन श्रम सगठनों की सबव्यापी तथा उत्पादन प्रक्रिया में केवल एक ही कारक मानने के विरुद्ध था । यदि श्रम सगठनों के इतने व्यापक महत्त्व को स्वीकार किया जाय तो ये श्रम सगठन स्वयं ही उत्पादन में एकाधिकार (monopoly) का रूप धारण कर लेंगे । एकाधिकार चाहे वह पूँजीपतियों का हो या श्रम सगठनों का, समाजवाद तथा लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों तथा सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा ।

सर्वहारा समाजवाद—बर्न्सटीन सर्वहारा अधिनायकवाद के माध्यम से समाजवाद की स्थापना के विरुद्ध था । जिस समय सामाजिक लोकतन्त्र के प्रतिनिधि सरकारों के विभिन्न पदों पर प्राप्ति होने जा रहे हैं, बर्न्सटीन का कहना था कि ऐसे समय सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व का प्रचार करना अति आपत्तिजनक था । सामाजिक

लोकतन्त्रवादी (Social Democrats) जिनके बर्न्सटोन स्वयं एक प्रमुख नेता थे, यह प्रयत्न कर रहे थे कि प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर एक उच्च सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाय किन्तु अधिनायकवादी माध्यम द्वारा नहीं। किसी एक वर्ग की तानाशाही, बर्न्सटोन के अनुसार, एक निम्न सम्पत्ता की ही शोभा दे सकती है। यह राजनीतिक प्रगति के विपरीत है। बर्न्सटोन व्यापक तथा पूर्ण प्रतिनिधि-प्रणाली को सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व का समुचित विकल्प मानता था।

राज्य का स्वभाव—मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग संगठन है। यह पूँजीपतियों तथा उच्च वर्ग के हितों को संरक्षण देने वाली संस्था है। मार्क्सवाद के अन्तर्गत साम्यवादी समाज में राज्य के लोप होने की बात कहते हैं। बर्न्सटोन राज्य के स्वभाव के विषय में मार्क्स के विवेचन से सहमत नहीं थे। वह राज्य को एक वर्ग संगठन न मानकर सहयोगी संस्था मानते हैं जिसके कार्यों में सभी को भाग लेना चाहिये।

राष्ट्रीय बनाम अन्तर्राष्ट्रीय समाजवाद—बर्न्सटोन ने इस विचार का विरोध किया कि सर्वहारा वर्ग की कोई भौतृभूमि नहीं होनी, वह एक मातृभूमि से सीमित होकर नहीं रहता तथा वह विश्व नागरिक है। बर्न्सटोन के अनुसार श्रमिक जैसे जैसे समाजवाद के प्रभाव में आता जायेगा वह सर्वहारा से हट कर नागरिक बनता चला जायेगा। बर्न्सटोन का प्रश्न था कि किस दृष्टि से सर्वहारा वर्ग को मातृभूमि से वंचित रखा जा सकता है जब कि उसे और उसकी सन्तान को उत्तम समुदाय (अथवा राज्य) शिक्षा का प्रबन्ध, स्वास्थ्य रक्षा तथा सुरक्षा प्रदान करता है। अपने विचारों से बर्न्सटोन ने राष्ट्रीय समाजवाद का समर्थन किया। बर्न्सटोन को राष्ट्रीय समाजवादी (National Socialist) भी कहा जा सकता है।⁹

मार्क्सवादी यूटोपियायी—बर्न्सटोन के अनुसार कार्ल मार्क्स के विचार वैज्ञानिक कम किन्तु यूटोपियायी अधिक हैं। बर्न्सटोन ने मार्क्स की इन धारणाओं को भ्रम बतलाया कि पूँजीवाद का अन्त निकट है, पूँजीवाद के स्थान पर श्रमिकवर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना होगी, तथा समाज समाजवाद से साम्यवादी व्यवस्था में प्रवेश करेगा। बर्न्सटोन ने मार्क्स के इन विचारों को कोरा काल्पनिक बतलाया जिन्हें व्यावहारिक रूप देना असम्भव था।

उदारवाद की समर्थन—बर्न्सटोन उदारवादी प्रवृत्तियों का प्रबल समर्थक था। यद्यपि सामन्तवादी व्यवस्था का उन्मूलन पूर्ण आवश्यक है किन्तु इसके साथ-साथ उदारवाद को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। समाजवाद को उदारवादी विचारों तथा संस्थाओं को समर्थन देना चाहिये। उदारवाद के समर्थन से समाजवाद व्यक्ति के स्वतन्त्र विचारों में सहायक बन सकता है। बर्न्सटोन ने यह स्वीकार किया है कि "समाजवाद, कार्यक्रम तथा भावना से उदारवाद का वैध

9. Gray, A., The Socialist Tradition, p. 436.

उत्तराधिनारी है। वह कहता है कि ऐसा कोई भी सही उदारवादी विचार नहीं है जिसका समाजवाद में स्थान न हो, समाजवाद का कार्य वास्तव में उदारवाद को व्यवस्थित करना है।¹⁰

मूल्यान्त

एडुअड वॉर्सटीन ने मार्क्सवादी ज्वर एंड ज्वार का डट कर सामना किया। एलेग्जेंडर ग्रे के अनुसार वॉर्सटीन ने इस सम्बन्ध में यह कभी दावा नहीं किया कि वह किसी नयी विचार को प्रस्तुत कर रहे थे। वह केवल उन तथ्यों का अनुमोदन कर रहे थे जो सामने आ चुके थे तथा समाज में जिनका रहस्योद्घाटन हो चुका था।¹¹ यद्यपि उनकी गणना मार्क्सवादियों में की जाती है किन्तु पूर्णतः वे न मार्क्सवादी थे और न मानसवाद जैसी उद्यम और विचार क्षमता ही थी।

पूँजीवादी व्यवस्था के दोषों के विषय में वे मानसवाद विचारों में अत्यन्त महत्त्व थे किन्तु उनके विचारों का प्रभाव दूसरी ओर लगे जाता है। वे प्रमुख सशोषनवादी थे जिन्होंने मार्क्सवाद अवरोध (Containment of Marxism) अभियान का तीव्रता के साथ संचालन कर पश्चिम यूरोप को मार्क्सवादी विचारधारा से मुक्त रखने का प्रयत्न किया। उनके विचारों से प्रायः यह आभास मिलता है (जैसा कि कट्टर मार्क्सवादी कहते हैं) कि वॉर्सटीन पूँजीवादियों को पूँछ थे जिन्होंने उच्च धर्म का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। वॉर्सटीन तथा सशोषनवाद पूँजीवादी व्यवस्था के दोषों एवं दुःखतनाओं को भी दूर करना चाहते थे। जैसा कि लास्की ने कहा है इनका मुख्य विचार था कि यदि राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में अशुभों के योगदान को स्वीकार किया जाय तो पूँजीवादी विक्रम सिद्धान्तों का प्रत्युत्तर दिया जा सकता है।

यथार्थता कुछ भी हो, लोकतांत्रिक समाजवाद के विकास में वॉर्सटीन के योगदान की अक्षयता नहीं की जा सकती और यदि आज के मार्क्सवादियों पर दृष्टि डाली जाय तो वास्तव में अभी (साम्यवादिया सहित) सशोषनवादियों की धरती में घात हैं।¹³ वॉर्सटीन तथा अन्य सशोषनवादियों को यह देखकर सम्भवतः आश्चर्य होता।¹⁴

10 Gray, A, *The Socialist Tradition*, p 406

11 Gray, A, *The Socialist Tradition*, p 402

12 Deane, Herbert A, *The Political Ideas of Harold J Laski*, p 183

13 Stankiewicz, W J (Ed) *Political Thought Since World War II*, p 137

14 Anderson, Thornton, *Masters of Russian Marxism*, p 260

छोटे उद्योगों की सहायता प्रदत्त होने हुए भी मानस की इन बातों से भना नहीं किया जा सकता कि पूँजीवाद में स्वयं को केन्द्रित कर एकाधिकार की प्रवृत्ति नहीं होनी। काँटस्की ने बड़े-बड़े आर्थिक निगमों (Corporations) की आलोचना की है। पूँजीपतियों के इन बड़े बड़े निगमों से समाज में सम्पत्ति के वितरण में बाधा आई है। इससे समाज का उत्पादन कुछ मालिकों तथा पूँजीपतियों के एक मुट्ठी भर वर्ग के हाथों में केन्द्रित हो जाता है। निगमों की स्थापना निधनों से धन इकट्ठा करने की जाती है। लेकिन इस धन का वे प्रयोग नहीं कर सकते। निगमों की राशि का प्रयोग केवल पूँजीपति ही कर सकते हैं। इससे पूँजीवादी व्यवस्था में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।

काँटस्की तथा वॉर्सटीन के मध्य सबसे तीव्र मतभेद इस बात पर था कि पूँजीवाद की समाजवादी व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तित किया जाय। अन्य शब्दों में यह चालों तथा साधनों को लेकर मतभेद था। वॉर्सटीन व्यापक मताधिकार तथा कानूनों के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार वह शान्तिपूर्ण प्रगति के समर्थक थे। काँटस्की वॉर्सटीन के इस विचार से सहमत नहीं थे। काँटस्की के अनुसार समाजवाद केवल आन्ति के द्वारा ही सम्भव है यद्यपि आन्ति में कम से कम हिंसा का प्रयोग किया जाना चाहिये। आन्ति में शक्ति तथा हिंसा का कितना अर्थ हो यह विरोधी शक्ति पर निर्भर करता है।

काँटस्की श्रमिक एवं सहकारी आन्दोलन के पक्ष में थे। एक सीमा तक श्रमिकों को समझ तथा कानून निर्माण में भाग लेना चाहिये ताकि श्रमिकों की दशा में सुधार किया जा सके। किन्तु इन गतिविधियों एवं ऐसे कार्यक्रमों को ही समाजवाद नहीं समझ लेना चाहिये। ये केवल समाजवाद की और दिशा बोध कराते हैं। समझ के कार्यों में भाग लेना, सहकारी आन्दोलन का विस्तार, श्रमिक संगठनों की वृद्धि तथा सुधार कानून ही पर्याप्त नहीं होने। ये गतिविधियाँ, काँटस्की के अनुसार इसलिए अधिक सफल नहीं हो सकती क्योंकि सहकारिता की अपेक्षा पूँजी सचय तथा एकाधिकार में वृद्धि अधिक गति के साथ होती है। श्रमिकों के वेतन से लाभ, प्रभुपात में अधिक बढ़ता है। इस प्रकार ये गतिविधियाँ अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती।

काँटस्की तथा अन्य कट्टरपन्थी मानसवादी सिद्धान्त में ही कट्टर से व्यवहार में नहीं। यद्यपि काँटस्की ने वॉर्सटीन की आलोचना की थी, व्यवहार में उन्होंने वॉर्सटीन जैसा ही कार्य किया। राजनीति में भाग लेने, अन्य गैर-समाजवादी दलों के साथ सहयोग करने आदि का काँटस्की ने अनुमोदन किया। काँटस्की का सशोषणवादियों की भाँति लोकतन्त्र के प्रति भी लगाव था।

जैसा कि जोर्डन (Z. A. Jordan) ने लिखा है काँटस्की और वॉर्सटीन दोनों ही समाजवाद के आदर्शों को स्वीकार करते थे किन्तु दोनों यह भी स्वीकार करते

ये कि समाजवाद की आधारशिला लोकतन्त्र है। उद्देश्यों के विषय में एक मत होते हुए भी वे इस विचार पर सहमत नहीं थे कि इन उद्देश्यों को प्राप्त के लिये कौनसे प्रभावकारी साधन अपनाए जाएं। इस विचार अंतर्दृष्टि ने बर्नस्टीन को पुनर्विचारवादी बना दिया किन्तु जिन बातों को लेकर उनमें गहनमति थी उनमें बर्नस्टीन किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनीतिक विचार शाला का स्थापक नहीं बन सका। बर्नस्टीन और कांटस्की न तो पूर्णतः सही थे न पूर्णतः गलत। लेकिन पश्चिम यूरोप के समाजवादी विकास ने कांटस्की की अपेक्षा बर्नस्टीन से प्रेरणा ग्रहण की।¹⁵

Udaipur UDAIPUR

कांटस्की तथा बर्नस्टीन के विवाद से कांटस्की के निम्नलिखित विचार स्पष्ट होते हैं—प्रथम, कांटस्की ने मार्क्स के अधिक विवेचन को स्वीकार किया है। द्वितीय, कांटस्की ने हिंसात्मक क्रान्ति के माध्यम से समाजवादी उद्देश्यों की प्राप्ति का अनुमोदन नहीं किया है। तृतीय, कांटस्की ने राजनीतिक लोकतन्त्र को धर्मिको द्वारा स्वीकार करने पर जोर दिया। चतुर्थ, एकदल कार्यक्रम को स्वीकार करते समय कांटस्की ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि धर्मिक एवं सर्वहारा वर्ग को बुद्धिजीवियों का मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिये।¹⁶ डा० आशीर्वादम् के शब्दों में "कांटस्की अपने को विकासवादियों में गिने को तैयार न थे। जहाँ तक उनके सिद्धान्त का सम्बन्ध है यह दावा ठीक था किन्तु व्यवहार में वह विगतवादियों के बिल्कुल नजदीक थे। वह लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक तरीकों के समर्थक थे और सम्भवतः उनकी दृष्टि में लोकतन्त्र समाजवाद से भी ज्यादा महत्व रखता था। वह दक्षिणपक्षीय और यामपक्षीय दोनों ही प्रकार के विचलन (deviation) के विरोधी थे।¹⁷

कांटस्की तथा लेनिन

1917 में रूस में साम्यवादी क्रान्ति से कांटस्की के मन में एक प्रकार की अज्ञान उत्पन्न हुई। उन्होंने यह अनुभव किया कि रूस की क्रान्ति तथा इस क्रान्ति का नेतृत्व करने वाले (विशेषतः लेनिन) मार्क्सवाद के सही अनुभायी सिद्ध नहीं हुए। कांटस्की तथा लेनिन के मतभेद मार्क्सवाद को समझने और उसकी व्याख्या के विषय में थे। कांटस्की तथा लेनिन ने मार्क्सवाद को अलग अलग रूप में समझा। कांटस्की के अनुसार मार्क्स ने ध्यापक महाधिकार से सर्वहारावर्ग द्वारा नियंत्रित लोकतान्त्रिक शासन का समर्थन किया था। लेनिन के अनुसार मार्क्स ने सर्वहारावर्ग के लिये साम्यवादी दल के अधिनायकत्व का अनुमोदन किया था।

15 Jordan, Z.A., *The Philosophical Background of Revisionism, in Political Thought Since World War II*, Ed. by W.J. Stankiewicz, p. 261

16 Anderson, T., *Masters of Russian Marxism*, p. 47.

17 आशीर्वादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 637.

शान्ति के उपरान्त रूस में जिस तानाशाही व्यवस्था का उदय हुआ वॉट्स्की ने इसे मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं माना। रूसी शान्ति के नेता रुस में ऐतिहासिक तथा आर्थिक विकास के अनुपात में अग्रिम गति ने देह रह है। वॉट्स्की ने रूसी शान्ति का अल्पमस्यरा द्वारा सत्ता को छीनना तथा शक्ति के घासन की सजा दी। जब तक सर्वहारा बहुमत का सक्रिय योगदान नहीं है, वॉट्स्की के अनुसार, कोई भी शान्ति सफल नहीं हो सकती। वह बोवशेविज्म का विरोध यह कह कर करते थे कि यह अल्पमत का शासन है और पशुवत या प्रतिनिधित्व करता है।

वॉट्स्की कबन पूँजीवर्ग के शोषण को ही नहीं, सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना चाहते थे चाहे यह शोषण किसी वर्ग एक दिन, तिग या जाति का ही क्यों न हो। इस प्रकार वॉट्स्की ने रुस में साम्यवादी शान्ति तथा लेनिन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बहुत आलोचना की।

मार्क्सवाद के विषय में वॉट्स्की के विचार तथा रुस में साम्यवादी शान्ति की बहुत आलोचना को लेनिन सहन करने वाले में से नहीं थे। लेनिन ने वॉट्स्की को पुस्तक-*Dictatorship of the proletariat*-का प्रत्युत्तर अपनी पुस्तक-*The Proletarian Revolution Kautsky the Renegade!*, 919-से दिया। लेनिन के अनुसार वॉट्स्की मार्क्सवाद को झिझक ही नहीं समझ सका। मार्क्स तथा वॉट्स्की में, लेनिन के अनुसार, उल्लास ही अन्तर है जितना एक सर्वहारा शान्तिकारी और तुच्छ पूँजीपति में है। लेनिन ने वॉट्स्की को एक दम वर्षीय डाकिया जैसा अनभिज्ञ तथा निष्क्रिय विद्वान बेइकूर (most learned arm-chair fool) कह कर भनना की।

लेनिन के अनुसार वॉट्स्की जिस लोकतन्त्र की बात करता है वह एक पुरा विवेकहीन विचार है। यहाँ वॉट्स्की वही त्रुटि करता है जो सभी पूँजीवादी लोकतन्त्र में दिखाने रहने वाले करते हैं। ऐन लोकतन्त्र में वॉट्स्की का समानता मन्दगी विचार झिझक बनाबटी और धोखा है। पूँजीवादी लोकतन्त्र के अन्तर्गत शोषण तथा शोषित वर्ग के मध्य समानता का प्रश्न ही नहीं उठता।

वॉट्स्की जिस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था को समाजवाद में परिवर्तित करने का वाद बहता है लेनिन के अनुसार, इससे समस्या का समाधान नहीं होता। लेनिन ने प्रश्न किया कि क्या पूँजीपति, भूमिपति, कारखाना के मालिक जो सर्वहारा शोषक रहें शोषित बहुमत के शासन को बिना शक्ति प्रयोग किए मसन सकते हैं?

वॉट्स्की का कहना था कि जब यह दावा किया जाता है कि रुस में सर्वहारा वर्ग का बहुमत है तो फिर तानाशाही व्यवस्था स्थापित करने की क्या आवश्यकता है। इसके अन्तर में लेनिन ने मार्क्स तथा ऐन्गल्स के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि सर्वहारा अधिनायक की आवश्यकता पूँजीपतियों तथा प्रतिनिध्यावादियों के विरोध

को कुचलने तथा जन-शासन को बनाये रखने के लिए अधिनायकवादी व्यवस्था के प्रौढत्व को चुनौती नहीं दी जा सकती ।

लेनिन ने संशोधनवादियों का सामना एक धर्मयुद्ध के समर्थन की भांति किया । उसने द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा बर्नस्टीन और कॉट्स्की की कट्टि आलोचना की । लेनिन ने बर्नस्टीन तथा कॉट्स्की को मार्क्सवादही, समाजवाद की घोषा देकर भागने वाला कहा । कॉट्स्की के लिये लेनिन ने एक लुच्चा तथा पूँजीपतियों के हाथों बिका हुआ होन मस्तिष्क वाला कहा ।¹⁸ अपनी एक पुस्तिका—*The Task of the Proletariat*—में लेनिन ने कहा है कि अक्सरवादी तथा द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय के समर्थकों के विचारों का समय एक भ्रष्ट युग है । लेनिन ने सर्वज्ञारावरण के लिये आह्वान किया कि वे संशोधनवादियों के भुलावे में न आकर साम्यवादी घोषणापत्र की ओर वापस जायें । साम्यवादी बर्नस्टीन के साथ-साथ कॉट्स्की को संशोधनवादी कहकर निन्दा करते हैं । वे कॉट्स्की के विचारों को मार्क्सवाद के प्रति विश्वासघात समझते हैं । 1961 में रूस के साम्यवादी दल ने लेनिन द्वारा संशोधनवादियों की जो तीव्र आलोचना की गई थी उसे पुनः दोहराया । समय-समय पर इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है ।

कार्ल कॉट्स्की के समाजवाद के विकास में योगदान को एक सीमा तक स्वीकार करना पड़ेगा । इस बात को नहीं भूल जाना चाहिये कि लेनिन द्वारा प्रतिपादित कुछ व्यक्तियों की तानाशाही के विरुद्ध लोकतन्त्र का अनुमोदन कर कॉट्स्की ने समाजवाद की एक बड़ी सेवा की है । यही कारण था कि लेनिन ने कॉट्स्की को सैद्धान्तिक भगोडा (renegade) की संज्ञा दी ।¹⁹ उनके विचारों को एडुअर्ड बर्नस्टीन तथा लेनिन के मध्य रखा जा सकता है । जैसा कि हेसोवेल ने लिखा है कॉट्स्की ने लोकतान्त्रिक परम्परा और मार्क्सवादी समाजवाद का समन्वय कर जर्मनी में सामाजिक लोकतान्त्रिक दल को विचार आधार प्रदान किया । वहीं-कहीं कॉट्स्की ने यह भी विचार दिया है कि लोकतन्त्र समाजवाद से अधिक महत्त्वपूर्ण है । समाजवाद शोषण का अन्त करने के लिये आवश्यक साधन है, स्वयं में साध्य नहीं । लोकतन्त्र तथा समाजवाद पृथक् होकर शोषण का अन्त नहीं कर सकते । शोषण का अन्त करने के लिये लोकतन्त्र और समाजवाद दोनों ही आवश्यक हैं, यही कॉट्स्की के विचारों का मूल है ।

पुनर्विचारवाद एवं संशोधनवाद का वर्तमान स्वरूप

एडुअर्ड बर्नस्टीन, कार्ल कॉट्स्की, प्लेखानॉव (George V. Plekhanov, 1856-1918) आदि को मार्क्सवाद पर पुनर्विचार करने या मार्क्सवाद विरोधी

18 Gray, A., *The Socialist Tradition*, p. 454.

19. Jordan, Z. A., *The Philosophical Background of Revisionism*, opp cit, p. 261.

20. Hallowell, J. H., *Main Currents in Modern Political Thought*, pp. 457-458.

विचारों को व्यक्त करने के आधार पर सशोधनवादी होने की सजा दी गई। उन्हें सशोधनवादी कहने का कारण सैद्धान्तिक मतभेद था तथा यह मतभेद माक्सवाद तक ही सीमित था। आगे चल कर माक्सवाद के साथ लेनिनवाद और जोड़ दिया गया। अन्य माक्सवाद लेनिनवाद पर सैद्धान्तिक मतभेदों के आधार पर सशोधनवादियों का निर्धारण होने लगा। स्टालिन के शासन काल में उनके विरोधियों को इसी आधार पर सशोधनवादी कह कर निन्दा की गई थी। ट्रॉट्स्की का सोवियत साम्यवादों दल तथा रूस में विकासन इसी कारण किया गया। उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने माक्सवाद-लेनिनवाद को विरुद्ध कार्य कर सशोधनवाद को प्रोत्साहन दिया। इसी प्रकार रूस में कई अन्य शीर्षस्थ नेताओं जैसे—बुखारिन (Nikolai I. Bukharin 1888-1938) जिन पर लेनिन विरोधी विचारों का आरोप लगाकर मृत्यु दण्ड दिया, तथा कामेनेव (Kamenev) जिनेव (Zinovev) तथा रायबोव (Rykov) आदि का भी इसी आरोपों के साथ उन्मूलन कर दिया गया। स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त निकिता ख्रुश्चव ने भी स्टालिन पर अन्य आरोपों के साथ लेनिनवाद विरोधी कहकर लगभग सशोधनवादी बोधक में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया।

अभी तक पुनर्विचारवादी शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता था जिन्होंने माक्सवाद में पुनर्विचार और सशोधन का मुभाव दिया हो। किन्तु चीन के सम्बन्ध में पुनर्विचारवाद का अर्थ व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा है। चीन में माक्सवाद के अतिरिक्त मार्क्सवाद की आलोचना करने वालों को भी पुनर्विचारवादियों की श्रेणी में लिया जाता है। चीन में तथाद्वितीय सांस्कृतिक क्रान्ति के समय ल्यू शाओ ची, चेन घी आदि की मार्क्सवाद के विषय में पुनर्विचारवादी और सशोधनवादी कह कर अपमानित किया गया एवं पदों से हटाया गया। इस श्रेणी में चीन के कई और शीर्षस्थ नेता आते आ रहे हैं। लिन पिआओ के बाद चेन पोटा (Chen Po-to) को आजकल प्रमुख सशोधनवादी कहा जाता है। जुलाई 1974 में चेन पोटा पर यह आरोप लगाया गया कि 1969-70 में उन्होंने अपने 'पुनर्विचारवादी भाषण' में मार्क्सवाद के कुछ पक्षों पर शका व्यक्त की। साथ ही साथ मार्क्स द्वारा निर्देशित सम्पूर्ण देश में 'क्रान्तिकारी समितियों' को अधिक कार्यशील बनाने की अवहेलना की। इन प्रकार चीन में पुनर्विचारवाद या सशोधनवाद के दो पक्ष निर्धारित कर दिये गए हैं। चीन द्वारा दूसरे देश के व्यक्ति को जब सशोधनवादी कहा जाता है इसका सम्बन्ध माक्सवाद-लेनिनवाद से है। जब चीन के किसी नेता पर सशोधनवादी होने का आरोप लगाया जाता है इसका तात्पर्य मार्क्सवाद के विषय में पुनर्विचार करने से है।

सशोधनवाद, साम्यवाद सत्ता सधर्ष

यदि सशोधनवाद का सही विवेचन किया जाय तो प्रत्येक प्रमुख साम्यवादी सशोधनवादी की थोड़ी भे घाता है। लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चव, मार्शल टीटो, मार्सो

पुनर्विचारवाद एवं संशोधनवाद

त्से-तुंग आदि सभी संशोधनवादी है। इन सभी ने मार्क्सवाद पर पुनर्विचार कर संशोधन किये यद्यपि साम्यवादी इसे संशोधन न कह कर परिवर्तन कहते हैं। लेकिन साम्यवाद के सन्दर्भ में संशोधनवाद को केवल सत्ता सघर्ष के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। ट्रॉट्स्की को संशोधनवादी एवं विचलनवादी (deviationist) इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे स्टालिन से सत्ता सघर्ष में असफल रहे। इसी प्रकार चीन में लिन पियाघो एवं लू शाघो ची को संशोधनवादियों की श्रेणी में लिया जाता है क्योंकि वे सत्ता सघर्ष में पराजित हुए। यदि स्टालिन या मार्शो त्से-तुंग सत्ता सघर्ष में पराजित एवं असफल होते तो सम्भवतः ये दोनों सबसे महान संशोधनवादी-विचलनवादी कहलाते। इसलिए वर्तमान में संशोधनवाद मार्क्सवाद के विवेचन में उतना सम्बन्धित नहीं जितना कि साम्यवादी राज्यों के अन्तर्गत सत्ता-सघर्ष से है।

साम्यवादी राज्यों के आपसी सम्बन्धों के विषय में भी संशोधनवाद और पुनर्विचारवाद का प्रयोग किया जाने लगा है। मार्शल टीटो के नेतृत्व में जब यूगोस्लाविया ने रूस से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया मार्शल टीटो पर भी साम्यवाद विरोधी और पुनर्विचारवादी होने का आरोप लगाया। किन्तु रूस और चीन ने अपने विगड़ने हुए पारस्परिक सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे पर मार्क्सवाद-लेनिनवाद विरोधी तथा पुनर्विचारवादी कह कर निन्दा की है। आजकल यह लगभग एक स्थायी तत्त्व बन गया है।

	5-3-84	I
	6-11	II 'D.V'
	12-14	Prad.
	15-20	9. Shaw
	21-25	25-28 I 29-30 9.
	26-28	I 29-30 9.

पाठ्य-ग्रन्थ

1. Anderson, T., Masters of Russian Marxism.
2. कोकर, फ्रांसिस., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन 31-P.A.M.
3. Cole, G.D H., अध्याय 4, प्रजातान्त्रिक एवं विकासवादी समाजवादी A History of Socialist Thought, Chapter V, Germany: The Revisionist Controversy.
4. Gray, A., The Socialist Tradition Chapter 14 (b) Eduard Bernstein and Revisionism.
5. Hallowell J. H. Main Currents in Modern Political Thought, Chapter 13, Socialism After Marx
6. Labedz, Leopold., Ed. Revisionism
7. Stankiewicz, W.J., Ed. Political Thought since World War II, Part III, Revisionism and Polycentrism.

फासीवाद एवं नात्सीवाद

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इटली में फासीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। फॅसिज़ (Fascism) शब्द की उत्पत्ति इटली भाषा के शब्द 'फॅसियो' (Fascio) से हुई है 'फॅसियो' शब्द का अर्थ है 'लकड़ियों का बन्धा हुआ गट्टा'। लकड़ियों का बन्धा हुआ गट्टा एकता, अनुशासन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का राज्य-चिह्न फॅसियो तथा कुल्हाड़ी था क्योंकि रोमन राजनीति एकता और शक्ति पर बल देती थी।

प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने के लगभग एक वर्ष पश्चात् 1915 में मिलान (Milan) शहर में मुसोलिनी (Benito Mussolini, 1883-1945) के नेतृत्व में फॅसियो (Fascio) नामक सन्ध्या की स्थापना हुई। इस सन्ध्या की स्थापना का उद्देश्य इटली के व्यक्तियों को एकता और अनुशासन के सूत्र में बाँधना था जो राष्ट्र के न्यून मर मिटने को संभार हो। इस दल ने भी फॅसियो को अपना चिह्न बनाया। इसके सदस्य 'फॅसिस्ट' कहलाते थे तथा उस दल की नीति एवं विचारधारा फॅसिज्म कहलामी जाने लगी। युद्ध के उपरान्त 1919 में कई बारणा में इस सन्ध्या का पुनर्निर्माण किया गया। इटली की मजदूरीय परिस्थितियों ने मुसोलिनी का साथ दिया। अक्टूबर 1922 के अन्तिम सप्ताह में इटली की शासन सत्ता मुसोलिनी के हाथों आयी जो जुलाई 24, 1943 तक इटली के एक-छत्र तानाशाह रहे।

जर्मन फासीवाद राष्ट्रीय समाजवाद

प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही फासीवाद का एक अन्य नामकरण व अन्तर्गत जर्मनी में प्रादुर्भाव हुआ। जिसे फासीवादी विचारधारा का जर्मनी में उद्भव हुआ उस नात्सीवाद (Nazism) के नाम से जाना जाता है। कुछ ही वर्षों को छोड़कर य दाना विचारधाराएँ एक ही हैं। जर्मनी में हिटलर (Adolf Hitler, 1889-1945) के नेतृत्व में नात्सीवाद, जिसे राष्ट्रीय समाजवाद भी कहा जाता था, का

प्रादुर्भाव हुआ। जिन परिस्थितियों में इटली में फासीवाद अपना लगभग वैसी ही परिस्थितियों से जर्मनी में नात्सीवाद का उद्भव हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी एक पराजित राज्य था। पेरिस शान्ति सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधि मण्डल को बड़ा ही अपमानित किया गया। बर्साय की शान्ति सन्धि (Treaty of Versailles, 1919) जर्मनी पर थोपी गई सन्धि थी, जो शान्ति सन्धि न होकर युद्ध का आमन्त्रण थी। बर्साय की सन्धि के अन्तर्गत जर्मनी का बहुत सा क्षेत्र छीन लिया तथा उसका पूर्णतः विसैन्यीकरण किया गया। युद्ध क्षति के रूप में जर्मनी को बहुत सी राष्ट्रीय सम्पत्ति विजेता राज्यों को देनी पड़ी। वास्तव में युद्ध क्षति के नाम पर विजेता राज्यों ने जर्मनी की आर्थिक लूट की। परिणामस्वरूप जर्मनी में भारी असन्तोष था। आर्थिक अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता ने जर्मनी में फासीवादी शासन की स्थापना करने में बड़ी सहायता दी। इस असन्तोष का लाभ हिटलर ने उठाया तथा 1933 के प्रारम्भ में वह जर्मनी का तानाशाह बन बैठा।

हिटलर के फासीवादी (या नात्सीवादी) विचार हमें उसकी आत्मकथा—Mein Kampf (मेरा संघर्ष)—में मिलते हैं। हिटलर तथा मुसोलिनी, अन्य शब्दों में फासीवाद और नात्सीवाद, के विचारों में तत्त्वतः कोई विशेष अन्तर नहीं है। इनमें इनके विचारों को एक ही अध्याय के अन्तर्गत लेना अनुपयुक्त नहीं होगा। राष्ट्र राज्य, व्यक्ति, इल, नेता, साध्य एवं साधन, विस्तारवाद आदि के विषय में इन दोनों के विचार लगभग समान ही हैं। इस अध्याय में कई स्थलों पर इन दोनों के विचारों को एक रूप में प्रस्तुत कर इनकी समानता को भी व्यक्त किया गया है।

फासीवाद केवल इटली और जर्मनी राज्य तक ही सीमित नहीं रहा, पूर्वी यूरोप के राज्य जैसे स्पेन और पुर्तगाल, तथा कुछ लैटिन अमरीकी राज्यों में भी फासीवादी अधिनायकत्व का प्रादुर्भाव हुआ। दोनों विश्व युद्धों के मध्य फासीवाद यूरोप पर छाया रहा। इटली तथा जर्मनी से समस्त यूरोप भयावह सा प्रतीत होने लगा। मुसोलिनी तथा हिटलर ने विस्तारवादी नीतियों को अपनाया। इन्हीं विस्तारवादी नीतियों के सन्दर्भ में इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने सन्तुष्टिकरण की नीति (Policy of Appeasement) स्वीकार कर फासीवादी विस्तारवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा समर्थन दिया। परिणामस्वरूप इटली ने अबीसीनिया तथा अलबानिया, जर्मनी ने आस्ट्रिया तथा ने कोस्लोवानिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उधर स्पेन में जनरल फ्रैन्को (General Franco) ने उस देश में फासीवादी व्यवस्था की स्थापना की। अन्त में मुसोलिनी तथा हिटलर की विस्तारवादी नीति तथा इसके प्रत्युत्तर में इंग्लैण्ड-फ्रांस के संतुष्टिकरण दृष्टिकोण ने विश्व को दूसरे महायुद्ध में धकेल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवादियों को क्षणिक विजय अवश्य प्राप्त हुई; किन्तु अन्त में उन्हें पराजित होना पड़ा। इस प्रकार विश्व को जो फासीवाद का भय था वह समाप्त हो गया। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह विचारधारा

सद्वच के लिए समान हो गई हो। समय समय पर यह विचारधारा कई देशों में अपना क्रूर स्वर ऊपर उठा लेती है। लेटिन अमरीकी राज्य अभी भी फासीवादी विचारधारा के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाय हैं।

प्रस्ताव एवं पृष्ठभूमि

फासीवाद के बहुत कुछ सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव या प्रचलन इटली में किमी न किमी रूप में प्रत्यक्ष युग में रहा है। प्राचीन काल में इसी क्षेत्र में कई प्रमुख राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। कुछ नगर राज्य निरंकुशता और एकता के लिए प्रतिष्ठित थे। जब रोम साम्राज्य का अन्वुदय एवं विस्तार हुआ, इटली तथा प्रतिष्ठित नगर रोम इस साम्राज्य का केन्द्र थे। उग्र राष्ट्रवाद, एकता, शक्ति राजनीति, विस्तारवाद और निरंकुशवाद रोम साम्राज्य के शासन-सिद्धान्त थे। मुसोलिनी ने रोमन परम्परा का पूर्णतः अनुकरण किया और ये तत्त्व फासीवाद के प्रमुख आधार बन गये।

रोम की देवी (The Goddess Rome) के स्मारक का निर्माण 1870 में किया गया। इस स्मारक को बनाने का उद्देश्य इटली की एकता और एकीकरण को मूर्तरूप देना था। रोम की देवी के प्रति मुसोलिनी की अटूट श्रद्धा थी। इटली की सत्ता सम्हालने के उपरान्त मुसोलिनी ने प्रधानमन्त्री के रूप में अपना सर्व-प्रथम भाषण रोम की देवी के चरणों के पास खड़े होकर दिया। सम्पूर्ण इटली तथा विशेषतः फासीवादियों के लिए यह मूर्ति एक विशेष प्रेरणा की स्रोत थी।²

एकता, गौरव तथा सीमा-विस्तार की आकांक्षा इटली की परम्परा रही है। रोमन साम्राज्य के पतन के उपरान्त इटली शताब्दियों तक अव्यवस्था और विघटन के अधकार में डूबा रहा। चौदहवीं शताब्दी में दान्ते (Dante, 1265-1321) इटली की एकता और विस्तार का प्रथम पैगम्बर सिद्ध हुआ। यह श्रेय दान्ते के ही जाता है कि उसने उस समय इटली की सीमा को स्पष्ट किया। दान्ते के अनुसार इटली की सीमा के अन्तर्गत व सभी क्षेत्र माने चाहिये जिन्हें आजकल, इटली, आस्ट्रिया तथा भूमध्य-सागरीय क्षेत्र कहा जाता है। दान्ते के ग्रन्थ - De Monarchia - में रोम की विश्व-विचार का स्रोत तथा विश्व शासन का केन्द्र कहा गया है। दान्ते के विचारों को मुसोलिनी ने ग्रहण किया। फासीवाद दान्ते के विचारों को पूर्णतः कार्यरूप देना चाहता था। सितम्बर 1933 में फासीवादी आन्ति दशक के समारोह के अन्त दान्ते के मकबरे पर ही हुआ था। यह मकबरा फासिस्टों के लिए एक तीर्थस्थल के समान था।³

पन्द्रहवीं शताब्दी में मेकियावेली (Niccolo Machiavelli, 1469-1527) प्रतिष्ठित व्यवहारवादी और कूटनातिक विचारक हुआ। वह राष्ट्रवाद, निरंकुशवाद

2 Munro, Ion S., Through Fascism to World Power, see footnote to Frontiers piece—The Shrine of Italy

3 पूर्व संस्करण पृ. 7-0

तथा शक्तिवाद का समर्थक था। इस पूर्वगामी विचारक का मुसोलिनी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। फासिस्टों की शिक्षा और आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि कुख्यात मेकि-गार्बेनी एक बार फिर जीवित हो उठा हो।⁴

इटली की एकता, मोरव एवं गरिमा में वृद्धि करने वाले प्रत्येक कार्य को फासिस्ट उचित मानते थे। 1870-71 में इटली का एकीकरण फासिस्टवादियों के समक्ष एक आदर्श घटना थी। इटली के एकीकरण ने इस क्षेत्र के कई छोटे-छोटे राज्यों को एकता के सूत्र में बांध कर एक नये राष्ट्र को जन्म दिया। इस एकीकरण ने इटली की शक्ति और समृद्धि में वृद्धि की तथा इसकी गणना मोरोप के अग्रणीय राज्यों में की जाने लगी। मुसोलिनी इस एकीकरण को अंतिम रूप देना चाहता था। उनका उद्देश्य इटली को एक भूमध्य-सागरीय शक्ति बनाना था जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रभावशाली योगदान दे सके।

फासीवाद के प्रेरणा-स्रोत अष्टादशवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में प्रचलित आदर्शवाद (Idealism), डार्विनवाद (Darwinism), अविज्ञानवाद (Irrationalism) और परम्परावाद (Traditionalism) आदि विचारधाराएँ थीं। इन विचारधाराओं से फासीवाद और नात्सीवाद ने बहुत से सैद्धान्तिक तत्त्व ग्रहण किये हैं। आदर्शवादियों में नान्त (Immanuel Kant, 1724-1804) तथा हीगल (Friedrich Hegel, 1770-1831) ने फासीवादियों को बहुत प्रभावित किया। हीगल का आदर्शवाद पूर्णतः राजसत्ताधारी और निरंकुशवादी था। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इटली में नव-हीगलवाद का प्रादुर्भाव हुआ। यह व्यक्तिवादी, उदारवादी परम्पराओं के विरुद्ध था। राज्य को वे अवयवी (Organic) और स्वयं-राज्य तथा व्यक्ति को साधन मात्र मानते थे। रूस में इन्होंने राज्य को सर्वोपरिता का प्रतिपादन किया। इटली के प्रसिद्ध विद्वान् गिओवानी गेंटाइल (Giovanni Gentile) नव-हीगलवाद के प्रयोग समर्थक थे जो मुसोलिनी के शासन काल में राज्य के शिक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रीय फासीवादी सांस्कृतिक संस्थान के निदेशक रहे। इन्होंने फासीवादी विचार-धारा का समय-समय पर विवेचन कर शासन व्यवस्था को बड़ा प्रभावित किया।

डार्विनवाद—उन्नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin) से फासीवादियों ने बहुत कुछ ग्रहण किया। डार्विन के विकासवादी सिद्धान्त (Evolutionary Theory) के अनुसार प्राणियों को जीवित रहने के लिये संघर्ष करना पड़ता है। जो सबल है वही जीवित और अपना अस्तित्व बनाये रखने में सक्षम होता है; निर्बल नष्ट हो जाते हैं। अन्य शब्दों में डार्विनवाद इन तत्त्वों पर आधारित था कि—

- (i) प्रगति के लिये संघर्ष आवश्यक है; डा. गेंटाइल
- (ii) यह संघर्ष व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं, समूहों में भी चलता है;

4. आशीर्वादिन्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ. 664.

(iii) वह समूह विजयी होता है जिसमें एकता और अनुशासन होता है। समाजिक डार्विनिवाद के इन सिद्धान्तों ने फासीवाद-नास्तोवाद को अत्यधिक प्रभावित किया। फासीवाद के सघर्ष तथा विस्तारवादी विचार-सूत्र इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त हैं।

अद्विवेकवाद—फासीवाद बोसवी शताब्दी में 'बुद्धि के प्रति विद्रोह' (Revolt against Reason) का व्यावहारिक रूप था।⁵ अबुद्धिवाद अथवा अद्विवेकवाद में बुद्धि तथा विवेकपूर्ण तर्क का कोई स्थान नहीं होता। फासीवादियों पर अबुद्धिवादी विचारक शॉपेनहोर (Arthur Schopenhauer, 1788-1860) नीत्से (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) सोरेल (George Sorel, 1847-1922) और बर्गसा (Henry Bergson, 1859-1941) का प्रमुख प्रभाव था। वे सोरेल और बर्गसा के अन्तर्प्रेरणा मिद्धात को स्वीकार करते थे। इसके अनुसार मनुष्य बुद्धि से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता। वास्तविकता यह है कि मनुष्य अपने आचरण में मूल प्रवृत्तियों एवं भावनाओं के बन्धीभूत रहता है न कि विवेक या तर्क से।⁶ फासीवाद तर्कसंगत विचारधारा तो थी नहीं। इसको जनप्रिय बनाने का प्रमुख साधन यही था कि मनुष्य की भावनाओं को यश राष्ट्रवाद आदि से उकसाया जाय जो अन्धविश्वास की तरह उनका पालन करे। मुसोलिनी तथा हिटलर ने इन्हीं मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण किया था। वे राष्ट्र एवं जाति के नाम पर ऐसी छद्म एवं विश्वास का सर्जन करना चाहते थे जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करे। वे सत्य के स्थान पर भ्रान्ति (myth) को प्राथमिकता देते थे। यही कारण है कि फासीवाद तर्क या प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, यह तो केवल इच्छा और विश्वास के कारण ही सत्य है।⁷

परम्परावाद—अद्विवेकवाद पर आधारित परम्परावाद फासीवाद का मूल प्रेरणा सत्व था। परम्परावाद भ्रान्तिकारी विचारधाराओं के विपरीत है। भ्रान्तिकारी विचारधारारों पुरातन एवं परम्परागत व्यवस्था को उखाड़कर नई व्यवस्था की स्थापना करती है। लेकिन परम्परावादी लडिया तथा पुरातन तत्वों के सम्पर्क होने हैं। इटली के प्रसिद्ध परम्परावादी विचारक जॉजफ् मत्सीनी का विचार था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास में परम्पराओं का विशेष योगदान रहता है। जिन राष्ट्रों ने अपने समाज की परम्पराओं का पोषण किया है वे बड़े राष्ट्र बने हैं। शासन सत्ता प्राप्त करने, उसे बनाये रखने के लिये फासीवादियों ने परम्परावादी दृष्टिकोण का ही आश्रय लिया। फासीवादी शासन के समर्थन में मुसोलिनी सदैव प्राचीन परम्पराओं के उदाहरण देता था। वह रोम साम्राज्य के गौरव को जनता के समक्ष रखकर उनकी भावनाओं को शासन के प्रति श्रद्धा में परिवर्तित करता था।

⁵ Hallowell, J H, Main currents in Modern Political Thought, p 604

⁶ Lancaster, L W, Masters of Political Thought, Vol III, p 267.

⁷ आशीवादिम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ 662.

फारसीवाद के उत्थान एवं प्रगति में इटली के निम्न मध्य-वर्ग से अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ। मुसोलिनी स्वयं इसी वर्ग से सम्बन्धित था। फारसीवादी दल के अधिपति सर सदस्य वूल्फ, लोटार, डबल रोटी बनाने वाले, छोटे-छोटे दुकानदार एवं पूंजीपति थे। यह वर्ग श्रमिक वर्ग एवं पूंजीवर्ग दोनों से ही डरे रहता है। यह समाजवादी व्यवस्था से डरता है क्योंकि इसके अन्तर्गत उसकी छोटी सी पूंजी अन्त होकर वहीं उनकी स्थिति धिको जैसी ही न हो जाय। निम्न मध्यवर्ग पूंजीपतियों की सम्पत्ति और वैभव से भी चिन्तनस्व रहता है। मुसोलिनी का पर्यक्रम इस मध्यवर्ग की मनोवृत्ति को सन्तुष्टि करना था, उसका चार्म-वर्ग इसी वर्ग के अनुकूल था। पूर्णतः मुसोलिनी पूंजीपतियों के एकाधिकार और श्रमिकों की द्रवित दोनों का ही विरोधी था, इसलिये निम्न मध्यवर्ग न उसका पूरी तरह साथ दिया। यही वर्ग मुसोलिनी की लोकतान्त्रिक धारणा की सन्तुष्टि कर फारसीवादी व्यवस्था पर लोकप्रिय आधार रख डालने में सहायक हुआ।

तत्कालीन परिस्थितियों की उपज: अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति—: इटली में फारसीवाद तथा जर्मनी में नात्सीवाद के उद्भव के तत्कालीन कारण प्रथम विश्वयुद्ध के उपरान्त शान्ति सन्धियों में निहित थे। इसी शान्ति सन्धियों के प्रावधानों के परिणामस्वरूप यूरोप में अधिनायकवाद का प्रादुर्भाव हुआ और इसी शान्ति सन्धियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को आमन्त्रण दिया। यद्यपि इटली प्रथम विश्वयुद्ध में विजयी राज्य था, जिन आशाओं को लेकर उसने इंग्लैंड, फ्रांस आदि का साथ दिया था युद्ध के उपरान्त पूरी नहीं हुई। युद्ध के पूर्व इटली 'त्रिदेशीय सन्धि' (Triple Alliance, 1882) का सदस्य था। किन्तु अप्रैल 26, 1915, को लन्दन में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और इटली के मध्य एक गुप्त सन्धि हुई जिसके अन्तर्गत इटली को धन तथा बर्तुत का प्रदेश देने का वचन दिया। युद्ध के उपरान्त इटली को आशा थी कि शान्ति सन्धियों के अन्तर्गत उसे आस्ट्रिया का कुछ भाग तथा अफ्रीका में कुछ उपनिवेश प्राप्त होंगे। उसे प्रमुख भूमध्यसागरीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया जायगा।⁸ इंग्लैंड तथा फ्रांस अपने साम्राज्यवादी धर्मों की ही दृष्टि में तीन रटते तथा पराजित क्षेत्रों को इन्होंने स्वयं ही हड़प लिया। इटली को निराशा के अतिरिक्त और कुछ न मिल सका। भूमध्यसागरीय प्रदेश न तो इटली के प्रभाव क्षेत्र में आ सके और न ही वह राष्ट्रसभ में कोई प्रभाव अर्जित कर सका। इटली ने युद्ध के उपरान्त सभी व्यवस्थाओं को सदैव अपने अधिमान समझा। इस असन्तोष का मुसोलिनी ने अपने लिए सत्ता में आने के लिए पूर्णतः प्रयोग किया। मुसोलिनी स्वयं ही इस गहरे असन्तोष की भावना का मूर्तरूप था।⁹

8 Marriot, J A R., Modern England, 1885, 1943, p 393.

9 आशीर्वादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय भाग, पृ० 660.

आन्तरिक परिस्थिति—इटली में लोकतांत्रिक एवं ससदीय परम्पराओं की जड़ें कभी भी गहराई तक नहीं पहुँच पायीं। 1861 से, जबकि इटली के कई राज्य, इटली के राज्य में परिणत हो गये उस समय में अंग्रेजी ढंग की ससदीय पद्धति स्थापित की गई, किन्तु यह व्यवस्था सफल न हो सकी। इटली में जो छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित हुए वे मध्ययुग से हीस्वान्त रहते प्राये थे, जिनकी राजनीतिक परम्पराएँ निम्न थीं वहाँ उत्तरदायी शासन प्रणाली की सफलता सम्बन्धि ही थी। राजनीतिक दलों की अधिपत्या और अस्थिरता, स्थानीय परम्पराओं की शक्ति और जनता में निरक्षरता की व्यापकता के कारण वहाँ ससदीय शासन प्रणाली को कार्यान्वित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।¹⁰

व्यावहारिक राजनीति में नीकरशाही, निर्वाचन सम्बन्धी अप्टाचार, भ्रयोग्य एवं महात्वाकांक्षी नेतृत्व, जनता की राजनीतिक उदासीनता एवं अज्ञानता का लोकतन्त्र की अक्षमता में मुख्य योगदान था। डिप्रेटिस (Depretis) 1878 से 1887 तक आठ बार प्रधानमंत्री बने। इससे प्रशासनिक अस्थिरता की अभिव्यक्ति तो होती ही है किन्तु शासन-सत्ता को प्रदग्ध करने के लिए डिप्रेटिस ने ग्राम चुनावों में खूली धमकी, रिश्वतखोरी तथा दगाव आदि का प्रयोग किया। क्रिस्पी (Crispi) का शासनकाल स्वेच्छाचारिता, निरकुशता, अमीबो का दमन और लोकतान्त्रिक स्वतंत्रता का अक्षयकरण करने के लिए प्रसिद्ध था। प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व जिओलिट्टो (Giollitti) का उदार एवं राजतन्त्रवादी था, राजनीतिक गतिविधियों में दगाव एवं अप्टाचार से मुक्त नहीं था। लोकतन्त्र के इस अक्षम प्रयोग का विकल्प इटली के लोगो की फासीवाद में मिला।

प्रथम विश्व युद्ध के कारण इटली की अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी। विश्व का विस्तीय निष-अणु अन्य विजेता राज्यों के हाथों में पहुँच चुका था। लड़न सन्धि के अन्तर्गत इटली को लगभग पाँच करोड़ पाँड का ऋण मिलने को था, वह भी नहीं मिल सका। युद्ध बन्द होने के उपरान्त मैना तथा अन्य उद्योगों में छूटनी की गयी जिससे बेरोजगारी में काफी वृद्धि हुई। दूसरी ओर अमीबो द्वारा हड़तालों से उत्पादन में निरन्तर कमी होती जा रही थी। इटली की जनना बढ़ती हुई कीमतों, आवश्यक वस्तुओं के अभाव से परेशान हो चुकी थी उसने असतोप व्याप्त था। इटली की तत्कालीन औद्योगिक सरकार इन परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ सिद्ध हुई। शांति एवं व्यवस्था लगभग भंग होनी चली जा रही थी। 1922 के मध्य इटली में तनाव, असतोप और गृह-युद्ध जैसी स्थिति थी। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और इटली की आन्तरिक परिस्थिति ने मुसोलिनी को सत्ता प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

¹⁰ नीकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 487.

Ebenstein, William, Modern Political Thought, p 357

फासीवाद एवं नात्सीवाद

दूसरे साथ-साथ मुसोलिनी के व्यक्तिव में सैनिकवाद¹¹, अधिनायकवाद, राष्ट्रवाद, अवसरवाद आदि के तत्त्व विद्यमान थे ही। वह सम्पूर्ण इटली को एक गून में बांध कर देश में शान्ति, व्यवस्था, अनुशासन, समृद्धि लाकर उसे यूरोप में प्रथम श्रेणी की शक्ति बनाना चाहता था। पहली अगस्त 1922 को फासीवादियों ने समस्त देश में हड़ताल की घोषणा की। यह हड़ताल काफी सफल रही। 28 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने अपने अनुयायियों के साथ रोम पर धावा बोलकर शासन पर लगभग अधिकार सा कर लिया। 30 अक्टूबर को इटली के सच्चाट ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया। यही से इटली में फासीवादी अधिनायकवाद का युग प्रारम्भ हुआ।

फासीवादी प्रादुर्भाव की मार्क्सवादी व्याख्या

फासीवादी उत्थान के विषय में मार्क्सवादी व्याख्या भी उल्लेखनीय है।¹² मार्क्सवादियों के अनुसार फासीवाद पूँजीपतियों का पडपन्धमात्र था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप यूरोप में भुखमरी, बेरोजगारी, निर्धनता में निरन्तर वृद्धि हो रही थी। कुछ समय पहले (1917) रुम में साम्यवादी शक्ति हो चुकी थी। यूरोप का श्रमिक-वर्ग इसी शक्ति से प्रेरणा प्राप्त कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। इस भाव्य को लेकर इटली में एक समाजवादी दल भी विकसित हुआ। 1919 में साम्यवादियों के नेतृत्व में हड़तालों की शृंखला प्रारम्भ हुई। 1920 में लगभग दो हजार हड़तालें हुईं, जिससे जनजीवन बड़ा ही अस्त-व्यस्त रहा। इसी वर्ष श्रमिकों ने उद्योगों तथा अन्य आर्थिक प्रतिष्ठानों पर भी अधिकार करना प्रारम्भ कर दिया था। 1920 के अन्त में जब नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उनमें साम्यवादियों को भारी सफलता मिली तथा उन्होंने कई नगरों पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना भी करली थी।¹³

मुसोलिनी को समाजवादियों से घृणा थी तथा उसने समाजवादियों का खुलकर विरोध किया। फासीवादी अनुयायियों ने साम्यवादी तथा समाजवादी सभाओं को भंग किया, उनके समाचार-पत्रों के कार्यालयों को जला उाला तथा उनके नेताओं के साथ दुर्भेद्यहार किया गया। साम्यवादी तथा समाजवादियों के प्रति फासीवादियों ने आतंक-

11. मुसोलिनी स्वयं ही सैनिक रहे चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में वह दो वर्ष तक सक्रिय सैनिक था।
12. फासीवादी उत्थान के लिये मार्क्सवादी व्याख्या का विस्तृत विवरण इस पुस्तक में मिलता है—

Bradly, Robert A., *The Spirit and Structure of German Fascism*,
New York, 1937.

13. Charaous and Ewen, *Profits and Politics in the Post-War World* — 60 60

वादी मान ग्रपनाया । फासीवाद का नारा था 'समाजवादी खतरे का अन्त करो।' समाजवाद विरोधी नीति न मुसोलिनी की पूँजीपति क्षेत्र में बड़ा लोकप्रिय बना दिया।

इटली के पूँजीपतियों को उस समय साम्यवाद का सबसे अधिक भय था। रूस, आस्ट्रिया, हंगेरी आदि के उदाहरणों से प्रेरणाहित हो इटली का श्रमिक-वर्ग पूँजीपतियों के लिए एक खतरा बन गया था। साम्यवादी ऊपर एक उदार का मामला करने के लिये पूँजीवग कोई नई व्यवस्था चाहता था। इटली की लाकतान्त्रिक व्यवस्था साम्यवादी विस्तार का सामना करने में असमर्थ थी। जिस समय यह स्थिति थी उस समय इटली में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं था जिसका समर्थन में बहुमत हो तथा स्याई सरकार बना सके। इटली में ही विभाजित थे। इसलिये इटली के पूँजीपति मुसोलिनी के समाजवाद विरोधी विचारों से बड़े प्रभावित हुए।

पूँजीपतियों के लिये मुसोलिनी से अधिक उपयोगी और कौन हो सकता था जिसने समाजवादी आन्दोलन को समाजवादी शब्दों से ही काट करन की क्षमता हो। अतः उन्होंने लोकतन्त्र का आवरण उतार कर अधिनायकवाद की समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार फासीवाद पूँजीपतियों द्वारा साम्यवादी शक्ति को रोकने के लिये एक साधन था। यही कारण था कि इटली और जर्मनी के अधिनायकों ने श्रमिक आन्दोलनों को दशान तथा साम्यवादी विचारों का दमन करने के लिये जब राज्य शक्ति का पूरा प्रयोग किया, पूँजीपतियों ने इनका पूरी तरह सहायता दिया। इस फासीवादियों और पूँजीपतियों का सहयोग एक पड़व्यक्त व्यक्त होगा है।¹⁴ साम्यवादियों ने फासीवाद को पूँजीवाद के पतन की चरम सीमा कहा है।¹⁵

फासीवाद को पूँजीवाद का ही पड़व्यक्त मानना भूल होगी। मुसोलिनी का व्यक्तित्व अवसरवादिता पर आधारित था। स्वयं को सत्ता में बनाये रखने के लिये मुसोलिनी सभी धर्मों का समर्थन किसी न किसी प्रकार प्राप्त करता रहता था। उसने श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये पूँजीवादी विरोधी नारों का भी खूब प्रयोग किया।¹⁶ सम्भवतः उसने पूँजीपतियों और श्रमिकों दोनों का ही कमजोरियों का लाभ उठाया। फिर भी यह सत्य है कि पूँजीपतियों ने फासीवाद को खूब चन्द दिया, समर्थन दिया और साम्यवादी खतरे को सदैव ही दूर रखा।

फासीवादी विचारधारा

फासीवाद लगभग इक्कीस वर्ष तक इटली की राजकीय विचारधारा रहकर भी कोई निश्चिन्त एक तर्कमग्न दर्शन नहीं बना सका। राम पर धावा बोलने के पहले फासिस्टों के पास सिद्धान्तों में उलझने का समय ही नहीं था। इनके अलावा फासीवादियों का सिद्धान्तों से बंधकर रहने में भी कोई विश्वास नहीं था। अपने एक

14 Hallowell, J H, Main Currents in Modern Political Thought, p 592

15 Ebenstein, W, Modern Political Thought, p 359

16 Ebenstein W, Modern Political Thought, p 357

लेख¹⁷ में मुसोलिनी ने इस पक्ष को कई स्थलों पर स्पष्ट किया है। मुसोलिनी ने लिखा है कि "ग्रीपचारिक सिद्धान्त लोहे तथा टीन की चेड़ियाँ हैं। फासिस्ट इटली की राजनीति के जिप्सी हैं। वे किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों से बंधे नहीं हैं।" "हम विवाद और सिद्धान्त के बादलों में निकलना चाहते हैं। मेरा कार्यक्रम कार्य है, बातें नहीं।" इसके आगे मुसोलिनी ने लिखा है—

"हमारा कार्यक्रम सरल है। हम इटली पर शासन करना चाहते हैं। वे हमसे कार्यक्रम पूछते हैं, किन्तु पहले से ही बहुत से कार्यक्रम हैं। वास्तव में इटली की मुक्ति के लिए कार्यक्रमों की कमी नहीं। आवश्यकता है मनुष्यों की तथा इच्छाशक्ति की।"¹⁸

इस तथ्य को प्रमिद्ध फासीवादी विचारक एल्फ्रेडो रॉको (Alfredo Rocco) ने व्यक्त करते हुए लिखा है—

"यह सत्य है कि फासीवाद मुख्यकर कार्य तथा भावना है और उसे ऐसा ही बना रहना चाहिए। यदि इसके विपरीत बात हुई, तो वह अपनी उस प्रेरक शक्ति को, उस नवीनीकरण की शक्ति को स्थिर नहीं रख सकता जो उसमें इस समय है, और उस समय वह कुछ चुने हुए व्यक्तियों की मनन की ही चीज रह जायेगा।"¹⁹

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि फासीवादी दर्शन कार्य साधक रहा है। किये हुए कार्यों का औचित्य सिद्ध करना, आने वाली परिस्थितियों का सामना करना और आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर विचारों में परिवर्तन करना, फासीवाद की प्रमुख नीति थी। फासीवाद में कार्य को प्राथमिकता होने के कारण सिद्धान्तों का निर्माण एवं निर्माण कार्य द्वारा ही हुआ। उन्होंने पहले कार्य किया तथा बाद में उस कार्य को सही ढंग से करने के लिए विचार व्यक्त किये। जब मुसोलिनी की स्थिति मुहड़ हो गयी तो उसने मनमाने ढंग से कार्य किये। उन्हें उचित ठहराने तथा सिद्धान्तिक बनाने में उसने फासीवादी दर्शन की रचना कर डाली। वास्तव में फासीवादी विचारधारा तदर्थ (Ad hoc) विचारों का संकलन था। संबाइन ने लिखा है कि फासीवाद विभिन्न स्रोतों से लिये गये उन विचारों का योग है जो परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार एकत्रित किए गए हैं।²⁰

मह बहना कि फासीवाद का कोई विचार-दर्शन नहीं था, फासीवाद के जो भी विचार मूल थे वे तर्कहीन, असंगत तथा तदर्थ थे, इनमें सत्यता तो है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता। यद्यपि फासिस्ट राज्य की स्थापना किमी पूर्व प्रचलित

17. The Political and Social Doctrine of Fascism, 1935.

18. Ibid.,

19. Alfredo Rocco, The Political Doctrine of Fascism, 1926, p. 10.

20. Sabino, A., History of Political Theory, p. 710.

विचारधारा पर नहीं की गयी, लेकिन जैसे ही इटली में फासिस्ट व्यवस्था की स्थापना हुई फासीवाद को एक क्रमबद्ध या दार्शनिक रूप देने का प्रयत्न किया गया। मुसोलिनी तथा अन्य सहायकों ने फासीवाद के विषय में समय समय पर विस्तारपूर्वक विचार व्यक्त किये हैं, जिनका प्रकाशन दिन प्रतिदिन की पुस्तिकाओं—*The Political and Social Doctrine of Fascism—Day to day Pamphlet*—में होता रहता था। लगभग दस वर्षों के पश्चात् मुसोलिनी ने फासीवादी विचारधारा के विषय में चिन्तन करने का समय मिला। 1932 में मुसोलिनी ने—*The Doctrine of Fascism* (फासीवाद के सिद्धान्त) नामक निबन्ध लिखा जिसका प्रकाशन एनसाइक्लोपीडिया इटेनियाना (*Encyclopaedia Italiana*) में हुआ।²¹ यह फासीवाद का प्रारम्भिक अधिष्ठित अभिरूढन है। इसमें मुसोलिनी ने फासीवाद के दार्शनिक, नैतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावहारिक दैयत्तिक, सामूहिक राजनीतिक आदि पक्षों की स्पष्ट व्याख्या की है।

मुसोलिनी के अनिर्दिष्ट कुछ अन्य फेसिस्ट सिद्धान्तवादियों के नाम प्रसिद्ध एवं उल्लेखनीय हैं। एल्फ्रेडो रोकको (Elfredo Rocco) जो पहले वेनुषा के विश्वविद्यालय में व्यावसायिक कानून का प्रोफेसर और फेसिज्म के उदय के पूर्व उत्साही राष्ट्रवादी था, सन् 1925 से 1932 तक न्याय मन्त्री रहा और इटली के फेसिस्ट शासन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कानूनों का निर्माता था। जियोवेनी जेण्टाइल (Giovanni Gentile) जो इटली का प्रसिद्ध हेगलवादी दार्शनिक था और 1922 के बाद ही फेसिस्ट बना, सन् 1922 से 1924 तक शिक्षामन्त्री रहा तथा इटली की शिक्षा प्रणाली में मौलिक सुधार किये। एनरिको कोर्रादियो (Enrico Corradini) जो फेसिज्म के एक दशक से पूर्व सीनेटर तथा राष्ट्रीयता का प्रचारक था, ल्यूगो फेडरजोनी (Luigi Federzoni) राष्ट्रवादी दल का एक संस्थापक, प्रथम फेसिस्ट कैबिनेट में उपनिवेश मन्त्री, बाद में गृहमन्त्री और उपनिवेश मन्त्री तथा सन् 1929 से सीनेट का अध्यक्ष था, मोरजियो मारविग्लिया (Maurizio Maraviglia) जो पहले फेसिस्ट प्रचार-कार्यालय का प्रमुख था, रॉबर्टो फोर्जेस-दवन्जात (Roberto Forges-Davanzati) नामक राष्ट्रीयवादी (बाद में फासिस्ट) समाचार पत्र भी फासीवादी विचारधारा का एक प्रमुख मुखपत्र समझा जाता था।²²

फासीवादी राज्य

राष्ट्र की कल्पना या भ्रान्ति (myth of nation)

फासिस्ट विचारधारा सकुचिन एवं उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित है। राष्ट्र व्यक्तित्वा का एक ऐसा धनुत्प समूह है जो सामान्य भाषा, प्रथा परम्पराओं तथा धर्म

²¹ This essay has been reproduced in *Through Fascism to World Power* by Ion Munro, part II, Chapter 1

²² बोर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ 502.

से बंधा हुआ है। राष्ट्र को गौरवान्वित करना उनका धर्म है। फासीवादियों के अनुसार राष्ट्र स्वयं का एक व्यक्तित्व, एक इच्छा तथा उद्देश्य होता है। राष्ट्र अपने में एक आत्मनिर्भर इकाई है, जिसका जीवन स्थिर तथा स्थायी होता है। राष्ट्र समस्त सामाजिक जीवन का उद्देश्य है। व्यक्तियों का महत्व केवल राष्ट्रीय प्रसंग में है, उससे पृथक् होकर नहीं। व्यक्तियों का कर्तव्य राष्ट्र की सेवा करना है तथा उनके वे ही कार्य विचार तथा भावनाएँ अन्तर्नीय समझी जायेंगी जो राष्ट्र-शक्ति के विकास में सहायक हों। इस प्रकार फासीवादी एक राष्ट्र की कल्पना अथवा पौराणिकता अथवा भ्रान्ति अथवा 'मिथ' (myth of nation) में विश्वास करते हैं। यही उनके राज्य दर्शन का आदि एव अन्त है। अपने एक महत्त्वपूर्ण भाषण में इस भावना को व्यक्त करते हुए मुसोलिनी ने कहा था कि—

“हमने अपनी कल्पना (myth) का सर्जन कर लिया है। यह कल्पना विश्वास है, भावावेग है। यह आवश्यक नहीं है कि इसमें वास्तविकता हो। यह वास्तविक इसलिए है क्योंकि यह एक प्रेरणा है, एक विश्वास है, एक साहस है। हमारी कल्पना राष्ट्र है, राष्ट्र की महानता है। इस कल्पना, इस महिमा को हम पूर्ण वास्तविकता में परिणत करना चाहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिये हम सब अर्पणस्थ हैं।”²³

प्रारम्भ में फासीवादी राष्ट्र तथा राज्य में राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं किन्तु बाद में वे राष्ट्र तथा राज्य में भेद नहीं करते। वे राज्य का तात्पर्य राष्ट्रीय राज्य से लेते हैं। राज्य, राष्ट्र-कल्पना की अभिव्यक्ति करता है। तथा उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। फासीवाद राज्य को एक ऐसी आध्यात्मिक इकाई मानते हैं जिसके द्वारा राष्ट्र को राजनीतिक तथा आर्थिक संगठन प्राप्त होता है। मुसोलिनी के शब्दों में “राज्य, राष्ट्र का राजनीतिक, वैधानिक तथा आर्थिक संगठन है, इसलिए उसे राष्ट्र को आत्मा का मूर्त रूप मानना चाहिए।”²⁴ किन्तु आगे चलकर फासीवादी राज्य को अधिक महत्त्व देने लगते हैं। राष्ट्र संगठित एवं शक्तिशाली राज्य के माध्यम से ही हो सकता है। इस विचार प्रक्रिया में वे राज्य को राष्ट्र से एक स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान कर देते हैं। मुसोलिनी ने लिखा है:—

“राष्ट्र राज्य को जन्म देता जैसा कि उन्नीसवीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्य के प्रचारकों ने समर्थन किया है। इसके विपरीत राष्ट्र का निर्माण राज्य के द्वारा होना है जो व्यक्तियों को उनकी नैतिक एकता, इच्छा तथा समर्थ अस्तित्व को जेतना प्रदान करता है।”²⁵

23. Naples, October 24, 1922, Quoted by H. Finer in *Mussolini's Italy*, New York, 1935, p. 218.

24. Mussolini, B., *The Political and Social Doctrine of Fascism*, Day to day Pamphlet, No. 18, 1933, p. 22.

25. Quoted, Munro, Ion S., *Through Fascism to World Power*, p. 307.

राज्य का अधिनायकवादी स्वरूप

फासिस्टवाद अधिनायकवादी राज्य को प्रेरणा देता है। वे व्यक्तिवादी धारणा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, का पूर्ण खण्डन करते हैं। वे साम्यवाद, अराजकतावाद और सिन्डिकलवाद की भाँति राज्य के घट कराने का विचार स्वीकार नहीं करते। इसका विपरीत फासिस्टवाद राज्य हेगल के दर्शन पर आधारित था। तदनुसार राज्य एक नैतिक तथा धार्मिक विचार है जो समाज को आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति कराता है। फासिस्टवादी धर्म राज्य को ईश्वर तुल्य मानन की प्रेरणा देता है, जिससे अन्तर्गत राज्य को अन्ध-विश्वास की तरह स्वीकार करना चाहिए। फासिस्टवादी राज्य सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी है। उसे सब शत्रु तथा गतिविधियों पर निषेध रखने का अधिकार है, वह जीवन के प्रत्येक पहलु में हस्तक्षेप कर सकता है। मुसीबती के क्षण में 'सब राज्य के अन्तर्गत हैं, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं तथा कोई भी राज्य का विरोध नहीं कर सकता।'²⁶

राज्य तथा व्यक्ति

फासिस्टवादी राज्य में व्यक्ति की पूर्ण उपेक्षा की गयी है। इस विचारधारा में व्यक्ति राज्य या समाज में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। इस सन्दर्भ में उनकी निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण मान्यताएँ हैं—

प्रथम, फासिस्टवादी राज्य व्यक्तिवादी प्राणविक सिद्धान्त का खण्डन कर सां-यविक स्वरूप (Organic nature) को स्वीकार करते हैं। व्यक्तियों का राज्य में वही स्थान होता है जो शरीर में अंगों का। राज्य के बिना व्यक्ति अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। राज्य में पृथक व्यक्तियों का कोई आध्यात्मिक और नैतिक जीवन नहीं हो सकता। राज्य एक अनिवार्य प्राकृतिक सस्था है।

द्वितीय, फासिस्टवादी राज्य स्वयं में साध्य है तथा व्यक्ति साधन। राज्य का प्रमुख उद्देश्य अपनी शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि करना है, इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। राज्य तथा व्यक्ति के सम्बन्धों की व्याख्या करते हुए मुसोलिनी ने कहा था—

“राज्य मनुष्य के ऐतिहासिक अस्तित्व की सार्वभौम इच्छा और अन्त करण है। उदारवाद न विशिष्ट व्यक्ति के स्वार्थों के लिये राज्य को अंगी-कार किया, किन्तु फासिस्टवाद राज्य को ही व्यक्ति की सच्ची आस्तविकता मानता है। अतः फासिस्टवाद के लिये सब कुछ राज्य के अन्तर्गत ही है, राज्य के अन्तर्-जिमी मानवीय अस्तित्व, आध्यात्मिक तत्त्व, अस्तित्व नहीं हो सकता, मूल्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी अर्थ में फासिस्टवाद समग्र-वादी है और फासिस्टवादी राज्य सब मूल्यों और मान्यताओं की एकता है, वह

जनता के सम्पूर्ण जीवन का निर्वचन, उसका विनाश और उसे शक्ति देता है ।' 27

फासीवादी लोग राज्य को केवल वर्तमान से ही नहीं, अतीत और भविष्य से भी बधा हुआ एवं सम्बन्धित मानते हैं। राज्य सदियों से भाषा, विश्वास, रीति-रिवाजों के विकास का परिणाम है, जिसकी तुलना में मनुष्य का अल्प जीवन कुछ भी नहीं होता। राज्य को व्यक्ति की सीमाओं से किसी भी प्रकार नहीं बाधा जा सकता। राज्य व्यक्तियों और पीढ़ियों को एक परम्परा और उद्देश्य सूत्र में बाधता है। इससे व्यक्ति-जीवन को विस्तार मिलता है। इन धारणाओं से स्पष्ट है कि फासीवादी राज्य में स्वतन्त्रता का कोई स्थान नहीं है। राज्य के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का कोई महत्त्व नहीं। व्यक्ति राज्य में विलीन होकर ही अपना विकास तथा स्वतन्त्रता का उपभोग कर सकता है। स्वतन्त्रता क्या है, स्वतन्त्रता किन-किन बातों में निहित है, कौन-कौन सी स्वतन्त्रताएँ व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिये, इसका निर्णायक राज्य है, न कि व्यक्ति। कानून और स्वतन्त्रता की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति राज्य है, राज्य की अधिकतम शक्ति ही व्यक्ति की अधिकतम स्वतन्त्रता है। राज्य में व्यक्ति का निषेध नहीं बल्कि स्वयं कई गुना हो जाता है। प्रसिद्ध फासिस्ट विचारक अल्फ्रेड रॉको (Alfred Rocco) ने राज्य तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विषय में इस प्रकार व्याख्या की है—

“फासीवादियों को व्यक्तियों के अधिकारों का घोषणा-पत्र स्वीकार नहीं है जो व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठतर बना देता है और उसे समाज के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। हमारा स्वतन्त्रता सम्बन्धी विचार यह है कि व्यक्ति राज्य की ओर से अपना विकास करे।”

इन सिद्धान्तों पर आधारित इटली तथा जर्मनी के फासीवादी राज्य अधिनायकवादी थे, जहाँ राज्य के कार्य-क्षेत्र की कोई सीमाएँ नहीं थी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप था। सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे शिक्षा, संगीत, विज्ञान, चित्रकला, फैशन आदि सब पर शासन का नियन्त्रण था। प्रेस राज्य के हाथों कठपुतली था नये विचारों के प्रतिपादकों के लिए कारागार के बराबर सदैव खुले रहते थे।

फासिस्ट दल

यदि राज्य राष्ट्र की भावना व्यक्त करता है, तो राज्य व्यवस्था का मुख्य दायित्व फासीवादी दल पर रहता है। दल फासीवादी शासन व्यवस्था का आधार निर्देशन केन्द्र था। फासिस्ट प्रणाली 'एक दलीय राज्य' (Mono-party State) पर आधारित थी। दल तथा राज्य के संगठन प्रायः समान थे। या, दल तथा राज्य

के कार्यों में कोई अंतर स्थापित करना अशक्य था।²⁸ मुगोलिनी और हिटलर दोनों ही पार्टी के संगठन, एकता अनुशासन में विश्वास रखते थे। इटली में फासिस्ट दल के सदस्यों की संख्या बड़ी सीमित थी, सदस्यों की भर्ती बड़ी सावधानी और सतर्कतापूर्वक की जाती थी। उन्हें व्यापक प्रशिक्षण तथा बटोर अनुशासन से होकर तैयार करना पड़ता था। लेकिन जो भी व्यक्ति दल के सदस्य होने से, समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी तथा उनका महत्व एवं प्रभाव उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से भी अधिक रहता था।

एक-दलीय व्यवस्था होने के कारण फासिस्ट दल ही मताधारी दल था। इसमें विरोधी दलों के अस्तित्व की स्वीकार नहीं किया जाता। फासी दल के विरोध का तात्पर्य राज्य का विरोध करना था। कोई भी दल या सरकार का विरोध नहीं कर सकता था। 1926 में इटली में समस्त राजनीतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। इटली की ससद के एक प्रतिद्वंद्व सदस्य मट्टोटी (Matteoti) की विरोधी होने के नाते रूसमयी दंग से हत्या कर दी गई। उनका अपराध केवल यह था कि ससद में उन्होंने अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त किये। इसी प्रकार काउन्ट बाल्बो (Count Balbo) के जीवन का अन्त अफ्रीका में बड़ी ही सदिग्ध परिस्थितियों में हुआ। इन सब में फासिस्टों का हाथ बतलाया जाता है।²⁹ नू रि फासिस्ट दल सीमित तथा विशिष्ट योग्यता वाले सदस्यों का ही समुदाय होता है जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता, शासन की वास्तविक वागडार इसी विशिष्ट वर्ग के हाथों में आ जाती है। यह जनता का न होकर एक कुलीनतन्त्रीय जैसा हो जाता है।

फासिस्ट नेतृत्व

फासीवादी दल की नीतियों के निर्धारण एवं कार्यान्वयन करने में नेतृत्व का सबसे प्रमुख स्थान रहता है। फासीवादियों की यह धारणा थी कि साधारण जनता न तो राजनीति में रुचि रखती है और न ही सामान्य व्यक्तियों में, जिनका समाज में भारी बहुमत होता है, स्वशासन की कोई क्षमता होती है। व्यक्ति अच्छी जीविका प्राप्त करने में ही अपनी पूर्ण संतुष्टि समझता है। यह तभी सम्भव होता है यदि जनता को ऐसा योग्य नेता मिल जाय जो राष्ट्र की आरम्भ और व्यक्ति की भावना को अच्छी तरह समझ सके। ऐसे नेतृत्व द्वारा ही जनता की इच्छा व्यक्त होती है। यह जनता की सामूहिक इच्छा का मूलरूप होता है। इन धारणाओं को मानकर तथा इटली की तत्कालीन स्थिति का पूर्ण अध्ययन कर मुगोलिनी ने इटली की जनता के समक्ष स्वयं को एक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। सफल यही स्थिति हिटलर की थी। इन्होंने अपने नेतृत्व की इतना व्यापक एवं सबल बनाया कि ये तानाशाह बन बैठे।

²⁸ Laski, H J, Reflections on the Revolution of Our Time, p 86

²⁹ फासीवादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 663.

फ़ामीवादी नेतृत्व की मूलनः निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

- (i) फ़ामीवादी नेतृत्व अधिनायकवादी होता है ।
- (ii) फ़ामीवादी नेता दल एवं सरकार दोनों का हा प्रभुत्व होता है ।
- (iii) यह नेतृत्व व्यक्ति-भुक्ति (Hero Worship) को प्रोत्साहित करता है, आदि ।

फ़ामीवाद तथा राष्ट्रीय समाजवाद पर आधुनिक इटली तथा जर्मनी की शासन व्यवस्थाएँ संरचनाधारी अधिनायकवादी थीं । सर्वोच्चकारवादी शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करने हेतु व्यक्ति और उनके समूह ने प्रत्येक कार्य एवं कृत को नियन्त्रित किया जाना है । प्रत्येक आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक पक्ष को राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत माना जाता है, जिसका उपयोग शासन द्वारा होना चाहिये । बिना आत्रा के राजनीतिक दल, धर्म संगठन तथा व्यावसायिक संगठनों का निर्माण नहीं हो सकता था । वस्तुओं का निर्माण, व्यापार तथा सम्पत्ति का कार्य नियन्त्रणहीन नहीं छोड़े जा सकते । प्रकाशन तथा समाज शासन के मार्गदर्शन के बिना आयोजित नहीं की जा सकती थी । शिक्षा, धर्म आदि राज्य के कृत में वृद्धि के साधन समझे जाते थे । विधायक एवं मनोरजन के दलों का प्रयोग प्रचार या प्रोपेण्डा के लिए किया जाता था । व्यक्ति के गोपनीय पारिवारिक जीवन के लिए समुचित वातावरण का पूर्ण अभाव था । सब पर शासन की दृष्टि रहनी थी ।³⁰

सर्वोच्चकारवादी शासन सैद्धान्तिक रूप में अधिनायकवादी या तानाशाही व्यवस्था होती है । इटली तथा जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाहों का शासन था । इन अधिनायकों ने शासन का केन्द्रीकरण कर संघीय एवं स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को समाप्त कर दी । उदार राजनीतिक संस्थाओं तथा न्यायपालिका को स्वतन्त्रता जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी । इटली में अधिनायकत्व की स्थापना बड़ी ही शीघ्रतापूर्वक की गई । 1923 से 1928 तक वातुनी एवं आदेशों द्वारा पूर्ण केन्द्रीकरण और निरंकुशता की स्थापना हो गई । जनवरी 1925 में मुसोलिनी ने खुले रूप में वैधानिक प्रणाली का अन्त कर दिया और अगले कुछ ही वर्षों में उसने स्वयं कानून का निर्देशन करके, फ़ासिस्ट नीतियों को कानूनी रूप दिया । 1926 में मन्त्रिमण्डल का सदन के प्रति उत्तरदायित्व भी समाप्त कर दिया । इसी वर्ष नवम्बर में समस्त विरोधी दलों को भंग कर दिया गया । वैधानिक लोकतन्त्र को संस्थाओं पर अन्तिम प्रहार 1928 में कानूनों द्वारा किया गया । इन कानूनों के अनुसार प्रतिनिधि सभा का अन्त कर, उसके स्थान पर एक 'कॉरपोरेटिव संसद' (Corporative Parliament) की स्थापना की गई ।³¹ जर्मनी में भी हिटलर ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया ।

³⁰ Sabine, G H, A History of Political Theory, pp. 745-46.

³¹ कोकर., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 495-97.

कॉरपोरेट अथवा निगमित राज्य The Corporate State

फासीवादी अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में मध्य-मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे न तो व्यक्तिवादी नियन्त्रणहीन अर्थ-व्यवस्था का और न समाजवादियों की भांति राष्ट्रीयकरण नीति का समर्थन करते हैं। उनको अर्थ-व्यवस्था राष्ट्रीय हित में पूँजीवाद और समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण थी। इसका तात्पर्य था कि राष्ट्रीय महत्व के उद्योग सरकार द्वारा संचालित हो तथा श्रेय उद्योगों को व्यक्तिगत क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए। लेकिन निजी क्षेत्र में भी उद्योगों के ऊपर राज्य का नियंत्रण आवश्यक था। इन प्रकार फासीवाद अर्थ व्यवस्था के नियन्त्रण और नियमन के पक्ष में थे।

कारपोरेट प्रणाली आर्थिक क्षेत्र में फासिस्ट सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप था। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यापार को राज्य द्वारा नियन्त्रित एकाधिकार सगठनों में विभाजित किया जाता था, जिन्हें कोरपोरेशन (निगम) कहते थे। राज्य में इस प्रकार के कई कोरपोरेशन थे, इसलिए फासिस्ट राज्य को कोरपोरेट राज्य भी कहते थे। फासीवादी राज्य को निगमित राज्य (Corporate State) इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि फासीवाद लोग राज्य को व्यक्तियों का समुदाय नहीं मानते। राज्य की इकाई व्यक्ति नहीं है, राज्य व्यावसायिक सघों का समूह होता है। फासिस्ट इटली में इस प्रकार के कई व्यावसायिक सगठन थे जो राज्य की प्रत्येक गतिविधियों की प्रमुख इकाई थे।

फासीवादियों का उद्देश्य राज्य को सबल बनाना तथा एकता स्थापित करना था। इसके लिए राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि तथा सार्वजनिक कल्याण की सिद्धि आवश्यक थे। यह सभी सम्भव था जब मालिक, श्रमिक और उपभोक्ताओं के हितों का समन्वय हो क्योंकि इन तीनों के हित एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इनके सहयोग में राष्ट्र की शक्ति एवं समृद्धि निहित थी। राज्य के अधीन निगम ऐसे स्रोत थे जिनसे माध्यम से राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति तथा विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

इन हितों का समन्वय पूँजीवादी व्यवस्था से सम्भव नहीं था क्योंकि इसके अन्तर्गत श्रमिक और मालिक दो विरोधी दलों में संगठित रहते हैं। दूसरी ओर समाजवादी व्यवस्था वर्ग-सघर्ष को प्रोत्साहित करती है। फासीवादियों के अनुसार समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं हैं, कई वर्ग होते हैं और जहाँ तक राष्ट्र हित में सम्भव हो सके इन सब हितों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुनरो (W B Muoro) ने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि कारपोरेट प्रणाली पूँजीवादी व्यवस्था और व्यक्तिगत सम्पत्ति संस्था को बनाये रखने हुए निगमों की स्थापना करने का कार्यक्रम था, जो मालिक और श्रमिक को निरन्तर राष्ट्रीय

महत्ता और उत्पादन में वृद्धि करे।³² निगम व्यवस्था के अन्तर्गत, जैसा कि मुसोलिनी ने कहा, राज्य की एकता को ध्यान में रखते हुए अर्थ-हितो का समन्वय किया गया। यह पूंजीवाद समाजवाद के कुछ तत्त्वों तथा श्रमिक, मालिक और उपभोक्ताओं के स्वार्थों को सामंजस्य करने का प्रयत्न था। फासिस्ट दल व्यवस्था को पूंजीवादी-उदारवाद तथा समाजवाद दोनों से ही अलग मानते थे।³³

कारपोरेशन व्यवस्था

दल व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसाय एवं उद्योग में फर्क मान में लेकर निर्मित करने का सारा काम एक निगम के अन्तर्गत होता है। फासिस्ट इटली में प्रदेश-जिले में स्थानीय श्रमिकों और मालिकों ने प्रधान-प्रथक संधि हुआ करते थे। स्थानीय संधियों को मिलाकर प्रांतीय संधियों का निर्माण होता था। प्रांतीय संधियों के ऊपर राष्ट्रीय निगम होते थे। राष्ट्रीय निगमों की संख्या 1925 में सम्भवतः 22 थी। प्रत्येक निगम की एक परिषद् हुआ करती थी जिसमें श्रमिक और मालिकों के प्रतिनिधि बैठते थे। ये प्रतिनिधि सामान्यतः फासिस्ट दल के सदस्य या समर्थक ही होते थे। इन 22 निगम परिषदों के ऊपर एक राष्ट्रीय निगम-परिषद् थी। राष्ट्रीय निगम परिषद् की केन्द्रीय समिति में विभिन्न निगमों के प्रतिनिधि, फासिस्ट दल का मन्त्री तथा राज्य के सभी मंत्री सम्मिलित हुआ करते थे। सरकार के निगम-मंत्रालय (Ministry of Corporations) का अध्यक्ष स्वयं मुसोलिनी था। इस प्रकार इटली की आर्थिक व्यवस्था इन निगमों के अन्तर्गत थी जिसमें फासिस्ट दल का सर्वत्र प्रभाव था।

निगमों की शक्तियाँ व्यापक थीं। ये श्रमिक विवादों का निबटारा, सामूहिक श्रमिक अनुबंध, उत्पादन में वृद्धि, वेतन, कार्य के घण्टे, वस्तुओं के मूल्य, आयात-निर्यात आदि प्रश्नों का निर्णय करते थे। लेकिन ये कार्य परामर्श देने तक ही सीमित थे। वास्तविक कार्य सरकार के ही नियन्त्रण में होता था। राज्य तथा फासिस्ट दल इन विवादों में निर्णायक वा कार्य करता था। इसके साथ-साथ इटली की प्रतिनिधि प्रणाली पर भी इनका प्रभाव था। फासिस्ट बाल में इटली की प्रतिनिधि सभा (Chamber of Deputies) का प्रतिनिधित्व इन्हीं निगमों द्वारा किया जाता था। समीक्षा

कारपोरेट प्रणाली मुसोलिनी के वर्णसंकर्य विचारों का प्रतिकर थी। यह धारणा मध्यकालीन गिल्ड व्यवस्था तथा आधुनिक सिन्डीकेलिवाद का मिश्रण थी। सिन्डीकेलिवाद पहले से ही इटली में प्रभावशाली था तथा इसके प्रमुख समर्थक जॉर्ज सोरेल (George Sorel) का मुसोलिनी पर विशेष प्रभाव था। गिल्ड समाजवादी राज्य को समुदाय वा समुदाय मानते हैं। ये सभी विचारधारामें बहुलवादी (Pluralist) है जो सामाजिक संगठन में समुदायों की महत्ता पर जोर देती

32. Munro, W. B., The Government of Europe; p. 685.

33. Munro, Ion S., Through Fascism to World Power, pp. 306-07.

हैं। लेकिन कारपोरेट प्रणाली, मिन्डीकलवाद तथा गिल्ड व्यवस्था को एक समझना भ्रम होगा। इनमें मूलभूत भिन्नता थी। मिन्डीकलवादी एक गिल्ड समाजवादी व्यावसायिक समुदायों की स्वायत्तता के प्रबल समर्थक हैं और इस आधार पर राज्य के संवर्गतिशाली और सर्वव्यापकता का स्वीकार नहीं करते। फासीवादी निगम प्रणाली के अन्तर्गत केवल सिद्धान्तिक स्वायत्तता ही थी। इस पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण था। य राज्य की सर्वोच्चता के अन्तर्गत ही कार्य कर सकत थे। इसका संगठन राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया था। इस प्रकार कारपोरेट व्यवस्था एक साधन मात्र ही थी।

कारपोरेट प्रणाली स्वामत्तता सिद्धान्त पर आधारित रहनी है। निगमों की स्थापना राष्ट्रीय हित में राज्य के द्वारा की जानी है, कानून के अन्तर्गत उन्हें अधिकार दिये जाते हैं। निगमों की स्थापना के बाद इन्हें अधिकारों की सीमा के अन्तर्गत पूर्ण स्वयत्तता प्राप्त होनी है। इन्हें अपने कार्यों और समस्याओं के प्रति मजबूत प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। अन्य प्रायों में, राज्य के अन्तर्गत मावर्जनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन्हें स्वशासन का अधिकार प्राप्त होना है। किन्तु फासीवादी निगम व्यवस्था इसमें भिन्न थी। य निगम पूरी तरह राज्य पर आधित थे। इनका सारा संगठन फासिस्ट दल पर निर्भर करता था। इससे इनकी स्वायत्तता का प्रश्न नहीं उठता था। य सरकारी विभाग की ही तरह कार्य करते थे। इन्हें किसी भी प्रकार की पहल तथा जोखिम उठाने का अधिकार नहीं था।

सिद्धान्तिक रूप में कारपोरेट प्रणाली उचित प्रतीत होनी है। इसमें पूंजीवादी, समाजवादी तर्कों का सम्मिश्रण कर श्रमिक, मानिक और उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया गया। लेकिन व्यवहार में यह बात भ्रमवद् नहीं हो सकी। फासीवादी अधिनियमवत्त्व जिसकी स्वयं की कुछ मूल मान्यताएँ थीं, के अन्तर्गत कारपोरेट व्यवस्था सफल नहीं हो सकती थी।

कारपोरेट प्रणाली में यह दावा किया गया कि यह श्रमिक वर्ग के हितों का समुचित एवं समान ध्यान रहेगा। इसलिये निगमों में श्रमिकों और मालिकों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन यह मानना भ्रम होगा कि समान प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अधिकार या सरकार तक समान पहुँच थी। यहाँ पर मालिकों की तुलना में श्रमिकों को छोड़ दे जाते थे और उनके हितों का संरक्षण पूरी तरह नहीं हो सकता था। अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये समस्त श्रमिक-माधन जैसे इटली, सोवियत संघ पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था तथा इसका उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड व्यवस्था थी। श्रमिक न्यायालय श्रमिकों के मागों में हस्तक्षेप कर सकत थे। श्रम-मालिक विवादों में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, इन न्यायालयों के निर्णय श्रमिकों के विरुद्ध ही जाते थे।³⁴

³⁴ मायोर्वाइन्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 667-68.

कॉरपोरेट राज्य की एक दृष्टि यह थी कि इसका संगठन युद्ध की तैयारी के लिये किया गया था। इनका निर्माण शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था के लिये नहीं था। सम्पूर्ण योजना का उद्देश्य साम्राज्यवादी विस्तार और युद्ध था। निगमों का सम्पूर्ण संगठन सैनिक मिद्धान्त और अनुशासन पर आधारित था। इसलिये इनका जो समुच्चिन एवं शक्ति: शक्ति विकास श्रेणी चाहिये था वह नहीं हो पाया। इनका नव होने हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली की कॉरपोरेशन प्रणाली युद्ध की चुनौती का सामना नहीं कर सकी। इटली उतना सैनिक मोर्चे पर असफल नहीं हुआ, जितना कि अर्थिक मोर्चे पर। निरक्षर व्यवस्था की निर्दलता इसमें और स्पष्ट होती है कि मुसोलिनी के पतन के उपरान्त यह प्रणाली इटली से नमात हो गई। इस प्रणाली में म्याथित्व के तत्व नहीं थे।

इटली में कॉरपोरेट राज्य की उपलब्धियाँ

आर्थिक प्रगति—यद्यपि कॉरपोरेट राज्य का समर्थन नहीं किया जा सकता, इटली में कॉरपोरेट प्रणाली की कुछ ऐसी उपलब्धियाँ थी जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसके अन्तर्गत सुनिर्धारित अर्थ-व्यवस्था पर बल दिया गया। निगमों की स्थापना के कारण उत्पादन में अवश्य ही वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप इटली एक शक्तिशाली राज्य के रूप में माना जाने लगा।

निगम व्यवस्था के अन्तर्गत बहूत्र सी आर्थिक बुरादियों का उन्मूलन कर दिया गया। सट्टेबाजी और अधिक लाभ पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सरकारी आदेशों द्वारा (1930 तथा 1933 में) वस्तुओं के मूल्यों को कम कर दिया गया जिससे उपभोक्ता वर्ग को बहुत राहत मिली। अनिर्णीत रक्षा में सुधार

श्रमिक भेम्ना कार्टा—निगम प्रणाली द्वारा मालिकों को अधिक सुरक्षण प्राप्त था, लेकिन हम व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों की दशा में भी सुधार हुआ। श्रमिकों के लिए अधिकार-पर की घोषणा कर उन्हें कुछ अधिकार दिये गये। इन अधिकारों में सबसेतन अवकाश, चिकित्सा सहायता, बुढ़ापे और मृत्यु सम्बन्धी बीमा अधिकार तथा अन्य सहायताएँ प्रमुख थी। जोड़ में इन अधिकारों को 'श्रमिकों का अधिकार पत्र' (Magna Carta of Labour) कहा है।³⁵

औद्योगिक शांति—इटली के कॉरपोरेट राज्य में उन सभी तत्त्वों का उन्मूलन करने का प्रयत्न किया गया जो मालिक और श्रमिकों के बीच तनाव उत्पन्न करते तथा औद्योगिक प्रगति में बाधक थे। विभिन्न निगमों में मालिक और श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व, उनके विवादों को सुलझाने के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था तथा इन सभी पर राज्य का प्रतिबन्ध ऐसा था कि इटली में न तो अधिक मुनाफा के लिए गुंजादश थी और न हड़तालें आदि की प्रोत्साहन। फासिस्ट

35. उद्धृत, आशीर्वादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ. 668.

इटली में सबके औद्योगिक शक्ति थी जिससे एतना तथा आर्थिक प्रगति में अत्यधिक महत्ता मिली।

रेवरेण्ड पी कार्टी तथा डा आर्शावाइज्म का मत है कि यद्यपि निगमित राज्य की धारणा द्वारा नहीं, पर निगमित समाज की धारणा में अत्यन्त ही आधुनिक राज्य के पुनर्गठन का आधार मिल सकता है। इस समय ऐसे निगमित समाज की आवश्यकता है जिसका संगठन शान्ति के लिये हो, जिसका निर्माण राज्या द्वारा न होकर व्यक्तिगत द्वारा हो तथा जहाँ समाज का सार्वजनिक कल्याण, राज्य और व्यक्तिगतों के अधिकार आदि का समुचित सम्मान और विकास हो।³⁶

फासिस्टवादियों का दावा था कि कोरपोरेशन व्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में उनका सबसे अधिक मौलिक योगदान था। मुसोलिनी का कहना था कि निगमवाद (Corporatism) अथवा कॉरपोरेट राज्य का निर्माण सबसे अधिक साहसपूर्ण मौलिक और शान्तिकारी कार्य था। इटली की कॉरपोरेट राज्य व्यवस्था ने बहुत से तत्कालीन राज्यों की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित किया। 1933 में पुर्तगाली संविधान के अन्तर्गत पुर्तगाल को कॉरपोरेट राज्य स्वीकार किया गया। पुर्तगाल के तानाशाह सालाजार ने मुसोलिनी के ही पदचिह्नों पर चलकर पूंजी और श्रम के मेल का प्रयत्न किया। 1938 में आस्ट्रिया में भी निगम व्यवस्था लागू की गई और श्रमिक सभों को तोड़ दिया गया। स्पेन में गृह-युद्ध (1936) के उपरान्त जनरल फ्रान्को ने कई निगमों की स्थापना की। 1937 का आज़ीन का संविधान तथा 1943 के बाद पीह तथा अज़ेन्टाइना की व्यवस्था भी इन कॉरपोरेट प्रणाली पर आधारित थी। इटली की व्यवस्था उनके प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य ने फासिस्ट कॉरपोरेट प्रणाली को नहीं अपनाया। यह सिर्फ अधिनायकों और तानाशाहों को ही आवृणित कर सकी।

फासीवाद और अन्तर्राष्ट्रीयवाद

फासीवादी विचारधारा में अन्तर्राष्ट्रीयता को कोई स्थान नहीं था। फासीवादी उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे, जिसके अनुसार वे अपने हितों को ही सर्वोपरि मानते थे। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों को हड़बने एवं बलिदान करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उनका राष्ट्र उद्यान दूसरे राष्ट्रों के लोप से ही सम्भव हो सकता था।

फासीवाद शान्ति विरोधी तथा युद्ध समर्थक था। उग्र राष्ट्रवाद में शान्ति का बैसे ही कोई महत्त्व नहीं होता। सैद्धान्तिक रूप से व अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को कायरता का प्रमाण मानते थे। फासीवाद अनुध, जाति, राष्ट्र, राज्य की उन्नति के लिये युद्ध को आवश्यक एवं स्वाभाविक मानते थे। मुसोलिनी के शब्दों में

³⁶ उपसुंक्त, पृ 666, 668-69.

'पुरुष जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो नारी के जीवन में मातृत्व का है।' हिटलर भी युद्ध को पुरुष शौर्यान्वित करता था। हिटलर के अनुसार अविगम युद्धों में ही मानव जाति की उन्नति हुई है, शान्ति की स्थापना में मानव जाति विनाश के गर्त में चली जायगी।

फ़ासिस्ट केवल अपने राष्ट्र तक ही सीमित एक उत्तरदायी है। वह दूसरे व्यक्ति की अन्तरात्मा, कोर्ट आदिक वर्ग, किसी अन्तर्राष्ट्रीय मन्था या समझ, अथवा किसी विश्व-मंत्रालय वर्ग के प्रति भक्ति को स्वीकार नहीं करता। फ़ासीवादी विश्व-सहयोग के विरुद्ध है। उसका विश्वास था कि भावी युद्ध अनिवार्य है। अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों के परामर्शों द्वारा ज्ञानि सम्भव नहीं। टटनी को दूसरे महान राष्ट्रों के समान मानना ही होगा। वह अपमान महन नहीं करेगा। वह शान्ति को उसी समय स्वीकार करेगा जबकि वह रोमन शान्ति होगी।³⁷

फ़ासीवादी राज्य शक्ति और विस्तार पर आधारित था। तदनुसार राज्य को निरन्तर अपनी शक्ति और विस्तार में अभिवृद्धि करने रहना चाहिए। यदि राज्य का प्रसार रुक जाता है तो उसका नाश हो जाता है। इसलिए, जैसा कि गेटिल ने व्यक्त किया है, राज्य केवल बढ़ सता ही नहीं है जो व्यक्तियों की इच्छाओं को कानूनों का रूप और आध्यात्मिक जीवन का मूल्य प्रदान करता है, किन्तु ऐसी शक्ति भी है जो अपनी इच्छा को दूसरे देशों पर स्थापित करती और अपना सम्मान बढ़ाती है। अन्य शस्त्रों में वह अपने विनाश की सभी आवश्यक दिशाओं में अपनी इच्छा की मार्गभूमिका के तथ्य का प्रदर्शन करती है। इन प्रकार इसकी तुलना मनुष्य की इच्छा से की जा सकती है जिसके विनाश की सीमाएँ नहीं होंगी, जो अपनी अमीमता की परीक्षा करके ही अपने को परिपूर्ण बनाती है।³⁸

फ़ासीवादी नस्ल को श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं। किन्तु उन सम्बन्ध में मुसोलिनी की अनेका नात्सीवाद में नस्ल की श्रेष्ठता सिद्धान्त का विशेष एवं विस्तार-पूर्वक प्रतिपादन किया गया है। हिटलर नस्ल के सिद्धान्तों को लेकर चला और उसकी गहायता से उसने राजनीति दर्शन को एक नया आधार देने का प्रयत्न किया। मेन कम्फ (Mein Kampf) में नस्ल-श्रेष्ठता का सिद्धान्त सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें हिटलर ने बतलाया है कि इतिहास न तो व्यक्ति की मुक्ति का संघर्ष है, और न वन-संघर्ष की कहानी। वह तो प्रकृत नस्ल-आयं नस्ल-की प्रतिभा के प्रस्फुटन का सिद्धान्त है। विषय में विभिन्न नस्लें जीवित रहने और अपने प्राण को शक्तिशाली बनाने के लिये संघर्ष करती हैं। उनमें जो नस्ल सर्वाधिक शुद्ध होती है वही राज्य शक्तिशाली होती है। हिटलर प्रायं नस्ल को सर्वश्रेष्ठ मानता था जिसकी

37. कोकर., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ. 519-11.

38. गेटिल., राजनीति चिन्तन का इतिहास, पृ. 444-45.

सुरक्षा राज्य का परम वर्तव्य था। वह ऐसे राज्य को लोक राज्य (Folkish State) कहता था।³⁹ हिटलर का श्रेष्ठ एव पवित्र नस्ल का सिद्धान्त विस्तारवादी है। उनमें लिखा है कि आर्य नस्लें अन्य-नस्लक होने हुए भी विदेशी जातियों को अपने अधीन कर लेती हैं। नस्ल के इस शक्ति विस्तार में राज्य को सहायक होना चाहिए। जैसे-जैसे नस्ल की संख्या में वृद्धि होती है वैसे-वैसे ही उसकी आर्थिक आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं तथा अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता अनुभव होती है। इसी अनुपात में श्रेष्ठ नस्ल को अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने तथा उसकी आर्थिक समृद्धि के लिये सीमा विस्तार करने का अधिकार है।⁴⁰

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हिटलर और मुसोलिनी दोनों ने ही अपनी विस्तारवादिता का परिचय दिया। इटली की अतिरिक्त जनसंख्या को अन्यत्र बसाने, या आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति के लिए मुसोलिनी ने ईथोपिया को हड़पने की योजना बनाई। ईथोपिया के साथ सीमा विवाद उत्पन्न कर 1936 में उस पर इटली का आधिपत्य हा गया। इसके अलावा मुसोलिनी भूमध्यसागरीय क्षेत्र को इटली के प्रभाव-क्षेत्र में लाना चाहता था। मुसोलिनी का उद्देश्य इटली को एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना था। विस्तारवाद के क्षेत्र में हिटलर मुसोलिनी से और भी आगे बढ़ गया था। प्रथम, हिटलर वर्साय की सन्धि (Treaty of Versailles, 1919) के अन्तर्गत जर्मनी की सीमा निर्धारण का मान्यता नहीं देता था। वर्साय की संधि के द्वारा वे क्षेत्र जो जर्मनी से छीन लिए गये थे हिटलर उन्हें वापस लेना चाहता था। द्वितीय, हिटलर अन्तिम बार जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहता था। इसलिए यूरोप में वे क्षेत्र जिनमें जर्मन जनसंख्या रहती थी, हिटलर उनका जर्मनी में विलयीकरण चाहता था। आस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में मिला कर एक सीमा तक इस उद्देश्य की पूर्ति की गई। तृतीय, हिटलर यही तंत्र सन्तुष्ट नहीं था, अन्तिम उद्देश्य सम्पूर्ण यूरोप को अपने आधिपत्य में करना था। जब हिटलर ने यूरोप के अन्य छोटे-छोटे राज्यों पर अधिकार करने की चेष्टा की, परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया।

उपरोक्त वध्य फासीवाद तथा नास्तीवाद की विस्तारवादी नीति का स्पष्ट प्रमाण है। यह विस्तारवाद कोई आकस्मिक नहीं था किन्तु फासीवाद के विस्तारवादी सिद्धान्तों पर आधारित योजनाबद्ध था। आन्तरिक असंतोष को ध्यान में रखते हुए तथा व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं को उक्तान के लिये इस प्रकार की विदेश नीति स्वाभाविक ही थी।⁴¹ इंग्लैंड और फ्रान्स की सन्तुष्टिकरण की नीति फासीवादी विस्तार में और भी सहायक सिद्ध हुई।

39 Sabine, G. H., A History of Political Theory, p. 731

40 Mein Kampf, p. 523

41 Laski, H. J., Reflections on the Revolution of Our Time, p. 57.

फासीवादी साधन

शक्ति-राजनीति (Power-Politics) फासीवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उन्होंने शक्ति का साधन के रूप में प्रयोग किया। फासीवादियों ने शक्ति द्वारा सत्ता प्राप्त की तथा सत्ता में बने रहने के लिये शक्ति का निरन्तर प्रयोग करते रहे। शक्ति उनका धर्म बन गया। विरोधियों का हिंसात्मक साधनों द्वारा उन्मूलन किया गया। बन्दीगृह फासीवादी विरोधियों से भरे पड़े थे। फासीवादी शासन के अन्तर्गत इटली और जर्मनी में शक्ति एवं हिंसा का जैसा नमन प्रदर्शन हुआ, सम्भवत ही रूसी गण्य ममाज में हुआ हो।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फासीवादी शान्तिपूर्ण साधन या बार्ना द्वारा समझौते का समाधान करने में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार शान्ति कायरो का स्वप्न है। अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये वे युद्ध को राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख अंग मानते थे। यह दृष्टिकोण ईथोपियाई संकट से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। ईथोपिया की समस्या का समाधान करने के लिये जब इंग्लैंड ने ईथोपिया का कुछ क्षेत्र इटली को देने का प्रस्ताव किया तो मुसोलिनी ने बड़े ही अपमानजनक शब्दों में कहा—“यदि मुझे ईथोपिया को चादी की प्लेट पर भी रख कर प्रस्तुत किया जाये तो मैं सधन्यवाद मना कर दूँगा, क्योंकि ईथोपिया को देने शक्ति से लगे का निश्चय कर लिया है।” इन साधनों के विषय में लास्की (H. J. Laski) ने लिखा है कि—

फासिस्ट प्रणाली शक्ति को छोड़ सभी मूल्यों का हनन करती है, यह युद्ध को राष्ट्रीय नीति के स्वाभाविक साधन के रूप में प्रयोग करने के लिये तैयार है, इसके द्वारा या तो मानव जाति को दास बनाना चाहिये या स्वयं नष्ट हो जाना चाहिये। इसमें इन विकल्पों के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग नहीं।⁴²

propaganda -

प्रसार (Propaganda)

फासीवादी विचारधारा में प्रचार का विशेष महत्व रहा है। फासीवादी धुबुद्धवादी तो थे ही। अपने प्रत्येक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों की भावनाओं को उभारना तथा भड़काना आवश्यक समझा जाता था। यह कार्य केवल प्रभावशाली प्रसार द्वारा ही सम्भव था।

प्रसार नास्तीवाद का मूल स्तम्भ था। हिटलर ने अपनी आत्मकथा—Mein Kampf—में प्रचार और संगठन के विषय में एक अलग ही अध्याय लिखा है। इस अध्याय में वह दल, संगठन आदि से भी प्रसार को अधिक महत्व एवं प्राथमिकता

42. Laski, H. J., Reflections of the Revolution of Our Time, p. 97.

देना है। प्रारम्भ में जब हिन्दु न नमन लखर पार्टी की सम्पत्ता ग्रहण की तो सब प्रथम उसन प्रसार शाखा का अर्पण अधान किया। बट्ट प्रसार के गृहत्व को समझता था। हिन्दु की प्रसार प्रणाली एक बहावन बन गई थी। जो काय मुद्र से सम्भव नहीं था हिन्दु उम प्रसार क द्वारा ही प्राप्त कर सकता था। गिना मुद्र के ही प्रसार द्वारा हिन्दु न आम्टिया और बन्धनाकारिया को अर्पण अधिकार म कर लिया था। एम प्रकार फासाबादी शासन व्यवस्था म प्रसार का एक साधन के रूप म विशेष स्थान था।

फासाबाद और साम्यवाद

फासाबाद और साम्यवाद म कई समान तत्व दृष्टिगोचर होन हैं। बाबर न लिखा है—

पमिज्म तथा कसी साम्यवाद म कुछ आवश्यक पक्षो म परस्पर विरोध होन हुए भी घटित आध्यात्मिक सम्बन्ध ह और कई धाना म उनके शासन की रीतिया समान हैं।⁴³

बाबर न साम्यवाद और फासाबाद म निम्नलिखित समानताया का उल्लेख किया है⁴⁴—

- (i) पमिटा और बाशविका दाना ने शासन-मत्ता अर्थात् अथवा हिमा का धर्मकी स प्रस्त की और दाना ही बन्ध प्रयोग का राजनीतिक काय का सर्वोच्च साधन मानत है।
- (ii) दाना ही विचारधाराएँ राजन न तथा न्दारवात् ही होंगे -दान हैं तथा उह अज्ञानिया के अविश्वास या क पना प्रिय रोगा क अव्यावहारिक अदश मानत है।
- (iii) दोना प्रणालियाँ स्वतन्त्रता विरोधी हैं। ये केसी कोन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं मानत विमता राज सत्ता विनाश नहीं कर सकती। य समाचार-पत्रा तथा स्कूला को अर्पण प्रचार का साधन माननर उन पर अर्पण अधिकार मानत है। य स्वतन्त्र विचार-प्रकाशन स डरत है और वही निदयता क साथ सका दमन करत ह।
- (iv) दोना व्यवस्था म शासन तथा राजनीतिक दन म अस्थिरता है। य एकदनाय शासन व्यवस्था म आस्था रखत हैं।

इन अन्तर्गत संबंधित⁴⁵ न राष्ट्रीय समाजवाद (नास्तोवाद) क मद्देन फासाबाद और साम्यवाद म कुछ अन्य समानताया का निम्नलिखित विवरण दिया है—

⁴³ बाबर, आधुनिक राजनीतिक चिंतन पृ 513

⁴⁴ उपपुक्त पृ 513

⁴⁵ Sabine G H A History of Political Theory p 751

- (i) इन विचारधाराओं का अग्रमुदय प्रथम विश्वयुद्ध के बाद उस समय दमनीय आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ।
- (ii) ये अधिनायकवादी शासन का समर्थन करती हैं।
- (iii) इनमें सत्ता कुछ मुठ्ठी भर व्यक्तियों के हाथों में रहती है।
- (iv) ये विचारधाराएँ मूलतः अन्ध मिथ्यान्तवादी हैं। एक नस्ल की श्रेष्ठता तथा दूसरा सर्वहारा वर्ग की महत्ता में विश्वास रखते हैं।
- (v) ये राजनीति को शक्ति ग्रहण करने का माधन मानते हैं। इस प्रकार दोनों शक्ति-राजनीति में विश्वास करते हैं।

फासीवाद और साम्यवाद उद्भव, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तथा व्यवहार में नहीं समान तथा कहीं अत्यधिक निकट है। फिर भी आलोचक इनमें साम्यवाद की श्रेष्ठता को स्वीकार कर विभिन्नताओं का उल्लेख करते हैं। साम्यवाद तत्परतः मानवतावादी है। उसकी निर्धन वर्ग की सेवा की नीयत को चुनौती नहीं दी जा सकती। साम्यवादी विचारधारा लगभग दो पीढ़ियों के मानसवादी अन्वेषण का परिणाम है। यह मानसवादी वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध दर्शन पर आधारित है। इसके विपरीत फासीवाद अन्तारवादी विचारों का बन्धन था जिन्हें आवश्यकतानुसार सशुद्धित कर लिया गया। यह बौद्धिक झूठ एवं प्रोपेगेंडा था। साम्यवाद पूँजीवाद का शत्रु है। यह पूँजीवाद को एक घोषण व्यवस्था मानता है। फासीवादी मूलतः उच्च वर्ग और पूँजीवर्ग के समर्थक थे।

वर्ग व्यवस्था के विषय में इन दोनों में मूल अन्तर है। साम्यवाद वर्ग-संघर्ष पर आधारित है। इसमें वर्ग-संघर्ष स्वाभाविक है। अन्तिम रूप में पूँजीवर्ग की समाप्ति और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना में साम्यवादी विश्वास करते हैं। किन्तु फासीवादी वर्ग-संघर्ष का उन्मूलन तथा सहयोग के आधार पर शासन रचना का समर्थन करते हैं। फासीवाद विभिन्न वर्गों की उग्रता को कुंठित कर उनका एक प्रणाली के अन्तर्गत समन्वयपरक है।

राज्य के प्रति इनके दृष्टिकोण में मूलभूत भेद है। फासीवादी सर्वसत्ताधारी राज्य में विश्वास करते हैं। वे राज्य को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। किन्तु साम्यवाद में केवल संक्रमण काल में ही राज्य के महत्त्व को स्वीकार किया जाता है। एक अन्तिम उद्देश्य के रूप में साम्यवादी राज्य-रहित समाज की स्थापना चाहते हैं।

फासीवाद और साम्यवाद में एक मूल अन्तर और है। फासीवादी उग्र राष्ट्रवाद में शास्त्रा रहते हैं। किन्तु साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं। इसका यही तात्पर्य है कि साम्यवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है। यह समस्त विश्व को साम्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत लाना चाहता है।

वैसे राजनयन फासीवाद और साम्यवाद की तुलना का केवल बौद्धिक सन्दर्भ ही रह गया है। फासीवादी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है जबकि साम्यवाद ने अपने

प्रसार में बहुत प्रगति की है। आलोचकों ने जब फासीवाद तथा साम्यवाद को एक ही स्तर पर रखने का प्रयत्न किया, सम्भवतः उनका उद्देश्य साम्यवाद को अपमानित करना है। साम्यवाद में बहुत खूटियाँ हैं फिर भी इसे फासीवाद के साथ एक ही कोष्ठक में नहीं रखा जा सकता।

सैद्धान्तिक तथा ध्यावहारिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में फासीवाद और साम्यवाद एक दूसरे के विरोधी थे। फासीवाद के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में माक्सवादी व्याख्या का इस अध्याय के प्रारम्भ में उल्लेख किया जा चुका है।⁴⁶ साम्यवादियों ने फासीवाद को पूँजीपतियों का पड़दन्त्र तथा पूँजीवाद के पतन की चरम सीमा बनलाया था। साम्यवादियों का लगभग यही दृष्टिकोण नात्सीवाद एवं हिटलर के प्रति था। साम्यवाद के प्रति फासीवाद का भी बड़ा आक्रामक दृष्टिकोण रहा है। मुसोलिनी ने इटली में अन्दर साम्यवादियों, समाजवादियों आदि का पूर्ण सफाया कर दिया था। हिटलर साम्यवाद तथा रूस का बहुत शत्रु था। उसने अपनी आत्मकथा में साम्यवाद के प्रति कई स्थलों पर निन्दनीय शब्दों का प्रयोग किया है। वह साम्यवादियों को खूनी, अपराधी, लुटेरा आदि कहता है। हिटलर का विचार था कि रूस का शीघ्र पतन होगा।⁴⁷ यूरोपीय राजनीति में भी इन राज्यों का कभी भी सहयोग नहीं रहा। यदि कभी सहयोग भी हुआ, जैसे रूस-जर्मनी की अगस्त 1939 में अनाक्रमक सन्धि, वह अक्षरवादीना पर ही आधारित था। इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया। अन्त में यह द्वितीय विश्व युद्ध के सघर्ष में परिवर्तित हो गया।

फासीवाद का मूलमार्क

फासीवाद का अध्ययन करने के पश्चात् इस विचारधारा में दोष ही अधिक दृष्टिगोचर होने हैं। फासीवाद के प्रत्येक सिद्धान्त-सूत्र (यदि फासीवाद को सैद्धान्तिक माना जाय तब) की कई दृष्टिकोणों से आलोचना हुई है। फासीवाद के कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं —

सदिग्ध विचारधारा (1)

सर्वप्रथम फासीवाद को एक विचारधारा के रूप में स्वीकार करना ही सदिग्ध है। इसका न तो कोई पूर्व दर्शन है और न विचार-सूत्रों में समरूपता। यह विचार धारा तदर्थ एक अक्षरवादी विचारों का सग्रह है। इस सम्बन्ध में लास्की ने लिखा है—

“फासीवाद का किसी भी रूप में कोई दर्शन नहीं है। इसके समर्थकों ने इसके जो सिद्धान्त-सूत्र प्रस्तुत किये हैं उनका परीक्षण करने पर प्रोपेगेंडा प्रतीत होने हैं जिनका अपनी सत्ता में वृद्धि करने के अलावा और कोई अर्थ नहीं।”⁴⁸

46. इसका लिए इस अध्याय के प्रारम्भ में माक्सवादी व्याख्या देखिए।

47. Mein Kampf, Chapter XIV, Germany's Policy in Eastern Europe

48. Laski, H. J., Reflections on the Revolution of Our Time, p. 97
Also see, Markl, Peter, Political Continuity and Change, p. 52)

फासीवादियों ने निरन्तर निपेधात्मक एवं विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाया। इनके प्रवक्ताओं और कार्यकर्त्ताओं ने कभी भी न तो रचनात्मक विचार व्यक्त किए और न कार्य ही किए। फासीवाद ने सभी प्रचलित आदर्शों का विरोध किया। व्यक्तिवाद, उदारवाद, मानववाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि विचारधाराओं की समस्त प्राधारभूत मान्यताओं और मूल्यों को उखाड़ फेंका। ध्वसात्मक प्रकृति के कारण फासीवाद में कोई भी ग्रहण करने योग्य आदर्श नहीं मिलता।

वर्णसंकरीय विचारधारा (१)

फासीवाद का अध्ययन करने से कभी-कभी यह भ्रम होता है कि यह विचारधारा कई विचारधाराओं का समन्वय है। सम्भवतः मुसोलिनी तथा अन्य समर्थकों ने इसे सर्व-ग्राह्य बनाने के लिए सभी विचारधाराओं से सिद्धान्त ग्रहण किए। ऐसा ममभना भूल होगी। फासीवाद अवसरवादिता पर आधारित तदर्थ (ad hoc) विचारों का सञ्चलन था। उन्होंने अलग-अलग अवसरों पर अलग प्रकार की बातें एवं विचार बहे। इनमें सभी वर्गों को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न किया गया। वे जिस वर्ग का नगर्यन चाहते थे उसी के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर देते थे। उनके ऐसे विचार चाहे परस्पर-विरोधी भी हो, उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं थी। वास्तव में फासीवाद बहुत कुछ धोखा था। श्रमिकों को अपने पक्ष में करने के लिये मुसोलिनी ने कुछ पूँजीवादी विरोधी नारों का प्रयोग किया। किन्तु साथ ही साथ पूँजीवादियों को यह भी धारवाग्न दे दिया कि इन नारों से उन्हें घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। यही हाल जर्मनों का था। 1930 में एक नात्सी नेता ने एक उद्योगपति को पत्र लिखकर यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि—

“हमारे कथन तथा व्यवहार से आप अपने लिए दुविधा (असमन्वय) में ग डालें। कुछ आकर्षक नारे हैं जैसे ‘पूँजीवाद का नाश हो’, लेकिन ये आवश्यक हैं। हमें अतन्तुष्ट एवं क्रुद्ध समाजवादों श्रमिकों की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कूटनीति को ध्यान में रखते हुए ही हम स्पष्ट कार्य-क्रम प्रस्तुत नहीं करते।”⁴⁹

फासीवादियों ने पूँजीवाद, समाजवाद, हीगलवाद, सिन्डीकलवाद, राष्ट्रवाद, अखिवेरवाद आदि से बहुत से तत्त्व ग्रहण किये, किन्तु इन सबका प्रयोग उन विचारधाराओं के सही अन्वय में नहीं किया। इसलिए फासीवाद इन विचारों का सही समन्वय न होकर वर्णसंकरीय विचारधारा बन गया।

फासीवाद धनिक-वर्ग के पङ्कज के रूप में (३)

इस तर्क में भी सत्यता है कि फासीवाद इटली के पूँजीवर्ग का पङ्कज था। मुसोलिनी और हिटलर दोनों को ही पूँजीवादियों का समर्थक माना जाता है। इनमें

49. Quoted, Sabine, G. H., A History of Political Theory, p. 710.

घोर पूंजीपतियों में बड़ी घनिष्ठता थी। इन लोगों की राशि बड़े-बड़े पूंजीपतियों में मिलनी रहती थी। यही कारण है कि जैसे ही मुसोलिनी को सत्ता मिली उसने अपना समाजवादी कार्यक्रम त्याग दिया। उसने धर्मियों की दृष्टियों का विरोध किया।⁵⁰ शासन में इस व्यवस्था में घनिष्ठ अधिक घनी घोर निर्धन और भी निर्धन होत चले गए। सामान्य जनता की आर्थिक चिन्ताओं से मुक्ति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। उन्हें केवल भावनाओं के भोजन से ही सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न किया गया। सर्वसत्ताधारी राज्य की स्थापना

फासीवादी राज्य सर्वसत्ताधारी होता है। इसके दो प्रमुख पक्ष हैं। प्रथम, राज्य साम्य है और व्यक्ति साधन। द्वितीय, शासन व्यवस्था में आधार शक्ति है। राज्य अथवा राष्ट्र को साध्य तथा व्यक्ति को साधन मानना भूल होगी। ऐसी शासन व्यवस्था में व्यक्तियों की स्थिति शोष के समान हो जाती है। प्रत्येक कार्य राष्ट्र की प्रतिष्ठा एवं शक्ति वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिसमें मानव मूल्य एवं मनुष्यों की गरिमा का कोई भी महत्त्व नहीं होता। यह अत्याचारी शासन का दूसरा नाम है। इसी तरह फासीवादी शक्ति को राज्य का रखाई आधार मानकर चलते हैं। इतिहास में इस प्रकार के अनेकों दृष्टान्त हैं कि शक्ति और हिंसा के आधार पर कार्य भी व्यवस्था रखाई नहीं रह सकती। शक्ति के शक्ति द्वारा ही पतन होता है। राज्य का आधार, जैसा कि शील ने कहा है, शक्ति नहीं, बरम्ब दृष्टि है।

जिस समय इटली में फासीवाद अपनी चरम सीमा पर था बहुत से पर्यवेक्षकों का मत था कि यह बल पर आधारित व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगी। प्रसिद्ध विद्वान् दार्शनिक वेनदेटो क्रोस (B Croce) तथा इतिहासकार फेरेरो (Guglielmo Ferrero) ने उस समय मत व्यक्त करते हुए लिखा था कि बल-प्रयोग पर आधारित शासन केवल पतनोन्मुख जातियों में ही अधिक मान्य तब बने रह सकते हैं। जो देश आगे बढ़ रहे हैं या जिनमें प्रगतिवादिता के अनेक तिर्यों न किसी रूप में विद्यमान हैं, यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। इसका अनिश्चित शक्ति ने जिस शासन का निर्माण हुआ है, उसका नाश भी शक्ति ने ही किया है। रोम साम्राज्य का अना द्वारा निर्माण हुआ था, और उसका अन्त भी सेना ने ही किया। फासीवादी शासन-व्यवस्थाओं का भाग्य भी भविष्य होगा। भारत में ऐसा हुआ भी। फासीवाद लगभग दो दशकों तक ही चल सका। द्वितीय विश्व युद्ध ने इटली तथा जर्मनी दोनों से ही फासीवाद को समाप्त कर दिया।⁵¹

फासीवाद और लोकतन्त्र

फासीवाद लोकतान्त्रिक व्यवस्था को महत्त्व नहीं देता। उनके अनुसार यह जन-

50 La-ki, H J., Reflections of the Revolution of Our Time, p 86,
काकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ० 493

51 कोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ० 520

शासन नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण जनता स्वार्थ के बन्धीभूत रहती है। वह स्वार्थ से ऊपर उठकर सम्पूर्ण सामाजिक हित में नहीं सोच सकती। इसके प्रतिरिक्त हम व्यवस्था में थोड़े से बालाक नेता हमेशा सत्ताधारी बने रहते हैं। हमें बहुसंख्यक सम्पत्ति का शासन सम्भना ध्रम होगा। फासीवादी लोकतन्त्र को 'सडा हुमा शय' और सत्तद को 'यातूनी दुकान' कहते हैं। फासीवादियों द्वारा लोकतन्त्र की आलोचना में आशिक सत्यता तो है, किन्तु इस आलोचना से वे लोकतन्त्र में सुधार नहीं करना चाहते, वे उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लोकतन्त्र व्यवस्था में कुछ दोष होते हुए भी फासीवादी व्यवस्था से तो प्रति उत्तम है।

फासिस्ट विचारधारा स्वतन्त्रता और समानता के आदर्शों के विरुद्ध है। उनका यह विचार कि स्वतन्त्रता एक विचार न होकर बर्तव्य है तथा शक्तिशाली राज्य के आशापालन में ही व्यक्ति की स्वतन्त्रता निहित है, गलत है। ये अधिनायकवाद की धेदी पर स्वतन्त्रता का बलिदान कर देते हैं। फासीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत मनुष्य एक मशीनी पुरजे के समान रह जाता है, जिसमें उसके व्यक्तित्व का पूर्ण तोप हो जाता है।

समानता के विषय में फासीवादी प्रकृति के आधार पर व्यक्तियों को असमान मानते हैं। उनके अनुसार समाज में व्यक्ति समान नहीं हो सकते। इससे मना नहीं किया जा सकता कि शारीरिक क्षमता, बौद्धिक प्रतिभा तथा आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किन्तु यही समझ कर राज्य उनको असमान माने यह भारी भूत होगी। राज्य के समक्ष मय व्यक्ति समान होने चाहिएँ, राज्य किसी भी आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य का कर्तव्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना होता है। इस सम्बन्ध में फासीवादी आलोचना के विषय में लास्की ने लिखा है कि फ्रांस के उपरान्त जिन संवैधानिक आधार और प्रतिनिधित्व लोकतन्त्र का विरासत हुआ फासीवाद में उन सभी को उखाड़ फेंका। यह मनुष्य को एक साध्य के रूप में बने भी स्वीकार नहीं करता।⁵²

कला एवं विज्ञान की अवनति (6)

फासीवादी राज्य में कला एवं विज्ञान की प्रगति नहीं हो सकती। अधिनायकवादी शासन में समाज एक व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष पर राज्य का नियन्त्रण रहता है। विज्ञान तथा कला को भी प्रोपेगेंडा का एक साधन माना जाता है। इस स्वति में कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान का ह्रास होता चला जाता है इस प्रकार के अनुनासिक और नियन्त्रित राज्य सामाजिक प्रगति के लिए कभी भी अव्युक्त नहीं हो सकते। अधिनायकतन्त्र का संचालन एक विशाल समन्वित संशोधन-ग्रह की भांति होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को नियत कार्य दिया जाता है और उसने सम्पादन पर गतकं दृष्टि रखी जाती है। यह पद्धति समाज-दोषी तथा अयोग्य एवं अक्षम व्यक्तियों के लिये ठीक हो सकती है, किन्तु बुद्धिमान, साहसी श्रेष्ठ

तथा चरित्रवादी के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। ऐसे व्यक्तियों को अधिनायक-तन्त्र, और वह भी अतिवैक्याद पर आधारित, पशुबल और पशुबुद्धि का सामना करने के विषय कुछ भी नहीं। किसी राष्ट्र के सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अत्यंत केन्द्रीभूत एवं दमनकारी निर्देशन साहित्य, विज्ञान तथा कला के विकास की सम्भावनाओं को नष्ट कर देता है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आइंस्टाइन (Albert Einstein) ने अपने एक सूक्ष्मलेख 19 शब्दों के निबंध में लिखा है—

‘अधिनायकतन्त्र का अर्थ है सब ओर से प्रतिबंध और उसके परिणामस्वरूप निरर्थक प्रयत्न। विज्ञान केवल स्वतन्त्र भाषण के वातावरण में ही अभिवृद्धि प्राप्त कर सकता है।’⁵³

अन्तर्राष्ट्रीय विचारों की आलोचना

फासीवादियों के अन्तर्राष्ट्रीय विचार अति भर्त्सना योग्य हैं। वे प्रथम, उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। द्वितीय स्वयं की नस्ल श्रेष्ठता के औचित्य को सिद्ध करते हैं। तृतीय, क्षेत्रीय विस्तारवाद को मान्यता देते हैं। चतुर्थ, युद्ध को राष्ट्रीय नीति का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। ये सभी विचार अन्तर्राष्ट्रीयता के शत्रु हैं। व अन्तर्राष्ट्रीय शांति को वायरो का स्वप्न कहते हैं, किन्तु शांति का कोई अन्य विकल्प हो ही नहीं सकता। यदि निरंतर युद्ध चलते रहे सभी राष्ट्र विस्तारवादी नीति अपना ले तो ऐसी स्थिति हो जायेगी जैसा कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के विषय में लिखा है। इसका परिणाम यह होगा कि सार्वजनिक बलाएँ की ओर न तो ध्यान ही जायेगा और न समय ही मिल पायेगा। युद्धों पर अब याघिक धनराशि व्यय होने से विकास और उन्नति का मार्ग छवरेड हो जायेगा। फासीवादियों के अन्तर्राष्ट्रीय विचार अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के विरुद्ध हैं। ये अन्धकारवादी और मानव जाति के लिए घातक हैं।

यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध ने फासीवादी-नाजीवादी इदृश्यों को पूरा नहीं होने दिया, यह सोचना भूल होगा कि फासीवाद मर चुका है। गटिल ने लिखा है कि उदारवाद इतना खर्चीला है कि बहुत कम लोग उसकी कीमत चुनाने को तैयार हैं अथवा इस योग्य हैं। जो विचार मनुष्य के मस्तिष्को में घट कर जाते हैं उन्हें युद्ध द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। इस समय ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि विश्व के बहुत से देशों से अधिनायकतन्त्र को त्यागने की वास्तविक इच्छा उत्पन्न हो गई है। वास्तविकता तो यह है कि यदि साम्यवाद के विरुद्ध दक्षिणपन्थी प्रतिक्रिया का जोर बढ़ा तो फासीवाद पुनः भयंकर शक्ति के रूप में उठ खड़ा होगा।⁵⁴

⁵³ उद्धृत, बोकर., प्राधुनिक राजनीतिक चिन्तन पृ० 519

⁵⁴ गटिल, राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, पृ० 453-54

फासीवाद एव राष्ट्रीय समाजवाद समकालीन परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोही थे। भविष्य में यदि इस प्रकार की परिस्थितियाँ पुनः उत्पन्न होती हैं तो असंदिग्ध रूप में इसी प्रकार की विचारधाराओं का फिर उद्भव होगा। इस प्रकार के विचारों का आगे विकास न हो, उसके लिये यह अति आवश्यक है कि हम अपनी समस्याओं का बुद्धिमानी के साथ सामना करें। फासीवाद तथा राष्ट्रीय समाजवाद की प्रेरणा शक्ति राष्ट्रीयता की उग्र भावना थी जिसका अभी भी अभाव नहीं है।⁵⁵ इसके विकल्प रूप में हमें शान्ति, सद्भाव, सहयोग के सिद्धान्तों को ही राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अपनाना पड़ेगा। अन्य विकल्पों का तात्पर्य विश्व को उन्हीं निर्दयी, अमानवीय शक्तियों को समर्पण करना होगा जिनसे हम एक पीढ़ी पहले ही जूझ चुके हैं। एक कामना के रूप में इस प्रकार की परिस्थिति पुनः नहीं आनी चाहिये।

पाठ्य-ग्रन्थ

1. Ashton., The Fascist,
Chapter 2, What is Fascism
2. आशीर्वादम्, ए डी राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड,
अध्याय 22, सर्वाधिकारवादी राज्य
3. Charques and Ewen., Profits and Politics in the Post-War
World (1934),
Chapter IV, Italy.
4. कोकर, फ्रांसिस., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन,
अध्याय 17, फेतिज्म.
5. Ebenstein, W., Today's Isms,
Chapter II, Totalitarian Fascism.
6. गेटिल, रेमण्ड गारफील्ड., राजनीतिक चिन्तन का इतिहास,
अध्याय 26, फासीवाद.
7. Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political
Thought,
Chapter 17, Fascism and
National Socialism.
8. Laski, H. J., Reflections on the Revolution of
Our Time,
Chapter 3, The Meaning
of Fascism.

⁵⁵ Sabine, G. H A History of Political Theory, p. 711.

- 9 Merks, Peter A Political Continuity and Change ,
Chapter 14, Fascism and National
Socialism.
- 0 Munro, Ion S Through Fascism to World Power
- 11 Sabine G H A History of Political Theory,
Chapter 35,
Fascism and National Socialism
-

लोकतान्त्रिक समाजवाद

लोकतान्त्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) के सम्बन्ध में कुछ धारणायाँ प्रचलित हैं। इन्निधे सर्वप्रथम उनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। कभी-कभी समष्टिवाद (Collectivism) तथा लोकतान्त्रिक समाजवाद को एक ही समझा जाता है, यह त्रुटिपूर्ण है। समष्टिवाद एक व्यापक विचार है, जिसके अन्तर्गत वे सभी विचारधाराएँ आती हैं जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को किसी न किमी रूप में सीमित कर किसी मर्यादा जैसे राज्य आदि को व्यापक अधिकार प्रदान करती हैं। इस प्रकार समाजवाद, साम्यवाद, फासीवाद आदि सभी समष्टिवादी विचारधाराएँ हैं। समाजवाद के मन्त्रों में समष्टिवाद का तात्पर्य राज्य तथा स्थानीय मर्यादाओं के आधिकार तथा अन्य कार्यों में विचार के रूप में ही लिया जाता है।

समष्टिवाद को राज्य समाजवाद कहा जा सकता है क्योंकि इसमें समाजवादी कार्यों को कार्यान्वित करने में राज्य को अर्थाधिक प्राथमिकता दी जाती है। लोकतान्त्रिक समाजवाद भी समष्टिवादी होता है, किन्तु लोकतान्त्रिक समाजवाद में लोकतान्त्रिक शक्तियाँ, सिद्धान्तों एवं मूल्यों को साध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा राज्य जो समष्टिवादी होता है, उन आदर्शों की प्राप्ति का साधन होता है। अग्रे शब्दों में यह कह सकते हैं कि समष्टिवाद एक तटस्थ राज्यवाद है जिसे विभिन्न आदर्शों के अनुसार निर्भी भी प्रकार के समाजवाद में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि मार्क्सवादी आदर्शों की प्राप्ति करनी है तो यह साम्यवाद है; यदि हिटलर और मुसोलिनी के उद्देश्यों की उपलब्धि करनी है तो यह नात्सीवाद और फासीवाद हो सकता है; तथा यदि लोकतान्त्रिक मूल्यों में अभिवृद्धि करनी है तो यह लोकतान्त्रिक समाजवाद कहा जा सकता है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद को परिभाषित करना कठिन कार्य होने के साथ-साथ सम्भव सा प्रतीत होता है। "इसका एक सुपरिभाषित विचारधारा वा होता तो दूर रहा, यह विभिन्न चिन्तकों और राजनीतिक शक्तियों के योगदान का मगूह जैसा लगता है। सम्भवतः कोई भी समाजवादी एक ही साव इन विचारों और सिद्धान्तों

का सार्किक (या विदेकपूर्ण ढंग से) निर्वाह नहीं कर सकता ।' ¹ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में समाजवाद की निम्नलिखित परिभाषा उल्लेखनीय है —

'समाजवाद उस नीति या सिद्धान्त को कहते हैं जिसका उद्देश्य एक केन्द्रीय लोकतान्त्रिक सत्ता द्वारा प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा धन का उत्तम वितरण एवं उसके अधीन रहते हुए धन का उत्तम उत्पादन उपलब्ध करना है ।'²

यह परिभाषा वास्तव में लोकतान्त्रिक समाजवाद की ओर ही इंगित करती है । इसमें समाजवाद के उद्देश्य, साधन एवं प्रणियाँ का जो उल्लेख है वह लोकतान्त्रिक समाजवाद का सन्दर्भ ही सही लगता है । फिर जब समाजवाद के विभिन्न सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट नाम ग्रहण कर चुके हैं, तब प्रचलित भाषा में समाजवाद का अर्थ लोकतान्त्रिक समाजवाद से ही लगाया जाता है ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद का कोई निश्चित दशन नहीं है । इसका विकास विभिन्न समय एवं देशों में विभिन्न परिस्थितियों के सन्दर्भ में हुआ है । लेकिन इसका मूल सैद्धान्तिक पक्ष जितना स्पष्ट है शायद ही किसी अन्य समाजवादी शाखा का हो । लोकतान्त्रिक समाजवाद में 'लोकतन्त्र' और 'समाजवाद' दोनों ही स्वयं स्पष्ट हैं । कोई भी समाजवादी विचारधारा जिसमें लोकतन्त्र को साध्य एवं साधन दोनों ही रूप में स्वीकार किया जाता है, लोकतान्त्रिक समाजवाद कहलाता है । लोकतान्त्रिक समाजवाद में लोकतान्त्रिक आदर्शों की उपलब्धि लोकतान्त्रिक साधनों से ही होनी चाहिये । सूक्ष्म में, लोकतान्त्रिक समाजवाद के तीन प्रमुख पक्ष हैं । प्रथम, समाज का उद्देश्य समस्त जनता का कल्याण होता है, किसी वर्ग विशेष का नहीं । द्वितीय, जन-कल्याण सम्बन्धी गतिविधियों का माध्यम राज्य या अन्य राजकीय संस्थाएँ होती हैं । तृतीय, उद्देश्यों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक साधनों से होनी चाहिये ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद का विकास

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोप में न तो लोकतन्त्र था और न समाजवाद । शासन व्यवस्था के रूप में निरंकुशवाद और सामन्तवाद का ही सर्वत्र प्रभुत्व था । कुछ घोट से व्यक्तिगत के हाथ में राजसत्ता और अर्थ-व्यवस्था केन्द्रित थी । उच्च वर्ग द्वारा साधारण जनता का दमन और शोषण एक सामान्य बात थी । लोकतन्त्र और समाजवाद के उदय में औद्योगिक क्रांति तथा उससे उत्पन्न परिस्थितियों का मूल योगदान रहा है । यहाँ पर यह भ्रमना दुर्लभ है कि पहले लोकतन्त्र का प्रादुर्भाव हुआ या समाजवाद का । औद्योगिक क्रांति के युग में लोकतन्त्र और समाजवाद का वही समानान्तर तथा वही मिला जुला सा विकास

1 Merkl, Peter H., Political Continuity and Change, p 139.

2 देखिये पृ 4

दृष्टा । किन्तु जैसे ही लोकतन्त्र और ममाजवादी विचारधाराएं अपना प्रलग-अलग अस्तित्व स्पष्ट करने लगी, इन दोनों की दृष्टियां एवं कमजोरियां दृष्टिगोचर होने लगी ।

उन्नीसवीं शताब्दी में उदारवादी और लोकतांत्रिक विचारधारा का धीरे-धीरे विकास हो रहा था । लेकिन यह उदारवाद व्यक्तिवाद पर आधारित था जो पूर्णतः पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में विरामित हुआ । यह वह युग था जब लोकतांत्रिक तथा उदारवादी सिद्धान्तों के प्रति चेतना में तो वृद्धि हुई पर राज्य का कोई विशेष महत्व नहीं था । राज्य को कुछ निश्चिन्त कार्यों तक ही सीमित रखकर अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार का प्रतिरोध किया गया । इस समय राज्य के अहमनक्षेप की नीति की सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त थी । गैटिल के अनुसार उस काल में इस विचार का आधिपत्य था कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो कम से कम शासन करता है । 'सरकार में स्वतन्त्रता न कि सरकार के द्वारा स्वतन्त्रता' उस काल का मुख्य आदर्श था । उस समय यह मान्यता थी कि सरकार का काम केवल व्यवस्था स्थापित करना है दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं । यह व्यक्तिवाद का अतिवादी रूप था ।³ ममाज की शक्तियां शुद्ध व्यक्तिवाद की दिशा में जा रही थी ।

औद्योगिक क्रान्ति से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई । अन्न व्यक्ति को यह आशा हो गई कि वह अपने परिश्रम से अधिकाधिक धन कमा सकता है । उसने अपने माधन और शक्ति से यूरोप तथा अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को कायापलट कर दी ।

व्यक्तिवादी विचारधारा और औद्योगिक-क्रान्ति के समन्वय ने पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म दिया । इससे साधन-सम्पन्न व्यक्ति तो उद्योगपति पूंजीपति बन गये किन्तु श्रमिकों की दशा अत्यन्त ही दयनीय थी । "नगरों की नदी वस्तियों में रहने वाले मजदूरों के रहन-सहन का स्तर अत्यन्त नीचा था; वे लगभग भुखमरी अवस्था में रहते थे । उनके सम्बन्ध में माल्थस ने जो भविष्यवाणी की थी वह मानो पूरी हो गई । आठ-आठ और नौ-नौ घण्टे के बच्चे प्रतिदिन जितने घण्टे कार्य करते थे, उतने घण्टे आज का पूरा आदमी भी नहीं करता । मालिक लोग समझते थे कि मजदूर तो अन्य विरूप वस्तुओं की भांति ही है, मजदूरों की तत्त्वतः वही स्थिति थी जो कि विरूप वस्तुओं की, अतः उनका उस मूल्य में जिसका वे अपने परिश्रम में सर्जन करते थे, वेतन के अतिरिक्त कोई साभा नहीं था । सम्पूर्ण मूल्य उन मालिकों की जेब में जाता जो कारखाना चलाते और जोखिम उठाते थे । इन परिस्थितियों में सरकी स्वतन्त्रता की बात करना तो सम्भव था किन्तु वास्तव में स्वतन्त्रता थोड़े लोगों को ही उपलब्ध थी । बहुसंख्यक लोग तो केवल इस अर्थ में स्वतन्त्र थे कि 'स्वतन्त्रतापूर्वक पुल के नांचे सो सकते थे' जैसा कि कार्लोस

3 गेटिल, राजनीतिक चिन्तन इतिहास, पृ. 397.

Thomas Carlyle (1795-1881) ने कहा था।⁴ जब उच्च वर्ग थमिको की दयनीय दशा से ही द्रवित नहीं हुआ, तो थमिको के राजनीतिक अधिकारों की कल्पना का प्रश्न ही नहीं था। समस्त राजनीतिक-आर्थिक अधिकार उच्च वर्ग तक ही सीमित थे।

इस स्थिति में प्रश्न यह था कि इस ग्रन्थाय और शोषण का किस प्रकार उन्मूलन किया जाय ? या, इस दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था के विस्तरण में और कौन सी व्यवस्था की स्थापना हो, जो इस प्रकार के दमन और शोषण से मुक्त कर सके। वास्तव में उस समय इस बात की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हुई कि—

- (I) समाज के उत्पादन साधनों पर किसी एक वर्ग विशेष का नियन्त्रण न हो,
- (II) समाज की सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण हो,
- (III) समाज के थमिक वर्ग को उसके थम के उपलक्ष में उचित वेतन मिले। यह वेतन उसे किसी वर्ग विशेष से आभार रूप में न मिले वरन् उसका यह अधिकार हो।
- (IV) थम व्यवस्था का उद्देश्य निजी लाभ के स्थान पर समाज सेवा को प्रतिष्ठित करना हो।

लेकिन इस बाध का उत्तरदायित्व कौन ले ? उस समय समस्त आर्थिक व्यवस्था पर पूँजीपतियों का आधिपत्य था। इन शोषण-कर्त्ताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि वे स्वयं ही न्यायोचित समाज की स्थापना में पहल करें। उदार भावना से प्रेरित हो धनिक लोग कुछ कार्य कर सकते थे किन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। एक शोषण-रहित समाज की स्थापना के दायित्व के लिए राज्य ही एक उपयुक्त सहायक था, जो समाज की ओर से उत्पादन के साधनों पर नियन्त्रण कर सामाजिक सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण कर सके। इस प्रकार उस समय यह मान जोर पकड़ने लगी कि राज्य को सामाजिक व्यवस्था में सन्निवृत्त भाग लेना चाहिए। अद्वैतवादीय की नीति से ग्रन्थाय का उन्मूलन नहीं हो सकता था। अब राज्य के सकारात्मक कार्यों की भूमिका को मान्यता मिलना प्रारम्भ हुआ।

उस समय जिस प्रकार से राज्य संगठित था, क्या वह इस प्रकार के उत्तरदायित्व के लिए समर्थ था ? क्या वह इस दायित्व का निष्पक्षनापूर्वक निर्वाह कर सकता था ? यह भी उस समय असम्भव सा जान पड़ा क्योंकि जिन लोगों का अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण था उन्हीं का शासन-व्यवस्था पर नियन्त्रण था। उन्हीं का शासन-व्यवस्था पर आधिपत्य था। उन्हीं ही से हस्तक्षेप का नीति को प्रोत्साहन दिया था और यदि राज्य कोई सन्निवृत्त कदम उठाया भी तो राज्य ऐसा करने में अनमथ था, क्योंकि राज्य का स्वरूप राजतंत्र, धनिकतन्त्र या सामन्तवादी जैसा ही था, जो अपने वर्ग हित को साधना के लिए कटिबद्ध था।

⁴ गेटिन, राजनीतिक विचारों का इतिहास, पृ० 398

प्रथम आवश्यकता इस बात की थी कि राज्य के वास्तविक स्वरूप में ही परिवर्तन किया जाय। राज्य की शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक ढंग में ही ताकि वह सही ढंग में समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। यही से राज्य को लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों पर संगठित करने की मांग न महत्व ग्रहण किया। इस प्रकार उस समय सामाजिक सम्पत्ति के स्रोतों का समाजोकरण करना तथा लोकतन्त्र की स्थापना के लिए चिन्तन और आन्दोलन का ही प्रादुर्भाव हुआ। यही लोकतान्त्रिक समाजवाद का आधार एवं प्रारम्भ था।

माक्सवादी विचारों से यूरोप में वास्तविक समाजवादी विचार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। माक्सवादी समाजवाद वर्ग-सर्पथ और त्रानि पर आधारित था। माक्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं, क्योंकि माक्स-एन्गल्स के विचार ऐतिहासिक तथ्यों, सामाजिक प्रभावों, मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक अध्ययन, कारण-परिणाम के सम्बन्धों पर आधारित था। सभी लोकतांत्रिक समाजवादी माक्सवादी विवेचन से प्रभावित तो हुए किन्तु माक्सवादी सिद्धान्त जैसे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग-सर्पथ, अमिन्न-त्राति, सर्वहारा वर्ग या अधिनायकत्व तथा राज्यरहित, शापणरहित अन्तिम साम्यवादी-व्यवस्था आदि को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि माक्सवाद उस समय सम्पूर्ण यूरोप पर छाया रहा, किन्तु यह लोकतान्त्रिक समाजवादियों के लिए प्रेरणास्रोत न बन सका। वास्तव में लोकतान्त्रिक समाजवाद का विराम माक्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ।

यूटोपियायी समाजवादी (सेन्ट साइमन, चार्ल्स फोरिये, रॉबर्ट ओबन आदि) प्रारम्भिक समाजवादी थे जिनके विचारों में समाजवाद के सभी सिद्धान्तों की आकी मिलती है। वे उस समय प्रचलित पूँजीवादी व्यवस्था, स्पर्धा लाभ आदि के कटु आलोचक थे तथा उनसे सम्बन्धित बुराइयों के उन्मूलन के पक्ष में थे। किन्हीं कारणों से उन्हें यूटोपियायी कहा जाता है, किन्तु वे वास्तव में लोकतान्त्रिक समाजवादी थे। यूटोपियायी समाजवादियों ने लगभग उन सभी सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जो लोकतान्त्रिक-समाजवाद के सिद्धान्त-सूत्र हैं, उदाहरणार्थ—

- (i) यूटोपियायी समाजवादी वर्गभेद में विवाद नहीं करते थे। उनका समाजवाद सम्पूर्ण समाज का था।
- (ii) सामाजिक बुराइयों को दूर करने तथा समाजवादी सुधारों के लिए वे राज्य एक विधि निर्माण के महत्व को स्वीकार करते थे।
- (iii) वे शान्तिपूर्ण एवं विकासवादी साधनों को मान्यता देने थे।

वेन्थम (Jeremy Bentham, 1748-1832) प्रमुख उपयोगितावादी थे। किन्तु उनके विचारों ने प्राचुरिक उदारवाद एवं समाजवाद को प्रभावित किया। वेन्थम का उपयोगितावादी सिद्धान्त — अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम

भना (greatest happiness of the greatest number) — इस समय प्रगतिशील सुधारों का मुख्य आधार बन गया।⁵ इस सिद्धांत ने सुधारों में उच्च वय की परिधि तयकर यह मान्यता प्रदान की कि कल्याणकारी गति विधियाँ के अतः समाज के अधिकांश से अधिक व्यक्ति को लाभ चाहिए। वह मानव स्वतंत्रता का प्रश्न समझकर या किन्तु व अधिकांश प्रकृति से नही राज्य या विधि द्वारा प्राप्त होने हैं। वे यम ने कई सुधारों का सुझाव दिया। वेथम ने जिन व्यावहारिक विधायी सुधारों पर बल दिया उनका बड़ा सम्बन्ध था जिनमें सर्वप्रथम नाव शिक्षा को स्वास्थ्य दरिद्र वय में सम्बन्धित कानून। म सुधार असैनिक मया सुधार आदि की योजनाय सम्मिलित था। यम पर वेथम को यम विज्ञान द्वारा कि य सभी सुधार व्यर्थ हूँ तक कि समाज में प्रतिनिधि प्रणाली व्यवस्था में लोकतांत्रिक परिवर्तन न किया जाये।⁶ इस प्रकार वेथम सांख्यिक सुधार और राज्य द्वारा सुधारवादी कार्यक्रम का समर्थक था। वेथम राज्य का उत्तम मन्त्रपूण स्थान नहीं था चाहना था किमस वह मानववर्गी अधिभूत का स्थान ग्रहण करे। व्यक्ति क सम्बन्ध में वह राज्य को सीमित मानता था। वेथम के अनुसार सामाजिक हित व्यक्ति का न सामूहिक हित है इसके अनिश्चित और कुछ नहीं।⁷ इस प्रकार वह मधसनाधरों राज्य का पूरक विरोधी था। मन्त्रों द्वारा वेथम जिन युराध्यों को स्वीकारना चाहता था उनमें सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण था कि जिस युराध्य का उद्घाटन किया जाय वह वास्तव में बुराई है तथा जिन साधनों का प्रयोग किया जाय वे उन युराध्यों से कम बुरे होने चाहिए।⁸ इस प्रकार वेथम साधनों की नमनीयता व पक्ष में था। उनमें बुरे साधनों को कभी मान्यता नहीं थी। वेथम के विचारों का समाजवादी तो नहीं वह मकने किन्तु निराल्पता को राजतांत्रिक समाजवादी मान्यता देना है उनका अन्त कृष्ण आधार वेथम के विचारों में मिलता है।

जान स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill 1806-73) व्यक्तिगत विचार धारा से जुड़ गए हैं किन्तु उनकी व्यक्तिगतता व्यक्ति के स्वयं तक नहीं सीमित थी। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की सामाजिक सम्बन्ध में पर्याय का है। उनके विचारों में लोकतंत्र और सामाजिकता दोनों का ही दिग्दर्शन है। मिल के ही शब्दों में —

मनुष्य जीवन में वैयक्तिक और सामाजिक दोनों अंशों के साथ साथ हाथों में य दोनों प्रश्नों का उत्तर देना तक सीमित रहता है जिन

5 Sabine G H A History of Political Theory p 566

6 गति राजनीतिक चिन्तन का इतिहास पृ 369

Sabine G H A History of Political Theory p 567

7 Hallowell J H Main Currents in Modern Political Thought p 214

गति राजनीतिक चिन्तन का इतिहास पृ 368

Hallowell J H Ibid p 214

वाणी से उनका विशेष और गहरा सम्बन्ध है। उन बातों में जिनसे कि केवल व्यक्ति के निज का सम्बन्ध है, व्यक्तिगतता की अभिव्यक्ति की अनि-यन्त्रित स्वतन्त्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के जिम आचरण और व्यवहार से समाज पर प्रभाव पड़ता है, उस आचरण और व्यवहार पर समाज का अधिकार होना चाहिए।⁹

मिल के विचारों से किमी समाजवादी सम्प्रदाय की सृष्टि नहीं हुई है किन्तु उन्होंने एक ओर तो अनियन्त्रित स्वतन्त्रता का विरोध किया, दूसरी ओर राज्य के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि का समर्थन किया। व्यावहारिक राजनीति में वे परिवर्तनवादी थे तथा उस समय प्रचलित तमाम बुराइयों के उन्मूलन के लिए विधि निर्माण का समर्थन करते थे। उनके विचार किसी न किमी रूप में लोकतन्त्र और समाजवाद के समन्वय की ओर इंगित करते हैं। आगे चलकर इन्हीं विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति इंग्लैंड की समाजवादी प्रवृत्ति में मिलती है।

ग्रीन (T. H. Green 1836-1882) आदर्शवादी-उदारवादी थे। उनके विचारों ने लोकतान्त्रिक समाजवाद को किसी न किमी रूप में प्रोत्साहन दिया। ग्रीन के पहले उदारवादी (Liberal) कानूनों का तदर्थ रूप (ad hoc) में कभी-कभी निर्माण होता था। ग्रीन ने उदार कानूनों को स्थाई आधार पर सम्पूर्ण समाज के लिए निमित्त करने का सुझाव दिया। ग्रीन ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक उत्तर-दायित्व को समन्वित तथा संतुलित करने का प्रयत्न किया। एक ओर तो उन्होंने मानव अधिकारों का समर्थन किया जो लोकतन्त्र के प्राण होते हैं, दूसरी ओर इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को आवश्यक बतनाया तथा राज्य के सकारा-त्मक कार्यों का सुझाव दिया जो समाजवाद का मुख्य तत्व है। ग्रीन के शब्दों में—

“राज्य को अधिकारों की पूर्ण कल्पना होनी है, और ये अधिकार व्यक्तियों के अधिकार होते हैं। उन्हें बनाये रखने के लिए समाज यह रूप ग्रहण करता है।”¹⁰

ग्रीन की नैतिकता का आधारभूत सिद्धान्त व्यक्ति और सामाजिक समुदाय जिमका कि वह सदस्य है, की पारस्परिकता है।¹¹ ग्रीन का यह कथन कि ‘स्वयं’ सामाजिक है (*Self is a Social Self*) अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है।¹² ग्रीन द्वारा उदारवाद की नयी व्याख्या का परिणाम यह हुआ कि राजनीति और अर्थशास्त्र के

9 Mill J S, Liberty and Representative Government, Hindi Translation by P. C Jain, Hindi Samiti, Suchna Vibhag, Uttar Pradesh, 1953, p 99

10 Green, T H, Lectures on the Principles of Political Obligation, Hindi Translation, by Dr. B M Sharma, Hindi Samiti, Suchna Vibhag, Uttar Pradesh, 1956, p. 137.

11. Sabine, G. H, A History of Political Theory, p. 611.

12. Ibid, p. 617.

मध्य जो एक स्टोर सीमा थी वह समाप्त हो गई। चीन के पहले उदारवादी अर्थ-शास्त्र तथा बाजार की स्वतन्त्र प्रक्रिया में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। चीन के अनुसार मुक्त एवं स्वतन्त्र बाजार प्रक्रिया भी एक सामाजिक सस्था है जिसे पूर्णतः स्वतन्त्र रखने के लिए विधि निर्माण एवं राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। येसाइन ने 'म सम्बन्ध में लिखा है —

‘चीन के उदारवाद में राज्य की स्पष्ट एवं गवारात्मक साध्य स्वीकार किया गया है, जिसका प्रयोग सकारात्मक स्वतन्त्रता (positive freedom) में योगदान हेतु विधि निर्माण के लिए किया जा सकता है। मूल्य में राज्य का उपयोग सामान्य कल्याण के क्रमों भी उद्देश्य के लिए हो सकता है।’¹³ राज्य सुरक्षा में वृद्धि नहीं बल्कि उन्मा उन्मूलन करना है।

चीन ने सामाजिक हित में राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने का सुभाव दिया। उनका विश्वास था कि राज्य द्वारा सार्वजनिक शिक्षा भिन्न अनुदान ही नहीं बल्कि उसे इससे अधिक कुछ और भी करना चाहिए। राज्य को स्वास्थ्य एवं सफाई, अच्छे भवन निर्माण, थमिकों के साथ समझौता पर नियंत्रण करने में अपने उत्तरदायित्वों का विस्तार करना चाहिए। राज्य अपने कार्यक्षेत्र में जो भी विस्तार करे, वह शक्ति द्वारा नहीं जन-इच्छा द्वारा होना चाहिए। चीन के ये विचार प्रथम ही लोकतान्त्रिक समाजवाद में योगदान के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं।

इंग्लैंड में फेबियन समाजवादियों ने वहाँ के चिन्तन को यहाँ प्रभावित किया। प्रशंसा को उसमें माक्सवाद के विकल्प के तत्त्व दृष्टिगोचर हुए। जोड (C E M Joad) ने फेबियनवाद को इंग्लैंड में लोकतान्त्रिक समाजवाद (जिसे जोड ने समष्टिवाद कहा है) का अग्ररूप माना है। फेबियन बुद्धिजीवियों ने यह स्वीकार किया कि पूँजीवाद और प्रतिभोगितावादी अर्थ व्यवस्था में कुछ ही लोगों को कुछ व सार्वम मिला है तथा बहुसंख्यका के कष्टों में वृद्धि हुई है। सामान्य लोगों का सुख एवं सुविधाएँ प्राप्त हो इसलिए समाज की ऐसी व्यवस्था की जाय जिसमें भूमि और औद्योगिक पूँजी को व्यक्ति या वर्ग विशेष के स्वामित्व से मुक्त करा कर सामाजिक स्वामित्व को स्थापना हो। फेबियन विचारकों ने प्रान्ति के स्वान पर लोक-तान्त्रिक नवैधानिक माधनों का समर्थन किया। फेबियन समाजवादियों की लोकतान्त्रिक समाजवाद प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यूटोपियायी समाजवादियों में ऊपर उठकर तथा मार्क्स के प्रान्तिकारी विचारों का वैज्ञानिक मानना कर फेबियनवादियों ने लोकतान्त्रिक या विकासवादी समाजवाद के मार्गों को प्रशस्त एवं स्पष्ट किया।

एडुवर्ड बन्तटाइन, जिन्हें प्रमुख सशोषणवादी कहा जाता है, को लोकतान्त्रिक समाजवाद के मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सशोषणवादी थमिकों

के हितैषी थे। वे मानते थे कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि राज्य उत्पादन का अधिक अच्छे ढंग से वितरण करे। इनके नेतृत्व में मोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक व्यापक समाजवादी कार्यक्रम¹⁴ स्वीकार किया जिसे यूरोप के विक्रमवादी समाजवादियों ने सामान्यतः स्वीकार किया था। इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीः—

1. सार्वजनिक, प्रत्यक्ष तथा समान मताधिकार,
2. जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व,
3. लोकमत के आधार पर विधि निर्माण करना,
4. निःशुल्क चिकित्सा
5. क्रमिक आय-कर (progressive income tax),
6. प्रति दिन आठ घण्टे काम,
7. राशि में काम लेने पर निषेध,
8. बच्चों से काम लेने पर निषेध, तथा
9. प्रत्येक नागरिक का जीवन बीमा आदि।

उपर्युक्त कार्यक्रम उस समय प्रगतिशील एवं समाजवादी था जिसने राज्य को एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। किन्तु लैस्ले, वॉर्स्टाइन आदि सभी की यह नीति थी कि यह कार्यक्रम वर्ग-समर्पण में निहित हिंसा के बिना ही सम्पादित किया जाय। उन्होंने परिवर्तनों के लिये लोकतान्त्रिक साधनों का समर्थन किया।

इंग्लैंड के मजदूर दल (The British Labour Party) का समाजवाद

लोकतांत्रिक समाजवाद का व्यावहारिक कार्यक्रम निर्धारित करने में इंग्लैंड के मजदूर दल (Labour Party) का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जोर्ड के अनुसार ब्रिटिश मजदूर दल बढ़ी हुई स्पष्टता के साथ समाजवादी गति-दिशा की ओर सवेत तथा शांतिपूर्वक उनका अनुसरण करता है। 1918 में इस दल ने 'मजदूर और तबदीन सामाजिक व्यवस्था' शीर्षक कार्यक्रम स्वीकार किया जो निम्नलिखित चार मौलिक सूत्रों पर आधारित थाः—

1. सबके लिये न्यूनतम राष्ट्रीय आय,
2. उद्योग का लोकतन्त्रीय नियन्त्रण,
3. राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में क्रान्ति,
4. अतिरिक्त सम्पत्ति का सार्वजनिक कल्याण के लिये उपयोग।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी सुभाष भी स्वीकृत किये गये, जिनको

¹⁴ यह कार्यक्रम गोथा कन्वेंशन (Gotha Convention, 1875) तथा एरफर्ट प्रोग्राम (Erfurt Programme, 1891) पर आधारित था।

See Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political Thought, pp. 447—450.

कायान्वित करत समय सामाजिक वर्गों व आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसका अतिरिक्त दल नोकरशाही और प्रति केन्द्रीकरण के भय से भी सजग है। इसलिये स्थानीय सस्थाओं की गतिविधियों को व्यापक बनाने का प्रयत्न किया गया। महत्वपूर्ण सेवाओं के राष्ट्रीयकरण और नगरपालिकाकरण के फलस्वरूप बहुत से अनिर्वात धन का निजो स्वामित्व स्वयमेव ही समाप्त हो जायेगा। आनुकम्बिक प्राय कर से पू जीपतिया व लाभ का अधिकांश भाग राज्य के पास चला जायगा। इस तरह राज्य जो धन राशि प्राप्त करेगा उसका प्रयोग राष्ट्र भर में शिक्षा फैलाने, न्यूनतम आय वाला का मानदण्ड ऊँचा करने, योमारा और निर्वेलो की शिक्षा और उनका पालन-पोषण करने, माता बनने वाली स्त्रियों की सहायता, वैधानिक शोधों को प्रोत्साहित और समाज के सामान्य जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिये किया जायगा। मजदूर दल के वे प्रादश, जो उस समय निश्चिन्त किय गये, ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें समाजवादी राज्य में ही प्राप्त किया जा सकता है।¹⁵

1929 में 'मजदूर और राष्ट्र' के नाम से एक और घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें मजदूर दल ने कोयले की खानों, भूमि, वातावात, जीवन बीमा व सामाजिककरण तथा बैंक ऑफ इंग्लैंड के राष्ट्रीयकरण का वचन दिया। 1940 में लेबर पार्टी ने एक कार्यक्रम प्रकाशित किया जो 'मजदूर, युद्ध और अन्ति' के नाम से प्रसिद्ध है।¹⁶ 1942 में लेबर पार्टी के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का यह भाग महत्वपूर्ण है—

"दश के मौलिक उद्योगों और सेवाओं का सामाजिककरण तथा सामाजिक उपयोग की दृष्टि से उत्पादन की योजना बनाना, क्योंकि यही एक ऐसी न्याय सगत समृद्ध आर्थिक व्यवस्था की स्थाई आधार-शिला है जिसमें राजनीतिक लोकतन्त्र और व्यक्तिगत स्वाधीनता के साथ सभी नागरिकों के लिए जीवन के एक न्याय सगत मानदण्ड की सगति वैठाने जा सकती है।"¹⁷

यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्त होते ही इंग्लैंड में चुनाव हुए। लेबर पार्टी के इतिहास में 1945 के ग्राम चुनावों का विशेष महत्व है। इसी वर्ष लेबर पार्टी पूर्ण सत्ताधारी दल के रूप में सामने आई। यद्यपि इसके पहले भी लेबर पार्टी 1924 और 1929-31 में सत्ता में आई थी, किन्तु उस अपन कार्यक्रम का कार्यान्वित करने के लिए समुचित अवसर नहीं मिल सका। यह अवसर अब 1945 में आया। 1945 के ग्राम चुनावों के पहले लेबर पार्टी ने वचन दिया था कि वह सत्तासूड होत ही आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की

15 जाड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवक्षिका, पृ 56-58.

16 जाड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवक्षिका, पृ 55.

17 उद्धृत, आनीबादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ 625-26

स्थापना कर देगा।¹⁸ क्लोमेण्ट ऐटली (C. R. Attlee) के नेतृत्व में गठित मन्त्रिमण्डल ने कोयले और इस्पात के उद्योगों, बैंक ऑफ इंग्लैंड, नागरिक उड्डयन, विद्युत, दूर-संचार, रेल और मोटर-बस परिवहन, जलमार्गों और गैस आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण स्वयं में एक साध्य नहीं है, किन्तु इसके द्वारा कुछ उद्देश्यों को प्राप्त होनी है। अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण आवश्यक है, क्योंकि इससे सरकार को उद्योगपतियों द्वारा सरकार पर नियन्त्रण बनाए रखने में मुक्ति मिल जाती है।¹⁹ परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का लगभग 20 प्रतिशत सार्वजनिक नियन्त्रण में आ गया। इसके अतिरिक्त रोटी और दूध के व्यवसाय को आर्थिक सहायता दी गई। आवास योजनाओं, वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मजदूर दल की महानतम सफलताओं में से एक है।²⁰

इस शताब्दी के लगभग सम्पूर्ण छठे दशक तथा 1974 के प्रारम्भ से हेरॉल्ड विल्सन (Herold-Wilson) के नेतृत्व में लेबर दल की सरकार का फिर प्रभुत्व स्थापित हुआ। विल्सन सरकार ने इस समाजवादी कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।

← ने. डे. वि. वि. 21. 21

स्कैनेडेवियन राज्यों में लोकतान्त्रिक सहकारी समाजवाद

स्कैनेडेवियन राज्यों (नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क) में लोकतान्त्रिक समाजवाद की विशेष भूमिका रही है वे छोटे-छोटे राज्य कई राजनीतिक-आर्थिक सुधारों की प्रयोगशाला रहे हैं।²¹ विशेषतः इनके लोकतान्त्रिक वातावरण में कई समाजवादी सुधारों का विकास हुआ है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही स्कैनेडेवियन राज्यों में मजदूर आन्दोलनों ने काफी गति और शक्ति का परिचय दिया है। इन सभी राज्यों में समाजवादी दलों ने सत्ता प्राप्त की और अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का सफल प्रयत्न किया है। 1935 में स्वीडन तथा 1945 में नार्वे में समाजवादी दल सत्तालब्ध हुए। इन समाजवादी दलों ने जो सुधार किये या जो समाजवादी नीतियाँ अपनाईं, उनका लोकतान्त्रिक समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्कैनेडेवियन समाजवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

प्रथम, समस्त अर्थ-व्यवस्था पर राज्य का नियन्त्रण नहीं है। जित-जित क्षेत्रों में राज्य के नियन्त्रण का विस्तार किया है वह शर्तः शर्तः हुआ है।

द्वितीय, अर्थ-व्यवस्था का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के लिए छोड़ गया है। वहाँ यह माना जाता है कि जन-कल्याण और कुशलता के लिए सार्वजनिक और

18. Attlee, C.R., As It Happened, pp. 162-63.

19. Attlee, C.R., As It Happened, pp. 163.

20. आर्चीवार्डन्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 626.

21. Albjerg and Albjerg, Europe from 1914 to the Present, p. 411.

निजी क्षेत्र में सहभावपूर्ण स्वर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार स्कैंडेवियन राज्यों की ग्रथ-व्यवस्था प्रत्येक दृष्टि से सन्तुलित है।

तृतीय स्कैंडेवियन समाजवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ का सहकारी समाजवाद है। इन राज्यों की ग्रथ व्यवस्था में सहकारी सत्याग्रह विशेषतः उपभोक्ता सहकारिता का विशेष योगदान है।

चतुर्थ इन राज्यों में राशन प्रणाली (Rationing System) बहुत ही कुशल है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्वीडन में प्रत्येक व्यक्ति को एक कमीज और एक शूट प्रनिवप मिलता था।²² राज्य द्वारा कितरण व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।

इस प्रगति का ग्रथ स्कैंडेवियन राज्यों का ग्रथिक ग्रथ की है जो अत्यन्त बुद्धिमान एवं कुशल हैं। ये सुधार चाहते हैं क्रांति नहीं।

इजराइल की समाजवादी व्यवस्था²³

इजराइल की नैकतात्रिक समाजवादी व्यवस्था सम्भवतः सर्वाधिक प्रगतिशील एवं आकर्षित है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि इजराइल की समाजवादी व्यवस्था साम्यवादी सिद्धांत से भी कई क्रम आगे है। इजराइल में इस समय प्रचलित व्यवस्था कोई नवीन विकास नहीं है। यह सदियों का विकास का परिणाम है। यह व्यवस्था यहूदी जाति की परम्परा का अभिन्न अंग है।

इजराइल में लेबर पार्टी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति है। सबसे शक्तिशाली ग्रथिक सत्या इजराइल ग्रथिक सघ (General Federation of Israel Labour) तथा लेबर पार्टी दोनों मिलकर इजराइल को ग्रथिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में इस उद्देश्य की प्राप्ति सामान्यतः हो चुकी है औद्योगिक क्षेत्र में इस लक्ष्य की उपलब्धि अभी शेष है।

इजराइल का आधुनिक समाजवादी विकास उसी समय में प्रारम्भ हो गया था जब फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का संरक्षण था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में रूस और रूमनिया से आगे हुए यहूदियों ने छोटे छोटे कृषि फार्म का निर्माण किया। बीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ में पूर्वी यूरोप में कुछ बुद्धिजीवी यहूदियों का भी आगमन हुआ। ये समाजवादी थे जो बुद्धिजीवी होते हुए भी ग्रथ की महत्ता समझते थे तथा सम्पत्ति के सामाजिक स्वामित्व में विश्वास करते थे जो यहूदी परम्परा के पूर्ण अनुसंधान थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले गतिशील क्षेत्र में एक दा सहकारी सामूहिक ग्राम (Collective Settlements) की स्थापना हुई। बाद में इनमें वृद्धि हो गई। इन सहकारी सामूहिक ग्रामों का स्वामित्व समाजिक व्यवस्था

²² Ibid p 735

²³ In this connection see Israel by Norman Bentwich Chapter 8 The Social Order

या समाज का था। यहूदी भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व में सामान्यतः विश्वास नहीं करते। कृषि सहकारी सामूहिक ग्रामों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम, छोटे-छोटे कृषकों के सहकारी ग्राम जहाँ प्रत्येक परिवार अपनी भूमि पर स्वयं श्रम करता तथा उससे पारिवारिक आय प्राप्त करता। भाड़ों पर श्रमिकों को लगाने पर प्रतिबन्ध था। केवल कृषि-उत्पादन, विक्रय आदि सहकारिता पर आधारित थी।

दूसरी श्रेणी में वे समूह आते हैं जिन्हें किबुट्ज़ (Kibbutz) कहा जाता है। इस व्यवस्था में सम्पूर्ण ग्राम को एक ही इकाई माना जाता है, जहाँ किसी की निजी सम्पत्ति नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति समानरूप से भागदार है। बच्चों की देख-रेख समाज करता है। व्यक्ति पूरे समाज के लिए कार्य करता है तथा इस व्यवस्था का संचालन ग्राम-सभा (Assembly of the Community) करती है। यह व्यवस्था इस सिद्धान्त पर आधारित है — कि-प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यतानुसार कार्य करे तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार मिले।

इजराइल की समाजवादी व्यवस्था में राज्य और विभिन्न समुदायों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का बड़ा अच्छा समन्वय किया गया है। इजराइली राज्य वास्तव में इन्हीं समुदायों का विस्तार है। इस व्यवस्था से इजराइल ने जो प्रगति एवं शक्ति संचय किया है वह आश्चर्यजनक है।

भारतीय समाजवाद

भारतवर्ष जैसे समाजवादी राज्य नहीं है किन्तु स्वाधीनता के उपरान्त जो संविधान का निर्माण किया गया उसमें ऐसे उद्देश्यों को स्वीकार किया गया है जो लोकतान्त्रिक समाजवाद ही हो सकता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत वास्तव में कल्याणकारी समाजवादी कार्यक्रम को स्पष्टतः मान्यता प्रदान की गई है। इन निर्देशक तत्वों में सभी व्यक्तियों को समुचित जीविका का अधिकार, अर्थ-व्यवस्था पर सामाजिक स्वामित्व एवं नियन्त्रण, सम्पत्ति संचय का विरोध, श्रमिकों के उत्थान, पिछड़े हुए वर्गों की प्रगति आदि को सम्मिलित किया गया है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वाधीनता से ही केन्द्र में सत्ताधारी रहा है, समाजवादी कार्यक्रम स्वीकार किया है। इस समाजवादी व्यवस्था की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं —

प्रथम, समाज के प्रत्येक आर्थिक साधनों पर राज्य का स्वामित्व है।

द्वितीय, राज्य के महत्त्व और व्यक्ति को गरिमा को स्वीकार किया गया है।

तृतीय, आर्थिक क्षेत्र में मिश्रित-अर्थ व्यवस्था (Mixed Economy) अपनायी गई है। महत्त्वपूर्ण उद्योगों, आर्थिक गतिविधियों, एवं सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया है। निजी क्षेत्र के लिए भी व्यापक क्षेत्र छोड़ा गया है। किन्तु निजी क्षेत्र को नियन्त्रणहीन नहीं छोड़ा गया है।

आलोचक है, क्योंकि इस व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर थोड़े से व्यक्तियों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। पूंजीवादी व्यवस्था से अभिन्न व्यक्तियों में धन-संचय, एकाधिकार, लाभ, स्पर्धा आदि को प्रोत्साहन देनी है। लोकतान्त्रिक समाजवाद पूंजीवादी शोषण, उससे सम्बन्धित अन्य बुराइयों को उन्मूलन करने का कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत आर्थिक साधनों पर सामाजिक नियन्त्रण तथा उनके न्यायोचित वितरण को पूर्णतः स्वीकार किया जाता है।²⁴

व्यक्ति और समाज का सावयव सम्बन्ध

समष्टिवादी मनुष्यों और समाज के सम्बन्धों के विषय में अवयवी सिद्धान्त के समर्थक हैं। उनके अनुसार समाज मनुष्य के लिये स्वाभाविक है। शारीरिक रचना और कार्य प्रणाली की ही भाँति समाज के विभिन्न अंगों का कल्याण परस्पर सहयोग पर निर्भर करता है। व्यक्ति और समाज के दिन में कोई अन्तर नहीं होता। व्यक्ति का सुख समाज की समृद्धि और सम्पन्नता में है तथा सुखी और प्रगतिशील व्यक्ति समाज के पूर्ण विकास में सहायक होता है।

लोकतान्त्रिक समष्टिवाद और स्वतन्त्रता ।

व्यक्तिवादी और पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्ति की अधिकतम स्वतन्त्रता पर आधारित है। लोकतान्त्रिक समष्टिवादी इस स्वतन्त्रता को वास्तविक नहीं मानते। यह तथाकथित स्वतन्त्रता है। प्रतियोगी समाज में केवल सबल की स्वतन्त्रता ही सुरक्षित रह सकती है। इन तथाकथित स्वतन्त्रता से बहुमत्तक लोग शक्ति और साधन सम्पन्न मुक़्ठीभर लोगों के परतन्त्र हो जाते हैं। इस व्यक्तिवादी, पूंजीवादी स्वतन्त्र समाज में भारी बहुमत अपनी आवश्यकताओं को वस्तुएँ भी उपलब्ध नहीं कर सकता, वे दरिद्रता के भार से दबे रहते हैं। या, यह कहना उपर्युक्त होगा कि व्यक्ति व्यक्तिवादी और पूंजीवादी जूझा जीवन भर अपने कंधों पर लादे रहता है जिसमें मुक्ति इस तथाकथित स्वतन्त्र समाज में मिलना मुश्किल है। इस दशा या स्थिति को स्वतन्त्रता कहना अन्याय और उपहास दोनों ही होगा।

लोकतान्त्रिक समष्टिवादियों का स्वतन्त्रता सिद्धान्त व्यापक और सकारात्मक है। वास्तविक और व्यावहारिक स्वतन्त्रता समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत ही सम्भव है। स्वतन्त्रता का तात्पर्य केवल बन्धनों का निराकरण ही नहीं है। राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल प्रधुरी और एकपक्षीय है। जब तक मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त नहीं होता, तब तक स्वतन्त्रता का बोध महत्त्व नहीं है। वास्तविक स्वतन्त्रता निषेधात्मक और सकारात्मक राजनीतिक और आर्थिक सभी है। इन उपलब्धियों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में ही मनुष्य का चतुर्मुखी विकास हो सकता है।

24. पूंजीवादी व्यवस्था के दोष और समाजवाद के लिये पूर्व अध्याय देखिये।

लोकतांत्रिक समाजवाद और राज्य (5)

अन्य समाजवादी सम्प्रदायों का भी लोकतांत्रिक समाजवाद में भाग राज्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहता है। कन्सांगारा कायक्रमा का नागू करन का मुख्य शक्ति राजकीय सम्बन्ध—राष्ट्रीय प्रांतीय और स्थानीय सम्बन्धों आदि—पर रहता है। राज्य द्वारा समाजवादी नीतियों का निर्धारण एवं उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। ऐसा कि वास्तव में सिद्धांत है कि यदि किसी भी प्रकार की समाजवादी व्यवस्था की कल्पना की जाती है तो वह राज्य समाजवाद ही हो सकती है।²⁵

सामाजिक न्याय में भाग लेना है कि जीवन का उद्देश्य जाति रहना नहीं, अर्थात् जीवन जीना है। यह मनुष्य के श्रेष्ठतम निराम की अभिव्यक्ति है। लोकतांत्रिक समाजवाद में यह उद्देश्य राज्य का है। राज्य बंधन अपना शक्ति के लिए जीवित नहीं रहना जिसका अर्थ उनका समस्त सदस्या की या कुछ सदस्या का जवन रहना है। अतः उनका जीवन का उद्देश्य है कि उनका समस्त वंश संभाल सकें जा सकें योग्य है।²⁶ लोकतांत्रिक समाजवाद में राज्य का व्यापक कार्य करने पड़ता है उचित विभिन्न प्रकार के समाजवादी कार्यों की योजना का जाता है। उस सम्बन्ध में राज्य के कार्यों का निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है—

प्रथम सामाजिक न्याय में वृत्त में महत्त्वपूर्ण कार्यों का राज्य स्वयं करता है। वही उच्चो उच्चो तथा महत्त्वपूर्ण सेवाओं का संयोजन किया जाता है।

द्वितीय में उद्योग एवं सेवाएँ जिन्हें निजी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है उन पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण रहता है। निजी क्षेत्र में सम्बन्धित कार्यों का निष्पादन, नीति निर्धारण व्यापक निर्देश आदि सभी जानने द्वारा ही दिये जाते हैं।

(5) राज्य के इतने व्यापक कार्य एवं अधिकार का तात्पर्य यह नहीं कि राज्य सर्वसत्ताधारी बन जाय। यह सब जन-हित में तथा जनतन्त्रिक माध्याम द्वारा ही किया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में राज्य और व्यक्ति के महत्त्व का समुचित समन्वय रहता है। भागनाय सविधान की प्रस्तावना में राज्य की प्रतिष्ठा तथा व्यक्ति की गरिमा दोनों की ही बात कही गई है। ऐसा ही विचार राज्य के विषय में लोकतांत्रिक समाजवाद के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता है। यह मध्य दिव्य स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में न तो राज्य कभी माध्य बन सकता है और न व्यक्ति शक्ति। इस मान्यता तक राज्य का अधिकार स्वीकार्य बनाया जाता है उसका उद्देश्य व्यक्ति का हित है न कि केवल राज्य को शक्ति-मत्ता सम्पन्न करना है। इसी प्रकार जब व्यक्ति का विकास भी न हो तो निश्चित किया जाता है उनका तात्पर्य व्यक्ति की सामाजिक हित की दृष्टि में देखना है। उचित सामाजिकता में ही व्यक्ति-व हित निश्चित है।

²⁵ Barker, Ernest., Political Thought in England, p 203

²⁶ उद्धृत, जॉर्ज एडवर्ड राउस, लोकतांत्रिक सिद्धान्त—प्रवर्धना, पृ 49

राज्य के अधिकारों से सम्बन्धित एक विचार और महत्त्वपूर्ण है। लोकतान्त्रिक समाजवाद का अर्थ केन्द्रीकरण नहीं है। राज्य अपने अधिकारों और बायों को प्रान्तों और स्थानीय सस्थाओं में भी विभाजित करता है। इन सभी स्तरों पर सस्थाएँ लोकतान्त्रिक हो तथा उन्हें राज्य कार्यों में समुचित रूप से भागीदार होना चाहिए। बार्नर्ड शॉ (Bernard Shaw) ने लिखा है—

“ कोई भी प्रजातन्त्रवादी राय उस समय तक प्रजातान्त्रिक समाजवादी राज्य नहीं बन सकता जब तक उसकी जनसंख्या के प्रत्येक केन्द्र में कोई ऐसा स्थानीय शासकीय निकाय न हो जिसका संगठन उतना ही प्रजातान्त्रिक हो जितना केन्द्रीय ससद का है।”²⁷

लोकतान्त्रिक समाजवाद और जन समुदाय 7)

लोकतान्त्रिक समाजवाद राज्य-समाजवाद है जिसमें राज्य की भूमिका को विशेषतः स्वीकार किया जाता है। किन्तु यह वह व्यवस्था नहीं है जिसमें राज्य आदेश देता रहे तथा जनता उनको भूक या भेड़-चाल के रूप में स्वीकार करती रहे। लोकतान्त्रिक समाजवाद में साधारण जनता की सचेतता, सक्रियता, सहयोग तथा सक्रियता अति आवश्यक है। इसी पक्ष का सबसे अधिक महत्त्व है। तभी तो समाजवाद जनता का तथा जनता के लिए हो सकता है। एक लोकतन्त्र व्यवस्था के अन्तर्गत समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जनता का प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित रहना एक आवश्यक दशा है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद का उद्देश्य : कल्याणकारी राज्य की स्थापना - (3)

लोकतान्त्रिक समाजवाद स्वयं में कोई साध्य नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था एवं कार्यक्रम है जिसमें मनुष्य के बहुमुखी विकास को सम्भव बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य जनहित है। जनहित का तात्पर्य केवल उसकी आर्थिक प्रगति से ही नहीं है, इसके अन्तर्गत उसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पक्ष सभी कुछ आ जाता है। अन्य शब्दों में यह कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है।

इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाजवादी स्टेफर्ड क्रिप्स (Stafford Cripps) ने समाजवाद के तीन उद्देश्यों को प्राथमिकता दी है, ये हैं—स्वतन्त्रता, शान्ति, और आर्थिक साधनों का न्यायोचित वितरण।²⁸ इसका तात्पर्य लोकतान्त्रिक समाजवाद सामाजिक सेवाओं का लक्ष्य है जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता और समता को सर्वाङ्गीण पूर्णता प्रदान करता है।

व्यक्तिवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति भौतिक शक्तियों के भार से कुचल जाता है। समाजवाद व्यक्ति को भौतिक चिन्ताओं के भार से मुक्त कर देना चाहता है ताकि वह अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत कर सके तथा स्वतन्त्रतापूर्वक

27. उद्धृत, जोड., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त—प्रवेशिका, पृ. 54.

28. Cripps, Stafford, Why This Socialism, p. 15.

व्यक्तित्व का विकास कर सके। "जीवन का उद्देश्य केवल जीवन का चिरस्थायीकरण ही नहीं है परन्तु इससे अधिक है, उत्कृष्ट जीवन केवल जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। यह सम्पत्ता का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को अस्तित्व के सर्प को नितान्त चिन्ताओं से विमोचित करे और उच्चतम गुण-सम्पन्न जीवन व्यतीत करने की क्षमता प्रदान कर सके।" 29 जोड़ ने लिखा है—

"यद्यपि हम यह मान लेते हैं कि सन्-जीवन अज्ञात आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने की हमारी योग्यता पर निर्भर करता है और इस बात पर भी कि हम उन आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति के लिये सतन् रूप से प्रयत्नशील हैं। सत्य का शोध सत्य के लिये ही करना, सुन्दर वस्तुओं का उनके सौन्दर्य के लिये निर्माण करना, ठीक काम करना, इसलिये कि वह ठीक है, ये सब बानों शारीरिक और मानसिक ससृष्टि के एक निश्चिन्त स्तर, सचि के विकास और परिष्कृत शिष्टाचार सहित सन् जीवन सत्य हैं।" 30

किन्तु इस चतुर्मुखी विकास के लिये आवश्यक ज्ञान और वित्तीय क्षमता भी आवश्यकता पड़ती है। यह सभी सम्भव है जब मनुष्य नितान्त अस्तित्व के लिये किये जाने वाले सर्प का अतिग्रहण कर सकता है। इस क्षमता में वृद्धि तथा आर्थिक चिन्ताओं से मुक्ति के लिये लोकतान्त्रिक समाजवाद एक महत्वपूर्ण विकल्प है।

लोकतन्त्र और समाजवाद एक दूसरे के पूरक हैं

लोकतन्त्र की उपलब्धि से राजनीतिक स्वतंत्रता और ममानता आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इसे वास्तविक लोकतन्त्र नहीं कह सकते। यद्यपि सार्वतान्त्रिक सत्ताओं की स्थापना तथा अधिकारों को मान्यता देना भी अधिक महत्वपूर्ण है, लोकतन्त्र की यही तन् सीमा रखना तथा बिना आर्थिक पक्ष के यह सब अधूरा है। एक निर्धन, भूखे व्यक्ति के लिए लोकतान्त्रिक सत्ताओं तथा मान्यताओं का कोई मूल्य नहीं होता। वह अपने अधिकारों का आर्थिक चिन्ताओं के मध्य संशुभयोग कर ही नहीं सकता। इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को मजबूत किया जाय। यह समाजवाद के द्वारा सम्भव है। समाजवाद लोकतन्त्र के पूर्ण एवं समुचित विकास के लिये आवश्यक है। दूसरी ओर समाजवाद का महत्व शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक साधनों में ही निहित है, ताकि लोकतान्त्रिक मूल्या में अभिवृद्धि हो सके। इस प्रकार लोकतन्त्र और समाजवाद एक दूसरे के पूरक हैं।

लोकतान्त्रिक समाजवादी अर्थ-व्यवस्था. (12)

आर्थिक सिद्धान्तों के विषय में लोकतान्त्रिक समाजवादियों के अलग-अलग

29 जोड़, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका पृ. 48-9

30 पूर्व संदर्भ, पृ. 49

विचार है। कुछ समष्टिवादी उग्र विचारको पर मार्क्सवाद का अधिक प्रभाव है। वे पूँजीवादी व्यवस्था की आलोचना के लिए मार्क्सवादो शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत अधिकतर राज्य-समाजवादी व्यक्तिवाद और पूँजीवाद के विरुद्ध हैं, लेकिन इनके विषय में वे मार्क्स के विवेचन को स्वीकार नहीं करते।

अधिकतर समाजवादो मार्क्स के श्रम-सिद्धान्त और मूल्य सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। उत्पादन किसी एक वर्ग विशेष द्वारा नहीं होता बल्कि उसमें किसी न किसी रूप में पूरे समाज का योगदान रहता है। किन्तु वे इस बात को भी स्वीकार नहीं करते कि पूँजीपति को पूँजी लगाने के कारण पूरे लाभ को हड़प लेने का अधिकार है।

लोकतांत्रिक समाजवादी आर्थिक क्षेत्र में श्रमिक और पूँजीपतियों के बीच सघर्ष को भी स्वीकार नहीं करते। यह सघर्ष श्रमिक और भालिकों के बीच नहीं, बल्कि समाज और उन कतिपय लोगों के बीच है जो सामाजिक हित को ध्यान में न रखकर स्वयं धनी होने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं और ये ही लोग राज्य पर अपना अधिकार बनाये रखना चाहते हैं।

समाजवादी, पूँजीवादी व्यवस्था का प्रमुख दोष यह मानते हैं कि इसमें थोड़े से लोग कार्य-विहीन और सेवा-विहीन सम्पत्ति के द्वारा धन के अधिकांश भाग पर अपना आधिपत्य करते हैं। बिना कार्य किये हुए तथा सामाजिक सेवा की श्रवहेलना कर जो सम्पत्ति का सचय होता है उससे समाज में द्वेष और वैमनस्य फैलता है। इस प्रकार व्यक्तिवाद और पूँजीवाद के दोषों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक समाजवादी निम्नलिखित आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करते हैं—

- (i) प्रत्येक व्यक्ति को वह चाहे हाथ या मस्तिष्क का कार्य करता हो परिश्रम का पूरा प्रतिफल मिलना चाहिये।
- (ii) समाज में धन का न्यायपूर्ण वितरण हो जिससे साधारण व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व का विकास कर सुख एवं सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत कर सके।
- (iii) उत्पादन, वितरण और वित्तिय के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व हो, ताकि भूमि और औद्योगिक पूँजी को किसी विशेष हित के स्वामित्व से मुक्त करा कर उसका पूर्ण समाज कल्याण के लिए प्रयोग किया जा सके।

आर्थिक साधनों के स्वामित्व के विषय में इन समाजवादियों में मतभेद है। कुछ राज्य के स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं; विशेषतः बैंक, खानें, इस्पात उद्योग, परिवहन के साधन आदि का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। अन्य आर्थिक क्षेत्रों में राज्य-नियन्त्रण में बढ़ा कर व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए छोड़ देना चाहिए।

कुछ लोकतांत्रिक समष्टिवादी रुझान तथा अन्य साम्यवादी राज्यों में राज्य-स्वामित्व को देखकर भयभीत हैं। जहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई है। वे राष्ट्रीयकरण के स्थान पर सामाजिककरण (Social Control) का समर्थन करते हैं। राज्य के स्थान पर यह कार्य सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाने की व्यवस्था नाबे, स्वीडन डेनमार्क आदि देशों में बड़ी लोकप्रिय है।

लोकतांत्रिक समाजवाद और साधन ॥

लोकतांत्रिक समाजवाद उदार प्रजातन्त्र की पूर्ण कल्पना करता है। लोकतन्त्र व्यवस्था में अतिवादी साधनों का कोई महत्त्व नहीं है। लोकतन्त्र और हिंसा एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवादी विकासवादी, लोक-तांत्रिक, सवैधानिक, शान्तिपूर्ण साधनों की ही मान्यता देते हैं।³¹ एडमंड बर्न्सटाइन ने 1909 में प्रकाशित अपनी पुस्तक—*Evolutionary Socialism*—में लिखा है—

“मुझे समाजवादी आन्दोलन में विश्वास है और मजदूरों की भावी प्रगति में विश्वास है। मजदूरों को अपने उद्धार के लिए एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आज का समाज, जिसमें अल्पसंख्यक व्यापारियों तथा ग-स्वामियों का आधिपत्य है, वास्तविक लोकतन्त्र का रूप धारण कर सके और उसके प्रत्येक विभाग का संचालन इस ढंग से हो कि काम करने वालों और सृजन करने वालों के हितों की रक्षा हो सके।”³²

रेमजे मेकडानेल्ड, जो ब्रिटेन के प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री थे, ने 1921 में लोकतांत्रिक समाजवाद के साधनों की व्याख्या करते हुए लिखा है—

“जिम बात का हमें प्रयत्न करना है वह यह है कि हम बिना विवेकपूर्ण योजना और उद्देश्य तथा व्यावहारिक ज्ञान के निर्देशन के बिना आगे न बढ़ें। समाजवादी यह दावा कर सकता है कि उसने यह सतर्कता काम में ली है।”³³

जोड (C E M Joad) ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं—

“समाजवादियों का कहना है कि समाज में परिवर्तन क्रमशः ही हो सकता है, और हर परिवर्तन समाज की पूर्ववर्ती स्वभाव की दशाओं के अनुकूल होना चाहिये। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम वर्तमान अवस्था से ही अपनी कार्य आरम्भ करें, और वर्तमान स्थिति के अनुसार ही भविष्य की दिशा, द्रुतता तथा उठाये जाने वाले चरण निर्धारित करें।”³⁴

³¹ See Merkl, Peter H., *Political Continuity and Change*, p 141

³² उद्धृत, नेटिल, राजनीतिक चिन्तन का इतिहास, पृ० 407.

³³ Ramsay MacDonald, J., *Socialism Critical and Constructive*; p 312

³⁴ जोड, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त-प्रवेशिका, पृ 52-53

पीटर मर्कल (Peter H. Merkl) ने अपनी पुस्तक—Political Continuity and Change, 1967—में लोकतान्त्रिक समाजवाद के विकासवादी साधनों के दो पक्ष बतलाए हैं। प्रथम, श्रमिकों को श्रम संगठनों का निर्माण करना चाहिए जिनके माध्यम से वे पूँजीपतियों से अछड़े वेतन, काम करने के लिए कम भ्रष्टाचार तथा उत्तम कार्य-परिस्थितियों के विषय में सामूहिक सौदा कर सकें। द्वितीय, समाजवादी चुनावों द्वारा सतत में बहुमत प्राप्त कर स्वयं ही सरकार का संगठन कर समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करें। सूक्ष्म में लोकतान्त्रिक समाजवादी साधनों की निम्न-लिखित व्याख्या की जा सकती है:—

(i) लोकतान्त्रिक समाजवादी उस मार्क्सवादी धारणा का खंडन करते हैं कि समाज में वर्ग-सघर्ष अवश्यम्भावी है और केवल मजदूर वर्ग की सहायता से समाजवाद की स्थापना की जायगी। लोकतान्त्रिक समाजवादी सभी वर्गों और बहुमत को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उनके विचार में एक वर्ग का उत्थान और दूसरे वर्ग का उन्मूलन ठीक नहीं।

(ii) इसका तात्पर्य यह हुआ कि लोकतान्त्रिक समाजवादी हिंसा या शक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करना चाहते। हिंसात्मक क्रान्ति के द्वारा परिवर्तन स्थायी नहीं होते। इसके प्रतिरिक्त यदि एक बार आतंकवादी मार्ग अपना लिया जाता है तो हिंसा के आधार पर प्राप्त व्यवस्था का उन्मूलन करना असम्भव होगा। यह समाजवादी न होकर कोई अधिनायकवादी व्यवस्था होगी।

(iii) लोकतान्त्रिक समाजवादी विकसनवादी हैं। वे समाज को एक अवयव की तरह मानते हैं। तदनुसार अवयव की तरह ही समाज का धीरे-धीरे विकास होता है। समाज में अन्तर्गत बदलने की क्षमता होती है।

(iv) इन समाजवादियों ने प्रजातान्त्रिक एवं संवैधानिक साधनों का मर्मयन किया है। इनका विश्वास था कि समाजवाद में विश्वास रखने वालों का एक राजनीतिक दल स्थापित किया जाय। यह दल चुनावों में भाग ले और बहुमत को अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करे। बहुमत प्राप्त होने के बाद सरकारी मशीन का समाजवादी व्यवस्था लाने के लिए प्रयोग किया जाय।

(v) लोकतान्त्रिक समाजवाद रचनात्मक समाजवाद (Constructive Socialism) है। संवैधानिक साधनों के माध्यम से समाज में ऐसा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाय जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो।

लोकतान्त्रिक समाजवाद के विषय में सतर्कता (2)

लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना एवं प्रगति के विषय में कुछ सतर्कता आवश्यक है। लोकतान्त्रिक समाजवाद का उद्देश्य लोकतन्त्र के आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ बनाना है। लोकतन्त्र में राजनीति स्वतन्त्रता एवं समानता की उपलब्धि तो हो

सकती है, किन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता एव समानता के बिना यह सत्र व्यर्थ है। यह समाजवादी कार्यक्रम से ही सम्भव है। इसलिए यहाँ समाजवाद का ध्येय लोकतान्त्रिक शक्तियाँ भी वृद्धि करना है। यह राज्य के माध्यम से ही सम्भव है। इसलिए यह किसी भीमात्सक समग्रता की ओर अग्रसर करेगा। यही पर सनकता की आवश्यकता है। समाजवादी कार्यक्रम से राज्य अधिनायकवादी न हो जाय अन्यथा न तो लोकतन्त्र ही रहेगा न समाजवाद। राज्य के कार्या क्षेत्र में केवल इतनी ही वृद्धि होनी चाहिए जितनी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक हो तथा जिसे मनुष्यों के अधिकारों का हनन नहाना हो। यह लोकतन्त्र तथा समाजवाद के समुचित समन्वय से ही सम्भव है।

जिन राज्यों में नास्ति द्वारा राजनीतिक परिवर्तन हुए है, या जहाँ अधिनायकवादी व्यवस्था "हले से ही विद्यमान है वहाँ लोकतान्त्रिक समाजवाद का पक्षपात सम्भव है। ऐसे राज्यों में समाजवादी कार्यक्रम की जनवल्याण के साधन के रूप में स्वीकार तो किया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोकतान्त्रिक शक्तियों में वृद्धि करना नहीं होता। साम्यवादी राज्य, विशेषतः रूस और चीन जो अभी समाजवादी स्थिति (जिन मानव ने सत्रमण-युग कहा था) से गुजर रहे हैं, जन-रत्याण के लिए राय कर रहे हैं किन्तु जो वास्तव में लोकतान्त्रिक सिद्धान्त या मूल्य हैं व वहाँ दृष्टि-गोचर नहीं होने। साम्यवादी राज्य अपने लिये लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी दोनों ही कहते हैं, पर व समाजवादी तो हैं, लोकतान्त्रिक नहीं।

इस सन्दर्भ में अफीकी राज्यों तथा अशिया के वे राज्य जहाँ सैनिक प्राप्ति या हो चुकी हैं, आदि के उदाहरण दिये जा सकते हैं। इन सभी राज्यों में किसी न किसी प्रकार के समाजवादी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का दावा किया जाता है, जिसे उद्देश्य सामान्य जनता की थोड़ी बहुत सुख सुविधा में वृद्धि करना तो रहा है, लोकतन्त्र को स्थापित करना नहीं। समाजवाद के नाम पर वहाँ राज्य की शक्तियाँ में जो वृद्धि हुई है, उसका उद्देश्य सैनिक तानाशाही की शक्ति को गृह्य कर विरोधियों को कुचलना है। मिश्र, लीबिया, सूडान, कांगो, घाना नाइजीरिया, तन्जानिया, उगान्डा, सीरिया, ईराक आदि सभी भी लोकतान्त्रिक समाजवाद के अन्तर्गत नहीं आ सकते। वास्तव में वे न तो लोकतान्त्रिक हैं और न समाजवादी। इन राज्यों में गृह्य तानाशाही तथा विरूत समाजवाद जैसी ही कोई व्यवस्था हो सकती है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद का मूल्यांकन

1) सर्वव्यापी राज्य की स्थापना

लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य को अधिकाधिक कार्य करने होंगे। उत्पादन और वितरण के समस्त साधन राज्य के नियन्त्रण में रहेंगे। इसलिए राज्य का क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक हो जायगा। समाज में स्वायत्तीय स्वशासन से राष्ट्रीय स्तर तक समस्त कार्यों का या तो राष्ट्रीयकरण होगा या उन

ऊपर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण होगा। अन्तिम रूप में, मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन राज्य के नियन्त्रण के अन्तर्गत होगा।

आर्थिक व्यवस्था पर राज्य नियंत्रण का परिणाम नौकरशाही के अधिनारी में वृद्धि होगी। राज्य कर्मचारियों में वृद्धि के साथ लान कौताशाही, अकर्मण्यता और अप्रत्याचार में भी वृद्धि होगी। समाजवादी व्यवस्था में जो भी लाभ मिलने की आशा है, वे बहुत कुछ नौकरशाही व्यवस्था में समाप्त हो जायेंगे। इसमें एक सम्भावना और हो सकती है। राज्यों के कार्यों में वृद्धि होने में प्रणामन इस बीच की उठाने में सम्मर्थ रहे।

समाज में व्यक्तिवाद और पूँजीवाद के जिन दुर्गुणा का उन्मूलन करने के लिए, जिस समष्टिवादी राज्य की स्थापना करना है, अन्तिम रूप में समष्टिवादी राज्य उन्ही दुर्गुणा का जन्म देगा या प्रोत्साहित करेगा। समष्टिवाद व्यक्तिगत-पूँजीवाद के म्यान पर राज्य-पूँजीवाद की स्थापना करेगा। इनके अन्तिम वर्ग के स्तर में कोई अन्तर नहीं आयेगा। उसे तो व्यक्ति या राज्य के मजदूर के रूप में कार्य करने रहना पड़ेगा। समष्टिवाद में प्रगति धीरे धीरे होगी, उत्पादन में कमी होगी तथा निश्चिन्ता में वृद्धि होगी।

मानव प्रवृत्ति के प्रतिबन्ध (2)

उत्पादन के समस्त माध्यमों पर राज्य-स्वामित्व के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत प्रोत्साहन की सम्भावना समाप्त हो जायगी। यदि व्यक्ति को अपने कार्य का कुछ लाभ या पुरस्कार नहीं मिलता तो वह अपनी प्रतिभा का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता और न दृष्टि एवं लगन से ही कार्य कर सकता है।

समष्टि धारण करने की इच्छा मनुष्य में स्वाभाविक एक मूल प्रवृत्ति है। वे व्यक्ति जो धन उपार्जन कर सकते हैं उन्हें प्रतिकूल भिन्नता ही चाहिए। जिन्हु दूसरी ओर वे व्यक्ति जिन्हें यदि यह विचार है कि राज्य की ओर से उन्हें काम और निर्वाह योग्य वेतन मिल जायगा तो वे आलसी, अनुत्तरदायी हो जायेंगे। उनमें नये प्रयोगों के प्रति न तो उत्साह और न जोशिम लेने की क्षमता या विराम हो सकता है।

शांतिपूर्ण साधनों की अनुपयुक्तता :

आलोचकों, जिनमें मार्क्सवादी प्रमुख है, का कहना है कि समाजवाद की स्थापना शांतिपूर्ण सर्वशान्तिक साधनों से नहीं की जा सकती। लौकिक समाजवादी समाजवाद के शोषों को समाप्त करना अशक्य है। जनतान्त्रिक व्यवस्था में पूँजीवाद के शोषों को समाप्त करना अशक्य है। जनतान्त्रिक व्यवस्था में पूँजीवादी व्यक्ति शासन-मशीन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में अपने व्यक्तियों का रखते हैं। प्रतिनिधि समाजवाद में अपने समर्थकों को अधिकधिक मर्यादा में पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। यह कार्य उनके लिए असम्भव नहीं है। धन द्वारा वे निर्णय लेने वाली सत्ताओं को अपने पक्ष में प्रभावित करते रहते हैं।

पूँजीपति रूपने विरोधी राजनीतिक दलों को भी नहीं पनपने दे गे। इस प्रकार पहली बात तो यह है कि समाजवादी दल सत्ता में आ ही नहीं सकता। दूसरे, यदि एक बार वह सत्ता में आ भी जाता है, तो यह गारन्टी नहीं है कि वह सदैव सत्ता में बना रहे और समाजवादी कार्यक्रमों को लागू कर सके। इंग्लैण्ड में दो तीन बार समाजवादी दल ने यदि सरकार बना भी ली है तो वहाँ समाजवाद की पूर्ण स्थापना नहीं हो पाई है।

स्वतन्त्रता एवं समानता का अर्थ १

समाजवाद व्यवस्था में राज्य द्वारा जनता में वृद्धि होगी। नियन्त्रण और हस्तक्षेप द्वारा मनुष्य की स्वतन्त्रता पर प्रहार होगा। व्यक्ति राज्य का दास बन जायेगा और समष्टिवाद एक गुलाम राज्य की नींव डालेगा।

समष्टिवाद प्राथिक एवं सामाजिक समानता को व्यापक रूप देना चाहता है। वह समानता को साकार करना चाहता है। कुछ आलोचक समष्टिवाद को इस प्रमुख उद्देश्य का अनुचित और अव्यावहारिक मानते हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक दृष्टि से मनुष्य समान नहीं हो सकते। मनुष्य शक्ति, बुद्धि आदि दृष्टि से असमान होते हैं। धनिक अर्थी योग्यता और परिश्रम के अनुसार कम या अधिक धन उपार्जन कर ले है। इस प्रकार प्राथिक क्षेत्र में समानता सम्भव नहीं है। जब योग्यता और परिश्रम से उपार्जित धन समानता लाद के लिए खीन कर दूसरों को दिया जाता है यह अनैतिक होगा। ऐसी समानता भी स्थायी नहीं होगी।

योगदान

लोकतान्त्रिक समाजवाद (विशेषतः इसमें सम्बन्धित समष्टिवाद) की साम्यवादी, व्यक्तिवादी आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचना हुई है। इस आलोचना में बहुत कुछ तथ्य है, किन्तु इतना सब कुछ होना ही नहीं लाकतान्त्रिक समाजवाद में गुणों का वास्तव्य है। परिणामस्वरूप यह समाजवादी सम्प्रदायों में सबसे अधिक महत्व द्रजित किए हुए हैं।

लोकतान्त्रिक समाजवाद अन्य समाजवादी विचारधाराओं से अधिक व्यावहारिक एवं स्थायी सिद्ध हुआ है। मिन्डोकलवाद, गिल्ड समाजवाद आदि कभी भी प्रभावशाली और सफल नहीं हो सके। ऐसी स्थिति में लोकतान्त्रिक समाजवाद ही सर्वाधिक उपयोगी प्रतीत लगता है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद मध्य-मार्गीय विचारधारा है। यह पूँजीवादी और सर्व-सत्ताधारी विचारधाराओं का सर्वोत्तम विरुद्ध है। लोकतान्त्रिक समाजवाद इन दोनों की दुरास्था और अतिवादिता को त्याग कर एक नई प्रणाली का प्रतिपादन करता है।

लोकतान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था लोकतन्त्र को पूर्ण बनाने का महत्तमपूरण माधन है। वैसे लोकतन्त्र में कई दोष हैं, लेकिन ये दोष समाजवाद महयोग से बहुत

कुछ दूर हो जाते हैं। यह लोकतन्त्र को स्याई और प्रभावशाली बनाने के लिए उत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। इसमें सन्देह नहीं कि लोकतन्त्र सर्वोत्तम प्रणाली है, समाजवादी कार्यक्रम इनके दोषों का उन्मूलन कर गुणों में अभिवृद्धि करता है।

लोकतान्त्रिक समाजवाद हिंसा, क्रान्ति, वर्ग-संघर्ष पर न होकर विनाशवादी, सर्वैधानिक साधनों पर आधारित है। ये साधन स्वयं में ही नैतिक हैं तथा मनुष्य के चतुर्मुखी विकास में ऐसे साधनों का सर्वश्रेष्ठ ही महत्त्व रहा है। फ़ान्तिपूर्ण साधनों से उपलब्ध लक्ष्य स्याई होते हैं।

आजकल विश्व में दो प्रकार की ही समाजवादी व्यवस्थाएँ प्रचलित हैं। प्रथम, अधिनायकवादी तथा सर्वसत्ताधारी समाजवाद जिसके अन्तर्गत साम्यवाद तथा कुछ अफ्रीकी राज्यों में प्रचलित समाजवादी व्यवस्था को ले सकते हैं। किन्तु इनमें साम्यवाद ही सबसे प्रमुख एवं प्रभावशाली है। द्वितीय, लोकतान्त्रिक समाजवाद, जिसका प्रचलन एवं प्रभाव लोकतान्त्रिक राज्यों में विशेषकर है। ये दोनों व्यवस्थाएँ विश्व में एक दूसरे का विकल्प बनने का प्रयत्न कर रही हैं।

पाठ्य-ग्रन्थ

1. कोकर, फ्रान्सिस., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन,
अध्याय 4, प्रजातान्त्रिक एवं विकासवादी समाजवादी
2. Ebenstein, W., Today's Isms,
Chapter IV, Democratic Socialism.
3. गेटिल, रेमण्ड गारफील्ड., राजनीतिक चिन्तन का इतिहास,
अध्याय 22, लोकतान्त्रिक समाजवाद का उदय
4. Hallowell, J. H., Main Currents in Modern Political
Thought,
Chapter 13, Socialism after Marx.
5. जोड, सी. ई. एम., आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त प्रवेशिका
अध्याय 3, समाजवाद: विशिष्टतः समष्टिवाद
से सम्बन्धित
6. Sabine, G. H., A History of Political Theory,
Chapter XXXI, Liberalism Modernized.
7. Stankiewicz, Political Thought Since World War II,
W. I. (Ed.), Part IV, Section I, Democratic Socialism

गांधीवाद का अध्ययन करने से पहले कुछ बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। सर्वप्रथम, क्या गांधीवाद, कोई 'वाद' है? इसका उत्तर 'हां' या 'ना' दोनों में ही हो सकता है। महात्मा गांधी हाथ, लॉक रूसो, मिल, हीगल, श्रोन आदि की भांति शास्त्रीय अर्थ में राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे। उन्होंने अध्ययन कक्ष या एकांत में बैठकर या किसी विश्व-विद्यालय को कुर्सी को सुशोभित कर अपने विचारों का प्रतिपादन नहीं किया। महात्मा गांधी एक कर्मयोगी तथा व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उनके सामने सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न भारत की स्वाधीनता का था। प्रब्रंजी साम्राज्य के विरुद्ध सघन चलाने की किस प्रणाली को अपनाया जाय? स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त देश की शासन प्रणाली का क्या स्वरूप हो? देश के समक्ष जो तमाम सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ थीं उनका क्या समाधान हो? अपने जीवन, भारतीय समाज तथा विश्व में जो भी समस्याएँ देखी, उन समस्याओं के सम्बन्ध में उनसे जो पूछा गया उस सम्बन्ध में गांधी जी ने अपने विचार व्यक्त किये। साथ ही साथ उन्होंने अपने विचारों को कार्यरूप देने का भी प्रयत्न किया जो विश्व के समक्ष आदर्श बन गये।

महात्मा गांधी ने कुछ पुस्तकें तथा काफी सख्या में लेख लिखे। नवजीवन प्रकाशन, हरिजन पत्रिका, यश इण्डिया, हिन्द स्वराज, आधुनिक मार्ग (Aryan Path) आदि जगभर उन्हीं के विचारों को प्रसारित करने के लिये सुरक्षित थे। इतना स्पष्ट होते हुए भी उन्होंने अपने विचारों को किसी 'वाद' का रूप नहीं दिया। इस सम्बन्ध में मार्च 1936 में सावली सेवा सघ में प्रवचन करते हुए गांधी जी ने कहा था—

“गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने वाद कोई सम्प्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं विन्ही नये सिद्धान्तों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैंने तो केवल अपने ढंग से आधार-भूत सच्चाइयों का अपने दिल की प्रति के जीवन एवं समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न किया है। मैंने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे सत्य यन्तिय नहीं हैं। मैं कल ही उन्हें परिष्कृत कर सकता हूँ। विश्व को मिथाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं

है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन हैं जितने कि पर्यंत के सिद्धर। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासम्भव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। आप इसे गांधीवाद न कहें इसमें कोई वाद नहीं है।”

गांधीवाद की स्पष्ट व्याख्या करना सम्भव नहीं है। महात्मा गांधी ने सम्भवतः सभी समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किये। उनके विचारों का क्षेत्र इतना व्यापक था कि उन्हें किसी एक वाद तक सीमित रचना सम्भव है। वे व्यक्तिवाद, प्रराज-कतावाद, बहुतावादी, समाजवादी सब कुछ थे। इसलिये गांधीवाद को किस वाद में सम्मिलित किया जाय या किस रूप में धरल गटा जाय, सम्भव नहीं है। गांधीवाद में कई विचारधाराओं का समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

गांधीवाद कभी भी एक क्रमबद्ध दर्शन नहीं बन पाया। गांधीजी के जीवन में कई उतार चढाव आये। कभी वे सत्याग्रह में, कभी जेल में, तथा कभी नाना प्रकार के सैधनिक सम्मेलनों में व्यस्त रहे। इन प्रकार गांधीजी को अपने विचारों को एक दारंनिर के रूप में व्यवस्थित करने का समय ही नहीं मिल सका।

गांधीजी ने अपने विचारों को न तो कभी पूर्ण माना और न उन्होंने उन्हें अन्तिम रूप दिया। उन्हें अपनी आत्मकथा लिखने में भी काफी हिचक थी। जिस चीज को वे सिद्धान्तरूप मानते थे, यदि वसा मानना छोड दें तब उन सिद्धान्तों का क्या होगा? यदि इन सिद्धान्तों में आये परिवर्तन करना पड़ा तो? 2 और वास्तव में वे अहिंसा तथा सत्याग्रह को एक विकसित विज्ञान मानते थे। 3 इन कारणों से गांधीजी किसी भी विषय में अन्तिम शब्द नहीं बहना चाहते थे। वे जीवन पर्यन्त सत्य का प्रयोग करते रहे। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि महात्मा गांधी के विचारों ने कोई निश्चितरूप ही नहीं लिया हो। सत्य तथा अहिंसा के सिद्धान्त प्रगतिशील होते हुए भी स्थायित्व ग्रहण कर चुके थे। ये ही गांधीवाद की जान थे। अपनी आत्मकथा की प्रस्तावना में गांधीजी ने लिखा है—

“अपने प्रयोगों के सम्बन्ध में मैं किसी तरह की सम्पूर्णता का दावा नहीं करता। जैसे विज्ञान-शास्त्री अपने प्रयोग अत्यन्त नियम, विचार सहित और सूक्ष्मतापूर्वक करता है, फिर भी उससे उत्पन्न हुए परिणामों को वह अन्तिम नहीं कहता, अथवा यह नहीं कहता कि यही सचे परिणाम है, इस सम्बन्ध में वह संशय नहीं तटस्थ रहता है, वैसे ही अपने प्रयोगों के विषय में मेरा भी मानना है। मैंने खूब आत्म निरीक्षण किया है, प्रत्येक भाष को जाना है, उसका विश्लेषण किया है, पर उससे पैदा हुए परिणाम सत्य के लिए अन्तिम ही है अथवा यही सही हैं, ऐसा दावा मैं कभी करना

1. Sitaramayya, B P., Gandhi and Gandhism, p. 26.

2. गांधी मो. क., सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ. 8. (प्रस्तावना)

3. Dhawan, G. N., The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, p 6

नहीं चाहता। हा, एक दावा जरूर करता हूँ कि मेरी नजरों में ये सही है और इस समय तो छाछिरी से लगते हैं।”⁴

गांधीजी के अनुयायियों, टीकाकारों ने उनके विचारों को अमबद्ध करने का प्रयत्न किया है। देश-विदेशों में उनके विचारों पर शोध ग्रन्थ लिखे गये। परिणाम-स्वरूप गांधीजी के विचारों ने एक वाद जैसा रूप ग्रहण कर लिया। आज गांधीवादी सिद्धान्तों का एक सप्रह सा बन गया है। उनके प्रत्येक अनुयायी अपने विचारों को गांधीवाद की कसौटी पर रखते हैं तथा समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान उनके विचारों में पाते हैं। गांधीवाद एक नैतिक मापदण्ड सा बन गया है। जीवन के प्रत्येक पहलू में हम क्या करना या नहीं करना चाहिए इस सम्बन्ध में गांधी जी के विचार मार्ग-दर्शन और कार्य-पद्धति का काम करते हैं। डॉ. पट्टाभि सीतारमय्या के शब्दों में गांधीवाद एक जीवन-शैली या जीवन दर्शन है जो एक नई दिशा की ओर सन्नेत करता है।⁵

प्रभाव एवं पूर्ववर्ती दर्शन

महात्मा गांधी ने स्वयं को एक मूल विचारक मानने का कभी भी दावा नहीं किया। सत्य अहिंसा के क्षेत्र में उन्होंने जो भी योगदान दिया वह एक प्रकार से प्राचीन परम्परा को ही आगे बढ़ाना था। उनके विचारों की व्यापकता और विभिन्नता को देखते हुए उनके विचार-स्रोत किसी एक देश या काल तक ही सीमित नहीं थे। उन्हें जहाँ जो भी अच्छा लगा, ग्रहण किया। इतना सब होते हुए भी उन पर भारत की परम्परा एवं मस्कृति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि गांधीवाद में भारतीयता के दर्शन होते हैं।

महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के जो प्रयोग किये उसकी परम्परा अनि प्राचीन है। भारत में सत्य और अहिंसा की जड़ें जितनी गहरी और मजबूत हैं शायद ही किसी अन्य देश में हों। गांधीजी के विचारों के स्रोत ऋग्वेद, जो प्राचीनतम ग्रन्थों में से एक है तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध हो सकते हैं। ऋग्वेद में वर्णाश्रम धर्म ने, जिसके अन्तर्गत शूद्र भी अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण बन सकता था, गांधीजी को प्रभावित किया। उपनिषदों में अहिंसा की महत्ता पर सदैव जोर दिया गया है। पतञ्जलि के योगशास्त्र में अहिंसा को कभी भी नकारात्मक या हिंसा का त्याग ही नहीं माना, बल्कि सरल मानवों के लिए सद्भावना प्रेरित करने वाला सत्त्व स्वीकार किया। उनका कथन था—

अहिंसा प्रतिष्ठाया ततस्त्रिषो वीरत्याग

यथाँरु जैसे ही अहिंसा पूर्णता को प्राप्त होती है अपने चारों ओर शत्रुता समाप्त हो जाती है।

4 गांधी, मो. क., सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ 5

5 Sitaramaya, B P. Ibid., p 35

21.]

सत्य और अहिंसा की परम्परा रामायण और महाभारत में भार भावकसित हुई। रामायण से गांधीजी का साक्षात्कार बचपन में ही हो गया था। उन्हें राम रथा स्तोत्र कंठस्थ था जिसका वे नियम प्रातः स्नान के बाद पाठ किया करते थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि "जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। मैं आज तुलसीदास की रामायण की भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ।"⁶

महाभारत को गांधीजी ने युद्ध ग्रन्थ नहीं माना है। उनके अनुसार महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने इस ग्रन्थ में युद्ध और हिंसा की निन्दा कर उसकी व्यर्थता पर जोर दिया है। युद्ध के पश्चात् विजेता में भी खानि एवं पश्चात्ताप की भावना प्रदर्शित होती है। साथ ही साथ महाभारत में प्रत्यक्ष रूप से भी अहिंसा का उपदेश मिलता है। धायल भीष्म पितामह को मृत्यु शय्या पर पड़े हुए कहते बतलाया गया है—

अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा परमं तप

अहिंसा परमं सत्यम्, ततो धर्मं प्रवर्तते

अर्थात् अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, सर्वोत्तम तप है, सबसे बड़ा सत्य है जिससे समस्त कर्तव्यों का उद्भव होता है।

महाभारत में विशेषतः गीता से गांधीजी को सर्वाधिक प्रेरण मिली। गीता के प्रति उनका दृष्टान्त प्रेम और श्रद्धा थी कि गीताजी के लगभग तेरह अध्याय उन्होंने कंठस्थ कर लिये थे। गीता के प्रभाव के विषय में गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि "मेरे लिए तो वह पुस्तक आचार की एक प्रौढ़ पथ-प्रदर्शिका बन गई। वह मेरा धार्मिक कोष हो गई.. उसके अपरिग्रह, समभाव वगैरह शब्दों ने मुझे पकड़ लिया.. दुस्ती शब्द का अर्थ गीताजी के अन्वय के फलस्वरूप विशेष रूप से समझ में आया। विद्यान शास्त्र के लिए आदर बख...अपरिग्रही होने में, समभावो होने में हेतु का, हृदय का परिवर्तन आवश्यक है, यह मुझे दीपक की भूति स्पष्ट दिखाई दिया।"⁷ गांधीजी ने स्वयं भागवत गीता की टीका लिखी थी उनकी गीता की व्याख्या नवीन प्रकार की है। वह गीता को अपने जीवन का 'आध्यात्मिक सन्दर्भ ग्रन्थ' (Spiritual Reference Book) मानते थे।⁸ वे जब कभी भी अपने लिए मानसिक उल्लभन या समस्याओं में पँसा पाते जब गीता अध्ययन से उन्हें सदैव सान्त्वना एवं समस्याओं का समाधान मिला। सत्य और अहिंसा ने बारे में गीता से उन्होंने बहुत कुछ सीखा।⁹

6. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ० 38-39.

7. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ० 329-30.

8. Gaudhi and Mahadev Desai, The Geeta According to Gandhi pp 122-123.

9. Kriplani, J B, Gandhi, His Life and Thought, p. 338.

जैन दर्शन में अहिंसा का प्रमुख स्थान है। अहिंसा के बिना जैन धर्म कुछ भी नहीं है। गांधीजी का परिवार वैष्णव था फिर भी जैन मुनियों के संस्कार में आता रहा। इससे अतिरिक्त जैन धर्म का प्रभाव जितना गुजरात में है भारत के अन्य भाग में नहीं। यही गांधीजी पैदा हुए तब जीवन के प्रारम्भिक वर्ष बिताये। इन प्रकार अहिंसा का गांधीजी के जीवन पर बचपन में ही प्रभाव पड़ा।

जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का महत्त्व है। इसके साथ-साथ इनका पवित्रता से प्राग्भ होकर प्रेम में अन्त होना है। बौद्ध अनुयायी विश्व की सभी प्रकार की पीड़ा एवं यातना का भार सहने की शपथ लेता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का अर्थ प्रेम तथा दूसरों को हानि न पहुँचाना है।

बौद्ध धर्म की शिक्षायों का सम्राट अशोक ने साकार किया। कलिंग युद्ध (सम्भवतः 262 ईसा के पूर्व) के बाद सम्राट अशोक हिंसा का त्याग करते हैं, इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध इतिहासकार वेल्स (H G Wells) लिखते हैं कि इतिहास में अशोक ही ऐसे एक सम्राट हुए हैं जिन्होंने विजय के बाद युद्ध न करने की शपथ ली।¹⁰ अशोक की अहिंसा का प्रति लगन, जन सेवा-भाग तथा शिला लेखों के सूत्रों ने गांधीजी को काफी प्रेरणा दी।

गांधीजी को नैतिक और राजनीतिक विचारधारा पर लाओ त्से (Lao Tse) और उनका समकालीन कन्फ्यूशियस (Confucious, about 551-478 B C) की शिक्षायों का भी प्रभाव पड़ा। लाओ त्से का कहना था कि 'जो मेरे प्रति अच्छे हैं मैं उनके प्रति अच्छा हूँ जो मेरे प्रति अच्छे नहीं हैं उनके प्रति भी मैं अच्छा हूँ। इस प्रकार सभी अच्छे हो जायेंगे।' 'जो मेरे प्रति सच्चे हैं मैं उनके लिए सच्चा हूँ, जो मेरे प्रति सच्चे नहीं हैं मैं उनके लिए भी सच्चा हूँ और इस प्रकार सभी सच्चे होते जायेंगे।' लाओ त्से ने नम्रता की उपमा जल से देते हुए कहा कि सर्वोत्तम मनुष्य जल के समान है। जल सभी वस्तुओं को लाभ पहुँचाता है, वह उनके साथ प्रतियोगिता नहीं करता। जल ऐसे निम्नतम स्थानों पर रहता है जहाँ कोई भी रहना पसन्द न करेगा। गांधीजी ने कन्फ्यूशियस से वह सिद्धान्त सीखा जिसके अनुसार मनुष्यों को दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा व्यवहार वे स्वयं दूसरों के द्वारा अपने प्रति न चाहते हों। दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करे जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें।

गांधीजी को गैर-हिंसक सोता में से वाइलिंग में दी गई शिक्षायों (Sermon on the Mount) ने काफी प्रभावित किया। गांधीजी का कहना था कि जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा तो यह सीधा ही उनके मन में उतर गया। अहिंसक प्रतिरोध (non-violent resistance) की शिक्षा उन्हें ईसा मसीह के इन शब्दों में मिली—

- “भगवान् उन्हें धमा कौजिए क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।”
 “यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो।”
 “अपने शत्रुओं को प्यार करो।”
 “बददुष्ठा देने वालों को दुष्ठा दो।”
 “जो तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ नेकी करो।”
 “जो तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं उनके लिए तुम भगवान् से प्रार्थना करो।”

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के एक मित्र रिवरेण्ड डोक (Rev. J J. Doak) का कहना है कि गांधीजी ने नयाग्रह भी प्रेरणा न्यू टेस्टामेण्ट (New Testament) और विशेषकर 'सर्जन ऑफ़ दी माउण्ट' से ली।¹¹

सामान्यतः इस्लाम धर्म को हिंसा और शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। किन्तु गांधीजी ने इस्लाम को एक शान्ति के धर्म के रूप में मान्यता दी है। यह सत्य है कि इस्लाम के अनुयायियों ने दूसरे धर्मावलम्बियों पर अत्याचार किये हैं, तलवार के जोर से दूसरों पर अधिकार जमाने तथा इस्लाम प्रसार का प्रयत्न किया। गांधीजी को इस्लाम में जो अच्छी बात लगी वह व्यक्तियों में भ्रातृत्व की भावना थी। मोहम्मद साहब के प्रति भी गांधी जी की श्रद्धा थी। उन्होंने कुरान का खूब मनन किया तथा उसमें कई स्थलों पर उन्हें शान्ति, प्रेम, उदारता, सहिष्णुता के संदर्भ मिले।¹² यह नहीं कहा जा सकता कि इस्लाम ने गांधीजी पर कोई विशेष प्रभाव छोड़ा। भूँकि वे सब धर्मों का आदर तथा सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, गांधीजी का इस्लाम के प्रति आदर भाव होना स्वाभाविक ही था। इसके प्रतिरिक्त, भारत में हिन्दू और मुसलमानों की अधिक संख्या होने के कारण उनमें एकता और सहिष्णुता की भावना भरने के लिए भी उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया। खिलाफत आन्दोलन (191-20) में टर्की के खलीफा का समर्थन धार्मिक भावना से नहीं जितना कि राजनीति तथा भारत में हिन्दू मुस्लिम एकता में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से था।

धर्म-निरपेक्ष विद्वानों में से थोरो (David Thoreau, 1817-62), रस्किन (John Ruskin, 1819-1900), और टॉलस्टॉय (Count Leo Tolstoi, 1828-1910) ने गांधीजी को सबसे अधिक प्रभावित किया। उनके मविनय अथवा आन्दोलन, कर-विरोध, तथा राज्य के विषय में अराजकतावादी विचारों पर अमरीकी अराजकतावादी थोरो की ही प्रतिष्ठाया थी। थोरो की पुस्तक—*Essay on Civil Disobedience*—के विचार कि “जनहित करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ अधिकतम सहयोग, और यदि वे अहित करे तो असहयोग” को गांधीजी ने पूर्णतः आत्मसात किया था। थोरो की पुस्तक के भारतीय संस्करण की भूमिका में

11. आशीर्वादम्., राजनीति शास्त्र, द्वितीय भाग. पृ 706.

12. Young India, Vol, III pp 43-44.

महात्मा गांधी ने लिखा है कि "मैं इस आदर्श को हृदय से स्वीकार करता हूँ कि वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो कम से कम शासन करती है.. इसका अर्थ अतंतोगत्वा वह होता है और जिस पर मेरा पूरा विश्वास है कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो विल्कुल ही शासन नहीं करती।"¹³

जान रस्किन (John Ruskin) की पुस्तक—*Unto This Last*—का गांधीजी के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसने उनके विचारों में बड़ा परिवर्तन किया। इस पुस्तक में उन्होंने यह सबक सीखा कि—

(i) व्यक्ति का कल्याण सभी व्यक्तियों के कल्याण में निहित है।

(ii) एक वकील के कार्य की महत्ता भी एक नार्स के कार्य के ही बराबर है। इस प्रकार सभी को अपने कार्य से आजीविका कमाने का अधिकार है।

(iii) एक धर्मिक तथा खेतिहर का जीवन ही वास्तव में जादित योग्य रहने वाला जीवन है।¹⁴

रस्किन के विचारों से गांधीजी ने शारीरिक श्रम की महत्ता को ग्रहण किया। आगे चल कर जब उन्होंने 'सर्वोदय' समाज की स्थापना के विषय में जो विचार व्यक्त किए वह रस्किन की इस पुस्तक पर ही आधारित थे। 'Unto This Last' का तात्पर्य ही 'सर्वोदय' है।

महात्मा गांधी टॉल्स्टॉय के विचारों के प्रति निकट थे। गांधीजी टॉल्स्टॉय के बहुत प्रशंसक थे, तथा अपने जीवन में टॉल्स्टॉय से बहुत कुछ ग्रहण किया। टॉल्स्टॉय की पुस्तक—*The Kingdom of God is Within you* (अर्थात् ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है)—का गांधीजी ने उस समय ही मनन कर लिया था जिस समय वे दक्षिण अफ्रीका में थे। इसने गांधीजी में अहिंसा के प्रति भावना को दृढ़ स्थापना की। अहिंसा और प्रेम टॉल्स्टॉय के विचारों के मूल आधार थे जिन्हें गांधीजी ने पूर्णतः स्वीकार किया। सितम्बर 7, 1910, को टॉल्स्टॉय ने गांधीजी को जो पत्र लिखा उसमें टॉल्स्टॉय ने प्रेम की जीवन का सर्वोच्च विधान बतलाया जो मानव में आत्मा की एकता तथा एक दूसरे के प्रति सद्भाव व्यक्त करता है।¹⁵

गांधीजी न यदि ग्रन्थों में गीता से सर्वाधिक प्रेरणा ली तो व्यक्तियों में उन पर सबसे अधिक प्रभाव बम्बई के एक जैन बंधु एवं सुधारक रायचन्द भाई का पड़ा। इंग्लैण्ड से आने के बाद गांधीजी इनके निकटतम सम्पर्क में आये। जिस प्रकार गांधीजी मानसिक उलझन तथा समस्याओं का समाधान पाने के लिए गीता का अध्ययन करते थे उसी प्रकार वे श्री रायचन्दजी से निरन्तर परामर्श और निर्देशन

13 गांधीवादिन्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय भाग, पृ० 709-10

14 Dhawan, Gopinath, The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, p 31

15 Dhawan, Gopinath, The Political Philosophy of Mahatma Gandhi pp 32-33

लेते रहते थे। रायचन्द भाई का गांधीजी से जव सम्पर्क हुआ। उस समय कवि की उम्र 25 साल की थी तथा हीरे जवाहरात के प्रसिद्ध व्यापारी थे। पहली ही भेंट में गांधीजी बिना प्रभावित हुए न रह सके। रायचन्द भाई की जिस बात पर गांधीजी मुग्ध हुए 'वह था उनका गम्भीर शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चारित्र्य और उनकी आत्म दर्शन की उत्कृष्ट लगन।'¹⁶ गांधीजी को कई धर्म आचार्यों से सम्पर्क बढ़ाने का अवसर मिला किन्तु, गांधीजी के शब्दों में 'जो छाप मुझ पर रायचन्द भाई ने डाली वह दूसरा कोई न डाल सका। उनके बहुतेरे वचन सीधे मेरे अन्तर में उतर जाते थे।'¹⁷

सभी व्यक्तिगत प्रभावों के विषय में गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख दिया है—

"मेरे जीवन पर गहरी छाप डालने वाले आधुनिक मनुष्य तीन हैं— रायचन्द भाई ने अपने सजीव सम्पर्क से, टॉल्स्टॉय ने अपना 'बैकूण्ड तेरे हृदय में है' नामक पुस्तक से, और रस्किन ने 'अनटू दिस लास्ट' (सर्वोदय) नामक पुस्तक से मुझे भुग्ध कर दिया।'¹⁸

गांधीवाद का आध्यात्मिक आधार

यदि महात्मा गांधी के जीवन एवं कार्यों को समझना है तो इसके लिए उनके आध्यात्मिक एवं धार्मिक विचारों को समझना अति आवश्यक है। क्योंकि उन्होंने अस्पृश्याचार अन्वय के विरुद्ध जो भी संघर्ष किया इसके लिए उन्हें आध्यात्मिक आदर्शों से ही शक्ति प्राप्त हुई।¹⁹

धर्म के विषय में गांधीजी के विचार बड़े उदार तथा संकीर्णता से पूर्ण परे हैं। हिन्दू धर्म के अनुयायी होते हुए भी उनके मन में सब धर्मों के प्रति आदर था। उनका कहना था कि सब धर्मों में कुछ समान सत्य हैं और इस प्रकार सब धर्म ठीक हैं। धर्म, गांधीजी के अनुसार, अलग अलग मार्गों की तरह हैं जो अन्त में एक ही आदर्श की ओर ले जाते हैं। यदि हम विभिन्न मार्गों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो अलग अलग मार्गों पर चलने में किसी को प्राप्ति नहीं होनी चाहिये। सब धर्मों में सत्यता होते हुए भी महात्मा गांधी किसी भी धर्म को पूर्ण नहीं मानते थे। सभी धर्मों का प्रतिपादन मनुष्यों के द्वारा ही किया गया है। जब मनुष्य ही पूर्ण नहीं है तो उनके द्वारा चलाये गये धर्म भी कैसे पूर्ण हो सकते हैं। धर्मों के विषय में उनका निष्कर्ष था कि सब धर्म सही हैं; सब धर्मों में स्रुटिया भी हैं।²⁰

16 सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ. 109-110.

17. उपरोक्त, पृ. 109-110.

18. उपरोक्त पृ. 112.

19. Kriplani, J. B., Gandhi His Life and Thought, p. 336.

1. Ibid., p 339

गांधीजी सब धर्मों को समान समझते थे। धर्मों की समानता उनकी धार्मिक सहिष्णुता का आधार था। किसी भी धर्म को दूसरों के मुकाबले में श्रेष्ठ धरवा घटिया मानना भूल है। इस प्रकार कोई धर्मवलम्बी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर उसका प्रकार कर, सही धर्म यह कभी भी निर्देश नहीं देता। विशेषतः गांधीजी धर्म परिवर्तन के बटुटर विरोधी थे। सब धर्मों को समान आदर देते हुए भी गांधीजी हिन्दू धर्म के सच्चे अनुयायी थे। 'हिन्दू धर्म' गांधी जी ने कहा था, "जैसा कि मैं समझता हूँ, मेरी आत्मा को पूर्ण सन्तुष्टि देता है, मेरे पूरे जीवन को भर देता है, और उससे मुझे सात्वता मिलती है।"²¹

हिन्दू धर्म, की मान्यताओं से ओत-प्रोत होते हुए भी गांधीजी ने सृष्टिवादिता को स्वीकार नहीं किया। हिन्दू धर्म के विभिन्न तत्त्वों को उन्होंने वैज्ञानिक एवं नवीन व्याख्या कर उसे जन-सेवा की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया। हिन्दू धर्म में पाछण्ड, ऊँच-नीच, जातियों तथा कई उप-सम्प्रदायों ने अपना स्थान जमा लिया था। गांधी ने इन कुरीतियों को हिन्दू धर्म से दूर करने का भरसक प्रयत्न किया।

गांधीजी आत्मा के अमरत्व तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्तों को मानते थे। हिन्दुओं का विश्वास है कि शरीर नश्वर है, तथा आत्मा अमर है। मनुष्य अपने जीवन में जो अच्छे बुरे कार्य करता है उसके अनुसार उसे मृत्योपरान्त नया जीवन धारण करना पड़ता है। जन्म-मरण का यह चक्र निरन्तर चलता रहता है। इस चक्र से छुटकारा केवल मोक्ष द्वारा ही हो सकता है। मोक्ष ही मानव जीवन का अन्तिम साध्य है। किन्तु महात्मा गांधी ससार को छोड़ सन्यास द्वारा मोक्ष का समर्थन नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य मानव जाति की सेवा करने ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि "मैं राष्ट्र की जो सेवा करता हूँ वह मेरी उस साधना का अंग है जिसे मैं अपनी आत्मा को शरीर के बन्धन से मुक्त कराने के लिए किया करता हूँ।"²²

महात्मा गांधी कभी-कभी उपवास आदि भी किया करते थे। कोई-कोई उपवास तो उनके ऐतिहासिक थे जो सप्ताहों तक चले। उपवास के पीछे गांधीजी का विचार था कि इससे भस्तिष्क केन्द्रित एवं सतुलित रहता है तथा इसका विचार शुद्धता पर भी व्यापक असर पड़ता है। कभी-कभी अपने कार्यों के प्रति उन्हें ग्लानि होती या उनके सहयोगी और समर्थक कोई गलत काम कर लें, उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर समझ कर पश्चाताप का रूप में वे उपवास को ही एक मुख्य साधन मानते थे।²³ गांधीजी ने लिखा है कि "उपवासादि सद्यो मार्ग में एक साधन के रूप में

21 Young India, Vol II, pp 1078-79.

सत्य के प्रयोग धरवा आत्मकथा, पृ 962

22 Harijan, December 24, 1934, p 363, Delhi Diary Vol I, p 185

23 Kripalani J B, Gandhi His Life and Thought, p 343

आवश्यक हैं, पर वही सब कुछ नहीं है। अगर शरीर के उपवास के साथ मन का उपवास न हो तो वह दम्भ में परिणत हो जाता है और हानिकारक सिद्ध हो सकता है।²⁴

गो-प्रतिपालन हिन्दू-धर्म का प्रमुख तत्त्व है। गांधीजी के अनुसार "गोरक्षा के मानी है गोवश-वृद्धि, गोजाति सुधार, बल से सीमित काम लेना, गोशाला को आदर्श दुग्ध-शाला बनाना इत्यादि।"²⁵ गांधीजी ने देश में कई स्थानों पर गोशालाएँ खोली तथा अपने आदर्शों के अनुसार चलने का प्रयत्न किया एवं करवाया भी। पर इस सम्बन्ध में उन्हें जिस सफलता की अपेक्षा थी वह न मिल सकी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में (धारा 48 के अन्तर्गत) गोरक्षा का प्रयोजन है किन्तु हमने इस विषय में कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। यही नहीं गोरक्षा के सिद्धान्त को अक्सर राजनीति में घसीटने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे गोरक्षा लाभ के स्थान पर हानि ही हुई है।

महात्मा गांधी का ईश्वर में अडिग विश्वास था तथा ईश्वर के अनन्य उपासक थे। लेकिन उनकी ध्याय्या परम्परागत हिन्दू दार्शनिकों से भिन्न है। वे ईश्वर को कई रूपों में देखते थे तथा ईश्वर की प्राप्ति के कई साधन मानते थे। वे सत्य को ईश्वर मानते थे तथा सत्य पर आग्रह करना ईश्वर की उपासना के ही बराबर समझते थे। एक स्थान पर उन्होंने नैतिकता को ही ईश्वर माना है। वहीं-कहीं उन्होंने प्रेम को ईश्वर बतलाया है।²⁶ किन्तु गांधीजी को ईश्वर के साक्षात् दर्शन दरिद्रनारायण में होते थे। वे दरिद्रों की सेवा या व्यापक रूप में समस्त प्राणियों की सेवा को ईश्वर की सेवा ही मानते थे। समाज में रामराज्य या सर्वोदय समाज की स्थापना करने का तात्पर्य ईश्वर से साक्षात्कार के लिये अग्रसर होना था।²⁷ ईश्वर के विषय में गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है:—

परमेश्वर की ध्याय्याएँ अनतिनत हैं; क्योंकि उसकी विभूतियाँ भी अनतिनत हैं। ये विभूतियाँ मुझे आश्चर्य में डाल देती हैं। मुझे तनिक देर के लिए मोह भी लेती हैं। पर मैं पुजारी तो सत्य रूपी परमेश्वर का हूँ। वही एक सत्य है और अन्य सब मिथ्या है। यह सत्य मुझे मिला नहीं; पर मैं इसका शोध करूँ। इसकी शोध में अपनी प्यारी-से-प्यारी वस्तु भी त्यागने को तैयार हूँ।²⁸

24 सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ० 829.

25 सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ० 534.

26 हरिजन, अगस्त 28, 1947, पृ० 285.

27 Delhi Diary, Prayer Speeches, from 10.9.47 to 30. 1. 48, p 98

28 सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, प्रस्तावना पृ० 6.

गांधीजी को धर्म का अधिक महत्त्व इसलिए और था क्योंकि यह मानव जीवन की गतिविधियों को नैतिक आधार प्रदान करता है। जो धर्म मनुष्य के नैतिक स्तर में वृद्धि नहीं कर सकता वह धर्म व्यर्थ है।²⁹

महात्मा गांधी राजनीति का आध्यात्मिकरण (Spiritualisation of politics) करना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि राजनीति को मानव जाति के लिये थाप न होकर आशीर्वाद होना है तो उसे उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए।³⁰ यही कारण था कि वे धर्म को इतना महत्त्व देते थे। वास्तव में गांधी जी धार्मिक अधिक और राजनीतिक कम थे। उन्होंने एक प्रसंग में कहा था कि 'बहुत से धार्मिक व्यक्तियों जिनसे मैं मिला हूँ, छुप छुप तौर पर राजनीतिज्ञ हैं, किन्तु मैं जो राजनीतिज्ञ का रूप रखता हूँ, हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हूँ।'³¹ धर्म के बिना राजनीति मृत्यु-जाल है जो आत्मा का हनन करदेती है।³²

महात्मा गांधी यह तो मानते ही थे कि मनुष्य राजनीतिक समाज में रहता है और इसलिये राजनीति ध्रुवगुण होते हुए भी उससे दूर नहीं रखा जा सकता। "यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूँ," गांधीजी ने एक स्थल पर कहा था, 'इसका केवल यही कारण है कि राजनीति हम सब से साप के घेरे की भांति लिपटो हुई है जिससे कितनी भी चपटा की जाये बाहर नहीं निकला जा सकता। मैं उस राजनीति रूपी सर्प से लड़ना चाहता हूँ। मैं राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।'³³ इसका यही तात्पर्य था कि गांधीजी धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहते थे क्योंकि धर्म राजनीति के विषलेपन को दूर कर आध्यात्मिक रूप तथा नैतिक आधार प्रदान करता है।

सत्याग्रह सिद्धान्त (The Theory of Satyagraha)

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को एक आन्दोलन में कूदना पड़ा। व भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका चले गये उनके साथ बड़ा बड़ा भ्रमानवीय व्यवहार किया जाता था। वे अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अयोग्यताओं से प्रसिद्ध थे। बड़ा रहने वाले भारतीयों को इन अयोग्यताओं से मुक्त कराने हेतु महात्मा गांधी एक ऐसी पद्धति की खोज में थे जो जीवन के मूल नैतिक सिद्धान्तों पर आधारित हो। वे चाहते थे कि जो सिद्धान्त व्यक्तिगत जीवन को निर्देशित करते हैं वे ही सामूहिक एवं सामाजिक जीवन की नई दिशा प्रदान करें। हरिजन पत्रिका में गांधीजी ने लिखा था—

29 Dhawan, Gopinath, the Political Philosophy of Mahatma Gandhi p 5

30 आशीर्वादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ 709

31 Speeches and Writings of Mahatma Gandhi, p 40

32 Dhawan, Gopinath, The Political Philosophy of Mahatma Gandhi p 3

33 Romain Rolland, Mahatma Gandhi, London, 1914, p 98

“व्यक्ति की दो अन्तरात्माएँ नहीं हो सकती—एक व्यक्तिगत एव सामाजिक और दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक सहिता का पालन किया जाना चाहिये।..... हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत व्यवहार के लिये ही नहीं, बरन् सधो, समुदायो और राष्ट्रों के व्यवहार का सिद्धान्त बनाना है।”³⁴

इसलिये गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और न्याय पर ही आधारित एक आन्दोलन का सूत्रपात किया। जो स्थिति दक्षिण अफ्रीका में थी लगभग वही भारत में थी। भारत में प्रेंचों के उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, तथा शोषण-नीति से दबा जा रहा था। वास्तव में सत्याग्रह आन्दोलन का प्रयोग एक व्यापक तथा निश्चित विज्ञान के रूप में गांधीजी ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ही किया।

सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति

दक्षिण अफ्रीका के लोग गौरी सरकार का विरोध पॅसिव-रेजिस्टेन्स (passive resistance) द्वारा करते थे। पॅसिव-रेजिस्टेन्स का वहाँ पर संकुचित अर्थ किया जाता था। उसे निर्बलों का ही हथियार माना जाता था। उसमें द्रोप की भी गुंजाइश थी और उसका अन्तिम स्वरूप हिंसा में प्रकट हो सकता था। गांधीजी को न तो पॅसिव-रेजिस्टेन्स शब्द ही पसन्द आया और न ही उससे सम्बन्धित उसका व्यावहारिक रूप। भारतवर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम परिचय देने के लिये वे किसी नये शब्द की खोज में थे लेकिन उन्हें कोई उचित शब्द सूझ नहीं रहा था। अतः उपयुक्त नामावली की खोज के लिये गांधीजी ने छोटा सा पुरस्कार रख कर “इन्डियन ओपिनियन” के पाठको में इसके लिये प्रतियोगिता आयोजित की इस प्रतियोगिता के माध्यम से ‘सदाग्रह’ शब्द सामने आया। सदाग्रह शब्द को अधिक स्पष्ट करने के विचार से गांधीजी ने ‘य’ शब्द और बढ़ा कर ‘सत्याग्रह’ शब्द बनाया।³⁵ सत्याग्रह शब्द भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में अधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय हुआ।

सत्याग्रह का अर्थ सत्य की खोज है। सत्याग्रह वा शब्दिक अर्थ सत्य पर अटल रहना है। महात्मा गांधी सत्याग्रह का जो अर्थ समझते थे उसके अनुसार यह सत्य पर अटल रह कर प्रेमपूर्वक स्वयं कष्ट उठाने के लिये तत्पर रहना है। सत्य वा उपासक सत्य को हिसात्मक साधनों से सिद्ध करने का कभी प्रयास नहीं करेगा। सत्याग्रह सत्य की प्राप्ति का अहिंसात्मक साधन है। सत्याग्रही आत्म-बुद्धि द्वारा विरोधी को गन्त मार्ग से हटाने वा प्रयत्न करेगा। वह घृणा वा प्रेम से, असत्य की सत्य से, हिंसा की अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह

³⁴ हरिजन मार्च 2, 1934.

³⁵ सत्य के प्रयोग अथवा आत्मज्ञान पृ. 809.

अत्याचारी से घृणा नहीं करता किन्तु अत्याचारी को अपने अन्याय को बनाये रखने में सहायता देने से मना करता है। गांधीजी ने इसे प्रेम बल तथा आत्म बल कहा है।

सत्याग्रह का एक अहिंसात्मक शस्त्र के रूप में प्रतिपादन करना गांधीजी के आध्यात्मिक विचारों का ही विस्तार है। उनका कहना था कि समस्त प्राणी ईश्वर की सन्तान हैं, इसलिए उनमें ईश्वरीय तत्त्व विद्यमान रहता है। मनुष्य के साथ हिंसा करने का अर्थ अपने निहित ईश्वरीय शक्तियों का अपमान करना होगा। गांधीजी की धारणा थी कि मनुष्य में ईश्वरीय शक्तियाँ निहित हैं। व्यक्ति चाहे कितना ही भ्रष्ट और पतित क्यों न हो उसका नैतिक मुद्धार किया जा सकता है। उसकी नैतिक चेतना जागृत कर व्यक्ति के हृदय-परिवर्तन को गांधीजी सत्याग्रह द्वारा असम्भव नहीं मानते थे।

गांधी का विश्वास था कि हिंसा के द्वारा कभी विजय नहीं हो सकती। यदि हिंसा के माध्यम से विजय उपलब्ध हो भी जाये तो वह कभी स्थाई नहीं रह सकती। हिंसा के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, सघर्ष निरन्तर बना रहता है क्योंकि पराजित पक्ष सदैव बदला लेने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत अहिंसात्मक प्रतिरोध से किसी भी पक्ष की हार नहीं होती। विरोधी अपनी भूल को स्वयं समझ लेता है और स्वेच्छापूर्वक नया व्यवहार प्रारम्भ करता है।

सत्याग्रह सिद्धान्त के अन्तर्गत जीवशास्त्र सम्बन्धी उस सिद्धांत को कोई स्थान नहीं है जिसके अन्तर्गत सबल को हा जीने का अधिकार होता है। यह हाव्स के उन विचारों को भी अस्वीकार करता है जिसके द्वारा यह माना जाता है कि मनुष्य का जीवन सभों का सभों के प्रति सघर्ष है। सत्याग्रह सिद्धान्त इन सबके विपरीत प्रेम, पारस्परिक सहयोग, सामाजिकता तथा मानव प्रगति में विश्वास रखता है। सत्याग्रह उस वेदान्त सिद्धान्त को स्वीकार करता है जिसके द्वारा 'समस्त मानव जीवन को एक' (all life is one) समझा जाता है। या, जैसा कि ईसाई धर्म में उल्लेख किया गया है कि 'हम सब एक दूसरे के सदस्य हैं' (we are members one of another) सत्याग्रह के बिल्कुल अनुकूल है।³⁶

युगों से यह प्रमाणित लगता है कि सामाजिक नैतिकता, राजनीतिक तथा अन्तर-सामुदायिक नैतिकता से काफी घाटे बड़ी हुई है। राजनीति में विभिन्न समुदायों के मध्य सम्बन्ध स्वार्थ, अविश्वास, घृणा, धोखा, हिंसा तथा युद्ध द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। जो सबल है वही अधिकारशुक्त होता है। एक राष्ट्र जब अपने हित की अपेक्षा अपने पड़ोसी राज्य के हित का ध्यान रखता है तो उसे मूलतः समझा जाता है। आजकल राज्य अपनी समस्याओं का समाधान उन साधनों द्वारा करना चाहते हैं जिनके द्वारा समस्याओं का समाधान कभी नहीं होता। बुराई को बुराई के द्वारा नहीं मुचारा जा सकता तथा घृणा को घृणा के द्वारा नहीं जीता जा सकता।

36 Kripalani, J B, Gandhi His Life and Thought, p 343

गांधीजी का सुभाव था कि मनुष्य जाति को ऐसे विकल्प की खोज करनी चाहिए जो चालाकी से परिपूर्ण, कूटनीति, हिंसा और युद्ध का स्थान ले ताकि विश्व में अन्याय, निरकुशता और क्रूरता समाप्त हो जाय। वास्तव में गांधीजी ने इस सम्बन्ध में श्रद्धा ही सत्याग्रह द्वारा मार्ग प्रशस्त किया। गांधीजी के अनुसार हिंसा और युद्ध का सत्याग्रह ही एक ऐसा विकल्प है जो प्रेम और अहिंसा पर आधारित समस्त प्रकार की समस्याओं को सुलभाने में पूर्ण समर्थ है।³⁷

युद्ध के समर्थकों का दावा है कि युद्ध से मनुष्य एवं राष्ट्र में देशभक्ति, अनुशासन, साहस और वीरता जैसे सद्गुणों का अम्युदय होता है। गांधीजी के अनुसार इन सद्गुणों का विकास करना युद्ध का ही एकाधिकार नहीं है। किसी प्रकार का विनाश किये बिना ही सत्याग्रह भी इन सभी गुणों को विकसित करने की क्षमता रखता है। सत्याग्रह द्वारा केवल वीरता और साहस ही नहीं, बल्कि भयहीनता की भी शिक्षा मिलती है। युद्ध में भाग लेने वाला दूसरों को मृत्यु के घाट उतारना चाहता है, किन्तु स्वयं मृत्यु से डरता है। उसे यह भी भय रहता है कि उसके साथी उसे वहीं छोड़ कर न चले जायें। सत्याग्रही सिपाही निडर होता है उसे मृत्यु का डर नहीं होता। उसका संघर्ष खुले मैदान में होता है। वह चोरी छिपके वार नहीं करता। सत्याग्रही की अन्तिम विजय निश्चित रहती है क्योंकि उसके पास अहिंसा का ऐसा सर्वश्रेष्ठ अस्त्र रहता है जिसका विश्व में कोई समता नहीं है। गांधीजी के ही शब्दों में:—

“अहिंसा मानव जाति के पास महानतम अस्त्र है। यह उन समस्त अस्त्रों से शक्तिशाली है जिनका निर्माण मनुष्य ने विनाश के लिये किया है।”³⁸

गांधीजी सत्य और अहिंसा के द्वारा अपने विरोधी में सुधार करना चाहते थे। सत्याग्रह की एक विशिष्टता यह है कि इसके द्वारा बुरे आदमी का नहीं बुराई का प्रतिरोध किया जाता है और वह भी घृणा द्वारा नहीं बल्कि प्रेम से। डॉ० राधा-कृष्णन् ने इस विषय में लिखा है—

“सत्याग्रह प्रेम पर आधारित है न कि घृणा पर; अपने विरोधी का प्रेम तथा पीड़ा सहकर हृदय-परिवर्तन करना है। यह पाप का प्रतिरोध करता है पापों का नहीं।”³⁹

सत्याग्रह के विभिन्न रूप

सत्याग्रह वा तात्पर्य निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive resistance) नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध के अन्तर्गत अहिंसा का प्रयोग एक नीति के रूप में किया जाता है

37. Ibid, pp. 345-47.

38. Quoted by J. B. Kriplani in Gandhi, His life and thought. p. 350.

39. Radhakrishnan, S., (Ed), Mahatma Gandhi, 100 Years, p. 4.

किन्तु परिस्थितियोंबश हिंसा का प्रयोग वजित नहीं है। गांधीजी ने निष्क्रिय प्रतिरोध को सत्याग्रह के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का अस्त्र है। इसके विपरीत सत्याग्रह सज्जनों का अस्त्र है जिसके अन्तर्गत अहिंसा को धर्म के रूप में ग्रहण किया जाता है, तथा हिंसा हर परिस्थिति और रूप में वजित है।

महात्मा गांधी सत्याग्रह को एक ऐसे बट वृक्ष की तरह मानते थे जिसकी अनेक शाखाएँ होती हैं। सत्याग्रह साधन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख पद्धतियों को गांधीजी ने स्वीकार किया था—

(1) असहयोग (Non-co-operation)—असहयोग का अर्थ है कि जिसके विरुद्ध सत्याग्रह किया जाता है उसके साथ असहयोग करें, उससे अपने सम्बन्ध तोड़ दें तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अनेक नार्थक कार्यों को सहयोग प्रयत्न प्रोत्साहन मिले। अंग्रेजों के विरुद्ध 1920-21 1930-31, तथा 1942 में गांधीजी के द्वारा चलाये गये आन्दोलन असहयोग की ही अभिव्यक्ति थे। इन आन्दोलनों में देशवासियों से अपील की गयी कि वे अंग्रेज सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करें। असहयोग अभिव्यक्ति कई तरीकों से हो सकती है जैसे—

(1) हड़ताल—इसके अन्तर्गत विरोधस्वरूप सत्याग्रही कार्य को बन्द कर देते हैं। इसका उद्देश्य सरकार एवं सम्बन्धित संस्था को धरने पदा में प्रभावित करना है। हड़ताल का प्रयोग कभी-कभी किसी कार्य के प्रति नाराजगी प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। साइमन आयोग के आगमन के समय समस्त देश में हड़ताल की गई।

(2) प्रदर्शन—प्रदर्शन किसी नीति या कार्य के विरोध में जन-शक्ति की अभिव्यक्ति है। स्वाधीनता आन्दोलन के समय देश भर में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ करते थे।

(3) बहिष्कार—किसी चीज को स्वीकार नहीं करना अथवा त्यागना बहिष्कार है। बहिष्कार सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही हो सकता है। गांधीजी के नेतृत्व में बहुत से लोगोंने अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार किया। इसके अलावा अंग्रेजी दफ्तरो, न्यायालयों आदि का भी बहिष्कार किया गया। यह सब असहयोग प्रदर्शित करता है।

(4) धरना—धरना का अर्थ जन निन्दा द्वारा किसी चीज की बुराईया नों बतलाना तथा उन पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करना है। विदेशी वस्त्रों तथा शराय की दुकानों के आगे धरना रखकर इन वस्तुओं के दोषों को बतलाकर उन्हें बन्द करना या बहिष्कार करने की सलाह देना धरना के अन्तर्गत आता है।

(5) सविनय अवज्ञा (Civil disobedience)—सविनय अवज्ञा असहयोग की तुलना में अधिक उग्र तथा अधिक सक्रिय एवं आश्रामक अस्त्र है। इसका अर्थ अनैतिक

कानूनों का उल्लंघन करना है। वे सरकार-निर्मित कानून जिन्हें जनता अनैतिक तथा शोषण का साधन समझती है, उन्हें न मानता, उन्हें जानबूझ कर तोड़ना ही सरकार की श्रवणा करना है। सविनय श्रवणा का कार्य छिपकर नहीं होता तथा श्रवणा करने वाला दण्ड से बचने का प्रयत्न नहीं करता। वह दण्ड का निर्भीकतापूर्वक स्वागत करता है।

(vi) हिजरत—गांधीजी के द्वारा समर्थित सत्याग्रह का एक अन्य रूप हिजरत था। हिजरत का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने स्थायी निवास स्थान छोड़कर चले जाएं। गांधी जी ने हिजरत का प्रयोग उन लोगों के लिए बतलाया जो यह अनुभव करते थे कि उनको कुचला और दबाया जा रहा है तथा उस स्थान पर वे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उनमें शक्ति का अभाव है। गांधीजी ने बारदोली के लोगों से 1928, जूनागढ़, ब्रिटिशगढ़ के लोगों से 1939 में हिजरत करने के लिए कहा। इसी प्रकार 1935 में उन्होंने कंधा के हरिजनों को परामर्श दिया कि वे अपना स्थान छोड़कर चले जाएं क्योंकि हिन्दुओं का उनके प्रति अत्याचारपूर्ण व्यवहार था।

सत्याग्रही अनुशासन (vii)

सत्य एवं अहिंसा के पुजारी का उच्च नैतिक स्तर होना अति आवश्यक है। सत्याग्रह आत्मशक्ति पर आधारित होना है तथा सत्याग्रही की नैतिकता ही उसे आत्मबल प्रदान करती है। गांधीजी चाहते थे कि सत्याग्रह के पुजारी को एक विशेष अनुशासन तथा आचार संहिता के अन्तर्गत रहना चाहिये जिससे उसमें शक्ति, संयम, आत्म-शुद्धि तथा अन्य गुणों का पूर्ण विकास हो सके।

(viii) ब्रह्मचर्य—एक सत्याग्रही के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना अति आवश्यक है। परम्परागत अर्थ में ब्रह्मचर्य का तात्पर्य अविवाहित रहना है पर गांधीजी ने ब्रह्मचर्य की घड़े व्यापक रूप में व्याख्या की है। उनके अनुसार "ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन-बचन-काया से सत्र इन्द्रियों का मयम।"⁴⁰ यह प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं पर नियंत्रण रखना है। यह वह मानसिक स्थिति एवं साधना है जब सत्य और अहिंसा का सेवक एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है।

ब्रह्मचर्य का तात्पर्य अविवाहित रहना नहीं है। एक विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। गांधीजी के अनुसार विवाह सम्बन्ध मनुष्य के लिए आवश्यक एवं स्वाभाविक है। किन्तु विवाह एक अनुशासन एवं शुद्धि का साधन होना चाहिए। "एक आदर्श विवाह का उद्देश्य शारीरिक सम्बन्धों द्वारा आध्यात्मिक एकता प्राप्त करना है। मानवीय प्रेम ईश्वरीय एवं विश्व प्रेम के लिये आगे बढ़ने का मार्ग है।"⁴¹ ब्रह्मचर्य का पालन स्त्री एवं पुरुष दोनों ही समान रूप से कर सकते हैं।

40. सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, पृ, 263.

41. Young India, May 21, 1931, p. 115.

गांधीजी का विचार था कि यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो स्यादेन्द्रियों पर काबू प्राप्त करना चाहिये। "मिरा अनुभव है," गांधीजी ने लिखा है, 'कि जीम की जीत लेने पर ब्रह्मचर्य का पालन अतिशय सरल है।'⁴² "इन्द्रियाँ ऐसी बलवान हैं कि उन्हें चारों ओर से, ऊपर से और नीचे से—(इस प्रकार) दशों दिशाओं से घेरा जाय तभी वे बश में रहती हैं।'⁴³

(IX) उपवास—सत्याग्रही के लिये महात्मा गांधी समय-समय पर उपवास का भी सुझाव देने हैं। स्वास्थ्य सिद्धान्त के आधार पर उपवास का महत्व तो होता ही है, किन्तु एक सत्याग्रही के लिये यह आत्म-शुद्धि, आत्म-जल, एकाग्रचित्तता और शान्ति का अमूल्य साधन है।

ब्रह्मचर्य स्थिति में इन्द्रिय दमन के लिये उपवास से बड़ी सहायता मिलती है। उपवास की सच्ची उपयोगिता बड़ी होती है जहाँ मनुष्य का मन भी देह दमन का साथ देता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी समय-समय पर उपवास किया करते थे।⁴⁴ सत्याग्रही का जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिये। उसमें अस्तेय तथा धरिद्रह आदि के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिये। तभी वह मामूहिक सत्याग्रह में जनसाधारण का नेतृत्व कर सकेगा।

अहिंसा का दर्शन (The Philosophy of Non-violence)

सत्याग्रह का मूल आधार अहिंसा का सिद्धान्त है। राजनीति और मानव जीवन को अहिंसा की शिक्षा और व्यवहार महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन हैं। उन्होंने 1920 में लिखा था "जिस प्रकार हिंसा मनुष्या की विधि है, उसी प्रकार अहिंसा मानव जाति की विधि है ...यह वह लक्ष्य है जिसकी ओर मानव समाज स्वाभाविक और अनजाने तौर पर बढ़ता जाता है। मेरे लिये अहिंसा केवल एक दार्शनिक सिद्धांत ही नहीं है। यह जीवन का ताना-बाना है, यह मस्तिष्क की वस्तु न शरीर हृदय की चीज है।"

महात्मा गांधी साध्य और साधन की एकरा में विश्वास करते थे। ईश्वर में उनका विश्वास था ही, सत्य को वे ईश्वर का स्वरूप मानते थे। इसका तात्पर्य 'राम नाम ही सत्य है'। सत्य की प्राप्ति सिर्फ अहिंसा के द्वारा ही हो सकती है। वैसे सत्य और अहिंसा को वे अलग-अलग साध्य और साधन मानते हैं। किन्तु मूलतः सत्य साध्य है और अहिंसा साधन।

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सत्य और अहिंसा के विषय में महात्मा गांधी मूल विचारक नहीं थे। भारत में शार्दीय काल से ही इनकी परम्परा रही है,

⁴² सत्य के प्रयोग अथवा आत्मन्या, पृ. 261

⁴³ उपसृंक्त, पृ. 262

सत्य के प्रयोग अथवा आत्मन्या, पृ. 263

लेकिन गांधीजी ने इस प्राचीन परम्परा को बनाये रखने के साथ-साथ अहिंसा को एक नया एवं व्यापक भावार्थ प्रदान किया। प्राचीन ऋषियों की तरह वे अहिंसा को मोक्ष का साधन मानते थे। डॉ० धवन ने इस सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा है—

“अहिंसा का अर्थ है हिंसा को छोड़ने का प्रयत्न, जो जीवन में अनिवार्य है। अहिंसा का लक्ष्य है मनुष्य को शारीरिक बन्धन से छुड़ाना ताकि वह ऐसी स्थिति प्राप्त कर सके जिसमें नाशवान शरीर के बिना जीवन सम्भव हो।”⁴⁵

व्यक्तिगत मोक्ष को साधन के रूप में स्वीकार करने के साथ-साथ गांधीजी ने अहिंसा का प्रयोग बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक अत्याचार से लड़ने के लिए किया। उन्होंने अहिंसा को सामाजिक क्रान्ति का एकसाधन बनाने का प्रयत्न किया।

अहिंसा के विषय में परम्परागत धारणा प्रायः निषेधात्मक रही है। अहिंसा जिसका तात्पर्य हिंसा का अभाव है, निषेधात्मक ही प्रतीत होता है। नकारात्मक दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है—

- (i) किसी प्राणी की हत्या न करना,
- (ii) किसी को शारीरिक कष्ट न पहुँचाना,
- (iii) किसी को मानसिक कष्ट न पहुँचाना; और
- (iv) किसी के प्रति अपने मन में घृणा अथवा द्वेष का भाव भी न रखना।

ये सभी विचार निषेधात्मक अहिंसा व्यक्त करते हैं। अन्य शब्दों में, अहिंसा का अर्थ है सत्कार की किसी भी वस्तु को मनसा, वाचा और कर्मणा क्षति न पहुँचाना।⁴⁶ इसका मतलब है घटोर शब्द न बोलना, कड़ी बात न कहना; ईर्ष्या, क्रोध, घणा और क्रूरता से बचना। विशेषतः इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने शत्रु के प्रति भी दुरे विचार नहीं रखने चाहिए। किन्तु अहिंसा के सकारात्मक अर्थ को गांधीजी ने प्राथमिकता दी थी। सकारात्मक रूप में अहिंसा का सर्वोच्च रूप सब मनुष्यों, बल्कि सब प्राणियों के प्रति सक्रिय प्रेम एवं सहभावना है।⁴⁷

महात्मा गांधी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है तथा परिस्थितियोंवश ही वह हिंसावान बनता है। मनुष्य की अहिंसात्मक प्रवृत्ति इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि आदिम काल का नरभक्षी व्यक्ति आज सम्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इन प्रकार समस्त मानव इतिहास में मनुष्य की अहिंसात्मक वृत्ति का विकास

45 Dhawan, G. N., The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, p. 64

47 Young India, Vol. II, p. 286

46 हरिजन, मितम्बर 7, 1935.

दुग्रा है और इसी कारण मानव जाति बढी जा रही है। गांधीजी का विचार था कि अहिंसा के आधार पर ही एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव प्रगति निर्भर है। यह समस्त जीवों का शाश्वत नियम है।

अहिंसा को गांधीजी ने सब शक्तियों से अधिक शक्तिशाली माना है। यह आत्मिक एवं आध्यात्मिक बल का प्रतीक है। अहिंसा में कठोर हृदय की भी पिघलाने की शक्ति है। यह विद्युत् से अधिक निश्चयात्मक और ईश्वर (ether) से भी अधिक शक्तिशाली है।⁴³ बड़ी से बड़ी हिंसा का अहिंसा से मुकाबला किया जा सकता है।

कभी-कभी अहिंसा का अर्थ बुराई को न रोकना या बुराई के सामने मुक जाना या चुपचाप ग्रन्थाय को सहन करते रहना समझा जाता है। यह धारणा गलत है। अहिंसा किसी भी रूप या परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके समक्ष समर्पण करना नहीं बल्कि आध्यात्मिक बल द्वारा प्रतिरोध का आदेश है।

गांधीजी का विश्वास था कि अहिंसा के सफल प्रयोग के लिये हमेशा जनसमूह की आवश्यकता नहीं होती। उनके अनुसार एक व्यक्ति ही हमका प्रयोग उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार लाखों व्यक्ति कर सकते हैं। आत्म-बल और नैतिक साहस वाला एक व्यक्ति हजार व्यक्तियों का काम कर सकता है। सत्याग्रह में सत्याग्रहियों की संख्या या महत्त्व नहीं, एक या षोडश से ही सत्याग्रही सत्य की खड़ाई जीतने के लिए काफी हैं।

अहिंसा द्वारा सत्याग्रह चलाने का तात्पर्य दबाव डालना या आर्थिक, मनो-वैज्ञानिक, राजनीतिक, नैतिक या किसी भी दृष्टि से बल प्रयोग नहीं है। वह अपने प्रतिद्वन्द्वियों के हृदय परिवर्तन की अपील करता है। इसका तात्पर्य विरोधी को धमकी देना या उसे नीचा दिखाने का प्रयत्न भी नहीं है, यह विरोधी को अपनी सच्चाई से प्रभावित कर उसे अपनी बात स्वीकार कराने के लिये बाध्य करता है। महात्मा गांधी निम्नलिखित तीन प्रकार की अहिंसा का उल्लेख करते हैं—

प्रबुद्ध अहिंसा (Enlightened non-violence)

यह साधन-सम्पन्न तथा बीर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकता के कारण नहीं, बल्कि नैतिक धारणाओं में अटिग विश्वास के कारण ही स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार की अहिंसा स्वीकार करने वाले व्यक्ति में प्रहार करने की पूर्ण क्षमता होती है किन्तु वह विरोधी के प्रति प्रहार करने का इच्छुक नहीं होता। ऐसे अहिंसक व्यक्ति अहिंसा को एक धर्म के रूप में ग्रहण करते हैं तथा किसी भी परिस्थिति में वे मानव-एकता तथा आतुरत्व-भावना का

⁴³ हरिजन, मार्च 14, 1939, पृ० 39

त्याग नहीं करते। गांधीजी इसे सर्वोत्कृष्ट अटिमा कहते थे। अहिंसा के इस स्वरूप को राजनीति में ही नहीं अपितु जीवन के समस्त पहलुओं में हड़नापूर्वक अपनाना चाहिए।⁴⁹

समयोचित अहिंसा (non-violence based on expediency)

अहिंसा के इस रूप को जीवन के किसी भी क्षेत्र में विशेष प्रावश्यकतानुसार एक नीति के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह निर्बल एवं प्रगहाय व्यक्ति का निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive resistance) है जो अहिंसा की नैतिक विश्वास एवं श्रद्धा के कारण ग्रहण नहीं करता। ऐसा व्यक्ति शिर्फ अपनी निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं करता। अहिंसा का यह रूप प्रबुद्ध अहिंसा जैसा शक्तिशाली साधन नहीं हो सकता। फिर भी यदि ईमानदारी, साहस और सावधानीपूर्वक इसका प्रयोग किया जाय, तो कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है।⁵⁰ कार्यों की निष्क्रिय अहिंसा (passive non-violence of the coward)

यह अहिंसा भय पर आधारित रहती है। डरपोक व्यक्ति अहिंसा का दम इसलिए भरता है क्योंकि वह डरपोक है। वह स्वतंत्रता का सामना करने की अपेक्षा भय छोड़ होता है। गांधीजी कारगरता के बिल्कुल ही पक्ष में नहीं थे। उनके ही शब्दों में "कारगरता और अहिंसा प्रायः और पानों की भांति एक साथ नहीं रह सकते।"⁵¹

सत्य एवं अहिंसा

माध्य एवं साधन (The End and the Means)

साधनों की पवित्रता, सत्य और अहिंसा का एक अभिन्न तत्त्व है। मानव जीवन का, गांधीजी के अनुसार, अन्तिम उद्देश्य स्वयं को जानना या स्वयं से साक्षात्कार करना या ईश्वर को आमने-सामने देखना, या पूर्ण सत्य की प्राप्ति या नाश प्राप्त करना है। आध्यात्मिक एकता (spiritual unity) में उनका विश्वास था; समस्त मानव प्राणी उसी एकता के विभिन्न अंग हैं, इसलिए मानव सेवा आध्यात्मिक मोक्ष का तत्कालीन उद्देश्य है। ईश्वर से साक्षात्कार ईश्वर द्वारा निर्मित प्राणियों के माध्यम से ही सम्भव है। गांधीजी ने, इस प्रकार मनुष्य मात्र ही सेवा की मोक्ष का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक साधन माना है।

महात्मा गांधी 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण' वाले उपयोगितावादी सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते। इसका तात्पर्य इकावन व्यक्तियों के कल्याण हेतु उनपचास व्यक्तियों को प्रवहेना करना ही होगा। यह सिद्धान्त मानव की आध्यात्मिक एका के विरुद्ध, हृदयहीन तथा अमानवीय है। सत्य और मानवीय

49. Dhanwan, G. N., The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, pp. 70-71.

50. Young India, Vol. I, p. 265.

51. हरिजन, नवम्बर 4, 1939 पृ० 331.

मिथ्यान्त तो सिर्फ सबं कल्याण है। जिसे गांधीजी 'सर्वोदय' कहा करते थे।⁵² इसमें समस्त व्यक्तियों के कल्याण की बात को स्वीकार किया जाना है। सर्वोदय, गांधीजी की समस्त विचारधारा का साध्य था।

महात्मा गांधी के अनुसार साध्य एवं साधन अभिन्न हैं। साधन सदैव साध्य के अनुरूप होना चाहिये। उन्होंने अधिनायकवादी साधन, जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार के साधन अपनाने जा सकते हैं। कभी भी स्वोत्पन्न नहीं किया। गांधीजी के विचारों में अच्छे साध्यों की प्राप्ति पवित्र साधनों द्वारा ही होनी चाहिए। साध्य और साधन दोनों का नैतिक होना आवश्यक है। साधना की अनैतिकता निरिच्छत रूप से साध्य को भ्रष्ट कर देती है। गांधीजी का कहना था 'साधन एक बीज की तरह है और साध्य एक पेड़ है। साधन और साध्य में वह सम्बन्ध है जो बीज और पेड़ में।' अतः साधना की पवित्रता पर ही साध्य की श्रेष्ठता निर्भर करती है।⁵³

राजनैतिक के क्षेत्र में गांधीजी ने साधनों की नैतिकता पर अधिक जोर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद एवं शोषण के विरुद्ध, स्वराज्य प्राप्ति के लिये, वे हिंसा और अत्याचार का प्रयोग करने के लिये तैयार नहीं थे। गांधीजी ने कहा था—

'मेरे जीवन दर्शन में साधन और साध्य एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ कहने है कि साधन साधन में साधन ही है। मैं कहूँगा कि साधन ही अन्त में सब कुछ है। जैसे साधन है वैसे ही साध्य होगा। साध्य और साधनों के मध्य अलगाव की कोई दीवार नहीं है। वास्तव में ईश्वर न हमें छोड़ा बहुत नियन्त्रण साधनों पर ही दिया है, साध्य पर बिलकुल नहीं।'⁵⁴

राज्य का प्रति दृष्टि कोण; अहिंसात्मक राज्य की कल्पना -

महात्मा गांधी दार्शनिक थे, किन्तु राज्य के वर्तमान या भावी स्वरूप को स्पष्टतः उन्होंने कभी लिपिबद्ध नहीं किया। अविष्य की कल्पना उन्हें दार्शनिक प्रतीति होती थी। उन्होंने अहिंसा पर आधारित राज्य की रूपरेखा के विषय में लिखना उचित नहीं समझा। उनका कहना था कि अहिंसा पर आधारित समाज का जब निर्माण होगा तो वह अवश्य ही आज के समय में पूरक भिन्न होगा। यद्यपि गांधीजी ने इन सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यापक रूप से प्रस्तुत नहीं किया फिर भी उनके विचार-सागर में से राज्य सम्बन्धी विचारों का सफलतापूर्वक किया जा सकता है।—

गांधीजी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। वे राज्य को कई कारणों से अस्वीकार करते हैं। राज्य के विरोध में गांधीजी के निम्नलिखित तर्क थे —

अधिकांश, दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधीजी का विचार

52 D-lhi Diary, Vol I, p 201

53 Young India, vol II, pp 364, 435, 956

54 Quoted by J B Kriplani in Gandhi His Life and Thought, p 349

था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायक नहीं होता। राज्य सत्ता की अनि-
वार्यता व्यक्तिगत कार्य के महत्त्व का अपहरण कर लेती है। व्यक्ति का नैतिक विकास
राज्य पर नहीं किन्तु उसकी आंतरिक इच्छाओं पर निर्भर करता है। अधिक से
अधिक राज्य मनुष्य की बाह्य दशाओं को प्रभावित कर सकता है।

द्वितीय, राज्य एक हिंसामूलक संगठन है और इस प्रकार सत्य और अहिंसा के
समस्त पहलुओं का विरोधी है। एक अहिंसा के पुजारी होने के नाते महात्मा गांधी
हिंसा पर आधारित किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके साथ-
साथ वे राज्य को हिंसात्मक इसलिये और मानते थे, क्योंकि यह निर्धन वर्ग के शोषण
में सहायक होता है। गांधीजी के शब्दों में—

“राज्य केन्द्रित और संगठित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता
है। व्यक्ति एक चेतनशील आत्मवान प्राणी है किन्तु राज्य एक ऐसा
आत्महीन यन्त्र है जिसे हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी
उत्पत्ति ही हिंसा से हुई है।”⁵⁵

तृतीय, राज्य के कार्य क्षेत्र में आजकल निरन्तर वृद्धि हो रही है। राज्य का
घटता हुआ कार्य क्षेत्र व्यक्ति में स्वावलम्बन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित
नहीं होने देता। इस सम्बन्ध में गांधीजी ने एक स्थान पर लिखा है:—

“मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय तथा शंका की दृष्टि से
देखता हूँ, क्योंकि बाह्य रूप से राज्य देखने में शोषण का विरोधी तथा
भलाई का कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, किन्तु व्यक्तित्व का विनाश कर
गह मनुष्य जाति को अधिक से अधिक हानि पहुँचाता है। हम ऐसे अनेक
उदाहरण जानते हैं। जहाँ मनुष्य ने एक संरक्षक के रूप में कार्य किया है,
किन्तु हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहाँ राज्य का अस्तित्व
बाह्य में दरिद्रों के कल्याण के लिये रहा हो।”⁵⁶

एक आदर्श रूप में महात्मा गांधी राज्य उन्मूलन के पक्ष में थे। किन्तु वर्तमान
परिस्थितियों में व्यावहारिकता के आधार पर वे एकदम तथा हिंसा द्वारा राज्य को
समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। वे मनुष्य को स्तिहाल इतना पूरे नहीं मानते थे कि
वह बिना राज्य के अपनी व्यवस्था स्वयं संचालित कर सके। “मनुष्य जाति उस
स्थल पर निवास करती है जहाँ सृष्टि के पाशविक राज्य और नैतिक राज्य की सीमा
मिलती है।”⁵⁷ इसलिये समाज में राज्य तथा हिंसा का पूर्णरूपेण बहिष्कृत करना
सम्भव नहीं।

55. Bose, N. K., Studies in Gandhism, p. 202;

Young India, July 2, 1931, p. 192.

56. Bose N. K., Studies in Gandhism, pp 202—04

57. Young India, Vol I, p. 253.

राज्य-विहीन समाज की स्थापना के विषय में गांधीजी की कुछ बातें स्पष्ट थीं। प्रथम, वे विकासवादी थे। ऐन समाज की रचना के लिए यदि एव-एक कदम भी प्रायः बड़ा ज़्यादा तो गांधीजी इसे सन्तोषजनक मानते थे। द्वितीय, जब तक राज्य-विहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती गांधीजी राज्य के अधिकारियों को पूर्णतः स्वीकृत करने के पक्ष में थे। राज्य को एक आवश्यक बुराई समझकर गांधीजी ने उसके प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया। उनका सुझाव था कि राज्य को कम से कम कार्य अपने हाथ में लेने चाहिए तथा व्यक्ति के जीवन में शून्यतम हस्तक्षेप करना चाहिए। वे प्रभरीकी अराजकतावादी हेनरी थोरो के इस विचार से सहमत थे कि 'सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है।'

तृतीय उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण के विषय पर बल दिया। सत्ता का केन्द्रीकरण सर्वत्र ही हानिकारक रहा है। विकेंद्रीकरण के विषय में गांधीजी की भारत के प्राचीन स्वावलम्बी ग्राम-समाजों से प्रेरणा मिली। उनका नारा था— 'गांव को वापन लो' (Back to the village) क्योंकि वे ग्राम-स्वराज में ही भारत की आत्मा का प्रतिबन्ध देखने में। राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि में स्वावलम्बी ग्रामों का चित्र-चित्रण करने वाले गांधीजी ने लिखा है—

मेरे ग्राम स्वराज्य का अर्थ यह है कि प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए वह अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहे। इन प्रकार खाने के लिये धान और कपड़ों के लिये रुई की फसल पैदा करना, प्रत्येक ग्राम का पहला कार्य होगा। ग्राम की अपनी नाट्य-शाला, मार्गदर्शक भवन और पाठशाला भी होनी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा प्रति बच्चा तक अनिवार्य होगी। यथासम्भव प्रत्येक कार्य सहकारिता के माध्यम पर किया जायगा। गांव का शासन पांच व्यक्तियों की पंचायत द्वारा संचालित होगा। पंचायत ही गांव की व्यवस्थापिका नभा, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सब कुछ होगी।' 58

चतुर्थ, गांधीजी के सम्प्रभु सिद्धान्त का भी खण्डन किया। वे राज्य को सम्प्रभु सम्प्रभु एव सर्व-शक्तिशाली सत्ता मानने के लिए कभी तैयार नहीं थे। हिन्दू समाजवादियों तथा बहुलवादियों की भांति गांधीजी राज्य को समाज में अन्य सत्ताओं जैसा ही समझते थे। राज्य के एक सत्ता के रूप में उनका ही अधिकार है जिन्होंने दूसरी सत्ताओं के। गांधीजी द्वारा सम्प्रभु सत्ता पर प्रहार उनके राज्य सम्बन्धी अन्य विचारों का ही विस्तार है।

प्रजातन्त्र एव प्रतिनिधि प्रणाली

विदेशी शासन को समाप्त करने के माध्यम-माध्यम गांधीजी देश में सभी प्रकार के शोषण से रहित लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। इस उद्देश्य

को ध्यान में रखते हुए गांधीजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन काल में ही रचनात्मक कार्य-क्रमों को प्रारम्भ कर दिया था ।”⁵⁹

महात्मा गांधी लोकतन्त्र की परम्परागत प्रणालियों के आलोचक थे । पश्चिमी राज्यों में लोकतन्त्र केवत नाम का ही है । ये लोकतन्त्र व्यवस्थाएँ हिंसा, अस्त्र-शस्त्र की होड़, पूंजीवाद, शोषण, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा, नेतृत्व को निर्धनता (Poverty of leadership) पर आधारित है ।⁶⁰

संसदीय व्यवस्था एवं प्रतिनिधि प्रणाली को भी गांधीजी ने अपनी आलोचना से अछूता नहीं छोड़ा । इंग्लैंड की संसद को गांधीजी ने एक 'बाँझ घोरत' की संज्ञा दी जो किसी कार्य के योग्य नहीं है । संसद के सदस्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं तथा संसद भिन्न-भिन्न मंत्रिमण्डलों के प्रति अपनी श्रद्धा का परिवर्तन करती रहती है ।⁶¹ इसी प्रकार आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली को गांधीजी ने श्रुतिपूर्ण बतलाया है । आज़रल के प्रतिनिधि वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

भारतीय परिस्थितियों के सम्दर्भ में गांधी जी कुछ समय के लिये संसदीय व्यवस्था बनाये रखने के पक्ष में थे, किन्तु वे इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे । वे नहीं चाहते थे कि संसद या संसदीय सरकार अपने हाथों में शक्ति संचय कर ले । संसद एवं सरकार को जनहित में बड़े ही व्यवस्थित एवं अनुशासित ढंग से कार्य करना चाहिये ।

महात्मा गांधी अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि प्रणाली के पक्ष में थे, किन्तु उनकी प्रतिनिधि प्रणाली का दूसरा ही स्वरूप था । उनके अनुसार भारत के सात लाख ग्राम अपने लिए जन-इच्छा के अनुसार संगठित करेंगे । ये ग्राम मिलकर अपने-अपने जिलों की शासन व्यवस्था का प्रबंध करेंगे । जिलों के द्वारा प्रान्तों के प्रशासन का चयन होगा । अन्त में प्रान्तों के द्वारा राष्ट्रीय सरकार का संगठन एवं चयन किया जायेगा । गांधीजी का विचार था कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक इकाई का महत्त्व होगा । सबसे पहले वे अपने शासन का प्रबन्ध करेंगे और साथ ही साथ अगली सीढ़ी वाले क्षेत्र के प्रशासन में भी योगदान देंगे ।⁶²

मतदाताओं की योग्यता के विषय में भी गांधीजी के विचार उल्लेखनीय हैं । वे प्रत्येक स्त्री-पुरुष जिसकी आयु इक्कीस वर्ष की हो चुकी है मतदान के योग्य मानते हैं । सम्पत्ति या पद या शैक्षणिक आधार को वे मतदाता की योग्यता का आधार स्वीकार नहीं करते । उनके विचार से वह व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करता है,

59. Kripkani, J B, Gandhi : His Life and Thought, p 352.

60. Fischer, Louis, A Week with Gandhi, pp. 82-83.

61. Dhawan, G N, The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, p 295

62. Fischer, Louis, A Week with Gandhi, p. 55;

Harjjan, July 26, 1942, p. 238.

वही वास्तव में मनदान के योग्य होना चाहिए। इस प्रकार गांधीजी धर्म-मताधिकार के पक्ष में थे।⁶³

महात्मा गांधी व्यक्ति को माध्य तथा राज्य को माध्यन मानते हैं। सैद्धान्तिक रूप में महात्मा गांधी राज्य का उन्मूलन चाहते हैं। व्यावहारिक में वे राज्य के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं किन्तु उसकी शक्ति को सीमित एवं विकेंद्रित करने के पक्ष में हैं। यह सब बुद्ध उनके विचारों के अनुकूल ही है, क्योंकि वे व्यक्ति के विकास के नामने किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते। इसलिए राज्य के अस्तित्व को वे स्वीकार करते हैं उनका उद्देश्य व्यक्ति का ही विकास करना है। वे राज्य को न तो गौरवान्वित करते के पक्ष में हैं और न ही वे उसे किसी भी प्रकार साध्या मानने को तैयार हैं।

अधिकार तथा कर्तव्य

गांधीवादी विचारों में अधिकारों का आधार मनुष्य की देवी प्रकृति है। मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। मनुष्य अपनी नैतिक प्रकृति का विकास करके भोग प्राप्त करना अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। अतः ईश्वरीय नियमों का पालन करने का मनुष्य को जन्मसिद्ध अधिकार होगा। गांधीजी के अनुसार मनुष्य के सभी अधिकार इस प्रमुख अधिकार में उपलब्ध होवें हैं। मनुष्य का नैतिक अस्तित्व प्रत्येक दृष्टि में अनुल्लंघनीय है।

महात्मा गांधी ने अधिकार और कर्तव्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। एक दृष्टिकोण से उन्होंने कर्तव्यों को अधिक महत्त्व दिया। उनका कहना था कि अधिकार कर्तव्यों से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अधिकार उसे स्वतः मिल जायेंगे। गांधीजी के शब्दों में—

“यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो हमें अपने अधिकारों की खोज में दूर नहीं जाना पड़ेगा। यदि हम कर्तव्यों का पूरा ध्यान बिना अधिकारों के पीछे दौड़ते लगे तो वे मृग-नरीशिका की भाँति हमसे दूर भाग जायेंगे। कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार है।”⁶⁴

महात्मा गांधी स्वतन्त्रता अधिकार के प्रथम समर्थक थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को आचरण तथा अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए, यदि उनकी स्वतन्त्रता दूसरों की स्वतन्त्रता में टक्कर नहीं करनी। मनुष्य की स्वतन्त्रता पर केवल सामाजिक कर्तव्यों का ही प्रभुत्व हो सकता है। गांधी जी अपने विचार विरोधियों का भी सम्मान करते थे, तथा उन्हें विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। स्वतन्त्र के मामले लेकर गांधीजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मतभेद

63 Harijan, January 2, 1927, p. 27c.

64 Gandhi, M. K., To the Princes and their People, p. 10

उत्पन्न हो गये थे। जनवरी 16, 1928, को सावरमती आश्रम से पंडित नेहरू को एक पत्र में इस मतभेदों के विषय में लिखा:—

“मैं यह चाहता हूँ कि आप को मेरे विचारों के विरुद्ध खुला सघर्ष करना चाहिये। क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं देश की अपार क्षति कर रहा हूँ, और इस प्रकार जब इसका आपको पता चल जाय तो आप को मेरे विरुद्ध विद्रोह अवश्य करना चाहिए।”⁶⁵

महात्मा गांधी के अनुसार बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के विचारों का दमन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। वे अल्पसंख्यकों के दृष्टिकोण का आदर करते थे। उसका बहना था कि यदि अल्पसंख्यक अपने दृष्टिकोण को उचित समझते हैं तो उसे मनवाने का उन्हें पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक स्थल पर उन्होंने कहा था:—

“बहुसंख्यक शासन को सीमित क्षेत्र में ही स्वीकार किया जा सकता है, अर्थात् व्यापक रूप में व्यक्ति को बहुसंख्यकों का आदेश मान लेना चाहिए। किन्तु हर विषय में बहुसंख्यकों के सामने समर्पण करना दासता है।”⁶⁶

जहाँ तक धर्म और नैतिकता का सवाल है, गांधीजी का कहना था कि इन मामलों में बहुसंख्यकों के आदेश का कभी भी पालन नहीं करना चाहिये चाहे उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हों।

समानता का अधिकार गांधीवाद का एक तार्किक तत्व है। वे सभी प्राणियों में एक ही आत्मा तथा समान नैतिक तत्वों का विद्यमान होना मानते थे, इसलिये प्रत्येक दृष्टि से सब मनुष्य समान हैं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में गांधीजी का विचार था कि सभी को नस्ल, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अधिकार मिलने चाहिए। भारतीय सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता (untouchability), तथाकथित नीचा जातियों (हरिजनों) के प्रति जो व्यवहार था वह समानता के अधिकार पर एक बलक था। पिछड़े हुए वर्ग के उत्थान के लिये, तथा अस्पृश्यता के विरुद्ध महात्मा गांधी ने जो संघर्ष किया, मानव इतिहास में शायद ही किसी ने किया हो। इस सम्बन्ध में उनके विचारों की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के तृतीय खण्ड में पूर्णतः होती है।

अपराध एवं दण्ड

गांधीजी के अनुसार समाज की असफलताओं एवं बुराइयों के कारण ही मनुष्य अपराध करता है। अहिंसात्मक राज्य में अपराध हो सकते हैं, किन्तु अपराधियों के

65. Nehru, Jawahar Lal, A Bunch of Old Letters, Asia Publishing House Bombay, 1958 pp 56-58.

66 Young India, Vol I p. 864.

साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। अहिंसात्मक राज्य की व्यवस्था नैतिक शक्ति पर आधारित होगी। इसनिये अपराध सम्बन्धी समस्याओं का अहिंसात्मक ढंग से ही समाधान किया जाएगा।

सामान्यतः महात्मा गांधी अपराधों को चाहें उनमें हिंसात्मक अपराध ही क्यों न किया हो, बन्दीगृह में रखकर दण्ड देने के पक्ष में नहीं थे। ब्रिटेन के दण्ड व्यवस्था को ही उचित नहीं मानते थे। किन्तु यह एक आदर्श था। पर जो भी दण्ड व्यवस्था अहिंसात्मक राज्य अपनायेगा वह प्रतिकार या भ्रान्त पैदा करने के उद्देश्य से नहीं दी जायेगी। गांधीजी के अनुसार दण्ड सुधारवादी मिडान्त पर आधारित होना चाहिये। इस दण्ड प्रणाली में अपराधी को याचना देना, डराना, घमसाना आदि का अन्त हो जायेगा। मृत्युदण्ड का प्रश्न ही नहीं उठता। मृत्युदण्ड अहिंसा मिडान्त के पूर्ण विपरीत है।

सुधारवादी दण्ड व्यवस्था में अपराधी को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा। बन्दीगृहों को सुधारगृह, वर्कशॉप तथा शैक्षणिक संस्थानों में परिवर्तित कर देना चाहिये। गांधीजी का विचार था कि अपराधियों के हृदय-उत्थरण का प्रयत्न होना चाहिये। जिस समय उन्हें बन्दीगृह में रखा जाय तो उन्हें किसी कला आदि का प्रशिक्षण देना चाहिये, ताकि वहाँ से जाने के बाद अपराधी स्वावलम्बी और एक अष्टदे नागरिक की भाँति अपना जीवन व्यतीत कर सकें।⁶⁷

गांधीवादी राष्ट्रवाद एवं अन्तर्राष्ट्रीयवाद

महात्मा गांधी सही अर्थों में राष्ट्रवादी थे। उनका सारा जीवन भाग्यीय राष्ट्रीय स्वार्थिता आन्दोलन में बीता। उन्होंने देश का राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय शिक्षा के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन किया, लेकिन गांधीजी सरीरों या उग्र राष्ट्रवाद के उपायक नहीं थे। स्वदेशी मिडान्त के अन्तर्गत गांधीजी ने कहा कि यह बड़ा व्यापक मिडान्त है, जो निकट पड़ोस से लेकर सम्पूर्ण विश्व को अपने में समेटे हुए है। इसलिए उनके अन्तर्राष्ट्रीयवाद तक पहुँचने के लिए कई सम्स्याओं को सेवा आशयक थी। उनका कहना था कि मनुष्य परिवार, पड़ोस, गाँव, प्रदेश, राष्ट्र इन सब को पार करके ही अन्तर्राष्ट्रीयवाद के आदर्श तक पहुँच सकता है। उनका विचार था कि मनुष्य राष्ट्रवादी हुए बिना अन्तर्राष्ट्रीयवादी नहीं हो सकता। अन्तर्राष्ट्रीयवाद तभी सम्भव हो सकता है जब कि पहले राष्ट्रवाद एक तथ्य बन जाये तथा विभिन्न देशों के लोग मर्गठित होकर एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने लगे। व भारत की सेवा को भी अन्तर्राष्ट्रीयता का एक अंग मानते थे। उन्होंने के शब्दों में—

“मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूँ ताकि सम्पूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं—

⁶⁷ Dhawan, G N, Political philosophy of Mahatma Gandhi, pp 304-305

चाहता। मैं उस राष्ट्र-भक्ति की निन्दा करता हूँ जो हम दूसरे राष्ट्रों के शोषण तथा मुनीवतों से लाभ उठाने के लिये प्रोत्साहित करती है।⁶⁸

इस प्रकार गांधीजी की राष्ट्रियता ही अन्तर्राष्ट्रीयता थी। किन्तु प्राकामक राष्ट्रवाद की उन्होंने भर्त्सना की। वे साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने इस सिद्धान्त का खंडन किया कि पिछड़े हुए राष्ट्रों की प्रगति एवं स्वतन्त्रता दूसरे राष्ट्रों के संरक्षण में रह कर ही सम्भव है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र स्वराज्य के लिये उपयुक्त होता है।

महात्मा गांधी राज्यसत्ता के विषय में सावंधीमवादी नहीं थे। उनका आदर्श था कि सत्ता के विभिन्न राज्य अपने लिये एक विश्व संगठन में लीन होकर समग्र एवं एकीकृत मानव समाज की स्थापना करें। यह इसलिये और आवश्यक था कि वो राष्ट्र शेष सत्ता से पृथक रह कर प्रगति नहीं कर सन्त। मानव जाति का कल्याण इसी में है कि सब राज्य मिलकर सहयोग स्थापित करें। प्राचीन हिन्दू आदर्श में भाति 'वस्तुष्वैव कुटुम्बकम्' के आदर्श में उनकी पूर्ण श्रद्धा थी।

महात्मा गांधी के आर्थिक विचार

महात्मा गांधी के आर्थिक दर्शन के मूल मंत्र अस्तेय (non-stealing), अपरिग्रह (non-possession), रोटो के लिये श्रम (bread-labour) और स्वदेशी (swadeshi) आदि सिद्धान्त हैं। ये सब सिद्धान्त सत्य और अहिंसा में निहित हैं।

अस्तेय व्रत (vow of non-stealing) (१)

सत्य का पालन एवं समस्त मानव जाति को प्रेम करने वाला कभी भी चोरी नहीं करेगा। अस्तेय अथवा चोरी न करने के सिद्धान्त की महात्मा गांधी ने व्यापक व्याख्या की है। इसका तात्पर्य किसी दूसरे की वस्तु उसकी आज्ञा के बिना लेना ही ही नहीं; किन्तु इसके अलावा इसका और भी व्यापक अर्थ है। एक व्यक्ति उन चीजों की प्राप्ति करे जिनकी उसे आवश्यकता नहीं, दूसरे की वस्तु को प्राप्ति करने की इच्छा करना, अपनी इच्छाओं में निरन्तर वृद्धि करना, भविष्य में किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिये पहले से ही प्रयत्न करना आदि ऐसे उदाहरण हैं जो अस्तेय व्रत के विरुद्ध हैं। वे माता-पिता जो अपने बच्चों से छिप कर कोई चीज खाते हैं गांधीजी के अनुसार, यह भी एक प्रकार की चोरी है। महात्मा गांधी की अर्थ व्यवस्था भारतवर्ष में अति आवश्यक और पारस्परिक कल्याण की वस्तुओं की उपलब्धि पर आधारित है 69

अपरिग्रह व्रत (vow of non-possession) (२)

अपरिग्रह अस्तेय व्रत का ही विस्तार है। इसका तात्पर्य उन वस्तुओं का परित्याग है जिनकी तत्काल भविष्य में आवश्यकता न हो। पूर्ण अपरिग्रह का अर्थ

68 Young India, April 4, 1929

69 D'Sa, G. N., The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, p. 83.

पूर्ण त्याग है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति को न तो धर न कपड़े और न कल के लिये अन्न का संग्रह रखना चाहिये वरन् दैनिक भोजन के लिये भगवान पर निर्भर करे। इस प्रकार अपरिग्रह का आशय भौतिक वस्तुओं पर निर्भर न रहकर व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त करना है। गांधीजी का यह विचार वास्तव में साम्यवादियों से भी अधिष्ठ उग्र है।⁷⁰

गांधीजी के अनुसार पूर्ण अपरिग्रह अव्यावहारिक है, लेकिन यदि हम शनैः शनैः अपरिग्रह के क्षेत्र में प्रयत्न करें तो हम एक सीमा तक समाज में बहु समता प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य साधनों से नहीं की जा सकती।⁷¹ गांधीजी यह भी स्वीकार करते थे कि किसी सीमा तक गुस्सिया एवं आराम का वस्तुएँ सत्याग्रही की नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति के लिये आवश्यक हैं। किन्तु इन आवश्यकताओं की सतुष्टि एक निश्चित सीमा तक ही होनी चाहिए, अन्यथा बहु सत्याग्रही की शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से मर्ति कर देगी। सत्याग्रही को अपनी आवश्यकताओं में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। उसकी आवश्यकताएँ केवल उसकी सामान्य सुविधा के ही अनुपात में होनी चाहिए। वे वस्तुएँ जो हमारे व्यक्तियों को उपलब्ध न हो सत्याग्रही को ग्रहण नहीं करनी चाहिये। सत्याग्रही सिर्फ उन वस्तुओं को ले सकता है जितनी हमारे को आवश्यकता नहीं हो। ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति करना किसी भी प्रकार की हिंसा एवं शोषण में सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए।

3. ट्रस्टीशिप सिद्धान्त अथवा आदर्श (Ideal of Trusteeship)

अपरिग्रहप्रवृत्त के साथ ही गांधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धान्त जुड़ा हुआ है। गांधीजी का विश्वास था कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना से, या किसी अन्य प्रकार से, सम्पत्ति का संचय समाज के अन्य सदस्यों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इस प्रकार धनवान एवं साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को हमारा का शोषण कर अर्पण हित में धन व्यय करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

वैसे महात्मा गांधी, यदि अहिंसा द्वारा सम्पन्न हो गये तो समस्त सम्पत्ति को समाज हित में लेने के पक्ष में थे। लेकिन जब तक साधन-सम्पन्न व्यक्ति यह करने को तैयार न हो, उन्हें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। वे अपनी सम्पत्ति के ऊपर समाज की ओर से स्वयं को एक सरदाक अथवा ट्रस्टी समझें तथा सम्पत्ति का प्रयोग समाज हित में करें।

ट्रस्टी को स्वयं भी सामाजिक कार्यकर्ता समझना चाहिए तथा ट्रस्टी के रूप में वे जो सेवा कर उगी अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक मिलना चाहिए। उन्हें रितना पारिश्रमिक मिले इसका निर्धारण राज्य करेगा।

70 Ibid, p 84

71 Bose, N K., Studies in Gandhism, Calcutta, 1947, p 201

मूल ट्रस्टी (original trustee) को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार हो तथा अन्तिम रूप में राज्य की स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। इस प्रकार गांधीजी व्यक्ति एवं राज्य दोनों को नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। एक ट्रस्टी का उत्तराधिकारी सिर्फ समाज ही हो सकता है।

महात्मा गांधी उत्तराधिकार में प्राप्त या बिना परिश्रम के धन के विरोधी थे। जब कोई व्यक्ति अपनी ट्रस्ट-सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है तब गांधीजी का मुभाव था कि राज्य न्यूनतम शक्ति का प्रयोग कर उम ट्रस्ट को अपने अधिकार में लेकर सुधारने का प्रयत्न करे।

महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का विवेचन करने से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं:—

प्रथम: यह सिद्धान्त वर्तमान व्यवस्था को समता पर आधागित व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न है। यह पूंजीवाद को कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता बल्कि उसे स्वयं को सुधारने का एक अवसर प्रदान करता है।

द्वितीय, यह सम्पत्ति के निजी स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता।

तृतीय, यह सम्पत्ति के विषय में समाज हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के हस्तक्षेप की स्वीकृति देता है।

चतुर्थ, इसके द्वारा मनुष्यों की न्यूनतम और अधिकतम आय को निश्चित करने का मुभाव मिलता है।

पंचम, आर्थिक उत्पादन का सामाजिक आवश्यकताओं द्वारा निर्धारण होना चाहिए न कि किसी की व्यक्तिगत इच्छाओं द्वारा।

ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के विरुद्ध आलोचकों का कथन है कि पूंजीपति इस सिद्धान्त से प्रभावित नहीं हो सकते। वे अहिंसात्मक तरीकों से अपनी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे। ट्रस्टीशिप सिद्धान्त पूंजीपतियों को अपनी स्थिति दूसरे ढंग से सुदृढ़ करने में सहायता देगा। इस प्रकार यह सिद्धान्त न तो प्रभावशाली है और न व्यावहारिक। गांधीजी ने इन आलोचनाओं का पूर्ण खण्डन किया है। उन्हीं के शब्दों में:—

‘मेरा ट्रस्टीशिप सिद्धान्त कोई धार्मिक तथा निश्चय ही किसी प्रकार का छल नहीं है। मुझे विश्वास है कि अन्य सिद्धान्तों के बाद भी प्रचलित रहेगा। इसके पीछे दर्शन और धर्म की शक्ति है। यदि धनी व्यक्ति इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य नहीं करता तो इससे यह सिद्धान्त गलत नहीं हो जाता, यह उम धनी व्यक्ति की कमजोरी ही प्रदर्शित करता है। इस सिद्धान्त के अलावा और कोई सिद्धान्त अहिंसा के अनुरूप नहीं हो सकता।’⁷²

72 Quoted by Dhawan, G. N., The Political Philosophy of Mahatma Gandhi, p. 56.

शारीरिक श्रम अथवा रोटी के लिए श्रम (bread labour)

रोटी के लिए श्रम सम्बन्धी अर्थशास्त्र का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने खाने और पहनने के लिए शारीरिक श्रम करना चाहिए। रोटी जीवन को परम आवश्यकता है इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए उत्पादन श्रम करना आवश्यक है। जो व्यक्ति बिना शारीरिक श्रम के भोजन करता है वह चोर है, क्योंकि वे व्यक्ति जो कोई शारीरिक श्रम किये बिना ही अपनी आवश्यकताओं में निरन्तर वृद्धि करते हैं व दूसरों के श्रम का शोषण करते हैं।

जुनि भोजन आवश्यकताओं में भी सबसे आवश्यक है कृषि से सम्बन्धित श्रम ही आवश्यक शारीरिक श्रम होगा। यदि यह सम्भव न हो सके तो व्यक्ति को अन्य आवश्यकताओं से सम्बन्धित श्रम जैसे, चरपा कातना, वड़ई या कार्य, लोहार का कार्य करना चाहिए। इन सबमें गांधीजी की प्राथमिकता चम्खा कातन की थी।

गांधीजी के अनुसार मस्तिष्क का कार्य (intellectual labour) शारीरिक श्रम के अन्तर्गत नहीं आता। शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति शारीरिक श्रम से ही हूँती चाहिए। बौद्धिक श्रम का महत्त्व अवश्य है किन्तु यह शारीरिक श्रम का निवर्त्य नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक श्रम से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए। बाल्य में शारीरिक श्रम बौद्धिक कार्य को और निखार देता है। गांधी जी का विचार था कि शारीरिक श्रम तथा बौद्धिक श्रम दोनों के लिए समान वेतन या पारिश्रमिक होना चाहिए।

रोटी के लिए श्रम को गांधीजी सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सेवा मानते थे, किन्तु यह स्वेच्छा पर आधारित होना चाहिए। यदि मनुष्य ने शारीरिक श्रम की महत्ता को समझ लिया तो बिना भी देज में भोजन और कपड़े का प्रभाव नहीं हो सकता। उनके अलावा शारीरिक श्रम से शरीर स्वस्थ रहता है तथा बीमारी आदि भी पास नहीं आने पाते। रोटी के लिये श्रम बुद्धि और शरीर दोनों में समन्वय स्थापित करना है।⁷³

मशीनयुगीय सभ्यता का विरोध

महात्मा गांधी बड़ी-बड़ी मशीनों के व्यापक प्रयोग तथा मशीनयुगीय सभ्यता का विरोधी थे। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मशीन प्रयोग का वे पूर्णतः विरोध करते थे। उनका विश्वास था कि मशीन का प्रयोग तब तक ठीक है जब तक वह मनुष्य की सेवा करे, मनुष्य में गुलामी और भ्रालस्य की प्रवृत्ति में वृद्धि न करे। वे छोटी-छोटी मशीनों के प्रयोग का स्वागत करते थे क्योंकि इससे श्रम की वृद्धि होती है। भारत के सन्दर्भ में उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर मशीन का उस समय तक

⁷³ इस सम्बन्ध में गांधीजी के विचारों के लिये देखिये—

प्रयोग नहीं होना चाहिये जब तक भारत को महान एवं अनमीमित जन-शक्ति और पशु-शक्ति का उपयोग न कर लिया जाय ।

मशीनयुगीय सभ्यता से, गांधीजी के अनुसार, नैतिकता का पतन हुआ है । मशीन औद्योगीकरण को जन्म देती है । औद्योगीकरण से शोषण को प्रोत्साहन मिलता है, बेकारी में वृद्धि होती है क्योंकि मनुष्य के श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं, उत्पादन विशेष क्षेत्रों में केन्द्रित हो जाता है; तथा केन्द्रीकृत उत्पादन के परिणाम-स्वरूप राजनीतिक शक्ति का भी केन्द्रीयकरण हो जाता है, जो लोकतन्त्र व्यवस्था की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करता है । इसके अलावा इससे परिवारिक एकता और बड़े परिवार के प्रति श्रद्धा को बड़ा धक्का लगता है । अन्य शब्दों में, गांधीजी का विचार था कि मशीन और मानव शक्ति का इस प्रकार समन्वय किया जाय कि मशीन को मनुष्य का स्थान न लेने दिया जाय तब वहाँ मानव व्यक्तित्व को न कुचल दे ।⁷⁴

कुटीर उद्योगों का समर्थन

औद्योगीकरण और मशीनीकरण का विकल्प, गांधीजी के अनुसार, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने में है । भारत की पूर्ण जनशक्ति को रोजगार देने, आर्थिक सत्ता को केन्द्रीकरण से बचाने, तथा आर्थिक स्वावलम्बन के लिए गांधीजी का सुझाव था कि कुटीर उद्योगों का जाल सम्पूर्ण देश में फैला देना चाहिए । प्रत्येक घर एक छोटा-मोटा कुटीर उद्योग का रूप ग्रहण करे । कुटीर उद्योगों में गांधीजी ने चरखा तथा खादी के उपयोग का सबसे अधिक समर्थन किया । एक बार उन्होंने बचन दिया था कि यदि देश चर्खा और खादी को अपना ले तो भारत को एक वर्ष में स्वराज्य मिल सकता है । उनके लिए चरखा एक गृह उद्योग ही नहीं, वरन् अहिंसा का एक मूल स्तम्भ तथा स्वराज्य का साधन था ।⁷⁵

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था

गांधीजी के आर्थिक विचारों का आधार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था थी । राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में वे चाहते थे कि प्रत्येक गाव या ग्राम-समूह में अपने उद्योग व धन्धे और उनका स्वशासित अस्तित्व हो । भारत के गाव अपनी आघार-भूत आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं समर्थ हों ।

स्वदेशी सिद्धान्त (Doctrine Swadeshi)

गांधी दर्शन में 'स्वदेशी' एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है । जैसे स्वदेशी का तात्पर्य अपने देश की या देश में निर्मित वस्तु से है । अन्य सिद्धान्तों की भांति गांधीजी ने 'स्वदेशी' की भी व्याख्या की है । गांधीजी इसे एक धार्मिक अनुशासन मानते थे । स्वदेशी वा उद्देश्य राजनीतिक न होकर आध्यात्मिक है, जो मनुष्य को दूसरे प्राणियों

74. आशीर्वादम्., राजनीतिशास्त्र, द्वितीय भाग, पृ. 273.

75. Tandulkar, D G, Mahatma, Life of Mohandas Karamchand Gandhi, Vol. V. p 381.

के साथ आध्यात्मिक एकता स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। जीवन का अन्तिम उद्देश्य सांसारिक बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाना है। जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मनुष्य को चाहिए कि ईश्वर द्वारा बनाये गए अन्य प्राणियों की सेवा कर ईश्वर से सम्बन्ध स्थापित करे। स्वदेशी सिद्धान्त इस धोरण मार्ग प्रदर्शन करता है। यह दूसरे प्राणियों की सेवा करने की एक विधि बतलाता है। इसी आधार पर गांधीजी ने स्वदेशी की यह परिभाषा दी है—

“स्वदेशी हममें वह वित्तवृत्ति (spirit) है जो हमें दूर के लोगों को छोड़कर अपने निकट रहने वालों की सेवा के लिए प्रेरित करती है। स्वदेशी वित्तवृत्ति हमें दूसरों को छोड़कर अपने पास-पड़ोसियों का सेवा का आभा देती है। केवल शर्त यह है कि जिन पड़ोसियों की इस प्रकार सेवा की गई है वह भी अपने पड़ोसियों की इसी प्रकार सेवा करें।”⁷⁶

स्वदेशी एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक देश-भक्ति है। इसका तात्पर्य है कि हम दूसरे देश की अपेक्षा अपने देश की सेवा को प्राथमिकता दें तथा देश के अन्तर्गत हम दूरस्थ रहने वालों की अपेक्षा निकट रहने वालों की सेवा करें। स्वदेशी की व्याख्या करते हुए सी एफ एन्ड्रयूज (C F Andrews) ने लिखा है—

“महात्मा गांधी के लिये स्वदेशी वह सिद्धान्त है कि प्रत्येक चीज की अपेक्षा अपने निकट क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाय, तथा मनुष्य की जन्म-भूमि दूसरों की अपेक्षा पहले श्रद्धा की पात्र है। इसके अलावा गांधीजी के लिए इसका यह तात्पर्य था कि अपने धर्म को छोड़ दूसरे धर्म को अंगीकार करने की तो कल्पना भी नहीं होनी चाहिये।”⁷⁷

स्वदेशी सिद्धान्त के अनुसार हमें स्वयं की आदर्श सस्थाओं का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य उनका प्रधानाकरण नहीं होना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो उनमें दूसरों के अन्भव से सुधार करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

स्वदेशी का सिद्धान्त अपने पड़ोसियों में सत्तर सम्पूर्ण विश्व को अपने में समा लेता है। सेवा की चक्र-वृद्धि धीरे-धीरे क्षमता के अनुसार होनी रहनी है। जब हम अपने निकटस्थ लोगों की सेवा कर चुकें तो फिर अपने ग्राम, क्षेत्र, देश तथा अन्त में समस्त विश्व की सेवा के लिए प्राण बढना चाहिए। स्वदेशी के अनुसार सेवा क्षेत्र केवल अपने समुदाय तक ही सीमित नहीं रहना, बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति इसमें अन्तर्गत आ जाती है।

स्वदेशी सिद्धान्त में गांधीजी ने दूर के लोगों की अपेक्षा अपने निकटस्थ व्यक्तियों की सेवा करने का जो सुझाव दिया है उसके उन्होंने कई कारण दिए हैं। मनुष्यों में सेवा-सामर्थ्य सीमित होना है इसलिए यदि वह निकटस्थ व्यक्तियों की सेवा कर ले तो वह भी पर्याप्त होगा। विश्व के विषय में हमारा ज्ञान भी पर्याप्त नहीं

76 Harijan, March 23, 1947, p 79

77 Andrews, C F, Mahatma Gandhi's Ideas, George Allen and Unwin Ltd, London, 1949 p 118

होता, इस प्रकार द्विग्व की सेवा करना आसान भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल दूर रहने वालों की ही सेवा करता है तब वह अपने निकट रहने वालों की सेवा नहीं कर सकता। गांधीजी गीता की पंक्तियों को इस सम्बन्ध में उद्धृत किया करते थे जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने कर्त्तव्य या स्वधर्म पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना उत्तम है। यह बात स्वदेशी के साथ भी मेल है।

स्वदेशी के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि कई पक्ष हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वदेशी सिद्धान्त का तात्पर्य भारत में ग्रामीण गम्यता में पूर्ण आस्था रखना है। आध्यात्मिक एवं नैतिक क्षेत्र में स्वदेशी का तात्पर्य भारत की दार्शनिक परम्पराओं का पालन करना है। धर्म के विषय में स्वदेशी का आशय अपने प्राचीन धर्म का पालन करना है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वदेशी का तात्पर्य अपने देश की समस्याओं में सुधार कर उन्हें आधुनिक बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन आदर्शों का पालन करना है।

आर्थिक स्वदेशी का तात्पर्य स्वावलम्बन से है। प्रत्येक ग्राम तथा देश अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं में स्वावलम्बी हो। विदेशों से केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात करना चाहिए जो जीवन विकास के लिये आवश्यक हो। एक व्यापक रूप में स्वदेशी का तात्पर्य अपने घर या देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग में है—लेकिन आवश्यकतानुसार बाहर से भी वस्तुएँ मगायी जा सकती हैं।

स्वदेशी सिद्धान्त की यह भाग है कि विदेशी वस्तु का प्रयोग न करना, क्योंकि हम अपने देश में अपनी आवश्यकता के अनुसार कपड़े का निर्माण कर सकते हैं। खाद उद्योग का विकास स्वदेशी की आत्मा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका कमाने का साधन प्राप्त हो सकता है।

महात्मा गांधी के सामाजिक विचार

स्वाधीनता आन्दोलन के साथ-साथ महात्मा गांधी ने सामाजिक सुधारों के प्रति भी अधिक ध्यान दिया। उनका कहना था कि समाज सुधार का काम राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के साथ-साथ चलना चाहिए। इसलिये गांधीवादी विचारधारा में रचनात्मक कार्यों को बहुत महत्त्व दिया गया है।

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महात्मा गांधी के विचार वर्ण-व्यवस्था, अस्पृश्यता, स्त्री-उत्थान, शिक्षा तथा साम्प्रदायिक एकता के विषय में अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

(1) वर्ण-व्यवस्था के विषय में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण अन्य समाज सुधारकों से भिन्न था। सामान्यतः वर्ण-व्यवस्था को जाति-पाति के भेदभाव से जोड़ा जाता है। किन्तु गांधीजी वर्ण-व्यवस्था को एक वैज्ञानिक व्यवस्था तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक मानते थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था सामाजिक असमानता को प्रोत्साहित करने में सहायक नहीं होनी चाहिए। वे वर्ण-व्यवस्था को जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण मानते थे जन्म के दृष्टिकोण से व्यक्ति को अपना पतृक पेशा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि

सामाजिक उपयोगिता का प्रत्येक कार्य आवश्यक होता है। भगी के काम का भी उतना ही महत्त्व है जितना कि प्रशासक, तकनीशियन, अध्यापक आदि के काम का। कर्म के आधार पर गांधीजी के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण से सम्बन्धित हो सकता है।

४) अस्पृश्यता हिन्दू समाज में सदियों से चली आ रही थी, जो एक प्रकार से सामाजिक अभिशाप सिद्ध हुई। इसने देश की एकता को विध्वंसित किया, सामाजिक असमानता को प्रोत्साहित किया तथा निर्दल वर्ग के शोषण में सहायक हुई। गांधीजी ने इस सामाजिक बलक को मिटाने का भागीरथी प्रयत्न किया। उन्होंने अस्पृश्यता को एक पाप बतलाया जिसका अन्त होना ही चाहिये। उन्होंने शूद्रा का प्रतिष्ठित एवं सम्मानित करन का पूर्ण प्रयत्न किया। वे उन्हें 'हरिजन' नाम से सम्बोधित करते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश करने तथा समाज के अन्य वर्गों के साथ पूजा एवं उपासना का अधिकार होना चाहिए।

५) महात्मा गांधी साम्प्रदायिक एकता के प्रबल समर्थक थे। धर्म के सम्बन्ध में उनके विचार उदार थे ही। वे सब धर्मों को आदर समान दृष्टि से देखते थे तथा सभी को एक मोक्ष का साधन मानते थे। इसलिए उनका कहना था कि धर्म के आधार पर आपस में लड़ना बुद्धिहीनता है। उनका विश्वास था कि साम्प्रदायिक एकता, विशेषकर हिन्दू मुस्लिम एकता के बिना, न तो सामाजिक प्रगति हो सकती है और न स्वराज ही मिल सकता है। राजनीति में वे धर्म-निरपेक्षता के समर्थक थे। महात्मा गांधी की सभाओं में जो प्रार्थनाएँ होती थी वे साम्प्रदायिक एकता की ही अभिव्यक्ति हैं।

६) स्त्री-सुधार के क्षेत्र में गांधीजी ने पर्व-प्रथा, बाल-विवाह, देवदासी प्रथा आदि बुराइयों का डटकर विरोध किया। वे स्त्रियों को जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में थे। वे कहा करते थे स्त्रियों को धवला कहना उनका अपमान करना है। कुछ गुणों में स्त्रियाँ पुरुषों से भी अधिक अग्रगण्य होती हैं। नैतिक बल, त्याग, सहन-शक्ति और अहिंसा स्त्रियों में पुरुषों से अधिक देखने को मिलती है। उनका कहना था कि यदि अहिंसा हमारे जीवन का अंग बन गयी तो भविष्य स्त्रियों के हाथों में होगा।

७) महात्मा गांधी भदिरापान के विरुद्ध थे। मद्य-निषेध गांधीवाद के सामाजिक कार्यक्रम का अंग है। मद्य-निषेध का विषय में राजकीय सरकारों ने कुछ प्रयत्न अथवा किये हैं किन्तु आजकल इस विषय में डिलाई जारी है।

८) महात्मा गांधी ने देश को एक नई शिक्षा प्रणाली दी जिसे बुनियादी शिक्षा (Basic Education) कहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा भारतीय परिस्थितियों के सम्बन्ध में बुनियादी शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान था। बुनियादी शिक्षा को निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(१) बुनियादी शिक्षा दस्तकारी के आधार पर होनी चाहिये।

(२) शिक्षा स्वावलम्बी हो ताकि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ स्वयं का खर्च भी चला सके।

(iii) शिक्षा का माध्यम मानृभाषा होना चाहिये ।

इन शिक्षा सिद्धान्तों को हम आज भी मान्यता देते हैं ।

गांधीवाद तथा मार्क्सवाद

महात्मा गांधी के कुछ समयक जितका इकाव साम्यवाद की ओर भी है, गांधीवाद और मार्क्सवाद (तथा साम्यवाद भी) में कोई विशेष अन्तर नहीं मानते । विशेषतः वे गांधीवाद और मार्क्सवाद को कुछ प्रमुख समानताओं का उदाहरण देते हैं । उनका कहना है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद राज-रहित समाज में विश्वास करते हैं । दोनों विचारधाराएँ सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध हैं । दोनों ही व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा लाभ को कोई मान्यता नहीं देते । वे सम्पत्ति के सामाजिकरण के पक्ष में हैं ।

गांधीवाद और साम्यवाद में कुछ बाह्य समानता अवश्य प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव में इनमें कोई समान आधार नहीं है । किशोरीलाल मगरूवाला ने अपनी पुस्तक 'गांधी और मार्क्स' में इन दोनों विचारधाराओं की भिन्नता के विषय में लिखा है:-

"गांधीवाद और साम्यवाद एक दूसरे में इनमें भिन्न हैं जैसे लाल से हरा रंग भिन्न होता है, यद्यपि हम जानते हैं कि आँख के उस रंगी को जितने रंग भेद की पहचान नहीं होती, दोनों समान प्रतीत हो सकते हैं । दोनों विचारधाराएँ बेमेल हैं, उनका अन्तर मूलभूत है और वे एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं ।" 78

मानव स्वभाव के विषय में दोनों दलों के दृष्टिकोणों में भिन्नता है । महात्मा गांधी पूँजीपतियों के हृदय परिवर्तन में आस्था रखते थे तथा उनका विश्वास था कि पूँजीपति अपनी सम्पत्ति का प्रयोग स्वार्थ में नहीं सामाजिक हित में करेंगे । मार्क्सवाद पूँजीपतियों को शोषक, अत्याचारी, स्वार्थी मानता है, जो स्वेच्छा से नहीं, हिंसात्मक-तरीकों से ही अपनी सम्पत्ति का परिष्कार करेंगे ।

धर्म एवं राजनीति के सम्बन्ध में मार्क्सवाद और गांधीवाद दो अलग-अलग ध्रुव संकेत हैं । इस ध्रुवीकरण का कारण था कि मार्क्स मूलतः भौतिकवादी तथा धर्म विरोधी था । गांधी जो ने कहा था कि जहाँ तक मार्क्सवाद हिंसा तथा ईश्वर के निषेध पर आधारित है वह मुझे अस्वीकृत है ।" मार्क्सवाद के विपरीत गांधीवाद आत्मा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा तथा धर्म सिद्धान्तों पर आधारित है । गांधीवादी भवन धर्म-नीति पर स्थापित है । धर्म से प्रेरित राजनीति गांधीजी के निषेध नीति का फल जैसा था । वे मार्क्स की तरह धर्म का राजनीति से किसी भी तरह बहिष्कार करने को तैयार नहीं थे । अन्य गण्डों में मार्क्सवाद भौतिकवादी है, जबकि गांधीवाद को अध्यात्मवाद से अभिन्न नहीं किया जा सकता ।

78. गांधीवाद और मार्क्सवाद की तुलना के लिए किशोरीलाल मगरूवाला की यह पुस्तक उत्तम विवेचन प्रस्तुत करती है, जो विशेष अध्ययन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।

माक्सवाद के अन्तर्गत साम्यवादी व्यवस्था राज्य-विहीन होगी, किन्तु वास्तव में माक्सवाद पर आधारित व्यवस्था समग्रवादी होती है जिसमें व्यक्ति और समाज के सम्पूर्ण जीवन को नियन्त्रण में रखा जाता है। गांधीवादी आदर्श-समाज में राज्य को कोई स्थान नहीं है लेकिन व्यावहारिक व्यवस्था के रूप में राज्य को एक आवश्यक बुराई माना जाता है। गांधीवादी राज्य कम से कम हस्तक्षेप करने वाली सत्ता होगा।

गांधीवाद विकेंद्रित प्रजातंत्र का समर्थक है जहाँ सत्ता ग्रामों और पंचायतों में विभाजित होगी। गांधीजी राज्य, किसी बग विशेष या किसी राजनीतिक दल के अधिनायकत्व में विश्वास नहीं करते। माक्सवादी, क्रान्ति के उपरान्त सर्वद्वारा ताना-शाही की स्थापना चाहते हैं। माक्सवाद पर आधारित साम्यवादी व्यवस्था में वास्तविक सत्ता मुठ्ठी भर साम्यवादी नेताओं के हाथों में रहती है, जन-साधारण में नहीं।

माक्सवाद बड़े-बड़े उद्योगों का विरोध नहीं करता। माक्सवादी भौतिकवादी समाज के लिए बड़े-बड़े उद्योगों का विकास आवश्यक है। माक्सवादी विचार-धारा श्रमिक समर्थक है तथा औद्योगिक मजदूर बग इस आशानी या अंधानुभाव से प्रेरण करने वाला माना जाता है। इसलिए बड़े-बड़े उद्योगों का माक्सवाद-साम्यवाद आदि में और भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विपरीत गांधीवाद बड़े बड़े उद्योगों तथा मशीनों सम्पत्ता के विरुद्ध है। गांधीवाद परबू उद्योग तथा छोटी मोटी मशीनों द्वारा चालित उद्योग का समर्थक है।

गांधीवाद माक्सवाद की तुलना में अधिक व्यापक विचारधारा है। माक्सवाद एक तरह से श्रमिकों का दशन है इसमें भौतिकवाद को ही प्राथमिकता दी गयी है जब कि गांधीवाद दरिद्र वर्ग का, जिसमें श्रमिक भी सम्मिलित है, कल्याण चाहता है। साथ ही साथ इसमें समस्त वर्गों के कल्याण की बात कही जाती है। गांधीवाद का उद्देश्य सर्वोदय है।

गांधीवाद प्रेम और सहयोग के सिद्धान्त में आधारित रखता है तथा सभी वर्गों में समानता एवं साम-जस्य स्थापित करने पर बल देता है। माक्सवाद वर्ग संघर्ष हिंसा तथा पूँजीपतियों के प्रति घृणा पर आधारित है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि गांधीवाद हिंसा रहित साम्यवाद है। इससे यह आश्वासन होना है कि यदि माक्सवाद से हिंसा (क्रान्ति) के तत्त्व को निकाल दिया जाय तो माक्सवाद एवं गांधीवाद में कोई अन्तर नहीं रहेगा। इसमें सन्देह नहीं कि गांधीजी ने साधन पर सबसे अधिक बल दिया तथा माक्सवाद से हिंसा के प्रभाव वाला तत्त्व अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। माक्सवाद से हिंसा को अलग करने से माक्सवाद एक विष-रहित सर्प जैसा हो जायगा, किन्तु हिंसा-रहित साम्यवाद और गांधीवाद में फिर भी व्यापक अन्तर विद्यमान रहना है, दोनों में मौलिक भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। माक्सवाद साधनों के विषय में पूर्णतः स्पष्ट है। माक्सवाद क्रान्ति पर आधारित है। पूँजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए इसमें वर्ग-संघर्ष, हिंसा तथा सभी प्रकार के

साधन मान्य हैं। इसके विपरीत गांधीवाद पवित्र एवं नैतिक साधनों पर आधारित है। अच्छे साधनों की प्राप्ति अच्छे साधनों द्वारा ही होनी चाहिए। ये साधन सत्य एवं अहिंसा से पृथक नहीं हो सकते। वास्तव में सत्याग्रह मार्क्सवादी क्रांति से भी अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ।⁷⁹

एक उल्लेखनीय पुस्तक—Indian Way to Socialism—में गांधीवाद और मार्क्सवाद के विषय में निम्नलिखित विवरण दिया है—

“मार्क्सवाद भौतिकवाद पर आधारित है। मार्क्सवाद के समस्त सामाजिक परिवर्तनों की कुंजी मानव जीवन के भौतिकवादी आधार में निहित है; दूसरी ओर गांधीजी के अनुसार सामाजिक प्रगति का आधार पदार्थ (matter) नहीं बल्कि विचार (mind) है। मार्क्स आर्थिक तर्कों पर समाजवाद के अवश्यभावोंपन को सिद्ध करता है, जब कि गांधीजी नैतिक आधारों पर। मार्क्स के अनुसार इच्छाओं में वृद्धि एक अच्छा उद्देश्य है, गांधीजी का आदर्श इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। वर्ग-संघर्ष तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त मार्क्स के अनुसार, समाजवाद की प्राप्ति की ओर आवश्यक कदम है; किन्तु गांधीजी सत्याग्रह एवं ट्रस्टीशिप में विश्वास रखते हैं। इन तथा अन्य मतभेदों के होने हुए भी मार्क्स तथा गांधीजी लाभ प्रवृत्ति वाले पूँजीवादी समाज के विरोधी थे तथा दोनों ने ही शोषित तथा निर्धनों के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर दिया था।”⁸⁰

मार्क्सवादी तथा गांधीवादी आदर्श में कुछ समताएँ हो सकती हैं, किन्तु मार्क्सवाद पर आधारित साम्यवादी राज्यों में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था अभी प्रचलित है, इसमें तथा गांधीवाद में कोई भी सामान्य आधार नहीं हो सकता।

क्या गांधीजी समाजवादी थे ?

गांधीवाद और साम्यवाद में व्यापक अन्तर पहले ही स्पष्ट है। महात्मा गांधी के विचारों के विषय में यह कुछ निश्चयतापूर्वक नहीं कहा जाता है कि वे समाजवादी थे। गांधीवादी चिन्तनों में यह भी एक विवादास्पद प्रश्न बन गया है। कुछ गांधीवादी समर्थकों, जैसे श्री मोरारजी देसाई, ने महात्मा गांधी को समाजवादी माना है; किन्तु श्री राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी आदि इस विचार से सहमत नहीं हैं।

डॉ. मजुमदार का कथन है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अन्तिम दो वर्ष में भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना का प्रयत्न किया। वे गांधीजी के समाजवादी विचारों की खोज 1910 से करते हैं, जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जोहन्सबर्ग के निक्ट टॉल्स्टॉय फार्म (Tolstoy Farm) की स्थापना की। इस फार्म पर लगभग बजालीस पुरुष, महिलाएँ तथा बच्चे रहते थे। प्रत्येक को प्रतिदिन

79 Kriplani, J. B., Gandhi His Life and Thought, pp 416-17.

80 Kamla Gadre, Indian Way to Socialism, Vir Publishing House, New Delhi, 1966, p. 27.

कुछ शारीरिक श्रम करना पड़ता था। फार्म पर सभी सम्प्रदाय के लोग थे, वे एक साथ भोजन करते थे तथा परिवार की तरह रहते थे।⁸¹

इसके विपरीत कमला गद्रे द्वारा लिखित पुस्तक—Indian Way to Socialism⁸²—में गांधीवाद के समाजवादी दावे का पूर्ण खण्डन किया गया है। इस पुस्तक ने ट्रस्टीशिप सिद्धान्त पर बड़ा ही बड़ा प्रहार किया है। इस सिद्धान्त को एक सदाब तथा समाजवाद से कोमो दूर बतलाया गया है।

महात्मा गांधी से कई बार पूछा गया कि क्या वे समाजवादी हैं? इस सम्बन्ध में उनके उत्तरों की ध्याट्या 'हाँ' तथा 'ना' दोनों में ही की जा सकती है। वास्तव में गांधीजी ने इसका स्पष्ट उत्तर कभी नहीं दिया। सम्भवतः वे अपने को दोनों पक्षों में रखना चाहते थे। इस प्रकार इस विवाद को अनिश्चितता में दृष्टि करने में गांधीजी स्वयं ही उत्तरदायी थे।

1927 और 1929 के मध्य पंजवाहर लाख नेहरू बड़े प्रभावशाली ढंग से मण्डलान्त्रिक समाजवाद के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उस समय गांधीजी न पं. जवाहरलाल नेहरू से आग्रह किया कि वे इस सम्बन्ध में कोई शोच्यता न करें तथा पश्चिमी समाजवाद का अनुसंधान न कर, ⁸³ एक स्थान पर उन्होंने कहा—

“मैंने समाजवाद का तात्पर्य सर्वोदय है। मैं समाजवाद की स्थापना ग्रन्थ बहरे और मूंगों की राख के ऊपर नहीं करना चाहता। पश्चिमी समाजवाद में इन लोगों को कोई स्थान नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य केवल भौतिक प्रगति है।”⁸⁴

महात्मा गांधी के समाजवादी होने के विषय में दो बातें स्पष्ट हैं। प्रथम, जैसा कि पाश्चात्य लेखक समाजवाद का अर्थ समझते हैं, महात्मा गांधीजी उस अर्थ में समाजवादी नहीं थे। कभी-कभी वे अपने लिए समाजवादी कहते थे जिसका स्रोत वे इषोपनिषद (Isopanishad) तथा भगवद्गुराण को मानते थे। भागवत में उल्लेख है—

यावद् भ्रियते जठर तावन् स्वत्व हि देहिनाम् ।

अधिक योऽभिमन्येत स तेनो दण्डमर्हति ॥

अर्थात् एक व्यक्ति सिर्फ उतना ही प्राप्त करने का अधिकारी है जिसका उसके पेट के लिये आवश्यक है। जो इससे अधिक लेता है वह चोर है, तथा जो एक चोर को दण्ड मिलता है वह उसे भी मिलना चाहिये।⁸⁵

द्वितीय गांधीजी जब अपने को समाजवादी कहते थे उसका तात्पर्य यह था किन्हीं क्षेत्रों में उनके तथा समाजवादी विचार मूल खाते थे। जैसे, दोनों ही समानता स्वतन्त्रता, निर्धन वर्ग का समर्थन करते हैं।

81 Majumdar B B, Gandhian Concept of State, p 182

82 Published by Vic Publishing House, New Delhi, 1966, The preface of this book is by Dr V K R V Rao

83 Nehru, Jawahar Lal, A Bunch of Old Letters, pp 55-56

84 Tandulkar, D G, Mahatma, Life of Mohandas Karamchand Gandhi, 1953, vol VII, pp 191-91

85 Majumdar, B B Gandhian Concept of State p 183

समाजवाद की तरह महात्मा गांधी भूमि पर निजी स्वामित्व के विरोधी थे। या, यह कहना उपयुक्त होगा कि वे सभी प्रकार की निजी सम्पत्ति के विरुद्ध थे। उनके विचार से "सम्पत्ति समाज की, भूमि गोपाल की" है। अन्य शब्दों में वे सम्पत्ति के सामाजीकरण के पक्ष में थे।

इसके अलावा दोनों ही विचारधाराएँ—

- (i) प्रजातन्त्र में विश्वास करती है, 1
- (ii) मानवतावादी है; 2
- (iii) शोषण के विरुद्ध हैं, तथा 3
- (iv) समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखती हैं। 4

लेकिन ये समानताएँ दोनों विचारधाराओं को एक ही नहीं बना देती। दोनों में मूलभूत अन्तर दृष्टिगोचर होते हैं। 21

प्रथम, समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये राज्य एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। किन्तु महात्मा गांधी सिद्धान्तिक रूप से राज्य संस्था में ही विश्वास नहीं करते। सिर्फ व्यावहारिक दृष्टि से वे राज्य की सीमित उपयोगिता स्वीकार करते हैं, पर वह भी एक आवश्यक बुराई के रूप में।

द्वितीय, समाजवाद सामान्यतः केन्द्रीकरण को प्रोत्साहित करता है, जब कि गांधीवाद विकेन्द्रित व्यवस्था का समर्थक है।

तृतीय, समाजवाद मूलतः भौतिकवादी है जबकि गांधीवाद आध्यात्मवादी है। इस भिन्नता का तात्पर्य यह नहीं है कि गांधीवाद और समाजवाद दो विरोधी विचारधाराएँ हैं। वास्तव में गांधीवाद एक व्यापक विचारधारा है तथा उसकी अलग-अलग दृष्टिकोण से व्युत्पत्ति की जाय तो वह सभी विचारधाराओं के निकट है। किन्तु गांधीवाद न तो मार्क्सवाद है और न समाजवाद। गांधीवाद सिर्फ गांधीवाद ही है।

मूल्यांकन

गांधीवाद जितना व्यापक विचार-समूह है उतनी ही व्यापक इसकी समीक्षा हुई है। गांधीवाद की आलोचना विभिन्न दृष्टिकोणों से हुई है। यद्यपि आलोचकों के तर्कों में सत्यता का अंश तो है, उन्हें पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता।

वैसे गांधीजी ने एक उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक होने का परिचय दिया है, पर आलोचकों का कहना है कि मानव स्वभाव में उनके विचार मनोवैज्ञानिक आधार पर सही नहीं कहे जा सकते। गांधीजी व्यक्ति में केवल अच्छाइयों का ही दर्शन करते हैं और इसी आधार पर उन्होंने सिद्धान्त रूपी भीनारों खड़ी की हैं। किन्तु मानव स्वभाव के विषय में सत्यता यह है कि उसमें अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। सभी लोगों से सत्य, अहिंसा, त्याग, सहयोग, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि की अपेक्षा करना एक भूल होगी।

गांधीवादी दर्शन के विरुद्ध एक मुख्य आक्षेप यह है कि यह वास्तविकता से परे तथा कल्पना प्रधान है। इसमें आदर्शवाद की प्रमुखता और व्यावहारिकता का अभाव है। गांधीजी द्वारा सत्य, अहिंसा के सिद्धान्त, उनके राज्य सम्बन्धी विचार, स्वदेशी एवं ट्रेस्टीशिप सिद्धान्त आदि में आदर्श तत्वों की मात्रा अधिक है। गांधीजी अहिंसा पर अधिक बल देते हैं तथा विदेशी आक्रमण का सामना करने और विदेशी नियन्त्रण से मुक्ति पाने के लिये वे अहिंसात्मक साधनों का मुझाव देते हैं। सीमित रूप में यह प्रभावकारी हो सकता है। परन्तु हिटलर या साम्यवादी शासन या सैनिक शासन, अथवा वियतनाम से विदेशी सैनिकों के नियन्त्रण से मुक्ति प्राप्त करना आदि अहिंसात्मक साधनों द्वारा सम्भव नहीं हो सकता। बांगला देश में पाकिस्तानी सैनिकों के समक्ष सत्याग्रही साधनों का प्रभावशाली होना बहुत कुछ सदिग्ध था। इसी प्रकार अहिंसात्मक राज्य में पुलिस और सेना से अहिंसा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी का अहिंसा-सिद्धान्त विवेक पर नहीं, भावना पर आधारित है। इस सिद्धान्त को धर्म के रूप में वे ही स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें ईश्वर, आत्मा पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा हो। अहिंसा का प्रयोग महात्मा गांधी जैसे ही व्यक्ति कर सकते हैं, यह सामान्य एवं औसत आदमी के बस की बात नहीं।

महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं वे वर्तमान समय के अनुकूल नहीं। वर्ण व्यवस्था मध्ययुगीन समाज के लिये उपयुक्त हो सकती थी, किन्तु आज उद्योग-धन्धों के स्वरूप, मनुष्य के स्वभाव एवं हथि आदि में परिवर्तन हुआ है कि वर्ण-व्यवस्था का पालन आसान नहीं रहा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक पेशे तक ही सीमित रहे तो रूस की ओर समाज दोनों की ही प्रगति बबरूद्ध हो जायगी। आज का समाज मूलतः औद्योगिक समाज है। जिसका प्रबन्ध वर्ण-व्यवस्था के आधार पर नहीं हो सकता। नित नये उद्योग धंधों की स्थापना होती है और यदि हर एक व्यक्ति अपना पेशेवर काम ही करता रहे तो नवीन उद्योगों में काम कौन करेगा? इसके साथ साथ यह भी सम्भव नहीं है कि हर व्यक्ति में अपने पूर्वजों के पेशे को चलाने की पूर्ण क्षमता हो।

महात्मा गांधी ने सामान्यतः बड़े-बड़े उद्योगों का विरोध तथा कुटीर उद्योगों का समर्थन किया है। इसमें सन्देह नहीं कि कुटीर उद्योगों का भी महत्व होता है, लेकिन इनसे देश का पूर्ण आर्थिक विकास नहीं हो सकता। आज के युग में किसी भी देश के पूर्ण आर्थिक विकास के लिये बड़े-बड़े उद्योग आवश्यक हैं। आज बल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, मनुष्यों और भिन्न-भिन्न देशों की आवश्यकताओं में जिस अनुपात से वृद्धि हो रही है उस अनुपात से आर्थिक प्रगति बड़े-बड़े उद्योगों के बिना नहीं हो सकती।

गांधीवाद में अन्तर्विरोध भी दृष्टिगोचर होता है। गांधीजी पूंजीवाद तथा इससे उत्पन्न आर्थिक विषमता एवं शोषण का विरोध करते हैं। किन्तु पूंजीवादी

व्यवस्था के विकल्प के रूप में वे ट्रस्टीशिप सिद्धान्त का सुझाव देते हैं। ट्रस्टीशिप सिद्धान्त अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद का संरक्षक होगा। सैद्धान्तिक रूप से वे राज्य का विरोध करते हैं किन्तु व्यावहारिक रूप में वे सीमित राज्य का समर्थन करते हैं। फिर राज्य को चाहे किसी भी रूप में स्वीकार क्यों न किया जाय यह पूर्ण रूप से अहिंसक नहीं हो सकता।

गांधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त को पूर्ण समाजवादी सिद्धान्त होने का दावा किया जाता है। ट्रस्टीशिप सिद्धान्त पूंजीपतियों से उनकी पूंजी को सामाजिक हित में प्रयोग करने की अपेक्षा करता है। यह आदर्श तो ठीक है किन्तु व्यावहारिक नहीं। पूंजीपति एक शेर की तरह है जिसे पास खाने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त में गांधीजी यूटोपियन समाजवादियों अधिक निकट हैं।

गांधीजी के अन्तर्राष्ट्रीय विचार एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीयता विश्व-बन्धुत्व, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में पूर्ण आस्था रखते हैं। ये सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का आधार हैं तथा आज भी मान्य हैं। किन्तु गांधीजी वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं कर सके। वे राष्ट्रीय हित को कोई विशेष महत्त्व नहीं देते। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित की अवहेलना नहीं कर सकता। सम्भवतः गांधीजी इस स्थिति से परिचित होते हुए भी हमारे समक्ष केवल एक आदर्श ही रखते हैं।

गांधीवाद की सब से अधिक महत्ता उसके मानववाद (Humanism) में निहित है। मानववादी दृष्टिकोण गांधीवाद में सर्वत्र बिखरा हुआ है। यद्यपि गांधीजी मूलतः धर्म-निष्ठावान तथा ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति थे, उनके विचारों का केन्द्र मनुष्य ही था। वे मनुष्य को सर्वतोमुखी प्रगति आध्यात्मिक एवं सीमित भौतिकवाद सहित, चाहते थे। यह प्रगति कुछ सीमित व्यक्तियों तक ही नहीं किन्तु समाज के सभी वर्गों को समेटे हुए होनी चाहिये। सर्वोदय उनका उद्देश्य था।

महात्मा गांधी ने उन सभी सिद्धान्तों को ठुकरा दिया जिसमें सम्पूर्ण समाज की भलाई की बात नहीं कही जाती। उपयोगितावाद एक उदारवादी विचारधारा थी किन्तु इसका यह विचार-सूत्र 'अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख'— गांधीजी को मान्य नहीं था। वे 'अन्तिम व्यक्ति तक' (Unto This Last) या सर्वोदय में विश्वास करते थे। उनका सर्वोदय समाज शिखर-वर्ग (summit class) से नहीं, निर्धन वर्ग से प्रारम्भ होता है, जिसमें साधारण से साधारण तथा अवाञ्छनीय व्यक्ति तक की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार गांधीजी ने पूर्ण सिद्धान्तों को पूर्ण करने में योगदान दिया। उनके विचारों से यह प्रेरणा मिलती है कि विधि एवं नीतियों का निर्माण किसी वर्ग विशेष या बहुमत के लिये ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण समाज के हित के लिये होना चाहिये। इसमें भी निर्धन वर्ग, जिसे वे 'दरिद्र-नारायण' कहते थे, को प्राथमिकता होनी चाहिये।

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को नवीन आयाम प्रदान किये। सामान्यतः सत्य और अहिंसा को न तो व्यक्तिगत और न सार्वजनिक जीवन में कोई विशेष महत्व दिया जाता है। महात्मा गांधी ने अपने व्यवहार और वाच से यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार का आधार तो है ही, सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती।

सत्य और अहिंसा के आधार पर गांधीजी ने सार्वजनिक जीवन को एक धार्मिक आधार प्रदान किया। धर्म एवं राजनीति का समन्वय करने का तात्पर्य धर्मोपदेश विचारों का प्रतिदान करना नहीं था। गांधीजी के अनुसार धर्म नैतिकता का प्रमुख एवं प्रधान स्रोत है। यदि राजनीति या सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन को नैतिक तथा पवित्र बनाना है तो धर्म के वैज्ञानिकत्वों को ग्रहण करना ही होगा। महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकीकरण (Spiritualisation of Politics) करने का जो प्रयत्न किया वह आज की स्वायत्तपरायण राजनीति के कचड़े को साफ करने में अत्यन्त सहायक हो सक्ता है। डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि गांधीजी एक क्रान्तिकारी चिन्तक थे, उन्होंने राजनीति को शुद्ध बनाने के लिये मानव स्वभाव के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।⁸⁶

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा जैसे मूल सिद्धान्त एवं शक्तियों का एक महान शक्ति के रूप में प्रयोग किया। अहिंसा को गांधी जी एक ऐसी शक्ति मानते थे जिसका पारिवारिक जीवन से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तक प्रत्येक परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद को भारत से उखाड़ फेंकने में सत्याग्रही साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आज भी अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये बहुत से नीचो नेताओं द्वारा तथा अफ्रीका में श्वेत शासन के विरुद्ध समय समय पर विभिन्न सत्याग्रही साधनों का प्रयोग अब एक सामान्य सा प्रचलन बनता जा रहा है।

महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन जिस वृत्तव्यता से किया उसने स्वतन्त्रता प्राप्ति को किसी सीमा तक सरल बना दिया। उन्होंने यह बिलकुल समझ लिया कि अंग्रेजी साम्राज्य का सामना सिर्फ सत्य और अहिंसा से ही किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस को भी उन्होंने एक समन्वयपरक संस्था बनाये रखा। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय कांग्रेस पार्टी में कई बार संघर्षित्व एवं व्यक्तिगत मतभेद हुए किन्तु गांधीजी ने विभिन्न तथा विरोधी विचारों को एकरूप एवं समन्वय करने की अपूर्ण क्षमता थी। डा. राजेन्द्रप्रसाद ने लिखा है कि इस क्षमता के ही कारण कांग्रेस पार्टी कई बार विघटित होते होते बची। कांग्रेस पार्टी के मंच पर सभी विचारधाराओं को एकत्रित कर एकरूप बनाना गांधीजी के ही वश की बात थी।⁸⁷

86. Radha Krishnan, S. Mahatma Gandhi, 100 Years p 1

87. Pyarelal, Mahatma Gandhi The Last Phase, Vol I, p. X (from Introduction by Dr. Rajendra Prasad)

स्वराज प्राप्ति तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का संचालन करने में महात्मा गांधी ने एक अत्यन्त ही निपुण आन्दोलन-कौशल (tactician), दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, और अनुभवी मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का परिचय दिया। भारतीय जनता का नेतृत्व करने के लिये यह आवश्यक था कि व्यक्ति सही अर्थ में भारतीय परम्परा का प्रतीक हो। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नैतिक शक्ति में दूसरों से श्रेष्ठ होने के साथ साथ सामान्य एवं साधारण जनता से अलग न हो। सत्य एवं अहिंसा का राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रयोग कर महात्मा गांधी ने एक महान एव श्रेष्ठतर आत्म शक्ति का उपयोग किया जिसने साम्राज्यवादियों को घुटने टेकने के लिये विवश ही नहीं किया बल्कि प्रतिद्वन्द्वियों ने भी गांधी जी प्रशंसा की। दक्षिण अफ्रीका में उनके प्रमुख विरोधी जनरल स्मट्स (F. M. Smuts) ने भी गांधीजी को 'विश्व का एक महान व्यक्ति' बतलाया।⁸⁸ गांधीजी के नेतृत्व के विषय में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक एव परमाणु शक्ति के जनक अलबर्ट आइन्स्टीन (Albert Einstein) ने एक बार कहा था:—

“गांधी ने यह प्रदर्शित कर दिया कि एक शक्तिशाली मानव समूह को, चालाकी या चालबाजी द्वारा ही नहीं, जैसा कि सामान्य राजनीति में किया जाता है, किन्तु जीवन आचरण के श्रेष्ठ नैतिक उदाहरण द्वारा संगठित किया जा सकता है। इस पूर्ण नैतिक पतन के युग में गांधी ही एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो राजनीतिक क्षेत्र में उच्च मानवीय सम्बन्धों पर हृदय रहे।”⁸⁹

महात्मा गांधी यह भी अच्छी तरह समझते थे कि भारतीय जनता से किस प्रकार अपील की जाय तथा किस प्रकार उनके मस्तिष्क को प्रभावित किया जाय। इसलिये उन्होंने सबसे पहिले स्वयं और जनता के मध्य की दूरी को समाप्त किया। उन्होंने अपने को भारत के निर्धन एवं दलित वर्ग से पूरी तरह मिला लिया। गांधीजी ने निर्धन वर्ग जैसी ही बेप भूषा को ग्रहण किया तथा एक दिन में अपने भोजन में कभी भी पांच खाद्य चीजों से अधिक न खाने का प्रण लिया था।⁹⁰

उनकी भाषण पद्धति पूर्णतः भारतीय शैली पर आधारित थी। प्रार्थना सभाओं में अपने विचार व्यक्त करना, धार्मिक उदाहरण देकर सामान्य जनता को समझाकर उन्हें विश्वस्त करना आदि से भारतीय जनता विना प्रभावित हुए न रह सकी। महात्मा गांधी ने भारतीयकरण का सही स्वरूप प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप वे बड़े लोकप्रिय हुए तथा लगभग सम्पूर्ण देश का प्रभावशाली नेतृत्व कर सके।

88. Pyarelal. Mahatma Gandhi, The Last Phase, Vol. I, p. II;

आशीर्वादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ. 709.

89. Quoted by Louis Fischer in The Life of Mahatma Gandhi, Jonathan Cape, London, 1951, p. 22-23.

90. Kulkarni, J. B., The Indian Triumvirate, p. 227.

Kriplani, J. B., Gandhi : His Life and Thought, p. 344.

गांधीजी के आदर्श समाज में राज्य अनावश्यक है। किन्तु आदर्श समाज की प्राप्ति जब हो सकती है यदि व्यक्ति पूर्ण हो तथा दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझे। गांधीजी का विचार था कि इस अवस्था की प्राप्ति में काफी समय लगेगा। इसलिए सब तक के लिए राज्य अनावश्यक होते हुए भी आवश्यक है। गांधीजी ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में ही स्वीकार किया है। चूंकि राज्य एक बुराई है इसलिए इसमें सुधार आवश्यक है। व्यावहारिक रूप में गांधीजी जिस राज्य को स्वीकार कर सकते हैं वह 'अहिंसात्मक राज्य (non violent state) ही हो सकता है।⁹¹

राज्य के विषय में गांधीजी के विचार अराजकतावादी हैं। इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य के बिना सिर्फ़ कार्य ही नहीं चल सकता, वरन् राज्य को व्यापक अधिकार भी देने पड़ते हैं। आजकल प्रत्येक राज्य विभिन्न सकारात्मक कार्य करता है ताकि जन-कल्याण में अभिवृद्धि हो सके। यहाँ तक तो गांधीवाद परिस्थितियों के अनुकूल नहीं लगता। किन्तु गांधीवाद में जो सत्यता है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य के व्यापक अधिकार होने चाहिए परन्तु इतने व्यापक नहीं कि राज्य अधिनायकवादी बन जाय तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अतिक्रमण होता रहे। गांधीवाद का महत्त्व इसी क्षेत्र में है। वे तत्त्वतः राज्य की अधिनायकवादी प्रवृत्ति के जितने विरुद्ध थे उतने राज्य सभ्यता के नहीं।

महात्मा गांधी ने आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में स्वतन्त्रता एवं समानता को सन्तुलित करने का प्रयत्न किया। सम्भवतः आलोचक इस तथ्य को समझने में त्रुटि करते हैं। गांधीवाद का यह तत्व ही पूर्ण विदित है कि वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रवल समर्थक थे। किन्तु वे यह भी स्वीकार करते थे कि आर्थिक स्वतन्त्रता एवं समानता के बिना अन्य सभी अधिकार खोखले एवं व्यर्थ हैं। यही कारण है कि उन्होंने व्यक्ति, ग्राम, तथा देश को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए बड़ी योजनाओं को कार्य रूप दिया। उनका स्वदेशी सिद्धान्त, गृह उद्योगों का समर्थन, चरखा एवं कटाई का महत्त्व, वषण व्यवस्था का पेशेवर आधार, शिक्षा एवं धर्म का सम्बन्ध स्थापित करना आदि, इसी धारणा की अभिव्यक्ति हैं। किन्तु वे आर्थिक प्रगति का उस सीमा तक ही समर्थन करते थे जहाँ तक कि वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। वे व्यक्ति या राज्य को भौतिकवादी नहीं बनने देना चाहते थे।

विश्व के सभ्य समाज तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं को महात्मा गांधी का एक और मुख्य योगदान साधनों के क्षेत्र में है। उन्होंने इस विचार को सभी भी

⁹¹ Ghosal, H. R., in *Gandhian Concept of State* edited by B. B. Majumdar, Bihar University, Patna, 1957, p. 156.

मान्यता नहीं दी कि अच्छे साध्यों की प्राप्ति किसी भी प्रकार के साधनों द्वारा हो सकती है। उनकी दृष्टि में साध्य तो श्रेष्ठ होना ही चाहिये किन्तु उनकी प्राप्ति भी पवित्र साधनों से होनी चाहिये। यदि साधन ठीक नहीं है तो उपलब्ध साध्यों का कोई महत्व नहीं।

भारत में कई समाज सुधारक हुए हैं। महात्मा गांधी इन समाज सुधारकों में सम्भवतः सबसे महान् थे। उन्होंने समाज से ऊँच-नीच, छुआ-छूत, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, तथा देवदासी प्रथा का डट कर विरोध किया। महिला उत्थान के अलावा उनकी विशेष दिलचस्पी हरिजन उद्धार, नशाबन्दी तथा गौ-बध पर प्रतिबन्ध लगाने में थी। भारत में दलित वर्ग, पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों के लिए जितना कार्य गांधीजी ने किया अन्य किसी समाज सुधारक ने नहीं किया। इनके लिये तो वे एक वेगम्बर जैसे ही थे।

गांधीजी ने धर्म को जो महत्ता दी तथा उनका 'रोटी के लिये धर्म' सिद्धान्त अपने आप में क्लान्तिकारी विचार है। भारत में सामान्यतः शिक्षित वर्ग में शारीरिक धर्म के प्रति घृणा पाई जाती है। उनमें 'बाबूगिरी' या 'साहबमन' की बू निरन्तर घर करती जा रही है। गांधीजी ने इस मनोविज्ञान की घोर निन्दा की। वे नहीं चाहते थे कि भारतीयों में शारीरिक धर्म के प्रति उदासीनता हो, तथा देश में धर्म करने वालों की उपेक्षा हो। आज के संदर्भ में धर्म की प्रतिष्ठा और भी महत्वपूर्ण है।

गांधीवाद के योगदान के विषय में आचार्य कृपलानी के समग्र विचारों को देना उचित प्रतीत होता है। निष्कर्ष रूप में आचार्य कृपलानी ने लिखा है—

“राजनीति का सत्य, अहिंसा और साधनों की पवित्रता द्वारा आध्यात्मिकीकरण करके, अन्याय एवं निरकुंशता का सत्याग्रह द्वारा सामना कर, तथा अपने रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा गांधीजी ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का संयोग एवं समन्वय करने का प्रयत्न किया, तथा प्रभावकारी लोकतन्त्र की स्थापना कर उन्होंने न्याय और समानता पर आधारित समाज की नींव डालकर विश्व शान्ति के लिये मार्ग प्रशस्त किया।”^{१३}

पाठ्य ग्रन्थ

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1 | Andrews C F , | Mahatma Gandhi's Ideas |
| 2 | Bose, N K , | Studies in Gandhism |
| 3 | Dhawan, Gopinath , | The Political Philosophy of Mahatma Gandhi |
| 4 | Fischer, Louis, | The Life of Mahatma Gandhi |
| 5 | गांधी मोहनदास करमचन्द | सत्य के प्रयोग अथवा आत्म कथा |
| 6 | Kripalani, J B . | Gandhi His Life and Thought. |
| 7. | Kulkarni, V B | The Indian Triumvirate,
Chapter 7 Gandhi An Appraisal |
| 8 | Mashruwala, K G , | Gandhi and Marx |
| 9, | Pyarelal , | Mahatma Gandhi,
Phase, Vols I II |
| 10 | Radhakrishnan, S
(Ed), | Mahatma Gandhi 100 Years
- |
| 11 | Tandulkar, D G , | Mahatma, Vols V. and VII |
-

सर्वोदय

स्वाधीनता के उपरान्त सर्वोदय दर्शन ने भारतीय जन-मानस को काफी प्रभावित किया है। स्वाधीनता संग्राम के युग में देशवासियों की आकांक्षा थी कि स्वतन्त्र भारत में एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाय जो स्वतन्त्रता, समता और न्याय पर आधारित हो। महात्मा गांधी इन आकांक्षाओं के मूर्तरूप थे जिन्होंने उन्होंने 'सर्वोदय' शब्द में व्यक्त किया। वे चाहते थे कि सत्य एवं अहिंसा पर आधारित वर्ण-विहीन जाति-विहीन तथा शोषण-मुक्त समाज की स्थापना की जाय जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह को अपने सर्वाङ्गीण विकास के अवसर एवं साधन प्राप्त हो। यही सर्वोदय का लक्ष्य था, यही गांधीवाद का रचनात्मक पक्ष था।¹

विकास

सर्वोदय का आदर्श हमारे लिये कोई नया नहीं है। विचार के साथ-साथ यह शब्द भी प्राचीन है। दो हजार वर्ष पूर्व जैनाचार्य समंतभद्र ने सर्वोदय-तीर्थ की भावना व्यक्त करते हुए कहा था:—

'सर्वापदामंतकरं निरंतं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव'

(सर्वोदय अन्तरहित [और] सब आपत्तियों का विनाशक [है] यह तेरा तीर्थ-निस्तारक ही [है] !)

गीता में 'सर्वभूतहिते रताः' का भी तात्पर्य सर्वोदय है। ऋषियों की यह प्रार्थना सैकड़ों वर्ष पुरानी है, जिसमें कहा गया है कि—

'सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा' कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॥

(सब ही सुखी हों। सब नीरोग हों। सब मंगलो का दर्शन करें। कोई भी दुःख न पाये।)

रस्किन (John Ruskin) की पुस्तक—Unto This Last—का गांधीजी के विचारों तथा सर्वोदय दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। रस्किन की इस पुस्तक का सार है कि—

1.- ईमानदारी के प्रति धृद्धा रखना तथा धन का ईमानदारी के साथ ही उपार्जन करना चाहिये।

¹ सर्वोदय के विषय में डॉ. इन्दु टिकेकर की पुस्तक का नाम 'क्रान्ति का समग्र दर्शन' है। यह शीर्षक उस पुस्तक पर ही आधारित है।

2. डाक्टर, लेखक या सिपाही आदि सभी की देश के लिये समान सेवा होती है।

3. सम्मान का मूल सद्भावना और सहानुभूति है।

4. समाज में विद्रोह सम्पत्ति के दुरुपयोग पर निर्भर करता है।

5. निधन का शोषण चोरी है।

रस्किन के विचारों का गांधीजी ने त्रि-सूत्री सार इस प्रकार दिया है

प्रथम, व्यक्ति का ध्येय समष्टि के ध्येय में ही निहित होता है।

द्वितीय, वकील के कार्य की कीमत भी नार्ड के काम की कीमत के समान ही है, क्योंकि हर एक को अपने व्यवसाय द्वारा अपनी आजीविका चलाने का समान अधिकार है।

तृतीय, श्रमिक का अर्थात् किसान अथवा कारीगर का जीवन ही सच्चा और सर्वोत्कृष्ट जीवन है।²

लेकिन जिस विचार का गांधीजी पर विशेष प्रभाव पड़ा वह था कि "सम्पत्ति निर्धनों की ओर बहनी चाहिये।" रस्किन ने लिखा था—

"सम्पत्ति तो नदी की तरह प्रवाहशील होती है। नदी समुद्र की ओर अर्थात् उतार की तरफ बहती है। उसी तरह सम्पत्ति का प्रभाव भी उतार की दिशाओं में अर्थात् गरीबों की ओर बह निकले, तो वह नि सन्देह जीवनदायी एवं सुखदायी सिद्ध होगा।"³

यह विचार रस्किन की पुस्तक का मूलमन्त्र था तथा यही गांधीजी का सर्वोदय था।

जिस अर्थ में आज सर्वोदय एक प्रेरक शक्ति बन गया है उस अर्थ में उसका सर्वप्रथम उपयोग गांधीजी ने ही किया था। रस्किन की पुस्तक का उन्होंने गुजराती में सक्षिप्त अनुवाद किया था तथा इसकी भूमिका में गांधीजी ने लिखा है—

"रस्किन की इस पुस्तक का मैंने शब्दश अनुवाद नहीं किया है, केवल सार दिया है। प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाता, तो यह सम्भव था कि वाइबल आदि ग्रन्थों के जितने ही टूटान पाठकों की समझ में न आते। मूल अंग्रेजी पुस्तक का नाम का भी शब्दश अनुवाद नहीं किया है : क्योंकि उमका भी अर्थ केवल वही पा सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजी में वाइबल पढ़ी है और इस पुस्तक का उद्देश्य तो सबका उदय यानी उत्कर्ष करने का है, अतः मैंने इसका नाम 'सर्वोदय' रखा है।"⁴

इस प्रकार सर्वोदय 'शब्द' और 'विचार' दोनों का ही अभ्युदय हुआ। आगे चलकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सन्दर्भ में जैसे-जैसे 'स्वराज' के आतीरक

2 शंकरराव देव, सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र, पृ. 43

3 उद्धृत शंकर राव देव, सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र, पृ. 25

4 उद्धृत, शंकरराव देव, सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र पृ. 8

तत्वों में विस्तार हुआ जैसे-जैसे रचनात्मक कार्यों के सन्दर्भ में सर्वोदय के विभिन्न सूत्रों का विकास होता चला गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद ही गांधीजी अपने आन्दोलन के दूसरे और वृहत्तर पहलू को कार्यान्वित करने के लिये किसी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की अपने मन में योजना बना रहे थे। महात्मा गांधी को यह अवसर नहीं मिल पाया कि वे समाज बदलने और उसके पुनर्निर्माण की अपनी अहिंसक पद्धति का दर्शन करा सकते। 'स्वराज' को व्यावहारिक रूप देने का जैसे ही अवसर आया, मौत ने उन्हें हमारे बीच से छीन लिया। इसमें सन्देह नहीं कि भावी रचनात्मक कार्यों के लिये गांधीजी ने बहुत कुछ कहा और लिखा। साथ ही साथ उन्होंने अपने भावी कार्यक्रमों की बुनियाद डालना लगभग उसी समय से प्रारम्भ कर दिया था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व 'स्वराज' शब्द से लोगों की प्रेरणा मिलती रही। 'स्वराज' शब्द इतना व्यापक था कि इसमें देश का स्वाधीनता संग्राम, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम सभी सम्मिलित थे। फिर भी गांधीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रम तथा स्वराज्य के उपरान्त 'मेरे सपनों का भारत' को एक नये ही शब्द में ढालना चाहते थे। अन्त में उन्हें वह शब्द मिल गया जिसे सर्वोदय कहते हैं। सर्वोदय वास्तव में स्वराज्य के आगे की कड़ी है।

सर्वोदय गांधीवाद का रचनात्मक विस्तार है। गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम ऐसे समाज की स्थापना का कार्यक्रम है जो प्रेम और अहिंसा का व्यावहारिक स्वरूप हो। देश जैसे-जैसे स्वतन्त्रता के निकट आता गया गांधीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न करने लगे। यहां दो बातों का उल्लेख आवश्यक है। प्रथम, स्वतन्त्रता संग्राम में गांधीजी ने अपना सर्वस्व जीवन न्योछावर कर दिया था। वे राष्ट्र के कर्णधार थे, उनके मार्गदर्शन से देश स्वतन्त्र हुआ। किन्तु अपने आदर्श के अनुरूप देश का पुनर्निर्माण करने के लिये सत्ता अपने हाथ में नहीं ली। द्वितीय, उनका प्रस्ताव था कि स्वाधीनता के उपरान्त कांग्रेस को राजनीतिक क्षेत्र से हटकर स्वयं को 'लोक सेवा संघ' में समेट लेना चाहिये। सच्चे गांधीवादी अनुयायियों को इनसे बड़ी प्रेरणा मिली। किन्तु इसी समय गांधीजी हमारे बीच नहीं रहे उनकी मृत्यु के बाद उनके विचार ही उनकी अंतिम इच्छा और वसीयत बन गये।

महात्मा गांधी के विचार दूरगामी तथा श्रेष्ठ आदर्श की अभिव्यक्ति थे। जैसा कि डा. राधाकृष्णन ने लिखा है, उनके विचार ऐसे नहीं थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनका रंग उतर जाय या मुरझा जाय।⁵ डा. राजेन्द्र प्रसाद की कामना थी कि कोई राष्ट्र या व्यक्ति अवश्य ही जागृत होगा जो गांधीजी द्वारा चलाये गये सत्य के प्रयोगों को आगे बढ़ा कर उन्हें पूरा करेगा ताकि उनके उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।⁶ कांग्रेस

5. Radhakrishnan S., (Ed). Mahatma Gandhi, 100 Years, p.1

6. Pyarelal, Mahatma Gandhi, the Last phase, vol. I, Introduction by Dr. Rajendra Parsad, D. XVI.

पार्टी के प्रमुख नेताओं ने सत्ता से अलग होना व्यावहारिक नहीं समझा। आखिर फिर देश का शासन कौन चलाता ?

राजनीति में जो गांधीवादी थे, या जिन्हें गांधीवाद में श्रद्धा थी वे अवश्य ही गांधीवादी रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। इसलिए कुछ गांधीवादियों ने स्वयं को राजनीति से अलग रख कर रचनात्मक कार्यों को अपने हाथों में ले लिया, ताकि किसी सीमा तक 'मेरे सपनों का भारत' को व्यावहारिक रूप दिया जा सके।

अप्रेजों ने भारत में काफी गहरे पैर जमाने का प्रयत्न किया किन्तु उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के समझ झुकना ही पड़ा। वे शान्तिपूर्वक देश छोड़कर चले गये। भारत से अप्रेजों के जाने से गांधीजी का एक महान उद्देश्य पूरा हुआ। अब भारत का भविष्य भारतवासियों के हाथों में आ गया। किन्तु इस देश के ही आर्थिक, सामाजिक अन्धकार का यदि उन्मूलन करना था तो उसके लिये क्या करना चाहिये था। अपने देश में भी राजें महाराजें, उच्चवर्गीय अमीर, पुलिस, गुण्डे आदि सभी थे। शोषण तथा सघर्ष भी कई रूप में दिखमान था। पच्छिम सरकार द्वारा सामन्त करने के लिये कृत-संकल्प थी, गांधीवादी यह मानते थे कि इन समस्याओं का सही ढंग से समाधान करना सरकार के घस की बात नहीं थी। इसके लिये नये सत्याग्रह की आवश्यकता थी। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ रचनात्मक कार्यकर्ता मार्च 1948 में सेवाग्राम में एकत्रित हुए। आचार्य विनोबा भावे इन कार्यकर्ताओं में अग्रणीय थे तथा उनके सुझाव पर 'सर्वोदय समाज' की स्थापना हुई। एक वर्ष के उपरान्त ही 'सर्व सेवा सघ' की भी स्थापना हुई जिसका उद्देश्य 'सर्वोदय समाज' के उद्देश्यों को कार्यरूप देना था। लगभग इसी समय वर्षा से एक हिन्दी पत्रिका 'सर्वोदय' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जो बाद में कई भाषाओं में प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार गांधीजी के वाद सर्वोदय विचारधारा ने सक्रियता ग्रहण की।

सर्वोदय का अर्थ

सर्वोदय के अर्थ के विषय में इस विचारधारा के जनक महात्मा गांधी के विचारों को सर्वप्रथम जानना आवश्यक है। गांधीजी के निम्नलिखित शब्दों से सर्वोदय का मूल एवं आधार स्पष्ट हो जाता है। गांधीजी ने अपनी पुस्तक 'सर्वोदय' की भूमिका में लिखा है—

“पश्चिम के देशों में साधारणतः यह माना जाता है कि बहुसंख्यक लोगों का सुख—उनका अन्धुदय बढ़ाना मनुष्य का कर्तव्य है। सुख का अर्थ केवल शारीरिक सुख, रुपये-पैसे का सुख लिया जाता है। ऐसा सुख प्राप्त करने में नीति के नियम भंग होते ही तो इसकी अधिक परवाह नहीं की जाती। इसी तरह बहुसंख्यक लोगों को सुख देने का उद्देश्य रखने के कारण पश्चिम के लोग धोड़ों को दुःख पहुँचाकर भी बहुतांश को सुख दिलाने”

में कोई बुराई नहीं मानते। इसका फल हम पश्चिम के सभी देशों में देख रहे हैं। किन्तु पश्चिम के कितने ही विचारवानों का कहना है कि बहु-संख्यक मनुष्यों के शारीरिक और आधिक सुख के लिए यत्न करना ही ईश्वर का नियम नहीं है। केवल बहुसंख्यकों के लिए ही यत्न करें तथा उसके लिए नैतिक नियमों को भंग किया जाय, यह ईश्वरोप नियम के विरुद्ध आचरण है।”

गांधीजी के विचारों से स्पष्ट है कि वे ‘बहुमत का सुख’ या ‘अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख’ वाले सिद्धान्तों को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। उनका ध्येय तो समाज के सभी व्यक्तियों का सुख है, जिसे वे सर्वोदय कहते थे।

इस समय सर्वोदय के अग्रणीय विचारक आचार्य विनोबा भावे ने सर्वोदय की एक दूसरे ही दृष्टिकोण से व्याख्या कर उसे व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है। सर्वोदय की व्याख्या करते हुए विनोबा भावे ने कहा है—

“सर्वोदय का एक बहुत ही सरल और स्पष्ट अर्थ है। हम जैसे-जैसे इसका प्रयोग करते जायेंगे, वैसे-ही-वैसे उसके और भी अर्थ निकलेंगे। लेकिन यह उसका कम से कम अर्थ है। इसी से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी कमाई का पाना चाहिए, दूसरों की कमाई का नहीं खाना चाहिये। हम अपना भार दूसरे पर नहीं डालना चाहिए।”⁷

यहाँ विनोबा भावे ने स्वयं श्रम की महत्ता को सर्वोदय का प्रमुख तत्व माना है। मनुष्य को अपने जीवनयापन के लिये दूसरे के श्रम का शोषण नहीं करना चाहिये। एक अन्य संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मनुष्य को भौतिकवादी नहीं होना चाहिये। उसे स्वर्ण-माया का दास बन कर नहीं रहना चाहिये। सम्पत्ति एवं संग्रह मनुष्यों के पारस्परिक प्रेम में बाधा है। लेकिन हम एक सादी सी बात समझ लें तो वह सघ जायगा। हर एक व्यक्ति दूसरे को फिक्र रखे और अपनी फिक्र भी ऐसी न रखे, जिससे दूसरे को तकलीफ हो। परिवार में भी यही चलता है। परिवार का यह न्याय समाज पर लागू करना कठिन नहीं, आसान होना चाहिये। इसी को ‘सर्वोदय’ कहते हैं।⁸ सर्वोदय के प्रमुख व्याख्याता शंकरराव देव ने सर्वोदय को निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया है:—

“सर्वोदय का सीधा और सरल अर्थ है ‘सबका उदय’-‘सबका विकास’ अर्थात् ‘सबका हित’। ‘अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख’ वाला तत्त्वज्ञान सर्वोदय स्वीकार नहीं करता। हमारी संस्कृति में मनुष्य को

7. शंकर राव देव, सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र, पृ. 7.

8. विनोबा : व्यक्तित्व और विचार, पृ. 347.

9. उपर्युक्त, पृ. 347.

सब भूलों के हित में रत रहना चाहिये—‘सर्वभूतहिते रता.’। एक मनुष्य का हित दूसरे मनुष्य के हित के विपरीत नहीं हो सकता, सबका हित एक दूसरे के हित के अनुकूल ही हो सकता है, यह सर्वोदय का विचार है।”¹⁰

सुप्रसिद्ध गांधीवादी एवं सर्वोदय चिन्तक दादा धर्माधिकारी सर्वोदय की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि—

“सर्वोदय का नाम भले ही नया हो, पर उसका अर्थ सबका जीवन, सम्पन्न हो, इतना ही है। जीवन का अर्थ है कि विनाश हो, अभ्युदय हो, उन्नति हो। विनाश हो, इसलिये ‘सर्वोदय’। लेकिन पुराने जमाने में ‘अभ्युदय’ शब्द का प्रयोग ‘ऐच्छिक वैभव इतने अर्थ तक ही सीमित था। इसलिये गांधीजी ने केवल ‘उदय’ शब्द का प्रयोग किया। एक साथ समान रूप से सबका उदय ही यही सर्वोदय का उद्देश्य है।”¹¹

सर्वोदय दर्शन

जिस प्रकार गांधीजी ने अपने विचारों को किसी ‘वाद’ का रूप नहीं दिया, उसी प्रकार सर्वोदय चिन्तक ने भी सर्वोदय को किसी ‘वाद’ या दर्शन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वैसे सर्वोदय के विभिन्न स्वरूपों का समग्रता से स्पर्श करने वाला एक नया दर्शन खड़ा करने का प्रयत्न किया जाय तो यह आसानी से हो सकता है। लेकिन सर्वोदय विचारक स्वयं ही यह नहीं चाहते। यह चीज भी अपने में एक महत्वपूर्ण सन्केत रखती है। “जो मानव के दुःख निवारण का कायल होता है, वह कभी तर्कप्रधान दर्शन का ढाँचा, वाद या ‘आइडियोलॉजी’ तैयार करने में नहीं लगता। आगे चल कर यही स्वतन्त्रचेता मनुष्य के लिये पजर (पिजड़े) बन जाते हैं तथा प्रवाही जीवन के सहज विकास में एकावट डालत है।”¹²

यह पहले ही स्पष्ट है कि सर्वोदय दर्शन का आधार गांधीवाद ही है। आधुनिक परिस्थितियों में यह गांधीवाद का ही विकसित रूप है। इस प्रकार सर्वोदय दर्शन के मूल गांधीवादी सिद्धान्तों से अभिन्न हैं। गांधीवाद की भाँति सर्वोदय का मूल सत्य एवं अहिंसा है। इसमें ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, स्वदेशी, ट्रस्टोशिप आदि सभी सिद्धान्तों का पूर्णतः स्वीकार किया गया है। राज्य, विकेंद्रा-व्यवस्था, व्यक्ति-महत्त्व आदि के विषय में सर्वोदय गांधीवाद का ही विस्तार है। किन्तु कुछ पक्षों में सर्वोदयी चिन्तकों ने अभिवृद्धि की है, जिसमें सर्वोदय का अपना स्वयं का एक विकसित रूप हमारे सामने आता है। अगले कुछ पृष्ठों में इन्हीं पक्षों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

10. शंकरराव देव, सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र, पृ. 5.

1. दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन, पृ. 23.

इन्दु टिक्कर, क्रान्ति का समग्र दर्शन, पृ. 2.

राज्य विलयन

राज्य के विषय में महात्मा गांधी के विचार आदर्शवादी और व्यावहारिक दोनों ही थे। एक आदर्श के रूप में वे राज्य के पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में थे। एक व्यावहारिक होने के नाते वे फिलहाल राज्य के अधिकारों को अत्यन्त ही सीमित कर देना चाहते थे। किन्तु सर्वोदयी विचारको ने इस सम्बन्ध में पूर्णतः अराजकतावादी आदर्श ग्रहण कर लिया है। सर्वोदयी चिन्तको का विश्वास है कि राज्य सत्था के होते हुए सर्वोदयी समाज की स्थापना नहीं हो सकती। वे राज्य के कार्य-क्षेत्र और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को गहरी शंका और भय की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा, वे सत्ता के विकेन्द्रीकरण को भी सर्वोदयी समाज रचना के लिये उत्साहजनक नहीं मानते। सर्वोदय का उद्देश्य शासन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना है जिसके लिये राज्य का उन्मूलन आवश्यक है।

मार्क्सवाद के अनुसार साम्यवादी व्यवस्था राज्य-रहित होगी। सर्वोदय उद्देश्य मार्क्सवाद से भिन्न नहीं है। किन्तु जिस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धान्तों पर आधारित कई देशों में साम्यवादी क्रान्तियाँ हुई हैं वे शासन राज्य उन्मूलन की ओर नहीं; अधिनायकवाद की ओर अग्रसर हुए हैं। सर्वोदयी सत्ता के मार्ग में राज्य विलयन का मुकाम कभी नहीं आ सकता। सर्वोदय विचारक मानते हैं कि सर्वोदय के अन्तर्गत राज्य विलयन सम्भव है। सर्वोदय में सत्ता, दल नियन्त्रण आदि में कोई विश्वस्त नहीं किया जाता। 'सर्वोदय समाज' स्वयं ही अपनी सत्थाओं एवं सेवकों पर कोई नियन्त्रण नहीं करता। उनका कहना है कि जहाँ प्रेम एवं सहयोग है, वहाँ शासन की कल्पना नहीं की जा सकती।¹³ मनुष्य जब बिना किसी प्रकार के बाह्य दबाव या अकुश के अपने साथियों में बन्धुत्व, न्याय और सहयोग के साथ रहने के योग्य हो जायगा इसका तात्पर्य होगा कि उसका विकास हो गया है। मनुष्य में बिना किसी प्रकार बाह्य दबाव या अकुश के अपने साथियों के मध्य सहयोग एवं न्यायपूर्वक रहने की क्षमता को विकास की कसौटी मानते हैं। सर्वोदयी विचारको का कहना है कि वे इस ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा राज्य विलयन के सिद्धान्त को सम्भव बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।¹⁴

दल-बिहीन व्यवस्था

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सर्वोदयी विचारक परम्परागत राजनीतिक साधनों में विश्वास नहीं करते। इसी कारण वे दल-पद्धति को कोई महत्व नहीं देते सर्वोदय विचारधारा दलगत राजनीति से पूर्ण पृथक है। उनके निश्चित साध्य

13. विनोबा, व्यक्तित्व और विचार, पृ. 409-10.

शंकरराव देव, सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र, पृ. 10.

14. जयप्रकाश नारायण, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, पृ. 49-51.

एक निश्चित साधन सिद्धान्त है, इसलिये समाज को विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार दल-विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं। यह सम्पूर्ण समाज को अपने साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है।

महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन राजनीति में बिताया, किन्तु वे परम्परागत अर्थ में राजनीतिज्ञ नहीं थे। गांधीजी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया तथा वे केवल इस दृष्टि से राजनीतिज्ञ थे क्योंकि इस आन्दोलन का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वाधीनता था। वह किसी दल के लिये सत्ता का आन्दोलन नहीं था। "यदि उसका लक्ष्य सत्ता था तो वह सत्ता पूरे भारतवर्ष की जनता के लिये थी। इसमें वे लोग भी सम्मिलित थे जो पाकिस्तान बनाने के लिये अलग हुए, और दोनों हिन्दुस्तानों में जितने दल मौजूद थे वे और जो भविष्य में बनेंगे, वे भी सम्मिलित थे। गांधीजी किसी दल के नेता नहीं थे जो अपने दल की सत्ता के लिये लड़ते और दाब-पेच खेलते। यदि ऐसा होता, तो उनके मन में कांग्रेस को सत्तावादी राजनीति छोड़ने की बात कहने का कभी विचार ही न आता।",¹⁵

गांधीजी के निर्दलीय विचार सर्वोदय के लिये प्रेरणा है। सर्वोदय विचारधारा के प्रचार के लिये 'सर्वोदय समाज' तथा अन्य संस्थाएँ जैसे 'सर्व-सेवा संघ' आदि की स्थापना की गई। ये सभी गैर राजनीतिक संस्थाएँ हैं। इसका तात्पर्य है कि 'सर्वोदय समाज' स्वयं में कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह एक अत्यन्त ही मुक्त संस्था है। कोई भी व्यक्ति वह चाहे किसी राजनीतिक दल का ही सर्वोदय समाज का सदस्य बन सकता है, और न ही प्रशासनिक कर्मचारियों पर ही कोई प्रतिबन्ध है। वे भी इसके सदस्य बनने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण जो समाजवादी दलों के शीर्षस्थ एक सक्रिय सदस्य रहे हैं, अब दलीय पद्धति के कटु आलोचक हैं। "दलीय राजनीति का," श्री जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, "परम्परागत स्वभाव है। सत्ता के लिये उसमें सब तरह से निर्वल और दूषित कर देने वाले सघर्ष होते ही हैं, यही बात मुझे अधिक चिन्तित करने लगी। मैंने देखा घन सगठन और प्रचार के साधनों के बल पर विभिन्न दल कैसे अपने की जनता के ऊपर साद देते हैं, कैसे जनतन्त्र यथार्थ में दलीय-तन्त्र अपने क्रम से स्थानिक चुनाव समितियाँ और निहित स्थायों से सम्बद्ध गुटों का राज्य बन जाता है, किस प्रकार जनतन्त्र केवल मतदान में सिमित और सिक्कड़ कर रह जाता है"¹⁶ आज की दल पद्धति जनतन्त्र को अवास्तविक बना देती है।

सर्वोदय में दल पद्धति को लोकनीति और जनशक्ति के विकास में बाधक माना जाता है, सर्वोदय समाज की स्थापना में जो स्वतन्त्रता और अभिक्रम

15. जयप्रकाश नारायण, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, पृ. 45-46

16. जयप्रकाश नारायण, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, पृ. 46,

(initiative) की अत्यन्त आवश्यकता है, उसे दलीय पद्धति कुंठित कर देती है। "दलीय पद्धति लोगों को भेड़ों की स्थिति में ला देना चाहती है, जिनका एकाधिकार केवल नियत समय पर गड़ेरियो को चुन लेना है, जो उनके कल्याण की चिन्ता करेंगे।"¹⁷ इस प्रकार इस प्रणाली में स्वतन्त्रता का कहीं दर्शन नहीं होता। यह स्वराज्य स्थापित करने और अपनी व्यवस्था अपने आप सभालने में कभी भी सहायक नहीं हो सकती।

सर्वोदय की दल-विहीन विचारधारा लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अव्यावहारिक है, किन्तु भारत में कम से कम स्थानीय स्व-शासन सस्याओं के चुनावों में इसका प्रभाव अवश्य ही दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः भारत के सभी राजनीतिक दल यह स्वीकार करते हैं कि स्थानीय चुनावों में वे अपने प्रत्याशी खड़े न करें। कम से कम एक सीमित क्षेत्र में ही इस विचार को सैद्धान्तिक मान्यता तो मिली ही है।

लोकनीति

सर्वोदय आजकल की प्रचलित राजनीति में विश्वास नहीं रखता। सर्वोदयी चिन्तक आज की राजनीति को राज्य-सत्ता, पुलिस और सेना-सत्ता पर आधारित मानते हैं। "यह शास्त्र-सत्ता पर जीती है, कानून की छत्रछाया में बढ़ती है, धन-सत्ता के भरोसे चलती पनपती है और विज्ञान के जरिये विकसित होती है। परन्तु इतने साधनों से सज्जित रहने पर भी यह शत-प्रतिशत जनता को सुखी करने में अपने को असमर्थ पाती है।"¹⁸ आज नागरिक सम्प्रदाय और जाति से भिन्न नहीं है। वह सत्ता के लिये सारी शक्ति खर्च कर देता है। सर्वोदयी ऐसी राजनीति का समर्थक है जो दल और सत्ता से मुक्त हो, जिसे विनोबा भावे 'लोकनीति' कहते हैं। राजनीति और लोकनीति में व्यापक अन्तर है। इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रमुख सर्वोदयी विचारक श्रीकृष्णदत्त भट्ट ने लिखा है:—

"राजनीति में जहाँ शासन मुख्य है, वहाँ लोकनीति में अनुशासन; राजनीति में जहाँ सत्ता मुख्य है, वहाँ लोकनीति में स्वतन्त्रता। राजनीति में जहाँ नियन्त्रण मुख्य है, वहाँ लोकनीति में संयम, राजनीति में जहाँ सत्ता व अधिकारों की स्पर्धा मुख्य है, वहाँ लोकनीति में कर्तव्यों का आचरण। सर्वोदय का क्रम यही है कि शासन से अनुशासन की ओर, सत्ता से स्वतन्त्रता की ओर, नियन्त्रण से संयम की ओर और अधिकारों की स्पर्धा की ओर से कर्तव्यों के आचरण की ओर बढ़े।"¹⁹

क्या संसद द्वारा लोकनीति सम्भव है? गांधीवादी परम्परा का पालन करते हुए सर्वोदयी चिन्तक संसद और आधुनिक प्रतिनिधि प्रणाली के विरुद्ध हैं। वे सम-

17. उपरोक्त, पृ. 47.

18. दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन, श्री कृष्णदत्त भट्ट द्वारा लिखित आमुख, पृ. 90.

19. उपरोक्त, पृ. 90.

सते हैं कि सर्वोदय क्रान्ति सत्सद के द्वारा सम्भव नहीं है क्योंकि इसमें जिस प्रकार के प्रतिनिधि होते हैं तथा इनकी जो कार्य-शक्ति है वह समदीय सस्थाओं की क्रान्ति के बिलकुल ही अनुपयुक्त बना देती है।

लोकनीति में सरकार को नहीं जनता को प्राथमिकता और प्रमुखता दी जाती है। लोकनीति की स्थापना में सरकार किसी भी तरह सहायक नहीं हो सकती। यह तो केवल अ-माध्यम से ही सम्भव है। एक प्रवचन में विनोबा भावे ने कहा है—

“सरकार इस कार्य में कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार सरकार एक बाल्टी (bucket) जैसी है, जबकि जनता एक कुएँ के समान है। यदि कुएँ में ही पानी नहीं होगा, तो बाल्टी में वहाँ से आयेगा। हम सीधे पानी की स्रोत-अर्थात् जनता—तक जायेंगे। जो कार्य सरकार नहीं कर सकती, वह जनता कर सकती है।”²⁰

विकेन्द्री व्यवस्था

सर्वोदय के अन्तर्गत तत्कालीन व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्री व्याख्या का समर्थन किया जाता है। श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने ग्रन्थ—“भारतीय राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना के कुछ सुझाव”—में विकेन्द्री व्यवस्था की व्याख्या की है। वे गांधीजी के शब्द उद्धृत करते हुए कहते हैं—

“मानवीय जगत असंख्य देहातों के व्यापक होते चले जाने वाले बतुं लों से सम्पन्न सागर के समान रहेगा। यह रचना पिरामिड जैसी चौड़े आधार पर चोटी तक चढ़ती जाने वाली नहीं रहेगी। इसका केन्द्र रहेगा व्यक्ति, जो देहात के लिए भर मिटने को तैयार होगा। हर देहात देहातों के समूह के हित के लिए अपना स्वार्थ पीछे रखेगा और इसी तरह आखिर तक सम्पूर्ण मानव-समाज व्यापक इकाइयों का बनता चला जायगा।”²¹

इन इकाइयों को जोड़ने वाली कठियाँ भी रहेंगी। लेकिन इनकी हर क्षेत्र में एवता आवश्यक नहीं। इस समाज-व्यवस्था का आदर्श होगा—“आवश्यक बायतों में एवता, शकापूर्ण अवस्था में आजादी और सभी व्यवहारों में त्रितिष्ठा।”²²

सर्वोदयी समाज किसी प्रकार की धार्मिक केन्द्रीयता पर आधारित नहीं होगा। तथाकथित लोकतान्त्रिक राष्ट्रों में जो केन्द्रस्थ महाकाय यत्नों के बन्धों पर चढ़ी हुई अर्थ व्यवस्था है उसने शुरू से आज तक गरीबों या गरीब देशों का शोषण ही किया है।²³ सर्वोदय में विनेन्द्रितता निहित है। राक्षसी केन्द्रित उत्पादन के बदले पर-

20. *Ureshi Sambhara, Vinoba's New Mission* p. 170

21. उद्धृत, इन्दु टिवेकर, क्रान्ति का समग्र दर्शन, पृ 41.

22. उपर्युक्त, पृ 41.

23. इन्दु टिवेकर, क्रान्ति का समग्र दर्शन, पृ 42

हर व्यापक क्षेत्र में लाखों लोग उत्पादन कार्य करें, यह उनको दृष्टि है। सर्वोदय व्यवस्था राज्य समाजवाद नहीं जन समाजवाद होगा।

आजकल प्रचलित विकेंद्रित राजनीति को सर्वोदयी विचारक मान्यता नहीं देते। आधुनिक राज्य में सत्ता का प्रान्तों, जिलों, नगरपालिकाओं, ग्राम-पंचायतों में वितरण तो किया जाता है, लेकिन सत्ता का केन्द्र पहले जैसा ही सबल बना रहता है। इसके अलावा जिन-जिन क्षेत्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया है, वे सभी क्षेत्र अपने लिये एक छोटा-छोटा राज्य बना लेते हैं। आज की विकेंद्रित राजनीति में हर एक व्यक्ति का अपना-अपना क्षेत्र और अपनी-अपनी सत्ता का छोटा मोटा केन्द्र है। यह न तो विकेंद्रीकरण है और न लोक सत्ता।

एक अन्तिम उद्देश्य के रूप में सर्वोदयी सभी प्रकार के सत्ता-केन्द्र, दलगत राजनीति आदि को समाप्त कर वर्ग-विहीन, शोषण-विहीन और राज्य-रहित समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इस व्यवस्था में प्रशासन कम होता चला जाये, अनुशासन बढ़ता चला जाये और अन्त में केवल स्व-शासन रह जाये। इस व्यवस्था में व्यक्तियों का नहीं, वस्तुओं का नियन्त्रण होगा। इस आदर्श की अभिव्यक्ति थी जयप्रकाश नारायण ने निम्नलिखित शब्दों में की है:—

सर्वोदय की भी एक राजनीति है; किन्तु यह राजनीति भिन्न प्रकार की है। मैंने इसको 'जुनवा की राजनीति' कहा है, जो सत्ता और दल की राजनीति से सर्वदा पृथक है। लोकनीति राजनीति से पृथक है। सर्वोदय की राजनीति में कोई दल नहीं होता और न सत्ता से ही उसका कोई सम्बन्ध होता है। वस्तुतः इसका लक्ष्य सत्ता के समस्त केन्द्रों को समाप्त कर देना है। जितनी अधिक यह नयी राजनीति बढ़ेगी, उतनी ही अधिक पुरानी राजनीति सिकुड़ेगी। सही अर्थ में यही होगा, राज्य का क्षय।¹²⁴

जन-शक्ति

भूदान तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के पीछे एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सर्वोदय में राज्य तथा शक्ति को वैसे ही मान्यता प्रदान नहीं की गई है। जब राज्य का क्षय प्रारम्भ होगा तथा किसी भी प्रकार की शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी, उस समय सब कुछ व्यक्तियों की नैतिक शक्ति पर निर्भर करेगा, व्यक्तियों को इस स्थिति के लिए जागृत करना होगा। रचनात्मक कार्यों के पीछे सर्वोदयी कार्यकर्ताओं का यह उद्देश्य है कि देश में 'स्वतन्त्र जनशक्ति' (self-reliant power of the people) का निर्माण किया जाय ताकि व्यक्तियों में 'विचार शासन' और 'कलंब्य विभाजन' का पूर्ण विकास हो जाय। विचार शासन का तात्पर्य शान्तिपूर्ण उपायों से दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित कर कार्य करने की प्रेरणा

देना है। कर्तव्य विभाजन का अर्थ है कि व्यक्ति बिना प्रशासन की सहायता के अपने-अपने कार्यों का विभाजन स्वयं ही कर ले। जब ऐसी जनशक्ति का निर्माण हो जायगा तब वर्ग-विहीन और शोषण-मुक्त समाज की रचना अधिक सम्भव हो जायगी।²⁵

‘जय हिन्द’ से ‘जय जगत’ की ओर

सर्वोदय विचारधारा का क्षेत्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं, यह विश्व की विचारधारा है। सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति इसका लक्ष्य है। “मानवमात्र एक प्रावृत्तमुदाय का अंग है। धर्म, जाति, वंश, लिंग, राष्ट्र, विचार आदि की विभिन्नताएँ मानव को मानव से अलग नहीं कर सकती। मानवता सब में समान है। इसलिये व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अधिकार हर एक को है। व्यक्ति-व्यक्ति के विकास में कोई विरोध नहीं है। वस्तुि सम्पूर्ण मानव-जाति का समग्र विकास और उत्थान अविभाजित एवं एकात्मकस्वरूप है।”²⁶ इस प्रकार सर्वोदय आन्दोलन का विश्वव्यापी होना स्वाभाविक ही है। एक देश में सर्वोदय तथा दूसरे में दमन एवं शोषण असह्य है।

सर्वोदय के अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष पर विचार व्यक्त करते हुए विनोबा भावे ने कहा कि दुनिया में वेग से विचार आगे बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे सभी देशों की सरहदें टूटने वाली हैं। अब विश्व को सम्मिलित परिवार बनाने की भावनाएँ बढ़ रही हैं।²⁷ इसी तत्व को श्री जयप्रकाश नारायण ने इस प्रकार व्यक्त किया है :—

“सर्वोदयी विश्व समाज में वर्तमान राष्ट्रों के क्रम से बने हुये राज्यों का कोई स्थान नहीं होगा। सर्वोदय-दृष्टि विश्व दृष्टि है और गांधीजी के समुद्रीय बतुल के केन्द्र में खड़ा हुआ व्यक्ति विश्व-नागरिक है।”²⁸

सर्वोदय का रचनात्मक पक्ष

क्रान्ति पद्धति

वर्ग-विहीन, शोषण-विहीन तथा राज्य-रहित सर्वोदयी समाज की स्थापना के लिये नवीन कार्य पद्धतियों का विशेष महत्व है। सर्वोदयी कार्य-पद्धति हिंसात्मक साधनों के विरुद्ध होने के साथ कानून की उपादेयता में भी आस्था नहीं रखती। वे कानून को भी एक प्रकार से बल प्रयोग ही समझते हैं। सर्वोदयी विचारधारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ऐसे साधनों का समर्थन करती है जिससे मनुष्य के जीवन में क्रान्ति आये, उसका हृदय परिवर्तन हो तथा अन्त में सर्वोदयी क्रान्ति के लिये मार्ग प्रशस्त हो सके। सर्वोदयी विचारकों का कहना है कि जय

25 Suresh Rambhai, Vinoba and His Mission, p 106, 171-79

26 इन्दु टिकेकर, क्रान्ति का समग्र दर्शन, पृ. 4.

27. विनोबा : व्यक्तित्व और विचार, पृ. 351.

28. जयप्रकाश नारायण, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, पृ. 59.

तक मनुष्य का हृदय नहीं बदलता, जीवन के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता, तब तक कोई स्थायी क्रान्ति नहीं हो सकती। डा. राधाकृष्णन् के शब्दों में "आचार्य विनोबा भावे ने जंगल के कानून को टुकरा दिया। उन्होंने असेम्बली के कानून तक का सहारा नहीं लिया बल्कि प्रेम के कानून के ऊपर उन्होंने अपनी श्रद्धा आधारित की है और यह प्रेम का ही कानून सबसे ऊँचा है।"²⁹

शान्ति सेना

सत्याग्रह चलाने के लिये महात्मा गांधी ऐसे स्वयं-सेवकों के दल का निर्माण करना चाहते थे जो सत्य और अहिंसा पर स्वयं को न्यौछावर करने के लिये सदैव तत्पर रहें। यही शान्ति सेना के गठन का आधार था। यह कहना सम्भव नहीं कि शान्ति सेना का निर्माण कब हुआ तथा इसका संगठन किस प्रकार का है। किन्तु सर्वोदय समाज के सभी सदस्य एक प्रकार से शान्ति सेना के सदस्य हैं। गांधीजी के सत्याग्रही सहयोगी, विनोबा भावे के भूदान कार्यकर्त्ता सभी शान्ति सैनिक हैं।

शान्ति सेना का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान शान्ति, प्रेम, अहिंसा द्वारा करना है। दुर्गुणों पर प्रेम द्वारा विजय प्राप्त कर सर्वोदयी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में प्रमुख योगदान देते हैं। दुर्दान्त निर्दयी डाकुओं पर सरकार की शक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकी। यह शान्ति सेना द्वारा ही सम्भव हो सका। जहाँ-जहाँ सरकार ने मद्य निषेध को समाप्त करने का प्रयत्न किया है वहीं-वही शान्ति सैनिक अड़ गये हैं। इस प्रकार देश की समस्याओं और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शान्ति सेना की अपनी ही पद्धति है।

भूदान (भूमिदान) आन्दोलन

सर्वोदय क्रान्ति के लिये भूदान सबसे महत्वपूर्ण आधार-आन्दोलन है। भूदान का प्रारम्भ अप्रैल 1951 में आन्ध्र प्रदेश के पञ्चमपल्ली (तेलंगाना) स्थान से हुआ। यहाँ कुछ हरिजन आचार्य विनोबा भावे से मिलने आये और उन्हें अपनी भूमिहीनता की कठण कहानी सुनाई। उन्होंने विनोबा भावे को बतलाया कि यदि उन्हें 80 एकड़ भूमि मिल जाती है, तो वे भूमि पर श्रम कर अपनी जीविका-अर्जन कर सकते हैं। विनोबा भावे ने उसी समय उपस्थित जन-समूह से पूछा कि क्या कोई 80 एकड़ भूमि दे सकता है? उसी समय पञ्चमपल्ली के श्री रामचन्द्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि के दान की तत्काल घोषणा की। यह सबसे पहला भूमिदान था। यही से भूदान आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ। इसके बाद तो भूदान ने एक गति पकड़ ली। दो वर्ष में लगभग 27,63,000 एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त हुई।

देश में भूमिहीनों की समस्या सुलझाने के लिए विनोबा भावे ने पांच करोड़

एकड़ भूमि के दान प्राप्त करने की योजना बनाई। ये देश के विभिन्न भागों में पद-यात्रा करते हुए अपने साथियों के साथ जाते हैं, वहाँ सर्वोदयी विचारधारा से व्यक्तियों को अवगत कराते हैं तथा भूमिदान के लिए आग्रह करते हैं। इस सम्बन्ध में विनोदा भावे को काफी सफलता मिली है।

भूदान सफलता की समीक्षा निम्नलिखित आंकड़ों से हो सकती है।

1. भूदान में प्राप्त भूमि	41, 76, 814. 93 एकड़
2. भूदान देने वाले व्यक्तियों की संख्या	5. 75, 88
3. वितरित भूमि	11, 75, 848. 13 एकड़
4. व्यक्तियों की संख्या जिन्हें भूमि वितरित की गई	4, 61, 681
5. वितरण के लिए अनुपयुक्त भूमि	18, 54, 882, 17 एकड़
6. भूमि जिसका वितरण शेष है	11,46,094, 63
7. दान में प्राप्त ग्रामों की संख्या	1, 68, 108
8. दान में प्राप्त जिलों की संख्या	47

(उपर्युक्त आंकड़े—Sunday World—October 1, 1972. में सुरेश राम के एक लेख—Sarvodaya Promise and Performance—पर आधारित हैं।)

भूदान को सर्वोदयी समाज की स्थापना में जो प्राथमिकता दी गई है उसके निम्नलिखित कारण हैं—

प्रथम, कृषि प्रधान देश में समाज परिवर्तन का आरम्भ भूमि की व्यवस्था से होता है।

द्वितीय, सर्वोदयी चिन्तकों का कहना है कि आज विश्व का जैसा रुख है उससे स्पष्ट है कि आगे की अर्थ-रचना अन्न-प्रधान और कृषि-प्रधान होने वाली है।

तृतीय, भूमि केवल अन्न उत्पादन का ही साधन नहीं है, यह वसुधैव कुटुम्बकम् भी है, समस्त धर्मों भूमि के नीचे है इस प्रकार बहुत सी वस्तुएँ मनुष्य को भूमि से ही उपलब्ध होती हैं। इसलिए क्रांति का प्रारम्भ भूमि से ही होना चाहिए। भूदान का तात्पर्य केवल स्वामित्व में ही परिवर्तन करना नहीं है, इसके माध्यम से स्वामित्व के मूल आधार और उत्पादक की भूमिका में परिवर्तन करना है। भूदान दर्शन के अन्तर्गत भूमि निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती। भूमि समस्त समाज की है। एक व्यक्ति को केवल उतनी ही भूमि रखनी चाहिए जितनी की उसे आवश्यकता है तथा जिस पर वह स्वयं श्रम कर सकता है। आवश्यकता से अधिक भूमि समाज को सौटानी चाहिए। जो भी भूमि व्यक्ति अपने पास रखता है, उस पर भी उसका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। उसे वह भूमि एक ट्रस्टी के रूप में अपने पास रखनी चाहिए।

सर्वोदय एक गतिशील (dynamic) विचारधारा है। भूदान आन्दोलन के प्रारम्भ होने के बाद देश के समक्ष जैसे-जैसे आर्थिक, सामाजिक समस्याएँ आती गयीं, सर्वोदय के स्वरूप की भी एक-एक पसुड़ी खुलती गयी। शनैः शनैः सर्वोदय के तत्वावधान में और भी कई कार्यक्रम अपनाये गये जैसे सम्पत्ति-दान धन-दान, बुद्धि-दान, जीवन-दान आदि। इनके अलावा सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओं ने मद्य-निषेध प्रचार तथा चम्बल घाटी में वर्षों से पले हुए दस्यु डाकुओं के हृदय परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है।

सम्पत्तिदान

भूदान से भूमिहीनों के लिये कुछ भूमि का प्रवन्ध तो हो सकता था, किन्तु इन भूमिहीन निर्धनों को खेती से सम्बन्धित सामग्री खरीदने के लिये कुछ आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता प्रतीत हुई। इसलिये विनोबा भावे ने सम्पत्तिदान प्रारम्भ किया। इसका उद्देश्य है कि सम्पत्तिवान् व्यक्ति कुछ धन दे, जिसे भूमिहीनों को भूमि देते समय दिया जाय, ताकि वे उस भूमि का उपयोग कर सकें।

भूदान की भांति सम्पत्ति-दान में भी विनोबा भावे छठा भाग मांगते हैं। यह भी वह दान देने वाले की स्वेच्छा पर छोड़ते हैं कि वह किस प्रकार अपनी सम्पत्ति के छठे भाग का दान करता है। विनोबा जी सम्पत्ति दान लेकर फिर निर्धनों में वितरित ही नहीं करना चाहते, उनका कहना है कि लोग अपनी सम्पत्ति या आय का छठा भाग समाज को दान करने का संकल्प लें, हर वर्ष उस राशि को समाज हित में व्यय करें तथा उसकी सूचना विनोबा जी को देते रहे। विनोबा भावे ने सम्पत्ति दान का समर्थन इस आधार पर भी किया है कि इससे लोगों में अस्तेय तथा अपरिग्रह की भावना का विकास हो जो व्यक्ति के कल्याण के लिये अति आवश्यक है।

ग्रामदान एवं ग्रामराज

भूदान का अगला कदम ग्रामदान है। ग्रामदान का अर्थ है ग्राम की सम्पूर्ण भूमि को अपने ही गाँव या पूरे समुदाय को सौंपना। लोग अपनी भूमि का सर्वस्व ही दान करें, तदुपरांत उसका प्रयोग, व्यवस्था एवं लाभ का वितरण पूरे गाँव में किया जाये।

ग्रामदान का प्रारम्भ 1952 में उत्तर प्रदेश के मानग्रोथ ग्राम के समस्त निवासियों द्वारा ग्रामदान करने के साथ प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे ग्रामदान की भावना ने लोगों को प्रभावित किया और चार वर्षों में ही 1500 ग्राम दान में प्राप्त हुए। अभी तक लगभग 1,68,108 ग्राम दान में प्राप्त हो चुके हैं।

ग्रामदान सर्वोदयी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये एक महत्वपूर्ण साधन है। सर्वोदय विचारधारा के अन्तर्गत ग्रामराज की स्थापना मूल लक्ष्य है। यह ग्राम दान

से ही सम्भव हो सकता है। इसका तात्पर्य होगा कि ऐसे ग्रामों की व्यवस्था व्यक्ति स्वयं करें, ग्राम की उन्नति के सम्बन्ध में निर्णय गांव द्वारा ही लिया जाय न कि सरकारी आदेश के माध्यम से। ग्राम स्वराज्य की स्थापना से लोगों में सहयोग, प्रेम की भावना का विकास होगा। इसके पीछे यह भावना है कि व्यक्तिगत भावना का अंत हो तथा पूरा ग्राम एक परिवार के रूप में रहे। जब इस प्रकार के स्वशासन की भावना का विकास कम चलेगा तो अंत में वर्ग विहीन, शोषण विहीन तथा राज्य विहीन समाज की स्थापना अधिक सुलभ हो जायेगी।

दान में प्राप्त ग्रामों की व्यवस्था के विषय में आचार्य विनोबा भावे के निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हैं —

प्रथम, प्रत्येक ग्राम, ग्राम सभा संगठित करे जिसका प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष सदस्य हो।

द्वितीय, ग्राम के सभी भूमिपति अपनी भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा को हस्तांतरित करें।

तृतीय, प्रत्येक भूमिपति अपनी भूमि का धारक भाग ग्राम सभा को दान में दें ताकि उसका वितरण उस ग्राम के भूमिहीनों में किया जा सके।

चतुर्थ, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम कोष की स्थापना हो जिसमें प्रत्येक भूमिपति अपनी उत्पत्ति का एक चौथाई भाग तथा धेनन या मजदूरी प्राप्त करने वाला एक दिन का धेनन या आमदनी का तीसवा हिस्सा उसमें जमा करें। यह राशि ग्राम व्यवस्था के लिये काम में आवेगी।

यह ग्रामदान में प्राप्त ग्रामों की आदर्श व्यवस्था की रूपरेखा है, जो व्यक्तियों को ग्रामदान के लिये और भी आकर्षित करने में समर्थ होगी।

जीवनदान

वे व्यक्ति जिनके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे समाज के लिये अर्पण कर सकें, ऐसे व्यक्ति सर्वोदय-साधना के लिये अपना जीवनदान कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवनदान करने वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि, श्रम और शक्ति का प्रयोग भूदान एवं सर्वोदय की सेवा में लगा सकते हैं। इसके अलावा वे व्यक्ति जो सर्वोदय के लिये अधिक करना चाहते हैं अपना जीवनदान कर सकते हैं। सर्वप्रथम श्री जयप्रकाश ने अप्रैल 1954 में अपना जीवनदान दिया। तत्पश्चात् विनोबा जी ने भी 'भूदान यज्ञमूलक ग्रामोद्योग प्रधान आर्थिक क्रांति के लिये' अपना जीवन समर्पण कर दिया। इस प्रेरणा से अनेक सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओं ने अपने जीवनदान की घोषणा की।

सर्वोदय समीक्षा

उपरोक्त अद्ययन से स्पष्ट है कि सर्वोदय गांधीवाद का विकसित सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष है। इसलिए गांधीवाद के विषय में सामान्यतः जो आलोचना की जाती है वह सर्वोदय के विषय में भी यही है। सर्वोदय दर्शन का दोष यह है कि यूटोपियायी विचारकों की भाँति यह मानव स्वभाव के नेबल स्वच्छ पक्ष को ही देखता है, जब की मनुष्य सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का मिश्रण है।

सर्वोदय दर्शन आदर्शवादी और काल्पनिक सा प्रतीत होता है। इसमें बहुत सीमा तक व्यावहारिकता का अभाव है। राज्य में ग्रामराज, विकेंद्रोकरण आदि विचारों को पूर्णतः व्यावहारिक रूप नहीं दिया जा सकता।

सर्वोदय विचारधारा का दमन राजनीति में विरवास नहीं है। आदर्श रूप में यह ठीक है, किन्तु आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालियों में राजनीतिक दलों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक व्यवस्था को गतिशील बनाने हैं। वास्तव में राजनीतिक दल के अभाव में लोकतान्त्रिक व्यवस्था चल ही नहीं सकती।

सर्वोदय चिन्तक इस विचारधारा को पूर्णतः काल्पनिक नहीं मानते। उनका दावा है कि इसको व्यवहार में लाया जा सकता है। सर्वोदयी विचारक श्री कृष्णदत्त भट्ट ने लिखा है "कि सत्रवा उदय कोरा स्वप्न, कोरा आदर्श नहीं है, वह आदर्श व्यवहार्य है वह अमल में लाया जा सकता है। सर्वोदय का आदर्श ऊँचा है, यह ठीक है; परन्तु न तो वह अप्राप्य है और न असाध्य है। वह प्रयत्न साध्य है।"³⁰

यद्यपि यह भी मान लिया जाये कि सर्वोदय में आदर्श की मात्रा अधिक है, किन्तु सर्वोदय दार्शनिक, सर्वोदय आदर्श की स्वयं ही उच्चता एवं पूर्णता प्रदान करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक सही आदर्श प्रस्तुत करना भी महत्वपूर्ण है। विनोबा भावे जीवन के सभी अंगों में गणित की अचूकता पसन्द करते हैं। बीसे श्रुति करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, लेकिन जब आदर्श श्रुतिपूर्ण होता है, तो कर्म का भूषण करने की गुंजाइश ही समाप्त हो जाती है। मकान खड़ा करने में चूक हो सकती है, लेकिन 'ब्लू प्रिन्ट' तो सदैव अचूक ही होना चाहिए।³¹

भूदान आन्दोलन के विषय से भी लोगों को शंकाएँ हैं। भूदान के आधार पर लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। भूदान आन्दोलन को लगभग बीस वर्ष हो चुके हैं, किन्तु भूमि समस्या में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज सरकार भूमि तथा शहरी सम्पत्ति की सीमा का भी निर्धारण कर रही है। यह भी सत्य है कि भूदान के अन्तर्गत कई स्थानों पर इस प्रकार की भूमि प्राप्त हुई है जो खेती के योग्य नहीं है। ऐसी भूमि को खेती के योग्य बनाया गया

30. दादा धर्माधिकारी, सर्वोदय दर्शन, पृ० 6.

31. इन्द्र टिक्केकर, ज्ञान्ति का समय दर्शन, पृ० 16.

सिचाई व्यवस्था का प्रबन्ध करना ही एक समस्या है यद्यपि भूदान द्वारा भूमि सम्बन्धी सुधार उतने व्यापक न भी हो सके, पर इतमे सन्देह नहीं कि भूमि के व्यापक एवं दूरगामी सुधारों के लिए यह आन्दोलन सहायक सिद्ध होगा।

भूदान आन्दोलन भारतीय जीवन पद्धति में निहित है। इसने अनुसार सामाजिक व्यवस्था परिवार का ही एक वृद्ध रूप है इस आन्दोलन के द्वारा यह अभिव्यक्ति होती है कि आध्यात्मिक स्वतन्त्रता केवल उन्हीं द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जो भौतिक जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं।³²

भूमिदान एवं ग्रामदान आन्दोलन के पीछे निहित विचार से सरकार को भी सहायता मिलती है। इस योगदान के विषय में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो इस आन्दोलन का निकला है वह उसके द्वारा निर्मित वातावरण का है, जो भूमि व्यवस्था सुधार के लिए कानून बनाने में सहायक होना है, क्योंकि उस विषय में लोगों के मानस की ही बदलना है। कानून भूमि-सुधार के लिए आवश्यक है, लेकिन जनता के मानस को बदलना मूलतः उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।³³

सर्वोदयी शांति सेना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कुख्यात डाकुओं के हृदय परिवर्तन करने का है। 1960 में आचार्य विनोबा भावे के प्रयत्नों से अनेक खूबवार डाकुओं ने समर्पण किया। इसी प्रकार अप्रैल 1972 में श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य सर्वोदयी कार्यकर्ताओं की प्रेरणा और प्रयासों से बम्बल घाटी के दो सौ से भी अधिक डाकुओं ने अंतिम समर्पण कर शान्ति एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। यह हृदय परिवर्तन का सफल प्रयोग है। सम्भवतः इस प्रकार के उदाहरण मिलना असम्भव है।

सर्वोदय का अर्थ केवल विचार-क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। साहित्य क्षेत्र भी उनका आभारी है। सर्वोदय साहित्य में हिन्दी भाषा के उत्तम से उत्तम शब्द देखने को मिलते हैं। मूल विचारों की प्रामाणिक एवं आकर्षित शब्दों में सवारने की प्रतिभा सर्वोदय साहित्यकारों में अद्वितीय है। सम्भवतः हिन्दी साहित्यकारों ने हिन्दी भाषा की उत्तरी सेवा नहीं की जितनी आज सर्वोदय साहित्य कर रहा है। सर्वोदय साहित्य में भारतीयकरण की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है।

सर्वोदय का अन्त्युदय किसी वाद की प्रतिन्या के रूप में नहीं हुआ। यह किसी वाद की प्रतिक्रिया नहीं। जिन वादों का जन्म प्रतिक्रिया स्वरूप होता है वे न तो स्थायी होते हैं और न गतिशील। उनमें कोई विचरतन मूल्य नहीं होता। सर्वोदय "भारत का अपना शब्द है और भारत की अपनी वस्तु है, पर ऐसा शब्द और ऐसी

32. Radhakrishnan, S, Forward to Vinoba Bhave and His Mission, by Suresh Ramabhai, p VI

33 उद्धृत, विनोबा व्यक्तित्व और विचार, पृ. 29.

वस्तु नहीं, जो दूसरे किसी देश या काल में लागू न हो सके। देश-काल-परिस्थिति के भेदानुसार उसकी बाह्य पद्धति में फर्क होता रहेगा। लेकिन उसका घातक रूप शाश्वत रहेगा।³⁴

सर्वोदय एक अराजनीतिक संस्था है, अराजनीतिक विचारधारा नहीं। वास्तव में सर्वोदय को दसगत राजनीति से, नीचे नहीं, ऊपर रहना चाहिये। सर्वोदय साहित्य का अध्ययन करने तथा सर्वोदय सेवकों से मिलने पर आभास होता है कि ये राजनीति से दूर भागते हैं उतना इन्हें भागना नहीं चाहिये। गांधीजी ने राजनीति को एक सर्प-कुंडल की सजा दी थी और कहा था कि परिस्थितियोंबश वे उससे संघर्ष करेंगे। उन्होंने जिन राजनीतिक बातों को उचित नहीं समझा, उनका प्रतिरोध कर मार्ग दर्शन भी किया। सर्वोदय चिन्तन में भी हमें इस प्रतिरोध वाली भावना को नहीं छोड़ना चाहिये। आज हमारे देश की राजनीति में कई विराट कुरीतियाँ एक सौत की तरह वेशर्मा और मजबूती से झुझा बनाये बैठी हैं। आज के राजनीतिज्ञ इन कुरीतियों को आश्रय दिये हुए हैं। सर्वोदय के अन्तर्गत इस कुरीतियों को दूर करने के लिए आदर्श प्रस्तुत करना, हृदय-परिवर्तन करना आदि ही सब कुछ नहीं है। इन कुरीतियों का प्रतिरोध भी करना चाहिये। यह प्रतिरोध दसगत राजनीति से भी सम्बन्धित नहीं होगा। उदाहरणार्थ हमारे राजनीति तथा जीवन प्रशासन में भ्रष्टाचार ने कई रूप धारण कर लिये हैं। इसे दूर करना राजनीतिज्ञों के वश की बात नहीं। सर्वोदय को इस भ्रष्टाचार रूपी सर्प से जूझना चाहिये अन्यथा यह सर्प सर्वोदय को भी निगल जायेगा। यह सब कुछ दसगत राजनीति से अलग रह कर भी हो सकता है। यदि सर्वोदय समाज यह कार्य नहीं कर सकता तो फिर राजनीति का शुद्धिकरण एवं आध्यात्मिकीकरण भी नहीं हो सकता।

बिहार और सर्वोदय आन्दोलन

उपर्युक्त शब्द 1972 के मध्य में लिखे गये थे। उस समय सर्वोदय आन्ति में लगभग गिरिलता या चुकी थी। सर्वोदय आन्ति को एक नवीन चेतना एवं कार्य-क्रम देने के 1973 के मध्य में सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन भविष्य के कार्य-क्रम की कोई नवीन योजना निश्चित नहीं कर सका। इसी समय देश की आर्थिक-राजनीतिक स्थिति ने सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं, विशेषतः श्री जयप्रकाश नारायण, को सर्वोदय आन्दोलन को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान किया।

गुजरात विधान सभा को भंग कराने की सफलता के उपरान्त 1974 के प्रारम्भ में श्री जयप्रकाश नारायण तथा सर्वोदय कार्यकर्त्ताओं ने बिहार को अपने नवीन आन्दोलन का मुख्य स्थल बनाया। श्री जयप्रकाश नारायण का आन्दोलन

³⁴ जयप्रकाश नारायण, समाजवाद से सर्वोदय की ओर, विनोबा भावे द्वारा

राजनीतिक प्रशासनिक घ्रष्टाचार, जमाखोरी, काला-बाजारी, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने चुनाव प्रणाली के दोषों को दूर करने, राजनीतिक जीवन के शुद्धीकरण तथा बिहार विधान सभा को भंग करना आदि को लेकर प्रारम्भ किया गया। इन आन्दोलन का लगभग वही स्वरूप है जो स्वतन्त्रता के पूर्व स्वाधीनता आन्दोलन का था। श्री जयप्रकाश नारायण के अनुसार यह आन्दोलन बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा, देश के समस्त भागों में इसका विस्तार किया जायेगा। इस आन्दोलन के पीछे निहित विचार श्री जयप्रकाश नारायण ने कई बार समय-समय पर प्रस्तुत किये हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण देश के शीर्षस्थ नेता हैं। स्वाधीनता आन्दोलन में उनका योगदान, उनका त्याग, सत्ता से दूर रहकर उनकी जनसेवा सर्वविधित है। इसके प्रतिरिक्त यह सभी जानते हैं कि श्री जयप्रकाश नारायण ने जिस आन्दोलन का प्रारम्भ किया है उसका उद्देश्य सुधारवादी है, स्वयं को सत्ता में लाना नहीं। उनकी नीयत पर किसी को अविश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री जयप्रकाश नारायण जो कुछ कहते हैं, चाहे हम उनके विचारों से सहमत हो या न हो, उन पर ध्यान देना आवश्यक है। सभी विवेकशील भारतवासी देश से इन सभी बुद्धियों का उन्मूलन करना चाहेंगे। इसलिए एक दृष्टि से यह आन्दोलन रचनात्मक है। किन्तु बिहार आन्दोलन के विषय में कुछ पक्षों का उल्लेख करना सामयिक होगा।

श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार विधान सभा को भंग करने की मांग एक विवाद बन गया है। यदि इस आन्दोलन की यह मांग पूरी होती भी है, तो इसके उपरान्त फिर अगला कदम क्या होगा? श्री जयप्रकाश नारायण ने लोकतन्त्र का कोई दूसरा स्वरूप व्यावहारिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। उनका दल बिहीन लोकतन्त्र अव्यावहारिक सा प्रतीत होता है तथा इस विचार को उगहोने न हो स्पष्ट किया और न विस्तृत रूप दिया है। फिर लोकतन्त्र की किसी अन्य व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय सहमति आवश्यक है। सर्वोदय दृष्टिकोण भले ही सही हो किन्तु इसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब तक किसी उचित विकल्प की खोज नहीं हो जाती प्रचलित व्यवस्था का विद्युत्तन करना उचित नहीं। श्री जयप्रकाश नारायण की अपना ध्यान एक सही विकल्प की खोज पर केन्द्रित करना चाहिए।

सर्वोदय कार्यकर्ताओं को अपने आन्दोलन के समर्थन में अग्र व्यक्तियों एवं राजनीतिक दलों से समर्थन प्राप्त करने में काफी संतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यदि असंतुष्ट राजनीतिज्ञ, सत्ता-लोलुप और निहित हित वाले व्यक्तियों का समर्थन स्वीकार किया जाता है तो इससे सर्वोदय आन्दोलन की प्रतिष्ठा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सर्वोदय आन्दोलन सर्वोदय कार्यकर्ताओं द्वारा ही संचालित होना चाहिए। इसे सत्ता संधर्ष का रूप ग्रहण करने से बचना चाहिए।

अपने इस आन्दोलन में श्री जयप्रकाश नारायण ने विद्यार्थियों को विशेष भूमिका निर्वाह के लिये आह्वान किया है। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा तथा शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कराने से सर्वोदय आन्दोलन में उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती। 1942 में स्वाधीनता आन्दोलन के समय विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार करने जैसा कार्यक्रम आज की परिस्थितियों में सामयिक नहीं है। विद्यार्थियों को अपने मूल शिक्षा-उद्देश्यों से विचलित नहीं करना चाहिये, विशेषतः निर्धन विद्यार्थियों पर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

जुलाई 11, 1974 को वर्षा आश्रम के निकट मधु सेवा संघ कार्यकारिणी ने बिहार आन्दोलन की समीक्षा की। बिहार आन्दोलन के प्रति सर्वोदय दृष्टिकोण विभाजित हो गया। परिणामस्वरूप कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों ने अपने पद त्याग का आग्रह किया। जुलाई 12, 1974 को सर्वोदय आन्दोलन को विपटित होने से बचाने के लिए सर्वसेवा संघ ने बिहार आन्दोलन का अनुमोदन कर दिया किन्तु माय हो साथ यह कहा गया कि यह आन्दोलन सत्य, अहिंसा पर ही आधारित हो।

बिहार आन्दोलन सर्वोदय के नवीन कार्य-क्रम की परीक्षा है। लगभग सम्पूर्ण देश की इस आन्दोलन पर दृष्टि लगी हुई है। यहाँ इसके घोरचित्य के विवाद में न पड़ते हुए इतना कहना आवश्यक है कि इस आन्दोलन में बढ़ती हुई महंगाई को रोकने, जीवन की मूल आवश्यकताओं को समाज के अन्तिम व्यक्ति तक उपलब्ध कराने, सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार की समाप्ति करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुुरुपयोग रोकने आदि के प्रति देश का ध्यान पूर्णतः आकर्षित किया है। स्वयं भारतीय कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी ने अगस्त 1974 में एक प्रस्ताव पास कर अपने सक्रिय सदस्यों की जमाखोरी, चोर बाजारी को रोकने तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए आह्वान किया है।

पाठ्य ग्रन्थ

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. दादा धर्माधिकारी, | सर्वोदय-दर्शन |
| 2. धवन, गोपीनाथ | सर्वोदय तत्त्व-दर्शन |
| 3. जयप्रकाश नारायण | समाजवाद से सर्वोदय की ओर |
| 4. शंकरराव देव | सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र |
| 5. Suresh Ramabhai, | Vinoba and His Mission. |
| 6. टिवेकर, इन्दु. | श्रुति का समग्र दर्शन |
| 7. बियोगी हरि, बनारसीदास, चतुर्वेदी, यशपाल जैन, आदि (सम्पादित) | विनोबा : व्यक्तित्व और विचार |

उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त गांधीवाद अध्याय से सम्बन्धित लगभग सभी ग्रन्थ सर्वोदय विचारधारा को समझने के लिए आवश्यक एवं उपयोगी हैं।

सम्प्रभुता एवं बहुलवाद

राजनीतिशास्त्र में सम्प्रभुता (Sovereignty) और बहुलवाद (Pluralism) विवाद का विषय रहे हैं। सम्प्रभुता को राज्य का अनिर्वायं तत्व माना जाता है जिसके बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी ओर बहुलवादी राज्य के इस सम्प्रभु तत्व से चौक जाते हैं या बौद्धता उठते हैं। बहुलवाद राज्य के स्वभाव में सुधार एक परिवर्तन चाहता है। यह राज्य का आलोचक है, उसे अपमानित करता है, राज्य को एक गौरवान्वित स्थिति से हटाने पर ध्यानस्थ स्तर पर लाना चाहता है। वास्तव में बहुलवादी जिम गॉर का इतना व्यापक विरोध करते हैं वह सम्प्रभु-सम्पन्न राज्य है जिसे वे एकत्ववादी अथवा अर्द्धतवादी राज्य (Monistic State) कहते हैं।¹ इसलिए बहुलवाद को समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले उस एकत्ववादी अथवा राज्य सम्प्रभु सिद्धान्त का अध्ययन किया जाय जिसके विरोध स्वरूप बहुलवाद का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ।

सम्प्रभुता का एकत्ववादी सिद्धान्त

Monistic Theory of Sovereignty

'सम्प्रभुता' अंग्रेजी शब्द सॉवरेण्टी (Sovereignty) का हिन्दी अनुवाद है। सॉवरेण्टी स्वयं लेटिन शब्द -*Superanus*- का पर्यायवाची है जिसका अर्थ 'सर्वोच्च सत्ता' है। राज्य की इसी सर्वोच्च सत्ता को सम्प्रभुता कहा गया है।

सभी राजनीतिशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि राजनीति शास्त्र में सम्प्रभुता का सिद्धान्त सम्भवतः सबसे अधिक विवादास्पद है, इसके विषय में एकमत होना सम्भव नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों ने सम्प्रभुता को स्पष्ट एवं परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। सम्प्रभुता के विषय में कुछ सामान्य परम्परागत परिभाषाएँ प्रायः देखने को मिलती हैं। बोदो (Jean Bodin) के अनुसार 'सम्प्रभुता नागरिकों तथा जनता पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कोई विधि बन्धन नहीं होता।' प्रासियस (Hugo Grotius) ने सम्प्रभुता को स्पष्ट करने के स्थान पर उसके निवास पर बल दिया है, सम्प्रभुता, राष्ट्रियता के अन्तर्गत, एक व्यक्ति में, अर्थात् सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिससे कार्य किसी अन्य पर आश्रित न हो तथा जिसकी इच्छा का अतिक्रमण न किया जा सके। ड्यूग्वी (Duguit) ने सम्प्रभुता को राज्य

¹ Hsiao, Kung Chuao, Political Pluralism, p 1

द्वारा आज्ञा देने वाली शक्ति कहा है जो राज्य के रूप में संगठित राष्ट्र की इच्छा है। यह राज्य द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत व्यक्तियों को निरंकुश आदेश देने का अधिकार है। एक अमरीकी विद्वान बर्गस (Burguess) के अनुसार सम्प्रभुता व्यक्तियों के समुदायों पर मौलिक, पूर्ण और असीमित शक्ति है। विलोबी (Willoughby) के मतानुसार सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। हार्वे वाकर (Harvey Walker) ने सम्प्रभुता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि "राजनीतिक दृष्टि से सम्प्रभुता अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत राज्य का एक तत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवहार में दूसरे राज्य के नियंत्रण या हस्तक्षेप के विरुद्ध यह राज्य की स्वतन्त्रता का गुण है।" 2 वास्तव में सम्प्रभुता राज्य द्वारा सर्वोच्च निर्णय निर्माण तथा निर्णयों को कार्यान्वित करने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग अन्तिम रूप में राज्य ही कर सकता है अन्य सामाजिक संस्थाएँ नहीं।

यदि विभिन्न परिभाषाओं का विवेचन किया जाय तो एक-बदादी सम्प्रभुता के विभिन्न लक्षण एवं पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं जो निम्नलिखित हैं:—

(1) निरंकुशता (absoluteness)—इसका तात्पर्य पूर्ण एवं निरंकुश सम्प्रभुता से है। सम्प्रभु के ऊपर किसी भी शक्ति या सत्ता का नियंत्रण नहीं हो सकता। निरंकुश सम्प्रभुता के दो पक्ष होते हैं—आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक दृष्टि से राज्य की सीमाओं के अन्तर्गत सम्प्रभु की शक्ति पूर्ण निरंकुश होती है। वह व्यक्तियों एवं समुदायों को आज्ञा दे सकता, उन पर अपनी इच्छा थोप सकता है, शक्ति द्वारा अपनी इच्छा को मनवा सकता है, उसके द्वारा बनाये गये कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। यदि कोई सीमाएँ होती हैं तो वे स्वयं के द्वारा ही निर्धारित की हुई होती हैं। बाह्य दृष्टि से राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति, संस्था या राज्य न तो उसे कोई आदेश दे सकता है और न नियंत्रण स्थापित कर सकता है। वह दूसरे राज्यों के साथ इच्छानुसार सम्बन्ध स्थापित करने में पूर्ण स्वतन्त्र होता है। सूक्ष्म में, राज्य के अन्दर न तो उसका कोई प्रतिद्वन्दी होता है और न बाह्य दृष्टि से उसके कार्यों को प्रतिबन्धित किया जाता है।

(2) सर्वव्यापकता (Universality or All-comprehensiveness)—राज्य के भीतर सम्प्रभु सत्ता सर्वव्यापी होती है। राज्य के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा सगठनों पर सम्प्रभु का नियंत्रण रहता है। उसकी शक्ति के परे कुछ नहीं होता। इस सम्बन्ध में केवल एक अपवाद है। प्रत्येक राज्य पारस्परिक समझौते तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टता के अन्तर्गत अन्य देशों से आये हुए राजदूतों तथा दूतावासी को विशेष सुविधाएँ एवं विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। इससे सम्प्रभुता की सर्वव्यापकता पर प्राच नहीं समझनी चाहिये।

५ स्थायित्व (Permanence)—सम्प्रभुता राज्य का स्थाई तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य और सम्प्रभुता की एक दूसरे के बिना बल्बना नहीं की जा सकती। सरकारों के परिवर्तन सत्राट आदि की मृत्यु से सम्प्रभुता का अन्त नहीं हो जाता।

६ अविभाज्यता (Indivisibility)—सम्प्रभुता एक पूर्ण एव समग्र तत्व है। इसका अर्थ है अधिक सम्प्रभुधारियों के मध्य विभाजन नहीं किया जा सकता। सम्प्रभुता के विभाजन का तात्पर्य सम्प्रभु सत्ता को नष्ट करना है। जैसा कि गेटल ने लिखा है कि यदि सम्प्रभुता का विभाजन कर दिया जाय तो एक से अधिक राज्यों स्थापित हो जायेंगे।³

७ अद्वेषता (Inalienability)—सम्प्रभुता को सम्प्रभु समाज से पृथक् नहीं किया जा सकता। सम्प्रभु शक्ति किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। सम्प्रभुता की तुलना शरीर में प्राण तत्व से की जा सकती है। प्राण तत्व के बिना शरीर मिट्टी रह जाता है उसी प्रकार यदि राजनीतिक समाज से सम्प्रभु जैसे मूल तत्व को निकाल दिया जाय तो राज्य सम्प्रभु नहीं रह सकता, उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जायगा। सम्प्रभुता का हस्तांतरण सम्भव नहीं क्योंकि वह राज्य के अस्तित्व का मूल एव सार है। स्वयं को नष्ट किये बिना राज्य सम्प्रभु तत्व से विनय नहीं हो सकता। राज्य द्वारा सम्प्रभुता से पृथक् करना आत्म-हत्या के समान है।

राज्य का यह सभ्रमु सिद्धान्त एकत्ववाद विद्वान् या राज्य सम्प्रभु सिद्धान्त (Monistic Theory of Sovereignty) के नाम से जाना जाता है। इसका तात्पर्य है कि किसी स्वतन्त्र समाज में राज्य की सत्ता ही सर्वोपरि होती है। राज्य की शक्ति निरंकुश एवं असीमित होती है। राज्य का नून का मूल एव प्रमुख स्रोत है। यह सिद्धान्त राज्य को समन्वय की ओर अग्रसर करता है जिसके अन्तर्गत राज्य जीवन के प्रत्येक पक्ष पर नियन्त्रण और हस्तक्षेप कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य पूर्ण स्वतन्त्र होना है तथा अन्य राज्यों के साथ अपने विवादों का समाधान करने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अन्य समुदाय अपने पारस्परिक विवादों के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते।⁴

डॉ० हितिसम्राओ के विचार में एकत्ववादी वह राज्य है जिसमें सत्ता का बवल एक ही स्रोत होता है जो सैद्धान्तिक रूप में सर्व-व्यापक एवं असीमित होता है। यह एकात्मक एवं निरंकुश शक्तिही 'सम्प्रभुता' (Sovereignty) कहलाती है तथा वह सिद्धान्त जो राज्य में इस प्रकार की सम्प्रभुता के अस्तित्व को स्वीकार करता है बहुसंवादिशो ने ऐसे राज्य को एकत्ववादी राज्य कहा है। मूढम में एकत्ववादी राज्य में एकात्मक तथा निरंकुश सम्प्रभु शक्ति निहित होती है जो राजनीतिक एवं वैध सत्ता का प्रत्यक्ष स्रोत होता है। ऐसे राज्य में सामान्यतः सम्प्रभु सत्ता का प्रयोग

³ Gettel, R. G., Political Science, p 95

⁴ डुवे, स., आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएँ, पृ. 298-99

एक उपकरण तथा एक व्यक्ति द्वारा (जैसा कि राजतन्त्र में) किया जाता है। किन्तु लोकतान्त्रिक तथा संघात्मक राज्य भी एकत्ववादी होते हैं जहाँ सम्प्रभु सत्ता का विभाजन विभिन्न अंगों में होता है।¹⁵

सम्प्रभुता सिद्धान्त का विकास

सम्प्रभुता सिद्धान्त का विकास प्राधुनिक युग में हुआ है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इसके पूर्व स्वतन्त्र और सम्प्रभु राज्य नहीं थे। प्राचीन तथा मध्य युग में सम्प्रभु-सम्पन्न राज्य की धारणा का अभाव था क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि प्राकृतिक नियम तथा साम्राजिक परम्पराएँ राज्य से स्वतन्त्र एवं ऊपर हैं। यूरोप में जैसे जैसे ईसाई धर्म का विकास होता गया तथा चर्च की सत्ता बढ़ती गयी राज्य की श्रेष्ठता की धारणा को कभी महत्व नहीं मिला। इसके प्रतिरिक्त सामन्तवादी व्यवस्था ने राज्य की शक्ति को विघटित एवं विभाजित रखा। इन कारणों से सम्प्रभुता का विचार पनप नहीं सका।

किन्तु धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन होने लगा। मध्य युग के उत्तरार्ध में चर्च सत्ता निर्बल होने लगी। शासन व्यवस्था पर चर्च की पकड़ कमजोर होती गयी। राज्य की स्थिति को भ्रम चर्च से स्वतन्त्र ही नहीं बल्कि चर्च को राज्य के अन्तर्गत स्वीकार किया जाने लगा। मध्य युग में प्रचलित सामन्तवादी व्यवस्था के विघटन तथा राष्ट्रीय राज्यों के प्रादुर्भाव से राज्य के अधिकारों में वृद्धि हुई। सोलहवीं शताब्दी में सम्प्रभु राज्य की धारणा को अमर्थन मिलने लगा। इस शताब्दी में सम्प्रभुता सिद्धान्त का प्रादुर्भाव सामन्तो, पोप तथा होलो रोमन सम्राट की अपेक्षा विभिन्न क्षेत्रीय सम्राटों के अधिकारों के अमर्थन में हुआ। अन्य शब्दों में, जैसे जैसे राष्ट्रीय राज्यों (Nation States) तथा राष्ट्रियता की भावना का विकास होता गया सम्प्रभुता के सिद्धान्त को बल मिलता गया। सत्रहवीं शताब्दी में सम्प्रभुता का सिद्धान्त एक राजनीतिक तथ्य बन गया।

बोदाँ हाँसराज्य 3118

सम्प्रभुता पर बोदाँ के विचार

सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त या अन्य शब्दों में राज्य-सम्प्रभुता के सिद्धान्त का प्रवर्तन बोदाँ और हाब्स ने किया तथा जिसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसिस के सम्प्रभु सिद्धान्त में मिलती है।

सोलहवीं शताब्दी में बोदाँ (Jean Bodin, 1530-1596) ने अपने ग्रन्थ—Six Livres de la Republique—में क्षेत्रीय सम्प्रभुता (Territorial sovereignty) का प्रतिपादन किया। इस ग्रन्थ के आठवें अध्याय में बोदाँ ने सम्प्रभुता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सम्प्रभुता नागरिकों तथा जनता पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई विधि बन्धन नहीं होता। सम्प्रभुता की प्रमुख विशेषता,

⁵ Kung Chuan Hsiao, Political Pluralism, p 7.

⁶ 1575 में प्रकाशित इस ग्रन्थ का विस्तृत लेटिन संस्करण 1586 में निकला।

बोदा के अनुसार, नागरिकों पर सामान्य एवं अविच्छिन्न विधि निर्माण की शक्ति है। सम्प्रभुता स्थाई है इसे समय या दशाओं से सीमित नहीं किया जा सकता। व्यवहार में, जैसा कि हेसोवेल ने लिखा है, इसका तात्पर्य हुआ कि सम्प्रभुता युद्ध की घोषणा, शांति करना, विधायकों का चयन, अन्तिम न्यायालय के रूप में कार्य करना, मुद्रा निर्माण तथा कर लगाने में व्यक्त होती है।⁷

जब बोदा ने लिखा है कि सम्प्रभुता विधि बन्धन से मुक्त है इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह सभी प्रकार के कानूनों से मुक्त है। प्रत्येक सम्प्रभु देवी कानून (divine law), प्राकृतिक कानून (law of nature) राष्ट्रीय सविधान व कानून तथा राष्ट्रा के सामान्य कानूनों (Common law of Nations) से बंधे हुए हैं। बोदा के अनुसार सम्प्रभु पोप द्वारा निर्मित कानून, रोमन कानून, तथा कॉर्ट्यूम (Cortume) से पूर्ण स्वतन्त्र है।⁸

बोदा के सम्प्रभु सिद्धान्त न राष्ट्रीय सम्राट के लिए सामन्तो चर्च के अधि कारियों तथा अन्य प्रचलित कानून व्यवस्थाओं के विरोध का सामना करने के लिए एक सैद्धान्तिक हथियार प्रदान किया। हॉब्स ने इस सिद्धान्त का और विस्तार किया।

हॉब्स के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार लेविथान

टॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes, 1588-1679) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ—Leviathan (1651)—में सामाजिक अनुबन्ध का सिद्धांत तथा इस सम्बन्ध में सम्प्रभुता के सिद्धांत पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति से समभूता कर अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक सम्प्रभु व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को सौंप देता है। तदुपरान्त राष्ट्रमण्डल या राज्य (Commonwealth) की स्थापना होती है। यह व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा—जिसे समस्त व्यक्ति अपने अधिकार देते हैं सम्प्रभु कहलायेगा। यह सम्प्रभु सामाजिक अनुबन्ध में भागीदार नहीं है इस प्रकार वह समस्त उत्तरदायित्वों से परे है। एक बार सम्प्रभु को अपने अधिकारों का त्याग करने के बाद व्यक्ति अपने अधिकारों को पुन वापस नहीं ले सकते। हॉब्स के मतानुसार सम्प्रभु की शक्ति असीमित तथा निरंकुश होती है। कोई भी व्यक्ति सम्प्रभु के प्रति अपने प्रतिबन्ध से मुक्त नहीं हो सकता। सम्प्रभु यदि अन्यायपूर्वक कार्य करे तब भी उसकी भक्तता नहीं की जा सकती क्योंकि सम्प्रभु की इच्छा ही न्याय है।

चूंकि हॉब्स एक महान व्यक्तिवादी था वह व्यक्तियों की एक स्थित्यन्तता का पूर्ण समर्थन करता है जिसे वह निरंकुश सम्प्रभु सत्ता का विरोध नहीं मानता। हॉब्स व्यक्तियों को स्वयं की व्यक्तिगत रक्षा का पूर्ण अधिकार देता है। यदि सम्प्रभु

7 Hallowell, J H., *Main Currents in Modern Political Thought*, p 63

8. *Ibid.*, p 68

न्यायोचित आधार पर व्यक्ति को स्वयं की आत्महत्या करने या ऐसा अन्य-कार्य करने जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता, की आज्ञा देता है मनुष्य को इस प्रकार की आज्ञा की अवहेलना करने की स्वतन्त्रता है।

हॉब्स राज्य तथा समाज, राज्य तथा सरकार, कानून तथा नैतिकता के मध्य भेद नहीं करता। ये समस्त शक्तियाँ सम्प्रभु में निहित हैं जिसे हॉब्स 'मरणशील प्रभु' (Mortal God) की सजा देता है। हॉब्स के सम्प्रभुता सिद्धांत के मूलतः चर्चें राज्य के अधीन रहना चाहिये। सम्प्रभु के प्रति वफादारी और ईश्वर के प्रति श्रद्धा में कोई विरोधाभास नहीं है।

हॉब्स ने अपने सम्प्रभु सिद्धांत में किसी भी प्रकार की सीमाओं एवं मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया है। बोदा ने सम्प्रभु के ऊपर फिर भी कुछ सीमाएं बाध दी थी, हॉब्स के सम्प्रभु सिद्धान्त में ये सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में हॉब्स का उद्देश्य निरंकुश राजतन्त्र का समर्थन करना था।

ऑस्टिन द्वारा सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त की व्याख्या

जॉन ऑस्टिन (1790-1859) इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिशास्त्री थे। इनके विचार उनकी उस समय बहुचर्चित पुस्तक—Lectures on Jurisprudence, 1832-में मिलने हैं। इन ग्रन्थ में ऑस्टिन ने वैधानिक दृष्टिकोण से सम्प्रभुता की व्याख्या की है। ऑस्टिन के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार एकत्ववादी सिद्धान्त की धारणा एवं प्रतिनिधि व्याख्या माना जाता है। सम्प्रभुता की व्याख्या करते हुए ऑस्टिन ने लिखा है—

‘यदि एक निश्चित श्रेष्ठ मानव उर्मा प्रकार के किसी अन्य श्रेष्ठ मताधारों की आज्ञापालन करने का अभ्यस्त न हो, उस समाज के अधिकांश व्यक्ति स्वाभाविक उसकी आज्ञा का पालन करते हो तो उस समाज में यह निश्चित मानवश्रेष्ठ सम्प्रभु है और सम्प्रभु सहित वह समाज, राजनीतिक एवं स्वतन्त्र समाज है।’

इसके धारण ऑस्टिन ने लिखा है—

“उस निश्चित मानव श्रेष्ठ के लिये समाज के अन्य सदस्य जनता तुल्य हैं या समाज के अन्य सदस्य उस मानव श्रेष्ठ पर निर्भर हैं। उस मानव श्रेष्ठ के प्रति अन्य सदस्यों की स्थिति अधीनता और निर्भरता की है। उनके पारस्परिक सम्बन्धों को सम्प्रभु और जनता तथा सम्प्रभुता और अधीनता की संज्ञा दी जा सकती है।”⁹

ऑस्टिन के सम्प्रभु सिद्धांत का विवेचन करने से निम्नलिखित पक्ष स्पष्ट होते हैं—

1. सम्प्रभु एक निश्चित शक्ति होना चाहिये। कोई अनिश्चित व्यक्ति, संस्था, दैविक शक्ति या सामान्य इच्छा सम्प्रभु नहीं हो सकता।

9. Austin, John; Lectures On Jurisprudence, 2nd ed. John, Murray, 1891, p. 170; Maine, Henry S., Lectures on the Early History of Institutions, p. 343.

यह सम्प्रभु कोई श्रेष्ठ व्यक्ति ही हो सकता है।

यह सम्प्रभु आन्तरिक तथा बाह्य दोनों ही क्षेत्राधिकार में पूर्ण स्वतन्त्र एवं निरंकुश होता है।

बिना सम्प्रभु या सम्प्रभुता के कोई भी समाज राजनीतिक समाज नहीं कहा जा सकता। सम्प्रभुता के अभाव पर ही राजनीतिक और गैर-राजनीतिक समाज में भेद किया जा सकता है।

सम्प्रभु कानून का मूल एवं अन्तिम स्रोत है। उसकी इच्छा ही कानून है।

डॉ. एशबुर्याथ ने आस्टिन के सम्प्रभु सिद्धांत का विवेचन करते हुए निम्न-लिखित चार विशेषताओं पर प्रकाश डाला है—

प्रथम, सम्प्रभु निश्चित व्यक्ति होता है,

द्वितीय, सम्प्रभु सर्वोच्च होता है जिस पर कोई आन्तरिक या बाह्य प्रतिबन्ध नहीं होता,

तृतीय, सम्प्रभु किसी भी आज्ञा का पालन नहीं करता इस प्रकार उसकी शक्ति का विभाजन नहीं हो सकता,

चतुर्थ, सम्प्रभु का अर्थ विधि-विधान है।¹⁰

सम्प्रभुता के विषय में आस्टिन के विचार निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते। वे अपने विचारों में स्वयं के व्यवसाय एवं वातावरण से मुक्त नहीं हो सके। आस्टिन अपने समय के प्रसिद्ध विधिवादी थे। सम्प्रभुता के विवेचन में वे न तो यथार्थवादी हैं और न आदर्शवादी, उनका दृष्टिकोण केवल उनकी विधिवादिता और विद्वता प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि आस्टिन विक्टोरिया युग की देन थे और उनके सम्प्रभुता सम्बन्धी विचारों में राजतन्त्र के अनुमोदन का आभास मिलता है।

सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) ने आस्टिन तथा अन्य एकत्ववादियों के प्रत्येक पक्ष को लेकर विवेचन किया है। सर हेनरी मेन ने अभिसमय तथा परम्परावादी (Conventional) दृष्टिकोण से आस्टिन के सम्प्रभु सिद्धांत की आलोचना की है। मेन ने भारत तथा कुछ अन्य पूर्वी राज्यों का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि कोई भी सम्प्रभु ऐसा आदेश नहीं दे सकता जो जन समुदाय की पूर्व प्रचलित अभिसमयों के विरुद्ध हो। महाराजा रणजीतसिंह का दृष्टान्त देते हुए सर हेनरी मेन ने लिखा है कि महाराजा रणजीतसिंह की शक्ति राजनीतिक दृष्टि से असीमित थी किन्तु उन्होंने भी कभी कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जिसे, जैसा कि आस्टिन ने लिखा है, कानून कहा जा सकता था।¹¹

आस्टिन के अनुसार सम्प्रभु का अर्थ ही विधि एवं विधान है। आस्टिन की

¹⁰ Ashburyatham, E., Political Theory, p 266-67

¹¹ Maine, Henry S., Lectures on the Early History of Institutions, pp 379-80

सम्प्रभुता एवं बहुलवाद

यह धारणा नृतिपूर्ण तथा केवल धार्मिक सत्य है। सम्प्रभु का अर्थ प्रभु का नून (एकमात्र स्रोत नहीं है)। रीति रिवाजों, परम्पराएँ, धार्मिक प्रथाएँ न्यायालय निर्णय, विधि-विद्वानों द्वारा टीकाएँ तथा मुख्यतः संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है। आस्टिन ने इन सब स्रोतों को अवहेलना कर केवल एक ही स्रोत पर अनावश्यक जोर दिया है।

आस्टिन का यह विचार कि सम्प्रभुता अतिरिक्त एव असीमित होती है व्यावहारिक तथा अन्य दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्व के किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का यदि विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि किसी भी देश में सम्प्रभुता असीमित एव अविभाज्य नहीं होती। सत्ता, कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अर्थ ही कुछ व्यक्तियों अथवा अंगों में विभाजन एव विभाजन रहता है। आजकल प्रत्येक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन तथा पारस्परिक रोध की व्यवस्था होती है। परिणामस्वरूप सम्प्रभु सत्ता असीमित होने में प्रश्न ही नहीं उठता।

आस्टिन का सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धांत लोकप्रिय सम्प्रभुता के विरुद्ध सत्ता का समर्थन करने वाला है। आस्टिन की सम्प्रभुता सम्बन्धी सभी भाष्यत लोकमत तथा जन इच्छा के प्रतिशूल है। उनकी धारणाएँ शक्ति पर आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाली हैं। आस्टिन के सम्प्रभु समाज की व्यवस्था अधिनायकवादी तथा पुलिस राज जैसी होगी।

स्वतन्त्रता के समर्थक आस्टिन के विचारों को एक उत्तरनाक कल्पना मानते हैं जो लोकतन्त्र के विरुद्ध तथा राजतन्त्र प्रोत्साहित करने वाले हैं। ये राज्य के एकत्ववादी सिद्धान्त के सभी तथ्यों का विरोध करते हैं। स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए इनका विचार है कि सम्प्रभु सत्ता का विभाजन विभिन्न संस्थाओं तथा केन्द्र और राज्यों में होना चाहिए। सम्प्रभुता का कोई निश्चित केन्द्र न होकर समय समय पर स्थान होता रहना चाहिए। सम्प्रभुता जनमत द्वारा सीमित होना चाहिए।

यद्यपि आस्टिन के सम्प्रभु सम्बन्धी विचारों अथवा राज्य के एकत्ववादी सम्प्रभु सिद्धान्त की सामान्य आलोचना हुई है किन्तु जितनों 'यापक' आलोचना बहुलवादियों ने की है सम्भवतः किसी अन्य ने नहीं। बहुलवादियों ने आलोचना एवं निन्दा से सम्प्रभुता का कोई भी पक्ष नहीं बच सका है।

बहुलवाद (PLURALISM)

प्लूरलिज्म (Pluralism) प्लूरल (Plural) शब्द से बना है। प्लूरल का अर्थ 'एक से अधिक' है। प्लूरलिज्म अथवा बहुलवाद समाज में एक से अधिक संस्थाओं को महत्व देता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (The Oxford English

Dictionary, Vol. VII, p 1026) के अनुसार बहुलवाद एक विचार सिद्धान्त अथवा विचार प्रणाली है जो एक से अधिक सिद्धान्तों को मान्यता देता है, यह एकत्ववाद (monism) के विरुद्ध है। राजनीतिक बहुलवाद वैयक्तिक अन्तरात्मा तथा विविध अभिव्यक्ति की आवश्यकता से सम्बद्ध है। यह समूहों के हितों पर आधारित है। सभी बहुलवादी राज्य सम्प्रभुता के गुणगान का विरोध करते हैं (Dictionary of Political Science, ed by Joseph Dunner, p 413) अन्व शब्दों में, बहुलवाद आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सत्ता के केन्द्रीकरण के विरुद्ध अवधारणा है। किन्तु इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति राज्य सम्प्रभु सिद्धान्त अथवा सम्प्रभु के एकत्ववादी सिद्धान्त के परिप्रेषा में तथा विरोधस्वरूप हुई है। बहुलवाद की व्याख्या करते हुए कोकर ने लिखा है कि बहुलवाद सामाजिक समूहों का समर्थन करना है क्योंकि उसका दावा है कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति की अभिव्यक्ति विविध समूहों में होती है। कोई भी समूह नैतिक या यावहारिक दृष्टि से एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। बहुलवादी राज्य को सर्वशक्तिमान और सर्वदायी नहीं मानते।¹²

बहुलवाद का प्रादुर्भाव - कारण

बहुलवाद के प्रादुर्भाव का इतिहास पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो यह तत्त्व स्पष्ट हो जाता है कि बहुलवाद उन सभी विचारों के विरुद्ध प्रतिजिया है जो राज्य को अत्यधिक महत्त्व देते हैं। ऐसी विचारधाराओं में राज्य का आदर्शवादी सिद्धान्त तथा सम्प्रभुता का एकत्ववादी सिद्धान्त है। पूर्वं पृष्ठा में अध्ययन किया गया है कि बोदा, हाँस तथा आस्टिन राज्य को पूर्णतः सम्प्रभु-सम्पन्न मानते हैं जो राज्य की निरंकुशता का दूसरा नाम है। बहुलवादी राज्य के इस सम्प्रभु सिद्धान्त के विवचन का पूर्ण खण्डन करने हैं।

राज्य को मातृवें आनमान तथा पहचाने का श्रेय आदर्शवादिशो में हीगेल को है। वे राज्य का 'पृथ्वी पर प्रभु' के तुल्य मानते हैं। राज्य का विषय में हीगेन ने कहा था—“राज्य वर्तमान चेतना के रूप में एक देवी इच्छा है जो गणित सत्कार के रूप में अपना उद्घाटन करती है।” हीगेलवादी राजन की व्याख्या करते हुए सवाइन ने लिखा है कि हीगेल के लिए राज्य साधन नहीं बल्कि साध्य है। यह विकास में विवकयुक्त आदर्श को और सम्पत्ता में आध्यात्मिक तत्त्व को प्रकट करता है। इस दृष्टि से वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नागरिक समाज का प्रयोग करता है या एक विशिष्ट आध्यात्मिक अर्थ में उसका निर्माण करता है। राज्य पूर्ण रूप से विवक युक्त है, वह देवी मत्ता है जो स्वयं जानती है और इच्छा करती है, वह चेतना की शाश्वत और आवश्यक सत्ता है वह सत्कार में ईश्वर की यात्रा है।¹³

हीगेनवाद के अन्तर्गत राज्य को वैधानिक तथा नैतिक दृष्टि से सर्वोच्च अर्थ-

¹² Coker, F, Recent Political Thought, pp 497-98

¹³ सवाइन, राजनीति-दार्शनिक का इतिहास, पृ० 619—20

कार प्राप्त है। हीगेलवादी राज्य में निहित नत्न यह है कि इसमें राज्य और समाज को एक रूप माना जाता है। राज्य में साव्यविक एकता होती है, राज्य एक केन्द्रीय सामाजिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को अपना स्थान बनाना पड़ता है। व्यक्ति का स्वयं अपने आप में न कोई महत्त्व एवं अस्तित्व है और न कोई पृथक मूल्य। व्यक्ति का महत्त्व इसलिए है कि वह राज्य की एक इकाई है। इस हीगेलवादी राज्य के विरुद्ध जो स्पष्ट प्रतिक्रिया हुई है वह बहुलवाद इंगी प्रतिक्रिया का भी परिणाम था।¹⁴

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैण्ड में तथा अन्यत्र जिस समय लोकतन्त्र की जड़ें जम रही थी उसी समय लोकतान्त्रिक क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रणाली के दोष सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। इंग्लैण्ड में इस प्रकार के कई दृष्टान्त सामने आये जब कि प्रतिनिधित्व व्यक्तियों का नहीं किन्तु सुनसान धीरान क्षेत्रों का होता रहता था। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमाकरण अत्यन्त दोषपूर्ण था। यद्यपि धीरे-धीरे निर्वाचन व्यवस्था में सुधार होता रहा किन्तु क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रणाली फिर भी दोषरहित नहीं थी। इस स्थिति में पूर्ण सुधार करने के लिए बहूतवादीयाने (जिनमें गिल्ड मराजवादी प्रमुख हैं) क्षेत्रीय या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के स्थान पर व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली का समर्थन किया। इस विचार ने बहुलवाद को आगे बढ़ाने में सहायता दी।

व्यक्तिवाद एवं पूँजीवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करते हैं। समाजवाद इनका विरोधी प्रत्युत्तर था। किन्तु समाजवाद के प्रादुर्भाव तथा राज्य के सकारात्मक कार्यों में वृद्धि के कारण नौकरशाही तथा उसके अधिकारों में वृद्धि हुई। समाजवाद, राज्य के सकारात्मक कार्य तथा नौकरशाही की मिश्रित प्रक्रिया में केन्द्रीकरण (Centralisation) पर आधारित प्रशासन को प्रोत्साहन दिया। केन्द्रीकरण ने कुछ समय में ही असंमित रूप धारण कर लिया। यहाँ तक कि शासन व्यवस्था, सामाजिक समुदाय व्यवस्था केन्द्रोत्करण के बोझ से दबकर रक्तहीन एवं गतिहीन होती जा रही थी। अब इस बात का अनुभव किया गया कि विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। विकेन्द्रीकरण का समर्थन बहुलवादियों का एक प्रमुख विचार बन गया जिसने इस विचार की वृद्धि में और सहायता दी।

प्रमुख बहुलवादी

बहुलवाद की उत्पत्ति, आशीर्वादिम् के विचार से, मध्ययुग की गिल्ड व्यवस्था में हुई। मध्य युग की अव्यवस्थित परिस्थितियों के सन्दर्भ में व्यापारियों, शिल्पियों तथा उनके मंडों को काफी स्वायत्तता एवं अधिकार मिल गये थे किन्तु राष्ट्रीय राज्य (Nation state) एवं राजतन्त्रों के विकास से मध्ययुगीय व्यवस्था समाप्त हो गई। राज्य सम्प्रभुता तथा केन्द्रवादी दोषों के निवारण के लिये कुछ लेखकों ने मध्ययुगीय व्यवस्था के पुनरुत्थान का अनुपादन किया। जर्मनी के अर्टो गिपक

14. आशीर्वादिम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 464, 708.

(Otto Von Guericke, 1841-1913) तथा ब्रिटेन में मैटलेण्ड (F.W. Maitland, 1850-1906) ने व्यावसायिक सभों की स्वायत्तता का समर्थन किया। इन दोनों को आधुनिक बहुलवादी अवधारणा का जन्मदाता माना जाता है। इनके अनिश्चित बहुलवाद के और भी अन्य समर्थक हैं। बहुलवाद को विवक्षित करने में किंगिस (J N Figgis) का महत्वपूर्ण योगदान है। किंगिस 15 ने राज्य और धर्म के सम्बन्धों के सम्बन्ध में यह प्रतिपादन किया कि धर्म सभों का अस्तित्व राज्य की कृपा पर निर्भर नहीं करना। धर्म-सभ में एक व्यक्ति की भाँति आत्म-दिव्यता की क्षमता होती है। किंगिस ने राज्य के सम्प्रभु सिद्धान्त को एक अन्धविश्वास की सजा दी है।

पोल बॉन्कर (Paul Boncour) तथा डर्कहोम (E Durkheim) ने व्यावसायिक एवं आर्थिक सभों की ओर में दावे प्रस्तुत किये हैं। हेरॉल्ड लास्की (H J Laski) ने राज्य सम्प्रभुता पर सबसे प्रबल प्रहार किया है। वे ऐसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं जहाँ असीमित एवं अनुत्तरदायी राज्य के ध्यान पर सम्प्रभुता का स्वायत्त सभों में विभाजन हो; कोल (G D H Cole) तथा अन्य गिल्ड समाजवादियों का विश्वास था कि समाज का विभाजन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के सभों में होना चाहिए। उन्होंने गिल्ड्स तथा राज्य के मध्य सह-सम्प्रभुता (Co-Sovereignty) का विचार प्रस्तुत किया है। मैकाइवर (R M MacIver) की पुस्तक—Modern State—में बहुलवाद की स्पष्ट टाया है। मैकाइवर ने राज्य तथा अन्य सामाजिक समस्याओं को एक ही स्तर पर ला खड़ा किया है। उनके विचार से समाज के अन्य सगठन उठते ही स्वाभाविक एवं आवश्यक हैं जिनका कि राज्य। वे राज्य की केवल एकता स्थापित करने वाली सस्था मानते हैं। बार्कर (Ernest Barker) राज्य तथा अन्य समुदायों के मध्य समुलन करने का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ वे सभों की निरकुशता का भी विरोध करते हैं। उन्होंने राज्य की व्याख्या सभों के सभ तथा समुदायों के समुदाय के रूप में की है। इनके अनिश्चित लिण्डसे (A D Lindsay), मिम फॉलेट (Miss Follett) आदि भी बहुलवाद के समर्थक हैं।

बहुलवादी सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त का कई तर्कों एवं दृष्टिकोणों से खण्डन करते हैं। राज्य के सम्प्रभु सिद्धान्त के विरुद्ध बहुलवादियों के सामान्यतः निम्नलिखित तर्क हैं—

ऐतिहासिक तर्क

राज्य सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त के विषय में बहुलवादियों का आरोप है

15 किंगिस के बहुलवादी विचार उनके निम्नलिखित ग्रंथों में मिलते हैं—

The Divine Right of Kings, Cambridge, 1914, Studies of Political Thought from Gerson to Grotius, Cambridge, 1916

कि सम्प्रभुता राज्य का मूलिक तत्त्व नहीं है। इतिहास का अध्ययन बतलाता है कि राज्य समाज में परिस्थितियों की उपज है, वह समाज का सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक तत्त्व नहीं रहा है। वे राज्य को एक प्राचीन सस्था के रूप में स्वीकार प्रवश्य करते हैं किन्तु वे यह मानने से इन्कार करते हैं कि राज्य सदैव ही सम्प्रभुता-सम्पन्न रहा है। उनके अनुसार सम्प्रभु राज्य की धारणा लगभग सोराहवीं शताब्दी की देन है। इसके पूर्व राज्य-सम्प्रभुता जैसा कोई तत्त्व नहीं था। सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप एक समाज माना जाता था जहाँ प्राथमिक षष्ठ में प्रभुत्व का अस्तित्व नहीं था। इसके प्रतिरिक्त राज्य की जो भी स्थिति थी उसकी शक्ति पर अनेक बंधन एवं सीमाएँ थी। राज्य कानून के ऊपर न हीरर उसके अन्तर्गत था। बहुलवादियों का कहना है कि विभिन्न समुदायों एवं संस्थाओं ने भी राज्य पर नियन्त्रण रखा है। मध्य युग में ईसाई धर्म का धार्मिक और सामाजिक जीवन पर ही नहीं, राजनीतिक जीवन पर भी काफी नियन्त्रण था। 16 वें से धार्मिक संगठन अस्तित्व में आये उनका भी राज्य पर किमी न किसी रूप में दबाव रखा है।

विधि एवं अन्तःकरण (Law and Conscience)

बृहत् बहुलवादियों, जिनमें फ्रांस के डेपूग्वी, हॉलेण्ड के श्रेय तथा इंग्लैंड के हेगैल्ट सास्त्री प्रमुख हैं, ने सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त का विधि दृष्टिकोण से पण्डन किया है। एकत्ववादी राज्य को विधि का प्रमुख स्रोत मानते हैं। जैसा कि आस्टिन ने लिखा है राज्य का आदेश ही कानून है। इन बहुलवादियों ने इस तर्क एवं मान्यता को स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में वे राज्य के अधिकार को चुनौती देते हैं। डेपूग्वी कानून को सम्प्रभु राज्य की रचना नहीं मानते। उनके अनुसार कानून राजनीतिक संगठन में पूर्वकालीन, स्वतन्त्र एवं श्रेष्ठ होता है। विधि सामाजिक जीवन का परिणाम है। कानून का पालन इसलिए नहीं किया जाता कि वे किसी सम्प्रभु द्वारा निमित्त या निर्देशित है किन्तु इसलिए कि वे समाज के आवश्यक नियम हैं जो पारम्परिक सम्बन्धों को संगठित करते हैं तथा एकता के सूत्र में बाँधते हैं। राज्य का कार्य इन विधियों को मान्यता एवं अपनी शक्ति प्रदान करना है। जैसा कि गैटेल ने लिखा है डेपूग्वी का मुख्य उद्देश्य सम्प्रभु सत्ता पर न्यायमूलक प्रतिबन्ध लगाना तथा राज्य के उत्तरदायित्व सिद्धान्त का विकास करना है।

सास्त्री का कहना है कि केवल वैधिक औचित्य ही सरकार को इस बात का अधिकार नहीं देता कि वह अपनी आज्ञाओं का बेलात्पूर्वक पालन कराए। राज्य के इस अधिकार में नैतिक औचित्य होना चाहिए। विधि का स्रोत राज्य नहीं है किन्तु व्यक्ति जो अपने अन्तःकरण के अनुसार चलता है। कानून की प्रस्थापना व्यक्तियों की सहमति के बिना नहीं हो सकती। व्यक्ति द्वारा केवल उन कानूनों का पालन करना चाहिए जो उसके अन्तःकरण के अनुरूप, उसकी सहमति पर आधारित तथा उसकी

आकाशवादी को पूरा करने में सहायक हो। लास्की का मत है कि जिन लोगों ने इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध, अठारहवीं शताब्दी में फ्रांसिसी निरपुण राजतन्त्र के विरुद्ध तथा 1917 में रूस के शेर के विरुद्ध विद्रोह किया उन्होंने विधि की कोई अवज्ञा नहीं की। वे लोग उस विधि के प्रति निष्ठावान थे जो राज्य के ऊपर है।¹⁷

सम्प्रभु सिद्धान्त के एकत्ववादियों का कहना है कि राजनीतिक समाज में सम्प्रभु निश्चित एवं अविभाज्य होता है। बहुलवादी इस मान्यता से सहमत नहीं हैं। सघातक राज्य का उदाहरण देते हुए उनका कहना है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में सम्प्रभुता बड़ा निवास करती है स्पष्ट करना अशक्य है। सघीय व्यवस्था में सम्प्रभु सत्ता निश्चित न होने के साथ साथ कई सत्ताओं तथा क्षेत्रीय स्तरों में विभाजित रहती है। विश्व के किसी भी सघीय सविधान का यदि अध्ययन किया जाय तो सम्प्रभुता की एकत्ववादी धारणा वही भी दृष्टिगोचर नहीं होती।

अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष

राज्य सम्प्रभु सिद्धांत के वाह्य पक्ष की आलाचना अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ताओं, अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था के समर्थकों ने की है। इनका कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई भी राज्य पूर्ण सम्प्रभु नहीं होता उसकी कुछ न कुछ सीमाएँ निर्धारित रहती हैं या व्यावहारिक दृष्टि से सीमाएँ एवं मर्यादाएँ स्वीकार करनी पड़ती हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अर्ध-सम्प्रभु राज्य (semi sovereign state) की अवधारणा का समर्थन करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीयवादियों का यह विचार है कि राज्यों को अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौतों के प्रति अपने दायित्वों को स्वीकार करना चाहिये। हेरॉल्ड लास्की ने राज्य को असंमित दाह्य सम्प्रभुता का विरोध करते हुए लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतन्त्र सम्प्रभु राज्य को धारणा मानव कल्याण के लिये घातक है। एक राज्य को दूसरे राश्या के साथ किस प्रकार रहना चाहिये इसका निर्णय करने का अधिकार एकमात्र उसी राज्य को नहीं दिया जा सकता।¹⁸

लास्की के अनुसार राज्यों का पारस्परिक जीवन एक ऐसा विषय है जिस पर राज्यों में समझौता होना चाहिये। उनकी व्यवस्था के लिये एक विश्व संगठन की आवश्यकता है। यदि मनुष्यों को महान मानव समाज में रहना है तो उस सहयोगमूलक व्यवहार सीखना होगा। एक विश्वराज्य में उसका निर्माण चाहे जिस प्रकार हो, उसमें चाहे जिस मात्रा में विकेंद्रीकरण हो, पृथक् सम्प्रभुता के लिये स्थान नहीं है। लास्की विश्व एवं मानवता के प्रति निष्ठा को सम्प्रभुता पर एक आवश्यक प्रतिबन्ध मानते हैं।¹⁹

¹⁷ आशीवादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 439

¹⁸ Laski, H J, A Grammar of Politics, p 65

¹⁹ आशीवादम्, राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 717-18

राज्य का व्यवहार एवं कार्य-स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकारों द्वारा सीमित होती है। राज्य स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का एक अंग है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में सकारात्मकवाद (Doctrine of Positivism) के अंतर्गत राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्वयं की स्वीकृति से परिवर्तित एवं सीमित की जा सकती है। इसकी अभिव्यक्ति राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिओं तथा प्रचलित परम्पराओं को स्वीकार करने में होती है। इसके अतिरिक्त सम्प्रभुता का तात्पर्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों की समानता से भी है।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जब तक सम्प्रभुता के सिद्धांत को मान्यता मिलती रहेगी अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की संस्थाएँ न तो कोई विशेष प्रगति कर सकती हैं और न वे शक्तिशाली हो सकती हैं। सैद्धान्तिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय एकात्मता एवं समन्वय का दृष्टिकोण एक सीमित परिधि से घाये नहीं जा सकता। यह बात संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य संस्थाओं जैसे यूरोपीय सभा बाजार (European Economic Community) आदि के व्यावहारिक अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है।

राज्य एवं समुदाय

समुदायों के समर्थन में सामान्य तर्क

बहुलवादी समुदायवादी हैं। उन्होंने समाज में विभिन्न समुदायों के हितों और अधिकारों का समर्थन कर सम्प्रभुता सिद्धान्त का खण्डन किया है। उनका अर्थ है कि प्रथम, समाज में समुदायों की सृष्टि राज्य नहीं करता। यह भ्रम है कि विभिन्न समुदाय अपने अस्तित्व के लिये राज्य की इच्छा प्रथवा सत्ता पर निर्भर करते हैं। समुदाय स्वतः उत्पन्न होते हैं, उनका स्वयं का व्यक्तित्व होता है जो राज्य की सत्ता से पृथक और स्वतन्त्र है। द्वितीय, यद्यपि राज्य स्वयं एक प्राचीन संस्था है किन्तु समाज में बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो राज्य से पूर्व तथा राज्य की सहायता के बिना अपना कार्य करते हैं। तृतीय, केवल राज्य अकेला ही विधि निर्माण का स्रोत नहीं है। समाज में विभिन्न संस्थाएँ तथा समुदाय कई प्रकार की धारणाओं, परम्पराओं एवं सिद्धान्तों को जन्म देते हैं आगे चलकर सामाजिक आचरण के नियम बन जाते हैं। राज्य का कार्य केवल इनको स्वीकार कर मान्यता प्रदान करना है।

मानव स्वभाव—बहुलवादियों ने अपने विचारों को मानव प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस सम्बंध में बहुलवादी स्वयं को एक निश्चित सीमा तक विवेक के प्रति विद्रोह (revolt against reason) से सम्बंध रखते हैं जो सामाजिक मनोविज्ञान एवं नवीन प्रवृत्तियों प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार मनुष्य में कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिनके कारण मनुष्य के विभिन्न उद्देश्य एवं आवश्यकताएँ होती हैं। इन सभी की पूर्ति राज्य नहीं कर सकता। राज्य की स्थिति समाज के कुछ निश्चित राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये है। यदि राज्य समाज के सम्पूर्ण कार्यों, राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक,

सभी को अपने हाथों में लेना भी चाहे तो या तो यह असम्भव है या अव्यावहारिक । इसलिए मनुष्य की विविध प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समाज में राज्य के अतिरिक्त और कई प्रकार की संस्थाओं—जैसे चर्च, संगीन-नाटक संस्थाएँ आदि—की स्थापना की जाती है । राज्य ही केवल ऐसी संस्था नहीं है जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रवृत्तियों की शतुष्टि के लिये सम्मिलित होता है । जैसा कि लास्की ने लिखा है—राज्य मानव समाज सभों के अनेक रूपों में से केवल एक है तथा इनमें सार्थ होने की स्थिति में व्यक्तिगत बफादारी एवं श्रद्धा के प्रति अपेक्षाकृत राज्य का अधिक दावा नहीं होता ।

राज्य समुदायों का समुदाय

बहुलवादी, जैसे फिगिस, लिण्डसे, बार्कर, लास्की आदि राज्य की व्यक्तियों का समुदाय नहीं मानते । इनके अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है । इसका तात्पर्य है कि पहिले मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं एवं प्रवृत्तियों के अनुसार राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक आदि समुदायों में संगठित करता है । तदुपरान्त इन समुदायों के आधार पर राज्य का निर्माण होता है । जैसा कि बार्कर ने लिखा है "राज्य सामान्य जीवन में व्यक्तियों का समुदाय कम है, यह उन व्यक्तियों का समुदाय अधिक है जो पहले ही सामान्य हितों की उपलब्धि के लिये विभिन्न समूहों में संगठित हैं ।"²⁰ बहुलवादी योजना का आधार व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तियों का समूह है ।

राज्य के विधिवादी सिद्धांत का विरोध सर्वप्रथम डा० गियर्क ने अपने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ—*Das deutsche Genossenschaftsrecht*²¹—में किया । गियर्क रोमन परम्परा के विरुद्ध जर्मन निगमवादों से । पश्चिमी समाज सदैव ही कई समूहों में विभाजित रहा है । मध्य युग में यह व्यवस्था अधिक प्रचलित थी । उस समय राज्य तथा विभिन्न समूहों के सम्बन्धों का निर्धारण एक समस्या थी । अन्य शब्दों में समस्या राज्य तथा अन्य समूहों के वैधानिक सम्बन्धों को निर्धारण करने की थी । पोप इनोसेन्ट चतुर्थ (Pope Innocent IV) ने 1243 में इन समस्या के हल के लिये एक काल्पनिक सिद्धान्त (The Fiction Theory) का प्रतिपादन किया जिसके अन्तर्गत कॉर्पोरेट व्यक्तित्व (Corporate personality) को मान्यता दी गयी । तदुपरान्त एक और सिद्धान्त कन्सेशन सिद्धान्त (The Concession Theory) का प्रचलन चला जिसका भाष्य था कि राज्य के अन्दर किसी भी समूह का वास्तविक

²⁰ Barker, E., *Political Thought in England, 1648—1914*, p 177

²¹ इसका अर्थ है—*The German Law of Associations* इस ग्रन्थ के तृतीय भाग को F. W. Maitland ने एक नये शीर्षक—*Political Theories of the Middle Age*—के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में अनुदित करने के साथ-साथ लगभग चालीन पृष्ठों की प्रस्तावना भी लिखी है ।

शक्तित्व नहीं होना, समूहों की अपने सदस्यों से पृथक् स्वयं की कोई इच्छा नहीं होनी या समूह-व्यक्तित्व केवल काल्पनिक तथा राज्य द्वारा निर्मित होना है। डा० गियर्क वास्तव में इस सिद्धान्त का विरोध कर बहुलवादी विचारधारा के लिये महत्वपूर्ण भेदान दिया।

निगम व्यक्तित्व तथा समूह व्यक्तित्व सिद्धान्त

मार्टो गियर्क तथा मेटलेण्ड ने निगमों के वैधानिक तथा ऐतिहासिक सिद्धान्तों को निरूपण किया। उनके इस सिद्धान्त को निगम व्यक्तित्व सिद्धान्त (The Theory of Personality of Corporation) अथवा समूह व्यक्तित्व सिद्धान्त (Theory of Group Personality) कहा जाता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए गियर्क लिखा है—

‘किसी राजनीतिक सिद्धान्त की दार्शनिक सत्यता, वैधानिक परीक्षण, नैतिक-परायणता, सहिता और निणयो म वैधानिक रूप से निहित, तथा व्यावहारिक सरलता के लिये निगम व्यक्तित्व को मान्यता मिलनी चाहिये।’²²

गियर्क तथा मेटलेण्ड के अतिरिक्त समूह व्यक्तित्व सिद्धान्त का विस्तार फिगिस (J. N. Figgis) ने किया। इस सिद्धान्त के अनुसार समाज कई समूहों और समुदायों में विभाजित होता है। इन समूहों का स्वयं का व्यक्ति होता है। अन्य शब्दों में, प्रत्येक एक वास्तविकता है, इसका स्वयं का जीवन, चेतना और इच्छा होती है। इनका अस्तित्व राज्य तथा कानून से स्वतन्त्र होता है। व्यथस्थित समूहों के व्यक्तियों की सति अधिकार और कर्तव्य होते हैं।

गियर्क ने समूह व्यक्तित्व सिद्धान्त का उपयोग आधुनिक राज्य में चर्च की स्वतन्त्रता के समर्थन में किया। लास्की ने गियर्क के तत्वों को ग्रहण किया किन्तु वे चर्च की स्वतन्त्रता के विषय में उतने इच्छुक नहीं थे। लास्की ने इस सिद्धान्त का उपयोग धार्मिक संगठनों की स्वतन्त्रता तथा राज्य के सम्प्रभु सिद्धान्त का खण्डन करने के लिये किया।

निगमों के कानूनी तथा ऐतिहासिक सिद्धान्त की व्याख्या कोकर ने इस प्रकार की है—

‘किसी समाज में जो स्थायी सस्थाएं जन्म लेती हैं उनके व्यक्तित्व वास्तविक होते हैं काल्पनिक नहीं और न वे बाहर से ही निर्मित होते हैं। प्रत्येक सस्था की एक सामूहिक चेतना एवं इच्छा होती है जो उसके व्यक्तित्व सदस्यों की इच्छाओं एवं तनाओं से भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त कानून के विस्तार में प्रत्येक सस्था एक मौलिक अंग का कार्य’

22. Quote J. Hsiao, Kuan Huang; Political Pluralism, p. 33.

करती है, प्रत्येक सस्था राज्य से रियायत प्राप्त करने के पूर्व भी काम करती है और ऐसी एजेन्सी के रूप में काम करती है जिसके द्वारा कानूनी प्रकृति के सामान्य विश्वासों की अभिव्यक्ति कानून के वास्तविक नियमों में होती है। इस कानून के विस्तार में राज्य का भाग प्रधान है, एकान्तिक नहीं।”²³

निम्न सिद्धान्त का प्रतिपादन राज्य सम्प्रभुता का खण्डन करने के लिये काफी सहायक सिद्ध हुआ। बार्कर ने नेटलेण्ड की समुदायों के 'वास्तविक व्यक्तित्व' को कल्पना को स्वीकार नहीं किया है किन्तु इस सिद्धान्त के वे इस मूल विचार को स्वीकार करते हैं कि ये समुदाय राज्य में पहले विद्यमान थे तथा इनमें प्रत्येक वैध व्यक्ति है जिनका निर्माण उसके सदस्यों के सामान्य विश्वास से हुआ है।²⁴

व्यावसायिक समुदाय—पाँत बकर (Bauf Boncour) तथा डकंहाइम (E Durkheim) ने कुछ धार्मिक पक्षों को लेकर बहुलवाद का समर्थन किया है। पाँत बकर ने कई व्यावसायिक समुदायों का अध्ययन करने के उपरान्त विचार व्यक्त किया है कि धार्मिक समुदाय स्वयं उत्पन्न होते हैं। वे धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाते हैं तथा अपने व्यवसाय पर पूर्ण-नियंत्रण रखते हैं। कोई कोई धार्मिक समूह इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वे स्वयं नियम निर्माण करते हैं, अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा कालान्तर में राज्य उनके इस स्वरूप को मान्यता प्रदान कर देता है। डकंहाइम का विचार है कि राज का राज्य औद्योगिक समाज में प्रगति का सामना करने में असमर्थ है। समाज में धार्मिक क्षेत्र में इतनी जटिलता एवं विशिष्टीकरण हो गया है कि राज्य इनका संचालन करने में असमर्थ है। इस प्रकार बहुलवाद के समर्थक धार्मिक क्षेत्र में राज्य की दुर्बलता तथा नीमाओं की ओर इंगित करते हैं।

बहुलवाद तथा राज्य

राज्य तथा समाज में भेद—बहुलवादी राज्य को सर्वशक्तिशाली नहीं मानते और इसलिए वे राज्य और समाज का विलयोकरण नहीं करते। वे राज्य तथा समाज में भिन्न स्थापित करते हैं। मैकाइवर (R M MacIver) के अनुसार यह कल्पना मूल होगी कि राज्य के प्रतिरिक्त तथा उससे बढकर और कोई सस्थाएँ नहीं हैं। वे समाज में विभिन्न समूहों एवं सस्थाओं की सेवाओं के महत्त्व को स्वीकार करते हैं।

बहुलवादियों ने सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त का जिस अक्षुब्ध भावना

²³ बार्कर, धार्मिक राजनीतिक चिन्तन पृ 534

²⁴ कुछ विस्तृत विचारों के लिये देखिये—

Barker, E., Political Thought in England From Herbert Spencer to the Present Day, pp 175—183

से तीव्र खण्डन किया है उससे ऐसा आभास होता है जैसे कि बहुलवादी राज्य को ही समाप्त करना चाहते हैं। अन्य शब्दों में वे अराजकतावादी तथा गिल्ड समाजवादीयों के प्रति निकट प्रतीत होते हैं। वास्तव में यह धारणा सत्य नहीं है। बहुलवादी न तो राज्य के विरोधी हैं और न वे राज्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। वे केवल राज्य के एकत्ववादी सिद्धान्त का विरोध करते हैं। वे एक निश्चित सीमा तक राज्य के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार राज्य—

- (1) समस्त समुदायों में प्रथम समुदाय है।
- (2) मनुष्य के विभिन्न हितों के लिए विभिन्न समुदाय होने हैं किन्तु मनुष्य के सामान्य हितों की रक्षा राज्य करता है।
- (3) अन्य समुदायों की अपेक्षा राज्य का कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक होता है।
- (4) विभिन्न समुदायों के कार्यों में तालमेल बैठाने तथा उनमें विवाद आदि को सुलभाने के लिए वे राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करने हैं।
- (5) राज्य की सदस्यता प्रतिवार्य होगी है यह अन्य समुदायों के विषय में नहीं है।
- (6) लास्की जैसे समाजवादी बहुलवादी आर्थिक क्षेत्र में राज्य के नियन्त्रण को स्वीकार करते हैं।

बहुलवादो राज्य की व्याख्या करते हुए डा० टिसिभाओ ने लिखा है—

“बहुलवादी राज्य वह राज्य है जहाँ सत्ता का केवल एक ऐसा स्रोत नहीं होता जो सर्व-सक्षम तथा सर्व-व्यापक हो अन्य शब्दों में सम्प्रभुता न कानून की एकीकृत व्यवस्था न प्रशासन का केन्द्रीकृत अंग, न राजनीतिक दृष्टि का सामान्यीकरण हो। इसके विपरीत यह राज्य तत्त्व एवं अभिव्यक्ति में बहुगुणनात्मक होता है, यह कई भागों में विभाजित होता है और होना भी चाहिए।”²⁵

बहुलवाद एवं प्रतिनिधि सरकार

लोकतांत्रिक प्रणाली प्रतिनिधि सरकार पर आधारित होती है। किन्तु प्रतिनिधि सरकार की कई पक्षों को लेकर आलोचना हुई है। बहुलवादी भी प्रतिनिधि सरकार तथा उससे सम्बन्धित अन्य संस्थाओं के दोषों की ओर इंगित करते हैं तथा विकल्प में कुछ सुझाव देते हैं। बहुलवादियों का कहना है कि स्वशासन तथा प्रथम लोकतन्त्र का जो स्वरूप ग्रीक नगर राज्यों में था अब उसमें व्यापक परिवर्तन एवं दोष उत्पन्न हो चुके हैं। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, राजनीतिक संगठनों की व्यापकता एवं जटिलता से वास्तविक लोकतन्त्र लगभग समाप्त हो चुका है। लोकप्रिय सरकार अब उतनी साधारण नहीं है जितना कि समझा जाता है। प्रति-

निधि प्रणाली भी लोकतन्त्र का कोई अन्तिम समाधान प्रस्तुत नहीं करनी बरन् इसने स्वयं ही कई अन्य समस्याओं को जन्म दिया है। सत्तह की सम्प्रभुता अन्व-विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लोकतन्त्र में दल पद्धति वास्तव में एक आवश्यक बुराई है, या दल पद्धति कुलीनत्वों द्वारा शासन पर अधिकार करने के लिए एक मुडौटा एक छलावा है। बहुलवादी इन दोनों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रणाली, प्रतिनिधि सभाएँ तथा दल-पद्धति के विषय में वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत करते हैं।

बहुलवादियों का प्रमुख सुझाव कार्यात्मक अथवा व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली (Functional Representation) है। व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली के अन्तर्गत कुछ सामाजिक श्रेणियों की मान्यता प्रदान की जायेगी। एक व्यक्ति के जितने हित हैं उतने मत दे सकता है। अन्य शब्दों में एक व्यक्ति एक मत' सिद्धान्त स्वीकार नहीं करते किन्तु बहुल मत (Plural Voting) सिद्धान्त का सुझाव देते हैं। इस सम्बन्ध में बहुलवादियों का दूसरा सुझाव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व (Territorial representation) के अन्तर्गत चुनाव क्षेत्रों का विभाजन व्यवसाय अथवा कार्य के आधार पर करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में बहुलवादियों और गिल्ड समाजवादियों में कोई अन्तर नहीं है। कोल (G D H Cole) व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली के प्रमुख समर्थक हैं। उनके विचारों को बहुलवादी तथा गिल्ड समाजवादी दोनों ही मान्यता देते हैं।²⁶

बहुलवादी लोकतन्त्र के अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाओं की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार वर्तमान सभाएँ राष्ट्र के युग में राज की निरन्तर बढ़ती हुई गति-दिशियों का भार वहन करने में असमर्थ हैं। ये केन्द्रीकृत व्यवस्था पर आधारित हैं तो हैं तथा सामान्य इच्छा (General will) का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। प्रमुख बहुलवादी जैसे वेब डम्पनी, लास्की, कोन आदि राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभाओं का व्यावसायिक विभाजन करने का सुझाव देते हैं।

बहुलवादी प्रतिनिधि प्रणाली तथा प्रतिनिधि सभाओं के अन्तर्गत राजनीतिक दलों के संगठन का सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि राजनीतिक दलों का संगठन प्रतिनिधि सभाओं के व्यावसायिक संगठन के समानान्तर होना चाहिए। अन्य शब्दों में वे राजनीतिक दलों का संगठन व्यावसायिक आधार पर चाहते हैं। इसका तात्पर्य यह होगा कि जितने व्यवसाय उतने ही राजनीतिक दल। इस प्रकार ये बहुलवादी प्रथा का समर्थन करते हैं। वेब डम्पनी का सुझाव है कि विभिन्न आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल विशेष परिस्थितियों में एक मुख्य दल में संगठित होकर उन राजनीतिक दलों का, जो केवल राजनीतिक लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, सफलतापूर्वक सामना या विरोध कर सकते हैं।

²⁶ गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली के लिए गिल्ड समाजवाद का अध्याय देखिये।

विकेन्द्रित व्यवस्था

पहले उल्लेख किया गया है कि बहुलवादी राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि सभाओं की अक्षमता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। बहुलवादियों के अनुसार लगभग यही स्थिति प्रशासन में विद्यमान है। यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि केन्द्रीकृत प्रशासन से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है किन्तु यदि यह व्यवस्था एक उचित या निश्चित सीमा को पार कर जाती है तब अक्षमता, निष्क्रियता, अपव्यय आदि परिणाम स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं। अति केन्द्रीकृत व्यवस्था बहुलवादियों के अनुसार एक पुरानी राजनीतिक बीमारी है जिसका उपचार आवश्यक है। विवल्प के रूप में बहुलवादी गिल्ड समाजवादियों की भाँति, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण (Administrative de-centralisation) का सुझाव देते हैं।

बहुलवादी क्षेत्रीय तथा कार्यात्मक (administrative and functional) दोनों ही प्रकार के विकेन्द्रीकरण का समर्थन करते हैं। उनका यह विकेन्द्रीकरण इंग्लैंड के वितरणवादी (Distributionists) जिनमें बेलोक (M. Belloc) प्रमुख थे, तथा फ्रांस के क्षेत्रीयवादी (Regionalists) जिनमें डेसचनेल, हेनेमी, रिबॉट (P. Deschanel, J. Hennessy, A. Ribot) आदि प्रमुख हैं के विचारों पर आधारित है। इंग्लैंड के वितरणवादी, कोकर के अनुसार, सम्पत्ति का वैयक्तिक स्वामित्व तथा सभ्यता के छोटे-छोटे समुदायों के मध्य स्वेच्छापूर्वक सहयोग का समर्थन करते थे। इसका उद्देश्य किसी एक स्थान पर राजनीतिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकना था। बहुलवादियों का विकेन्द्रीकरण मुख्यतः आर्थिक है, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण तो केवल एक साधन मात्र है। वे प्रशासनिक क्षेत्रों का पुनर्गठन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता का अनुमोदन करते हैं।²⁷

बहुलवाद तथा गिल्ड समाजवाद

बहुलवाद तथा गिल्ड समाजवाद का अध्ययन करते समय यह आभास लगता है जैसे ये दोनों एक ही ही। इसका प्रमुख कारण इनके कुछ विचारों और समर्थकों का एक होना है। हेरॉल्ड लास्की मार्क्सवादी, समाजवादी होते हुए भी बहुलवादी थे। बोल की गणना गिल्ड समाजवादी और बहुलवादी दोनों में ही की जाती है।

विचारों की दृष्टि से बहुलवाद तथा गिल्ड समाजवाद दोनों ही राज्य का किसी न किसी रूप में व्यापक विरोध करते हैं; दोनों विकेन्द्री व्यवस्था के प्रबल समर्थक हैं, दोनों क्षेत्रीय प्रतिनिधि व्यवस्था के आलोचक हैं तथा व्यावसायिक प्रतिनिधि प्रणाली का अनुमोदन करते हैं। दोनों में सबसे प्रमुख विचार-समता उनके द्वारा समाज के छोटे-छोटे समुदायों का समर्थन करना है।

किन्तु इनकी विचार-समता होते हुए इन भी दोनों को एक ही विचारधारा समझना मूल होगी। गिल्ड समाजवाद एक पूर्ण विचारधारा की श्रेणी में आता है। गिल्ड समाजवाद के अन्तर्गत प्रचलित सामाजिक व्यवस्था का विवेचन तथा उस आधार पर पूँजीवाद का विरोध, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था के विषय में इसके विचार-सूत्र एवं उद्देश्य, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये साधनों आदि सभी की व्याख्या मिलती है। बहुलवाद को केवल राज्य प्रभुता अथवा प्रभुता के एतत्त्ववादी सिद्धान्त के विरोध के अन्दर्भ तक ही सीमित रखा जाता है। शास्त्र में बहुलवाद को विचार-धारा की श्रेणी में लेना ही सम्भव नहीं। इनके अतिरिक्त गिल्ड-समाजवाद एक समाजवादी शाखा है, बहुलवाद समाजवादी अथवा अन्य किसी प्रकार की विदेशीय तथा समुदायवादी व्यवस्था हो सकता है। इस प्रकार दोनों में आहत समता होती है।

बहुलवाद का मूलभाजन

बहुलवादियों ने राज्य सम्प्रभु सिद्धान्त पर प्रत्येक ओर से प्रहार किया है। उनके दृष्टिकोणों का निष्कर्ष है कि वे इसे एक अनिष्टकारी एवं अर्थ का सिद्धान्त मानते हैं। उनके सुभाव भी उन्मूलक एवं अतिवादी है। ए० डी० लिण्डसे ने कहा है कि यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट है कि सम्प्रभु राज्य का सिद्धान्त खण्डित हो चुका है।²⁸ इस सिद्धान्त के सबसे कटु आलोचक हेराल्ड लास्की का विचार है कि राजनीतिक दर्शन के लिये प्रभुता के आधुनिक सिद्धान्त को बंध बनाना सम्भव नहीं है। यदि सम्प्रभुता को सम्पूर्ण सत्त्वता का परिधान कर दिया जाय तो यह राजनीति शास्त्र का एक स्थायी हित होगा।²⁹

राज्य सम्प्रभुता अथवा सम्प्रभुता के एतत्त्ववादी सिद्धान्त के विरुद्ध बहुलवादियों ने आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं किन्तु बहुलवाद स्वयं दोनों से मुक्त नहीं है। बहुलवाद को भी आलोचना कई पक्षों को लेकर हुई है। बहुलवाद के विरुद्ध सबसे प्रारम्भिक आलोचना यह है कि बहुलवाद का एक पृथक एवं स्पष्ट अवधारणा नहीं बन सका है। बहुलवाद को इस स्थिति में लाने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व इसके समर्थकों पर है। कोल गिल्ड समाजवादी, फेडियनवादी, बहुलवादी सब कुछ हैं। मिम फिलिट तथा अन्य बहुलवादी तथा सम्प्रभुतारहित राज्य के आदर्श को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। यही बात बहुलवाद के अन्य समर्थकों के विषय में है। ऐसे समर्थकों के कारण बहुलवाद एक पृथक अवधारणा के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रखने में सदैव लड़खड़ाता रहा। कई स्थलों पर गिल्ड समाजवाद तथा बहुलवाद समाधानतर चलने हैं।

अन्तिम कारक के अनुसार बहुलवादियों के विरतपण में दोष कुछ तो इस कारण है कि वे स्पष्ट रूप से यह बतलाने में असमर्थ रहें हैं कि एकत्ववादी समर्थकों

28. Lindsay A.D., The Modern Democratic State, pp 64—66

29. Laski, H.J., A Grammar of Politics, p 445

ने राज्य के जो विभिन्न कर्त्तव्य बतलाये हैं उनमें से वे किन कर्त्तव्यों को स्वीकार नहीं करते। इनके अनिश्चित कुछ दोष उनकी इन आधारभूत मान्यता के कारण हैं कि यदि केवल व्यक्ति या समुदाय राज्य के नियन्त्रण से मुक्त कर दिया जाय तो हमें ऐसी प्रवृत्ति प्राप्त होगी जिसमें स्वतः प्रवर्तित कार्य एवं आत्म-प्रभिव्यक्ति स्वतन्त्र रूप से हो सकेगी। अनुभव में यह मान्यता मध्य प्रमाणित नहीं होती।³⁰

कुछ बहुलवादियों के विचारों को एक सीमा तक निष्पक्ष अध्ययन नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जब राज्य सम्प्रभुता का श्रृंखलन कर समूहों एवं समुदायों का समर्थन किया उसके पीछे उनका पूर्व निर्धारित उद्देश्य था। फ्रिंस ने गियर्क के समूह व्यक्तित्व सिद्धान्त का समर्थन चर्च की स्वायत्तता के लिये किया। उसके परे यह अधिक नहीं देख सके। इसी प्रकार वास्को का उद्देश्य श्रम संगठनों की भूमिका में वृद्धि कर उन्हें अधिक स्वायत्त एवं शक्तिशाली बनाना था।

बहुलवादी परस्पर-विरोधी विचारों में भी उलझे हुए प्रतीत होते हैं। एक ओर वे राज्य की सम्प्रभुता का विभिन्न संधों में विभाजन चाहते हैं, दूसरी ओर उनका रुतना है कि समन्वयपरक शक्तियाँ राज्य को सीप दी जायें। गियर्क तथा मेटलेन्ड समूहवादी होने हुए भी राज्य की अन्तिम वैध सत्ता का चुनौती नहीं देते। सम्भवतः वे सीमित सम्प्रभु तथा अपग रहकर कार्य करने वाले राज्य की कल्पना करते हैं। शान्ति में राज्य को चाहे कितने ही सीमित कार्य क्यों न दिये जायें वह इन कार्यों को तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे अन्य समूहों की तुलना में किसी न किसी प्रकार की कानूनी सर्वोच्चता प्रदान न की जाय। यदि राज्य को यथार्थ में संधों का संघ, समुदायों का समुदाय बनना है तथा समाज के विभिन्न संघों के मध्य समन्वय और संतुलन स्थापित करना है, डा० आर्शीर्वाल्डम् के विचार से निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं—

प्रथम, राज्य को किसी ऐसी मस्या या संध का अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहिये जो मार्शजनिक्त हिन या नीति के विरुद्ध हो। द्वितीय, राज्य को सभी संधों या संस्थाओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी समुदाय को उसकी अधिक मस्या या दबाव डालने की अधिक क्षमता के कारण कोई विशेष शिष्यायने नहीं देनी चाहिये। तृतीय, राज्य द्वारा किसी भी संस्था को ऐसे कार्य नहीं करने देने चाहिए जिसका दायित्व राज्य या अन्य संधों ने पहले ही ले रखा है। उदाहरणार्थ किसी भद्र संघ को राजनीतिक कर तथा किसी धार्मिक संस्था को राजनीति कार्य-करने की अनुमति न दी जाय।³¹

फ्रिंस ने राज्य को 'समुदायों का समुदाय' माना है। वास्तव में राज्य की यह स्थिति किसी भी दृष्टि में नहीं हो सकती। राज्य के पाम दमनकारी शक्ति इन समु-

³⁰ कोकर; धाधुनिक राजनीतिक चिन्तन, 547.

³¹ आर्शीर्वाल्डम्; राजनीति शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ. 714.

दायो को अपनी सीमा के भीतर रखने के लिय आवश्यक है। बाकर का कहना है कि बहुलवादी प्रवृत्ति में हमें बहुत धागे नहीं बढ़ जाना चाहिए।³²

आलोचको का कहना है कि यदि राज्य तथा अन्य संगठनों को एक ही स्तर पर रखा जाय, यदि समाज में सत्तापूर्ण तथा किसी उच्च समन्वयपरक सत्ता का अभाव रहे इस स्थिति का परिणाम अराजकतावाद होगा। समाज न तो अनुशासित रह सकेगा और न व्यवस्थित। समाज का संगठन, व्यवस्था, समन्वय आदि कार्य और वह भी शान्तिपूर्ण ढंग से, राज्य सत्ता के बिना नहीं किये जा सकते।

बहुलवादी निरकुशता तथा नियंत्रण का विरोध करते हैं। किन्तु जिमर्न (A. E. Zimmerman) का कहना है कि बहुलवादी व्यवस्था भी कम अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं होगी। 'जो व्यक्ति राज्य की निरकुशता की बात करते हैं, वे इस सरल तथ्य की उपेक्षा करते हैं कि समीप के पड़ोसों के अत्याचार के समान अत्याचार दूसरा नहीं। समुदाय जितना ही छोटा होगा उतना ही अधिक बड़ा आपके जीवन तथा कार्यों पर प्रतिबन्ध होगा।'³³

बहुलवादी वितरणावादी है। व राज्य सत्ता तथा कार्यों को विभिन्न समूहों में विभाजित करता चाहते हैं। उनकी यह अवधारणा दासपूर्ण तथा अस्वाभाविक है। विभिन्न संगठनों के कार्यों का स्पष्ट विभाजन सम्भवतः सम्भव नहीं। राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की सह-सम्प्रभुता (Co-Sovereignty) से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त एक संगठन या समूह पूर्णतः एक कार्य या हित तक सीमित नहीं रख सकता। दूसरे संगठनों के कार्यों से उसकी स्पर्धा एवं टकराव हो सकता है। बहुलवाद के अन्तर्गत राज्य बनाम समूहों की समस्याओं का समाधान तो पहले ही नहीं हो सकेगा किन्तु इसके अतिरिक्त 'समूह बनाम समूह' की समस्याएँ और उत्पन्न हो जायगी। बहुलवाद उतनी समस्याओं का समाधान नहीं करता जितना कि समाज में समस्याओं को उत्पन्न करेगा।

बहुलवाद के विरोधियों का कहना है कि बहुलवाद के समर्थकों ने व्यर्थ में ही एक असंमित सम्प्रभु-सम्पन्न राज्य की कल्पना के सपने में अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। हागल का छाड़कर सम्भवतः किसी भी एकत्ववादी न राज्य का सर्वशक्तिमान नहीं माना है। एकत्ववादी स्वयं ही मानते हैं कि राज्य कई दृष्टियों से सीमित है। वादा, हानि आदि न भी इस दाव का दावा नहीं किया कि राज्य सत्ता को आलोचना, उमका अवज्ञा तथा उसका विरोध अनैतिक, अधार्मिक या असा-भाजिक है। गैटिल के अनुसार राज्य नैतिक व्यथना से सीमित है।

बोर्दा, हॉब्स तथा अस्तित्व द्वारा प्रतिपादित सम्प्रभु सिद्धान्त व प्रति कोकर का दृष्टिकोण उतना आलोचनात्मक नहीं है जितना कि अन्य आलोचकों का है।

³² Barker, E., Political Thought in England, pp 178-79

³³ उद्धृत, कोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ० 547

कोर ने इसे 'तथाकथित अर्द्धतवादी सिद्धान्त' कहा है। इसके अनुसार शारीरिक, बौद्धिक या सामाजिक दृष्टि से यह असीमित सत्ता का सिद्धान्त नहीं है। किसी भी अर्द्धतवादी या विश्लेषणकारी कानूनवेत्ता ने यह नहीं कहा है कि किसी राज्य के प्रभुत्वगम्य विभागों की वास्तविक नीति में लोकमत द्वारा संशोधन नहीं हो सकता। कोर के अनुसार ये केवल इतना मानते हैं कि राज्य का अस्तित्व कानून निर्माण करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिये है। इसलिये उस पर इस प्रकार की मर्यादाएँ नहीं लगाई जा सकती जिनका निर्माण करने और कार्यान्वित करने के लिये उसी स्थापना हुई है। तथाकथित एकत्ववादी गमयक राज्य को उत्तरदायित्वहीन नहीं मानते। ये केवल इतना ही मानते हैं कि सम्प्रभु किसी ऐगो सत्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकता जो उसी के समान या प्रकार की हो। संक्षेप में, कोर ने लिखा है कि एक नियत प्रदेश में कानून के निमित्त सगठन के रूप में राज्य उस प्रदेश में अंतर्गत अन्य समस्त समुदायों में कानूनी दृष्टि से सर्वोच्च है।³⁴

बहुलवाद का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी दोषरहित नहीं है। ये अन्तर्राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्रीय शक्ति (जिसे सम्प्रभुता कहा गया है) पर अकुश एव प्रतिबंध लगाते हैं। किसी भी राष्ट्र के शक्ति को श्रद्धा पहले अपने देश के प्रति होती है तथा बाद में किसी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति। इनके प्रतिरिक्त समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के मंदन में बहुलवाद का अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष मयायंता से काफी दूर है। आज की शक्ति राजनीति में प्रत्येक राज्य बड़ी शक्ति बनना चाहता है, अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहता है, यह राष्ट्रीय हित से प्रेरित होता है, यह कोई भी वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय बन्धन स्वीकार नहीं करता।

उपर्युक्त आलोचनाओं के अध्ययन से जो सबसे प्रमुख तत्त्व स्पष्ट होता है वह यह है कि बहुलवाद को सम्पूर्ण अवधारणा एवं संरचना राज्य के व्यापक अधिकार तथा राज्य सम्प्रभुता की आलोचना के आधार पर गड़ी की गई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि बहुलवादी समाज में अन्य संप्रो एव समुदायों को अधिवाधिक स्वायत्तता प्रदान करना चाहते हैं। यदि वास्तव में देखा जाय तो केवल विकृत राज्य को धाँवर सम्प्रभुता के विरोधी विचार तथा व्यावसायिक सचवाद में कोई पारस्परिक विरोध नहीं होना चाहिये। एक मयायंवादी एकत्ववादी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि राज्य स्वतः ही सामाजिक सगठनों को अधिक स्वायत्तता दे, उनमें वास्तविक कार्यों में हस्तक्षेप न करे, ऐसी स्थिति में बहुलवाद स्वयं ही मुरझा जायेगा।...

प्रतिनिधि सरकार, चुनाव प्रणाली तथा व्यावसायिक दल व्यवस्था भी दोषों से मुक्त नहीं है। वा हिमिघाओं का विचार है कि बहुलवादियों के इन विचारों में

³⁴ कोर., आधुनिक राजनीतिक चिन्तन, पृ० 532-33.

सम्प्रभुता को सम्मिलित करना और अन्त में राज्य के निरंकुशवाद एवं पैतृकवाद के विरुद्ध दृढ़तया व्यापक प्रतिक्रिया तथा साथ ही साथ किसी एक संस्था की सम्प्रभुता के विरुद्ध चेतावनी देना आदि बहुलवाद के महत्त्व को कोई भी निष्पक्ष विद्यार्थी स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता।³⁷

मिस फॉलेट (Miss Follett) ने अपनी पुस्तक—The New State—में बहुलवाद की निम्नलिखित अर्थात् अर्थों पर प्रकाश डाला है—

(i) बहुलवादियों ने सम्प्रभुता-सम्पन्न सिद्धान्त को निराधार सिद्ध कर दिया है;

(ii) वे संघ जीवन की विविधता को स्वीकार करते हैं जिसे राजनीतिक दृष्टि से मान्यता मिलनी चाहिए;

(iii) वे स्थानीय जीवन को फिर से जीवित करने की माग करते हैं;

(iv) उनका विचार है कि राज्य और उनके विभिन्न अंगों के हित सदैव एकरूप नहीं होते;

(v) बहुलवाद जनता के असंगठित समूह रूप की समाप्ति का प्रारम्भ है जो व्यवस्थित समूह रूप की ओर अग्रसर करेगा; तथा

(vi) बहुलवाद मनुष्य के व्यक्तिगत स्वरूप, उसके दलीय सदस्य के स्वरूप, उसके राज्य के सदस्य के स्वरूप को सही ढंग से बताने का प्रयत्न है।

सूक्ष्म में बहुलवाद लोकतन्त्र पर बल देता है; यह व्यक्तिवाद के प्रति आक्षेपित है; यह बहुलवाद है जिसके अन्तर्गत समाज में विभिन्न समुदायों के अधिकारों का समर्थन होता है, यह सर्वशक्तिशाली राज्य का विरोध करता है तथा विकेन्द्रीकरण का समर्थक है।³⁸ निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि बहुलवाद प्रतिवादी राज्य के विरुद्ध वांछित प्रतिक्रिया था। हीगेल का यह विचार कि राज्य का प्रत्येक कार्य सही है उचित प्रतीत नहीं होता। हमें एकत्ववाद तथा बहुलवाद के उचित विचारों को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हेगेल का बहुलवाद निष्कर्ष कि 'मैं यथासम्भव एकत्ववादी हूँ किन्तु अन्य विकल्प न होने पर बहुलवादी बनने को तैयार हूँ' बहुलवाद और एकत्ववाद के यथार्थवादी समन्वय का समर्थन है। किन्तु राज्य वैधानिक दृष्टि से सर्वोपरि है। सधों की महत्ता स्वीकार करने का तात्पर्य राज्य को उनके स्तर पर नहीं लाया जा सकता।

Kalpana

37. Hsiao, Kung Chuan; Political Pluralism, pp 243-249.

38 उद्धृत, आशोर्वादन; राजनीति-शास्त्र, द्वितीय खण्ड, पृ० 713.

पाठ्य ग्रन्थ

- 1 Barker, E , Political Thought in England,
from Spencer to to day
- 2 कोकर, आधुनिक राजनीतिक चिन्तन,
अध्याय 18, राज्य-प्रभुता पर बहुवादियों का आरोप
3. Elliot W Y , The Pragmatic Revolt in Politics,
Chapter III and IV
- 4 Gettell, R G History of Political Thought
Chapter 29, Pluralistic Theories of
Sovereignty
- 5 Gierke Otto Von, Political Theories of the Middle Age,
Introduction by F W Maitland
- 6 Hsiao, Kung chuan, Political Pluralism
- 7 Laski, H J , A Grammar of Politics,
Chapter 2, Sovereignty
Chapter 7, Authority as Federal
- 8 Lindsay, A D , The Modern Democratic State
- 9 MacIver, R M , The Modern State,
Introductory Chapter - What is the State
- 10 Maine, Sir Henry, Lectures on the Early History of
Institutions Chapter 15. Sovereignty

हेरॉल्ड लास्की के राजनीतिक विचार

प्रोफेसर हेरॉल्ड जसिक लास्की (Harold J. Laski) का जन्म 30 जून 1893 में मेनचेस्टर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये नाथन लास्की (Nathan Laski) तथा साराह लास्की (Sarah Laski) के द्वितीय पुत्र थे। लास्की परिवार की समृद्धशाली, कट्टरपथी तथा वहाँ के यहूदी समुदाय का नेतृत्व करने वाला था। बचपन से ही लास्की प्रतिभाशाली, अमाधायक तथा अद्भुत स्मरणशक्ति वाले थे। वे जन्मजात विद्रोही थे। उन्होंने अपनी पारिवारिक परम्पराओं तथा यहूदी धर्म की रूढ़िवादिता के विरुद्ध विद्रोह किया। अपने शिक्षण एवं शिक्षक जीवन में वे विद्रोही रहे। 1911 में अठारह वर्ष की उम्र में उन्होंने स्वयं से अधिक उम्र वाली गैरयहूदी लड़की फ्रिदा (Frida) से विवाह कर अपने परिवार के विरुद्ध विद्रोह का पूर्ण परिचय दिया। परिणामस्वरूप अपने माता-पिता के दबाव के कारण इन्हें कई वर्षों तक अपनी पत्नी से पृथक रहना पड़ा। अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में वे सदैव विद्रोही रहे।

1910 में, लगभग 17 वर्ष की आयु में वेस्टमिन्स्टर रिव्यू (Westminster Review) में लास्की का एक लेख—On the Scope of Eugenics (सुजनन के विषय पर) प्रकाशित हुआ, जिसकी कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने प्रशंसा की। 1911 से 1914 तक लास्की ने आक्सफोर्ड में अध्ययन किया। प्रारम्भ में उन्होंने विज्ञान का अध्ययन किया जिससे उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। बाद में उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया तथा 1914 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। कई प्रसिद्ध विद्वान जैसे फिशर (H.A.L. Fisher), मैटलैंड (F.W. Maitland) बार्कर (Ernest Barker) आदि उनके शिक्षक थे। 1914 में लास्की का अध्ययन समाप्त हुआ तथा इसी वर्ष इंग्लैंड के प्रसिद्ध समाचार-पत्र डेली हेरॉल्ड (Daily Herald) के सम्पादक मण्डल के एक प्रमुख सदस्य बन गये। प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ होते समय लास्की ने स्वयं को सेना में भर्ती कराना चाहा किन्तु अच्छा स्वास्थ्य न होने के कारण भर्ती नहीं किया गया। इस समय लास्की ने मैकगिल (McGill) विश्व-विद्यालय में अध्यापन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया, जहाँ उन्हें इतिहास का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। 1916 से 1920 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रहे। तदुपरान्त इंग्लैंड वापस आ गये। 1923 से 1950 तक लास्की ने लंदन

स्कूल थाफ इन्वॉलिव्ह मे अध्यापन कार्य किया जहा उन्हे सर्वाधिक श्याति मिली । उस समय लास्की के बिना लन्दन स्कूल थाफ इन्वॉलिव्ह की कल्पना नहीं की जा सकती थी ।

लास्की सक्रिय राजनीतिज्ञ भी थे । वे पेबियन सोसाइटी तथा लेबर दल के प्रमुख सदस्य रहे । कई वर्षों तक वे लेबर पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे । 1945 में लेबर पार्टी जब सत्ता में आई लास्की उसके अध्यक्ष थे, किन्तु वे सत्ता से सदैव दूर रहे । यह उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ विशेषता रही ।

लास्की को एक शिक्षक राजनीतिक चिन्तक, पत्रकार, लेबर पार्टी के नेता, स्वायंजनिब घत्ता तथा उस समय के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञों के प्रमुख सलाहकार के रूप में काफी श्याति मिली । विश्व के कई प्रमुख विश्वविद्यालयों में उन्हे व्याख्यान देने के लिए उन्हे आमन्त्रित किया । सम्भवत इतनी चतुर्मुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति इ ग्लैंड में इनके पहले न हुआ हो । लास्की के लेखों तथा ग्रन्थों को विश्व के लगभग सभी अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में पढ़ा गया । इनके लिपियों तथा मित्रों का विश्व भर में ज्ञान फैला हुआ था । इ ग्लैंड के प्रमुख बुद्धिजीवी एव छोटी के नेताओं के अनिरिक्त प्रमरीकी सार्धजनिक जीवन में कई प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमरीकी उच्चतम न्यायालय के कई न्यायाधीश जैसे जस्टिस पलिकस फ्रैंकफर्टर जस्टिस होम्स, प्रमरीकी राष्ट्रपति लविल तथा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उनके मित्रों की श्रेणी में आते थे । उनके विद्यार्थी देश विदेशों में कई उच्च पद आसीन रहे । भारत में श्री कृष्ण मेनन लास्की के प्रिय शिष्यों में से एक थे । अविकसित राष्ट्रों का सम्भवत कोई भी समाजवादी उनके प्रभाव से मुक्त नहीं रहा है । लास्की ने अपने लिए इतनी गतिविधियों से सम्बद्ध रखा जिनका निर्वाह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था । लोगों का विश्वास है कि लास्की जीवन भर अपनी बहुमुखी गतिविधियों में इतने व्यस्त रहे जिनसे उन्होंने स्वयं को ही समाप्त कर दिया । मार्च 1950 में पेफडो में पीडा हो जाने से 57 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई ।

लास्की ने लगभग 35 वर्षों में दर्जनों पुस्तकें एव लेख लिखे । लेखन क्षेत्र में उनकी समता इने गिने व्यक्ति ही कर सकते हैं । स्वाभाविक था कि लास्की राजनीति शास्त्र से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर विचार व्यक्त करते । उनकी लेखनी में राजनीति शास्त्र का शायद ही कोई पक्ष बचा हो ; इसलिए यह असम्भव है कि लास्की के सभी विचारों को प्रस्तुत किया जा सके ; यहाँ लास्की के केवल कुछ महत्वपूर्ण विचारों की व्याख्या करना ही सम्भव हो सका है ।

लास्की के विचारों का अध्ययन करने समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वे एक प्रयत्नशील विचार्क थे तथा नई नई घटनाओं और परिस्थितियों के परिदृश में उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया । लास्की के

राजनीतिक विचारों के प्रसिद्ध लेखक हर्वर्ट डीन¹ ने लास्की के विचार परिवर्तनों को निम्नलिखित कालचक्र में विभाजित किया है—

1. 1914-1924. इस दशाब्दी में लास्की बहुलवाद के प्रमुख समर्थक थे ।

2. 1925-1931. यह समय 1925 में प्रकाशित लास्की की पुस्तक—*A Grammar of Politics* से प्रारम्भ होता है । यह काल लास्की के विचार परिपक्वता का है । वे समाजवाद की ओर अग्रसर होते हैं ।

3. 1932-1939. यह काल 1931 में रेमजे मेकडॉनैल्ड की राष्ट्रीय सरकार बनने के बाद से द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक का है । इस काल में लास्की के विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं । 1933 में उनकी प्रकाशित पुस्तक - *Democracy in Crisis* - में उन्होंने राजनीति के नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया । उनके विचारों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ ।

4. 1940-1945. यह द्वितीय विश्व-युद्ध का समय था । इन वर्षों में लास्की युद्धवादी तथा राजनीतिक गतिविधियों में अत्यन्त व्यस्त रहे । यद्यपि इन वर्षों में उनके व्याख्यानो तथा लेखों की भरमार रही किन्तु उनमें प्रचार की मात्रा अधिक थी । इस समय उन्हें पूर्ण चिन्तन का अवकाश नहीं मिल सका ।

5. 1946-1950. युद्धोत्तर काल तथा 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद उनकी मृत्यु तक लास्की अपनी राजनीतिक तथा अन्य कई गतिविधियों में अत्यन्त व्यस्त रहे । इन वर्षों में 1948 में प्रकाशित लास्की का प्रमुख ग्रन्थ—*The American Democracy*— को एक पुराने विचारों वाला ग्रन्थ ही कहा गया है । लास्की के विचारों में कोई नवीनता नहीं रही । साथ ही साथ इस काल में उन ही कुछ धारणाएँ भी गलत सिद्ध हुईं । इन काल में लास्की अपने विचारों को पुनः व्यवस्थित करते हुए प्रतीत होते हैं ।

राज्य सम्प्रभुता और बहुलवाद

अपने अध्ययन काल में लास्की पर बहुलवादियों का बड़ा प्रभाव पड़ा । एर्नेस्ट बार्कर (Ernest Barker) के लास्की निष्पक्ष थे । गिदक (Otto Von Gierke) के बहुलवादी विचारों को फ़िगिस और मेटलेण्ड ने लास्की तक पहुँचाया ।

1914 से 1920 तक लास्की उत्तरी अमेरिका में रहे । यहाँ उनके बहुलवादी विचारों पर विलियम जेम्स (William James) तथा जॉन डीवी (John Dewey) का प्रभाव पड़ा । लास्की प्रायः जेम्स के इस कथन को उद्धृत करते रहते थे कि 'हम एक विश्व में नहीं कई विश्वों में रहते हैं' (We live in multiverse and not in a universe).

लास्की के प्रारम्भिक विचार सम्प्रभुता के एकत्ववादी सिद्धान्त पर प्रहार से

¹ Deanes, Herbert A., *The Political Ideas of Harold J. Laski*, 1954.

प्रारम्भ होते हैं। 1917 में प्रकाशित पुस्तक—*Studies in the Problems of Sovereignty*² में लास्की ने सम्प्रभुता से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का विवेचन कर सम्प्रभु के कात्पनिक एकत्ववादी सिद्धान्त की तीव्र घालोचना की है। लास्की के मतानुसार एकत्ववादी सिद्धान्त का मूल विचार राज्य का सम्प्रभु सिद्धान्त है जिसे बोदा घोर हॉम्स ने विकसित किया तथा जॉन मास्टिन ने प्राधुनिक कानूनी रूप दिया। लास्की ने अपनी घालोचना द्वारा सम्प्रभुता सिद्धान्त का निम्नलिखित तर्कों से पूर्णतः खण्डित करने का भरसक प्रयास किया है—

① राज्य तथा नागरिक—लास्की का कहना है कि यदि राज्य और नागरिकों के सम्बन्धों को देखा जाय तो मास्टिन के सिद्धान्त जैसी बात कही पर लागू नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति सदैव ही राज्य की आज्ञा का पालन करे। जब राज्य तथा चर्च, राज्य तथा श्रमिक सघों जैसी संस्थाओं के मध्य सघर्ष हो ऐसी स्थिति में चर्च तथा श्रमिक सघ की ओर नागरिकों की श्रद्धा का अधिक झुकाव होता है। यदि व्यक्ति स्वभावतः राज्य की आज्ञा का पालन करता होता तब पुलिस तथा न्यायालयों को रखने की आवश्यकता न होती। लास्की का तर्क है कि राज्य के प्रति नागरिकों की श्रद्धा सदैव पूर्ण एवं अन्तिम नहीं होती।

② सम्प्रभुता और नैतिकता—लास्की के अनुसार सम्प्रभु सिद्धान्त का नैतिक आधार पर भी समर्थन नहीं किया जा सकता। मास्टिनवादी राज्य के अन्तर्गत मनुष्यों में पूर्ण आज्ञाकारिता की भावना का विकास होगा। वह स्वभाव से राज्य की अच्छी बुरी सभी आज्ञाओं का अन्धा पालन करेगा। इसका तात्पर्य होगा कि मनुष्य का स्वयं का विवेक और अन्तःकरण जैसी कोई चीज नहीं होगी तथा वह अपनी निर्णय क्षमता सदैव के लिये राज्य को शरोहर रखा देगा। यह सिद्धान्त, लास्की के अनुसार, नागरिकों के व्यक्तित्व तथा नैतिक विकास में बाधक होगा।

③ समाज, राज्य, सरकार में भेद—लास्की ने सम्प्रभुता को पुनः परिभाषित किया है। इसके अन्तर्गत वह राज्य तथा समाज, राज्य तथा सरकार के मध्य विभाजन रेखा खींचते हैं। लास्की ने घादशंकादियों की घालोचना करते हुए लिखा है कि वे राज्य तथा समाज में भेद स्थापित करने में असफल रहे। वे यह भूल जाते हैं जिस तरह व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध होते हैं वैसे ही व्यक्तियों व पारस्परिक, सामाजिक संबंध होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति राज्य के माध्यम से नहीं हो सकती। लास्की का

² इसके प्रतिरिक्त लास्की की निम्नलिखित पुस्तकों में सम्प्रभुता एवं बहुलवाद से सम्बन्धित विचार मिलते हैं—

Authority in the Modern State, 1919.
A Grammar of Politics, 1925

कहता है कि समाज के प्रति व्यक्ति के प्राथमिक कर्तव्य हैं तथा राज्य के प्रति श्रद्धा इसके उद्गार ही हो सकती है।³

इसी प्रकार लास्की राज्य और सरकार को लेकर आदर्शवादियों की आलोचना करते हैं। लेकिन सप्रभु मिदान्त का उलटन करने की प्रक्रिया में लास्की राज्य को सरकार के स्तर पर ला देते हैं। लास्की का विचार है कि जिसे हम राज्य का कार्य कहते हैं वह वास्तव में सरकार द्वारा कार्य होता है।

3) राज्य का वितरणत्मक स्वरूप—राज्य सप्रभुता के एकत्ववादी मिदान्त का ध्वस्त करके लास्की ने बहुलवादी विरुद्ध प्रस्तुत किया है। लास्की का कहना है कि राज्य निरंकुश एवं निरपेक्ष नहीं होता जिसके अन्तर्गत सब कुछ समा जाय तथा विमर्श मात्र पर नियंत्रण हो। राज्य के विभिन्न भाग भी वास्तविक एवं स्वयं-निर्भर होते हैं। राज्य वितरणत्मक (distributive) होता है, सामूहिक (Collective) नहीं। राज्य विभिन्न मानव समुदायों में से एक है, राज्य तथा वेमवॉल क्लब के स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं है।⁴ किन्तु हमका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिये कि राज्य को समाप्त कर दिया जाय। लास्की राज्य को अधिक महत्व नहीं देते।

4) बहुतंत्रवाद (Polyarchism)—लास्की का बहुलवाद अति व्यक्तिवाद की श्रेणी में आता है। व्यक्ति राज्य महित कई समुदायों का सदस्य होता है। इन समुदायों में मनुष्य की निष्ठा के लिये स्पर्धा सम्भव हो सकती है। इस संघर्ष में व्यक्ति जिस समस्या के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करना चाहे उसके लिये वह स्वतन्त्र है। लास्की का मुख्य विचार है कि नू कि समाज स्वभावतः संघात्मक है सप्रभु सत्ता राज्य या किसी अन्य समन्वयकारक समस्या को देना विवेकहीन होगा। सामाजिक संगठन में सत्ता वहा रहनी चाहिये जहा उसका विवेकपूर्ण तथा सामाजिक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये उपयोग किया जा सके।⁵

लास्की के अनुसार प्रत्येक समाज में विविध प्रकार के व्यावसायिक और धार्मिक हित होते हैं। ये हित न तो एकरूप हैं न समान। उनलिये इन हितों को एकरूप बनाने का प्रयत्न नहीं किया जाय। बहुलवादी राज्य संघात्मक होगा जिसमें सप्रभु सत्ता विभिन्न व्यावसायिक समुदायों एवं समूहों तथा समाज के विभिन्न श्रेणीय विभागों में वितरित होगी। सप्रभु राज्य की संरचना गोपान पद्धति (hierarchical) जैसी होती है जबकि बहुलवादी राज्य कई समुदायों का समूह होगा।⁶ लास्की ने इस प्रकार की व्यवस्था को 'बहुतन्त्रवाद' (polyarchism) का नाम दिया है।

3 Laski, H J, Authority in the Modern State, p 122.

4 Deane, Herbert A., The Political Ideas of Harold J. Laski, p. 23.

5 Laski, H J, Authority in the Modern State, p 74

6. Ibid, p 84

लास्की का राजनीतिक सत्ता के केन्द्रीकरण में विश्वास नहीं है। राज्य सत्ता विभी एन केन्द्र या स्थान पर एकत्रित नहीं होनी चाहिए। लास्की का सुझाव है कि सत्ता का विभाजन होना चाहिए। यह विभिन्न कार्यों द्वारा विकेन्द्रीकरण के माध्यम से हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मनुष्य तथा उनके समूहों के धार्मिक, सामाजिक अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होगा।

1925 में प्रकाशित पुस्तक—*A Grammar of Politics*—में लास्की के विचारों में परिष्कृतता और प्रगतिशीलता की भूलक मिलती है। राज्य सम्प्रभुता के विषय में लास्की ने लिखा है—

'राजनीति शास्त्र के लिए यह एक स्थायी लाभ होगा यदि सम्प्रभुता की सम्पूर्ण अवधारणा को समाप्त कर दिया जाय। तब यह है कि जिन अवधारणा का हम उल्लेख कर रहे हैं वह, सम्प्रभुता नहीं, शक्ति है, और शक्ति के स्वभाव के विषय में महत्व उसी उद्देश्य का है जिसके लिये इसका प्रयोग किया जाता है तथा जिन प्रकार उस उद्देश्य के लिये शक्ति को कार्य में लाया जाता है।'⁷

यहां लास्की सम्भवतः यह स्वीकार करने को तत्पर प्रतीत होते हैं कि सम्प्रभु के कानूनी या वैध मिद्धान्त को चुनौती नहीं दी जा सकती किन्तु इसे राज्य का एक सामान्य औपचारिक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। लास्की सम्प्रभुता का एक अनुभववादी विवेचन करते हुए कहते हैं कि राज्य की सम्प्रभुता केवल वह शक्ति एव सत्ता है जिसके द्वारा कृष्य उद्देश्य और उत्तरदायित्व पूरे किये जाते हैं।⁸ लास्की का यह विवेचन राज्य की शक्तिशाली या निर्बल बना सकता है। यह इस पर निर्भर करेगा कि राज्य के क्या उद्देश्य हैं, उसकी क्या सीमाएँ हैं तथा उस सन्दर्भ में सत्ता का क्या तक प्रयोग किया जाय।

1929-30 तक लास्की अभी भी बहुदलीयता का समर्थन करने हैं किन्तु राज्य के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। यद्यपि लास्की का कहना है कि राज्य की इच्छा को सम्पूर्ण समाज को इच्छा नहीं कहा जा सकता समाज के विभिन्न समुदाय मनुष्य के लिये अपने ही स्वामाविष्ट हैं जिनका कि राज्य। समुदाय अपने अस्तित्व के लिये राज्य पर निर्भर नहीं करते।⁹ किन्तु राज्य तथा अन्य समुदायों को एक ही स्तर पर नहीं लाया जा सकता। राज्य तथा अन्य समुदायों के स्वभाव

7 "it would be of lasting benefit to Political Science if the whole concept of sovereignty were surrendered. That, in fact, with which we are dealing is power, and what is important in the nature of power is the end it seeks to serve and the way in which it serves that end." Laski, H J, *A Grammar of Politics*, Ed 1950, pp 44-45

8 Laski, H J, *A Grammar of Politics*, p 662, Deane, Herbert A., *The Political Ideas of Harold J Laski*, p 78

9 Laski, H J, *A Grammar of Politics* pp 21, 28, 39 98

में मूल अन्तर यह है कि अन्तिम रूप में राज्य का साधन शक्ति है यह अन्य समुदायों के पास नहीं। अब लास्की यह स्वीकार करते हैं कि राज्य की इच्छा समाज की इच्छा का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य का समाज में वही स्थान है जो शरीर में हड्डियों के ढाँचे का।¹⁰ आवश्यकता पड़ने पर राज्य अन्य समुदायों पर उचित नियन्त्रण कर सकता है। साथ ही साथ लास्की यह भी स्वीकार करने लगे कि समाज में विभिन्न समुदायों को राज्य का उन्मूलन करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती।¹¹ ऐसा प्रतीत होता है कि लास्की अपने प्रारम्भिक बहुलवादी विचार तथा राज्य के विषय में अपने नवीन दृष्टिकोण का समन्वय करना चाहते हैं। अब लास्की का विचार है कि यदि राज्य मानव नन्तुष्टि के अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है तो उसके ऊपर दबाव डाला जाय ताकि राज्य अपनी निर्णय प्रक्रिया में व्यक्तियों और उनके समूहों को सम्मिलित कर सके। क्षेत्रीय योजना, गृह निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य द्वारा स्थानीय सत्ताओं का अधिक सहयोग लेना चाहिये।¹² 1931 में प्रकाशित—*An Introduction to Politics*—में लास्की राज्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। अब लास्की के अनुसार राज्य अपनी सत्ता उसकी सीमा के अन्तर्गत रहने वाले व्यक्तियों और समूहों पर लागू करता है। राज्य की इच्छा का नैतिक रूप में (यद्यपि नैतिक दृष्टि से नहीं) सम्प्रभु इच्छा है। लेकिन राज्य को अपनी सत्ता का प्रयोग सामाजिक मार्गों के अनुरूप ही करना चाहिये।¹³

10) लास्की के समाजवादी विचार

वचन में ही लास्की को कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनसे उनके समाजवादी विचारों का विकास हुआ। वास्तव में देखा जाय तो लास्की के समाजवाद का प्रारम्भ समानता की आकांक्षा से होता है। लास्की यहूदी थे। वचन में ही उन्होंने देखा कि यहूदी परिवार को राष्ट्रीय जीवन के मुख्य प्रवाह में किस प्रकार पृथक रखा जाता है, उनके साथ किस प्रकार भेदभाव रखा जाता है, उनके साथ किस प्रकार भेदभाव तथा असमानता का व्यवहार किया जाता है। आइमफोर्ड में अपने शैक्षणिक काल में भी उन्हें इसी प्रकार का अनुभव हुआ। किन्तु प्रांसफोर्ड में उनके समाजवादी विचारों को स्पष्ट दिशा देने में फेब्रियनवाद का योगदान रहा। वहाँ वे फेब्रियन समाजवादी शाखा के एक सक्रिय सदस्य थे।¹⁴

राजनीतिक आन्दोलन में एक सक्रिय सदस्य की भाँति लास्की ने सर्वप्रथम सहिता प्रताधिकार के समर्थन में भाग लिया। यह समानता के प्रति उनकी निष्ठा

10 Laski, H J, Liberty in the Modern State, p 174

11. Ibid., p 168

12 Deane, Herbert A, The Political Ideas of Harold J Laski, pp 93-98.

13 Laski H J, Politics, pp. 13-14 (quoted)

14 Deane, Herbert A, The Political Ideas of Harold J Laski, p. 51.

की अभिव्यक्ति थी। धीरे-धीरे वे ग्रामिक मण्डनों के समर्थक बनने लगे तथा लेबर दल की सक्रिय सदस्यता से उनके समाजवादी होने में श्रव किसी को प्रविश्वास नहीं रहा। समाजवाद, जैसा कि लास्की ने स्वयं स्वीकार किया था, उनके जीवन का मुख्य विश्वास था।

बहुलवादी विचारधारा पर लास्की अधिक वर्षों तक स्थिर नहीं रह सके। बदलती हुई परिस्थितियों के सन्दर्भ में लास्की यह अनुभव करने लगे कि बहुलवाद एक सम्पूर्ण विचारधारा नहीं हो सकती जो राज्य की नवीन भूमिका से सम्बन्धित चुनौती का सामना कर सके। धीरे-धीरे उनके विवेचन का स्वरूप समाजवादी होता चला गया।

हरॉड लास्की न्याय और स्वतन्त्रता की ओर पहले से ही पूर्णतः झुके हुए थे किन्तु कुछ परिस्थितियों ने उनके समाजवादी विचारों को और अधिक विकसित होने में योगदान दिया। लास्की ने मार्क्सवाद का व्यापक अध्ययन किया तथा मार्क्सवाद के कई पक्षों का विभाषण आर्थिक पक्ष का, उन्होंने समर्थन किया। किन्तु अभी वह पूर्ण मार्क्सवादी बनने में दूर थे।

1917 में रूस में साम्यवाद का आगि ने भी लास्की के विचारों को प्रभावित किया। यद्यपि वे लनिनवाद तथा रूस में नवीन क्रांति के कई विकासों से महमन नहीं थे, आगे चल कर वे रूस में साम्यवादी व्यवस्था का अनुपादन करने बाध बनत चले गये। किन्तु वे साम्यवादी नहीं थे। लास्की के विचार बहुलवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद के त्रिकोण में ही उनसे रहे, उन्होंने किसा एक आधार का अपना स्थिर स्थान नहीं बनाया।

1920 में उत्तरी अमेरिका में वापस आने के बाद लास्की का एक समाजवादी चिन्तन के रूप में देखा जा सकता है। इंग्लैंड में उन पर फेबियनवादियों का प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ वे इंग्लैंड के मजदूर दल (लेबर पार्टी) के एक सक्रिय सदस्य बने। यद्यपि लास्की ने सरकार में कभी कोई पद स्वीकार नहीं किया किन्तु वे लेबर पार्टी के शिखर तक पहुँचे तथा कई वर्षों तक वे इसका अध्यक्ष रहे। लेबर पार्टी के एक प्रमुख सैद्धान्तिक प्रवक्ता होने के कारण उन्होंने राजनीतिक समस्याओं एवं विचारों का समाजवादी विवेचन प्रस्तुत किया। मन्दन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स में लास्की जब तक राजनीति शास्त्र विभाग के अध्यक्ष रहे यह मस्यदा लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारों का विश्व भर में एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। राजनीतिक विचारों के इतिहास में लास्की का महत्त्व एक लोकतान्त्रिक समाजवादी के रूप में ही अधिक है।

बहुलवाद का समाजवादी विवेचन

राज्य सम्प्रभुता का खण्डन तथा बहुलवाद का अनुमोदन लास्की का प्रारम्भिक मूल विचार था। किन्तु मार्क्सवाद तथा लोकतान्त्रिक समाजवाद के प्रभाव में लास्की

ने परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में बहुलवाद को समाजवादी आधार देने का प्रयास किया। लास्की इसी आधार के कारण अन्य बहुलवादियों से भिन्न हैं।

लास्की द्वारा प्रारम्भ में राज्य सम्प्रभुता की कटु आलोचना करने का एक मूल कारण यह भी था कि वे यह समझते थे कि राज्य परम्परागत श्रमिकों और उनके दुनियनों के अधिकारों और आकांक्षाओं के विरुद्ध है। राज्य की इच्छा सरकार द्वारा व्यक्त की जाती है तथा सरकार पर उन व्यक्तियों का अधिकार होना है जिनका अर्थ-व्यवस्था पर नियन्त्रण होता है। लास्की का विचार था कि इस प्रकार की राज्य एवं शासन व्यवस्था समयानुकूल न होने के साथ-साथ अन्यायपूर्ण भी है। इसके स्थान पर लास्की का सुझाव था कि श्रम संगठनों पर आधारित नई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिये। लास्की समाज में अन्य संस्थाओं की अपेक्षा श्रमिक संगठनों में राज्य की सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के पक्ष में थे।

राजनीति में आर्थिक कारकों का प्रभाव

समाजवादी तथा मार्क्सवादी होने के कारण लास्की के विचारों में आर्थिक कारकों का अत्याधिक महत्व है। लास्की के अनुसार समाज का प्रत्येक विकास क्रमों में किसी आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। राजनीति में आर्थिक कारकों के महत्व के विषय में उनके विचार बहुत कुछ मार्क्सवाद से ग्रहण किये हुए लगते हैं। आर्थिक व्यवस्था में जब जब परिवर्तन होता है उसके साथ ही राज्य तथा सामाजिक सम्बन्धों में परिवर्तन होता है। मानव जीवन का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जहाँ विचार तथा संस्थाएं आर्थिक दशाओं का प्रतिबिम्ब न हो। लास्की द्वारा कानून प्रणाली का विवेचन तथा फ्रान्स की क्रान्ति जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में उनका कहना है कि यह उत्पादन प्रणाली के परिवर्तन में निहित था। सत्ता के लिये संघर्ष, श्रमिकों तथा मालिकों के मध्य संघर्ष—आर्थिक कारकों से ही प्रभावित होता है। लास्की द्वारा प्रतिपादित राजनीति पर आर्थिक कारकों के प्रभाव को हरबर्ट डीन से सूक्ष्म में इस प्रकार व्यक्त किया है:—

“राजनीतिक सत्ता, तथा इसके विभाजन में परिवर्तन लगभग पूर्णतः आर्थिक मत्ता पर निर्भर करते हैं। राज्य सत्ता-मध्यम आर्थिक वर्ग का साधन है, लोकतंत्र की सीमाएँ पूँजीवादी लाभ की आवश्यकताओं से निर्धारित होती हैं; राजनीतिक दल समाज के आर्थिक आधार से सम्बन्धित विरोधी दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति हैं; लास्की के विवेचन में प्रत्येक स्थान से राजनीति एक स्वतन्त्र परिवर्तनशील तत्व के रूप में सामना हो गया है।”¹⁵

किन्तु साथ ही साथ लास्की यह मानते हैं कि प्रत्येक विकास केवल आर्थिक प्रभावों का परिणाम नहीं है। धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि भी ऐसे तत्व हैं जो कई विकासों को प्रभावित करते हैं।

पूँजीवाद का विवेचन

समाजवादी होने के नाते लास्की ने पूँजीवाद का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लास्की ने पूँजीवाद के कई पक्षों को लेकर आलोचना की है किन्तु विशेषतः पूँजीवाद तथा युद्ध पूँजीवाद तथा लोकतन्त्र के विषय में उनके विचार उल्लेखनीय हैं। लास्की के मतानुसार युद्ध पूँजीवाद का तात्त्विक विस्तार है, या अन्य शब्दों में पूँजीवाद की युद्ध में परिणति होना स्वाभाविक तथा अनिवार्यम्भावी है। पूँजीवाद विस्तारवादी होता है तथा इस प्रक्रिया में उसे राज्य की सहायता एवं संरक्षण प्राप्त रहता है। मिस्र पर ब्रिटेन का, चीन पर जापान का आधिपत्य इसी श्रेणी में आते हैं। पूँजीवाद सदैव ही कच्चे माल के स्रोत तथा बने हुए माल के लिए बाजारों की खोज तथा उन पर आधिपत्य करने का प्रयत्न करता है। पूँजीपतियों के हितों को संरक्षण देने के लिए राज्य ने सदैव ही दूसरे देशों में हस्तक्षेप तथा उनसे युद्ध किया है। अमरीकी सरकार द्वारा वहाँ के पूँजीपतियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए निकारागुआ, हैटी पनामा आदि राज्यों में सैनिक हस्तक्षेप किया था। लास्की ने इसका यह भी निष्कर्ष निकाला है कि पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद सैनिकवाद को जन्म देता है।

लोकतन्त्र तथा पूँजीवाद

लास्की का यह एक प्रमुख विचार है कि पूँजीवादी व्यवस्था तथा लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों में परस्पर विरोध है। उन्नीसवीं शताब्दी में यह विरोध स्पष्ट नहीं था किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त पूँजीवाद और लोकतन्त्र का यह परस्पर विरोध शन-शन सामने आने लगा। पूँजीवादी शासक वर्ग को अब विश्वास हो चला कि लोकतन्त्र प्रक्रिया वास्तव में सम्पत्ति स्वामी तथा उनके विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। लास्की के अनुसार पूँजीवाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये वैधानिक और प्रतिनिधि सरकार सिद्धान्त का त्याग करने के लिये उत्सुक लगने लगा। फासीवाद और साम्राज्यवाद वास्तव में पूँजीवाद के इसी दृष्टिकोण का परिणाम थे। अधिक से अधिक पूँजीवाद लोकतन्त्र का मुखौटा लगाये रहना चाहता था। लास्की इस प्रकार की पूँजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध थे। उन्होंने पूँजीवादी लोकतन्त्र के स्थान पर समाजवादी लोकतन्त्र की स्थापना का समर्थन किया। कभी कभी लास्की का समाजवादी लोकतन्त्र का विचार इस समाजवादी लोकतन्त्र के प्रति निकट पहुँच जाता है।

लास्की के अनुसार पूँजी के स्वामियों की अधिकतम भौतिक समृद्धि के लिये प्रयास करता, पूँजीवादी, मालिक, का, मूल, विचार है, ऐं, मालिक, का, स्वतन्त्रता, का, तात्पर्य इस अधिकतम समृद्धि के उपर कोई प्रकुण न लगाना है। उत्पादन साधन से सम्पन्न वर्ग को ऐसे बंधनों से मुक्त रखना जो उसकी पूर्ण क्षमता पर बाधात करे पूँजीवादी समाज का मुख्य उद्देश्य है। लास्की का विचार है कि उदारवादी राज्य

का विकास इसी पूंजीवादी विचार का विस्तार है। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही उदारवादी राज्य की प्रस्थापना की गई।

माकसवादी धारणाओं के अनुरूप लास्की का विचार था कि देर-अदेर पूंजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन होगा।¹⁶ लास्की के मतानुसार पूंजीवादी व्यवस्था के अन्त का प्रारम्भ 1929 में हो चुका था जब कि अति मुद्रा स्फीति के कारण श्रमिकों की श्रम शक्ति का पूर्ण ह्रास हुआ तथा मांग की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि रहने से पूंजीवाद की आत्मा पर आघात हुआ। पूंजीपतियों के लाभ में कमी हुई जिस पर कि यह व्यवस्था आधारित है।

औद्योगिक लोकतन्त्र (Industrial Democracy)—लास्की समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में औद्योगिक लोकतन्त्र के समर्थक थे। औद्योगिक लोकतन्त्र से लास्की का भाव था कि उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न पद्धति और तकनीक का निश्चय करना, उद्योग में तकनीशियनों का चयन करना तथा कार्य अवधि और मजदूरी आदि के विषय में निर्धारण करना आदि सभी कार्य-श्रमिकों द्वारा होने चाहिए।¹⁷ श्रमिकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि राज्य द्वारा ऊपर से थोपे गये नियन्त्रण के विवल्प में वे सहयोगपूर्वक उत्पादन कार्य करें।

श्रमिक संगठन (Labour Unions)—औद्योगिक व्यवस्था को एक नया रूप देने के लिए लास्की श्रमिक संगठनों को एक मूल आधार मानते थे। श्रमिक संगठनों के आधार पर ही नवीन औद्योगिक व्यवस्था का विकास सम्भव है। लास्की के अनुसार लोकतन्त्र का भविष्य संकट में नहीं श्रमिक संगठनों में निहित है। श्रमिक संगठनों का आन्दोलन पद्धत से ही राज्य की भूमिका निर्भा रहा है तथा सरकार के कार्य और उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। श्रमिक संगठन अपने सदस्यों की आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का ध्यान रखते हैं तथा राज्य से भी अधिक अपने सदस्यों को श्रद्धा एवं निष्ठा आकर्षित करते हैं। लास्की का कहना है कि श्रमिक संगठन पूंजीवादी ढाँचे को अपने में समा लेगे तथा समाजवादी लोकतन्त्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने में सहायक होंगे।

राष्ट्रीयकरण का विरोध—आवश्यक एवं भारी उद्योग धन्यो का राष्ट्रीयकरण समाजवादी व्यवस्था का एक सामान्य एवं महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। लास्की के विचार इसके विपरीत हैं। वे राष्ट्रीयकरण के विरोधी हैं। वे फेबियनवादियों की राज्य समाजवादी धारणा को अस्वीकार करते हैं। लास्की द्वारा राष्ट्रीयकरण के विरोध का आधार है कि इसमें उद्योगों तथा श्रमिकों पर सरकार का संरक्षक

16. इस विवेचन के लिये लास्की की पुस्तक देखिये—

State in Theory and Practice, pp. 167-177.

17. Laski H. J., Authority in the Modern State, p. 87.

दृष्टिकोण' (Paternalistic attitude)¹⁸ व्यक्त होता है। राष्ट्रीयकृत उद्योग औद्योगिक लोकतन्त्र के मार्ग में बाधक हैं। लास्की का कहना है कि मात्र तब ऐसा उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि राज्यकृत उद्योगों में श्रमिकों के नियन्त्रण या औद्योगिक लोकतन्त्र को कोई महत्त्व दिया हो, या इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया गया हो। राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत श्रमिकों की भौतिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य होता है किन्तु, लास्की के अनुसार राष्ट्रीयकरण का विचार कभी भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस व्यवस्था में औद्योगिक स्वामित्व को एक धाँ से लेकर दूसरे धर्म को हस्तान्तरित करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे दोष जो पूँजीवादी धर्म व्यवस्था में निहित है राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत राजशाही और नौकरशाही के नियन्त्रण में भी व्याप्त रहते हैं।¹⁹ राष्ट्रीयकरण से पूँजीवादी धर्म व्यवस्था के दोषों एवं दुर्बलताओं का निराकरण नहीं हो सकता।

अधिकार, स्वतन्त्रता और समानता (5) 3

लास्की के अनुसार "अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। एक राज्य कहा तक प्रगतिशील है इसका अनुभव इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि अधिकार राज्य के द्वारा प्रदत्त किये जाते हैं। अधिकार राज्य से पूर्ववर्ती होते हैं क्योंकि वे किसी न किसी रूप में राज्य के पहले विद्यमान थे। अधिकार मनुष्य से सम्बद्ध हैं क्योंकि वे 'नैतिक स्वयं' (moral self) के विकास के लिए आवश्यक हैं। किन्तु व्यक्तियों द्वारा अधिकारों का उपभोग उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। इस आधार पर सामान्यतः समाज के अधिकार व्यक्तियों का पूर्ण उपभोग नहीं कर सकते।²⁰

आर्थिक दृष्टि से लास्की का मत है कि प्रत्येक नागरिक को कार्य का अधिकार होना चाहिए तथा वैरोजगारी समस्या में जीविन रहने के साधन उपलब्ध होने चाहिए। व्यक्ति को समुचित पारिश्रमिक, कार्य करने की उचित अवधि तथा विश्राम का अधिकार, शैक्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार जो नागरिक को अपने कर्तव्य निर्वाह करने के लिए योग्य बना सके आदि आवश्यक है। लास्की औद्योगिक व्यवस्था में श्रमिकों द्वारा भाग लेने का अधिकार को मान्यता देते हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में नागरिक को मत देने तथा सार्वजनिक पदों पर चुन जाने का अधिकार होना चाहिए। इनके अतिरिक्त नागरिकों को भाषण देने, विचार व्यक्त करने, धार्मिक, संगठन तथा सभा आदि की स्वतन्त्रता का अधिकार होना आवश्यक है। सभी अधिकारों की, लास्की के अनुसार, न्यायिक सुरक्षा प्राप्त होना चाहिए।²¹

18. Laski, H J, Authority in the Modern State, p 95

19. Ibid., p 95

20. Laski, HJ, A Grammar of Politics, pp 39, 91

21. Ibid., pp 95, 130

स्वतन्त्रता

लास्की स्वतन्त्रता को अधिकारों की देन मानते हैं। यद्यपि लास्की के विचार राज्य विरोधी तथा राज्य के सम्बन्ध में आदर्शवादी धारणा के विपरीत हैं किन्तु स्वतन्त्रता, समानता तथा प्राकृतिक अधिकारों के विषय में उनकी व्याख्या आदर्शवादी सिद्धान्तों पर ही आधारित है। जब हम, लास्की ने लिखा है, यह स्वीकार करते हैं कि राज्य का सिद्धान्तिक उद्देश्य उनके गदस्यों की योग्यता का पूर्ण विनाश करना है इस आशय में सहज ही स्वतन्त्रता और समानता निहित है। राज्य के उद्देश्यों। स्वतन्त्रता और समानता को पृथक नहीं किया जा सकता।

स्वतन्त्रता सिद्धान्त के विषय में लास्की के विचारों में समय-समय पर परिवर्तन पाए हैं। प्रारम्भ में लास्की स्वतन्त्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को मान्यता नहीं दे। स्वतन्त्रता का आशय केवल बन्धनों का अभाव नहीं है। लास्की के अनुसार स्वतन्त्रता "स्वयं के लिए सकारात्मक और समान अवसरों की प्राप्ति है।" 1929 अपनी पुस्तक—A Grammar of Politics—के द्वितीय संस्करण की भूमिका में लास्की अपनी भूल स्वीकार कर पूर्ण परिभाषा का त्याग देते हैं। लास्की ने लिखा कि "1925 तक मेरा विचार था कि स्वतन्त्रता को नकारात्मक वस्तु से कुछ अधिक मानना उचित होगा। अब मेरा विश्वास है कि यह मेरी त्रुटि थी। मेरा पूर्ण विश्वास कि स्वतन्त्रता बन्धनों का अभाव है, केवल यही नागरिकों के व्यक्तित्व को रक्षण दे सकता है।" 1930 में प्रकाशित पुस्तक—Liberty in the Modern State—के प्रारम्भिक पृष्ठ में लास्की स्वतन्त्रता का एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने स्वतन्त्रता को पुनः परिभाषित किया है। लास्की की स्वतन्त्रता सम्बन्धी नवीन परिभाषा उन्हीं के शब्दों में—

"स्वतन्त्रता से मेरा अभिप्राय उन सामाजिक दशाओं पर बन्धनों का

अभाव है जो प्राकृतिक सम्बन्धों में व्यक्तिगत गुण की आवश्यक मापदण्ड है।" 23

लास्की ग्रीन (T. H. Green) की स्वतन्त्रता सम्बन्धी परिभाषा का पूर्ण पस्यन्द करते हैं जिसके अनुसार स्वतन्त्रता "कुछ करने या आनन्द लेने योग्य कार्य को करने या आनन्द लेने की नकारात्मक शक्ति है, यह भी जब यदि हम दूसरों के साथ इनका उपभोग करें।" 24

स्वतन्त्रता के पक्ष—लास्की के अनुसार स्वतन्त्रता के प्रमुख तीन पक्ष होते हैं— व्यक्तिगत, राजनीतिक और धार्मिक। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का आशय अपनी इच्छा-नुसार कोई भी कार्य करना यदि उसका दूसरों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। धार्मिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्तर्गत आती है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अर्थ में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। राजनीतिक स्वतन्त्रता का

23 Laski, H.J., Liberty in the Modern State, p. 37.

24. Ibid., p. 55.

24 Quoted by Laski Ibid., p. 55.

तात्पर्य सांख्यिक जीवन में अपने विवेक का स्वतन्त्रापूर्वक प्रयोग। इस सम्बन्ध में राज्य को नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजनीतिक स्वतन्त्रता के सही प्रयोग के लिए लास्की के अनुसार शिक्षा तथा समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता आवश्यक देगाएँ हैं। आर्थिक स्वतन्त्रता से लास्की का तात्पर्य प्राजीविका प्राप्त करने के समान अवसरों की प्राप्ति से है। आर्थिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत लास्की उद्योगों में जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को अत्याधिक महत्त्व देते हैं।

बाधाएँ—स्वतन्त्रता के समुचित उपयोग के मार्ग में लास्की प्रमुखतः तीन बाधाएँ मानते हैं। किसी भी समाज में स्वतन्त्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि—
 प्रथम, घोड़े से व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, द्वितीय, कुछ व्यक्तियों के अधिकार अन्य व्यक्तियों के सुख पर निर्भर करते हैं, तृतीय राज्य की सत्ता किसी समूह के प्रति पक्षाघात करती है। अन्य शब्दों में लास्की के अनुसार विशेषाधिकारों की समाप्ति, सभी के लिए विकास के समुचित अवसर तथा व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में न्यूनतम अन्तर आदि स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ हैं।²⁵ स्वतन्त्रता के विषय में लास्की एक बाधा को एक सीमा तक अपवाद के रूप में स्वीकार करते हैं। लास्की के अनुसार समाजवाद की उपलब्धि के लिए स्वतन्त्रता के हनन को स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वर्ग-विहीन समाज में ही स्वतन्त्रता को सकारात्मक रूप प्रदान किया जा सकता है।

समानता (Equality)—लास्की ने समानता को कई दृष्टिकोणों से परिभाषा की है मूलतः समानता का अर्थ सभी को पर्याप्त अवसरों की प्राप्ति से है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। किन्तु पर्याप्त अवसरों का तात्पर्य समान अवसरों से नहीं है। जैसा कि लास्की ने लिखा है—समानता सभी व्यक्तियों को अपनी क्षमता तथा आवश्यकताओं से भिन्न है, के साथ समान व्यवहार नहीं है किन्तु मूल आवश्यकताओं तथा आवश्यक न्यूनतम जीवन स्तर को सभी को गारन्टी होनी चाहिए।²⁶ अन्य शब्दों में, समानता व्यक्तियों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति के प्रयत्नों के अनुपात में होनी चाहिए।

आर्थिक समानता (Economic equality)—समानता का तात्पर्य लास्की मुख्यतः आर्थिक समानता से लेते हैं जिसके अन्तर्गत आय और सम्पत्ति की समानता भी सम्मिलित है। जब मनुष्य के स्तर, सत्ता और प्रभाव में असमानता होती है इसका मूल कारण भौतिक असमानता है। लास्की के लिए आदर्श समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का समान पारश्रमिक मिले सामाजिक उत्पादन में उसका समान हिस्सा हो। इस सम्बन्ध में केवल एक अपवाद मान्य हो सकता है।

25 Laski H. J., A Grammar of Politics, p. 157

26 Ibid., p. 160

व्यक्तियों के पारथमिक में कुछ अन्तर स्वीकार किया जा सकता है यदि यह स्पष्ट हो जाय कि इससे कुल उत्पादन में वृद्धि होगी तथा तुलना में जिन्हे कम पारथमिक मिला है उन्हें भी इसका लाभ हो।²⁷

स्वतन्त्रता एवं समानता (Liberty and Equality)—स्वतन्त्रता और समानता का सम्बन्ध बड़ा ही विवादास्पद रहा है। बहुत से लोग इनको परस्पर-विरोधी सिद्धान्त ब्रथा इनका समान सम्बन्ध नहीं हो सकता ऐसा मानते हैं। किन्तु लास्की इस धारणा में सहमत नहीं हैं। लास्की के अनुसार स्वतन्त्रता सिद्धान्त में समानता पूर्णतः अपेक्षित है। स्वतन्त्रता और समानता एक ही उद्देश्य के दो पक्ष हैं। इस तथ्य को लास्की ने यन्ने प्राप्ति स्पष्ट किया है। पूंजीवाद के अन्तर्गत लास्की के मतानुसार, जनमाधारण के लिए स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं रहता। इस व्यवस्था में स्वतन्त्रता का उपयोग केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही कर सकते हैं। जिस समाज के नागरिकों में जीवन से सम्बन्धित वस्तुओं की उपलब्धि में व्यापक विषमता है वहाँ वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। स्वतन्त्रता को समानता के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जन कल्याण के साधनों पर उस वर्ग के स्वामित्व को समाप्त किया जाय जो समाज में कोई भी उपयोगी कार्य नहीं करता। इस सन्दर्भ में समानता का अर्थ मनुष्यों की उन समान आवश्यकताओं की पूर्ति है जो उसके व्यक्तित्व का अधिकतम विकास कर सकें।²⁸ जन साधारण के लिए स्वतन्त्रता तभी सम्भव है जब समानता पर आधारित समाज की स्थापना की जाय, जहाँ उत्पादन के साधनों पर सभी का नियन्त्रण हो। लास्की के अनुसार ऐसा समाज जहाँ सम्पत्ति स्वामियों और श्रमिकों में निरन्तर वर्ग अर्थ की स्थिति बनी रहती है वहाँ न तो लोकतन्त्र सम्पन्न हो सकता है और न स्वतन्त्रता एवं समानता की प्राप्ति हो सकती है।²⁹

यद्यपि स्वतन्त्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं किन्तु समानता स्वतन्त्रता नहीं हो सकती। लास्की के अनुसार एक अधिनायकवादी शासन के अन्तर्गत मनुष्य सामान्यतः समान रह कर भी स्वतन्त्रता से वंचित रहते हैं। इतना आवश्यक है कि कुछ समानताओं के अभाव में स्वतन्त्रता की आशा नहीं करनी चाहिए।³⁰

लास्की की धारणा है कि जब नागरिकों में समान उद्देश्यों के विषय में सहमति होती है तथा जब वे उन समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये पारस्परिक सहयोग करते हैं ऐसी स्थिति में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं।³¹ इस विचार के समर्थन में लास्की युद्ध के समय ब्रिटेन तथा साम्यवादी नान्दिक के उपरान्त रूस का उदाहरण देकर यह व्यक्त करना चाहते हैं कि इन

27. Deane, Herbert A., The Political Ideas of Harold H J., Laski, p 187

28. Laski, H J., Reflections on the Revolution of our Time, p. 208.

29. Deane, Herbert A., The Political Ideas of Harold J Laski, p 255

30. Laski, H J., Liberty in the Modern State, p 7

31. Laski, H. J., Reflection on the Revolution of our Time, 1943, p 386

देशों में नागरिक अपने स्वार्थ से हट कर सामान्य उद्देश्यों की उपलब्धि में कार्य करते हुए वास्तविक स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं। यहाँ लास्की द्वारा रूस तथा ब्रिटेन का एक समान स्थान और स्तर पर रखना बतुका प्रतीत होता है।

सम्पत्ति

लास्की ने जब समानता का अनुमोदन किया है इसका तात्पर्य ब्यक्तिक सम्पत्ति का उन्मूलन नहीं है किन्तु उनका विचार है कि सम्पत्ति अधिकार का उपभोग सामाजिक सेवा तथा उपयोग पर निर्भर करता है। लास्की के अनुसार सम्पत्ति की वर्तमान व्यवस्था काफी शोषणपूर्ण है। सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार का वर्तमान स्वरूप बिना कोई कार्य किए हुए सचय का अधिकार देता है। केवल जन्म के संयोग से कोई व्यक्ति समीर धनधानि निर्धन हो सकता है। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति सचय असामाजिक कार्यों जैसे जुआ, सट्टा आदि जैसे गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है। आज की सम्पत्ति का स्वरूप तथा सेवा में कोई तालमेल नहीं है। लास्की का मुझव है कि कार्य के आधार पर समाज को व्यवस्थित करना चाहिए तथा व्यक्ति के अधिकार उनके कार्य पर निर्भर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति की केवल उतनी ही मात्रा रखने को अनुमति दी जाय जितना कि वह सामाजिक सेवा तथा सामाजिक आवश्यकता का कार्य करता है। तभी जाकर व्यक्तिगत हित का सामान्य हित के साथ समन्वय हो सकता है। इसका तात्पर्य यह होगा कि मट्टेबाजी, एकाधिकार तथा उत्तराधिकार के अधिकारों को काफी सीमित करना होगा। किन्तु यह कार्य जस्टिसी में न टोकर जन-जन धनधनियों के विचारों में परिवर्तन द्वारा किया जाय। यह सचय केवल सम्पत्ति और निर्धनता के मध्य ही होना चाहिये।

लास्की के अनुसार सम्पत्ति का स्वामित्व पूँजीवाद की घोर अक्षर करता है जिसका तात्पर्य उत्पादन अधिको तथा शासन पर नियन्त्रण करना है। इसका कारण सम्पत्ति का समुचित वितरण न होना तथा उत्पादन के क्षेत्र में आवश्यक बस्तुओं को प्राथमिकता न देना है। उदाहरणार्थ जब मकानों की आवश्यकता होती है उस समय मिनमा घरों का निर्माण किया जाता है। बस्तुओं का उत्पादन समाज सेवा के लिए नहीं लाभ के लिए किया जाता है। यह व्यवस्था समझनी चाहिए।

विधि सिद्धान्त (Theory of law) सिद्धान्त

आस्टिन के विधि सिद्धान्त में लास्की ने स्वीकार किया है कि कानून में राजा का तत्त्व निहित है। आधुनिक समाज में कानून बल पर आधागित है किन्तु इसके पीछे समाज की शक्ति चौकूट रहती है। एक भावसंवादी की भाँति लास्की का कहना था कि विधि व्यवस्था दर्ग सचय की भाँति निर्धारित होती है। विद्रोह सम्बन्धी कानून तथा श्रमिक विवादों में न्यायालय की आज्ञाओं का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है किन्के द्वारा पूँजीपतियों का समर्थन और श्रमिकों के हितों पर घाघात

होता है। पूँजीवाद के आलोचक होते हुए लास्की का कहना है कि इस प्रणाली-दोषों का कानून व्यवस्था पर प्रभाव पडा है। पूँजीवादी व्यवस्था में कानून प्रणाली का प्रयोग शासक वर्ग के हित में किया जाता है। कानून सक्रिय भागों का प्रत्युत्तर है, जो वर्ग आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है वह अपनी भागों को कार्यरूप दिला सकता है। पूँजीवाद के अन्तर्गत कानून का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत सम्पत्ति सन्ध्या को संरक्षण देना होता है। साथ ही साथ उन सम्बन्धों को मान्यता देना है जो लाभ कमाने में सहायक होते हैं।³²

लास्की बहुलवादी है इस प्रकार उनके विधि सिद्धान्त पर इस दृष्टिकोण का प्रभाव है। वे यह नहीं मानते कि कानून को समाज में सर्वोच्च स्तर प्राप्त हो। उनके अनुसार कानून राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है तथा इसका महत्त्व समाज के अन्य समूहों की इच्छा से प्राथमिक और श्रेष्ठ नहीं है। लास्की के विधि सिद्धान्त में प्राकृतिक कानून का महत्त्व है जो राज्य निर्मित विधि विधान पर अंकुश रखते हैं।

विधि के विषय में लास्की का अनुभववादी एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। अनुभववाद के आधार पर लास्की मानते हैं कि विधि सिद्धान्त स्वयं में पूर्ण अथवा स्वयं सार्थक नहीं है। यह सामाजिक भागों एवं आकांक्षाओं की सन्तुष्टि का साधन है। लास्की का यह दृष्टिकोण उपयोगितावादी दृष्टिकोण के निकट है। लास्की ने निम्ना है—

“हम एक बार फिर साप्ताहिक प्रयासों के युग में आये हैं। हम कानून की पुनर्स्थापना साप्ताहिक आवश्यकताओं के सदर्भ में करते हैं। हमारा कार्य है कि कानून को आधुनिक जीवन की गति के अनुरूप ढालें। इसका तात्पर्य विभिन्न हितों का समन्वय करना होगा। इस सामाजिक उपलब्धि के विकास के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारे समक्ष यही समस्या है।”³³

अनुभववादी आधार पर लास्की विधि को एक सुविधा का नियम मानते हैं जिसकी अर्थात् एवं महत्ता उसके परिणाम में निहित है।

एक औपचारिक श्रद्धा को छोड़कर, लास्की का कहना है कि केवल अर्थात् कानूनों को ही स्वीकार करना चाहिए। एक विद्रोही चिन्तक के रूप में लास्की व्यक्तिगत आत्मा की आवाज को महत्त्व देते हैं। वे व्यक्ति द्वारा विधि प्रणाली के मूल्यांकन की बात को स्वीकार करते हैं। यहाँ लास्की कानून के नैतिक आधार को मान्यता देते हैं। राज्य की आज्ञा पालन के विषय में लास्की यथार्थवादी आदर्शवादी तथा व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का समर्थन करते हैं। मनुष्य को वह कार्य करना

³² Laski, H J, *The State in Theory and Practice*, pp. 100-117.

³³ Quoted, Deane, Herbert; *The Political Ideas of Harold J Laski*, pp 22-23

हिए जो नैतिक दृष्टि से उचित हों। वह जिस कानून की आज्ञा का पालन करे वह उसके नैतिक स्तर के अनुकूल हो। व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन तभी करेगा यदि राज्य का उद्देश्य नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होगा।

जन सहमति द्वारा क्रान्ति (Revolution by Consent)

समाजवादी सोकलन्यकी स्थापना के लिए साधनों के विषय में लास्की के विचार सम्भवतः सर्वाधिक उलझे हुए लगते हैं। ऐसा आशय लगता है कि वे साधनों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करते। लास्की के शालीचको का कहना है कि उनके विषय में यह कहना असम्भव है कि वे शान्तिवादी थे अथवा हिंसात्मक क्रान्ति का अनुमोदन करने वाले। लास्की शान्ति के समर्थक थे। उनके विचारों में दो प्रकार की क्रान्ति का उल्लेख है— प्रथम हिंसात्मक क्रान्ति (Revolution by Violence), तथा द्वितीय, सहमति पर आधारित क्रान्ति (Revolution by Consent) आदि। यद्यपि लास्की ने स्वयं ही हिंसात्मक क्रान्तिकारों होने का खण्डन किया, साधनों को लेकर उनके विचार इतने विवादास्पद बन गये कि इस विषय में उन्हें न्यायालय की शरण लनी पड़ी। किन्तु इन प्रक्रिया में 'जन सहमति द्वारा क्रान्ति' के विषय में उनके विचार कुछ और स्पष्ट होते हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध काल में लास्की ने जो भाषण दिए उनमें उन पर हिंसात्मक क्रान्ति का समर्थन होने का आरोप लगाया गया। दिसम्बर 13 1941 को बोर्नमाउथ (Bournemouth) तथा 1945 में चुनाव आन्दोलन के समय, विशेषतः नैवार्क-मार्केट-प्लेस (Newark Market Square or Place) पर दिए गये उनके भाषणों से उनके विचारों पर काफी धूल उछानी गई। जून 20, 1945 को टोंगी दल (अनुदार दल) के समर्थक लगभग सभी समाचार-पत्रों ने लास्की पर आरोप लगाया कि उन्होंने 'समाजवाद चाहे हिंसा द्वारा ही क्यों न हो' (Socialism even if it means violence) कह कर हिंसात्मक क्रान्ति का आह्वान किया। लास्की ने इन आरोपों का खण्डन किया तथा इन सभी समाचार पत्रों पर मानि ज्ञानि तथा उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए लास्की ने कहा कि द्वितीय विश्वयुद्ध ने एका प्रवृत्ति प्रदान किया है कि जनता आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन सहमति पर आधारित क्रान्ति के द्वारा स्वीकार कर सकती है। किन्तु यदि हमने यह प्रवृत्ति हाथ से निकल जाने दिया तो हम हिंसात्मक क्रान्ति का सामना करना पड़ेगा। न्यायालय में लास्की ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा—

"मैं हिंसात्मक क्रान्ति की कभी भी वकालत नहीं का है जिसका मुझ पर आरोप लगाया गया है। नैवार्क-मार्केट प्लेस पर मैंने कहेना कहा था कि युद्धकालीन स्थिति में परिवर्तन लाना महज रहना है क्योंकि उस समय व्यक्ति परिस्थितियोंबश व्यापक परिवर्तन के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार रहना है बजाय इसके कि बुद्धोपरान्त

विजय प्रतीक्षा में परिवर्तन की वह इच्छा समाप्त हो जाय तथा सहमति प्राप्त न की जा सके जिसे श्रमिक श्रमहनीय भार अनुभव करें। ऐसे ही समाज हिंसा की ओर झुक जाते हैं। जिन परिवर्तनों को दूसरे राज्यों में हिंसा के माध्यम से लाया गया है युद्ध के समय ऐसे परिवर्तनों को सहमति द्वारा लाना हमारी सामर्थ्य के भीतर था।³⁴

न्यायालय में लास्की को पराजित होना पड़ा तथा उन्हें भारी हर्जाना देना पड़ा। इस निर्णय ने लास्की के दिल और दिमाग पर भारी आघात पहुँचाया जिसने उन्हें मृत्यु के अधिक निकट ला दिया। किन्तु यहां प्रमुख बात यह है कि इस निर्णय में लास्की के माधुन सम्बन्धी विचारों पर शंका का पर्दा पड़ा रहा। उनके विचारों को अब उनके विरोधियों द्वारा और भी आलोचना हुई। विस्टन चर्चिल का आरोप था कि लास्की इंग्लैंड को एक श्रमिक गृह द्वारा शासित करना चाहते थे। लेबर पार्टी में एर्नेस्ट बेवेन (Ernest Beven) जैसे उनके सहयोगी भी उनके विचारों पर घबराव करने लगे।³⁵ किन्तु लास्की ने सर्व्व ही कहा कि वे हिंसा के कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय रूस द्वारा पूर्वी यूरोप पर शक्ति द्वारा आधिपत्य करने की निन्दा करते हुए लास्की ने कहा—

“क्रान्ति गुलाबी जल से नहीं लाई जाती, किन्तु यह भी स्पष्ट है कि हिंसा स्वतन्त्र नागरिकता की सराशक नहीं बन सकती।”³⁶

लास्की का विचार था कि द्वितीय विश्वयुद्ध में कुछ अच्छे परिणाम भी निकल सकते थे। पिछले कई वर्षों से लास्की यह कहते आ रहे थे कि पूँजीवादी व्यवस्था अब पतन की ओर अग्रसर हो रही है। यदि उच्च वर्ग अपनी कुछ सत्ता, शक्ति तथा विशेषाधिकारों को त्यागने के लिए इच्छुक नहीं होगा तो शक्ति के आधार पर क्रान्ति होगी। लास्की के अनुसार युद्ध ने ऐसा अवसर प्रदान किया है जब एक नई सामाजिक व्यवस्था की ओर शान्तिपूर्ण संक्रमण हो सकता है। युद्धकाल में केवल सैनिक दृष्टिकोण से ही किसी अंश अथवा रूप में समाजवाद रहता ही है। लास्की चाहते थे कि लेबर पार्टी के नेतृत्व को युद्धकाल में युद्ध के बाद आने वाले समाजवाद का आधार तैयार करना चाहिए। इस प्रकार क्रान्ति जन सहमति के द्वारा आ सकती है। युद्धकालीन मन्त्रिमण्डल में लेबर दल का सम्मिलित होने का अभिप्राय युद्ध विजय तथा समाजवाद दोनों की ही प्राप्ति करना था।³⁷

मावर्सावाद की ओर

राज्य सम्प्रभुता के विरुद्ध बहुलवाद से प्रारम्भ होकर लास्की का चिन्तन प्रवाह

34. Quoted, Martin, Kingsley; Harold Laski, p. 175.

35. Ibid., p. 175.

36. Ibid., p. 187.

37. Ibid., pp. 138, 142.

जवाद की ओर ले जाया है। विन्तु अपने चिन्तन के अन्तिम वर्षों में वे समाज-
 द की सामान्य रेखा तक सीमित न रह कर मार्क्सवाद तथा कहीं-कहीं साम्यवाद के
 निकट आ जाते हैं। एक तो लास्की के विचारों में एक प्रकार से साम्यवादी उन्नति
 आ जाती है, इसके अतिरिक्त उनके विरोधियों ने उन्हें मार्क्सवादी तथा अर्ध-साम्य-
 वादी कह कर निन्दित करने का प्रयत्न भी किया। लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
 में लास्की को लाल अथवा साम्यवादी प्रोफेसर (Red Professor) कहा जाता था।
 लास्की स्वयं कहा करते थे—“मैं मार्क्सवादी हूँ तथा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी
 पक्ष को लेकर मार्क्सवादी है।”

तीसरे दशक में प्रकाशित लास्की के ग्रन्थों एवं लेखों से प्रतीत होता है कि वे
 पूर्ण मार्क्सवादी न होते हुए उनके विचार मार्क्सवाद के निकट थे। 1938 में—A
 Grammar of Politics—के नवीन संस्करण में लास्की ने नवीन प्रस्तावना को
 जोड़ा। यहाँ से वे बहुलवाद के प्रारम्भिक स्वरूप को छोड़ कर मार्क्सवाद की ओर
 आधे से अधिक मार्ग पर कर लेते हैं। 1925 तक लास्की फेबियन समाजवादी रहे,
 विन्तु बाद में कुछ घटनाओं से उनके विचारों में परिवर्तन हुआ। 1929 का आर्थिक
 संकट, 1931 में रेमजे मेकडॉनल्ड द्वारा अनुदार दल से साठ गांठ कर राष्ट्रीय सरकार
 बनाना, जर्मनी तथा स्पेन में फासीवाद के अभ्युदय से लास्की ने यह निष्कर्ष निकाला
 कि लोकतन्त्र घोषणा है यदि लोकतन्त्र समानता पर आधारित नहीं है, समानता फेबि-
 यन समाजवाद के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, इसके लिए कुछ अधिक उपवादी
 उपचार की आवश्यकता है। इसके बाद लास्की के विचारों में मार्क्सवादी विवेचन को
 अधिक स्थान मिलता गया।³⁸

लास्की अब राज्य को पूँजीवादी वर्ग के उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन मानत
 हैं। आधुनिक विधि-विधान में न्याय का सिद्धान्त सम्पत्ति के स्वामिदा तथा उनकी
 रक्षा के लिये है। वह व्यक्ति जो सम्पत्तिहीन है, लास्की के अनुसार अपने अधिकारों
 का प्रयोग नहीं कर सकता यद्यपि सिद्धान्ततः सभी अधिकार सम्पूर्ण सामान्य जनता
को दिये जाते हैं।³⁹

लास्की की अन्तिम पुस्तकों में पूँजीवाद के प्रति अविश्वास की स्पष्ट भूक
 मिलती है। अथ तथा पूँजी के मध्य सघर्ष की सम्भावना जर्मनी स्थिति का वे अनुभव
 करन लगे। दिन प्रति दिन उनका यह विश्वास बढ़ता गया कि अथ तथा पूँजी के
मध्य समझौता असम्भव है। पूँजीवाद के विरुद्ध तथा अर्थिका के समयन में उनका
 विचार कहीं-कहीं मार्क्स की पुनरावृत्ति जैसे लगते हैं।

1945 में इंग्लैंड के ग्राम चुनावों में लेबर दल को बहुमत मिला और सर्व-
 प्रथम एक पूर्ण लेबर दल की सरकार बनी। इस राजनीतिक घटना या विश्वास न

38 Martin, Kingsley, Harold Laski, pp 74—75

39 Laski, H J, Introduction to Politics, pp 74—75

लास्की की प्रमुख राजनीतिक धारणाओं को विघटित कर दिया। अभी तक लास्की ने इन धारणा का प्रतिपादन किया था कि राज्य सम्पत्ति-सम्पन्न व्यक्तियों के एक छोटे से वर्ग के हितों की अभिवृद्धि का माध्यम है। पूंजीवादी वर्ग कभी भी ऐसी सरकार नहीं बनने देगा जो लोकतंत्र द्वारा सम्पत्ति व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहे। किन्तु 1945 में लेबर दल की सरकार बनने से लास्की के विचारों की सम्पूर्ण संरचना विघटित हो जाती है। अब वर्ग संगठन, राज्य का स्वभाव, राजनीतिक दल, लोकतंत्र, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के सिद्धान्त आदि के निष्कर्षों के विषय में शंका उत्पन्न होने लगी। इसके बाद लास्की ने पूंजीवादी लोकतंत्र को समाजवादी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण साधनों द्वारा परिवर्तन करने के विचार का प्रतिपादन किया। इस सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट नहीं हो सके।

माक्सवादी प्रभाव में आकर लास्की ने बहुलवाद की दुर्बलता की एक और यास्या की है। लास्की ने स्वीकार किया था कि बहुलवाद में इस तथ्य की अवहेलना हो गई है कि राज्य वर्ग-सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है। राज्य समाज में उत्पादन कर्तव्यों पर नियन्त्रण करने वाले वर्ग का एक माध्यम है जिसके द्वारा वे अपने हितों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिये यदि राज्य की शक्ति को कम करना है तब सबसे पहले समाज में वर्ग व्यवस्था को समाप्त करना चाहिये जब तक वर्गविहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती तब तक समाज से राज्य की शक्ति और सत्ता में कमी नहीं आ सकती। जब सम्पत्ति पर आधारित संघर्ष की समाप्ति होगी तभी समाज में शीघ्र प्रथम से संघात्मक व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी। इसके उपरान्त ही एक सिद्धान्तिक और व्यावहारिक बहुलवाद सम्भव है।⁴⁰ यद्यपि लास्की बहुलवाद से अभी भी उलझे हुए हैं उनका यह नवीन विवेचन माक्सवाद की ओर ले जाता है। लास्की के विषे बहुलवाद अब दूरगामी तथा वर्ग-विहीन समाज की स्थापना निकटस्थ उद्देश्य है।

सन् 1932 तक लास्की की मान्यता थी कि व्यक्ति को राज्य की आज्ञा का पालन उम स्थिति में करना चाहिये यदि राज्य का आदेश न्यायिक और उचित हो। किन्तु लास्की पर जैसे जैसे माक्सवादी प्रभाव बढ़ता जाता है वे राज्य के प्रति प्रवृत्ति का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण छोड़ते जाते हैं। अब लास्की का ध्यान व्यक्ति से टूटकर 'वर्ग' पर जाता है। उनका कहना है कि बहुमत शोषित वर्ग को शोषक वर्ग, जो राज्य पर नियन्त्रण रखता है, को राज्य की प्रवृत्ति करने का अधिकार है।

लास्की हम में साम्यवादी क्रान्ति तथा साम्यवादी शासन व्यवस्था के कुछ पक्षों का समर्थन अथवा अनुमोदन करते हैं। अपने लेखों तथा पुस्तकों में उन्होंने इस प्रकार के कई उदाहरण दिये हैं। जैसे, रूस में जारशाही के विरुद्ध जन क्रान्ति का समर्थन, हम में आर्थिक समानता लाने के प्रयासों की प्रशंसा आदि से कई बार यह आभास मिलता था जैसे कि वे साम्यवादी बन गये हो।

40. Laski, H. J., A Grammar of Politics, 1933, pp xi-xiii

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कुछ तो लास्की के उग्रवादी वामपंथी विचार तथा कुछ ईर्ष्यालु विरोधियों द्वारा प्रचार ने उन्हें यदि वास्तविक साम्यवादी नहीं किन्तु साम्यवादी-महयोगी की श्रेणी में प्रवृत्त ला दिया।

लास्की के 'सहमति द्वारा शान्ति' के अस्पष्ट विचार के आधार पर उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंसात्मक शान्ति का सुभाव एवं प्रोत्साहन दिया। न्यायालय में भी यह आरोप चलत मिट्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ लास्की की श्रमिकों तथा धर्मिक संगठनों के प्रति पूर्ण सहानुभूति ने भी उन्हें इस स्तर पर लाने में योगदान दिया। स्वयं विस्मय चर्चित ने लास्की की आलोचना करते हुए कहा था कि वे ब्रिटेन में एक श्रमिक गुट की सरकार घोषणा चाहते थे। यद्यपि इन आरोपों का मस्य नहीं कहा जा सकता, लास्की के विरुद्ध इस प्रकार का दातावरण अवश्य ही विद्यमान था। लास्की ने मार्क्सवाद के कई सिद्धांतों एवं उप-सिद्धान्तों का खण्डन किया। वे राजनीति में श्रायिक कारकों के महत्त्व को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों में वर्ग-विरोध की अभिव्यक्ति मिनती है, किन्तु उन्होंने मार्क्स द्वारा 'इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या' तथा वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त का भी अनुमादन नहीं किया। श्रमिक मूल्य का सिद्धान्त सम्भवन उनके विवेक के परे था। इसी प्रकार लास्की ने साम्यवादी जैसी हिंसात्मक शान्ति तथा इसके उपरान्त सवहारा वर्ग के श्रमिकों के अवधारणाओं का समर्थन करना तो दूर रहा समय समय पर तीव्र आलोचना भी की है। लास्की के वास्तविक मार्क्सवादी स्वभाव के विषय में क्रिस्ले मार्टिन ने लिखा है—

"लास्की के तक मल ही मार्क्स से ग्रहण किये गये हो किन्तु अन्तिम रूप में वे नवनि क नहीं विनियम मोरिम् क अनुयायी थे। वे मार्क्सवादी इतलिय थे, जैसा कि उनक मिय मुदम लकी का कहना है, क्योंकि काले मार्क्स का समाजवाद उत्तम मानवनावादी था। विनियम मोरिम् की भांति वे समाजवाद तथा बन्धुत्व भावना को एक ही धस्तु समझते थे।" 41

मार्क्स का प्रमुख कार्य, लास्की के अनुसार, स्वयं से पूव समाजवादियों के प्रमुख विचारों को अन्तिम रूप में विस्तारपूर्वक विवेचन कर प्रस्तुत करता है। मार्क्स ने पूँजीवादी मन्धता की नैतिक अपूर्णता को प्रदर्शित किया। साथ ही साथ वह न्याय का प्रबल समर्थक था। मार्क्स ने जमा कि लास्की ने लिखा है, जनता के बन्धों के उम भार को दूर करन का प्रयत्न किया जिससे वे दबे जा रह थे। उनसे श्रमिकों के मय को एक छाशा में परिणत किया जिससे वे एक छाशावादी भविष्य की ओर देख सकें। शोषित, वर्ग, की, श्रुति के लिए लिए, मा, श्रमिकों, के, भाव, की, यथा, की, श्रम्य नहीं कर सकता। 42

41 Martin, Kingsley, Harold Laski, p 270

42 Laski, H J, Karl Marx An Essay, p 46, Dean, Herbert A, The Political Ideas of Harold J Laski, p, 69

लास्की के विचारों का मूल्यांकन

लास्की के विभिन्न ग्रन्थों एवं राजनीतिक विचारों के विषय में कई आक्षेप लगाये जाते हैं। संक्षेपिक दृष्टिकोण में आलोचकों का कहना है कि उनके विचारों में पुनरावृत्ति और निरन्तर परिवर्तन हुआ है। परिणामतः उनके विचार अस्पष्ट और अस्पष्ट हुये प्रतीत होते हैं। 1914 में 1950 तक लास्की ने अपने प्रमुख विचार सन्न्युता, बहुलवाद; राज्य का स्वभाव, स्वतंत्रता, समानता, मार्क्सवाद एवं समाजवाद की ही पुनरावृत्ति की है। यदि उनके विचारों का सही सम्पादन किया जाय तो उनके ग्रन्थों एवं लेखों में लगभग आधे पृष्ठ आसानी से निकाले जा सकते हैं। पुनरावृत्ति के अनिश्चित लास्की ने अपने प्रमुख विचारों में निरन्तर परिवर्तन किया है। प्रारम्भ में लास्की बहुलवादी हैं किन्तु आगे चल कर वे लगभग इस विचार का त्याग कर बहुलवाद विरोधी विचारधारा समाजवाद-मार्क्सवाद का अनुमोदन करते हैं। यहाँ यह कि इंग्लैंड में ही उनके समर्थक उन्हें बहुत मार्क्सवादी और साम्यवाद का समर्थक समझने लगे। ऐसे विचार परिवर्तन के सन्दर्भ में यह समझना कि लास्की वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, किस विचार का प्रतिपादन कर रहे हैं अशक्य है।

सम्भवतः लास्की के विषय में यह कहना उचित होगा कि अपनी पीढ़ी को समाज के प्रचलित दोषों से अलग कराना चाहते थे इसलिए उन्होंने खूब लिखा जिसे वे मध्य समझते थे, उसकी सदैव पुनरावृत्ति की। भाषा की दृष्टि में उनके खूब सखे कई पत्रियों वाले वाक्य उनके विचारों की स्पष्टता को व्यक्त करने में बाधक रहें। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय तथा उसके उपरान्त लास्की अपने ही गतिविधियों में व्यस्त रहे। वहीं वहीं लास्की के विचार प्रचार का पुट लिए समय से काफी पिछड़े लगते हैं। लास्की के पास न तो समय था न साधन कि वे राजनीतिक समस्याओं का एकान्त में गम्भीरतापूर्वक चिन्तन पर आधारित निष्पक्ष विवेचन कर सकते।

लास्की के लेखों में पुनरावृत्ति अवश्य है किन्तु उनके विचारों में समय समय पर जो परिवर्तन हुआ इसे उनके विचारों की प्रगतिशीलता भी कहा जा सकता है। लास्की ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य का कोई भी एक विद्वान्त पूर्ण या स्याई नहीं माना जा सकता।⁴³ इसलिए जैसे जैसे नवीन परिस्थितियों का प्रादुर्भाव हुआ तथा व्यावहारिक दृष्टि और अनुभव के आधार पर जब लास्की ने स्वयं के विचारों का समय समय पर मूल्यांकन किया उनके विचारों में परिवर्तन स्वाभाविक ही नहीं उचित था। यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि उनके परिवर्तित विचारों से हम सहमत हैं या नहीं।

कई स्थलों पर लास्की के विचारों में परस्पर-विरोध दृष्टिगोचर होता है। हैरोवेल के अनुसार उनके विचारों में एक बड़नी हुई प्रवृत्ति थी कि वे मुनियोजित उत्पादन तथा श्रमजन्य को एक ही समझते हैं। आगे चलकर वे इस में निरंकुश

व्यवस्था की घोर से आँखें बन्द कर रूस के अनन्य प्रशंसक बन जाते हैं।⁴⁴ मैक्स केम्पलमैन (Max Compelman) ने लिखा है कि लास्की ने सदैव ही स्वयं को परस्पर विरोधी विचारों में उलझाये रखा। वे एक ही साथ ब्रिटेन में लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा रूस में अधिनायकवादी समाज के गीत गाते रहे।⁴⁵ अपने परस्पर-विरोधी विचारों के कारण लास्की को स्वयं ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। 1946 में लास्की द्वारा चलाया गया मान हानि का मामला जब चल रहा था वे अपने पक्ष को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सका। उनके विरोधी लास्की के विचारों में परस्पर-विरोध सिद्ध करने में सफल रहे तथा इसी कारण वे लास्की के विरुद्ध अपना बचाव कर सके।

लास्की के विचारों की यद्यपि व्यापक आलोचना हुई है, उनके विचारों की अप्रस्पष्ट, उलझे हुए, परस्पर विरोधी, अस्थिर एवं निरन्तर परिवर्तित होते रहने वाला बतलाया गया है किन्तु यदि उनके विचारों का निष्पक्ष विवेचन कर उनके सार प्रथवा प्रमुख धारणाओं को खोजने का प्रयत्न किया जाय तो यह असम्भव नहीं है। लास्की ने जब राज्य सम्प्रभुता का खण्डन तथा बहुलवाद का अनुमोदन किया, उनके विचार अन्धवहारिक प्रतीत होते हैं। किन्तु इसके पीछे उनके मूल विचारों को ध्यान से समझा जा सकता है। लास्की किसी एक स्तर या स्थान पर सत्ता सच्चय, शक्ति एकाधिकार तथा सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध थे। उनकी यह धारणा उनका विचारों में सर्वत्र विद्यमान है। उनके बहुलवाद का यही निष्कर्ष था।

लास्की समाजवादी थे इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। जैसा कि लास्की ने अनेकों बार स्वीकार किया है कि समाजवाद उनके लिए केवल एक विचार तक ही सीमित नहीं था किन्तु उनका जीवन में एक दृढ़ विश्वास के रूप में धर कर चुका था। उनके समाजवाद को किस श्रेणी या सम्प्रदाय के अन्तर्गत लिया जाय इसका कोई आसाम उत्तर नहीं हो सकता। इतना निश्चय अवश्य है कि वे लोकतान्त्रिक समाजवादी थे तथा उन्होंने विकेंद्रित समाजवाद का समर्थन किया।

लास्की ने यद्यपि कुछ माक्सवादी मान्यताओं को स्वीकार किया तथा रूस में साम्यवादी व्यवस्था के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया किन्तु वे साम्यवादी नहीं थे। राज्य के पूँजीवादी स्वरूप की आलोचना करने, सरकार को किसी एक वर्ग की व्यवस्था बतलाने, आर्थिक-समता का पूर्ण अनुमादन करने, श्रमिकों की आकांक्षाओं के प्रति अधिक सहानुभूति रखने में कोई व्यक्ति साम्यवादी नहीं हो जाता घोर वास्तव में माक्सवादी होने का तात्पर्य साम्यवादी नहीं है। मूलतः साम्यवादी वह है जो वर्ग-संघर्ष, सशस्त्र क्रान्ति तथा सबहारा वर्ग के अधिनायकत्व का समर्थन करते हैं। लास्की ने इन्हें या विश्व व्यवस्था में परिवर्तन करने का ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया।

⁴⁴ Hollowell, H J, *Main Currents in Modern Political Thought*, pp 423-74

⁴⁵ *Ibid.*, Notes, p 727

संक्रमणकालीन और कारणा एवं परिणाम का सम्बन्ध सदैव नहीं रहता। तृतीय, ऐसे मनुष्यों द्वारा समाज तथा विभिन्न समूहों का निर्माण होता है। इस प्रकार समूह व समाज के कार्य भी विवेक और अविवेक की अभिव्यक्ति होते हैं। चतुर्थ, विवेक प्रति विद्रोह मानव स्वभाव तथा समाज का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करता है। उसे मानव स्वभाव की यथार्थता के आधार पर मनुष्य के कार्यक्षमताओं को समझने प्रयत्न किया जाता है। पंचम, विवेक के प्रति विद्रोह परम्परागत दार्शनिक जति को अस्वीकार करता है। यह समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान के अन्तर्गत विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग है।

यहां विवेक के प्रति विद्रोह तथा अविवेकवाद (Irrationalism) के मध्य अंतर समझना आवश्यक है। अविवेकवाद ने विवेक को कोई स्थान नहीं है। किन्तु 'विवेक के प्रति विद्रोह' विवेक का पूर्ण विरोध नहीं करता। इसके समर्थक विवेक को खेच लेना ही महत्त्व देने हैं जितना कि मानव स्वभाव में उसका योगदान है, उसे अधिक नहीं। वे विवेक को केवल प्रकार्यात्मक (Functional) साधन मानते हैं। इहीं वही अविवेकवाद तथा विवेक के प्रति विद्रोह में अन्तर स्थापित करना असम्भव है।

विवेक के विरुद्ध विद्रोह के कारण

मॉरिस कोहेन (Morris Cohen), जो विवेकपूर्ण ज्ञान के प्रबलतम समर्थक में अपनी बहुचर्चित पुस्तक-Reason and Nature-में विवेक के प्रति विद्रोह के कारणों का विवेचन किया है। कोहेन ने विवेक के पतन के लिए मनोवैज्ञानिक तर्क (Arguments of Psychologism), इतिहासिक तर्क (Arguments of Historicism), तथा अनुभववादी तर्क (Arguments of Empiricism) आदि का प्रयोग किया है। मनोवैज्ञानिक तर्क के अनुसार विवेक के समर्थकों ने विवेक को अति महत्त्व दिया है। मनुष्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां विवेकपूर्ण कार्य द्वारा ही किन्तु अचेतन भावना (unconscious spirit) के कारण प्राप्त हुई हैं। इतिहासिक तर्क विवेक की अस्तित्वना कर प्रत्येक विकास को इतिहास के तथ्य द्वारा प्रमाणित करना है। अनुभववादी तर्क प्राकृतिक विज्ञान, प्रयोग तथा पर्यवेक्षण पर आधारित है। इनके अनुसार विज्ञान विवेक में विकास नहीं करता। इन तर्कों के नर्पकों का दावा है कि ग्रीक के लोग विज्ञान का पूर्ण आधार रखने में असफल रहे क्योंकि वे विवेक के नये में ही डूबे रहने से।

भाव का पुन वैज्ञानिक पुन है फिर भी बुद्धि और विवेक की प्रतिष्ठा का अन्तःकरण पतन होता जा रहा है। आधुनिक विज्ञान तथा उसकी विभिन्न शाखाओं का निर्माण बुद्धि और विवेक के आधार पर हुआ है किन्तु विवेक के प्रति इन्होंने श्रद्धा में कमी की है। विलियम जेम्स (William James) ने अपने ग्रन्थ-Pluralistic Universe-में विवेक और बौद्धिक तर्क पर भरपूर आघात किया है।

विवेक के प्रति अविश्वास के कारण आज के युग के बानावरण में निहित है। आज का युग अस्तिर है, मनुष्य तीव्र गति से प्रगति करना चाहता है। वह विकसित व्यवस्था को गति से सन्तुष्ट नहीं है। वह समझने लगा है कि अविवेकपूर्ण साधनों से शीघ्र प्रगति सम्भव है।¹

विवेक के पतन का एक प्रमुख कारण जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि भी है। आजकल लोकतान्त्रिक व्यवस्था भीड़तन्त्र की ओर अग्रसर हो रही है। कोई भी नेता जब बृहद् जनसमुदाय के समझ अपना भाषण देता है उसमें बुद्धिवादिता तथा विवेक की मात्रा का कम होना स्वाभाविक है।

इस भीड़तन्त्र से शिक्षा के क्षेत्र में भी विवेक का पतन हुआ है। प्राचीन शिक्षा दीर्घकाली थी तथा थोड़े से ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार था। आजकल कक्षाओं में विद्यार्थियों की असीमित संख्या, विद्यार्जन करने वालों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होना, जहाँ समय के अभाव आदि में विवेक और बुद्धि पर आधारित चिन्तन-मनन एवं व्यवहार सम्भव होना जा रहा है।

विवेक की अहलना का एक प्रमुख कारण तथ्य सम्बन्धी ज्ञान (Factual Knowledge) में अप्रत्याशित विकास एवं वृद्धि होना है। यह आद्यगमन के साधनों में वृद्धि, भय-भय समाज एवं मानव समुदायों की खोज, नये अन्वेषण, नवीन विवेचन पद्धतियों से सम्भव हो सका है। इस प्रकार नये तथ्यों की खोज ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है।

सत्ता (Authority) को विवेक का सबसे प्रबल विरोधी समझा जाता है। सत्ता के तीन प्रमुख स्तंभ-चर्च, परम्परा तथा अपन से श्रेष्ठ व्यक्तियों का मन-बहु मान कर चलने हैं कि विवेक को इनके अधान रहना चाहिए। उनका विचार मनुष्य का विवेक नमनीय तथा परिवर्तनशील रहना है इसलिए उसे सत्ता के विभिन्न खोजों एवं तथ्यों के नीचे लाना चाहिए। वे चर्च को सत्य का प्रतीक मानते हैं। वे विवेक के स्थान पर परम्परागत धारणाओं में विश्वास करते हैं। जैसा कि बर्क (Edmund Burke) ने कहा है मनुष्य को स्थिर परम्पराओं पर विश्वास करना चाहिए। सत्य की खोज में विवेकपूर्ण विवेचन करना समय नष्ट करने के बराबर है। इसी प्रकार न्यायाधीश मक्लेन (Judge Meclain) सर्वधार्मिक परिवर्तनों के विरुद्ध ये क्या कि उनके विचार से इंग्लैंड का संविधान दो हजार वर्ष से अधिक एग्नो-सेक्वन्त अनुभव का परिणाम है। धार्मिक विवेक के आधार पर उन्होंने सर्वधार्मिक परिवर्तनों का समर्थन नहीं किया। विवेक के कुछ विरोधी श्रेष्ठ व्यक्तियों के मत एवं विचारों के समर्थक हैं। उनके अनुसार यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य शिक्षा, धर्मना, बुद्धि, अनुभव में समान नहीं होता। इतनी सामान्य व्यक्तियों को अपने धार्मिक विवेक को श्रेष्ठ व्यक्तियों के मत के अधीनस्थ कर देना चाहिए।

¹ Cohen, M., Reason and Nature, p 3

विवेक-विरोध का विकास

विवेक के प्रति विद्रोह के विकास को किसी न किसी रूप में प्राचीन युग से ही देखा जा सकता है, किन्तु इस विद्रोह का सूत्रपात मध्य युग से हुआ। धार्मिक मान्यताओं तथा अन्ध-विश्वास का सर्वत्र ही पारस्परिक विरोध रहा है। यूरोप में ईसाई धर्म तथा चर्च संस्था के प्रादुर्भाव एवं विकास से विवेक को काफी आघात पड़ा। धीरे-धीरे चर्च द्वारा सत्ता का सचय, श्रद्धा की मांग तथा कालान्तर में अन्ध विश्वास के व्यापक प्रवेश ने विवेक पर आधारित ज्ञान को पृष्ठभूमि में कर दिया। चिन्तन की यह स्थिति सम्पूर्ण मध्य युग में धनी रही।

रिनेशाँ (Renaissance-पुनर्जागृति) युग (लगभग पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक) से मानव समाज का आधुनिक युग में सञ्चरण होता है। टॉमस एक्विनास से लेकर लॉक तक राजनीतिक चिन्तन में कई महत्वपूर्ण प्रतियोगियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने मानव चिन्तन के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किये। रिनेशाँ के पूर्व ज्ञान के समस्त भण्डार और शाखाओं पर धर्मशास्त्र (Theology) का सर्वत्र प्रभाव था। पन्द्रहवीं शताब्दी में ईसाई धर्मशास्त्र तथा इसके सरक्षक चर्च को राष्ट्रवाद तथा बुद्धिवाद (Rationalism) की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह चर्च की सत्ता तथा परम्परागत मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह था। स्वयं चर्च में नैतिक साहस का अभाव था जिस कारण वह इन शक्तियों को आत्मसात करने में असफल रहा।

रिनेशाँ से मानव विवेक का युग (Age of Reason) प्रारम्भ होता है। सर्वप्रथम इसने धार्मिक नैतिकता तथा परलोक सम्बन्धी बातों का खंडन कर धर्म-निर्गमेशता को प्रतिष्ठित किया। ईश्वर और चर्च की महिमा गायब के स्थान पर त्वय मनुष्य को गौरवान्वित किया गया। इस युग का विचार था कि मनुष्य किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, वह स्वयं का स्वामी है। चिन्तन का साध्य चर्च या ईश्वर नहीं, मनुष्य है। इस मानववाद (Humanism) ने समाज के समस्त रहस्यों को प्रभावित कर एक नई दिशा दी। एक अन्य सम्बन्धित उपलब्धि के रूप में रिनेशाँ वातावरण ने सत्य की खोज तथा ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया एवं पद्धति में परिवर्तन कर एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन दिया। यह मानव विवेक युग के साथ-साथ आधुनिक युग का प्रारम्भ था। रेने डेसकार्टेस (Rene D. scartes, 1596-1650) को विवेकवाद का जनक माना जाता है। रेने डेसकार्टेस तथा कुछ अन्य ने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान विवेक है तथा वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान का उद्देश्य परलोक का अध्ययन नहीं, इसका आधार मानव मस्तिष्क और अनुभव है। वास्तव में रेने डेसकार्टेस ने विवेकवाद को अनुभव और यथार्थता के आधार पर इस प्रकार आगे बढ़ाया कि

विवेकवाद का जनक होने के साथ-साथ उनके विचारों में विवेक के प्रति विद्रोह के बीज भी दृष्टिगोचर होते हैं।

रिनेशाँ युग के उपरान्त विवेक के समर्थन और विरोध का नम चलता रहा। एक ओर रिनेशाँ ने राजनीतिक चिन्तन को धर्म तथा अन्धविश्वास से मुक्ति दिला कर विवेकपूर्ण अंधार पर लान का प्रयास किया, दूसरी ओर मेकियावेली तथा हॉस ने विवेक के स्थान पर शक्ति तथा स्वार्थ को प्रतिष्ठित किया। इसी विवेक का समर्थन तथा विरोध दोनों ही करते हुए प्रवृत्त होते हैं। इसी का विश्वास था कि मनुष्य के लिये सबसे अधिक महत्व भावनाओं और सहज वृत्तियाँ का है। विचारशील मनुष्य पतित पशु है। इसी की दृष्टि में मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण भाग थे। इसी के अनुसार सेबींइन के शब्दों में, "बुद्धि भयानक है क्योंकि वह श्रद्धा को कम करती है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि वह विश्वास को नष्ट कर देता है, विवेक दुःख है क्योंकि वह नैतिक सहज ज्ञान के विरोध में तक-वितक को प्रतिष्ठित करता है।"²

इतना सब कुछ होते हुए भी अनुबन्धवादी युग के विचार जैसे प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून आदि में विवेकपूर्ण मान्यताओं में वृद्धि की।

अनुभववाद और विवेक (Empiricism and Reason)

'मनुष्य केवल अपने विवेक से ही प्रेरित नहीं होता, इस पक्ष पर तथा दर्शन-शास्त्र के विवेकपूर्ण तत्व पर अनुभववादियों ने प्रबल प्रहार किया है। आधुनिक अनुभववाद के प्रमुख प्रतिपादक जॉन लॉक (John Locke 1632-1704) ने 1690 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ—*Essay Concerning Human Understanding*—में मानव स्वभाव एवं आचरण का जो विवरण प्रस्तुत किया है उसमें विवेक का पूर्ण सङ्कल्पना स्वीकार नहीं की गयी है। लॉक के अनुसार जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक सफेद कोरे बागल की भाँति होता है। जन्म में मनुष्य को जो असीमित ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है इसका मुख्य कारण एवं स्रोत उसका अनुभव है। यह अनुभव उसके प्रत्यक्ष ज्ञान (perception) पर आधारित होता है। लॉक के इस विचार को एक नवीन और क्रान्तिकारी सिद्धान्त कहा गया। इसका महत्त्व इस बात में है कि इसने दार्शनिक परम्परा का छण्डन किया है तथा केवल मानव, अनुभव को ज्ञान के स्रोत में स्वीकार किया है। साथ ही साथ यह वैज्ञानिक अध्ययन की ओर दिशा ज्ञान कराता है।³ लॉक के अतिरिक्त डेविड ह्यूम (David Hume 1711-1776), जॉन स्टुअर्ट मिल (J S Mill, 1806-1873) तथा कान्त (Immanuel Kant, 1724-1804) आदि ने इस अनुभववादी सिद्धान्त का और विस्तार किया। डेविड ह्यूम ने 1739-40 में प्रकाशित अपने ग्रन्थ—*Treatise of Human Nature*—में विवेक का विवरण किया है। ह्यूम के अनुसार, जैसा कि

² समाप्त, राजनीति दर्शन का इतिहास, पृ. 540

³ Hallowell, J H., *Main Currents in Modern Political Thought*, pp 100-101

सेवाशन में लिखा है, विवेक स्वयं कार्य की किसी पद्धति का आदेश नहीं देता। विवेक आवेगों का दास होता है और उसे ऐसा होना भी चाहिये। विवेक का कार्य आवेगों को सेवा और आज्ञा पालन करता है वह और अन्य कार्य नहीं कर सकता।⁴

वैज्ञानिक प्रगति से भी यह स्पष्ट हुआ है कि मनुष्य की गतिविधियों और चिन्तन में विवेक का प्रमुख स्थान नहीं रहता। आधुनिक विज्ञान का दावा है कि मस्तिष्क (जो विवेक का मूल स्थल है) शरीर से पृथक नहीं है तथा मस्तिष्क और शारीरिक गतिविधियों में सामन्जस्य होना चाहिये। हॉबहाउस (L. T. Hobhouse) के अनुसार यह सामन्जस्य एक दूसरे के अधीन नहीं किन्तु पारस्परिक-निर्भर विकास की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विवेक ही सब कुछ नहीं है किन्तु उस पारस्परिकता का एक भाग है। हॉबहाउस ने प्लेटो की उस धारणा का खण्डन किया है जिसके अनुसार समाज में विवेक या विवेकशील उच्च वर्ग ही मरदाक वर्ग होना चाहिये।⁵

विवेक का सबसे प्रबल विरोधी जर्मन दार्शनिक फ्रेड्रिक नीत्से (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) था। नीत्से ने इस धारणा को पूर्णतः रद्द किया है कि मानव जीवन का निर्देशन विवेक से होता है। नीत्से के अनुसार आज का मनुष्य आधुनिक मनुष्य है क्योंकि वह ईश्वर और विवेक से मुक्त एवं पृथक होता चला जा रहा है। नीत्से शक्ति का समर्थक था। शक्ति स्वयं में सत्य है, उसके औचित्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं।

प्रयोगवाद और विवेक (Pragmatism and Reason)

प्रयोगवाद भी मानव विवेक की महत्ता स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार सत्य यही है जिस पर मनुष्य विश्वास करले। सत्य का अर्थ विचार तर्क संगत हो नहीं है और न इसका अर्थ यथार्थता है, किन्तु वह है जो प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्य चलता है। प्रयोगवाद कोई विचार प्रणाली नहीं है, यह केवल पद्धति है। प्रयोगवाद स्वयं में कोई दर्शन नहीं है किन्तु एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। यह मनोविज्ञान की उस अवधारणा से प्रारम्भ होता है कि मनुष्य उस पर ही विश्वास करता है या उसे ही सत्य मानता है जो उसे भावात्मक संतुष्टि प्रदान करे।⁶ किन्तु प्रयोगवाद का निष्कर्ष कुछ भिन्न है। प्रयोगवाद के अनुसार सत्य, विश्वास वह है जो भावात्मक संतुष्टि दे या जिससे कार्य चलता है। सत्य की खोज नहीं की जाती, सत्य का निर्माण किया जाता है। सत्य पूर्ण या स्थिर तत्व नहीं है, इसमें निरन्तर परिवर्तन होना रहता है।

प्रयोगवाद के प्रमुख प्रवर्तक अमरीकी दार्शनिक पियर्स (C. S. Pierce, 1840-

4 सेवाइन, राजनीति-दर्शन का इतिहास पृ. 563.

5 Greaves, H. R. G., The Foundations of Political Theory, p 77.

6 Hallowell, H J., Main Currents in Modern Political Thought, pp 544-45

1914) तथा विलियम जेम्स (William James, 1842-1919) थे। इस पद्धति का विस्तार प्रोफेसर जॉन डेवी (John Dewey) ने किया।

समाजशास्त्र एवं अविवेकवाद

विवेक का इतने निम्न स्तर का मूल्यांकन करने में समाजशास्त्रियों का भी योगदान रहा है। समाजशास्त्रियों ने प्राकृतिक विज्ञान की विभिन्न पद्धतियों को आधार मान कर सामाजिक विकास के नियमों को समझाने का प्रयत्न किया है। समाजशास्त्र के संस्थापक कॉम्टे (Auguste Comte, 1798-1857) तथा उनके अनुयायियों का दावा था कि उन्होंने सामाजिक विकास एवं व्यवस्था के नियमों को खोज कर लिया है। कॉम्टे ने इस विचार का प्रतिपादन अपने त्रि-सोपान विधान (The Law of the Three Stages) में किया है। कॉम्टे के अनुसार मानव विचारों के इतिहास को तीन युगों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था (आदिम युग से मध्य युग तक) मनुष्य सुपर-प्राकृतिक, परलोक तथा ईश्वरीय ज्ञान से ज्ञानित रहा। द्वितीय अवस्था (घट्टारहवीं शताब्दी) में मनुष्य के विचारों पर (metaphysical forces) का प्रभाव रहा, जैसे—सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अंधकार, जन-सम्प्रभुता आदि विचारों ने मानव-चिन्तन का निर्धारण किया। घट्टारहवीं शताब्दी के बाद की अवस्था को कॉम्टे ने सकारात्मक या स्वीकारात्मक (positive) कहा है। यह वैज्ञानिक अवस्था है जिसके अन्तर्गत अमूर्त और अवधारणाओं के स्थान पर घटना-क्रम के अनुभववादा अवलोकन की मांग्यता की गई है। अनुभव के आधार पर सामाजिक विधि-विधान को समझा जा सकता है। कॉम्टे के अनुसार इस अवस्था की ओर ही मनुष्य जाति बढ़ रही है तथा वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से एक पूर्ण एवं सहयोगी समाज की स्थापना होगी। कॉम्टे के ये विचार प्रस्थान बिन्दु थे जहाँ से सामाजिक शास्त्रों को आधुनिक विज्ञान के दायरे में समेटने का प्रयत्न किया जाता है।⁷ उसके विचार विवेक की महत्ता से मेल नहीं खाते।

एमील ड्यूरकहीम

(Emile Durkheim, 1858-1917)

कॉम्टे के अतिरिक्त फ्रान्स तथा इटली में कुछ अन्य भिद्धान्तकार हुए जिन्होंने सामाजिक कार्य-कलापों में अविवेक का भूमिका की स्वीकार किया है। इनमें प्रमुख गैब्रियेल टार्डे (Gabriel Tarde, 1843-1904), ल वॉन (Le Bon, 1841-1931), ड्यूरकहीम तथा पेरेटो प्रमुख थे। किन्तु ड्यूरकहीम तथा पेरेटो की विविष्ट विचार भूमिका के कारण उनका विवेचन आवश्यक है।

⁷ सेबार्डन, राजनीति-दर्शन का इतिहास, पृ० 672

डर्कहोम के पिता एक यहूदी धर्म उपदेशक थे। इन्होंने फ्रांस, जर्मनी आदि में दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र तथा शिक्षा के विभिन्न पक्षों का विशिष्टतापूर्वक अध्ययन किया। फ्रांस में डर्कहोम कई विश्व-विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्धित रहे तथा कई संस्थाओं की स्थापना की। यूरोप के तत्कालीन समाजशास्त्रियों में डर्कहोम का प्रमुख स्थान था। इनके कई अनुयायी थे तथा इनके विचारों के आधार पर समाजशास्त्र में डर्कहोम सम्प्रदाय का प्रचलन चला। डर्कहोम के प्रमुख ग्रन्थ थे—*The Division of Labour in Society*, 1893, तथा *Rules of Sociological Method*, जिसका प्रकाशन 1895 में हुआ। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त डर्कहोम ने समाजवाद, शिक्षा आदि पर भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे।

डर्कहोम के विचारों पर कांते, स्पेन्सर आदि का प्रभाव पड़ा किन्तु इनका इन्होंने ग्रन्थों में छुसरा नहीं किया। डर्कहोम का मुख्य विचार था कि समाजशास्त्रियों को समाज का अध्ययन करना चाहिये, किन्तु यह अध्ययन सम्पूर्ण समाज का नहीं सामाजिक संस्थाओं का होना चाहिये। संस्थागत अध्ययन ही डर्कहोम के लिये समाजशास्त्र का वास्तविक अध्ययन था। यह अध्ययन व्यक्तिगत और भौतिक दृष्टिकोण से न होते हुए तथ्यों की पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए।

डर्कहोम ने व्यक्ति के मस्तिष्क को समूह मस्तिष्क का प्रतिबिम्ब माना है। उसका व्यवहार, चिन्तन, धार्मिक विचार, नैतिक उद्देश्य आदि उसके सामूहिक जीवन की प्रतिक्रिया है। व्यक्तियों के समुदाय को एक सामूहिक तना (Collective Consciousness) होती है जो व्यक्तिगत चेतना से भिन्न है। सामूहिक चेतना के स्वयं के विचार तथा 'सामूहिक प्रतिनिधित्व' होता है जिन्हे व्यक्तिगत चेतना को नैतिक, धार्मिक, न्यायिक और विधि नियमों के रूप में प्रदान किये जाते हैं। इनके पीछे एक शक्ति निहित शक्ति होती है, व्यक्ति इसका विरोध करने में असमर्थ है।

समाज का विवरण देते हुए डर्कहोम ने निखा है कि समाज तर्कसंगत तथा पूर्ण सम्बद्ध है। समाज की सामूहिक चेतना मानसिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। चूंकि सामूहिक चेतना व्यक्ति से उच्च एवं परे है इसलिये यह सामाजिक तत्त्वों को स्थाई और आवश्यक रूप में देख सकती है। यह व्यक्ति की अपेक्षा उत्तम और दूरगामी दृष्टि रखने वाली है।

समाज में समय का वितरण जैसे घण्टे, दिन, महीना, माह, वर्ष आदि की व्यवस्था तथा समय-समय पर उत्सव, भोजन, सार्वजनिक समारोह आदि सभी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। एक सामाजिक कैलेंडर सामूहिक गतिविधियों की गति एवं व्यवस्था निर्धारित करता है।

डर्कहोम का विशिष्ट अध्ययन घातमहत्या (Suicide) तथा धर्म के विषय में था। धर्म के अध्ययन से डर्कहोम के ज्ञान सिद्धान्त (Theory of Knowledge) का

प्रादुर्भाव हुआ तथा इसी आधार पर उनके समाजशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान का विस्तार हुआ। अपने इन अध्ययनों में डर्कहीम ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य पूर्णरूपेण विवेक से निर्देशित नहीं होता। मनुष्य कई सामाजिक तत्वों, जिनका विवेक से कोई सम्बन्ध नहीं है, से प्रेरित होता है। आत्महत्या को प्रेरणा विवेक से नहीं मिलती किन्तु इसके सामाजिक कारण होते हैं।⁸ डर्कहीम के अनुसार धर्म विश्वास और व्यवहार का एकीकृत रूप है। धर्म के कर्म वाण्ड आचार-व्यवहार शक्तियों से प्रेरणा लेते हैं।

विलफ्रेडो पारेटो

(Vilfredo Pareto, 1848—1923)

आधुनिक समाज सिद्धान्तकारों में पारेटो का नाम सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण है। पारेटो इटली के एक प्रसिद्ध इन्जीनियर थे किन्तु उनकी ख्याति एक समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक सिद्धान्तकार के रूप में हुई। पारेटो के माता-पिता इटालियन थे तथा इटली के एकीकरण के जनक मेजिनी के समर्थक होने के कारण उन्हें इटली से निर्वासित कर दिया गया था। फ्रांस में पारेटो का जन्म हुआ। 1858 में पारेटो के माता-पिता पुनः इटली वापस आ गये। किन्तु बड़ा होने पर पारेटो ने मेजिनी के ही उदारवादी और समाजवादी विचारों का विरोध किया। 1892 में पद से अवकाश ग्रहण के बाद स्विट्जरलैंड चले गये। इसी वर्ष पारेटो को लोसेन (Lausanne) विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया जहाँ मुसोलिनी उनका प्रिय शिष्य था। मुसोलिनी पारेटो के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। जब मुसोलिनी सत्ता में आया तब उसने अपने गुरु को सीनेट का सदस्य बनाया किन्तु यह पद ग्रहण करने के पहले ही पारेटो की मृत्यु हो गयी।

पारेटो के प्रमुख ग्रन्थ निम्नलिखित थे —

- 1 Manual of Political Economy, 1906
- 2 Treatise on General Sociology, 1916
3. The Mind and Society, 1915-16

पारेटो ने उपरोक्त ग्रन्थों में अपनी चतुर्मुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन ग्रन्थों में—The Mind and Society—प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह ग्रन्थ सामाजिक वास्तविकता का वैज्ञानिक विश्लेषण है।

गौण अथवा अवशिष्ट प्रवृत्तियों का सिद्धान्त
(Theory of Residues and Derivations)

पारेटो ने ग्रीक-रोमन इतिहास और सभ्यता के आधार पर मानव कार्यकलापों का व्यापक अध्ययन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि व्यवहार या तो तार्किक (विवेकपूर्ण) होता है जिसके अन्तर्गत साधनों के अनुरूप साधनों का प्रयोग होता है,

⁸ See Western Social Thought by Kilzer and Ross, p. 362

या गैर-तार्किक अथवा अवुद्धिपूर्ण (non-logical) जिसमें व्यवहार की एकरूपता नहीं होती। पेरैटो के अनुसार मानव समाज की व्यवस्था तथा विकास में गैर-तार्किक व्यवहार का प्रचलन एवं महत्व अधिक रहता है। पेरैटो ने इन असम्बद्ध कारकों (non-logical factors) के विवरण तथा वर्गीकरण के विषय में व्यापक उल्लेख किया है। पेरैटो का दावा था कि उसने कुछ ऐसे प्रेरक तत्वों तथा व्यवहार बोध कराने वाले कुछ गौण तत्वों (पेरैटो ने इन्हें residues कहा है) की खोज करली जो मानव इतिहास के सभी युगों तथा विश्व के सभी समाजों में स्थिर है। पेरैटो ने इन तत्वों का छः भागों में वर्गीकरण किया है जैसे वे प्रवृत्तियाँ जो मनुष्यों को एक दूसरे के सम्पर्क में लाती हैं तथा पारस्परिक विचार और कार्य की ओर प्रवृत्त करती हैं; वह प्रवृत्ति जो अपने समुदाय की पूजा, रक्षा आदि के लिए प्रोत्साहित करती है, वे बाह्य कार्य जो व्यक्ति की आन्तरिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वह प्रवृत्ति जो व्यक्ति को अपने समुदाय की एकरूपता अंगीकार करने के लिये अग्रसर करती है; तथा वह प्रवृत्ति जो मनुष्य को व्यक्तिगत निष्ठा, लिंग प्रवृत्ति और समानता के लिये प्रोत्साहित करती है। ये तत्व एव प्रवृत्तियाँ सभी व्यक्तियों में विद्यमान रहती हैं किन्तु इनकी मात्रा का वितरण व्यक्तियों तथा उनके समूहों में भिन्न भिन्न होता है। जिस व्यक्ति या समूह में जिस प्रवृत्ति की अधिकता होती है उसी के अनुरूप वहाँ का समाज होता है। ये प्रवृत्तियाँ विवेकपूर्ण सत्य हैं या नहीं पेरैटो के अनुसार यह कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि मनुष्य इनसे प्रभावित एव प्रेरित होता है तथा जिनके माध्यम से मनुष्य और उसके समूह की अभिव्यक्ति होती है।

पेरैटो के अनुसार गौण तत्वों एवं प्रवृत्तियों को मौखिक रूप से तर्क-संगत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पेरैटो ने डेरिवेशन (derivations) कहा है। इसका तात्पर्य साध्य के अनुरूप माध्याम का प्रयोग न करना, गैर-तार्किक विचार तथा स्पष्टीकरण आदि प्रस्तुत करना है। डेरिवेशनस अवुद्धवादी होते हैं।

सामाजिक सन्तुलन सिद्धान्त (Theory of Social Equilibrium)

गौण तत्व एव प्रवृत्तियों, तथा डेरिवेशनस के सिद्धान्तों के उपरान्त पेरैटो सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख कारकों को निर्धारण करने का प्रयत्न करते हैं। उनका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तनों के नियमों की खोज करना है। इस सन्दर्भ में पेरैटो 'सामाजिक सन्तुलन सिद्धान्त' प्रस्तुत करते हैं। पेरैटो के अनुसार समाज न तो अव्यव है और न कोई मशीन वरन् एक सामाजिक व्यवस्था (Social System) है। इस व्यवस्था में एकतापरक तत्व विघटनकारी तत्वों को नियन्त्रित रखते हैं। समाज के सन्तुलन एवं स्वरूप का निर्धारण, पेरैटो के अनुसार, निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है 9—

- 1 भौतिक वातावरण (physical environment) जो स्थायी तत्व है,
- 2 शेष तत्व एवं प्रवृत्तियाँ (residues),
- 3 हित (interests) या सामान्यतः आर्थिक हित होने हैं,
- 4 डेरिवेशन (derivations), और
- 5 समान में शिखर समूह अथवा विशिष्ट वर्ग (elite) का वर्ग परिवर्तन ।

इनके अतिरिक्त वा और तत्वा का प्रमुख भूमिका रहती है। प्रथम, समाज के बाह्य तत्व जैसे विश्व का अन्य सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव, तथा द्वितीय, सामाजिक व्यवस्था व आन्तरिक तत्व जैसे नस्ल उनकी अनुभूति, इच्छाएँ विचारधाराएँ तथा अन्य मानव गुण जो समाज का निर्माण करते हैं।

असम्बद्ध कारक (non-logical factors)

समाज के विभिन्न प्रेरक तत्वों के परिणाम एक मात्रा का निर्धारण, उनके प्रभाव व किस प्रकार एक दूसरे से सहबद्ध हैं तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का यदि ज्ञान कर सकें तो समाज तथा उसके विभिन्न पक्षों का पूर्ण विवेचन किया जा सकता है। इन तत्वों के आधार पर समाज के व्यवहार को समझा जा सकता है।

परंतु के अनुसार सामाजिक कारकनाशों में विवेक का प्रभाव कोई विशेष नहीं होता। मनुष्य विवेक से अधिक प्रेरणा नहीं लेता। विवेक केवल यह बता सकता है कि हम जो करना चाहते हैं उसे कैसे करें। वादनीय कार्य तथा मनुष्य की आन्तरिक इच्छाओं के विषय में विवेक कुछ नहीं कह सकता। परिणामस्वरूप मनुष्य का अधिकतम व्यवहार असम्बद्ध अथवा गैरतांत्रिक कारकों (non-logical factors) से प्रेरणा लेने है और प्रभावित होना है।

कारण और परिणाम (causes and effects)

पेरेंटो अनुक्रम वैज्ञानिकों की धारणा में आते हैं जिन्होंने अपने सिद्धान्तों को सामाजिक तथ्यों व विवेचन, उनकी एकरूपता, नैतिक मूल्यांकन तथा 'कारण और परिणाम' से मुक्त विचारों से ग्रहण किया है। पेरेंटो ने कारण-परिणाम सिद्धान्त का स्वीकार नहीं किया है क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तनों की एकपक्षीय, सामान्य और बाह्य तन्वीर प्रस्तुत करता है। पेरेंटो के अनुसार समाज की निरन्तर परिवर्तन-शील तन्वीरों का पुत्र है। यह तत्व एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इनमें क्रिया को कारण और क्रिया को परिणाम कहना अशक्य है। राजनीति, धर्मशास्त्र, धर्म, नैतिकशास्त्र पारस्परिक कार्यों से सम्बन्धित है न कि कारणों से।

शिखर समूह अथवा विशिष्ट वर्ग सिद्धान्त (Theory of Elite.)

पेरेंटो के मतानुसार शिखर समूह सिद्धान्त का तात्पर्य कुलीन नेतृत्व से है। यह नेतृत्व किसी भी व्यवस्थित समाज के नियंत्रक है। नेतृत्व की कुलीनता से परिवर्तन में सामाजिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। जब निम्न वर्गों के लोग

उच्च वर्ग तथा उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग में प्रवेश करते हैं इससे सामाजिक सन्तुलन भंग हो जाता है। पेरेंटो मनुष्य की सामाजिक विशेषताओं के साथ साथ समाज में वर्ग-विभाजन का उल्लेख करते हैं। पेरेंटो के अनुसार समाज दो वर्गों में विभाजित रहता है—प्रथम, उच्च वर्ग (elite), द्वितीय उच्च वर्ग के बाद बचे हुए व्यक्ति (non-elite) जिसे निम्न वर्ग कहा जा सकता है। उच्च वर्ग पुनः दो भागों—शासक तथा अन्य में विभाजित किया जा सकता है। शासक उच्च वर्ग में भी एक छोटा समुदाय होता है जो समाज पर नियंत्रण स्थापित रखता है। यह बात सभी शासन व्यवस्थाओं में सही है चाहे वह लोकतन्त्र, कुलीनतन्त्र, राजतन्त्र अथवा तानाशाही हो।

प्रत्येक समाज में, पेरेंटो के अनुसार, उच्चवर्ग में परिवर्तन होता रहता है। निम्न वर्ग के व्यक्तियों का उच्च वर्ग में सम्मिलित होने का क्रम निरन्तर बना रहता है तथा प्रत्येक उच्च वर्ग कभी न कभी समाप्त होता है। मनुष्यों के व्यक्तिगत गुणों एवं विशेषताओं के कारण भी उच्च वर्ग में परिवर्तन होता रहता है। यदि शासक उच्च वर्ग में दूसरों को आत्मसात या अपने में समा लेने की अथवा वे व्यक्ति जो उस समूह में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें नष्ट करने की क्षमता है तब यह शासक वर्ग स्थायी रहता है अन्यथा क्रांति की सम्भावना रहती है।

राजनीति और शक्ति


पेरेंटो का विचार है कि शासन कला शक्ति तथा दूसरों को धोखा देने पर निर्भर करती है। दूसरों की भावनाओं को समझ उनसे लाभ लेने से शासन सफलता की ओर अग्रसर होता है। यह तभी सम्भव है जब व्यक्ति स्वयं को अपनी भावनाओं से मुक्त कर दूसरों के मनोभाव को समझ सके। पेरेंटो के अनुसार समाज में शक्ति आवश्यक है। जब शासक वर्ग शक्ति का प्रयोग न कर अपनी बुद्धि और कुशलता पर ही निर्भर करता है उस समय यदि समाज प्रगति और समृद्धि चाहता है शक्ति का प्रयोग आवश्यक ही जाता है। जो वर्ग शक्ति का प्रयोग कर सकता है वह उस शासक वर्ग को अपदस्त कर देता है जो शक्ति पर निर्भर नहीं करता। सीजर महान शक्ति के बल से ही रोमन समाज को पतन से बचा सका था।

पेरेंटो के विचारों का मूल्यांकन

पेरेंटो का स्वयं यह विचार था कि उसका कार्य सामाजिक यथार्थता का वैज्ञानिक विवेचन है। उसका समाजशास्त्र किसी पूर्व निश्चित सिद्धान्तों पर नहीं बरन् सामाजिक तथ्यों तथा उनका अवलोकन करने के बाद सामाजिक एकरूपता पर आधारित है। यह पहले के समाजशास्त्र के सिद्धान्तों से भिन्न है क्योंकि यह नैतिक मूल्यांकन तथा आध्यात्मिक चिन्तन और अटकलबाजियों से मुक्त है। किन्तु समाजशास्त्री पेरेंटो के विचारों को विशेष मान्यता नहीं देते क्योंकि वह अपने निष्कर्षों को निकालने में तार्किक-प्रायोगिक पद्धति (Logico-experimental

method) का उपयोग करने में असफल रहे। यद्यपि पेरेंटो के सिद्धान्त सामाजिक अवलोकन, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थे किन्तु वे तथ्य ऐसे नहीं थे जिन्हें विश्वव्यापी मानकर उनका सामान्यीकरण या मंडान्तीकरण किया जा सकता। पेरेंटो अन्य समाजशास्त्रियों के अनुसन्धान से भी लाभ नहीं उठा सके। मानव कार्य-रूपाय के विषय में उनके विचार पक्षपातपूर्ण हैं क्योंकि वे मूल्यात्मक तथा आदर्शवाद के स्थान पर ग्राम्भवद कारकों को प्राथमिकता देते हैं।¹⁰

पेरेंटो के सामाजिक मनाविज्ञान की व्यापक आलोचना हुई है। हेनोवेल ने पेरेंटो को आन्तिवादी उदारवादी कहा है उनके विचार सनक और मानव व्यक्तित्व की निन्दा पर आधारित हैं। बीमवी मदी की यह विचित्र बात है कि इतने अधिक बुद्धिवादियान विवेक के विरुद्ध या अविश्वासवाद के समर्थन तथा उनके शोचिस्पष्ट म विवेकपूर्ण तर्कों की ही मजायना मी है।¹¹ पेरेंटो ने अपने सामाजिक विप्लेषण को वैज्ञानिक होने का दावा किया है। किन्तु वैज्ञानिक आचरण के नीचे उसने मेकियावेगी के 'प्रिन्स' (The Prince) को पुनः निम्न दिया जिसमें लमने बननाया है कि सम्राट को मत्ता पत्रण करन, मत्ता में कैम बना रहने, शक्ति आदि के विषय में विवेचन किया है। पेरेंटो ने 'प्रिन्स' में प्रस्तुत विचारों का विश्वास कर ममकान तक पहुँचा दिया है। प्रोफेसर मेलविन रेडर ने पेरेंटो के विषय में लिखा है कि उमने राजनीति में आनवाजी का मूभव दिया है तथा शक्ति ममर्थन में विज्ञान की प्रतिष्ठा का प्रयोग किया है। पेरेंटो 'सांख्यिक-प्रायोगिक पद्धति' (logico-experimental method) का प्रवर्तक हान हुए भी उमर विचारा के विषय में गलतफहमी अथवा आन्ति रह सकती है।¹²


 ग्राहम वालास
 (Graham Wallas 1858-1932)

ग्राहम वालास इंग्लैंड में बुद्धिजीवी समाज के एक अग्रणी व्यक्ति थे। इनका जन्म तथा लालन-पालन एक पादरी परिवार में हुआ। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक थे तथा जीवन के अधिकांश समय लंदन में रहे। ग्राहम वालास पेरिबलन सामाज्यी के प्रारम्भिक सम्स्थापका में से थे तथा इन सस्था के लक्षावधान में प्रकाशित निबन्धा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे एक संश्लेषण रूप में सक्रिय राजनीति में भी सम्बद्ध रहे कुछ समय तक लंदन काउन्टी बोमिल के मन्थ्य चुन मर तथा कई आयोगों में कार्य किया। किन्तु अध्यापन के क्षर में इन्हें सर्वाधिक स्वानि मिली। वे लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स के सम्स्थापका में थे। 1895 में 1923 तक वालास लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे

10 Kitzler and Ross, *Western Social Thought*, pp 312-13

11 Hallowell, J H., *Main Currents of Modern Political Thought* p 542

12 Melvin Rader, *No Compromise, The Conflict Between Two Worlds*, quoted by Hallowell, p 542

जिन्होंने लास्त्री, लासेवेल जैसे विद्वानों को प्रभावित किया। इस सस्या से जब इन्होंने परकाश ग्रहण किया, उनका स्यान हेरॉल्ड लास्की ने लिया।

ग्राहम वालास का महत्वपूर्ण योगदान राजनीति में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र सम्बन्धीपद्धतियों का प्रयोग करने में है। यह उनके निम्नलिखित महत्वपूर्ण ग्रन्थों से विदित होता है—

1. Life of Francis Place, 1898. (फ्रेन्सिस प्लेस का जीवन)
2. Essays in Fabian Socialism, 1889. (फेबियन समाजवाद)
3. Human Nature in Politics, 1908. (राजनीति में मानव स्वभाव)
4. The Great Society, 1912. (महान समाज)
5. Our Social Heritage, 1921. (हमारी सामाजिक धरोहर)
6. The Art of Thought, 1926. (चिन्तन कला)

ग्राहम वालास द्वारा विवेक के विरुद्ध विद्रोह अभियान का जो मर्मर्न किया गया उनके इन विचारों को कई पक्षों ने प्रभावित किया। अपने परिवार के धार्मिक पातावरण में इनका जो लालन-पालन हुआ उससे इन्होंने यह सीखा कि मनुष्य किस प्रकार विवेकरहित धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होता है। वालास को लगभग आधी शताब्दी तक अपने सार्वजनिक जीवन के अनुभव से भी सहायता मिली। समाज में वालास का सम्पर्क कवि, विद्वानों तथा निर्धन वर्ग से अधिक रहा। ये वर्ग अपने लिए वैज्ञानिक नहीं मानते थे। वालास द्वारा इनके पर्यवेक्षण से अविवेकपूर्ण तत्वों के महत्व को जानने में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त उस समय उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नये-नये विचारों का प्रादुर्भाव तथा प्रयोग किये जा रहे थे। औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव भी सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। ग्राहम वालास जैसे विवेकशील व्यक्ति मनुष्य समाज में अविवेकशील तत्वों का विवेचन किये बिना न रह सके। ग्राहम वालास के सामने समस्या यह थी कि इस ज्ञान तथा रहस्य को विचारों की प्रक्रिया के परिणाम में किस प्रकार प्रयोग किया जाय।

मानव स्वभाव

वालास के सम्पूर्ण विचारों का आधार तथा महत्व मानव स्वभाव के विवेचन में है। वालास के अनुसार मनुष्य के कार्य परिणाम द्वारा निर्देशित नहीं होते। मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए उन शक्तियों को समझना आवश्यक है जो उसे कार्य के लिए प्रेरित करती हैं। वालास के अनुसार ये शक्तियाँ मानव स्वभाव में निहित वृत्तियाँ (instinct), आवेग (impulses) अव्यक्त अवस्था में कार्य आदि हैं। वालास के अनुसार मनुष्य में विवेक होता है किन्तु उसका विवेकपूर्ण स्वभाव अस्थिर होता है। वालास का विचार है कि मनुष्य के विभिन्न कार्य-कलापों में मानव स्वभाव के वेपय में अन्तर्दृष्टि आवश्यक है।

राजनीति में मानव स्वभाव

ब्राह्म वालास का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'राजनीति में मानव स्वभाव' (Human Nature in Politics) है। 'राजनीति में मानव स्वभाव' ब्राह्म वालास का राजनीतिशास्त्र के लिए एक मौलिक और महत्वपूर्ण योगदान है। इस पुस्तक में वालास ने राजनीतिक विश्लेषण तथा सामाजिकीकरण में मनोवैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया है। वालास का विचार है कि सस्यागत उपागम (Institutional Approach) राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिये पूर्णतः अनुपयुक्त है। कई राज्यों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधि सभ्यता की घमघमाता के कारण बालास ने राजनीतिक प्रेरणा के लिए किसी अन्य उपयुक्त अध्ययन को आवश्यक माना है। परिणामस्वरूप उन्होंने राजनीति में मनोविज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया। वालास का यह दृश्य बुद्धिवादी विचारों की अभिव्यक्ति है। वालास ने कहा है कि राजनीति में मानव स्वभाव का परीक्षण बुद्धिवाद जो राजनीति शास्त्र की परम्परा तथा सामान्य व्यक्ति की मानसिक प्रकृति का परिणाम है, के ऊपर विजय में प्रारम्भ होना चाहिये।¹³ 'राजनीति में मानव स्वभाव का प्रमुख विचार राजनीतिक चिन्तन में 'बुद्धिवादी भ्रम (Rationalist Fallacy) है।¹⁴

जिस समय राजनीति में सस्यागत विधिवादी तथा मार्क्सवादी उपागम प्रचलित थे बालास ने मनोवैज्ञानिक उपागम का प्रतिपादन किया। बालास ने यह विचार रखा कि मनोवैज्ञानिक मानव जन्म के अस्तित्व के विकास का परिणाम है। मानव प्रकृति में आदिम युग से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बालास ने बुद्धि मनोवैज्ञानिक जैसे स्नेह, भय शक्ति, सम्पत्ति, इच्छा, उत्सुकता आदि का राजनीतिक व्यवहार तथा राजनीतिक सम्प्रदायों में महत्व बतलाया है। बालास ने सम्पत्ति, अधिकार, स्वतन्त्रता, सत्ता, न्याय, राष्ट्र, राजनीतिक दल आदि का मनोवैज्ञानिक आधार पर विवेचन किया है।

'मानव स्वभाव और राजनीति' में बालास प्लेटो के विचार सिद्धान्त, रूसो के प्राकृतिक अधिकार का सिद्धान्त तथा वेन्डम के उपयोगितावाद की विवेकपूर्ण धारणा के आलोचक से प्रतीत होते हैं। बालास के अनुसार ये विद्वान अपनी बुद्धिवादिता से स्वयं घुमराह हुए हैं। उन्होंने राजनीति में बेदल विवेक के महत्त्व को ही स्वीकार किया तथा राजनीति में अविवेकपूर्ण तत्त्वों की अवहेलना की है। किन्तु दूसरी ओर बालास ने हॉब्स के मनोविज्ञान को भी ठीक नहीं बतलाया जा सके। भय पर आधारित है।

ब्राह्म बालास का कहना था कि मनुष्यों द्वारा विवेक को अत्यधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए। राजनीति बाल्पनिक व्यक्ति का अध्ययन नहीं है, राजनीति व्यावहारिक पक्ष भी है इसलिए राजनीति के अर्थ में अध्ययन के लिए सामान्य

¹³ Wallas, Graham, Human Nature in Politics, p 45

¹⁴ Rowse, A. L., Introduction to Human Nature in Politics, p 2.

मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए जो भावनाओं, उत्तेजनाओं तथा अन्य प्राकृतिक इच्छाओं का पुंज है। वालास का विचार है कि यदि मनुष्य द्वारा जीवन भर किये गये कार्यों का विवेचन किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उसके अधिकांश कार्य सामान्य इच्छा, विवेक या गम्भीर चिन्तन का परिणाम नहीं है। अपितु वह अपने अधिकांश कार्यकलापों में आदतों, पदावतों, नैसर्गिक भावनाओं तथा आवेग से प्रेरित होता है। इन नैसर्गिक कृतियों तथा आवेगों के अन्तर्गत वालास ने स्नेह प्रेम, सन्देश, उत्सुकता, सम्पत्ति की इच्छा, प्रगति की इच्छा तथा संधर्ष आदि की सम्मिलित किया है।¹⁵ उनके बहून में कार्य अचेतन या अर्ध-चेतन अवस्था में होने हैं। इसी प्रकार राजनीतिक कार्य एवं व्यवहार भी इन्हीं भावनाओं, आवेग, दूसरों को देखकर आदि से अधिक नया विचार एवं विवेक से कम निर्देशित होते हैं। वालास का मुभाव था कि यदि राजनीति का विद्यार्थी राजनीति का विज्ञान के स्तर पर लाना चाहता है, या सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहता है तो उसे मानव स्वभाव की इन नैसर्गिक वृत्तियों को समझना आवश्यक है। इनके बिना उनका ज्ञान एवं अध्ययन कान्यनिक तथा यथार्थता से दूर होगा।

शासन व्यवस्था और मानव स्वभाव¹⁶

मानव समाज जिन प्राधुनिक लोकतान्त्रिक संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत रह रहा है उनका निर्माण करने वाले की व्यक्ति थे जो मानव स्वभाव के बुद्धिवादी विचार से प्रेरित थे। वे वास्तविक मानव स्वभाव का मूल्यांकन नहीं कर सके यही कारण है कि आज की राजनीतिक प्रणाली, यथार्थता से दूर होती जा रही है।¹⁷ इस मन्द में वालास ने लोकतन्त्र, प्रतिनिधि प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली की यथार्थता पर मन्देश प्रकट किया है। वालास के अनुमार दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र का आज जो व्यावहारिक रूप है उसमें व्यापक अन्तर है। प्रतिनिधि प्रणाली वास्तव में सहमति या जन इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। आज के राजनीतिक मनुष्यों की अर्ध-चेतना मनःस्थिति में लाभ उठाकर मत एवं बहुमत प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में चिन्हों, चित्रों, विज्ञापनों तथा सम्मोहन शक्ति का भरपूर प्रयोग किया जाता है। मतदाता को उसकी सही मनःस्थिति से बाकी दूर कर दिया जाता है। मतदाता को गम्भीरतापूर्वक सोचने का अवसर ही नहीं मिलता।¹⁸ वालास ने राजनीतिक व्यवस्था के दोषों को दूर करने के कई सुभाव दिये हैं यद्यपि उनके सुभावों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है।

15. Gettell, R.G., History of Political Thought, p 447.

16. इस सम्बन्ध में वालास के पूर्ण अध्ययन के लिये Human Nature in Politics के द्वितीय भाग का द्वितीय अध्याय देखिए।

17. Wallas, Graham; Human Nature in Politics, p. 215.

18. Ibid., p. 229.

महान समाज

'मानव स्वभाव और राजनीति' के छ वर्ष उपरान्त वालास के दूसरे प्रमुख ग्रन्थ—The Great Society (महान समाज) का प्रकाशन हुआ। 'महान समाज' वास्तव में 'मानव स्वभाव और राजनीति' का ही पूरक ग्रन्थ था। 'महान समाज' में वालास राजनीतिक अद्विवादि की भुटि को सही करते हैं। साथ ही साथ सामाजिक उद्देश्यों के लिए विचारों को व्यवस्थित करने की सम्भावना की खोज करते हैं।

इस ग्रन्थ में वालास न भौतिकी एवं तकनीकी क्रान्ति द्वारा समाज में उत्पन्न समस्याओं को समझन का प्रयास किया है। इन पुस्तक में भी वानाम मानव स्वभाव में प्रवृत्ति और मनोवेग के महत्त्व का स्वीकार करते हैं किन्तु इसके अतिरिक्त अन्य पद्धतियाँ जैसे ऐतिहासिक पद्धति, मनुष्य के जीवन में सम्बन्धित सामग्रियों, अनुभव आदि को भी महत्त्व देते हैं। इस पुस्तक में वानाम का एक और महत्त्वपूर्ण योगदान राजनीतिक अध्ययन के लिए परिमाणमत्क (quantitative) तथा सांख्यिकी (statistical) पद्धति का समर्थन करना है।

'हमारी सामाजिक घण्टी' (ग्रन्थ विरासत) में वालास सामाजिक प्रक्रिया में सांख्यिक पद्धति का विवेचन करते हैं। उनकी एक अन्य पुस्तक 'चिन्तन कला' (The Art of Thought) में वालास चिन्तन प्रक्रिया का विवेचन करते हैं किन्तु धूम फिर कर मानव स्वभाव के विवेचन पर ही आ जाते हैं। 'चिन्तन कला' राजनीति में मानव स्वभाव की पुनरावृत्ति जैसी पुस्तक लगती है।

प्राहम वालास के विचारों का मूल्यांकन

प्राहम वालास ने मानव व्यवहार में सहज प्रवृत्तियों, भावेग, मनोभाव आदि को अत्यधिक महत्त्व दिया है। इन प्रवृत्तियों को सामान्य से अधिक महत्त्व देना उतना ही भ्रष्टपूर्ण है जितना मानव कार्यकलापों में विवेक को अत्यधिक महत्त्व देना है। वालास का यह विचार कि चिरकाल से विरासत में प्राप्त इच्छाओं का भी मानव व्यवहार में महत्त्व रहता है। ये वर्तमान कार्यकलापों को प्रभावित करते हैं। वालास के इस विचार में भी अतिशयोक्ति है। यह आवश्यक नहीं है कि सांख्यिकीय इच्छाओं की पूर्ति वर्तमान में ही हो। कभी कभी इच्छाओं का दमन भी करना पड़ता है तभी प्राथमिक समाज की जटिलताओं में मध्य रहा जा सकता है।

वालस न विवेक की महत्ता को स्वीकार नहीं किया है। इतना अवश्य माना जाता है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार रहन चिन्तन अथवा पूर्ण विवेक से प्रेरित नहीं होता किन्तु विवेक के महत्त्व का इतना निम्न मूल्यांकन उचित नहीं लगता।

मनुष्य की मानसिक संरचना में अद्विवादी अनुमानों में भेद स्थापित करना आसान नहीं है किन्तु इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि भविवेकशील तत्वों की मानव व्यवहार व्यापक भूमिका रहती है। यह सम्भव है (फासीवाद-नास्तीवाद के

परिप्रेक्ष्य में यह दृष्टा भी है) कि चालाक राजनीतिज्ञ इन ध्येयतन धनुमानों का स्वयं के स्वायं में प्रयोग करे। यह भी सम्भव है कि इस दिशा में जो प्रक्रिया प्रारम्भ हो वह उस स्थिति तक पहुँच जाय कि उस पर नियन्त्रण रखना असम्भव हो जाय।¹⁹

'राजनीति में मानव स्वभाव' में वालास ने केवल सामान्य राजनीतिक व्यवहार में विवेकहीन तत्त्वों को मान्यता नहीं दी। एक विवेकशील की भाँति उन्होंने राजनीतिक व्यवहार में विवेकशील तत्वों का समर्थन देने की बात कही है तथा इसीलिए राजनीतिक एवं सामाजिक शिक्षा को अधिक क्रियाशील बनाने का सुझाव दिया है। वालास का दृष्टिकोण बेन्थमवादी या जिसके अनुसार राजनीति का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को सुखी बनाना है किन्तु इसको उपलब्धि किस कार्यक्रम से की जाय तथा ऐसे कार्यक्रम और बीसवीं सदी के अनुरूप किस प्रकार का राजनीतिक व्यवहार हो ऐसे विचार प्रस्तुत करने में वालास असमर्थ रहे हैं।²⁰

राजनीति में मानव स्वभाव' तथा महान समाज दोनों मिलकर फेबियनवादी धारणा में उपयोगितावाद की पुनरावृत्ति जिसके अन्तर्गत वे यदभाष्यम् (Laissez-Faire) से हटकर राज्य हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं ताकि सामूहिक साधनों द्वारा सुख की सकारात्मक वृद्धि की जा सके। वालास के विचारों में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक साथ ही राज्यवादी और उदारवादी दोनों ही थे किन्तु उनमें यह कमी थी कि उनमें विलक्षण प्रतिभा एवं बुद्धि होते हुए भी इन विचारों को स्पष्ट और व्यापक नहीं कर सके।²¹

ग्राहम वालास के विचारों को मौलिकता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मानव व्यवहार में अविवेकशील तत्वों के महत्त्व का ग्राहम वालास के पहले भी ग्रहण-कृत हुआ है। वालास का महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने अविवेकपूर्ण तत्वों का राजनीति शास्त्र के अनुभववादी ज्ञान में प्रयोग किया है।

कोल (G D H. Cole) का विचार है कि ग्राहम वालास के विचारों में स्थायित्व नहीं था। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन पर सदैव स्थिर नहीं रह सके। वालास का— Human Nature in Politics, 1908—उनका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ था। जिसमें उच्च श्रेणी के ग्रन्थ के सभी तत्व विद्यमान थे किन्तु जीवन भर वे अपने इन विचारों को न तो पूर्णतः स्पष्ट कर सके और न कोई स्पष्ट दिशा दे सके। एक और ग्रन्थ—The Great Society, 1914—से ऐसा आभास होता था कि उनके विचार स्थिर हो रहे हैं किन्तु यहाँ भी वे इधर-उधर की ही बातों में उलझे प्रतीत हो रहे हैं तथा रचनात्मक विचारों का विकास करने में असफल रहे।²²

ग्राहम वालास ने सर्वप्रथम एक व्यापक रूप में मनोविज्ञान का राजनीति में प्रयोग किया है। किन्तु यह मनोविज्ञान मनोवृत्ति (instinct) पर आधारित है जो

19. Varma, V.P., Political Philosophy, p. 341.

20. Cole, G D H., A History of Socialist Thought, Vol. III, Part I, p. 221.

21. Ibid., p. 222.

22. Cole, G D H., Ibid., pp 221—22.

धन सामायिक नहीं रहा। मनोविज्ञान में मनोवृत्ति शाखा का स्थान धन प्रेरणा (drive) शाखा ने ले लिया है। इसका अतिरिक्त प्रकार्यात्मक मनोविज्ञान (functional Psychology), पशु व्यवहार, अमाधारण व्यवहार तथा फ्रायडवाद के विषय में धन और अधिक अन्वेषण हुआ है। इन सभी शाखाओं में मानव व्यवहार को समझने में सहायता दी है। मनोविज्ञान के इन नए सम्प्रदायों के समझ वालास या मनोवृत्ति मनोविज्ञान पुराना सा लगता है। इस नवीन ज्ञान के आधार पर वालास के राजनीतिक मनोविज्ञान पर पुनर्विचार होना चाहिए।²³

वालास के विचारों में बौद्धिक श्रेष्ठता जैसी कोई बात नहीं थी। वालास की गणना न तो प्रथम श्रेणी के मनोविज्ञानिक या समाजशास्त्रियों में की जा सकती है। उन दार्शनिक श्रेणी में भी नहीं लिया जा सकता। वालास की क विचारों के पीछे जिस विचार सम्प्रदाय का निर्माण भी नहीं हुआ है। किन्तु उन्होंने राजनीति में एक नए विचार का प्रवर्तन कर नई दिशा प्रदान की। विशेषतः उनका दो प्रमुख विचार योगदान को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रथम, राजनीतिक व्यवहार में वास्तविक मानव स्वभाव की भूमिका, तथा द्वितीय, राजनीति में सत्तात्मक विधि अपनाए जाने का समर्थन। 'राजनीति में मानव स्वभाव' राजेश के मतानुसार, इस शाखा में किसी अर्थ द्वारा राजनीतिक विचारों को निरन्तर सर्वाधिक मौलिक तथा महत्वपूर्ण योगदान है। यह ही सच है कि हम यहाँ वालास के विचारों से सहमति व्यक्त न करें कि तु कुल मिला कर हम ग्रन्थ में सत्यता है। हमने एक नये विचार के लिये मार्ग खोला। यह ग्रन्थ उन सभी को पढ़ना चाहिए जो राजनीति में थोड़ा बहुत रूचि रखते हैं।²⁴

विलियम मैकडुगल

William McDougall, 1871-1938

प्रोफेसर विलियम मैकडुगल प्रसिद्ध अर्थज्ञान मनोविज्ञानिक थे। प्रारम्भ में प्रोफेसर मैकडुगल ने केम्ब्रिज, लन्दन और ऑक्सफोर्ड में अध्यापन किया। 1920 से 1927 तक हारवर्ड तथा 1927 से मृत्यु पूर्व तक ब्रिक्सविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। वे परम्परावादी मनोविज्ञान के समर्थक नहीं थे। मनोविज्ञान में मैकडुगल वृत्ति शाखा (instinct branch) तथा सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादकों में से थे। विवेक के विरुद्ध विद्रोह के समर्थकों में मैकडुगल का भी सम्मिलन किया जाता है।

प्रोफेसर मैकडुगल के कई ग्रन्थों में निम्नलिखित प्रमुख हैं —

- 1 An Introduction to Social Psychology, 1908
- 2 The Group Mind, 1920
- 3 Body and Mind, 1912
- 4 Outline of Psychology, 1923

²³ Varma, V P., Political Philosophy, p. 348

²⁴ Rowse, A. L., Introduction to Human Nature in Politics, pp. 1-4

प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि से प्रथम दोनो ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं। इन ग्रन्थों के आधार पर मैकडुगल के विचारों की निम्नलिखित पक्षों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है।

वृत्ति सिद्धान्त (The Instinct Theory)

प्रोफेसर मैकडुगल मनोविज्ञान में वृत्ति सिद्धान्त के एक प्रमुख प्रवर्तक हैं। मैकडुगल की धारणा थी कि मनुष्य में कई स्वाभाविक और वंश-परम्परागत प्रयोजन अथवा प्रेरक तत्व (motives) होते हैं जो मानव अनुभव को प्रेरणा देते हैं। 1908 में अपनी पुस्तक—*An Introduction to Social Psychology*—में मैकडुगल ने इस प्रकार के कुछ प्रेरक तत्वों की एक सूची प्रकाशित की जिन्हें उन्होंने वृत्ति (Instinct) कहा तथा बाद में इनको प्रवृत्ति (propensities) नाम दिया। प्रत्येक प्रवृत्ति किसी भावना (emotion) से सम्बद्ध रहती है। 1921 में इस पुस्तक के चौदहवें संस्करण में मैकडुगल ने सात प्रमुख प्रवृत्तियों तथा उनके साथ सम्बद्ध भावनाओं की सूची प्रस्तुत की जैसे—

1. भय की भावना तथा संघर्ष प्रवृत्ति
2. विरक्ति भावना तथा घृणा प्रवृत्ति
3. आश्चर्य भावना तथा उत्सुकता प्रवृत्ति
4. क्रोध भावना तथा युद्ध प्रवृत्ति
5. पराधीन भावना तथा स्वयं-अवमान प्रवृत्ति
6. वात्सल्य भावना तथा मातृक-पैतृक प्रवृत्ति
7. उल्लास भावना तथा दृढता की प्रवृत्ति

इनके अतिरिक्त मैकडुगल ने और कई छोटी प्रवृत्तियों की सूची दी है। मैकडुगल की यह सूची समय समय पर परिवर्तित होती रही है।

मैकडुगल नैसर्गिक प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार में काफी महत्व देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य तर्क-मगत या विवेकपूर्ण सिद्धान्तों या इच्छाओं से निर्देशित नहीं होता, वह मूलतः प्रवृत्ति प्राणी है। मैकडुगल के शब्दों में—

‘प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की गतिविधियों का संचालन प्रवृत्तियों द्वारा होता है। इनके द्वारा प्रत्येक गतिविधियों के उद्देश्य का निर्धारण तथा संचालन शक्ति प्रदान की जाती है।²⁵

जैसा कि बेटेल ने कहा है कि मैकडुगल का विश्वास था कि समस्त मानव गतिविधियों का आधार मनुष्य की प्रवृत्तियाँ हैं तथा प्रत्येक प्रवृत्ति एक विशेष भावना से जुड़ी हुई है। मानव कार्यकलाप आवेग का परिणाम है; आवेग प्रवृत्तियों तथा आदतों का परिणाम है। इस प्रकार मानव व्यवहार को प्रवृत्तियों द्वारा समझा जा सकता है। इनका अनुभव द्वारा कुछ समोधन हो सकता है।²⁶

25. McDougall W, *An Introduction to Social Psychology*, p. 44

26. Gestell, *History of Political Thought*, p 448.

मैकडुगल मनुष्य की बहुवादी प्रवृत्ति (Pluralistic nature of man) में विश्वास करते हैं। मनुष्य की प्रकृति एकाकी नहीं बहुमुखी होती है। मनुष्य का स्वभाव कई वृत्तियों का समूह है। मनुष्य के परम्पर-सम्बन्धित वृत्तियों में श्रेयता लेता है। वृत्तियों के अभाव में मानव क्रिया असम्भव है। फिर भी ये वृत्तियाँ मनुष्य को स्वयं प्राप्त नहीं होतीं ये उसे विरामदण्ड से प्राप्त होती हैं। मैकडुगल वृत्तियों के अश्रितपरम्परागत होना का समर्थन करते हैं।

सामाजिक मनोविज्ञान (Social psychology)

प्रारम्भ में मैकडुगल समाधारण मनोविज्ञान में रुचि रखते थे किन्तु बाद में वे सामाजिक मनोविज्ञान के एक प्रमुख प्रवक्ता बन गए। इस पक्ष की अभिवृत्ति उनकी पुस्तक—The Group Mind—में मिलती है। मैकडुगल के अनुसार समाज में अन्तर्विवेक (Conscience) का स्थान अथ समूह मस्तिष्क अथवा समूह विचार सिद्धान्त (Theory of Group Mind) न बहरा किया है। समूह मस्तिष्क, मैकडुगल के अनुसार, 'व्यक्तिगत मस्तिष्क' से बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। समाज का जीवन एवं लक्ष्य व्यक्ति से सर्वत्र पृथक् होता है।

मैकडुगल के अनुसार मनुष्य केवल मूल प्रवृत्तियों द्वारा ही नहीं किन्तु सामाजिक वातावरण भी उस पर प्रभाव डालता है। प्रत्येक मनुष्य अपूर्ण है, वह उस बृहद व्यवस्था की एक इकाई है जिसका अभिव्यक्ति मनुष्य के विभिन्न विभिन्न स्तरों में होती है। मनुष्य का चिन्तन और कार्य उस समूह द्वारा निर्धारित होता है जिसका कि वह सदस्य है।

राष्ट्र

मैकडुगल ने अपनी 'समूह मस्तिष्क सम्बन्धी पुस्तक में सामूहिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत एक पृथक् अध्याय में राष्ट्र का विवेचन भी प्रस्तुत किया है। मनोविज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्र, मैकडुगल के अनुसार, एक जाति या जनसंख्या का अर्थ है जिसका स्वयं की भाँसा, मस्तिष्क चरित्र द्वारा इच्छा शक्ति होती है। राष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन होता है। मैकडुगल के विचार से, राष्ट्र का मूल आधार मनोविज्ञानिक है। राष्ट्रियता की भावना ही मनुष्यों को एकतामय में बाँधती है। यह भावना और मनोवृत्ति दोनों ही हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क (Nation mind) में सामान्यतः वे सभी तत्व होते हैं जो व्यक्तिगत मस्तिष्क की विशेषता है किन्तु एक समूह-दृष्टि से राष्ट्र-मस्तिष्क व्यक्ति-मस्तिष्क से श्रेष्ठ होता है।

मैकडुगल मनोविज्ञान को सामाजिक राष्ट्र को समझने की कुंजी मानते हैं। वे व्यक्तिवादी और स्थिर मनोविज्ञान का विरोध करते हैं, वे मनोविज्ञान की गतिशील होने के साथ साथ मानव व्यवहार का शास्त्र मानते हैं। मैकडुगल का विश्वास है कि एक सम्पूर्ण मानव दर्शन में पूर्ण एवं नयी प्रकार के मनुष्यों का अस्तित्व मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इसमें नमस्त्र प्रवृत्तियाँ, छाँदना और विचार की समस्त

मस्तिष्क का निर्माण करते हैं तथा जिसकी क्रिया एवं प्रतिक्रिया आदि सभी का समावेश होना चाहिये। मनोविज्ञान द्वारा समूह जीवन (group life) के सामान्य सिद्धान्तों की खोज कर उन्हें विशिष्ट समूहों के ज्ञान के लिए प्रयोग करना चाहिये 27

व्यवहारवाद

मैकडुगल ने अपने ग्रन्थों में मानव व्यवहार का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। व्यवहार के विषय में मैकडुगल बातावरण तथा प्रवृत्तियों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। उनके विचार से मनुष्य शारीरिक रूप से आवेग द्वारा प्रभावित होता है। आवेग की समाप्ति पर व्यक्ति फिर सामान्य व्यवहार करता है। मनुष्य किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयास करता है किन्तु जैसे ही उद्देश्यों की प्राप्ति होती है मनुष्य के प्रयास समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य का व्यवहार मानसिक क्रियाओं का परिणाम होता है। मानव व्यवहार में पुनरावृत्ति होती है तभी उसके व्यवहार का विवेचन कर समझा जा सकता है।

मैकडुगल ने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। उनके ग्रन्थ पशु या मानव व्यवहार का अवलोकन करने के बाद ही लिखे गए हैं। मैकडुगल के व्यवहार की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने व्यक्तिगत तथा सामूहिक व्यवहार दोनों का ही विश्लेषण किया है। मूल प्रवृत्तियों एवं भावनाओं के आधार पर उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य एक इकाई तथा मनुष्य एक समूह में किस प्रकार का व्यवहार कर सकता है। मैकडुगल का योगदान विशेषतः सामूहिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में है। यद्यपि उस समय ग्राहम वालास तथा मैकडुगल के अध्ययन में व्यवहारवाद की प्रवृत्तियाँ पूर्णतः दृष्टिगोचर होती थीं आगे चल कर राजनीति वैज्ञानिकों ने इस अध्ययन का और विकास किया।

मूल्यांकन

प्रोफेसर विलियम मैकडुगल के विचारों में कोई भी मनोवैज्ञानिक आलोचनाओं की सामग्री की खोज कर सकता है। किन्तु यह पक्ष मनोवैज्ञानिकों से जितना सम्बन्धित है राज-शास्त्रियों से नहीं। मैकडुगल ने मानव वृत्तियों को अत्यधिक महत्त्व दिया है। इससे मानव व्यवहार में अन्य तत्वों की महत्ता को भ्रष्ट करने की गई है। मैकडुगल के समकालीन मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि वृत्तियाँ ही नहीं किन्तु हमारी बुद्धिमत्ता का भी पतृक आधार है।

मैकडुगल द्वारा प्रतिपादित 'समूह मस्तिष्क' का सिद्धान्त भी आलोचना से मुक्त नहीं है। जहाँ तक इस पुस्तक के शीर्षक का प्रश्न है, स्वयं मैकडुगल सदिग्ध हैं। इस पुस्तक में मैकडुगल ने समूह नस्ल, राष्ट्र को अधिक महत्ता प्रदान की है। 'समूह मस्तिष्क' में व्यक्ति की इकाई का विलय करना एक उचित विचार नहीं लगता। यह व्यक्ति और उसकी स्वतन्त्रता का हनन है।

मैंकडुगल का राष्ट्र सम्बन्धी विचार भी सही नहीं है। वे देश तथा राष्ट्र में भेद स्थापित नहीं कर सके। देश सम्बन्धता की प्राचीनता से सम्बद्ध है जब कि राष्ट्र एक पाश्चिमी अवधारणा है। इसी प्रकार उनका 'राष्ट्रीय-भाषा' के विचार में प्रतिपादित एकता, एक उद्देश्य तथा संगठन की प्राप्ति अनम्भव है। मैंकडुगल द्वारा राष्ट्रीय एकता की कल्पना एक सैनिक संगठन में ही उपलब्ध हो सकती है।

मैंकडुगल मूलतः मनोविज्ञान थे तथा उनके सभी ग्रन्थ मनाविज्ञान तथा सामाजिक मनोविज्ञान से सम्बन्धित हैं। उन्होंने कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा जिसे राजनीतिशास्त्र की परिधि में सम्मिलित किया जा सके। ब्राह्म बालास का ग्रन्थ राजनीति और मनोविज्ञान दोनों से सम्बन्धित है किन्तु मैंकडुगल के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। मैंकडुगल का योगदान मानव वृत्ति के सम्बन्ध में नहीं है, उनके कुछ वर्ष पहले ब्राह्म बालास इस विचार को प्रस्तुत कर चुके हैं। किन्तु उनका 'समूह मस्तिष्क' का विवेचन अवश्य ही महत्त्वपूर्ण है जिसकी प्रवहेलना कोई भी राजनीतिक प्रचारक तथा राजशास्त्री नहीं कर सकता।

हेरॉल्ड लासवेल

(Harold Lasswell, 1902—)

सिगमण्ड फ्रायड (Sigmund Freud, 1856-1939) ने मनोविज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। फ्रायड-मनोविज्ञान के आधार पर समाज के पूर्ण अध्ययन के लिये कई सामाजिक-मनोविज्ञानियों ने कार्य किया है। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हेरॉल्ड लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान का राजनीति में प्रयोग किया है। लागवेल का अध्ययन एवं अध्यापन दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का तथा विविधनाओं से पूर्ण रहा है। इन्होंने विश्व के प्रमुख स्थानों जैसे लन्दन, पेरिस, बर्लिन, जेनेवा तथा मास्को (केवल अध्ययन प्रसंग के लिए) आदि में अध्ययन किया। 1927 में लासवेल ने शिकागो में प्रसिद्ध अमरीकी राजशास्त्री चार्ल्स मेरियम के निर्देशन में डॉक्टरेट प्राप्त की। लागवेल को फ्रायड के अनिर्गित व्हाइटहेड, ब्राह्म बालास आदि ने भी प्रभावित किया। इस प्रकार लासवेल पर राजशास्त्रिया, मनोविज्ञानियों तथा समाजशास्त्रियों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। लासवेल के विचारों में इन सभी के शास्त्रों के सम्बन्ध की भूलक मिलती है। लासवेल का अध्यापन कार्य भी विश्व व्यापी रहा है। इन्होंने शिकागो, वाशिंगटन, दल, टोक्यो, चाण्किंग आदि विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा चिली, भारत, नेपाल आदि राज्यों में भी अध्यापन क्षेत्र से सम्बद्ध रहे हैं।

राजनीतिशास्त्र में लासवेल वैज्ञानिक अनुभववादों तथा यथार्थवादों शाखा के प्रमुख प्रवक्ता हैं। उनके इन विचारों का निम्नलिखित पुस्तकों में विवेचन मिलता है—

1. Propaganda Technique in World War, 1927 (विश्व युद्ध में प्रचार तकनीक)

2. Psychopathology and Politics, 1930 (मनोविकार और राजनीति)

3. World Politics and Personal Insecurity, 1935 (विश्व-राजनीति और व्यक्तिगत असुरक्षा)

4. Politics: Who gets What, When, How, 1939 (राजनीति: कौन क्या, कब, वैसे प्राप्त करता है)

5. Power and Society, (शक्ति और समाज)

6. The Analysis of Political Behavior, 1948 (राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण)

7. The Future of Political Science, (राजनीति शास्त्र का भविष्य)

इन पुस्तकों के प्रतिरिक्त लासवेल के विचार कई अन्य सम्पादित पुस्तकों तथा लेखों में प्राप्त होते हैं ।

लासवेल राजनीति में मनोवैज्ञानिक शाखा के प्रमुख समर्थक हैं । इस क्षेत्र में लासवेल ने ग्राहम वालास जैसे विद्वानों द्वारा प्रारम्भ किये गये कार्य का विस्तार किया है । लासवेल मानव स्वभाव में अतन् प्रेरणा तथा आवेग (impulse) के महत्त्व को स्वीकार करते हैं । लासवेल का कहना है कि मनुष्य के राजनीतिक विचार उसके अग्रवट एवं अचेतन भावनाओं के समझे बिना नहीं समझ सकते । व्यक्तिगत प्रभावों का सार्वजनिक कार्यों एवं उद्देश्यों पर अग्रवट ही प्रभाव पड़ता है । मनुष्य का आदिकालीन मनोविज्ञान जाने अनजाने व्यक्ति के कार्य एवं प्रयासों को नियन्त्रित करता है । इस प्रकार ऐसे पक्षों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने से व्यक्ति तथा उसके समूह के राजनीतिक विचार एवं व्यवहार का महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । राजनीति शास्त्र में समाज और मनुष्य के मनोवैज्ञानिक पक्ष जैसे जैसे मान्य एवं स्वीकार होते जायेंगे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक दार्शनिकों का स्थान ग्रहण कर लेंगे । लासवेल के अनुसार अब यह समझने का समय आ गया है कि राजनीतिक समस्याओं का समाधान विवाद या परिचर्या द्वारा नहीं किन्तु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से होगा । वाद-विवाद से सामाजिक समस्याएँ और भी अटिष्ठ हो जाती हैं । राजनीति की समस्या संघर्ष को उतना कम करने की नहीं है जितनी कि उस पर रोकथाम करने की है । लासवेल के विचार से राजनीतिक समस्याओं की पुनः परिभाषा होनी चाहिए । इसे समस्याओं के रोकथाम करने वाली या 'निषेधात्मक राजनीति' (Preventive Politics) कहना अधिक उपयुक्त होगा । वास्तव में अभी तक हमारे चिन्तन को गुमराह तथा मलत मार्ग की ओर से जाया गया है । अब समस्याएँ लोकतन्त्र बनाम तानाशाही या लोकतन्त्र बनाम बुलीतन्त्र की नहीं हैं । हमारी समस्या मानव के सहयोगपूर्ण सम्बन्धों तथा उन दशाओं की सत्यता ग्रहण करने की है । यह केवल मानसिक विश्लेषण या मनोवैज्ञानिक खोजों से ही सम्भव है ।

'मनोविकार एव राजनीति' में लासवेल का विश्वास है कि 'राजनीतिज्ञों के मानसिक विश्लेषण से राजनीति के विभिन्न पक्षों का महत्त्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कुछ राजनीतिज्ञ क्यों अच्छे प्रशासक होते हैं? कुछ राजनीतिज्ञ अनुदार क्यों हैं? कुछ राजनीतिज्ञों में आन्दोलनकारी प्रवृत्ति क्यों होती है? इन सब बातों का अनुमान राजनीतिज्ञों के मानसिक विश्लेषण से लगाया जा सकता है। लासवेल ने राजनीतिज्ञों को तीन श्रेणियों में विभोजित किया है जैसे—प्रशासक (administrators), राजमन्त्र (statesmen) और आन्दोलनकारी (agitators) आदि। लासवेल के अनुसार प्रति प्रेम करने वाले लोग आन्दोलनकारी होते हैं। प्रारम्भिक प्रेम सम्बन्धों में बाधाएँ मानने से ऐसे व्यक्तियों की आन्दोलनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है।²⁸

लासवेल की बहुवर्णित पुस्तक—*Politics—Who gets, What, When, How, 1936*—ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक हलचल सी उत्पन्न कर दी। इस पुस्तक में लासवेल पर ईर्ष्यापन समाजशास्त्र के पचासवाँ दशक में दृष्टिकोण को स्पष्ट धारण दृष्टि-गोचर होती है। राजनीति में लासवेल तीन प्रकार के मूल्यों (Values) का प्रतिपादन करते हैं जैसे भाव (deference), आय (income) और सुरक्षा (Safety) आदि। जो इन मूल्यों का अधिक से अधिक भाग प्राप्त करता है वह विशिष्ट सम्प्राप्ति वर्ग (clite) कहलाता है, बाकी समूह जनता वर्ग में प्राता है। लासवेल राजनीति में प्रभाव (influence) को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व मानते हैं। राजनीति में विभिन्न घटनाओं का कौशल या हुनर (skill), वर्ग (class) और व्यक्तित्व (personality) की सरसता का अन्तर्गत विवेचन कर सकते हैं। मध्ययुगीय यूरोप में विशिष्ट वर्ग संता की हस्तगत करने में इसलिए सफल हुआ क्योंकि वह शक्ति का प्रयोग करने की बला या हुनर में माहिर था उस समय सम्राट अपने सामन्तों की शक्ति दबाने में भी सफल रहे क्योंकि वे राष्ट्रीय राज्य की सही ढंग से स्थापित कर सके थे। औद्योगिक क्रांति आर्थिक कौशल के कारण सम्भव हो सकी। बीसवीं सदी में राजनीति व्यवस्था की सकलता के लिए सत्ता साधनों का प्रयोग किया गया। लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी मूलतः दृष्टिकोणों (attitudes) से सम्बद्ध है। पश्चिमी यूरोप की स्थिति के विषय में राजशास्त्री को बाह्य दृष्टिकोणों (externalised attitudes), सामुदायिक दृष्टिकोणों (community attitudes) तथा उग्र दृष्टिकोणों (militant attitudes) आदि का ध्यान रहना पड़ता है।

लासवेल ने राजनीति के व्यवहार में मनोवैज्ञानिक-विश्लेषणात्मक अध्ययन का प्रयोग किया है। मार्क्सवाद की विवेचन लासवेल ने भी आधारा पर किया है। हिटलर के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ने आधारा पर लासवेल का कहना है सामुदायिक युग में कुलीनवर्ग के स्थान पर अधम प्राय वर्ग का कौशल का उत्थान हुआ है। मार्क्सवादी आन्दोलन इसी वर्ग के उत्थान का परिणाम था। लासवेल के अनुसार

हिटलर निम्न मध्यम वर्ग की निराशा भाव शान्ति के काङ्क्षण ही मता में धरा सका था। हिटलर के यहूदी विरोधी अभियान का-विश्लेषण करते हुए लासवेल ने लिखा है कि यह एक धीरे-यहूदी सर्वहारा वर्ग का विरोध करने तथा दूसरी ओर समृद्ध यहूदियों के विरुद्ध छोटे मोटे जर्मन पूंजीपतियों को धृष्ट को सन्तुष्ट करने का प्रयास था। हिटलर ने प्रार्थित-व्यक्तित्व, जनता के समक्ष उनके व्यक्तित्व की प्रपील तथा जनता में उन्माद पैदा करने की क्षमता को लासवेल उसके उत्कर्ष का कारण मानते हैं।

'विश्व-राजनीति तथा वैयक्तिक-असुरता' में लासवेल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में लासवेल राष्ट्र और वर्गों को स्वयं की अभिव्यक्ति का प्रतीक मानते हैं। राष्ट्रों के स्वाधीनता आन्दोलन साम्राज्यवादी आर्थिक एवं राजनीतिक प्रधिपत्य के विरुद्ध सम्यक्ता को अभिव्यक्ति है। घाघुनिक विश्व में संचार एवं आवागमन की सुविधाओं में वृद्धि के कारण व्यक्तियों के पारस्परिक सम्पर्क में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इससे विश्व एकता के विचार को काफी बल मिला किन्तु आवश्यक यह है कि हिंसा के महत्त्व को कम से कम कर माय ही माय सुरक्षा की भाँग को प्रवर्ध करार किया जाय। लासवेल के अनुसार विश्व में विभिन्न प्रतीकों (symbols) जैसे राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, समाजवाद, विश्व साम्यवाद आदि के मध्य संघर्ष चल रहा है। लासवेल स्वयं लोकतांत्रिक गरिमा तथा समानता का पूर्ण समर्थन करते हैं।

कापलन (M. Kaplan) के सहयोग से लिखी गई पुस्तक 'शक्ति और समाज' में लासवेल ने राजनीति शास्त्र की महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं (Concepts) तथा उनकी त्रियोत्मक परिभाषाओं का विवेचन किया है। इन पुस्तक में राजनीति शास्त्र की व्यवहारवादी सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। लासवेल-केपलन के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक सम्पर्क, उनके कार्य, उनका समूह में विभक्त होना आदि राजनीति शास्त्र की विषय सामग्री है। अभी तक राजनीति शास्त्र का अध्ययन ऐतिहासिक या विधिवादी तथा (संस्थागत, अध्ययन के परिपेक्ष्य में किया गया है। लासवेल ने राजनीति शास्त्र में घटना-संस्थापन (event orientation) का समर्थन किया है। इस पद्धति के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान में 'अल्प-कालीनता' के महत्त्व को मान्यता दी गई है। राजनीति शास्त्र का दीर्घकालीन विश्लेषण नहीं किया जा सकता यह विभिन्न घटनाओं के माध्यम से अल्पकालीन ही हो सकता है। लासवेल के अनुसार व्यक्तियों और उनके समूहों का राजनीतिक व्यवस्थाओं में विभाजन प्रभाव (influence) और 'शक्ति' (power) की ओर अग्रसर करता है। राजनीति शक्ति अर्जन तथा शक्ति को बनाये रखने की तकनीक है। राजनीतिक गतिविधियाँ मुख्यतः 'शक्ति-प्रक्रिया' से सम्बन्धित हैं। शक्ति-राजनीति शास्त्र की मूल भूत प्रवधारणा है।

राजनीति शास्त्र में लामबैल के विचारों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। विवेक के प्रति विद्रोह करने तथा राजनीति शास्त्र को एक नया स्वरूप प्रदान करने में लामबैल की सामरिक भूमिका रही है। लामबैल ने राजनीति शास्त्र में अनुभववादी, मनोवैज्ञानिक-विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति के आधार पर लामबैल न कई व्यक्तियों का साक्षात्कार कर 'मनोविकार और राजनीति' की विषय सामग्री एकत्रित की।

लामबैल राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिकों एक व्यवहारवादी मार्ग के प्रवर्तकों में से एक हैं। वे राजनीतिक प्रक्रिया में यथार्थवादी अध्ययन तथा मानव व्यवहार की गतिशीलता में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का समर्थन करते हैं। 'मनोविकार और राजनीति' के प्रतिरिक्त 'प्रचार तकनीक और विश्व-युद्ध' राजनीतिक प्रक्रिया, प्रमुख व्यक्तियों तथा घटनाओं का मौलिक एवं गहन अध्ययन है। वास्तव में लामबैल के विचारों का महत्व उनकी राजनीतिक प्रक्रिया की अन्तर्दृष्टि के विषय में है। लामबैल का उद्देश्य पूर्व परिचित धार्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान को पुनरावृत्ति करना नहीं है। वे *फ़ंक्शनल* (functional) तथा समस्याओं पर आधारित विवेचन से राजनीति शास्त्र को अनुभववाद के अन्तर्गत लाते हैं। लामबैल आधुनिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई-नई तकनीक के प्रयोग का समर्थन करते हैं। लामबैल के अनुसार राजनीति विज्ञान इतना बृहत् एवं व्यापक विषय है कि इसके अध्ययन के लिए किसी एक पद्धति का प्रयोग अपूर्ण होगा। वे राजनीति शास्त्र की विभिन्न सामग्रियों के लिए विभिन्न पद्धतियों का समर्थन करते हैं। वे केस स्टडी (Case study), फ़ील्ड स्टडी (Field Study), प्रतिबन्धन (Sampling), सहसम्बन्ध (Correlation) आदि का समर्थन करते हैं। उनका विचार है कि राजनीतिशास्त्रियों को 'निर्णय-समीक्षा तकनीक' (Decision Seminar Technique) में प्रशिक्षित करना चाहिए।

विवेक के प्रति विद्रोह का सामान्य मूल्यांकन

विवेक व विद्रोह विद्रोह न यद्यपि मनुष्य और समाज की यथार्थता को समझने में सहायता दी है, विवेक-विद्रोह की आलोचना भी काफी हुई है। सबसे मूल बात यह है कि विवेक विरोधियों ने विवेक के विद्रोह अपने तर्कों को व्यवस्थित करने में विवेक का ही सहारा लिया है। विवेक का विशेष करण बाल विज्ञान के क्षेत्र में विवेक की भूमिका का न्यूनतम मूल्यांकन करते हैं। वास्तव में विज्ञान विवेक पर आधारित है। विवेक की पूर्णता सबसे अधिक विज्ञान में ही दृष्टिगोचर होती है। विवेक के प्रति विद्रोह व्यवस्थित ज्ञान व विद्रोह है। ज्ञान उत्तम और परिष्कृत म मान्य होता है। विवेक के प्रति विद्रोह ज्ञान तथा व्यवस्थित ज्ञान की उपशा है। जब तक कोई विचार विवेक पर आधारित न हो उस पर यकीन नहीं हो सकती। जो विचारधाराएं विवेक विरोध पर आधारित रही हैं उनका अस्वीकार महत्व रहा है, उनमें स्थायित्व का नईव प्रभाव रहा है।

मानव जीवन को एक गलित जैसी सूक्ष्मता में डालना, या उसे केवल प्राणियास्य सम्बन्धी तथ्य समझना, या भौतिकी संरचना मानना मनुष्य की गरिमा और व्यक्तित्व का हनन करना है। मनुष्य के व्यक्तित्व और विवेक का इतना घनादर अधिनायकवादों व्यवस्था के ही मनुकूल हो सकता है।²⁹ एतीने गिलसन (Etienne Gilson) ने दार्शनिक दृष्टिकोण से विवेक के विरुद्ध विद्रोहियों की कटु आलोचना की है। गिलसन का विचार है कि दर्शन-पद्धति का वैज्ञानिक विकल्प मनुष्य को प्राकृतिक आवश्यकताओं के समक्ष आत्म-समर्पण करने का विवश कर देता है। दर्शनशास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा विज्ञान प्रकृति तथा स्वभाव का निर्धारण किया जा सकता है। दार्शनिक ज्ञान का त्याग करने से मनुष्य ने प्रकृति को समझने तथा उसे अपने अधीन रखने का अधिकार छोड़ दिया है। केवल तथ्यों पर आधारित विकल्प उत्तरदायित्वहीन सामाजिक घटनाओं की ओर प्रसरण कर सकता है। यह अधिनायकत्व के आविर्भाव को भी सिद्ध करने में सहायक हो सकती है।³⁰

विवेक के प्रति विद्रोह ने मानव स्वभाव तथा सामाजिक शक्तियों के अध्ययन को पूर्ण एवं वास्तविकता के स्तर पर लाने का प्रयास किया किन्तु इस विचार से मानव समाज की जो हानि हुई अथवा होने की सम्भावना है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। विवेक विरोधियों ने मानव समाज का सही दिशा की ओर निर्देशन नहीं किया है। 'विवेक के प्रति विद्रोह' के कई प्रवर्तकों एवं समर्थकों ने कुछ खतरनाक विचारों को जन्म दिया। पेर्रेटो को फॅमीवाद का जनक माना जाता है। हर्बर्ट स्पेन्सर ने 'सबल के अस्तित्व' (Survival of the fittest) का समर्थन किया। राजनीतिक क्षेत्र में इनमें से कई ने (जैसे लासवैल आदि) शक्ति की प्रमुखता तथा उसे गौरवान्वित किया है। इन विचारों ने मानव जाति की कोई सेवा नहीं की है। इसके द्वारा प्रतिष्ठित तथ्यों को प्रतिष्ठित किया गया है। विवेक के पतन से मानवीय आदर्शों का अग्रमान हुआ है। राष्ट्रीय अहं के नये दर्शन में स्थानीय तथा नरल सम्बन्धी हितों को इतना गौरवान्वित किया है जिससे सामान्य मानवीय जीवन का भी घनादर हुआ है।³¹

विवेक के विद्रोही आदर्शों में विश्वास नहीं करते। किन्तु आदर्शों के आधार के बिना जिन मिद्धान्तों का वे प्रतिपादन करते हैं उनको अंधेरा, बुरा तथा सही या त्रुटिपूर्ण कैसे कहा जा सकता है। मानव समाज किन्हीं आदर्शों को लेकर आगे बढ़ता है। मनुष्य का उद्देश्य 'सदैव यही रहा है (तथा रहना भी चाहिए) कि वह पारम्परिक गृहयोग, प्रेम, सेवा आदि आदर्शों के आधार पर समाज की रचना

29 Hallowell, J H, Main Currents in Modern Political Thought, pp. 522-23.

30 Gilson, E., The Unity of Philosophical Experience, p. 277.

31 Cohen, M. Nature and Reason, p. 4

करे। अद्विवेकवादियों ने इस दिशा की ओर अग्रसर होने में बाधाएं उत्पन्न की हैं। वे मनुष्य को यथार्थता तक ही सीमित रखना चाहते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य तथा उसका समाज पूर्ण नहीं है, उनके प्रारम्भिक सम्बन्धों में अद्विवेक की भी भूमिका रहनी है। सामाजिक सम्बन्धों में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या भावनाएँ आदि भी सामाजिक सम्बन्धों का निर्धारण करती हैं, किन्तु इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर भी एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए इन सभी तत्वों का सामन्जस्य आवश्यक है। यह बसल विवेक से ही सम्भव है।

श्री श्री मुष्ण श्र श्री पाठ्य ग्रन्थ श्री 25 0

1. Cohen, Morris R., Reason and Nature, Chapter 1, The Insurgence Against Reason
2. Gittell, R G., History of Political Thought, Chapter 28 Psychological Influence on Political Thought,
3. Graves H R G Foundations of Political Theory Chapter 5 Reason and Political Purpose
4. Hallowell, J H Main Currents in Modern Political Thought, Chapter-Revolt Against Reason
5. Kilzer and Foss Western Social Thought, Chapter 18, Later European Sociology
6. Lasswell H D Psychopathology and Politics
7. McDougall W, An Introduction to Social Psychology, The Group Mind
8. Varma V P Political Philosophy, Chapter 28, Harold D Lasswell
9. Wallas Graham, Human Nature in Politics

राजनीति-विज्ञान के नवीन आ्याम

लगभग गत बीस वर्षों से राजनीतिशास्त्र के स्वभाव, क्षेत्र तथा अध्ययन पद्धतियों में जो व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनसे इस विषय की काया-पलट हो गई है। राजनीतिशास्त्र नया रूप ग्रहण करता जा रहा है तथा नये आ्याम की ओर अग्रसर हो रहा है। राजनीति शास्त्र में नवीन परिवर्धन आज के विश्व में नवीन परिवर्तनों की ही अभिव्यक्ति है। इनसे राजनीतिशास्त्र के परम्परागत तथा वर्तमान स्वरूप में सुलभता से भेद स्थापित किया जा सकता है।

राजनीतिशास्त्र का परम्परागत स्वरूप

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व तथा कुछ वर्षों उपरान्त राजनीतिशास्त्र पर लिखे गये बहुत से ग्रन्थ, आज की शब्दावली में, परम्परावादी, दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीति शास्त्र के कुछ प्रमुख विद्वान जैसे गार्नर, गैटिल, गिलक्राइस्ट, लीकॉक, ब्लंशली आदि ने इस विषय को जिस प्रकार परिभाषित किया है उनसे परम्परागत दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। परम्परावादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत राजनीति शास्त्र को, प्रथम, संस्थागत अध्ययन माना गया है। राजनीति शास्त्र का अध्ययन राज्य तथा सरकार, जैसी संस्थाओं पर केन्द्रित था। जैसा कि गार्नर ने लिखा है राजनीति विज्ञान का प्रारम्भ और अन्त राज्य से होता है। द्वितीय, राजनीतिक संस्थाओं के विभिन्न अंग, उनकी संरचना, उनके सम्बन्ध, राज्य के विभिन्न तत्त्व, सरकार के विभिन्न स्वरूप आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता था। तृतीय, परम्परागत राजनीतिशास्त्र में कुछ परम्परागत सिद्धान्तों जैसे राज्य की उत्पत्ति तथा विकास के सिद्धान्त, राज्य के स्वभाव के सिद्धान्त, शक्ति प्रयत्नकीकरण का सिद्धान्त आदि को ही सब कुछ समझा जाता था। चतुर्थ, परम्परावादी दृष्टिकोण औपचारिक, ऐतिहासिक, तथा विधिवादी रहा है। विधिवादी दृष्टिकोण का प्रचलन यूरोप तथा मुख्यतः जर्मनी में था, कुछ प्रमुख विचारक जैसे बॉस, बेन्थम, मॉरिस्टन, विलोबी आदि इन विधिवादी वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। परम्परावादी राजनीतिशास्त्र में दार्शनिक तथा आदर्शवादी दृष्टिकोण सदैव विद्यमान रहा है। पूर्वे निश्चित लक्ष्यों एवं मूल्यों जैसे न्याय, स्वतन्त्रता, समानता आदि को स्वीकार किया जाता था। ये ही आदर्श राजनीतिशास्त्र के विवेचन का आधार रहे हैं।

अन्य शब्दों में राजनीति शास्त्र के परम्परावादी अध्ययन में निम्नलिखित पक्षों का अभाव रहा है या घबहेलना की गई, जैसे—

(i) मनुष्य, जो भ्रमस्त गतिविधियों का स्रोत एवं आधार है, को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया ।

(ii) राजनीतिक संस्थाओं के सम्पूर्ण कार्यों का मूल्यांकन का प्रभाव रहा है ।

(iii) राजनीतिक संगठनों के अन्तर्गत आन्तरिक कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के अध्ययन का प्रभाव रहा है ।

(iv) राजनीति शास्त्र में विभिन्न समाजशास्त्री तथा मनोविज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

(v) राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक, अनुभववादी, व्यवहारवादी पद्धतियों और उपागमों को ग्रहण करने की गई ।

(vi) राजनीतिक वातावरण, विभिन्न राजनैतिक शक्तियों, प्रभावों आदि को राजनीतिक अध्ययन में कोई स्थान नहीं था ।

राजनीति विज्ञान का नवीन स्वरूप

आज का युग राजनीति शास्त्र, अन्य समाजशास्त्रों, सामाजिक व्यवस्था तथा मानव मस्तिष्क में शान्ति एवं परिवर्तन का है । परम्परागत मूल्य, तत्त्व तथा सिद्धान्त समयानुकूल नहीं रहे हैं । राजनीति शास्त्र का परम्परागत अध्ययन नवीन प्रवृत्तियों, नवीन विज्ञानों को स्थान छोड़ता जा रहा है । अब राजनैतिक विज्ञान केवल सम्पागत अध्ययन नहीं रहा है । राजनीति शास्त्र में विषय में गान्ध, ब्रह्मली गति आदि के विचार पिछड़े हुए लगने हैं । वर्तमान में राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक दर्शन, शासन प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं कानून आदि को सम्मिलित किया जाता है । राजनीति विज्ञान में अब मनुष्य विभिन्न संगठन, अन्य प्रभावकारी तत्व जैसे शक्ति (power), सत्ता (authority), प्रभाव (influence), नियंत्रण (control) तथा अन्य अनुभववादी, व्यवहारवादी ज्ञान के अध्ययन को महत्त्व दिया जाता है । इसके अन्तर्गत हम उन प्रक्रियाओं का पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा, जैसा कि हेरमन हलर (Herman Heller) ने लिखा है, भौगोलिक, जनवायु सम्बन्धी, जातीय, प्राकृतिक, धार्मिक, सैनिक, नैतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय वातावरण और कानून का अनुसार जन-शक्ति राज्य संस्था का रूप धारण करती है। इन परिवर्तनों का परिणामस्वरूप लामबेल (Harold Lasswell) ने राजविज्ञान का नीति एवं नियम विज्ञान, बेटलिन (G.E.G. Catlin) ने नियंत्रण का अध्ययन, डेविड एस्टन (David Easton) ने 'मूल्या का सत्तात्मक वितरण' कहा है।¹ किंग्सी राइट (Quincy Write) का अनुसार राजविज्ञान निश्चित तथ्यों की प्राप्ति के लिए समूहों को प्रभावित एवं

1 Heller, Herman; Encyclopaedia of Social Sciences, Vol. XIII, p 209

2 Catlin, G E G, Systematic Politics, p 64

नियंत्रण करने का अध्ययन है। राजवैज्ञानिकों के ये विचार राजनीतिशास्त्र के परिवर्तित स्वरूप की अभिव्यक्ति है।

मानव अध्ययन (1)

परम्परावादी अध्ययन का विरोध राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है।³ इस विकास का सबसे व्यापक प्रभाव अध्ययन सामग्री के आधार पर पड़ा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। राजनीतिशास्त्र का परम्परावादी अध्ययन मूलतः सत्यागत रहा है, किन्तु अब इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। अब राजनीति विज्ञान में मनुष्य तथा उसके व्यवहार पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। यह पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य मनुष्यों का ही संगठन है तथा सरकार मानव क्रियाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। इसलिए राजनीति विज्ञान को मानव-अध्ययन के बिना नहीं समझा जा सकता। मनुष्य की मौलिक मान्यताओं द्वारा ही राजविज्ञान का सर्वांगीण स्वरूप निर्धारित किया जाता है।

अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन (Interdiscipline Study) (2)

राजनीति विज्ञान अब मनुष्य के राजनीतिक कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं रहा है। राजनीतिक गतिविधियों से मनुष्य का समग्र जीवन सम्बद्ध है, इस प्रकार उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि पक्षों को एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। व्यवहारवादी अपने अन्वेषण में मनुष्य के बहुपक्षीय व्यवहार को सम्मिलित करता है। चूँकि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान मनुष्य के कार्यकलापों के किसी विशेष पक्ष को लेकर विकसित हुआ है, मानव स्वभाव तथा उसके विविध कार्यकलापों का अध्ययन विभिन्न विज्ञानों में बिखरा हुआ है, इसलिए राजनीतिक अध्ययन के लिए विभिन्न शास्त्रों जैसे, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के अध्ययन एवं पद्धतियों का समावेश करना अति आवश्यक हो गया है। वास्तव में राजनीति का अध्ययन कई ज्ञान-शास्त्रों के अध्ययन का संगम है। राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन में समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों की भी वही भूमिका है जो परम्परागत राजनीतिशास्त्रियों की रही है।⁴ इस दृष्टि से राजविज्ञान एक अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन हो गया है।

शक्ति एवं राजनीति (3) राजनीति विज्ञान में एक नवीन 'शक्ति सम्प्रदाय' जिसे 'यथार्थवादी सम्प्रदाय' (Realist School) भी कहा जाता है, शक्ति को अधिक महत्त्व देता है। इस शक्ति शाखा के प्रमुख समर्थक हेन्स मोरगेन्थो, हेरॉल्ड लासवेल आदि हैं।⁵ मोरगेन्थो ने राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है।⁵ लासवेल के अनुसार राजनीति

3. Kirkpatrick, Evron; The Impact of 'Behavioural Approach' on Traditional Political science, p. 57.
 4. Hyman, Herbert H., Political Socialization, p. 7.
 5. Easton, David; The Political System, p. 12.
 6. Lasswell, H., Politics, p. 12.
 7. Easton, D. C., System of Political Science, p. 12.
 8. Morgenthau, Hans, Politics Among Nations, p. 12.

प्रभाव और प्रभावशील का अध्ययन है।⁶ लासवेल का मुख्य विचार शक्ति के वितरण का है। शक्ति का वितरण असमान है अतः मूल्य तथा मूल्यवान् वस्तुओं की प्राप्ति सबको एक सी, एक समय तथा एक प्रकार से नहीं होती। इस प्रकार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह यह स्पष्ट कर सके कि “कौन क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है।” लासवेल की पुस्तक—Who Gets What, When, How 1936—शक्ति वितरण की ही व्याख्या है। 1962 में केटलिन द्वारा प्रकाशित सशोधित ग्रन्थ Systematic Politics—में शक्ति एवं नियन्त्रण (Control) को राजनीतिक कार्यकलापों का एक प्रमुख पक्ष मानते हैं। मोरगेन्थो की भाँति केटलिन ने राजनीति को प्रमुख एवं नियन्त्रण के लिए मध्यम की सजा दी है।⁷

कुछ राजनीति वैज्ञानिकों का कहना है कि शक्ति इतनी व्यापक अवधारणा है कि यह राजनीति विज्ञान की समुचित पद्धतियों के विस्तार में राधा बनेगी। केटलिन तथा लासवेल ने शक्ति अवधारणा की इतनी व्यापक व्याख्या की है कि समस्त मानव कार्यकलाप राजनीतिशास्त्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। पारिवारिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, चर्च के कार्य यहाँ तक कि डाकुओं की गतिविधियाँ किसी न किसी रूप में शक्ति एवं प्रभाव की अभिव्यक्ति हैं। इस स्थिति में राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक कार्यों में भेद करना असम्भव हो जायेगा।

डेविड ईस्टन ने केटलिन तथा लासवेल की शक्ति अवधारणा में कुछ सुधार कर उसे नीति, मत्ता और समाज (Policy, Authority and Society) के अन्तर्गत विवेचन किया है।⁸ डेविड ईस्टन अपने इस प्रयास में पूर्ण सफल नहीं हो सके, किन्तु यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि शक्ति के इन समर्थकों द्वारा शक्ति की धारणा राजनीतिशास्त्र में अब उतनी घृणित या निन्दनीय नहीं है जितनी कि मेकियावेलो तथा हॉब्स के विचारों की प्रतिक्रिया से प्रतीत होता है।

गैर-राजनीतिक तत्व (Non-Political elements)

वर्तमान राजनीति विज्ञान केवल राजनीतिक तत्वों से ही सम्बन्धित नहीं है, इसके अन्तर्गत गैर राजनीतिक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। जब किसी संस्था द्वारा कोई राजनीतिक निर्णय लिया जाता है उस पर कई गैर-राजनीतिक कारकों, संस्थाओं का प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत संस्थाएँ, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, धार्मिक संस्थाएँ, दबाव गुरु आदि गैर-राजनीतिक संस्थाएँ राजनीतिक प्रक्रिया पर प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में इन गैर-राजनीतिक प्रभावों के अध्ययन की अवहेलना नहीं की जा सकती। रॉबर्ट हाहल (Robert

6 Lasswell, H, Politics, Who Gets What, When, How, p 13

7 Catlin, G E G, Systematic Politics, p XIII

8 Easton, David, The Political System, pp 123-129

A. Dahl) ने लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत मानवीय सम्बन्धों के समस्त स्वरूप या जाते हैं जिनमें किसी भी मायामें 'शक्ति, नियम और मत्ता' रहते हैं।⁹

नवीन अध्ययन पद्धतियों का समावेश

अभी तक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बड़ा सीमित रहा है, परिणामस्वरूप इस ज्ञान-शाखा की अध्ययन पद्धतियों का समुचित विकास नहीं हो सका था। इसी प्रकार अध्ययन पद्धतियों का क्षेत्र भी सीमित रहा है। वर्तमान में राजविज्ञान की पद्धतियाँ राज्य तथा राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित नहीं हैं, इसके अन्तर्गत मनुष्य के व्यवहार, राजनीतिक संगठन, समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन, तथा राजनीति के विभिन्न तत्त्वों में सम्बन्ध स्थापित करने वाली शक्तियों के अध्ययन के लिए नवीन पद्धतियों को विकसित किया जा रहा है। मानव व्यवहार पर आधारित व्यवहारवादी मार्ग, निर्णय निर्माण सिद्धान्त, संरचना (Structure) तथा व्यवस्था (System) के सिद्धान्तों का सामान्यीकरण (generalisation), मॉडल निर्माण (Model building), समस्या समाधान (Problem-Solving) प्रक्रिया आदि का राजनीति विज्ञान में समावेश हुआ है। राजनीति वैज्ञानिकों ने अब नियन्त्रित प्रयोग (Controlled experimentation) की दिशा में भी प्रगति की है जिसके अन्तर्गत नेतृत्व, व्यवहार, प्रचार, अफवाहें आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। कुछ प्रसिद्ध विद्वानों जैसे ग्राहम बालास, चार्ल्स मेरियम (Charles Merriam), लासवैल, स्नाइडर (R. Snyder) केटलिन, डेविड ईस्टन (David Easton), मॉर्टन कापलन (Morton A. Kaplan), कार्ल टॉयस (Karl W. Deutsch), जेम्स रॉसनो (James N. Rosenau), रॉबर्ट डहल (Robert Dahl) आदि के प्रयासों से राजनीति विज्ञान में नवीन पद्धतियों, सिद्धान्तों तथा अध्ययन मार्गों का समावेश हुआ है। फलस्वरूप राजनीति विज्ञान की विषय सामग्री के संकलन, विश्लेषण, उसे व्यवस्थित करने तथा विश्वसनीय बनाने के प्रयत्नों ने इस ज्ञान शाखा को और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में योगदान दिया है।

राजनीतिशास्त्रियों के लिए राजनीति में निश्चितता तथा सामान्यीकरण का वापस आना नहीं। प्रत्येक राजनीतिक स्थिति में मानव व्यक्तित्व सम्बन्धित है; मानव व्यवहार की जटिलता तथा निरन्तर परिवर्तित सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धों के कारण वे राजनीति विज्ञान में कोई भी निष्कर्ष निश्चितता तथा अन्तिम रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते। फिर भी इन कारणों से वे अपने प्रयासों को रोक नहीं देते। वे राजनीति शास्त्र में अंकशास्त्र, गुणज्ञान, मनोविज्ञान के कुछ उपकरण (tools) और तकनीक का प्रयोग कर इस विषय को और अधिक वैज्ञानिक रूप देना चाहते हैं। आजकल राजनीति विज्ञान में नई दिशा की ओर प्रस्थान का यहाँ आधार एवं विचार है।

⁹ Dahl, Robert A., *Modern Political Analysis*, p. 6.

व्यवहारवादी अध्ययन-मार्ग

Behavioural Approach

मार्ग अथवा उपागम (approach) राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है। इसके माध्यम से विषय सामग्री को व्यवस्थित तथा विवेचन कर कुछ निष्कर्षों तक पहुँचा जाता है। जब किसी अध्ययन-मार्ग द्वारा निश्चित निष्कर्षों की प्राप्ति होती रहती है तब ये निष्कर्ष सिद्धान्त बन जाते हैं। वर्तमान राजनीति विज्ञान में विभिन्न अध्ययन मार्गों का विकास हुआ है तथा होता जा रहा है। इनमें व्यवहारवादी अध्ययन-मार्ग, निर्णय निर्माण अध्ययन-मार्ग, संचार अध्ययन-मार्ग आदि प्रमुख हैं। व्यवहारवादी अध्ययन-मार्ग (Behavioural Approach) राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास माना जाता है। यहाँ तक कि इसे एक ग्रान्दोलन तथा श्रान्ति की सज्ञा दी गई है।

व्यवहारवादी शब्दावली—एक समस्या

सर्वप्रथम व्यवहारवादी अध्ययन-मार्ग से सम्बन्धित शब्दावली को स्पष्ट करना आवश्यक है। व्यवहारवादी अध्ययन के नामकरण के विषय में मतभेद रहे हैं। डेविड ईस्टन (David Easton) ने इस समस्या की व्याख्या की है।¹⁰ इस अध्ययन के लिए व्यवहारवाद (Behaviourism) तथा व्यवहारात्मक (Behaviouristic) शब्दों के प्रयोग का सुभाव रहा है किन्तु ये सुभावाधिकार व्यवहारवादियों को मान्य नहीं हैं। व्यवहारवाद का प्रादुर्भाव मनोविज्ञान की एक पद्धति एवं शाखा के रूप में हुआ। इसका विकास जॉन वाटसन (John B Watson) ने सर्वप्रथम 1913 में किया। वाटसन का कहना था कि मनोविज्ञान की आत्मनिरीक्षण को अपेक्षा पर्यवेक्षण योग्य बाह्य कार्यों और व्यवहार से सम्बद्ध रहना चाहिए। मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की भाँति वैज्ञानिक पद्धतियों से किया जाय। इस आधार पर वाटसन ने प्रेरक-प्रतिक्रिया सिद्धान्त (Stimulus-Response अथवा S-R) को विकसित किया। मनोविज्ञान की इस पद्धति का प्रभाव इस शताब्दी के द्वितीय तथा तृतीय दशकों में रहा। राजनीतिक व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन के लिए 'व्यवहारवाद' शीर्षक को उपयुक्त नहीं समझा है। इसके अतिरिक्त 'व्यवहारात्मक' शीर्षक को भी मान्यता नहीं दी गई। उनके अनुसार Behaviouralism अथवा Behavioural Approach शब्द ही इस अध्ययन के लिये उपयुक्त होंगे।

व्यवहारवादी अध्ययन-मार्ग का विकास

व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग, का प्रारम्भ अमेरिका से हुआ। यद्यपि इसका व्यापक प्रचलन द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त हुआ किन्तु व्यवहारवादी अध्ययन की प्रवृत्तियाँ इन जनान्वी के प्रारम्भ से ही देखी जा सकती हैं। इग्लैंड में ग्राहम वानास

¹⁰ See Easton, David, The Current Meaning of Behavioralism, CPA, pp 12-14.

की प्रसिद्ध पुस्तक—Human Nature in Politics (1908) को व्यवहारवादी अध्ययन का प्रारम्भ माना जा सकता है। वालास ने राजनीतिक गति-विधियों में मनुष्य के (न कि संस्थाओं के) मनोवैज्ञानिक तथा मानव समूह के सामाजिक मनो-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन का समर्थन किया। किन्तु 1908 में ही अमेरिका में आर्थर बेन्टले ने व्यवहारवादी अध्ययन के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

आर्थर बेन्टले (Arthur F. Bentley)

आर्थर बेन्टले अमेरिका में कोलम्बिया विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर थे। यद्यपि इन्हें राजनीतिक चिन्तक की श्रेणी में नहीं लिया जाता किन्तु इनके विचारों के कारण इन्हें व्यवहारवादी अध्ययन के एक प्रमुख प्रेरक के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1908 में प्रकाशित पुस्तक—The Process of Government—में बेन्टले ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उनकी यह पुस्तक सक्रिय व्यक्ति तथा सक्रिय समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है।

बेन्टले के विचारों का आधार समूह (group) उनके हित तथा उनकी क्रियाओं का विवेचन है। बेन्टले ने समूह शब्द का प्रयोग विशेष भावार्थ में किया है। उनके अनुसार समूह समाज का वह भाग है जो अन्य समूहों से भौतिक रूप से नहीं किन्तु क्रिया के आधार पर भिन्न होता है। समूहों का स्वयं का हित तथा कार्य करने की प्रक्रिया होती है। बेन्टले ने सरकार, सरकार के विभिन्न भंग, राजनीतिक दल आदि को समूह के अन्तर्गत लिया है। इसी आधार पर बेन्टले ने समूह-हित (group interests) सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार बेन्टले का कहना है कि एक समूह में कई व्यक्ति कार्य करते हैं जिनका उद्देश्य कुछ हितों की प्राप्ति करना होता है। बेन्टले के विचारों में समूह क्रियाओं (group activities) का महत्वपूर्ण स्थान है। बेन्टले का मत है कि किसी समाज का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम समाज के अन्तर्गत विभिन्न समूहों का अध्ययन आवश्यक है। यही बात राजनीति के विषय में सत्य है। राजनीति का अध्ययन करने के लिए उन वर्गों तथा समूहों, जिनका राजनीति से सम्बन्ध है, का वर्गीकरण तथा विवेचन आवश्यक है।

आर्थर बेन्टले ने सरकार की क्रियात्मक व्याख्या की है। उनके अनुसार सरकार विभिन्न पद या पदाधिकारियों की रचना तथा उनका केवल योगमात्र नहीं है। सरकार क्रियाओं का योग है। सरकार तथा उसके अन्तर्गत किसी पदाधिकारी की शक्ति उसकी क्रिया से निर्धारित होती है न कि संविधान में दिये गये अधिकारों से। बेन्टले ने सरकार की कार्य-प्रणाली प्रयत्न प्रक्रिया को दबाव, संपर्क, बमनस्य आदि से सम्बन्धित किया है। शासन प्रक्रिया में समूह हितों का निर्माण होता रहता है जहाँ सीदेबाजी, संपर्क, दबाव किसी न किसी रूप में चलता रहता है।

सरकार की भांति ही बेन्टले ने कानून की व्याख्या की है। बेन्टले के अनुसार विधि निर्माण एक सामूहिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न समूह अपने हितों

की उपलब्धि के लिए दबाव डालते हैं। अन्तिम रूप में कानून विभिन्न समूहों के हितों के समन्वय या व्यवस्था का रूप ग्रहण करता है। इसी प्रकार लोकमत (Public Opinion) को वेन्टले ने समूह प्रक्रिया माना है। लोकमत एक या कई समूहों की क्रिया एवं हितों की अभिव्यक्ति होता है।

चार्ल्स मेरिएम (Charles E. Merriam)

अमरीकी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में चार्ल्स मेरिएम की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हें व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग का बौद्धिक जनक माना जाता है। मेरिएम शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनके नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन गया। प्रागे चलकर व्यवहारवादी अध्ययन के प्रमुख प्रवक्ता हेराल्ड लासवैल, डेविड ट्रूमेन, हरबर्ट साइमन, प्रेवील एलमॉन्ड आदि मेरिएम के अनुयायी तथा विद्यार्थी थे। इन सभी के व्यवहारवादी, यथार्थवादी तथा शक्ति-समर्पित विचारों को सामूहिक रूप से शिकागो सम्प्रदाय (Chicago School) का नाम दिया गया है।

1921 में चार्ल्स मेरिएम ने एक लेख—The Present State of the Study of Political Science—में समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगोल, प्राणिशास्त्र तथा अकशास्त्र में उपलब्धियों और पद्धतियों की घोर ध्यान आकर्षित किया। 1923 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइन्स एसोसिएशन ने मेरिएम की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसका उद्देश्य राजनीति शास्त्र के विभिन्न पक्षों का विवेचन कर उसके अध्ययन के विषय में प्रतिवेदन तैयार करना था। इस समिति की रिपोर्ट में मेरिएम ने राजनीति में मनोविज्ञान के प्रयोग का समर्थन किया। इसके प्रतिरिक्त मेरिएम ने राजनीति के अध्ययन में सध्य एवं सामग्री संकलन तथा उनके परिभाषण की प्रवृत्ति का अनुमोदन किया। 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से सम्बोधित करते हुए मेरिएम ने कहा—

“किसी दिन हम औपचारिक पद्धति के स्थान पर, अन्य विज्ञान की भांति, एक दूसरे ही अध्ययन मार्ग को ग्रहण कर सकते हैं तथा राजनीतिक व्यवहार को अनुसन्धान के एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार करने लगेंगे।”¹¹

1925 में ही मेरिएम की बहुचर्चित पुस्तक—New Aspects of Politics—का प्रकाशन हुआ जिसमें मेरिएम ने राजनीति में मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के विस्तार का समर्थन किया है। इस पुस्तक में मेरिएम ने राजनीतिक व्यवहार की विशेषताओं, उद्देश्यों, पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं की प्रारम्भिक व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार मेरिएम ने राजनीतिक अध्ययन में व्यवहारवादी मार्ग का प्रवर्तन किया। सूक्ष्म में, मेरिएम ने राजनीति विज्ञान में, प्रथम, राजनीतिक प्रक्रिया पर मनोवैज्ञानिक

प्रभाव; द्वितीय, राजनीति विज्ञान में अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन, तृतीय राजनीतिक अध्ययन में तथ्यात्मक परिमाण का प्रबल समर्थन किया। चार्ल्स मेरिएम के कार्य को हेरॉल्ड लासवेल ने पुनः विवेचन कर और आगे बढ़ाया।

चार्ल्स मेरिएम के समकालीन प्रोफेसर केटलिन (G. E. G. Catlin) के अध्ययन में भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण मिलता है। उनकी पुस्तको—The Science and Methods of Politics, 1927, तथा A Study of the Principles of Politics, 1930, ने राजनीति में व्यवहारवादी प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। केटलिन ने शक्ति को राजनीति का मूल तथा आधार कहा है। इस विचार को हेरॉल्ड लासवेल ने एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है जो शिकागो सम्प्रदाय का एक मुख्य विचार बन गया। लासवेल ने अपने कई ग्रन्थों में व्यवहारवादी मार्ग के अनेक पक्षों जैसे राजनीति विज्ञान पर मनोविज्ञान का प्रभाव, समस्त व्यवहारवादी विज्ञानों की एकता आदि का विवेचन किया है।

सकारात्मक दृष्टि से व्यवहारवादी अध्ययन को अमरीकी विचार प्रवाह से सम्बद्ध किया जाता है। अमेरिका में इस अध्ययन मार्ग का विकास वहाँ की परम्परा तथा वातावरण में निहित है। अमरीकी संस्कृति अनुभववादी तथा प्रयोगवादी विचारों से सम्बद्ध है। अमरीकी विद्वानों में तथ्यों के सकलन तथा उनके परिमाणीकरण के प्रति रुचि रही है। अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन का विकास इसी प्रवृत्ति से प्रारम्भ हुआ, किन्तु इसके विकास के और भी अन्य कारण हैं। लगभग 1930 के उपरान्त अनेको यूरोपीय विद्वानों ने अमेरिका में शरण ली। इनमें से बहुत से विद्वान अमरीकी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र विभागों में उच्च पदों पर आसीन हुए। इन विद्वानों ने अमरीकी विश्वविद्यालयों में यूरोपीय प्रभाव का प्रसार किया। इन्होंने राजनीति में समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के प्रयोग पर जोर दिया। इन्होंने मार्क्स, डर्कहीम, फाइट, वेबर आदि की ओर ध्यान आकर्षित किया। इस प्रभाव ने व्यवहारवादी अध्ययन को काफी योगदान दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध से व्यवहारवादी अध्ययन को और प्रोत्साहन मिला। राजनीतिशास्त्र के बहुत से विद्वानोंने अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आकर—दिन प्रति दिन—की यथायंता को समझने का प्रयत्न किया। युद्ध स्थिति से उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिये परम्परावादी साधन अपूर्ण, एवं असामयिक प्रतीत होने लगे।—उनके अनुसार परम्परावादी अध्ययन में वास्तविकता को समझने तथा अविष्य के विषय में कुछ निर्देश देने की क्षमता नहीं है। उन्होंने यथायंता—तथा अनुभव के आधार पर राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का सुभाव दिया।

व्यवहारवादी अध्ययन की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान अमरीकी सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् ने दिया। यह परिषद् अनुसन्धान का क्षेत्र केवल

पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। इसने यथार्थवादी, वैज्ञानिक, और व्यवहारवादी अध्ययन का समर्थन किया। 1945 में इस परिपद के तत्वावधान में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए एक समिति की स्थापना की गई। इस समिति में गौटिया आदि आयोजित की तथा अपने प्रतिवेदनो में व्यवहारवादी अध्ययन पर व्यापक जोर दिया। चूंकि समय-समय पर इस समिति से हेरिंग (E. Pendleton Herring), की (V O Key), डेविड ट्रुमैन (David Truman) आदि जैसे प्रसिद्ध विद्वान सम्बद्ध रहे, इससे व्यवहारवादी अध्ययन को और अधिक प्रोत्साहन मिला।

व्यवहारवादी अध्ययन को प्रोत्साहन देने में कुछ अमरीकी सत्ताओं जैसे रॉकरवेलर प्रतिष्ठान, फोर्ड प्रतिष्ठान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सत्ताओं के तत्वावधान में व्यवहारवादी अध्ययन के लिए समितियाँ गठित की गईं तथा इन्हें धन की सहायता दी गयी। इनके अन्तर्गत कई व्यवहारवादी प्रोजेक्ट्स प्रारम्भ किये गये। इन कार्यक्रमों से लगभग सभी प्रसिद्ध अमरीकी विद्वान सम्बद्ध रहे हैं।

राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी अध्ययन की एक पद्धति—सर्वेक्षण पद्धति (Survey Method) पहले से ही प्रचलन में थी। इस पद्धति के माध्यम से मतदाताओं के व्यवहार का पता लगाया जाता है। इस पद्धति ने मानव स्वभाव तथा व्यवहार को समझने में बड़ी सहायता दी। मतदाताओं के सर्वेक्षण से राजनीति वैज्ञानिकों को व्यवहारवादी मार्ग की ओर प्रस्थान करने का आधार मिल गया। इस समय सर्वेक्षण पद्धति व्यवहारवादी अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग का अर्थ—

व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग की पूर्ण व्याख्या करना सम्भव है। जैसा कि डाहल ने लिखा है इससे सम्बन्धित स्वयं शब्दावली ही स्पष्ट नहीं है। जबसे व्यवहारवादी मार्ग के विषय में विचार शक्त होना प्रारम्भ हुआ है तभी से इस सम्बन्ध में अमूर्त तथा परस्पर विरोधी विचार सामने आये हैं।¹² इससे अतिरिक्त विभिन्न समर्थकों ने इसे प्रवृत्ति या दृष्टिकोण या प्रक्रिया के रूप में देखा है। डाहल ने व्यवहारवादी अध्ययन को एक मनोभाव (mood) की संज्ञा दी है। कर्कपेट्रिक ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में अभिविन्यास (Orientation) के रूप में स्वीकार किया है। राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन के विकास के प्रारम्भिक चरण में इसे परम्परावाद के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट (protest) माना जाता था। उस समय यही इसका स्वरूप और यही इसकी परिभाषा थी। जैसा कि कर्कपेट्रिक (Evrom Kirkpatrick) ने लिखा है कि राजनीति में व्यवहार-

¹² Dahl, Robert A. The Behavioural Approach in Political Science, Changing Perspective in Contemporary Political Analysis, ed by Ball and Lauth, p 108

झाद एक उस छनछामा की भाति पा जिसने उन सभी गुटों को शरण दी जो राजनीति में परम्परावादी अध्ययन से असन्तुष्ट हो एकत्र हो गये थे।¹³ किन्तु जैसे यह अध्ययन गति पकड़ता गया इसको परिभाषित करने के भी प्रयत्न किये गये। 1944-45—में अमरीकी सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद् के वार्षिक प्रतिवेदन में राजनीति में व्यवहारवादी मार्ग की निम्नलिखित व्याख्या की गई थी—

“राजनीतिक परिस्थितियों के व्यवहार पर केन्द्रित यह मार्ग मनुष्यों के नागरिक, प्रशासक और विधायक के रूप में राजनीतिक सम्बन्धों का उन अध्ययन शास्त्रों द्वारा परीक्षण का सुभाव देता है जो इससे सम्बन्धित समस्याओं पर प्रकाश डाल सकें ताकि विभिन्न संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार से सम्बन्धित एकरूपता का निरूपण (निर्माण) और परिकल्पनाओं (hypothesis) का परीक्षण किया जा सके।”¹⁴

एल्मोंड एवं पॉवेल ने व्यवहारवादी अध्ययन की परिभाषा करते हुए लिखा ¹⁵

“साधारणतः इसका अर्थ राजनीतिक भूमिकाओं का निर्वाह करने वालों के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन से है न कि वैधानिक नियम अथवा विचारधाराओं की व्यवस्थाओं से। इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि यह विधि-विधान, विचारधाराओं तथा औपचारिक संस्थाओं का अनादर करता है किन्तु इसका सम्बन्ध उनसे है जो राजनीतिक कार्यों को प्रभावित या उनकी अभिव्यक्ति करते हैं।”¹⁵

व्यवहारवादी अध्ययन के समर्थक अपनी सीमाओं, क्षेत्र की नवीन परिधियों तथा अनुभव के आधार पर इसकी संशोधित एवं व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अब वे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार के बाह्य कार्यों, अच्युत कार्यों, बोधात्मक, प्रेरणात्मक, आदर्शात्मक पक्षों, मनुष्य का सांस्कृतिक एवं सामाजिक अध्ययन सब कुछ सम्मिलित करते लगे हैं। अन्य शब्दों से व्यवहारवादी विश्लेषण के अन्तर्गत मनुष्य के वे सभी पक्ष आ जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यवेक्षण किया जा सके या अन्य सामग्री अथवा विश्लेषण द्वारा निष्कर्ष प्राप्त करने में योग दे सकें।

व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग की प्रमुख विशेषताएँ

राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन पर काफी साहित्य लिखा गया है। इससे स्पष्ट है कि इस मार्ग के सभी समर्थक कई पक्षों पर एक मत नहीं हैं। किन्तु कई विद्वान जैसे रॉबर्ट डाहल, डेविड ईस्टन, कर्कपेट्रिक आदि ने व्यवहारवादी अध्ययन

13. Kirkpatrick, Evron; The Impact of Behavioural Approach on the Traditional Political Science, Ball and Lauth, p. 77.

14. Quoted, Dahl, Robert A., opp., cit., p. III.

15. Almond, G.A., and Powell, B.G., Comparative Politics, A Developmental Approach, p. 7.

मार्गों की कुछ विशेषताओं को प्रस्तुत किया है। सामान्यतः व्यवहारवादी अध्ययन के निम्नलिखित पक्षों को प्रस्तुत किया जा सकता है। 716-2017-18 716-2017-18

(i) व्यवहारवादी अध्ययन राजनीतिशास्त्र में परम्परावादी दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह है। यह यथा-स्थिति का विरोध करता है। व्यवहारवादी परम्परागत औपचारिकता के स्थान पर अनुभववादी यथार्थवादी अध्ययन के समर्थक हैं। इसके माध्यम से ही राजनीति तथा राजनीति से सम्बद्ध पक्षों जैसे सामाजिक वर्ग, संस्कृति, धार्मिक परिवर्तन आदि के विषय में गहन एवं गतिशील अध्ययन किया जा सकता है। जैसा कि एल्मंड एव पावेल ने लिखा है कि अनुभववाद, यथार्थवाद के अन्तर्गत राजनीतिविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वही व्यवहारवादी अध्ययन है।¹⁶

(ii) व्यवहारवादी मार्ग राजनीतिक स्थिति में व्यक्ति और उनके समूहों में व्यवहार को सैद्धान्तिक और अनुभववादी विवेचन को एक इकाई अथवा उद्देश्य रूप में स्पष्ट करता है किन्तु यह मानव व्यवहार को केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व स्तर तक ही सीमित नहीं रखता बल्कि सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक स्तर तक सम्बन्धित है।

(iii) व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में अन्तर्जास्त्रीय मार्ग है। इसके अन्तर्गत विभिन्न समाजशास्त्रों को व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। राजनीति विज्ञान तथा अन्य समाज विज्ञानों की एकता पर जोर दिया जाता है। यह राजनीति सिद्धान्त तथा अन्वेषण को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा मानव-शास्त्र की सामान्य संरचना के अन्तर्गत लाना चाहता है। यह अन्तर्जास्त्रीय पक्ष एक आवश्यक परिणाम है जो व्यवहार को विवेचन की एक मुख्य इकाई के रूप में स्वीकार करता है।

(iv) व्यवहारवादी मार्ग राजनीति में अन्वेषण का प्रयोग एवं विकास, सामग्री आदि का पर्यवेक्षण, वर्गीकरण, मापन, तकनीक का प्रयोग तथा जहाँ सम्भव हो वहाँ प्रकृतिशास्त्र तथा गणित के नियमों के प्रयोग का समर्थन करता है।¹⁷

(v) व्यवहारवादी अध्ययन राजनीतिशास्त्र को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का प्रयास है। सभी व्यवहारवादी समर्थक इस पक्ष पर सहमत हैं कि उनका अध्ययन मार्ग प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियाँ का उत्पत्ति पर आधारित बहुत कुछ वैज्ञानिक बन सकता है। व्यवहारवादी प्रयोगों में राजनीतिक अध्ययन वैज्ञानिक परिपक्वता (scientific maturity) की ओर प्रगम हो रहा है किन्तु यह प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। व्यवहारवादी इस दिशा में अभी माध्यम प्रक्रिया में हैं।¹⁸

¹⁶ Almond, G A, and Powell, B G, Comparative Politics, A Developmental Approach, p 7

¹⁷ Glendon, P k, Studies in Contemporary Political Theory, pp 7-8

¹⁸ Lyson, David, The Current Meaning of Behaviouralism, CPA, pp 17-18.

(vi) व्यवहारवादी अध्ययन का उद्देश्य राजनीति विज्ञान में व्यवस्थित और अनुभववादी सिद्धान्तों का निर्माण करना है। जैसा कि यूलाउ (Heinz, Eulau) ने लिखा है यह राजनीति अध्ययन में सिद्धान्तीकरण करने की क्रिया है। कर्कपेट्रिक (Evron Kirkpatrick) ने इस पक्ष का विस्तार करते हुए लिखा है कि व्यवहारवादी अध्ययन सैद्धान्तिक निरूपण तथा परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं के विकास पर आधारित होना चाहिए। व्यवहारवादी अन्वेषण, पद्धतियाँ तथा तकनीक का ऐसी सतर्कता से विकास करना चाहिए ताकि सामान्य अवधारणाओं की संरचना के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को समझा जा सके।¹⁹

डेविड ईस्टन (David Easton) ने लिखा है कि व्यवहारवादी मार्ग के एक प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तकों एवं लेखों में व्यवहारवाद की शब्दावली को स्पष्ट करना, उसके वास्तविक अर्थ की व्याख्या, इस मार्ग की सीमाएँ तथा उपयोगिता का विवेचन प्रस्तुत किया है। डेविड ईस्टन की पुस्तक—The Political System, 1953; A Framework for Political Analysis, 1965 उनके द्वारा सम्पादित पुस्तक—Varieties of Political Theory तथा उनका बहु प्रचलित निबन्ध—The Current Meaning of Behaviouralism in Political science—में ईस्टन ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ईस्टन व्यवस्था (system) को राजनीतिक व्यवहार के विवेचन की प्रमुख इकाई मानते हैं। उनके अनुसार व्यवहारवाद सामाजिक अन्वेषण में नवीन प्रवृत्ति एवं प्रति आधुनिक विकास है। यह बौद्धिक प्रवृत्ति (intellectual tendency) और शैक्षणिक आन्दोलन (academic movement) दोनों ही हैं। ईस्टन व्यवहारवादी अध्ययन को सामान्य, व्याख्या प्रधान, विप्लेषणात्मक मार्ग मानते हैं जिसके वैज्ञानिक आधार से समाजशास्त्रों के सिद्धान्त परिपक्व हो चले हैं।

डेविड ईस्टन तथा राजनीतिक व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिलाएँ

डेविड ईस्टन²⁰ ने व्यवहारवादी अध्ययन की अवधारणाओं के विषय में निम्न-लिखित आठ बौद्धिक आधार शिलानों (intellectual foundation stones) को प्रस्तुत किया है:—

(1) नियमन (Regularities)—राजनीति से सम्बन्धित मानव व्यवहार में कुछ सामान्य अथवा एकरूप तत्त्व होते हैं जिनकी खोज की जा सकती है। इस प्रकार के एकरूप व्यवहार को, जिनका क्रम बना रहता है, सामान्यीकरण या सिद्धान्तबद्ध किया जा सकता है। इन सिद्धान्तों का महत्त्व भविष्य में व्यवहार बतलाने तथा विप्लेषण करने में है। ईस्टन ने इसे नियमन कहा है।

19. Ball and Lauth; Changing Perspective in Contemporary Political Analysis, p 60.

20. See Easton, David; The Current Meaning of Behaviouralism in Contemporary Political Analysis, Edited by James Charlesworth.

(2) सत्यापन अथवा प्रमाणीकरण (Verification)-इसका तात्पर्य सामान्य सिद्धान्तों की मान्यताओं वा मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण करने से है-अन्य शब्दों में मानव व्यवहार से सम्बन्धित सामग्री की पुनः परीक्षण एवं पुष्टि की जा सके।

(3) तकनीक (Techniques)-तकनीक वा तात्पर्य माध्यम से है जिनके आधार पर तथ्य प्राप्त किये जा सके तथा उनका विश्लेषण किया जा सके। विश्वसनीय ज्ञान एवं सामग्री एकत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्वसनीय एवं सर्वमान्य तकनीक एवं प्रवृत्तियों का प्रयोग किया जाय। अभी व्यवहारवादी अध्ययन में तकनीक के कई पक्षों का विकास हो रहा है।

(4) परिमाणन (Quantification)-अन्वेषण में तथ्य, सामग्री आदि जो उपलब्ध होते हैं उनको वारीकी या सूक्ष्मता के साथ रिकार्ड करना, उद्देश्यों के सन्दर्भ में परिमाण या मापदर्शक करना ताकि अभिप्राय और उपयुक्तता को समझा जा सके।

(5) आदर्श निर्माण अथवा मूल्य निर्धारण (Values)-नैतिक मूल्यरक्त और व्यवहारसिद्ध व्याप्य यद्यपि भिन्न हैं किन्तु व्यवहारवाद के अन्तर्गत इन दोनों के पृथक् या सम्मिलित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(6) क्रम-व्यवस्थीकरण (Systematization)-उपलब्ध सामग्री को इस प्रकार व्यवस्थित करना ताकि सामान्य सिद्धान्तों की सृष्टि तथा मानव व्यवहार में कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। अन्वेषण व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए। अन्य शब्दों में सिद्धान्त (theory) और अन्वेषण में निकटतम सम्बन्ध होना चाहिए क्योंकि ये दोनों व्यवस्थित ज्ञान के प्रमुख अंग हैं। सिद्धान्तहीन अन्वेषण तथा तथ्यों और अन्वेषण के बिना सिद्धान्त व्यर्थ है।

(7) विशुद्ध विज्ञान (Pure science)-ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप देना वैज्ञानिक कार्य का उतना ही भाग है जितना सिद्धान्त वा। राजनीतिक व्यवहार को समझना और उसका विश्लेषण वह आधार प्रस्तुत करते हैं जिससे राजनीतिक ज्ञान को समाज की आवश्यक एवं व्यावहारिक समस्याओं का हल निकालने में प्रयोग किया जा सके। मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाले तत्त्व पूर्णतः वैज्ञानिक रहें। व्यवहारवादी अध्ययन यथार्थता का अध्ययन है।

(8) समग्रता (Integration)-सभी सामाजिक शास्त्र मानव परिस्थितियों के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पक्षों का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक व्यवहारवादी अन्य समाज शास्त्रों की खोजों की अवहेलना नहीं कर सकता। उसे अन्य सामाजिक शास्त्रों की उपलब्धियों का प्रयोग करना चाहिये। इसमें राजनीति शास्त्र और अन्य शास्त्रों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होगा तथा अध्ययन समग्रता की स्थापना होगी। अन्य शब्दों में मानव व्यवहार का अध्ययन खण्डा में नहीं होना चाहिये। मानव व्यवहार का समग्र अध्ययन के लिए राजनीतिक अध्ययन को समाज शास्त्र का अंग बनना पड़ेगा।

उपरोक्त घाठ सूत्रो सूची मे डेविड ईस्टन ने व्यवहारवादी अध्ययन के सिद्धान्तों को सम्मिलित किया है। इनके आधार पर ही अन्वेषण के परम्परावादी और व्यवहारवादी पद्धतियों मे भेद स्थापित किया जा सकता है।

क्षेत्र एवं पद्धतियां-प्रबधियां

व्यवहारवादी मार्ग राजनीतिक तथ्यो की व्याख्या एवं विश्लेषण पद्धति है, सिद्धान्त नहीं। यह मनुष्य तथा उसके समूहो के व्यवहार से सम्बद्ध है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना तथा निष्कर्षों के परिमाणन मे सहायता देना है। यह अनुभव पर आधारित तथा क्रियात्मक अध्ययन है जिमे तत्वा-वधान में कुछ पद्धतियो, प्रबधियो का विकास हुआ है। ये पद्धतिया तथा तकनीकियां विषय सामग्री के ऊपर निर्भर करती है। यद्यपि व्यवहारवादियों का दावा है कि राजनीति विज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र व्यवहारवादी अध्ययन के अन्तर्गत आ सकता है किन्तु मतदान व्यवहार, छोटे छोटे समूह एवं सगठन, राजनीतिक प्रणालिया, नीति निर्धारण, प्रक्रियाएँ आदि का अध्ययन इस मार्ग के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है। मतदान व्यवहार के विषय मे अन्वेषण व्यवहारवादी अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। इस सम्बन्ध मे उन सभी कारकों-जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि का विश्लेषण किया जाता है जो व्यक्ति के मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सबसे अधिक व्यवहारवादी अध्ययन मतदान व्यवहार के विषय में हो हुआ है।

राजनीतिक सामाजिककरण (Political Socialization) राजनीति मे व्यक्तित्व की अन्तर्क्रिया से सम्बन्धित है। इस पद्धति का विकास सामान्यतः समाजशास्त्री तथा सामाजिक-मनोवैज्ञानिक राजनीति के क्षेत्र मे कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत 'भूमिका' (role) महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा व्यक्तित्व और सामाजिक संस्थाओं का विवेचन सम्भव हुआ है। राजनीतिक भूमिका (Political role) वर्तमान मे कई व्यवहारवादी अध्ययन तथा राजनीतिक सामाजिककरण के अध्ययन मे राजनीतिक व्यवस्था वा प्रमुख कार्य माना जाता है।

व्यवहारवादी अध्ययन के लिए एक अन्य प्रमुख क्षेत्र राजनीतिक व्यक्तित्व का अध्ययन है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति राजनीतिक विश्लेषण को इकाई होता है। इस अध्ययन का उद्देश्य व्यक्तित्व तथा राजनीतिक व्यवहार के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ उन सभी कारको का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा मनुष्य राजनीतिक भूमिका के लिए तैयार होता है।

संवैधानिक कानून के क्षेत्र मे व्यवहारवादी अध्ययन का उद्देश्य उन प्रभावो का पता करना होता है जो कानून निर्माण को प्रभावित करते हैं। इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत अध्ययन, न्यायाधीशो की आत्मकथाओ, शासन प्रक्रिया, न्यायालयो के सामूहिक हितो तथा राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है।

व्यवहारवादियों का विचार है उनकी पद्धतिया राजनीतिक हथि के समस्त पक्षों तथा शक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यान्विता की जा सकती हैं। इसलिए व्यवहारवादी सर्व-धार्मिक विधि, तुलनात्मक शासन, स्थानीय सस्थापना, लोक प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों आदि में अपनी पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं।

व्यवहारवादी अध्ययन के अन्तर्गत गुनीय पद्धतियों एवं प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है किन्तु सामान्यतः साक्षात्कार (Interview), सर्वेक्षण (Survey), प्रश्न-वली (questionare), विषय विश्लेषण (Content analysis), सांख्यिकी तकनीक (Statistical technique), प्रतिरूप (model) आदि का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि ये पद्धतिया राजनीति विज्ञान में पूर्णतः विकसित नहीं हो पाई हैं किन्तु सन्तोषजनक प्रगति हो रही है।

व्यवहारवादी अध्ययन की सीमाएँ

व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विश्लेषण करते समय उसके सामान्य स्वभाव, पृष्ठभूमी, संस्कृति, वातावरण आदि को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी मानव व्यवहार के निश्चित विवेचन में कई सीमाएँ हैं। मोहान (Eugene Meehan) ने अपने एक निवन्ध में मनुष्य की भौतिक संरचना, चेतन-अचेतन अवस्था तथा बाह्य वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मानव व्यवहार की अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता का विश्लेषण किया है। मोहान के अनुसार मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसमें किसी चीज को सीखना तथा भूलना की प्रिया क्षमता रहती है। इस प्रिया के सम्बन्ध में उसके व्यवहार में परिवर्तन एवं संशोधन होता रहता है। इसके प्रतिरिक्त मनुष्य का व्यवहार कुछ शारीरिक तत्त्वा, कुछ बाह्य वातावरण से निर्देशित रहता है। मनुष्य का बाह्य कार्य सदैव उसकी आन्तरिक इच्छा से सम्बन्धित नहीं रहता। मनुष्य का राजनीतिक जीवन का अधिकतम भाग मानव व्यवहार की सतह के नीचे रहता है जिसकी व्यवहारवादी या तो अवहेलना करते हैं या निश्चित रूप से उसके विषय में कुछ विश्लेषण नहीं कर सकते। वास्तव में मानव व्यवहार के विषय में सामान्यीकरण अथवा मिथ्यान्तीकरण करने में कई बाधाएँ तथा सीमाएँ हैं। कभी-कभी मनुष्य अपने विरोधों को धर्म, भुलावि तथा धोखे में डालने के लिए कुछ चलन से ही व्यवहार करता है। उसके व्यवहार में पीछे वास्तविक इच्छा का विश्लेषण स्वयं में एक समस्या बन जाता है। मानव व्यवहार की इन समस्याओं का राजनीति वैज्ञानिक के लिए बहुत ही सीमित अर्थ है यद्यपि यह मनोविज्ञान के माध्यम से सम्बन्धित सम्भव हो सकता है।

राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी अध्ययन के लिए सीमित क्षेत्र है। यह अध्ययन धार्मिकता के पारस्परिक सम्बन्ध, उनका सामूहिक व्यवहार जैसे मतदान, या अधिक से अधिक छोट-छोट समूह और संगठना, उनके आन्तरिक संगठन एवं प्रक्रिया

तक ही महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। किन्तु संस्थाओं के पारस्परिक सम्बन्ध जैसे राजनीतिक दल एवं व्यवस्थापिकाएँ, राजनीतिक दल एवं चुनाव पद्धतिया तथा इसी प्रकार के अन्य पक्षों के व्यवहार का अन्वेषण करने के लिए व्यवहारवादी तकनीक अधिक विश्वसनीय नहीं है। शेरीफ एव कॉसलिन (M. Sherif and B. L. Koslin) संस्थागत मार्ग (Institutional Approach) को महत्त्व देते हैं तथा संस्थाओं के अध्ययन के विषय में व्यवहारवादी मार्ग की उपयोगिता को सीमित समझते हैं।²²

व्यवहारवादी अध्ययन से निश्चित सिद्धान्तों की रचना असम्भव है। सर्वप्रथम मनुष्य के व्यवहार के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना ही असम्भव है। इसके प्रतिरिक्त विश्व इतनी विविधताओं से भरा हुआ है कि विभिन्न स्थानों पर एक ही कारण की विभिन्न प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। एक ही राजनीतिक स्थिति में एक भारतीय, एक अफ्रीकी, एक साम्यवादी, एक यूरोपीय व्यक्ति की प्रतिक्रिया सम्भवतः एक सी नहीं रहेगी। फिर मानव व्यवहार के आधार पर राजनीतिक व्यवहार के विषय में सामान्यीकरण कैसे सम्भव हो सकता है। हा, व्यवहारवादी अध्ययन से एक छोटे और एकलूप मानव समूह के विषय में कुछ सामान्यीकरण किया जा सकता है किन्तु ऐसे सिद्धान्तों का निर्माण नहीं जिनको विश्व व्यापक सिद्धान्त कहा जा सके।

मलफोर्ड सिबली (Mulford Q. Sibley) ने व्यवहारवादी अध्ययन की सीमाओं का नीति निर्माण के क्षेत्र में विवेचन किया है।²³ सिबली के अनुसार नीति-निर्माण के सम्बन्ध में व्यवहारवादी मार्ग की स्पष्ट सीमाएँ हैं। नीति निर्माण से अनुभववादी तथा नैतिक पक्ष सम्बद्ध हैं। साथ ही साथ व्यवस्थापिका की प्रमुख भूमिका रहती है। व्यवहारवादी अध्ययन नैतिक पक्ष की अवहेलना करता है। नैतिक पक्ष सिद्धान्तों का सोपान है जिसके अन्तर्गत अधिकार, न्याय, कर्तव्य आदि आते हैं। व्यवहारवादी 'क्या उद्देश्य होने चाहिये' के विषय में कुछ नहीं बतलाता। वैसे व्यवहारवादी अध्ययन का आदर्शात्मक पक्ष पहले से ही कमजोर है, नीति निर्माण के क्षेत्र में यह दुर्बलता और भी स्पष्ट हो जाती है।

व्यवहारवादी अध्ययन में पहल घबरा प्रारम्भिक अध्ययन की कमी रहती है। व्यवहारवादी अध्ययन वही सम्भव है जहाँ व्यक्ति समूह या संस्था पहले से सक्रिय हो या कोई विकास या घटना घीटत हो चुकी हो। इसके भीतर व्यवहारवादी अध्ययन एक सामान्य अन्वेषणकर्ता को दिन प्रतिदिन की राजनीति से पृथक् कर देता है। यह व्यवहारवादी अध्ययन की गम्भीर दुर्बलता एवं सीमा है कि दिन प्रतिदिन की राजनीति का अन्वेषण इसके अन्तर्गत नहीं आता।

व्यवहारवादी अध्ययन के समक्ष धन, समय तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव की सीमाएँ सदैम रही हैं। व्यवहारवादी अन्वेषण प्रत्येक व्यक्ति या संस्था अपने

22. Charlesworth, James; Contemporary Political Analysis, p 17.

23. Sibley, M Q., The Limitations of Behaviouralism, CPA, pp-68-69.

हाथों में नहीं ले सकते। व्यवहारवादी तबनीक एव प्रवृत्तियाँ घन राशि के बिना प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। साथ ही साथ इसमें समय एव धर्म की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त व्यवहारवादी अन्वेषण प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका योग सम्बन्ध एव कुशल व्यक्तियों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। व्यवहारवादी अन्वेषण इच्छुक व्यक्तियों को व्यवहारवादी तबनीक के प्रशिक्षण देने पर ही सम्भव है। इस प्रकार के प्रशिक्षण की इस अध्ययन में कमी है। व्यवहारवादी अध्ययन की सीमाओं के विषय में यूलाउ (Heinz Eulau) ने लिखा है—

“वास्तव में सीमाएँ प्रबन्ध हैं। किन्तु ये सीमाएँ स्थितिवज हैं। समय, प्रवृत्त और माध्यमों की सीमाएँ, व्यवहारवादी अध्ययन में पक्षपात, भ्रम और अदूरदर्शिता से उत्पन्न सीमाएँ, वैज्ञानिक पद्धति में निहित कुछ सीमाएँ जैसे प्रारम्भ में अटिपूर्ण चालें, करने या न करने की भूलें तथा अन्वेषण उपकरण अथवा पद्धतियों का सीमित होना।”²⁴ किन्तु ये सीमाएँ ऐसी नहीं हैं जिन पर काबू न पाया जा सके।

व्यवहारवादी अध्ययन मार्ग की आलोचना परम्परावादी आक्षेप

व्यवहारवादी अध्ययन को जैसे ही मान्यता मिलना प्रारम्भ हुआ इसके साहित्य की भरमार प्रारम्भ हो गई। साथ ही साथ इसके, डेविड ईस्टन के शब्दों में, सत्तगणों (doctrines) और आलोचकों ने पक्ष विपक्ष न सूत्र तक प्रस्तुत किये। यह वह समय था जबकि राजनीति में व्यवहारवाद अध्ययन पूर्णतः आन्दोलन बन कर छा जाना चाहता था। इस स्थिति में एक दिव्य तथा शान्त अध्ययन सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त प्रारम्भ में व्यवहारवादी शब्दावली से भी कुछ कठिनाई एव भ्रम उत्पन्न हुआ। व्यवहारवादी अध्ययन के विषय में कई शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसा कि डेविड ईस्टन ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद (Behaviourism) तथा राजनीति में व्यवहारवादी अध्ययन को समान्यतः एक ही समझा जाता था। प्रारम्भिक चरण में व्यवहारवादी अध्ययन के विद्वत् वे सामान्य आलोचनाएँ थीं। व्यवहारवादी मार्ग की परम्परावादियों ने लगभग समस्त पक्षा को लेकर आलोचना की है। परम्परावादियों के आक्षेपों को सूक्ष्म में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

(1) व्यवहारवाद मूल्यरहित अध्ययन को अग्रहीलना करता है। यह मार्ग मूल्य मुक्त (Value free) है तथा तथ्यों और मूल्यों में सर्वत्र भेद बनाए रखा जाता है। यह मार्ग राजनीति शास्त्र को आदर्शों की ओर नहीं ले जाता। यह उद्देश्यात्मक निर्देशन देकर बदल सकार्यता के अध्ययन में सन्तुष्ट रहता है। इस प्रकार आदर्शों को अग्रहीलना अथवा मूल्य-निरपेक्षता के प्राप्ति पर, जैसा कि लिओ स्ट्राउस (Leo Strauss) ने लिखा है अच्छे-बुरे में अन्तर स्थापित नहीं किया जा सकता। इसका

²⁴ Eulau, Heinz, Segments of Political Science Most Susceptible to Behavioural Treatment, CPA, p 33

तात्पर्य होगा कि मानव तथा दानव में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। ऐसा करके व्यवहारवादी निम्न एवं निन्दनीय पक्ष की विजय का समर्थन करते हैं।²⁵ साथ ही साथ परम्परावादियों का कहना है कि वैसे भी कोई भी अध्ययन (व्यवहारवादी अध्ययन सहित) मूल्य-मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि, प्रथम, अध्ययन एवं अन्वेषण के लिए जब विषय का चयन किया जाता है वह किसी न किसी प्रकार आदर्शों द्वारा ही निर्धारित होता है। द्वितीय, अन्वेषण के निष्कर्षों पर भी आदर्शात्मक मूल्यों का प्रमुख प्रभाव रहता है।

(2) व्यवहारवादी अपने अन्वेषण के लिए सामान्यतः ऐसे महत्त्वहीन विषय चुन लेते हैं जिनका मानव उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इनके बहुत से अन्वेषण व्यर्थ तथा निष्कर्ष पूर्व अनुमानित रहते हैं। मानव जाति का अनुभव हजारों वर्षों का है। मनुष्यों तथा उनके समूहों के व्यवहार का अवलोकन सदियों से चला आ रहा है। एक अनुभवी व्यक्ति बिना व्यवहारवादी साधनों तथा तकनीक के वे ही निष्कर्ष कह सकता है जो एक व्यवहारवादी तमाम समय, राशि व्यय कर तथा कई पद्धतियों की सहायता लेकर कर सकता है। थोड़ा बहुत अन्तर परिमाणीकरण में प्रवश्य हो सकता है।

(3) प्रमुख व्यवहारवादियों के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया जाता है कि इनका अध्ययन निष्पक्ष नहीं है। लगभग सभी व्यवहारवादी उदार लोकतन्त्र (Liberal democracy) के समर्थक हैं तथा वे अपने अन्वेषण और निष्कर्षों में इसी विचार से प्रभावित रहे हैं। इस सम्बन्ध में व्यवहारवादियों के अध्ययन एवं व्यवहार में परस्पर-विरोध दृष्टिगोचर होता है। एक ओर उनका अध्ययन मूल्य निरपेक्ष है तथा दूसरी ओर वे उदार लोकतन्त्र के सिद्धान्तों से भी प्रभावित हैं।

(4) व्यवहारवादी मार्ग के समर्थक अपने विचारों को नवीनता देने की उत्सुकता में नये-नये जटिल, यहाँ तक कि भद्दे लगने वाले शब्दों की रचना कर रहे हैं। व्यवहारवादी अध्ययन में शब्द-जाल अधिक है।

(5) परम्परावादियों का कहना है कि व्यवहारवादी समर्थक समाज विज्ञानों को एकता में विश्राम करते हैं। व्यवहारवाद अधिकतर मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र पर आधारित है। परम्परावादियों को भय है कि इस अन्तर्शास्त्रीय दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान कहीं राजनीतिक समाजशास्त्र (Political Sociology) बन कर न रह जाय तथा राजनीति विज्ञान का एक पृथक ज्ञान शाखा के रूप में ही अस्तित्व समाप्त न हो जाय। इसी पक्ष को प्रोफेसर बर्न्स (Walter Berns) ने अन्य शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है कि व्यवहारवादी अध्ययन के अन्तर्गत समस्याओं का अध्ययन राजनीति वैज्ञानिकों के हाथों से निकल कर व्यवसायी मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों

²⁵ Strauss, Leo; What is Political Philosophy, p. 89.,

Dahl, R.A., Modern Political Analysis, p. 105.

का अध्ययन होता जा रहा है। वह व्यक्ति जो अपने लिए व्यवहारवादी कहता है वास्तव में वह राजनीतिक न होकर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यवहारवादी बन जाता है।²⁶

(6) व्यवहारवादी अध्ययन में पद्धतियों एवं प्रवृत्तियों पर मुख्य जोर दिया जाता है। परम्परावादियों का विचार है कि इस कारण राजनीति में परम्परागत विन्तन तथा दर्शन में रुचि कम होने के साथ-साथ दार्शनिक पद्धतियों का अभाव होता जा रहा है। रसेल कर्क (Russel Kirk) की शका है कि वही व्यवहारवादी हम दार्शनिक बुद्धि को ही घसीट कर न ले जायें।²⁷

(7) व्यवहारवादी अध्ययन एक पक्ष को धार ही धार्मिक झुका हुआ है। व्यवहारवादियों ने अपने धर्मोपपाठ्यों के चयन में सर्वाधिक महत्त्व मतदान व्यवहार को दिया है। इस अध्ययन को वे सामाजिक मनोविज्ञान तथा राजनीति विज्ञान का सगम मानते हैं। किन्तु यह अध्ययन निष्पदा नहीं हो सकता। यह पूर्व निश्चित धारणाओं जैसे मतदान में धर्म, आयु, धार्मिक वर्ग, परिवार, जातीय पृष्ठभूमि आदि पर आधारित रहता है।

(8) व्यवहारवादी समर्थकों का कहना है कि उनके अध्ययन से राजनीतिक व्यवहार में परिमाणन में प्रगति हुई है। किन्तु व्यवहारवादी पद्धतियों के आधार पर महो परिमाणन भी सम्भव नहीं। उदाहरणार्थ सर्वदलील पद्धति में कुछ चुने हुए व्यक्तियों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। उन्हें सर्वत्र पूरे समुदाय का निष्कर्ष मानना मूल होगी। इसके अतिरिक्त यह सम्भावना भी सर्वदलील रहती है कि जिनसे साक्षात्कार लिया गया है वे सभी बातें सही न बतलाएँ, इस प्रकार व्यवहारवादी पद्धतियाँ वैज्ञानिक विश्लेषण और अटकलवाजी दोनों पर ही आधारित रहती हैं।

(9) व्यवहारवादियों का कहना है कि उनके माध्यम से राजनीति-शास्त्र विज्ञान बन जायेगा। हालाँकि के विचार से उनकी यह मान्यता सत्य सिद्ध नहीं हुई है। वे अभी तक मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए हैं। राजनीतिक अध्ययन को विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए उनके प्रयासों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली है।

उत्तर-व्यवहारवादी अध्ययन (Post-Behaviouralism)

व्यवहारवादी भाग का जिस समय प्रादुर्भाव हो रहा था उसे परम्परावादी विरोध का सामना करना पड़ा था। इस स्थिति से एक और परम्परावादी बूढ़े विचार तथा दूसरी ओर व्यवहारवादी युवा-विचारों के मध्य तर्क-मुद्द प्रारम्भ हो गया। परिणामस्वरूप राजनीतिक वैज्ञानिक दो जिवितों में विभाजित हो गये। दोनों ही भागों के तर्क-विचारों का क्रम चलता रहा। किन्तु दोनों के तर्कों में निष्पक्ष

²⁶ See Mulford Q Sibley, The Limitations of Behaviouralism, CPA, p 55
²⁷ Dunner, Joseph, Dictionary of Political Science, p XVI

राजनीति विज्ञान के नवीन आयाम

विवेक का प्रभाव था। धर्म दोनों मार्गों के समर्थन मानने लगे। है कि उनके विरोधियों के कुछ तर्कों तथा अध्ययन मार्ग की प्रवृत्तियाँ नहीं की जा सकती। इस सामन्वय प्रवृत्ति ने उत्तर-व्यवहारवादी अध्ययन की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

तत्कालीन व्यवहारवादी प्रगति का समय लगभग 1965 तक माना जाता है। इस समय तक व्यवहारवादियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर राजनीति विज्ञान में अपना प्रतिष्ठित स्थापित कर लिया था। व्यवहारवादी अध्ययन के कुछ समर्थक इस स्थिति से लगभग सन्तुष्ट थे तबले थे किन्तु अधिकांश व्यवहारवादी अपने अध्ययन मार्ग की दुर्बलताओं को महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने व्यवहारवादी अध्ययन को अधिक प्राज्ञ तथा समन्वयपरक बनाने के पुनर्मूल्यांकन का कार्य प्रारम्भ किया। इसका उद्देश्य विरोधी दालोवनाओं के सन्दर्भ में अपनी दुर्बलताओं को दूर करना तथा साथ ही साथ उनके अच्छे तर्कों को ग्रहण करना था।

लगभग इसी समय राजनीतिक जगत में घनेक राजनीतिक, सामाजिक विकास हुए जिन्होंने वास्तव में व्यवहारवादी अध्ययन के समक्ष एक संकट उत्पन्न कर दिया। यह आवश्यक था कि इन नवीन स्थिति में व्यवहारवादी मार्ग अपनी उपयोगिता और उपयोगिता बनाये रखे नहीं तो इस प्रगतिशील युग में उनका अध्ययन पिछड़ा हुआ लगने लगेगा। नवीन परिस्थितियों के साथ धारमतात करने तथा नवीन समस्याओं के समाधान करने के लिए व्यवहारवादी अध्ययन को मध्य बनाया जाय इस पक्ष पर लगभग सभी जोर देने लगे। वास्तव में इन प्रवृत्ति एवं प्रयास को उत्तर-व्यवहारवादी पुनरावलोकन कहा गया है। यहाँ से व्यवहारवादी अध्ययन का एक दूसरा चरण प्रारम्भ होता है।

रविड ईस्टन उन प्रमुख व्यवहारवादियों में से हैं जिन्होंने उत्तर-व्यवहारवादी पुनरावलोकन की ओर ध्यान आकर्षित किया। 1969 में 'अमेरिकी पॉलिटीकल साइन्स एसोसिएशन' के वार्षिकी भाषण में उनके विचारों का यही आधार था। उन्होंने नवीन परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारवादी अध्ययन की प्रगति पर निराशा व्यक्त की। उनका कहना था कि राजनीति विज्ञान का मोक्ष तब अध्ययन की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे वह वर्तमान समस्याओं के साथ अपनी संगति स्थापित कर सके। इसके उपरान्त लगभग सभी व्यवहारवादियों के प्रयास इस ओर लगे हुए हैं। उत्तर-व्यवहारवादी अध्ययन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत किया जा सकता है :—

तकनीकी प्रतिपादितता से मुक्ति

पूर्व-व्यवहारवादियों को तकनीक-परस्त कहा गया है। उन्होंने व्यवहारवादी प्रवृत्तियों को इतना महत्व दिया है कि कभी कभी वे अन्यथा में अपने मूल उद्देश्यों को भी भूल जाते हैं। उत्तर-व्यवहारवादियों ने अपनी इस त्रुटि से मुक्ति बचाई है।

वे तकनीक से पूर्व उन व्याप्तिकताओं को महत्व देना चाहते हैं जिनका सम्बन्ध गम्भीर सामाजिक समस्याओं से है। जैसा कि हास एव बेकर (M Hass and T. L. Becker) ने लिखा है उत्तर-व्यवहारवादी अध्ययन का उद्देश्य स्वयं को तकनीक की प्रतिवादिता से मुक्त कराना है। ये व्यवहारवादी अध्ययन में सश्लेषणात्मक एव बहु-पद्धति-विज्ञानात्मक पक्ष का समर्थन करते हैं।

आदर्शात्मक अथवा मूल्यात्मक अध्ययन

व्यवहारवादी मार्ग के विरुद्ध जो व्यापक आलोचना हुई है व्यवहारवादियों ने उन्हें पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है। सभी प्रमुख व्यवहारवादियों ने उनकी आलोचना के प्रत्येक पक्ष का प्रत्युत्तर दिया है। रॉबर्ट डहल (Robert Dahl) ने यह आक्षेप स्वीकार नहीं किया है कि व्यवहारवाद मूल्य मुक्त अथवा मूल्य निरपेक्ष है। "निश्चय ही कोई सिद्धान्तकार जो राजनीति में तटस्थ और निष्पक्ष अनुभववादी विवेचन का विकास करता है इसका अर्थ यह नहीं कि वह मूल्य निरपेक्ष ही हो। अच्छे और बुरे के आधार होते हैं किन्तु राजनीति में उनका प्रयोग करने से पहले यह जानना भी आवश्यक होना है कि विभिन्न विकल्पों के चयन के क्या परिणाम हो सकते हैं। नैतिकता का प्रयोग शून्यता में नहीं किया जाता, हम नैतिक आधारों का प्रयोग घटनाओं के विश्व में करते हैं। जहाँ तक सम्भव होता है हम विश्व घटनाओं को सही ढंग से समझते हैं।²⁸ उत्तर-व्यवहारवादी अध्ययन आदर्शों के प्रति सचेत है तथा आदर्श निष्ठाओं की ओर दिशा दर्शन कराने का प्रयास करता है।

सम्बन्धपरक अध्ययन होना चाहिये (3)

राजनीति विज्ञान के अध्ययन में परम्परावादी अति-हृदिवादी तथा व्यवहारवादी अति-प्रगतिवादी प्रकीर्त होत हैं। राजनीति विज्ञान का सन्तुलित अध्ययन इन दोनों सम्प्रदायों के मध्य की स्थिति में सम्भव है। राजनीतिशास्त्र के परम्परागत दार्शनिक दृष्टिकोण की अवहेलना नहीं की जा सकती। एल्फ्रेड ग्राज़िया ने लिखा है—

"चिन्तन मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। सभी मनुष्य जिनके विषय में हम थोड़ा बहुत जानते हैं चाहते हैं आदिवासी अथवा तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील हो अपने जीवन के अर्थ को व्यक्त करते हैं। चिन्तन के मनुष्य केवल एक बोलने वाला पशु ही रहगा।"²⁹

सामान्यतः व्यवहारवादी सभी व्यवहारवादी विज्ञानों की एकता में विश्वास व्यक्त करते हैं किन्तु डेविड ट्रूमन के विचार कुछ भिन्न हैं। ट्रूमन के विचार से राजनीतिशास्त्र में परम्परावादी तथा व्यवहारवादी अध्ययन मार्गों में जिनके समान आधार हैं उतने अन्य व्यवहारवादी विज्ञानों के पारस्परिक सम्बन्धों में नहीं। शोनी

²⁸ Dahl, Robert, Modern Political Analysis, p 106

²⁹ Grazia, Alfred, de; Political Behaviour, p 15

परम्परावादी और व्यवहारवादी अध्ययनों का उद्देश्य शासन संस्थाओं और प्रक्रियाओं के विश्लेषण से सम्बन्धित हैं। टूमेन इन दोनों अध्ययन मार्गों को एक दूसरे का पूरक समझते हैं तथा राजनीतिक अध्ययन में दोनों के समन्वय का सुझाव देते हैं। व्यवहारवादी अन्वेषण व्यक्ति पर केन्द्रित है तथा राजनीति विज्ञान का आधार संस्थाएं हैं। राजनीतिक व्यवहारवादी अध्ययन में संस्थागत अध्ययन का अभाव है किन्तु दूसरी ओर संस्थाओं का वर्णनात्मक अध्ययन अपूर्ण एवं असामयिक हो गया है। यहाँ व्यवहारवादी अध्ययन अवश्य ही परम्परागत अध्ययन का पूरक हो सकता है। सभी व्यवहारवादी अब इस तथ्य से अवगत हैं।³⁰ स्वयं अमेरिका में जो व्यवहारवादी आन्दोलन की जन्मभूमि है, व्यवहारवादी और संस्थावादी मार्गों का उर्ध्व अध्ययनो में प्रयोग किया जा रहा है। अमरीकी व्यवस्थापिका (काग्रस), तुलनात्मक शासन, संवैधानिक कानून आदि के विषय में इस प्रकार का अध्ययन सफल आ है। संस्थाओं का मैक्रो-विश्लेषण (macro-analysis) तथा उनसे सम्बन्धित परिवर्तनशील कारकों (variables) का माइक्रो-विश्लेषण (micro-analysis) राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अवश्य ही समृद्धिशाली बनायेगा।³¹

व्यवहारवादियों के समक्ष अपने अध्ययन के क्षेत्र और उद्देश्य को स्पष्ट करने ही समस्या है। व्यवहारवादियों को राजनीतिक व्यवहार का, न कि समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का अध्ययन करना है। किन्तु कौनसा व्यवहार राजनीतिक है यह कहना प्रसम्भव है। आज के सन्दर्भ में कोई भी समस्या विशुद्ध राजनीतिक नहीं हो सकती। उसे आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य पक्ष भी सम्बद्ध रहते हैं। अमेरिका में नीग्रो समस्या केवल राजनीतिक ही नहीं, वह नस्ल-भेद, आर्थिक, न्याय आदि से भी सम्बद्ध है। इसलिये राजनीति को समझने के लिए केवल व्यवहारवादी ही बने रहना सब कुछ नहीं है। राजनीति वैज्ञानिक को व्यवहारवादी होने के प्रतिरिक्त इतिहासकार विधिवेत्ता और नैतिकवादी भी होना चाहिये।

उत्तर-व्यवहारवादी अध्ययन अति निकट का विकास है इसलिए इसका स्वरूप एवं प्रमुख विशेषताएं अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पायी हैं। किन्तु इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान में स्वयं के भविष्य को आरक्षित रखना है। वैसे व्यवहारवादी अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन चुका है। इस सम्बन्ध में रॉबर्ट डाल्ट के विचारों द्वारा निष्कर्ष प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। डाल्ट ने लिखा है—

“व्यवहारवादी मनोदशा (mood), जिसे एक असहमति आन्दोलन समझा गया है, अब इस स्थान से कहा ले जायेगा? मेरे विचार से यह लुप्त हो जाएगा।

10. Ball and Lauth, *Changing Perspectives in Contemporary Political Analysis*, p. 67

11. Ghosh, P.K., *Studies in Contemporary Political Theory*, p. 14

इससे मेरा तात्पर्य है कि इसका एक पृथक् एक विशिष्ट मनोदशा और दृष्टिकोण के रूप में शनं शनं पतन हो जायेगा क्योंकि राजनीति विज्ञान में इसका समावेश हो जायेगा और वास्तव में ही भी चुका है। व्यवहारवादी मनोदशा का लोप इसलिए नहीं होगा कि यह सम्पन्न हुआ है, किन्तु इसलिए कि यह मफल हुआ है। इससे इसके एक पृथक्, एक साम्प्रदायिक जैसे तथा एक गृहबन्दी जैसे दृष्टिकोण का अन्त हो जायेगा। 32

व्यवहारवादी अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन चुका है। व्यवहारवादी अध्ययन-मार्ग की यद्यपि सीमाएँ हैं किन्तु राजनीति विज्ञान में इसकी उपयोगिता में घटा नहीं किया जा सकता। राजनीति शास्त्र की जब में एक प्रथक ज्ञान शाखा के रूप में स्वीकार किया गया है इसे विज्ञान बनाने के निरन्तर प्रयास चलते रहें। व्यवहारवादी अध्ययन ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

निर्णय निर्माण सिद्धान्त Decision Making Theory

[7] समाजशास्त्र की विभिन्न ज्ञान शाखाओं में निर्णय (अथवा विनिर्चय) निर्माण सिद्धान्त के प्रति अध्ययन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। निर्णय निर्माण सिद्धान्त के बढ़ते हुए महत्त्व को जूडिथ शक्लर (Judith Shklar) ने निर्णयवाद (Decisionism) कहा है। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन एकप्रमुख उद्देश्य बन गया है ताकि मनुष्य की निर्णय रुचि बनीयता, विकल्प आदि के रहस्य को समझा जा सके। राजनीति के अध्ययन में यह विकास तथा है किन्तु मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रशासन में इनका व्यापक प्रयोग हो चुका है। राजनीति विज्ञान में यह अध्ययन राजनीतिक समस्याओं एवं परिस्थितियों से ही सम्बद्ध है। मूहम में इसका अर्थ विभिन्न विकल्पों का चयन तथा निष्कर्षों पर पहुँचने का अध्ययन है। पॉल डीजिंग (Paul Diezang) ने राजनीतिक निर्णयों की परिभाषा करते हुए लिखा है कि इनका सम्बन्ध निर्णय संरचना (दाव) को बनाये रखना तथा उत्तम सुधार करना है। प्रत्येक निर्णय किसी न किसी प्रकार की निर्णय निर्माण संरचना के अन्तर्गत ही लिए जाते हैं किन्तु राजनीतिक निर्णयों की निर्णय निर्माण संरचना इसकी विषय सीमाएँ हैं। ब्रुनो लिओनी (Bruno Leoni) के अनुसार राजनीतिक निर्णयों का उद्देश्य शक्ति के सम्बन्ध से है या उससे पूर्व शक्ति-परिस्थिति में सुधार करना है।³³ डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक - The Political System (1953) - में राजनीति को मूल्यांकन प्रणाली का सत्तात्मक निर्धारण (the authoritative allocation of values) कह कर परिभाषित किया है। ईस्टन के इस विचार को निर्णय निर्माण से जोड़ा

32. Dahl, Robert A., *The Behavioural Approach in Political Science*, Ibid, p. 119

33. Robinson and Majak, *The Theory of Decision Making*, CPA, p. 175

जाता है। ईस्टन ने लिखा है "जैसा कि अधिकतर राजनीति-वैज्ञानिक इस शब्द का प्रयोग करते हैं राजनीतिक निर्णय निर्माण सार्वजनिक रूप से सत्तात्मक निर्धारण या वितरण करता है।"³⁴ निर्णय निर्माण सिद्धान्त का क्षेत्र इतना व्यापक है कि राजनीतिक निर्णयों से सम्बन्धित संरचनाएँ, निर्णय प्रक्रिया, निर्णयों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, निर्णय सम्बन्धी विभिन्न विकल्पों का चयन, सरकार के सभी षट्, प्रशासन के सभी स्तर आदि का अध्ययन इसके अन्तर्गत आता है। अध्ययन की व्यापकता को देखते हुए विभिन्न ज्ञान शाखाओं से इसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है।

हरबर्ट साइमन (Herbert Simon)

राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण सिद्धान्त के विकास में हरबर्ट साइमन तथा रिचर्ड स्नायडर का मूल योगदान है। हरबर्ट साइमन चार्ल्स मेरियम के शिष्य तथा शिकागो सम्प्रदाय के एक प्रमुख सदस्य रहे हैं। लोक प्रशासन में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक-Administrative Behaviour-ने एक नवीन अध्ययन का प्रवर्तन किया है। उनकी यह पुस्तक प्रशासनिक संगठनों में निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन पर आधारित है। साइमन निर्णय निर्माण को संगठनों की सर्वाधिक महत्त्व की क्रिया मानते हैं। वे इस अध्ययन को संगठनों का मूलभूत संयन्त्र तथा राजनीतिक प्रक्रिया का केन्द्र भाग मानते हैं। साइमन ने संगठन समस्याओं का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि भ्रम विभाजन कार्यों पर नहीं किन्तु शक्तियों के आधार पर निर्णय निर्माण करने के अधिकारों-से है। जितना उच्च पदाधिकारी होगा उसके कार्य करने का क्षेत्र कम होकर निर्णय लेने के अधिकार अधिक होते हैं। सर्वोच्च अधिकारी नीति सम्बन्धी निर्णय लेते हैं किन्तु उनके बाद के प्रशासक विस्तारपूर्वक निर्णय लेते हैं। इस प्रकार समस्त संगठन निर्णय निर्माण में भाग लेता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया को साइमन ने एक प्रतिरूप (model) द्वारा अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यह प्रतिरूप मनोविज्ञान पर आधारित है। वास्तव में इस प्रतिरूप के माध्यम से साइमन ने निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न विकल्पों एवं परिणामों का विश्लेषण किया है। इस आधार पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपयुक्त विकल्पों के चयन का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है, रिचर्ड स्नायडर (Richard C. Snyder)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण सिद्धान्त के प्रयोग का श्रेय स्नायडर को दिया जाता है। स्नायडर अमेरिका के प्रिन्सटन तथा केलीफोर्निया विश्वविद्यालय से सम्बन्धित रहे हैं। प्रिन्सटन विश्वविद्यालय में ब्रुक (H. W. Bruck) तथा बर्टन सेपिन (Burton Sapin) के सहयोग से स्नायडर की प्रसिद्ध पुस्तक-Foreign Policy Decision-Making—An Approach to the Study of International Politics (New York, Free Press, 1962) प्रकाशित हुई। रॉसनो (James Rosenau)

34 Robinson and Majak; Theory of Decision-Making, CPA, p 175.

का विचार है कि इस पुस्तक ने निर्णय निर्माण मार्ग के क्षेत्र में मूल एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह प्रथम प्रयास था जिसके माध्यम से विदेश नीति के क्षेत्र में निर्णय निर्माण की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। स्नायडर के बाद इस सम्बन्ध में और भी कार्य हुआ है किन्तु उनका अध्ययन एवं प्रवर्तन कार्य माना जाता है।

रिचर्ड स्नायडर ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को क्रिया, प्रतिक्रिया तथा अन्तःक्रिया (actions, reactions and interactions) माना है। जहाँ क्रिया है वहाँ उससे प्रतिक्रिया भी सम्बन्धित रहती है। चूँकि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कई क्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ तथा अन्तःक्रियाएँ होती हैं तदनुसार प्रक्रियाएँ भी कई प्रकार की होती हैं। इस स्थिति ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रमुख इकाई होता है तथा उसी की प्रमुख भूमिका रहती है। किन्तु राज्य का कार्य उनके द्वारा चलाया जाता है जो राज्य के नाम पर कार्य करते हैं। वे ही निर्णय लेने वाले होते हैं। स्नायडर के विचार में निर्णय निर्माण करने वाले पदाधिकारियों के व्यवहार का विश्लेषण आवश्यक है इसके अतिरिक्त गैर सरकारी कारक भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं इसके लिये यह राजनीति, भौगोलिक तत्व, राष्ट्रीय वातावरण, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्धों का विवेचन आवश्यक है। ये वास्तव तथा अन्तरिक दशाएँ परिवर्तित होती रहती हैं तथा निर्णय निर्माण प्रक्रिया के विवेचन में इन परिवर्तनों के विश्लेषण का ध्यान रखना आवश्यक है।

निर्णय निर्माण सिद्धान्त की संरचना (frame-work)

निर्णय निर्माण के अन्तर्गत विषय सामग्री का चयन और व्यवस्थित करन के लिए एक सामान्य संरचना होती है। इस संरचना के कुछ आवश्यक तत्व एवं स्तर होना हैं जैसे—(i) निर्णय परिस्थितियाँ (decision situations) जिनके अन्तर्गत निर्णय लिए जाते हैं। (ii) निर्णय निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्ति (decision participants) तथा उनका विवेचन अर्थात् उनका व्यक्तित्व, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, अनुभव तथा उनके द्वारा विभिन्न नैतिक मूल्यों को दो जाने वाली प्राथमिकता आदि। (iii) निर्णय संगठन (decision organisation) अर्थात् प्रशासनिक संगठन जिसके अन्तर्गत निर्णय लिये जाते हैं; तथा निर्णय संगठन की विभिन्न इकाइयाँ तथा निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका। (iv) निर्णय प्रक्रिया (decision process) अर्थात् जिस क्रम से निर्णय लेने की प्रगति होती है, तथा (v) निर्णय निष्कर्ष (decision outcome) आदि। सभी प्रकार के निर्णयों के लिए एक जैसा संरचना प्रस्तुत करना असम्भव है किन्तु राजनीतिक निर्माण की दृष्टि से निर्णय प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह सिद्धान्त निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक सम्बद्ध है।

निर्णय प्रक्रिया अथवा प्रगति क्रम (Decision process)

"प्रक्रिया का तात्पर्य तकनीक, पद्धतिया, क्रिया विधि ब्यूह रचना—चेतन या अचेतन का योग है जिनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है।" 35 निर्णय प्रक्रिया में 'कौन निर्णय लेता है' को सम्मिलित नहीं किया जाता किन्तु 'निर्णय किस प्रकार लिया जाता है' यह प्रमुख है, जैसे किस अवसर या परिस्थिति में निर्णय लिया गया, किस प्रकार के संगठन के अन्तर्गत निर्णय लिया गया तथा उसका क्या परिणाम हो सकता है आदि। हेरॉल्ड लासवेल ने अपनी पुस्तक—The Decision Process (1956) में निर्णय प्रगति-क्रम के सात क्रियात्मक सोपानों (functional stages) का उल्लेख किया है जैसे— (i) सूचना (information) इस स्तर पर समस्या का पता करना तथा सूचना एकत्रित की जाती है। (ii) विचार स्तर (recommendation) अर्थात् विभिन्न विकल्पों के विषय में विचार करने का स्तर। (iii) विकल्प चयन (prescription) इस स्तर पर विभिन्न विकल्पों को स्वीकार किया जाता है। (iv) अस्थाई क्रिया (invocation) अस्थाई रूप से कार्यान्वित करने का स्तर। (v) अनुप्रयोग (application) निर्णय को विशिष्ट रूप से कार्यरूप देना। (vi) मूल्यांकन (appraisal) निर्णय तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना। (vii) अन्तिम स्तर (termination) अर्थात् निर्णय को बनाये रखना या उसमें सुधार करना या उसे समाप्त करने का अन्तिम स्तर। हरबर्ट साइमन तथा अन्य ने निर्णय निर्माण की चार प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। प्रथम, समस्या समाधान (problem solving); द्वितीय, अनुनय (persuasion); तृतीय, सौदेबाजी (bargaining); तथा चतुर्थ, राजनीति (politics) इनके अनुसार दो या दो से अधिक प्रक्रियाओं का निर्णय निर्माण में योगदान होता है।

निर्णय उप-प्रक्रियाएँ (Decision sub-processes)

निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्य निर्णय उप-प्रक्रियाएँ होती हैं जिन पर अनेको कारकों का प्रभाव पड़ता है। इन कारकों को बौद्धिक (intellectual), सामाजिक (social) और अर्ध-यान्त्रिक (quasi-mechanical) आदि पक्षों में विभाजित किया जा सकता है। निर्णय निर्माण उप-प्रक्रिया में बौद्धिक पक्ष का अर्थ निर्णय निर्माण के विश्लेषण से है। यह विश्लेषण व्यक्तिगत या समूह रूप से किया जा सकता है। निर्णय अन्तर्दृष्टि, अन्तर्ज्ञान, अनुभव ज्ञान, समस्या समाधान, समस्या से सम्बन्धित सूचना आदि का संग्रह, विकल्पों का चयन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य बौद्धिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएँ भी निर्णय लेने पर प्रभाव डालती हैं। विभिन्न समूहों में सहयोग, अन्तर्से मूह हितों का आदान प्रदान आदि इन पक्ष के अन्तर्गत आते हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक पक्ष महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्ति, समूह, संगठन

थादि अपने हितों को सुरक्षा देते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। ग्रह-प्राप्तिक पक्ष का प्रभाव बजट तथा मूल्य व्यवस्था के ग्रहप्रयत्न में देखने को मिलता है। इन सभी पक्षों में सामाजिक प्रक्रिया का निर्णय-निर्माण उप-प्रक्रिया पर सर्वाधिक प्रभाव है तथा सामाजिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।

निर्णय-परिणाम (Decision outcome)

निर्णय निष्कर्ष सम्पूर्ण निष्पत्ति प्रक्रिया का मांग है। इस स्तर के तीन पक्ष महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आउटपुट या निष्पत्ति (output), आउटकम या परिणाम (outcome) तथा प्रभाव (effect) में विभाजित किया जा सकता है। आउटपुट का तात्पर्य निर्णय निर्माण में विभिन्न उप-प्रक्रियाओं के निष्कर्ष से है। आउटकम का तात्पर्य निर्णय निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया (उप-प्रक्रियाओं सहित) के अन्तिम निर्णय से है। अन्य शब्दों में विभिन्न उप-प्रक्रियाओं के निष्कर्ष (output) के योग तथा सम्बन्धपूर्ण स्थिति को आउटकम कहा जा सकता है। आउटपुट एक प्रकार से निर्णय निर्माण इकाई की मध्यवर्ती प्रक्रिया है जबकि आउटकम अन्तिम निर्णय (end product) है। आउटपुट का उपयोग निर्णय इकाई के अन्दर होता है जबकि आउटकम निर्णय इकाई के बाहर निर्णय स्थिति है। इस प्रकार अन्तिम वैकल्पिक प्रभाव सम्बन्धी स्तर शेष रहता है। आउटकम को व्यावहारिक रूप देने तथा उसके परिणाम सम्बन्धी पक्षों को निर्णय प्रभाव (effect) कहते हैं। यह व्यावहारिक तथा प्रभाव पक्ष होने के साथ साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया का अन्तिम स्तर है।

प्रशासनिक साधन में निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले से हो चली आ रही है किन्तु इसका स्वरूप मुख्यतः निर्देश सिद्धान्त (Prescriptive Theory) द्वारा निर्धारित या अर्थात् निर्णय निर्माण सिद्धान्त अन्तर्गत के विश्लेषण तार्किक विवेक तथा सामान्य अनुभव पर आधारित था। अब इसका स्वरूप बदल चुका है। अब निर्णय निर्माण के विषय में वर्णनात्मक सिद्धान्त (Descriptive Theory) में रुचि बढ़ती जा रही है। इसके अन्तर्गत यह विश्लेषण किया जाता है कि व्यक्ति जिस प्रकार विनिश्चय घबरा लिए लेता है, विवेकपूर्ण निर्णय लेने में कौन सी बाधाएँ हैं तथा किन परिस्थितियों के अन्तर्गत वे विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वास्तव में इस ग्रहप्रयत्न का विस्तार व्यक्ति से लेकर संगठन तक है। इस सम्बन्ध में हरवर्ट साइमन ने मार्च (J G March) के सहयोग में लिखी पुस्तक—Organisations, (New York, Wiley, 1958) में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में व्यवहार विज्ञान (Search 'behaviour') पर अधिक ज़ारूरत दे रखी है।

सूचकांक

1/ निर्णय-निर्माण प्रणाली के विरुद्ध आवाजों की एक प्रारम्भिक शक्ति है। क्या निर्णय-निर्माण प्रणाली को 'सिद्धान्त' का श्रेणी में दिया जा सकता है?

मालोचक इसे सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते। रॉबिन्सन तथा माजक का मत है कि निर्णय-निर्माण केवल एक प्रक्रिया का विवेचन है इस आधार पर कोई मध्यम सिद्धान्त नहीं बन जाता। सिद्धान्त निर्माण इन बातों पर निर्भर करता है कि इसको विषय सामग्री का ऐसा विस्तार हो जिससे यह समझा जा सके कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं तथा उनका निर्णय इकाई के अन्दर तथा बाहर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिए कि निर्णय-निर्माण मध्यम की राजनीतिक सिद्धान्त का रूप दिया जाय जिससे हमारे उस ज्ञान में वृद्धि हो कि 'कोन क्या, कब और कैसे पाता है' (who gets what, when, how) 37 जेम्स रॉसनाउ (James Rosenau) के भी समझ में ऐसे ही विचार हैं यद्यपि उनके तर्क कुछ भिन्न हैं। रॉसनाउ के अनुसार यह मध्यम सिद्धान्तकरण की ओर अग्रसर होने में असफल रहा है। निर्णय-निर्माण के प्रारम्भिक एवं मूल प्रतिपादन में सिद्धान्त का अभाव था। रिचर्ड स्नापडर ने स्वयं ही निर्णय-निर्माण में विभिन्न सम्बन्धों एवं कारकों के अस्तित्व का उल्लेख करते हुए भी सिद्धान्तकरण नहीं किया। 38

निर्णय-निर्माण में सिद्धान्त के अभाव का कारण स्पष्ट है। यद्यपि संगठन सम्बन्धी चराचर तत्त्वों का विस्तारपूर्वक विवेचन है किन्तु अन्तरिक तथा बाह्य व्यवस्था से सम्बन्धित चराचर तत्त्वों को केवल छोड़ा ही परखा गया है। रिचर्ड स्नापडर निर्णय-निर्माण को विदेश नीति में सम्बद्ध करने की ओर अधिक दृष्टि देने के लिए प्रभाव डालने वाले अन्तरिक तत्त्वों की सामान्यतः अवहेलना की है। प्रशासनिक अधिकारी क्या सम्भावित निर्णय लेने इनका सिद्धान्तबद्ध करना भी आसान नहीं। देश के अन्दर विभिन्न मार्गों तथा राष्ट्रीय आकाशाएँ विदेश नीति के प्रमुख स्रोत हो सकती हैं, किन्तु ये दगाएँ जिनके अन्तर्गत प्रशासन अधिकारी निर्णय लेते हैं अनिश्चित हैं। बाह्य दशाओं तथा आकाशाओं का मापदण्ड करना और भी अनिश्चित है।

राजनीतिक निर्णय-निर्माण सिद्धान्त निर्माण लेने वाले अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रह सकते। जिस वातावरण में निर्णय-निर्माण प्रक्रिया चलती है तथा निर्णय लिये जाते हैं उसका महत्त्व भी कम नहीं। विश्व का अवलोकन निर्णय-निर्माण करने वालों के दृष्टिकोण में ही नहीं करना चाहिए किन्तु राजनीतिक अध्येतक को स्वयं विश्व का भी परीक्षण करना चाहिए ताकि निर्णय-निर्माण की व्यापकता को समझा जा सके। जैसा कि जेम्स रॉसनाउ ने लिखा है "राजनीतिक निर्णय-निर्माण का कोई सिद्धान्त नहीं हो सकता यदि वह उस राजनीतिक वातावरण जिसमें निर्णय लिए जाते हैं से पृथक है।" 39 रॉसनाउ ने निर्णय-निर्माण के एक

37. Robinson and Majak; *Ibid.*, pp. 187-88.

38. Roscau, James N., *The Premises of Decision Making Analysis*, CPA, p.

39. Rosenau, James, N., *The Premises of Decision Making Analysis*, CPA, p. 209.

समग्र (unified) सिद्धान्त का समर्थन किया है। जिसमें सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सके।

निर्णय-निर्माण अध्ययन के समझ सबसे महत्वपूर्ण समस्या एक कार्य प्रक्रिया निर्णय (process outcome) के क्षेत्र में अन्वेषण को प्रांगे बढ़ाने की है। अभी तक निर्णय अध्ययन का अधिकतम ध्यान इकाई या प्रक्रिया के अन्दर ही केन्द्रित रहा है न कि प्रक्रिया और निष्कर्ष के विषय में। आज के जटिल और विस्तृत समाज में निर्णय लेने वाली सत्ताएँ स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर, तथा प्रत्येक स्तर पर विभिन्न समस्याओं में विचेन्द्रित हैं। इन सभी का समग्र अध्ययन निर्णय-निर्माण के लिए एक चुनौती है। इसके अतिरिक्त विभागीकरण (departmentalization) तथा प्रक्रिया के समूहीकरण (Collectivism) ने निर्णय-निर्माण अध्ययन के लिए और भी समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। निर्णय प्रक्रिया के अन्तर्गत मुख्य उत्पत्ति स्थानों को खोजना असम्भव हो गया है। इससे प्रक्रिया और निष्कर्ष सम्बन्ध और जटिल हो गया है। निर्णय निर्माण सिद्धान्त का इन सभी जटिलताओं, प्रवृत्तियों को अपने अन्वेषण एवं अध्ययन में समावेश करना आवश्यक है।

राजनीति विज्ञान में निर्णय निर्माण के अन्तर्गत राजनीतिक निर्णयों का ही अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। किन्तु आजकल समस्याएँ विशुद्ध राजनीतिक नहीं रहो हैं। अधिकांश समस्याओं के साथ आर्थिक तथा अन्य पक्ष भी सम्बद्ध रहते हैं इसलिये इस अध्ययन को बहुपक्षीय एवं अन्तर्शास्त्रीय होना आवश्यक है।

निर्णय प्रक्रिया के विश्लेषण से उन विभिन्न तत्वों के विषय में ज्ञान हाता है जो इन पर प्रभाव डालते हैं। इससे हमें उन शक्तिशाली किन्तु गुप्त कारकों की भी जानकारी होती है जिनके प्रभाव की सामान्यतः जानकारी नहीं रहती। अमरीकी राष्ट्रपति कनेडी ने एक बार कहा था कि निर्णय प्रक्रिया में कुछ ऐसे अवाञ्छनीय एवं जटिल कारक छुपे रहते हैं जो सर्वोच्च पदाधिकारियों के लिये भी एक रहस्य बन रहते हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के ज्ञान से हमें ऐसे तत्वों की समझने, अधिक प्रभावों निर्णय लेने तथा नीति निर्धारण में सहायता मिलती है।⁴⁰

यद्यपि निर्णय निर्माण सम्बन्धी अध्ययन प्रारम्भिक परिधि से निकल कर अवधारणात्मक अवस्था तक पहुँच कर एक उपागम अथवा अध्ययन मार्ग बन गया है किन्तु अभी भी अपूर्णता के कारण सिद्धान्त की धरोहर में नहीं आ सका है। फिर भी इसकी प्रगति को देखते हुए कम से कम 'निर्णय निर्माण' शब्द का व्यापक प्रयोग होने लगा है। राजनीति शास्त्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी भी हमें प्रति बिना आक्षेपित हुए बिना नहीं रह सके। अब यह अध्ययन प्रशासन, सेना, विदेश नीति में पूर्णतः मान्य

⁴⁰ Holsman, Roger, Policy Making as Politics, in International Politics and Foreign Policy Ed by James N Rosenau, pp 237-38

गया है। इस अध्ययन ने राजनीति शास्त्र को और अधिक वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संचार सिद्धांत

Communication Theory

सिद्धान्त के प्रवर्तक : नॉरबर्ट वीनर तथा कार्ल डॉयश

नॉरबर्ट वीनर (Norbert Wiener, 1894-1964) को संचार सिद्धान्त का प्रारम्भिक प्रवर्तक माना जाता है। नॉरबर्ट वीनर अमेरिका में मैसेचुसेट विश्वविद्यालय में टेक्नॉलॉजी संस्थान के सुप्रसिद्ध गणितशास्त्री थे। वीनर ने सन्देश सिद्धान्त (Theory of Messages), सायबरनेटिक्स (Cybernetics) तथा फीडबैक सिस्टम (Feedback System) के आधार पर संचार सिद्धान्त का विकास किया। राजनीति विज्ञान में संचार सिद्धान्त का प्रवर्तक कार्ल डॉयश (Karl W. Deutsch) ने किया है। कार्ल डॉयश अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शासन के प्रोफेसर हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में इनकी गणना प्रमुख विद्वानों में की जाती है। उनकी पुस्तकें हैं—Nationalism and Social Communication (राष्ट्रीयता और सामाजिक संचार) 1954; The Nerves of Government (सरकार का ज्ञानयुतंत्र) 1963; The Analysis of International Relations (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विश्लेषण-1968, आदि। कार्ल डॉयश ने अपनी पुस्तक—The Nerves of Government) में संचार सिद्धान्त की व्याख्या की है। कार्ल डॉयश के संचार सिद्धान्त का आधार नॉरबर्ट वीनर का ही संचार सिद्धान्त है तथा उसका ही विकास एवं विस्तार किया है। डॉयश ने इस पुस्तक में संचार के विभिन्न तन्त्रों का विवेचन कर उनकी शासन से तुलना की है। इसके अन्तर्गत डॉयश ने 'सूचना प्रवधारणा' (Concept of Information), फीडबैक तन्त्र (Concept of Feedback) का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

संचार सिद्धांत की व्याख्या

संचार सिद्धांत (Communication Theory) का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त राजनीतिक व्यवस्था के कुछ पक्षों के विश्लेषण करने के लिए एक उपकरण अथवा साधन के रूप में किया गया। मूलतः इस सिद्धान्त का विकास गणित शास्त्र के अन्तर्गत हुआ किन्तु कुछ राज-वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग राजनीति के क्षेत्र में किया है।

संचार (Communication) का तात्पर्य उन प्रमुख अवधारणाओं से है जिनका सम्बन्ध मानव व्यवहार के वर्तमान अध्ययन मार्गों से है। वारेन वीवर (Warren Weaver) के अनुसार 'संचार' शब्द के अन्तर्गत वे सब प्रक्रियाएँ आ जाती हैं जिनके द्वारा दूसरे के विचारों को प्रभावित किया जाता है। इसमें

लिखित व मुद्राग्र भाषण ही नहीं मानव व्यवहार भी सम्मिलित है।⁴¹ डेनिएल लर्नर (Daniel Lerner) न संचार का अर्थ सूचना के आदान प्रदान (information) से लिया है। सूचना कोई भी संदेश (Message) हो सकता है जिसका अर्थ संदेश भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला समझ सके। संदेश का आदान प्रदान शब्दों, संकेतों तथा अन्य माध्यम से हो सकता है। संचार प्रणाली (Paradigm) में तीन प्रमुख पक्ष होते हैं—(i) संदेश भेजने वाला, (ii) संदेश तथा (iii) संदेश प्राप्त करने वाला। संचार की यह प्रणाली राजनीति में संचार सिद्धांत का आधार है।⁴²

जैसा कि रॉबर्ट नार्थ (Robert North) न लिखा है—संचार सिद्धांत एक दृष्टिकोण है जो सुझाव देता है कि समस्त सगठन कुछ विशेषताओं के आधार पर एक जैसे ही होते हैं। प्रत्येक सगठन संचार द्वारा एक मूल में बांधे रहते हैं, दो या अधिक व्यक्तियों अथवा सगठनों में सम्पर्क केवल संचार माध्यम से ही स्थापित होता है। इस प्रकार समाज को केवल संदेशों के अध्ययन तथा उनके विषे संचार सुविधाओं के आधार पर ही समझा जा सकता है।⁴³

संचार सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक गतिविधियाँ एक सीमा तक मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति तथा उनके आदान प्रदान पर निर्भर हैं। यह केवल एक साधारण व्याख्या है। इसके प्रवर्तकों ने संचार अध्ययन का सांख्यिक-नैतिक तथा फीडबैक सिस्टम के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

सांख्यिक-नैतिक (Cybernetics)-नार्वेड वीनर का संचार सिद्धान्त संदेश सिद्धान्त पर आधारित है तथा संदेश सिद्धान्त सांख्यिक-नैतिक पर आधारित है। सांख्यिक-नैतिक का एक मूलतः सिद्धान्त शरीर तकनीक के समूह में है जिसका प्रयोग कुछ मशीन, पशु, मानव, समाज, राष्ट्रीय-राज्यों की उन सम्भावनाओं तथा संदेश प्रक्रिया द्वारा नियंत्रण के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक सीमा तक सामाजिक-राजनीतिक सगठन की प्रमुख विशेषताएँ वातावरण, जनसंख्या, तकनीक के स्तर पर निर्भर करती हैं। अन्य शब्दों में यह ज्ञान तथा कुशलता की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। मनुष्य अनुकूल वातावरण में अपने ज्ञान तथा कुशलता में वृद्धि करता है किन्तु इन पर 'सांख्यिक-नैतिक' प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है।

फीडबैक सिस्टम (Feedback System)—यह एक तुलनात्मक व्यवस्था का नाम है जिसके अन्तर्गत वास्तविक स्थिति अथवा व्यवस्था की अल्पकालिक उत्तम व्यवस्था में तुलना कर उन दोनों का अन्तर मापन किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त की गई सूचना तथा उनके प्रयोग करने की प्रक्रिया वास्तव में वास्तव

41 North, R. C., The Analytical Prospects of Communications Theory, CPA, p. 300

42 Dunner, Joseph, Dictionary of Political Science, p. 109

43 Charlesworth, James, Contemporary Political Analysis, p. 302